सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
और
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
और
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग

भाग - I

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	1-4
2	नीति	5-10
3	उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन	11-16
4	नियामक, सलाहकार और अन्य निकाय	17-48
5	योजनाएं और कार्यक्रम	49-72
6	केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान	73-100
7	अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान	101-118
8	प्रौद्योगिकी समर्थित अधिगम	119-156
9	दूरस्थ शिक्षा	157-162
10	भाषा संस्थान	163-198
11	अनुसंधान परिषद	199-208
12	आईसीसी और यूनेस्को	209-220

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

भाग - II

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1.	**समग्र शिक्षा**	
(i)	समग्र शिक्षा	
(ii)	राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020	
(iii)	स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)	
(iv)	राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस)	
(v)	निःशुल्क वर्दी और पाठ्यपुस्तकें	
(vi)	राज्यों के लिए शिक्षण–अधिगम और परिणाम को मजबूत करना (स्टार्स)	
(vii)	उभरते भारत के लिए पीएम स्कूल (पीएम श्री)	
(viii)	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी)	
(ix)	समग्र शिक्षा के अंतर्गत "पुस्तकालय घटक"	
(x)	समग्र शिक्षा के अंतर्गत "खेल अनुदान" घटक	223-248
(xi)	योग	
(xii)	राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए)	
(xiii)	समग्र शिक्षा के तहत टिंकरिंग लैब्स	
(xiv)	लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण	
(xv)	विद्यांजलि	
(xvi)	आकांक्षी जिला कार्यक्रम	
(xvii)	आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी)	
(xviii)	एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान (2022–23)	
(xix)	व्यावसायिक शिक्षा	
(xx)	सांख्यिकी	

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
2.	**स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की प्रमुख योजनाएँ**	249-272
(i)	पीएम–पोषण	
(ii)	प्रौढ़ शिक्षा (उल्लास)	
(iii)	राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार	
(iv)	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस)	
(v)	भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता योजना	
(vi)	वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम	
(vii)	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम–जनमन)	
3.	**स्कूल शिक्षा को संस्थागत सहायता**	273-371
(i)	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	
(ii)	जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी)	
(iii)	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)	
(iv)	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस)	
(v)	राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)	
(vi)	केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)	
(vii)	राष्ट्रीय बाल भवन	
	अनुलग्नक	373-379

उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के साझा अध्याय

भाग - III

क्र.सं.	अध्याय का नाम	पृष्ठ सं.
1.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा	383-401
2.	पूर्वोत्तर और पर्वतीय राज्यों का शैक्षिक विकास	403-424
3.	अल्पसंख्यकों की शिक्षा	423-429
4.	महिलाओं का शैक्षिक विकास	431-437
5.	दिव्यांगजनों का शैक्षिक विकास	439-450
6.	प्रशासन	451-459
7.	सीएंडएजी लेखापरीक्षा	461-463
8.	बजट	465-476
9.	**अनुलग्नक**	
	I. संगठनात्मक चार्ट – उच्चतर शिक्षा विभाग	477
	II. संगठनात्मक चार्ट – स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	478

भाग - I

उच्चतर शिक्षा विभाग

01

प्रस्तावना

प्रस्तावना

शिक्षा मंत्रालय में दो विभाग हैं:

- **स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (एसई और एल)**
- **उच्चतर शिक्षा विभाग (एचई)**

"भारत सरकार (कार्य का आवंटन) नियम, 1961" के अनुसार शिक्षा मंत्रालय को निम्नलिखित विषय आवंटित किए गए हैं:

क. स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

1. प्रारंभिक शिक्षा
2. बुनियादी शिक्षा
3. बाल भवन, बाल संग्रहालय
4. सामाजिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा
5. इस सूची में प्रविष्टियों के संदर्भ में दृश्य–श्रव्य शिक्षा
6. सूची में मदों के संबंध में पुस्तकें (उन पुस्तकों के अतिरिक्त जिनका संबंध सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है) और पुस्तक विकास (स्टेशनरी पेपर और समाचार प्रिंट उद्योगों को छोड़कर, जिनका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है)।
7. सूची में मदों के संबंध में शैक्षिक अनुसंधान।
8. सूची में मदों के संदर्भ में प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।
9. सूची में मदों के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण।
10. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद।
11. इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित परोपकारी और धर्मार्थ संस्थान, परोपकारी और धार्मिक निधियां।
12. माध्यमिक शिक्षा और व्यावसायिक मार्गदर्शन।
13. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद।

ख. उच्चतर शिक्षा विभाग

1. विश्वविद्यालय शिक्षा; केंद्रीय विश्वविद्यालय; उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा योजना और स्कूल शिक्षा के विकास से संबंधित ग्रामीण उच्चतर शिक्षा विदेशी सहायता कार्यक्रम।
2. उच्चतर शिक्षा संस्थान (विश्वविद्यालयों को छोड़कर)।
3. सूची में मदों के संबंध में पुस्तकें (उन पुस्तकों के अतिरिक्त जिनका संबंध सूचना और प्रसारण मंत्रालय से है) और पुस्तक विकास (स्टेशनरी पेपर और समाचार प्रिंट उद्योगों को छोड़कर, जिनका संबंध वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से है)।

4. सूची में मदों के संदर्भ में श्रव्य दृश्य शिक्षा।
5. क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्य–पुस्तकें तैयार करना।
6. शैक्षिक अनुसंधान।
7. प्रकाशन, सूचना और सांख्यिकी।
8. बहुभाषी शब्दकोशों सहित हिंदी का विकास और प्रसार।
9. हिंदी के शिक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
10. संस्कृत का प्रचार और विकास।
11. विस्थापित शिक्षकों और छात्रों से संबंधित पुनर्वास और अन्य समस्याएं।
12. केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड।
13. यूनेस्को और यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग।
14. इस विभाग द्वारा निपटाए जाने वाले विषयों में विदेशों और विदेशी एजेंसियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी छात्रवृत्तियों से संबंधित मामले, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, गैर–अधिसूचित, खानाबदोश और अर्ध–घुमंतू जनजातियों के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों, और विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति और विभिन्न योजनाएं शामिल नहीं होंगी।
15. विदेशों में भारतीय छात्रों की शिक्षा और कल्याण; विदेशों में भारतीय मिशनों के शिक्षा विभाग; विदेशों में शिक्षा संस्थानों और भारतीय छात्र संघों को वित्तीय सहायता।
16. शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम; शिक्षकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों, आदि का आदान–प्रदान; भारत और विदेशों के बीच विद्वानों का आदान–प्रदान कार्यक्रम।
17. विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों को विदेश में असाइनमेंट स्वीकार करने की अनुमति देना।
18. भारतीय संस्थानों में विदेशी छात्रों का प्रवेश।
19. इस विभाग के अंतर्गत आने वाले विषयों से संबंधित धर्मार्थ और परोपकार संस्थान, परोपकार और धार्मिक निधियां।
20. विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में उच्च गणित, परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा में अनुसंधान को छोड़कर तदर्थ वैज्ञानिक अनुसंधान।
21. विज्ञान मंदिर।
22. गणित, परमाणु विज्ञान और परमाणु ऊर्जा के अलावा अन्य क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विदेश जाने वाले वैज्ञानिकों को आंशिक वित्तीय सहायता के संबंध में सामान्य नीति।
23. तकनीकी शिक्षा का विस्तार, विकास और समन्वय।
24. योजना तथा वास्तुकला विद्यालय।
25. क्षेत्रीय मुद्रण स्कूल।
26. तकनीकी शिक्षा के लिए राज्य सरकार के संस्थानों, गैर–सरकारी संस्थानों, पेशेवर निकायों और संघ राज्य क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों को सहायता अनुदान। बुनियादी विज्ञान में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सहायता अनुदान, शैक्षिक संस्थानों में उच्चतर

वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के विकास के लिए सहायता अनुदान; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मौलिक अनुसंधान के लिए अनुदान सहायता; मौलिक अनुसंधान के लिए व्यक्तियों को अनुदान।

27. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, जिसमें राष्ट्रीय डिप्लोमा और राष्ट्रीय प्रमाणपत्र परीक्षा आयोजित करना शामिल है।

28. इंजीनियरिंग और तकनीकी संस्थानों के छात्रों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण सुविधाएं।

29. भारत सरकार के अधीन पदों पर भर्ती के प्रयोजनों के लिए व्यावसायिक तकनीकी योग्यता की मान्यता।

30. राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप और अध्येतावृत्ति।

31. भारत में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में विदेशी परीक्षा आयोजित करना।

32. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

33. नेशनल बुक ट्रस्ट।

34. एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, हैदराबाद।

35. इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स एंड एप्लाइड जियोलॉजी, धनबाद।

36. खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, चेन्नई, दिल्ली, गुवाहाटी और रुड़की में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान।

37. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर।

38. टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई।

39. भारत और विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट हाउस।

40. आधुनिक भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजनाएँ।

41. इंजीनियरिंग व्यावसायिक सेवाओं का विनियमन।

42. वास्तुकार अधिनियम, 1972 (1972 का 20)।

❖ ❖ ❖

02

नीति

नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (एनईपी 2020)

हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद दिनांक 29.07.2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक शिक्षा प्रणाली की कल्पना करती है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके, भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके।

एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

(i) पूर्व–प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना;

(ii) 3–6 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना;

(iii) नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना (5 + 3 + 3 + 4)

(iv) कला और विज्ञान के बीच, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच बड़ा अंतर सुनिश्चित न करना;

(v) मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन की स्थापना;

(vi) बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर; कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन अधिमानतः ग्रेड 8 और उसके बाद तक, शिक्षा का माध्यम घरेलू भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा होगी।

(vii) मूल्यांकन सुधार– किसी भी स्कूल वर्ष के दौरान दो अवसरों पर बोर्ड परीक्षा शुरू करना, एक मुख्य परीक्षा और यदि वांछित हो तो सुधार के लिए एक;

(viii) एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना;

(ix) समान और समावेशी शिक्षा– सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल देना;

(x) वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक अलग जेंडर समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करना;

(xi) शिक्षकों की भर्ती और योग्यता आधारित प्रदर्शन के लिए मजबूत और पारदर्शी प्रक्रियाएं;

(xii) स्कूल परिसरों और समूहों के माध्यम से सभी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(xiii) राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (एसएसएसए) की स्थापना;

(xiv) स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना;

(xv) उच्चतर शिक्षा में जीईआर को 50: तक बढ़ाना;

(xvi) कई प्रवेश/निकास विकल्पों के साथ समग्र बहु–विषयक शिक्षा का परिचय;

(xvii) एनटीए द्वारा एचईआई में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा शुरू करना;

(xviii) एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना;

(xix) बहु–विषयक शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालयों (एमईआरयू) की स्थापना;

(xx) राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एनआरएफ) की स्थापना;

(xxi) 'लाइट बट टाइट' विनियमन तैयार करना;

(xxii) चिकित्सा और कानूनी शिक्षा को छोड़कर शिक्षक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एकल व्यापक बहुआयामी निकाय की स्थापना – भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (एचईसीआई) के साथ मानक निर्धारण के लिए स्वतंत्र निकायों जैसे सामान्य शिक्षा परिषद; वित्त पोषण–उच्च शिक्षा अनुदान परिषद (एचईजीसी); प्रत्यायन–राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (एनएसी); और विनियमन–राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद (एनएचईआरसी);

(xxiii) जीईआर बढ़ाने के लिए मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का विस्तार।

(xxiv) शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण.

(xxv) व्यावसायिक शिक्षा उच्चतर शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। स्टैंड–अलोन तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विधि और कृषि विश्वविद्यालय, या इन या अन्य क्षेत्रों में संस्थान, बहु–विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य रखेंगे।

(xxvi) शिक्षक शिक्षा – 4 साल के एकीकृत चरण–विशिष्ट, विषय–विशिष्ट स्नातक शिक्षा की शुरूआत

(xxvii) सलाह के लिए एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना.

(xxviii) एक स्वायत्त निकाय, राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच (एनईटीएफ) का सृजन जो अधिगम, मूल्यांकन, योजना, प्रशासन को संचालित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग पर विचारों के मुक्त आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उचित एकीकरण।

(xxix) उच्चतर शिक्षा के वाणिज्यीकरण का सामना करने और रोकने के लिए जांच और संतुलन के साथ कई तंत्र की शुरूआत करना।

(xxx) सभी शिक्षण संस्थानों को लेखापरीक्षा और प्रकटीकरण के समान मानकों के लिए 'लाभ के लिए नहीं' इकाई के रूप में माना जाएगा।

(xxxi) केंद्र और राज्य शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे ताकि जल्द से जल्द सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत तक पहुंच सके।

(xxxii) गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर समग्र ध्यान केंद्रित करने के लिए समन्वय सुनिश्चित करने हेतु केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को मजबूत करना।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में शिक्षा को अधिक छात्र–केंद्रित और बहु–विषयक बनाने के लिए देश में स्कूल शिक्षा के साथ–साथ उच्च शिक्षा में सुधार की सिफारिश की गई है। इसका उद्देश्य देश में स्कूल और उच्चतर शिक्षा प्रणालियों में परिवर्तनकारी सुधारों का मार्ग प्रशस्त करना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, नीति के कार्यान्वयन के लिए कई पहलों और कार्यों की आवश्यकता होती है, जिसे कई निकायों द्वारा समकालिक और व्यवस्थित तरीके से करना होगा। इसलिए, इस नीति के कार्यान्वयन का नेतृत्व शिक्षा मंत्रालय, सीएबीई, संघ और राज्य सरकारों, शिक्षा से संबंधित मंत्रालयों, राज्य शिक्षा विभागों, बोर्डों, एनटीए, स्कूल और उच्च शिक्षा के नियामक निकायों, एनसीईआरटी, एससीईआरटी, स्कूल और एचईआई सहित विभिन्न निकायों द्वारा किया जा रहा है। चूंकि शिक्षा एक समवर्ती विषय है, इसलिए इसे केंद्र और राज्यों के बीच सावधानीपूर्वक योजना, संयुक्त निगरानी और सहयोगात्मक कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। तदनुसार, मंत्रालय और इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों, नियामक निकायों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य हितधारक मंत्रालयों/विभागों ने एनईपी 2020 के कार्यान्वयन की दिशा में पहल करना शुरू कर दिया है।

इस दिशा में, मंत्रिमंडल सचिवालय ने दिनांक 21.10.2021 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ नीति आयोग द्वारा समन्वित मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का प्रस्ताव रखा। 15 से 17 जून 2022 तक धर्मशाला में मुख्य सचिवों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का एक विषय 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन' था। यह सम्मेलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एनईपी

2020 के कार्यान्वयन की स्थिति, अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं, कार्यान्वयन प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों और एनईपी, 2020 के बेहतर कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली भविष्य की कार्रवाई के बारे में बातचीत करने और साझा करने का एक अवसर था।

सम्मेलन में निम्नलिखित निर्णय लिए गएः–

(i) शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए कार्रवाई के रोडमैप के कार्य बिंदुओं के संबंध में लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिगम प्रक्रिया को साझा करने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

(ii) एचईआई की रैंकिंग के लिए कार्यप्रणाली का अध्ययन और रैंकिंग मापदंडों के आधार पर, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर भारतीय एचईआई की विषयवार और विश्वविद्यालय–वार रैंकिंग में सुधार करने के लिए उचित रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) भारतीय ज्ञान प्रणाली/पारंपरिक औषधियों का अनुसंधान और प्रसार, ताकि इसे विश्व स्तर पर विज्ञान/औषधि के रूप में स्वीकार किया जा सके और उचित प्रोटोकॉल विकसित किया जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श के आधार पर, शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान कार्यान्वयन के लिए कुछ कार्य बिंदुओं को अंतिम रूप दिया गया और शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रारूप में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया। नीति आयोग के शासी परिषद की 7वीं बैठक 7 अगस्त 2022 को हुई थी। इस बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ यह निर्देश दिया गया कि वरिष्ठ स्तर पर नियमित निगरानी होनी चाहिए और एनईपी के कार्यान्वयन के लिए एक स्पष्ट समयबद्ध रोडमैप होना चाहिए। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, एनईपी 2020 के कार्यान्वयन, कार्यनीति और एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई के रोडमैप पर चर्चा करने के लिए दिनांक 31.10. 2022 और 05.12.2022 को राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ दो परामर्श–सह–समीक्षा बैठकें आयोजित की गई। जिसके उत्तर में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए 18 कार्य बिंदुओं/लक्ष्यों पर की गई अपनी कार्रवाई साझा की। 36 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से, 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के लिए अपने लक्ष्य प्रस्तुत किए थे, जबकि 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने मात्रात्मक लक्ष्य और उपलब्धियां साझा की थीं। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन और उच्च शिक्षा क्षेत्र में इसकी उपलब्धि का मामला क्रमशः 28.02.2023, 09.03. 2023, 24.03.2023, 11.05.2023 और 09.06.2023 को आयोजित क्षेत्र–वार परामर्श–सह–समीक्षा बैठकों और पत्राचार के माध्यम से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उठाया गया है।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023

शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा 29 और 30 जुलाई 2023 को स्कूल, कौशल और उच्च शिक्षा को कवर करते हुए दो दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया गया। इस अवसर पर, माननीय प्रधान मंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत चयनित 6207 स्कूलों को 630 करोड़ रुपये की पहली किस्त जारी की। उन्होंने 12 भारतीय भाषाओं में अनुवादित शिक्षा और कौशल पाठ्यक्रम की पुस्तकों का भी विमोचन किया।

विभिन्न पृष्ठभूमियों से 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने उद्घाटन सत्र में भाग लिया। उद्घाटन सत्र के बाद, एबीएसएस, 2023 कार्यक्रम के दौरान स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा के क्रॉस–कटिंग विषयों पर 16 विषयगत सत्र आयोजित किए गए। लगभग 3000 शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने विषयगत सत्रों में भाग लिया, जिसने सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया। विभिन्न विषयों पर अलग से 27 लघु संवाद सत्र भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर, बाल–वाटिका, खिलौना आधारित शिक्षा, आईकेएस, अटल टिंकरिंग लैब्स, आइडिया लैब्स, स्टार्ट–अपस, विश्वविद्यालयों/एचईआई और

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों आदि द्वारा सर्वोत्तम प्रथाएं जैसे विषयों पर शिक्षा और कौशल मंत्रालय के तहत संस्थानों, संगठनों, उद्योग और प्रमुख हितधारकों द्वारा लगभग 200 स्टालों के साथ मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। लगभग 2 लाख उपस्थित लोगों ने प्रदर्शनी का दौरा किया।

एबीएसएस, 2023 के दौरान उच्चतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा और कौशल जैसे विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 106 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। अन्य गतिविधियों में एक मोबाइल ऐप, लोगो और उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने को समझना): कार्यक्रम का नारा, नव भारत साक्षरता को शुरू करना शामिल था। साथ ही, 25 चयनित छात्रों को सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी में तीन पाठ्यक्रमों नामतः आईआईटी एम द्वारा निर्देशित वायुमंडलीय एवं जलवायु विज्ञान में एमटेक; सार्वजनिक नीति में एमए – आईआईटीएम द्वारा मार्गदर्शन; और ऊर्जा प्रौद्योगिकी एवं नीति में एमए – आईआईटी कानपुर द्वारा मार्गदर्शन में प्रवेश की पेशकश की गई। केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) की 10 प्रमुख परियोजनाओं के तहत पुस्तकें जारी की गईं। बौद्धिक विरासत पर अलग से 7 पुस्तकें नामतः 'सीमाओं से परे– मन की बात के सामाजिक प्रभाव का एक अध्ययन'; 'गरीबों और सीमांत लोगों के लिए नीतियां – भारत में गरीब कल्याण योजना का एक अध्ययन'; नए भारत की ओर – बुनियादी ढांचे, समुदाय और विकास का एक अध्ययन'; नवीकरणीय ऊर्जा – भारत में हरित ऊर्जा और इसके सतत उपयोग का अध्ययन'; और 'मेकिंग न्यू इंडिया' का विमोचन किया गया। उपरोक्त के अलावा दो और पुस्तकें नामतः 'मन की बात – एक राष्ट्र और उसके लोगों की प्रेरक परिवर्तनकारी क्षमता' और 'सशक्त भारत' का भी विमोचन किया गया।

माननीय प्रधानमंत्री 29 जुलाई, 2023 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन के अवसर पर संबोधित करते हुए

अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 (29–30 जुलाई, 2023)

❖ ❖ ❖

03

उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन

उच्चतर शिक्षा का सिंहावलोकन

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई)

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) देश में उच्चतर शिक्षा पर डेटा का एकमात्र व्यापक स्रोत है। इसे 2011 में शुरू किया गया था और उसके बाद वर्षों से उच्चतर शिक्षा के लिए एक मजबूत और समावेशी डेटाबेस बनाने के लिए वार्षिक आधार पर आयोजित किया जा रहा है। नीति–निर्माण के लिए विभिन्न मूल्यवान जानकारी, जैसे छात्र नामांकन (जेंडर–वार और श्रेणी–वार), एआईएसएचई के तहत पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की संख्या, शिक्षण/गैर–शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या (जेंडर–वार और श्रेणी–वार) रिपोर्ट की गई, बुनियादी ढांचे (पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कौशल विकास केंद्र, कंप्यूटर लैब, शौचालय आदि) और संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात (जीईआर), छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर), जेंडर समानता सूचकांक (जीपीआई) जैसे संकेतकों आदि की गणना एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र किए गए डेटा से की जाती है। ये सूचित नीतिगत निर्णय लेने में उपयोगी हैं। यह उल्लेख करना उचित है कि एआईएसएचई रिपोर्ट में प्रकाशित परिणाम उन संस्थानों की संख्या पर आधारित हैं जिन्होंने एआईएसएचई में पंजीकरण किया है और अपनी जानकारी अपलोड की है। नवीनतम एआईएसएचई सर्वेक्षण वर्ष 2021–22 के लिए पूरा किया गया है।

उच्चतर शिक्षा में नामांकन:

उच्चतर शिक्षा में वर्ष 2014–15 में कुल नामांकन 3.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है, अर्थात नामांकन में लगभग 26.5% की वृद्धि हुई है।

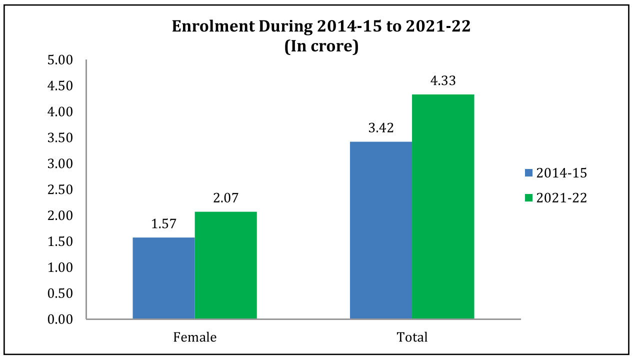

- उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन बढ़कर 2.07 करोड़ हो गया (2014–15 से 31.6% की वृद्धि)।
- वर्ष 2021–22 में नामांकित 4.33 करोड़ छात्रों में से 15.3% अनुसूचित जाति से, 6.3% अनुसूचित जनजाति से, 37.8% अन्य पिछड़ा वर्ग से और शेष 40.6% छात्र अन्य समुदायों से हैं।
- **एससी नामांकन:** अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2020–21 में 58.95 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 66.23 लाख हो गया है। वर्ष 2014–15 से एससी छात्र नामांकन में कुल मिलाकर 43.8% की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जाति की महिला छात्रों का नामांकन

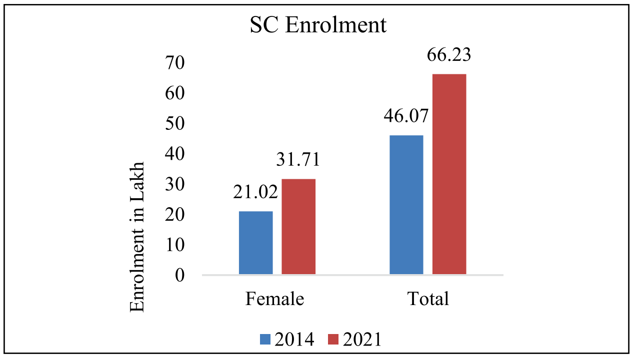

वर्ष 2020–21 में 29.01 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 31.71 लाख हो गया है। वर्ष 2014–15 से एससी महिला छात्र नामांकन में कुल वृद्धि 50.9% है।

- **एसटी नामांकन:** अनुसूचित जनजाति के छात्रों के मामले में, नामांकन वर्ष 2020–21 में 24.12 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 27.10 लाख हो गया है। वर्ष 2014–15 से एसटी छात्र नामांकन में कुल वृद्धि 65.2% है। एसटी महिला छात्रों का नामांकन वर्ष 2020–21 में 12.21 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 13.46 लाख हो गया है। वर्ष 2014–15 से एसटी महिला नामांकन में 80.1% की वृद्धि देखी गई है।

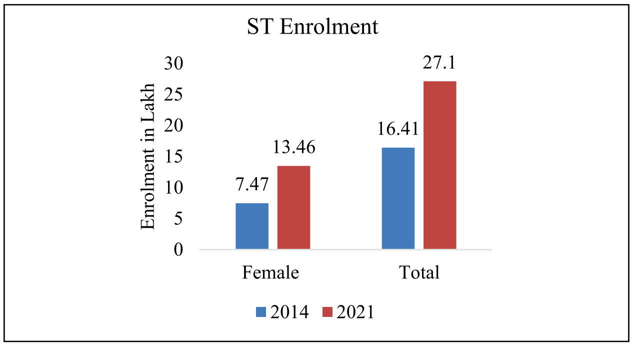

- **ओबीसी नामांकन:** अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों का नामांकन वर्ष 2020–21 में 1.48 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में लगभग 1.63 करोड़ हो गया है। वर्ष 2014–15 से ओबीसी छात्र नामांकन में 45.1% की वृद्धि हुई है। ओबीसी महिला छात्रों का नामांकन वर्ष 2020–21 में 72.88 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 78.19 लाख हो गया है। वर्ष 2014–15 से ओबीसी महिला छात्र नामांकन में कुल वृद्धि 49.3% है।

- **अल्पसंख्यक नामांकन:** अल्पसंख्यक नामांकन वर्ष 2014–15 में 21.8 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 30.1 लाख हो गया है (38% की वृद्धि)। वर्ष 2014–15 से महिला अल्पसंख्यक नामांकन में 42.3% की वृद्धि हुई है (2014–15 में 10.7 लाख से बढ़कर 2021–22 में 15.2 लाख।)

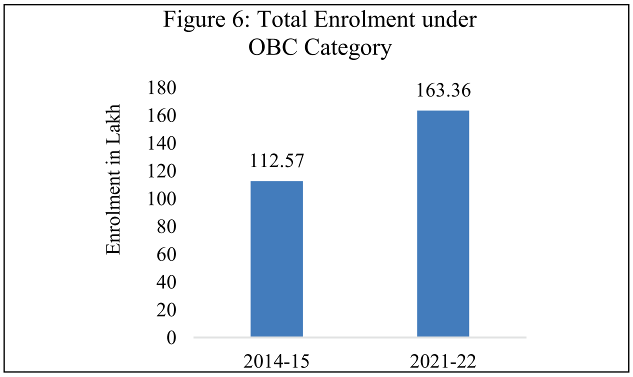

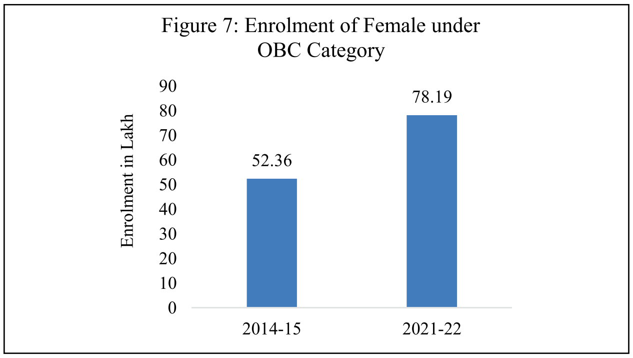

- **पूर्वोत्तर नामांकन:** पूर्वोत्तर राज्यों में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2014–15 में 9.36 लाख की तुलना में वर्ष 2021–22 में 12.02 लाख है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2021–22 में महिला नामांकन 6.07 लाख है, जो पुरुष नामांकन 5.95 लाख से अधिक है।

- **विदेशी नामांकन:** उच्चतर शिक्षा में नामांकित विदेशी छात्रों की कुल संख्या 46,878 है। विदेशी छात्र 170 विभिन्न देशों से आए हैं। वर्ष 2021–22 में, विदेशी छात्रों की सबसे अधिक हिस्सेदारी नेपाल (28%) से है, इसके बाद अफगानिस्तान (6.7%), संयुक्त राज्य अमेरिका (6.2%), बांग्लादेश (5.6%), संयुक्त अरब अमीरात (4.9%), और भूटान (3.3%) हैं। शीर्ष 10 देशों से कुल 64.7% विदेशी छात्रों हैं।

स्तर–वार छात्र नामांकन: विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग/संघटक और संबद्ध कॉलेज – वर्ष 2021–22: एआईएसएचई–2021–22 परिणाम के अनुसार स्नातक छात्रों का नामांकन 78.9%, स्नातकोत्तर छात्रों का 12.1%, अनुसंधान (पीएचडी) 0.5%, डिप्लोमा 6.7%, और

एकीकृत पाठ्यक्रम 1.1% है।

- **पीएच.डी. स्तर में नामांकनः** कुल पीएच.डी. नामांकन वर्ष 2014–15 (1.17 लाख) से वर्ष 2021–22 (2.12 लाख) में 81.1% बढ़ गया है। महिला पीएच.डी. वर्ष 2014–15 (0.48 लाख) से 2021–22 में नामांकन दोगुना (0.99 लाख) हो गया है। पीएच.डी. स्तर पर, वास्तविक प्रतिक्रिया के आधार पर नामांकन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (24.8%) में सबसे अधिक है, इसके बाद विज्ञान (21.3%) है।

अवर स्नातक स्तर पर विषय–वार छात्र नामांकनः 2021–22

- 1.13 करोड़ छात्रों के साथ सबसे अधिक नामांकन कला विषय में है, जिनमें से 51% महिलाएं और 49% पुरुष हैं। विज्ञान विषय में 49.18 लाख छात्र नामांकित हैं (उनमें से 50. 8% महिलाएं हैं और 49.2% पुरुष हैं)। वाणिज्य विषय में 44.08 लाख छात्र नामांकित हैं (उनमें से 47.2% महिलाएं और 52.8% पुरुष छात्र हैं)। इसी तरह, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में 39. 04 लाख नामांकित छात्र हैं, जिनमें से 29.1% महिलाएं और 70.9% पुरुष हैं।

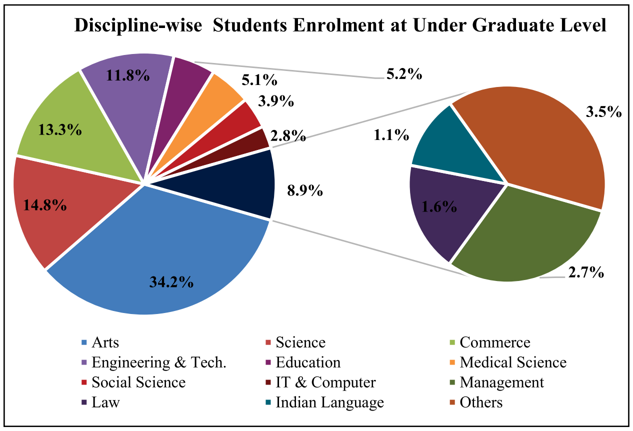

- शिक्षा विषय के तहत, 17.19 लाख छात्रों ने दाखिला लिया, जिनमें से 62.4% महिलाएं और 37.6% पुरुष छात्र हैं।

- चिकित्सा विज्ञान विषय के तहत 17.05 लाख छात्र नामांकित हैं, जिनमें से 57.6% महिलाएं और 42.4% पुरुष छात्र हैं।

- वर्ष 2021–22 के लिए उच्चतर शिक्षा का संकाय–वार नामांकन; कुल नामांकन में से छात्रों के नामांकन का हिस्सा कला संकाय में (34.2%), विज्ञान (14.8%), वाणिज्य (13.3%), इंजीनियरिंग / टेक्नोलॉजी (11.8%), शिक्षा (5.2%), चिकित्सा विज्ञान (5.1%), सामाजिक विज्ञान (3.9%), आईटी और कंप्यूटर (2.8%), प्रबंधन (2.7%), विधि (1.6%), भारतीय भाषा (1.1%) और अन्य (3.5%)।

- **एसटीईएम में नामांकनः** वर्ष 2021–22 में, वास्तविक प्रतिक्रियाओं के आधार पर कुल नामांकन में से, यूजी, पीजी, पीएचडी और एम.फिल. स्तर के लिए एसटीईएम में छात्र नामांकन की संख्या 98,49,488 (25.6%) है। साइंस स्ट्रीम में महिलाएं पुरुषों से आगे हैं।

संस्थानों की संख्याः

इस सर्वेक्षण में एआईएसएचई पोर्टल www.aishe.gov.in. में एआईएसएचई कोड के साथ पंजीकृत देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। संस्थानों को 3 व्यापक श्रेणियों – विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्टैंड–अलोन संस्थान में वर्गीकृत किया गया है।

एआईएसएचई वेब पोर्टल पर 1,168 विश्वविद्यालय, 45,473 कॉलेज और 12,002 स्टैंड अलोन संस्थान सूचीबद्ध हैं और उनमें से 1162 विश्वविद्यालय, 42,825 कॉलेज और 10,576 स्टैंड अलोन संस्थानों ने सर्वेक्षण–2021–22 के दौरान प्रतिक्रिया दी है।

वर्ष 2021–22 के दौरान, 1677 कॉलेजों को एआईएसएचई के साथ पंजीकृत किया गया है। कुल कॉलेजों में से 21.5% सरकारी कॉलेज, 13.2% निजी (सहायता प्राप्त) और 65.3% निजी–गैर सहायता प्राप्त हैं।

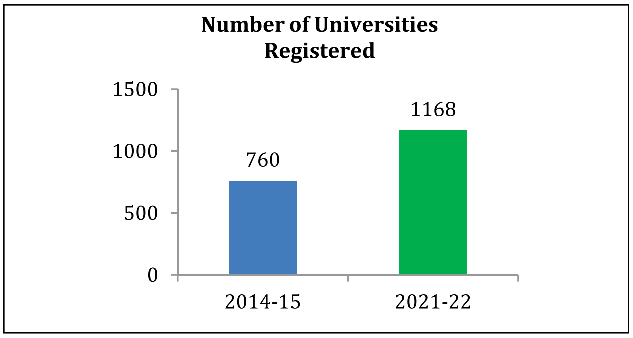

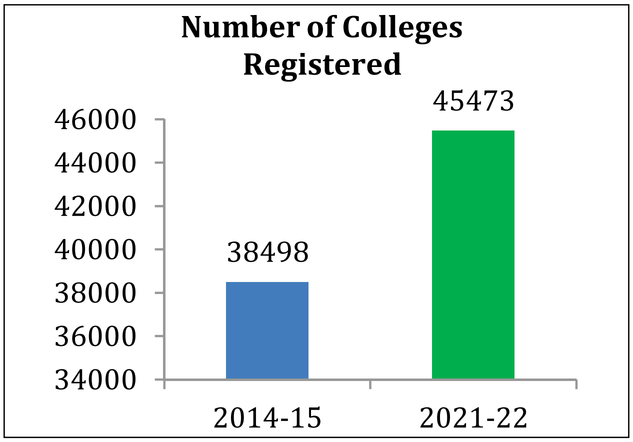

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर):

वर्ष 2021–22 में, 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में अनुमानित सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.4 है, जबकि 2014–15 में यह 23.7 था (2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या अनुमान के अनुसार)। महिला जीईआर वर्ष 2014–15 में 22.9 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 28.5 हो गया है। **वर्ष 2017–18 से लगातार पांच वर्षों से महिला जीईआर पुरुष जीईआर से अधिक बना हुआ है।**

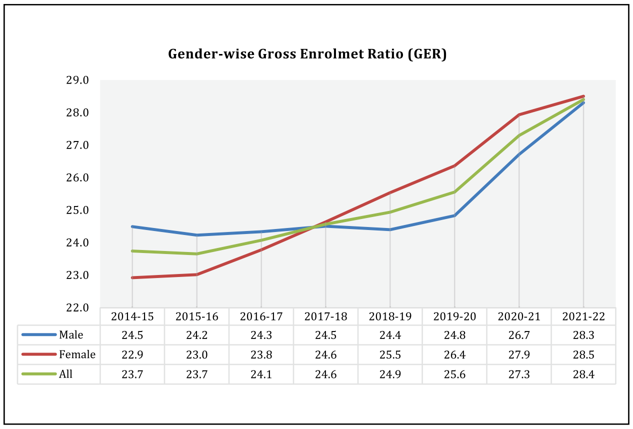

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
Male	24.5	24.2	24.3	24.5	24.4	24.8	26.7	28.3
Female	22.9	23.0	23.8	24.6	25.5	26.4	27.9	28.5
All	23.7	23.7	24.1	24.6	24.9	25.6	27.3	28.4

- **एससी जीईआर:** एससी छात्र जीईआर वर्ष 2014–15 में 18.9 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 25.9 हो गया है। एससी महिला जीईआर वर्ष 2014–15 में 18.1 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 26.0 हो गई है। एआईएसएचई वर्ष 2021–22 के अनुसार महिला एससी जीईआर लगातार चौथे वर्ष पुरुष जीईआर से अधिक बनी हुई है।
- **एसटी जीईआर:** एसटी छात्र जीईआर वर्ष 2014–15 में 13.5 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 21.2 हो गया है। एसटी महिला जीईआर वर्ष 2014–15 में 12.2 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 20.9 हो गया है।

शिक्षण स्टाफ :

शिक्षकों की कुल संख्या 15,97,688 है, जिनमें लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएँ हैं। कुल महिला संकाय/शिक्षकों की संख्या वर्ष 2014–15 में 5.69 लाख से बढ़कर 2021–22 में 6.94 लाख हो गई है (2014–15 से 1.25 लाख की वृद्धि, अर्थात 22%)। वर्ष 2020–21 की तुलना में वर्ष 2021–22 में शिक्षकों की संख्या में 46,618 की वृद्धि हुई है। प्रति 100 पुरुष शिक्षकों पर 77 महिला शिक्षक हैं, जो 2021 में 75 थी।

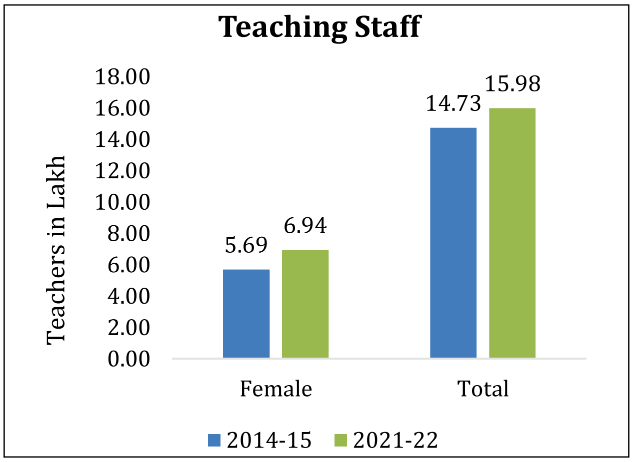

- **छात्र–शिक्षक अनुपात (पीटीआर):** नियमित मोड के लिए, विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र शिक्षक अनुपात (पीटीआर) 24 है जबकि

विश्वविद्यालयों और इसकी घटक इकाइयों के लिए नियमित मोड में पीटीआर 18 है।

- **गैर–शिक्षण कर्मचारी:** गैर–शिक्षण कर्मचारियों की संख्या 12,08,466 है, जिनमें से लगभग 56.3% पुरुष और 43.6% महिलाएं हैं। प्रति 100 पुरुष गैर–शिक्षण कर्मचारियों में महिलाओं की औसत संख्या 78 है।

आउट टर्न/पास आउट:

वर्ष 2020–21 में 95.4 लाख की तुलना में 2021–22 में पास–आउट की कुल संख्या बढ़कर 1.07 करोड़ हो गई है। अवर स्नातक स्तर पर, सबसे अधिक आउट–टर्न बैचलर ऑफ आर्ट्स (बी.ए.) में 24.16 लाख है, इसके बाद बैचलर ऑफ साइंस (बी.एससी.) में 12.53 लाख, बैचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) में 11.08 लाख है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग (बी.ई.) और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (बी.टेक.) में संयुक्त रूप से 8.47 लाख है।

स्नातकोत्तर स्तर पर, सबसे अधिक आउट–टर्न मास्टर ऑफ आर्ट्स (एम.ए.) में 7.02 लाख है, इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस (एम.एससी.) में 3.56 लाख, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (एमबीए) में 2.32 लाख और मास्टर ऑफ कॉमर्स (एम.कॉम.) में 1.9 लाख है।

डिप्लोमा में, कुल पासआउट्स की संख्या 9.2 लाख है। वर्ष 2021–22 के दौरान, 32,588 छात्रों को पीएच.डी. से सम्मानित किया गया जिसमें 18,464 पुरुष और 14,124 महिलाएं थीं। सबसे अधिक पीएच.डी. विज्ञान में 7,408 और उसके बाद इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी में 6,270 प्रदान की गईं।

❖ ❖ ❖

04

नियामक और सलाहकार निकाय

नियामक और सलाहकार निकाय

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रचार और समन्वय के लिए और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा और अनुसंधान के मानकों के निर्धारण और रखरखाव के लिए 1956 में संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित एक सांविधिक निकाय है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किये गये विनियामक सुधार:

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए, यूजीसी को यूजीसी, अधिनियम, 1956 की धारा 26 के प्रावधानों के तहत विनियम बनाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। निम्नलिखित नियमों को 2023 के दौरान अधिसूचित किया गया है:

1. यूजीसी (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023
2. यूजीसी (कॉलेजों को स्वायत्त दर्जा प्रदान करना और स्वायत्त कॉलेजों में मानकों के रखरखाव के लिए उपाय) विनियम, 2023
3. यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023
4. यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023
5. यूजीसी (विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2023
6. यूजीसी (भारत में विदेशी उच्च शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2023

उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता

यूजीसी प्रत्येक पात्र विश्वविद्यालय को उनके समग्र विकास के लिए सहायता करता है, जिसमें विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है जैसे पहुंच बढ़ाना, इक्विटी सुनिश्चित करना, प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करना, गुणवत्ता और उत्कृष्टता में सुधार करना, विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना, अधिक संकाय सुधार कार्यक्रम प्रदान करना, छात्रों के लिए सुविधाओं को बढ़ाना, विश्वविद्यालयों की अनुसंधान सुविधाएं बढ़ाना और अन्य योजनाएं। वर्ष 2023–24 के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालयों/कॉलेजों, समविश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/आईयूसी/छात्रवृत्ति और अध्योतावृत्ति और प्रशासनिक व्यय के लिए ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रमशः ₹ 11337.63 करोड़, ₹ 500 करोड़ और ₹ 5360 करोड़ का अनुदान आवंटित किया गया है।

राष्ट्रीय शैक्षिक परीक्षण:

मानविकी के कई विषयों (भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं सहित), योग, सामाजिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और अनुप्रयोग, इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान, फोरेंसिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में शिक्षण व्यवसाय और अनुसंधान में प्रवेश लेने वालों के लिए न्यूनतम मानक सुनिश्चित करने के लिए सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) के लिए

पात्रता निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (यूजीसी–नेट) आयोजित की जाती है। यह परीक्षा देश भर में कई शहरों में प्रतिवर्ष दो बार आम तौर पर जून और दिसंबर माह में 83 विषयों में आयोजित की जाती है। इसके साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) बुनियादी विज्ञान के अंतर्गत आने वाले विषयों के लिए जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए पात्रता हेतु संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी टेस्ट भी आयोजित करती है। इसके साथ ही, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) पांच मुख्य विज्ञान विषयों, जैसे, रसायन विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान; प्राणि विज्ञान; गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान में लेक्चरशिप के लिए जेआरएफ और पात्रता के लिए संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी परीक्षा आयोजित करता है। अध्येतावृत्ति की अवधि अधिकतम पांच वर्षों के लिए उपलब्ध है। सीएसआईआर के तत्वावधान में पांच प्रमुख विज्ञान विषयों, अर्थात् रासायनिक विज्ञान; पृथ्वी, वायुमंडलीय, महासागर और ग्रह विज्ञान; जीवन विज्ञान; गणितीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान में जून और दिसंबर के महीनों में संयुक्त सीएसआईआर–यूजीसी परीक्षा आयोजित की जाती है। जून 2023 में 37,267 उम्मीदवारों ने यूजीसी–नेट उत्तीर्ण किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने दिसंबर 2023 यूजीसी–नेट का आयोजन दिनांक 06.12.2023 से 22.12.2023 तक किया है।

राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ)–

दिनांक 10.04.2023 को अधिसूचित राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) अधिगम परिणामों को मापने और क्रेडिट देने के लिए एक मानकीकृत और पारदर्शी प्रणाली प्रदान करता है। यह शैक्षणिक, व्यावसायिक और अनुभवात्मक शिक्षा जैसे विभिन्न आयामों से अधिगम के श्रेय के बुनियादी सिद्धांतों को निर्धारित करता है। सभी उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) अपने संस्थानों में एनसीआरएफ फ्रेमवर्क को लागू करेंगे।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का एक मुख्य आकर्षण अधिगम परिणामों के संदर्भ में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने वाली उच्च शिक्षा का वर्णन करने के लिए राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क का निर्माण करना है। यूजीसी ने सभी स्तरों पर उच्चतर शिक्षा योग्यताओं में पारदर्शिता और तुलनीयता की सुविधा के लिए "राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क (एनएचईक्यूएफ)" तैयार किया है। तदनुसार, यूजीसी ने दिनांक 11.05.2023 को एनएचईक्यूएफ को अधिसूचित किया है और सभी एचईआई से इसे लागू करने का अनुरोध किया गया है।

ई–समाधान

सभी हितधारकों के लिए अपनी शिकायतें दर्ज करने हेतु यूजीसी ई–समाधान पोर्टल, एक एकल खिड़की प्रणाली, 5 सितंबर, 2022 को शुरू की गई थी। यह मंच शिकायतों के निवारण के लिए एक समयबद्ध तंत्र सुनिश्चित करता है। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक कुल 23,234 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 8146 शिकायतें समाप्त कर दी गईं, 8403 शिकायतें संबंधित एचईआई को स्थानांतरित कर दी गईं। शेष शिकायतें प्रक्रियाधीन हैं।

यूजीसी की छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप योजनाएँ कार्यक्रम

I. विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ): विद्वानों को एम. फिल/पीएचडी करने के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करना। भाषाओं सहित विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में डिग्री के लिए, यूजीसी उन उम्मीदवारों को जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करता है जो यूजीसी की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) और राष्ट्रीय

परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित यूजीसी – सीएसआईआर संयुक्त परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। जेआरएफ के तहत प्रति वर्ष 9400 स्लॉट हैं। वर्तमान में 34,416 (लगभग) लाभार्थी एम.फिल/पीएचडी कर रहे हैं। जेआरएफ के तहत यूजीसी सीधे लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से भुगतान करता है। वर्ष 2023 के दौरान विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में जेआरएफ के तहत ₹ 1375.32 करोड़ का व्यय किया गया है।

II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः समाज के वंचित वर्गों के उम्मीदवारों की सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, उन्हें व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई करने का अवसर प्रदान करने हेतु यह योजना लागू की जा रही है। प्रति वर्ष स्लॉट की संख्या 1000 होती है। यह योजना वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल है। वर्ष 2023 के दौरान 1,727 लाभार्थियों को ₹ 13.47 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

III. विश्वविद्यालय रैंक धारकों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तिः यह छात्रवृत्ति प्रतिभा को बढ़ावा देने और उसका पोषण करने तथा स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए स्नातक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करने के व्यापक उद्देश्य के साथ शुरू की गई थी। इस छात्रवृत्ति के लिए अवर स्नातक स्तर पर पहली और दूसरी रैंक धारक और किसी भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले पात्र हैं। प्रत्येक वर्ष 3000 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्रावधान है। यह योजना वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल है। वर्ष 2023 के दौरान 2257 लाभार्थियों को ₹ 8.59 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

IV. गैट/जीपैट उत्तीर्ण छात्रों के लिए एम.ई/एम. टेक/एम–फार्मा हेतु पोस्ट ग्रेजुएट छात्रवृत्तिः इस योजना का उद्देश्य एचईआई में पोस्ट ग्रेजुएट स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए युवा प्रतिभाशाली स्नातक छात्रों की मदद करना और उनको आकर्षित करना है। भारत में विश्वविद्यालयों/संस्थानों/कॉलेजों में पूर्णकालिक/नियमित माध्यम से एम.ई./एम. टेक/एम.फ़ार्मा करने के लिए गैट/जीपैट योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह छात्रवृत्ति वर्ष 2016–17 में शुरू की गई थी। वर्ष 2023 के दौरान 1214 लाभार्थियों को ₹10.64 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

V. पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 'ईशान उदय' विशेष छात्रवृत्ति योजनाः मंत्रालय और यूजीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली है। जीईआर में सुधार करने, उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह योजना शैक्षणिक सत्र 2014–15 से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 10,000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। यह योजना वर्ष 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान 13,201 लाभार्थियों को ₹ 109.84 करोड़ की राशि वितरित की गई है।

VI. फैकल्टी रिचार्ज प्रोग्राम (एफआरपी): फैकल्टी रिचार्ज वर्ष 2011 में शुरू किया गया था, जिसके तहत विज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के स्तर पर विभिन्न संकाय पदों को भरने के लिए बनाया गया था। वर्ष 2023 के दौरान, 149 संकायों को कुल ₹ 51.00 करोड़ वितरित किए गए हैं।

VII. डॉ. डी.एस. कोठारी पोस्ट–डॉक्टरल फ़ेलोशिपः इस योजना के तहत अनुसंधान अध्येताओं को बुनियादी विज्ञान/चिकित्सा / इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में पोस्ट–डॉक्टरल अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चयन के लिए दिनांक 28.01.2021 तक प्राप्त आवेदनों पर विचार किया गया और उसका परिणाम सितंबर 2021 में घोषित किया गया और उसके बाद, इस योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया। वर्ष 2023 के दौरान 359 पीडीएफ को 21.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

VIII. नवनियुक्त संकाय के लिए स्टार्ट–अप अनुदानः सभी शिक्षक जो बुनियादी विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संकायों में स्थायी पद के लिए सहायक प्रोफेसर के स्तर पर नव नियुक्त हैं, इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। चयन पूरे वर्ष भर किया जाता है। इस योजना का कार्यकाल 2 वर्ष है जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत 10.00 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक प्राप्त आवेदनों पर चयन के लिए विचार किया गया और परिणाम सितंबर 2021 में घोषित किया गया और उसके बाद, योजना के तहत कोई नया चयन नहीं किया गया। वर्ष 2023 के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के लिए 90 संकाय सदस्यों को ₹ 4.86 करोड़ की राशि जारी की गई।

अल्पसंख्यकों/एससी/एसटी और महिलाओं के लिए आवासीय कोचिंग अकादमी

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का उद्देश्य अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित छात्रों और महिलाओं को केंद्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों और आईआईटी/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए छात्रावास सुविधाओं के साथ निःशुल्क/नाममात्र शुल्क, बिना ट्यूशन शुल्क कोचिंग प्रदान करके समाज के सभी वर्गों को समान विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है। यह योजना चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों नामतःजामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में चलाई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान 115.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र (आईयूसी)

यूजीसी ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (सीसीसी) के तहत 1984 से आठ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर (आईयूसी) स्थापित किए हैं। आईयूसी विश्वविद्यालय प्रणाली के भीतर स्वायत्त निकाय हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शोधकर्ताओं के लाभ के लिए सुविधाएं, जो आम तौर पर लागत कारकों के कारण कई विश्वविद्यालयों में उपलब्ध नहीं हैं, को केंद्रीय रूप से अत्याधुनिक उपकरण प्रदान करना है।

पीठों की स्थापना

यूजीसी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चिंतन के लिए विश्वविद्यालय प्रणाली के शैक्षणिक संसाधनों को समृद्ध करने हेतु, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों जो या तो भारतीय नागरिक रहे हैं या भारतीय मूल के हैं, के नाम पर पीठों की योजना तैयार की है। इस योजना के तहत 13 विश्वविद्यालयों को 2.67 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है। यूजीसी ने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कोरापुट में संत कवि भीमा भोई पीठ की स्थापना की है।

राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

यूजीसी राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)

के तहत तीन योजनाएं नामतः राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के तहत सामुदायिक कॉलेज, बी.वॉक डिग्री कार्यक्रम, और कुशल मानव क्षमताओं और आजीविका के ज्ञान अधिग्रहण और उन्नयन के लिए दीन दयाल उपाध्याय केंद्र (डीडीयू कौशल केंद्र) का भी कार्यान्वयन कर रहा है। । वर्ष 2023–24 (31.12.2023 तक) के दौरान सामुदायिक कॉलेजों, बी.वॉक डिग्री कार्यक्रम और डीडीयू कौशल केंद्रों की योजनाओं पर क्रमशः ₹ 5.85 करोड़, ₹ 8.52 करोड़ और ₹ 3.04 करोड़ का व्यय किया गया।

अनुसंधान कार्मिकों के लिए परिलब्धियों और दिशानिर्देशों में संशोधनः

शिक्षा मंत्रालय ने देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय और इसकी एजेंसियों और संस्थानों के अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम में लगे अनुसंधान कर्मियों के लिए परिलब्धियों में वृद्धि की है। बढ़ी हुई परिलब्धियाँ 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होंगी। जेआरएफ और एसआरएफ की मासिक परिलब्धियाँ क्रमशः 31,000/– से 37,000/– और 35,000/– से 42,000/–रुपये कर दी गई हैं। इसके अलावा, रिसर्च एसोसिएट–I, रिसर्च एसोसिएट–II और रिसर्च एसोसिएट–III की मासिक परिलब्धियां भी क्रमशः 47,000/– से 58,000/– ₹ 49,000/– से 61,000/– और 54,000/– से ₹ 67,000/– कर दी गई हैं।

एचईआई के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करना

डॉ. के. राधाकृष्णन, अध्यक्ष बीओजी, आईआईटी कानपुर और अध्यक्ष, आईआईटी परिषद की स्थायी समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति की मसौदा रिपोर्ट 19 मई 2023 से 22 जून 2023 तक सार्वजनिक डोमेन में रखी गई थी; बाद में इसे 15 जुलाई 2023 तक और फिर 8 अगस्त 2023 से 15 अगस्त 2023 तक बढ़ा दिया गया। इसके अलावा, हितधारक परामर्श के एक भाग के रूप में, एचईआई के मूल्यांकन, प्रत्यायन और रैंकिंग में सुधार पर एक ऑनलाइन परामर्श कार्यशाला भी 7 जुलाई 2023 को आयोजित की गई थी। इस मसौदा रिपोर्ट पर हितधारकों की विभिन्न श्रेणियों से प्राप्त लगभग 1450 फीडबैक पर विचार करने के बाद, समिति ने 'भारत में सभी एचईआई के आवधिक मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' पर अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप कार्यनीतिक सुधारों की शुरूआत और एक सत्यापन योग्य और सुरक्षित केंद्रीकृत डेटाबेस के साथ एचईआई की मान्यता और प्रौद्योगिकी–संचालित प्रणालियों के माध्यम से रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास–आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया है। इस समिति द्वारा हितधारकों के लिए व्यवसाय करने में आसानी की सुविधा प्रदान करने, संस्थानों/कार्यक्रमों के चयन के लिए अधिक सूचित विकल्प चुनने में छात्रों को उचित सुविधा प्रदान करने की पद्धतियों पर भी विचार किया गया है। ये सिफ़ारिशें एचईआई की भागीदारी के साथ–साथ मान्यता स्तर को प्रतिष्ठा, महत्व और वैश्विक प्रशंसा की ओर बढ़ाने की योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करती हैं।

डॉ. राधाकृष्णन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट https://www.education@gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/reforms@moe.pdf पर उपलब्ध है।

रैगिंग रोधी प्रकोष्ठ

यूजीसी ने रैगिंग की बुराइयों पर ध्यान केंद्रित करने, रैगिंग में लिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने और परिषद/नियामक निकायों आदि के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित एंटी रैगिंग मॉनिटरिंग कमेटी की एक बैठक आयोजित की। यूजीसी रैगिंग विरोधी

उपायों के कार्यान्वयन के उपायों पर चर्चा करने के लिए एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, आईएनसी और बीसीआई आदि जैसी वैधानिक पेशेवर परिषदों के साथ नियमित रूप से इंटर काउंसिल बैठकें भी आयोजित करता है। यूजीसी ने एंटी रैगिंग रोकथाम कार्यक्रम के लिए एक निगरानी एजेंसी भी नियुक्त की है जो समय–समय पर एचईआई की गैर–अनुपालन रिपोर्ट यूजीसी को प्रस्तुत करती है।

यूजीसी ने 12 अगस्त को एंटी रैगिंग दिवस और उसके बाद 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग सप्ताह मनाने का भी निर्णय लिया है। इस संबंध में, यूजीसी ने दिनांक 05.07.2023 को सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न रैगिंग विरोधी गतिविधियों जैसे कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रतियोगिताओं आदि का आयोजन/संचालन करने के लिए एक एडवाइज़री जारी की है। यूजीसी ने एफएम रेडियो, प्रसार भारती, दूरदर्शन, डिजिटल सिनेमा, लोकसभा टेलीविजन, पेटीएम और शेयरचैट द्वारा पूरे देश में मीडिया अभियान भी शुरू किया है। इस अभियान के तहत टीवीसी, शॉर्टफिल्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्में विकसित करना, पोस्टर बनाना, लोगो, स्लोगन फिल्म निर्माण प्रतियोगिता, विजेताओं को पुरस्कार समारोह आदि जैसी गतिविधियां शुरू की गईं।

यूजीसी उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए यूजीसी विनियमों के सख्त अनुपालन के संबंध में वर्ष में दो बार एक परिपत्र जारी करता है, जो यूजीसी की वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक www.ugc.gov.in पर उपलब्ध हैं।

दिनांक 01.01.2023 से 21.12.2023 तक दर्ज रैगिंग शिकायतों का विवरणः–

प्राप्त शिकायतें	समाप्त शिकायतें	सक्रिय शिकायतें
944	794	150

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) की स्थापना नवंबर 1945 में राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी, जो तकनीकी शिक्षा संबंधी सुविधाओं पर सर्वेक्षण करने और समन्वित और एकीकृत तरीके से देश में विकास को बढ़ावा देने के लिए थी। वैधानिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 12 मई 1988 को देश भर में तकनीकी शिक्षा प्रणाली की उचित योजना और समन्वित विकास, नियोजित मात्रात्मक विकास के संबंध में ऐसी शिक्षा के गुणात्मक सुधार को बढ़ावा देने और तकनीकी शिक्षा प्रणाली में मानदंडों और मानकों के विनियमन और उचित रखरखाव और उससे जुड़े मामलों के लिए की गई थी। एआईसीटीई के दायरे में विभिन्न स्तरों पर इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर और देश आयोजना, प्रबंधन, फार्मेसी, अनुप्रयुक्त कला और शिल्प और डिजाइन, होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी आदि में प्रशिक्षण और अनुसंधान सहित तकनीकी शिक्षा के कार्यक्रम शामिल हैं।

अनुमोदन स्थिति

एआईसीटीई ने ई–गवर्नेंस के माध्यम से अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही शुरू करके वार्षिक अनुमोदन प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए कई पहलें की हैं और सभी हितधारकों के साथ अनौपचारिक और औपचारिक बातचीत के माध्यम से अनुमोदन प्रक्रिया में अधिक आसानी के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया है। यह परिषद नए तकनीकी संस्थानों को शुरू करने और पहले से अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में नए पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान करती है। संबंधित राज्य सरकारों और संबद्ध विश्वविद्यालयों के परामर्श से अनुमोदन प्रदान किए जाते हैं। अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक 2024–27 प्रकाशित की गई थी और संस्थानों को निम्नानुसार तकनीकी कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वीकृति दी गईः

कार्यक्रम	डिप्लोमा	पीजी	यूजी
	संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या	संस्थानों की संख्या
अनुप्रयुक्त कला एवं शिल्प	67	8	35
वास्तुकला और योजना	-	19	6
डिज़ाइन	2	9	46
इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी	3,593	1,773	2,886
होटल प्रबंधन एवं खानपान	28	5	93
प्रबंध	19	3,228	-
एमसीए	-	1,254	-
कुल योग	**3,629**	**4,454**	**3,000**

एआईसीटीई की गुणवत्ता पहल

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के अनुरूप, एआईसीटीई ने एक नियामक से एक सुविधाकर्ता और एक सक्षमकर्ता के रूप में बदलने के लिए अपनी भूमिका में सुधार किया है। एआईसीटीई एनईपी 2020 की सिफारिश के अनुसार मौजूदा पाठ्यक्रम मॉडल में सुधार कर रहा है और इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा, अवरस्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए एक परिणाम–आधारित मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया है। कॉर्पोरेट जगत में या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं या विकास क्षेत्र में छात्र इंटर्नशिप को पुनःपरिभाषित और अनिवार्य कर दिया गया है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एजुकेशन को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया है। चुनिंदा गुणवत्ता पहलों की मुख्य विशेषताएं और प्रगति इस प्रकार हैं:

➢ **मॉडल पाठ्यक्रम को नया रूप देना**

- पीएम गति शक्ति अभियान का समर्थन करना, लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में बी.टेक के लिए मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में एम.टेक के लिए मॉडल पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया और शुरू किया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी) में बी.टेक के लिए एक अद्यतन मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
- बी.टेक के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में अद्यतन मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।
- बी.टेक के लिए रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
- इवेंट मैनेजमेंट, मीडिया कम्युनिकेशन, एनीमेशन, गेम डिजाइन, फिल्म और टीवी प्रोडक्शन और डिजिटल मार्केटिंग में डिप्लोमा के लिए मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया।
- प्लंबिंग (जल और स्वच्छता) में वैकल्पिक/लघु पाठ्यक्रम का मॉडल पाठ्यक्रम प्रक्रिया में है।
- औद्योगिक इंजीनियरिंग, कृषि इंजीनियरिंग, धातुकर्म इंजीनियरिंग, खनन इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रुमेंटेशन इंजीनियरिंग और

टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के लिए मॉडल पाठ्यक्रम प्रक्रिया में है।

- योजना में स्नातक डिग्री और योजना में पीजी डिग्री के लिए मॉडल पाठ्यक्रम अद्यतन किया गया।
- इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग (वीएलएसआई डिजाइन और प्रौद्योगिकी) में माइनर डिग्री कोर्स के लिए मॉडल पाठ्यक्रम शुरू किया गया है।

➢ **पॉलिटेक्निक को स्वायत्त दर्जा देने की नीतिः** भारत में तकनीकी और कौशल शिक्षा की रूपरेखा पर एनईपी 2020 दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा गया है किः ''जवाबदेही के साथ स्वायत्तता का मिलानः संस्थानों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के लिए नियामक कामकाज को फिर से सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है। छात्रों की क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर गतिशीलता सुनिश्चित करने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एक रूपरेखा के माध्यम से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के संदर्भ में एकरूपता हासिल की जाए; परिणाम–आधारित शिक्षा प्रणाली (ओबीईएस) को सभी संस्थानों द्वारा अपनाया जाता है। इसके अलावा, एनईपी 2020 पर उसी दस्तावेज़ में; गुणवत्ता विनियमन में सुधार के अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि ''सरकार की भूमिका को आदेश और नियंत्रण से मूल्यांकन और संचालन की भूमिका में बदलकर संस्थागत स्वायत्तता को सक्षम करने की आवश्यकता है''। जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों में उच्च मानक के कार्यक्रम पेश करने की क्षमता है, उन्हें पेश करने की स्वतंत्रता नहीं है। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में छात्रों, शिक्षकों और प्रबंधन के सह–भागीदार होने के साथ, यह जरूरी है कि वे एक बड़ी जिम्मेदारी साझा करें। इसलिए, शिक्षा आयोग (1964–66) ने स्वायत्तता की सिफारिश की, जो संक्षेप में, अकादमिक उत्कृष्टता को बढ़ावा देने का साधन है। एआईसीटीई ने पॉलिटेक्निक संस्थानों को स्वायत्तता देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

➢ **संकाय के संरचित प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के लिए व्यापक दिशानिर्देशः** उच्चतर शिक्षा प्रणाली, संस्थान में, सूचना–ज्ञान–ज्ञान अंतरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक शिक्षकों द्वारा सुगम बनाया जाता है। आम तौर पर शिक्षक अपनी स्नातकोत्तर या शोध डिग्री पूरी करने के तुरंत बाद इस पेशे में शामिल हो जाते हैं और फिर अपने करियर में प्रगति करते हैं। वे नया ज्ञान उत्पन्न करते हैं, युवाओं को कौशल और ज्ञान प्रदान करते हैं, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और संस्थान के प्रशासन के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करते हैं। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कुछ भी गलत न करें क्योंकि वे जो उपदेश देते हैं उसका अभ्यास उन्हें अवश्य करना चाहिए। संकाय भी अपने करियर के दौरान अलग–अलग भूमिका निभाते हैं जो अलग–अलग व्यक्तियों के लिए गतिशील रूप से भिन्न होते हैं। अभी तक, ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं है जो उन्हें शिक्षण पेशे में विभिन्न भूमिकाएँ निभाने के लिए तैयार करता हो। इस दिशा में एक कदम के रूप में, ''उच्च शिक्षा संस्थानों में उनकी उभरती और बहुआयामी भूमिका के लिए संकाय के प्रेरण, संरचित प्रशिक्षण और सलाह'' के लिए मॉड्यूल का सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कैरियर के विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मॉड्यूल का सुझाव दिया।

➢ **एआईसीटीई – अनुमोदित संस्थानों में कामकाजी पेशेवरों के लिए तकनीकी कार्यक्रमों हेतु दिशानिर्देशः** एआईसीटीई ने

एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों में कामकाजी पेशेवरों के लिए तकनीकी शिक्षा की सुविधा के लिए जो स्वयं को उन्नत करना चाहते हैं और डिग्री और कौशल हासिल करने के इच्छुक हैं, को तकनीकी पाठ्यक्रमों में कामकाजी पेशेवरों के प्रवेश के लिए नीति पेश की है। एआईसीटीई–अनुमोदित संस्थान केवल एनबीए मान्यता वाले अनुमोदित विषयों/पाठ्यक्रमों में कार्यरत पेशेवरों के लिए वित्तीय 2023–24 से तकनीकी कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए पात्र हैं।

➢ **एआईसीटीई द्वारा बीसीए, बीबीए और बीएमएस पाठ्यक्रमों को अनुमोदन प्रदान करना:** अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (संक्षेप में, "एआईसीटीई अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार जैसा कि इसके अध्याय 2–जी में उल्लिखित है के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 से प्रबंधन में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों (बीबीए/बीएमएस) और कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) के साथ–साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एमबीए/एमएमएस) और कंप्यूटर एप्लीकेशन (एमसीए) को विनियमित करेगा। तदनुसार, सभी मौजूदा संस्थान या जो प्रबंधन (बीबीए/बीएमएस) और कंप्यूटर एप्लीकेशन (बीसीए) में यूजी पाठ्यक्रम पेश करने का इरादा रखते हैं, उन्हें वित्तीय वर्ष 2024–25 से एआईसीटीई की मंजूरी लेनी होगी। इस परिषद ने इस संबंध में दिशा–निर्देश जारी किए हैं।

संस्थागत, संकाय और छात्र विकास योजनाएँ

एआईसीटीई, देश में तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए दिए गए जनादेश के आधार पर, कई गतिविधियाँ और संचालन योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं में अनुसंधान के वित्तपोषण से लेकर संकाय को विदेश में सम्मेलनों में भाग लेने के लिए यात्रा अनुदान तक शामिल हैं; संस्थानों में बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण से लेकर छात्रावासों के निर्माण तक; और मेधावी से वंचित छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। निम्नलिखित अनुभाग चुनिंदा योजनाओं और उनमें हुई प्रगति का विवरण देते हैं।

➢ **मार्गदर्शन एवं मार्गदर्शक योजना:**

तकनीकी शिक्षा के मानक को उन्नत करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन योजना वर्ष 2016–17 के दौरान शुरू की गई थी। मार्गदर्शन योजना के तहत मान्यता के लिए जाने वाले संस्थानों को खुद को अच्छी तरह से स्थापित संस्थानों के साथ जोड़ने और एनबीए मान्यता प्राप्त करने के लिए चयनित संस्थानों से मार्गदर्शन लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मार्गदर्शन योजना के तहत एक हब–एंड–स्पोक प्रणाली लागू है, जिसमें एक प्रतिष्ठित संस्थान 200 किमी के भीतर दस तकनीकी संस्थानों (स्पोक) को मार्गदर्शन और ज्ञान के प्रसार के लिए मेंटर (हब) के रूप में काम करता है।

संस्थानों को एनबीए से मान्यता प्राप्त करने में मदद करने के लक्ष्य के साथ, मार्गदर्शक योजना वर्ष 2018–19 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत, संस्थानों को मार्गदर्शन देने, अपने पाठ्यक्रमों को मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थानों को मार्गदर्शन और तैयार करने के लिए अनुभवी संकाय की पहचान की जाती है और उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। 50 तकनीकी संस्थानों को मेंटर इंस्टीट्यूट (एमआई) के रूप में नामित किया गया है और 391 वरिष्ठ शिक्षाविदों को 986 मेंटी लाभार्थी संस्थानों (एमबीआई) को सलाह देने के लिए मार्गदर्शक के रूप में लगाया गया है। इस प्रकार, अगले कुछ वर्षों में एनबीए से मान्यता प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हुए, इस योजना के तहत 986 एमबीआई को सुविधा प्रदान की गई है।

➢ रोजगार संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी)

एआईसीटीई ने वर्ष 2013 में रोजगार संवर्धन प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईईटीपी) के नाम से अपनी पूर्ण स्कूल योजना को नया रूप दिया, जिसका उद्देश्य नए इंजीनियरिंग स्नातकों के बीच निरंतर प्रदर्शन करियर की सफलता और बढ़ती उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए व्यवसाय और सॉफ्ट कौशल प्रदान करने के लिए रोजगार बढ़ाना है। कौशल पहल के तहत रोजगार के अवसरों के कार्यान्वयन और वृद्धि के लिए, परिषद ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के एआईसीटीई अनुमोदित कॉलेजों के छात्रों को अत्याधुनिक आईटी/आईटीईएस और दूरसंचार कौशल प्रदान करने की आवश्यकता का समाधान करने के लिए तकनीकी संस्थानों को सुविधा प्रदान करने हेतु आईसीटी अकादमी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निर्धारण वर्ष 2017–18 और 2018–19 के लिए आईसीटी अकादमी द्वारा प्रदान किए गए प्रशिक्षण का विवरण इस प्रकार है:

शैक्षणिक वर्ष	नामांकित छात्र	प्रशिक्षण पूरा करने वाले छात्र	नैस्कॉम द्वारा मूल्यांकित छात्र	नियोजित छात्रों की संख्या
2017-18	5247	4006	277	शून्य
2018-19	6557	2422	242	55

➢ गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी)

डिग्री–स्तरीय तकनीकी संस्थानों के संकाय सदस्यों के उन्नयन, योग्यता और क्षमताओं के उद्देश्य से, भारत सरकार ने वर्ष 1970 में गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) शुरू किया, जिसे अब परिषद द्वारा कार्यान्वित और मानीटर किया जा रहा है। इस योजना के तहत, एआईसीटीई–अनुमोदित संस्थानों के संकाय सदस्यों को अपनी योग्यता बढ़ाने का अवसर दिया जाता है। वर्ष 2023 के दौरान, एआईसीटीई ने 31 दिसंबर 2023 तक स्नातकोत्तर और पीएचडी शोधकर्ताओं को छात्रवृत्ति पर लगभग 12.95 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

क्र. सं.	बैच वर्ष	पीएच.डी.	एम.टेक. / एम.ई.
1	2019-20	167	शून्य
2	2020-21	159	11
3	2021-22	180	25
4	2022-23	177	22
5	2023-24	113	शून्य
	कुल	**796**	**58**

➢ एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (एटीएएल) अकादमियां

तकनीकी शिक्षा में अकादमिक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के अपने प्रयास में एआईसीटीई ने कई गुणवत्तापूर्ण पहलें की हैं, जिसमें देश भर के कॉलेजों में पढ़ाने वाले संकाय के विकास पर प्रोत्साहन भी शामिल है। एआईसीटीई प्रशिक्षण और शिक्षण (एटीएएल) अकादमी एक ऐसी पहल है जो आईओटी, एमएल, एआई, रोबोटिक्स, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, नवीकरणीय ऊर्जा, एआर/वीआर और कई अन्य उभरते क्षेत्र आदि जैसे उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संकाय ज्ञान प्रदान करने/उन्नत करने के लिए विभिन्न संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) आयोजित कर रही है। अनुभवात्मक शिक्षा, व्यावहारिक और ऑफलाइन

एफडीपी के लिए जयपुर (राजस्थान), बेंगलुरु (कर्नाटक), गुवाहाटी (असम), और मुरथल (हरियाणा) में चार अटल अकादमियां स्थापित की गई हैं।

वर्ष 2022–23 से, अटल एफडीपी को फिर से डिजाइन किया गया है, जो नवोन्मेषी और हाइब्रिड एफडीपी/सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (सीपीडीपी) उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों, महत्वपूर्ण सोच, समस्या–समाधान, टीम निर्माण और परियोजना प्रबंधन आदि में ज्ञान के अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एफडीपी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम (सीएएस) के लिए स्वीकार्य के रूप में दो सप्ताह (1 सप्ताह ऑफ़लाइन और 1 सप्ताह ऑनलाइन) के लिए मिश्रित/हाइब्रिड मोड में आयोजित किए गए।

वर्ष 2022–23 के अटल एफडीपी/सीपीडीपी

क्र. सं.	एफडीपी/ सीपीडीपी का प्रकार	आवंटित संख्या	पूर्ण की गई एफडीपी/ सीपीडीपी
1	अटल एफडीपी	200	194
2	भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस)	20	18
3	पीएम गति शक्ति एफडीपी	43	20

वर्ष 2023–24 से, अटल एफडीपी को डिजाइन किया गया है, जो फेस टू फेस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को वापस लाने के साथ अभिनव है, जो एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों के समन्वयकों द्वारा आयोजित किया जाता है, जो उभरते महत्वपूर्ण क्षेत्रों, महत्वपूर्ण सोच, समस्या समाधान, टीम निर्माण और परियोजना प्रबंधन, आदि में व्यावहारिक सत्र के साथ आवेदन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये एफडीपी कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) के लिए स्वीकार्य 1 सप्ताह के लिए ऑफ़लाइन मोड में आयोजित किए जाते हैं।

वर्ष 2023–24 के अटल एफडीपी/ सीपीडीपी (26.03.2024 तक)

क्र. सं.	एफडीपी/ सीपीडीपी का प्रकार	आवंटित संख्या	पूर्ण की गई एफडीपी/ सीपीडीपी
1	अटल एफडीपी	450	381

➢ **राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल**

एआईसीटीई राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल एक गतिशील बाज़ार के रूप में कार्य करता है, जो देश भर में 1.88 करोड़ से अधिक छात्रों को मूल्यवान, उद्योग से जुड़े, भुगतान किए गए इंटर्नशिप अवसरों से जोड़ता है। ये इंटर्नशिप पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर की जा सकती है, छात्रों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक अनुभव और इंटर्नशिप पूरा होने का प्रमाण पत्र मिलता है।

यह व्यापक पोर्टल वन–स्टॉप समाधान के रूप में कार्य करता है, जो न केवल एमओएचयूए, एनएचएआई, रेलवे, एमओएसजेई जैसे सरकारी क्षेत्र में, बल्कि एमएसएमई, कॉर्पोरेट क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों, स्टार्ट–अप और अनुसंधान संगठनों में भी इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विविध प्रकार के अवसर प्रदान करना और यह सुनिश्चित करना कि विभिन्न पृष्ठभूमि और विषयों के छात्र सार्थक इंटर्नशिप तक पहुंच सकें।

➢ **एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना**

o **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभों के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:** भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को

सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई दिशानिर्देशों के अनुसार जीएटीई/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और एआईसीटीई अनुमोदित संस्थान/कार्यक्रम और एम.ई./एम.टेक./एम. आर्क./एम. देस में प्रवेश पाने वाले छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 24 महीने के लिए 12400/– रुपये प्रति माह की दर से स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

o **प्रारंभ तिथि:** 1987 से

o **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:** पीजी छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश के समय वैध जीएटीई/सीईईडी स्कोर है।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	**सभी के लिए**		**एससी**		**एसटी**		**कुल संख्या**	**कुल राशि का योग**
एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना	**संख्या**	**कुल राशि**	**संख्या**	**कुल राशि**	**संख्या**	**कुल राशि**		
गैर–एनईआर	8466	104977574	1401	17371987	340	4216000	10207	126565561
एनईआर	77	954800	15	186000	87	1078800	179	2219600
कुल योग	**8543**	**105932374**	**1416**	**17557987**	**427**	**5294800**	**10386**	**128785161**

➢ **एआईसीटीई डॉक्टोरल फ़ेलोशिप (एडीएफ)**

o **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभों के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:** संस्थान और स्टार्ट–अप वाले उद्योगों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देकर इंजीनियरिंग/प्रबंधन/डिजाइन में तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभा का पोषण करके एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/विभागों/संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र विद्वानों को फेलोशिप दी जाएगी।

o **परिलब्धियाँ और भत्ते:** चयनित शोध विद्वानों को पहले दो वर्षों के लिए 37,000 रुपये प्रति माह और उसके बाद 42,000 रुपये प्रति माह की फ़ेलोशिप और केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) मिलता है। इसके अलावा, आकस्मिक अनुदान के रूप में 15,000 रुपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाती है।

o **प्रारंभ तिथि:** 2018–19

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	सभी के लिए		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
एआईसीटीई डॉक्टोरल फ़ेलोशिप (एडीएफ)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	365	155970549	86	36691445	18	6514596	469	199176590
एनईआर	32	13081942	7	3234880	5	1696657	44	18013479
कुल योग	**397**	**169052491**	**93**	**39926325**	**23**	**8211253**	**513**	**217190069**

- **दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना**
  - o **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:** एआईसीटीई दिव्यांग न्यूनतम 40% छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रति वर्ष 50,000/– रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
  - o **प्रारंभ तिथि:** 2014–15
  - o **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से देश भर के एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	सभी के लिए		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	207	10016399	10	500000	4	200000	221	10716399
एनईआर	10	500000	0	0	0	0	10	500000
कुल योग	**217**	**10516399**	**10**	**500000**	**4**	**200000**	**231**	**11216399**

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	सभी के लिए		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	997	49850000	207	10350000	41	2050000	1245	62250000
एनईआर	9	450000	0	0	0	0	9	450000
कुल योग	**1006**	**50300000**	**207**	**10350000**	**41**	**2050000**	**1254**	**62700000**

➢ एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना

- o **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:** एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस योजना में अनाथ बच्चों, बच्चे जिनके माता–पिता की कोविड–19 के कारण मृत्यु हो गई, ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बच्चों (शहीद) को शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने हेतु 50,000/– रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है।
- o **आरंभ तिथि:** वर्ष 2021–22
- o **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से देश भर के एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	सभी के लिए		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
एआईसीटीई स्वानाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	527	26850000	32	1650000	8	400000	571	28900000
एनईआर	2	100000	0	0	1	50000	3	150000
कुल योग	**529**	**26950000**	**32**	**1650000**	**9**	**450000**	**574**	**29050000**

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकृत)								
योजना का नाम	सभी के लिए		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–पूर्वोत्तर	248	12400000	28	1400000	18	900000	294	14700000
पूर्वोत्तर	2	100000	0	0	0	0	2	100000
महायोग	**250**	**12500000**	**28**	**1400000**	**18**	**900000**	**296**	**14800000**

➢ निवारण (एमओडीआरओबी) योजना का आधुनिकीकरण तथा समापन

इस योजना का उद्देश्य एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं, प्रयोगशालाओं, कार्यशालाओं और कंप्यूटिंग सुविधाओं का उन्नयन करना है। वित्त पोषण की सीमा 20 लाख रुपये है और परियोजना की अवधि 2 वर्ष है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अवसंरचना के समय पर उन्नयन में सहायता करके शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों के लिए तकनीकी संस्थाओं की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि करने के लिए इस योजना का प्रचालन कर रही है।

वर्ष 2022–23 के दौरान एमओडीआरओबी योजना के तहत दिए गए अनुदान का राज्यवार वितरण

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	53.76
2	अरुणाचल प्रदेश	6.96
3	छत्तीसगढ़	2.52
4	दादरा और नगर हवेली	3.12
5	दिल्ली	2.48
6	गुजरात	21.19
7	कर्नाटक	69.20
8	केरल	14.26
9	मध्य प्रदेश	17.59
10	महाराष्ट्र	84.64
11	नागालैंड	13.96
12	ओडिशा	60.99
13	राजस्थान	4.19
14	तमिलनाडु	107.80
15	तेलंगाना	81.34
16	त्रिपुरा	13.53
17	उत्तर प्रदेश	14.98
18	उत्तराखंड	8.52
19	पश्चिम बंगाल	5.00
	कुल	**586.02**

योजना का एक रूप, एमओडीआरओबी–ग्रामीण वंचित ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित संस्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा उन्हें नियमित एमओडीआरओबी योजना में प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए शुरुआत की गई थी। सरकार/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान और विश्वविद्यालय विभाग अधिकतम 5 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि स्व–वित्तपोषित 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान एमओडीआरओबी–ग्रामीण योजना के तहत दिए गए अनुदान का राज्यवार वितरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	जारी की गई राशि
1	आंध्र प्रदेश	4.63
2	हरियाणा	2.63
3	गुजरात	1.60
4	महाराष्ट्र	13.15
5	तमिलनाडु	7.90
6	तेलंगाना	1.74
	कुल	**31.67**

- **एआईसीटीई आइडिया लैब योजना**

  एआईसीटीई आइडिया लैब योजना विचार विकास, मूल्यांकन और इसके अनुप्रयोग के लिए है। यह भारत में तकनीकी संस्थानों के छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच नवाचार और विचार को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई की एक पहल है। विचारों को प्रोटोटाइप में अंतरण और प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं एक ही छत के नीचे तैयार की जा रही हैं। संस्थान जिनके पास तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों में अनुमोदन के 10 क्रमिक विस्तार (ईओए) हैं और कम से कम एक लाइव मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र हैं।

- **एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना**

  (i) उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभों के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण: भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों/कार्यक्रमों में भर्ती छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 24 महीने के लिए 12400 रुपये

प्रति माह की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है और दिशानिर्देशों के अनुसार गेट/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले एमई/एमटेक/एम आर्क/एम डेस की अनुमोदित संख्या के भीतर है।

(ii) प्रारंभ करने की तिथि: 1987 से

(iii) योजना के कार्यान्वयन का तरीका: पीजी छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश के समय वैध गेट/सीड प्राप्रांक है।

➢ एआईसीटीई– पूर्वोत्तर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए अनुदान (जीईएनईआर)

पूर्वोत्तर भारत के दूर–दराज के क्षेत्रों में स्थित तकनीकी संस्थानों की कार्यात्मक दक्षता में वृद्धि करने के लिए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने वर्षा जल संचयन प्रणाली के निर्माण, वैकल्पिक विद्युत सहायता और इंटरनेट सुविधा की उपलब्धता/कनेक्शन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र के तकनीकी संस्थानों को रसद संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू की है। पूर्ववर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष योजना (सौर ऊर्जा संयंत्र, जल समस्या का समाधान और इंटरनेट कनेक्शन)।

संस्थानों को वित्तीय सहायता के लिए:

- पानी की समस्या का समाधान
- वैकल्पिक बिजली सहायता प्रदान करना
- इंटरनेट कनेक्शन

पात्रता: सरकारी/ सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान कम से कम पांच वर्ष के अनुभव के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के पॉलिटेक्नीक

परियोजना की अवधि: 2 वर्ष

वित्तीय सहायता:

- जल की समस्या का समाधान : ₹ 15 लाख
- वैकल्पिक बिजली सहायता प्रदान करना : ₹ 20 लाख
- इंटरनेट कनेक्शन : ₹ 05 लाख

वर्ष 2020–21 से शुरू योजना

	2020-21		2021-22	
	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)
लाभार्थी	16	148.8	39	406.37

➢ अनुसंधान संवर्धन योजना (आरपीएस)

एआईसीटीई स्थापित और उभरते क्षेत्रों में तकनीकी विषयों और नवाचारों में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए लंबे समय से आरपीएस योजना संचालित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य एआईसीटीई अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में संकाय की सामान्य अनुसंधान क्षमताओं को बनाना और अद्यतन करना है, जिसके लिए प्रति परियोजना 25 लाख रुपये तक की निधियां प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्यक्रम/ योजना/ गतिविधियाँ	वर्ष	जारी निधि/ अनुदान /खर्च किए गए (लाख रुपये में)
	अनुसंधान संवर्धन योजना (आरपीएस)	2017-18	16.22
		2018-19	678.49
		2019-20	76.53
		2020-21	327.40
		2021-22	145.17

➢ ई–शोध सिंधु योजना

यह योजना संस्थानों को वेब ऑफ साइंस,

स्कोपस, एएसएमई, एएससीई और बेंथम साइंस जैसे ई–संसाधनों की सदस्यता प्रदान करती है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आदेश पर इनफ्लिबनेट केन्द्र, गांधी नगर, गुजरात द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को ई–जर्नलों/ई–संसाधनों के लिए निशुल्क अभिदान प्रदान किया जाता है।

अन्य गतिविधियां/पहल

तकनीकी शिक्षा का समग्र विकास और वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के अलावा अनेक राष्ट्रीय पहलों में शामिल है। निम्नलिखित अनुभागों ने ऐसी कुछ गतिविधियों/पहलों और उनमें हुई प्रगति का विवरण दिया है।

➢ **स्वयं**

स्वयं (स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव–लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स) प्लेटफॉर्म सभी विषयों को शामिल करने वाले स्कूल से विश्वविद्यालय स्तर (स्नातकोत्तर छात्रों) तक सभी पाठ्यक्रमों के लिए इंटरैक्टिव ई–सामग्री के लिए वन स्टॉप वेब लोकेशन है; किसी भी समय, कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले अधिगम का अनुभव; कला प्रणाली की स्थिति जो आसान पहुंच, निगरानी और प्रमाणन की अनुमति देती है; सहकर्मी समूह बातचीत और चर्चा मंच संदेह को दूर करने के लिए और एक हाइब्रिड मॉडल जो कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्दि करना है। स्वयं पर आयोजित पाठ्यक्रम 4 चतुर्थांशों में हैं–

1. मल्टीमीडिया के साथ वीडियो व्याख्यान,
2. विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/मुद्रित किया जा सकता है
3. परीक्षण और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण
4. शंकाओं को दूर करने के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच।

ऑडियो–वीडियो का उपयोग करके सीखने के अनुभव को समृद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं; मल्टी–मीडिया और अत्याधुनिक शिक्षाशास्त्र/ स्वयं प्लेटफार्म पर 11717 पाठ्यक्रम हैं जिनमें से 10891 पाठ्यक्रम क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं और शेष 826 पाठ्यक्रम स्व–पुस्तक पाठ्यक्रमों सहित गैर–क्रेडिट पाठ्यक्रम हैं।अब तक, स्वयं प्लेटफॉर्म पर नामांकन की कुल संख्या 39,27,136 है, जिनमें से कुल 39,27,136 शिक्षार्थियों ने स्वयं ऑनलाइन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए अपना पंजीकरण कराया है। एनपीटीईएल/आईआईआईटीएम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अब तक शिक्षार्थियों को 20,41,241 प्रमाण पत्र प्रदान किए गए हैं। अब तक, 218 देशों की स्वयं प्लेटफॉर्म तक पहुंच है।

➢ **कर्म (एआईसीटीई कौशल संवर्धन और पुनर्गठन मिशन)**

एआईसीटीई स्किल हब इनिशिएटिव (एसएचआइ) शुरू किया गया है ताकि संस्थानों को कौशल प्रशिक्षण के लिए ऑफ आवर्स के दौरान उच्च शिक्षा प्रणाली के उपलब्ध बुनियादी ढांचे का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, विशेष रूप से कौशल पाठ्यक्रमों के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे को फिर से संगठित करके, प्रशिक्षण एड्स, पाठ्यक्रम, मॉडल पाठ्यचर्या, आदि योजना स्व–वित्त पोषण मोड में कार्यान्वित की गई है।

➢ **छात्रों के प्रवेश संबंधी सार्वभौमिक मानव मूल्य संकाय विकास कार्यक्रम (यूएचवी एफडीपी एसआई)**

एनईपी 2020 शिक्षा से अपेक्षाओं पर बहुत

स्पष्टता के साथ आया है। मूल्यों पर शिक्षा तीन सार्वभौमिक, मूल मूल्यों सत्य (सत्य), सामंजस्यपूर्ण अस्तित्व और रहन–सहन (सद्भाव, धर्म) और प्रेम और करुणा (न्याय, न्याय) पर केंद्रित है, जिसे एनईपी 2020 में भी स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है. एआईसीटीई ने देश भर में अब तक एक लाख से अधिक शिक्षकों के साथ विभिन्न एफडीपी के माध्यम से यूएचवी सामग्री साझा की है। आत्म–विकास के लगभग तात्कालिक और सकारात्मक संकेतक के साथ–साथ उनके संस्थानों में प्रगति काफी उत्साहजनक रही है।

➢ **तकनीकी पुस्तक लेखन योजना**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप, एआईसीटीई ने भारतीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए वर्ष 2021–22 में एक तकनीकी पुस्तक लेखन योजना शुरू की है। एआईसीटीई ने पहले वर्ष के लिए अंग्रेजी में मूल पुस्तक लेखन शुरू किया और फिर एआईसीटीई के मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार और परिणाम–आधारित शिक्षा मॉडल का पालन करते हुए, मूल लेखन के बाद 12 भारतीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया। पहले वर्ष में, 20 पुस्तकों की पहचान की गई (11 डिप्लोमा स्तर पर और 9 स्नातक स्तर पर) और शुरू में उनका अनुवाद 12 भारतीय भाषाओं अर्थात् हिंदी, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, मलयालम और असमिया में किया गया। शेष एक भारतीय भाषा (उर्दू) में अनुवाद प्रगति पर है।

वर्ष 2022–23 में, एआईसीटीई ने अंग्रेजी में दूसरे वर्ष की मूल पुस्तक लेखन की प्रक्रिया शुरू की। 87 विषयों– डिग्री स्तर पर 41 और डिप्लोमा स्तर पर 46– और देश भर के विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनों की भागीदारी के साथ 12 भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद प्रगति पर है। अब तक द्वितीय वर्ष की 47 मूल पुस्तकें पूर्ण होकर ई–कुंभ पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं।

द्वितीय वर्ष की पुस्तकों का अनुवाद कार्य पूरा किया गया है: तमिल – 8 हिंदी – 18 तेलुगु– 11 बंगाली– 5 मलयालम– 12 उर्दू– 19 असमिया– 3 गुजराती– 28 कन्नड़– 10 मराठी– 18 और पंजाबी – 15 अनूदित पुस्तकों के दूसरे वर्ष में डिजाइन का कार्य प्रगति पर है। परिषद ने तीसरे वर्ष के मूल पुस्तक लेखन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। लेखकों की पहचान की जाती है तथा कार्य उन लोगों को सौंपे जाते हैं जिनके पास 31 मई, 2024 तक इसे पूरा करने की समय सीमा है

भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 12 नवंबर 2022 को भुवनेश्वर में माननीय राज्यपाल ओडिशा, माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा, माननीय शिक्षा मंत्री, भारत सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में ओडिया माध्यम में एआईसीटीई परिणाम–आधारित इंजीनियरिंग पुस्तकों का शुभारंभ किया।

उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी

माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण वर्ष 2016–17 के अनुसार, उच्चतर शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए), एक गैर–लाभकारी संगठन की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी, जिसमें प्रारंभिक सरकारी इक्विटी भागीदारी और बाजार से धन प्राप्त करने, उन्हें दान और सीएसआर फंड आदि से प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के साथ, उच्चतर शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए स्थापित किया गया था। केनरा बैंक को हेफा की स्थापना और इसके प्रबंधन के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में पहचाना गया था। हेफा को एनबीएफ़सी लाइसेंस के साथ धारा 8 कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था प्रारंभिक अधिकृत पूंजी 2,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें से सरकार की इक्विटी

1,000 करोड़ रुपये होगी। केनरा बैंक कुल इक्विटी का 10% निवेश करेगा। एचईएफए की स्थापना का उद्देश्य बजटीय अनुदान पर शैक्षिक संस्थानों की निर्भरता को कम करना और तेजी से गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक बुनियादी ढांचे के निर्माण को सक्षम बनाना था।

इसके बाद, वर्ष 2018 में, बजट वर्ष 2017–18 में "राइज़ (2022 तक शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनरोद्धार) के एक हिस्से के रूप में, सरकार ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों के अलावा केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, एम्स को शामिल करने के लिए हेफा के दायरे को बढ़ाने को अनुमोदन दिया। इस दिशा में, एचईएफए की अधिकृत पूंजी को 2000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें से सरकार की इक्विटी 6,000 करोड़ रुपये है और केनरा बैंक सरकार की हिस्सेदारी का 10% योगदान देगा। वर्तमान में, चुकता पूंजी 5293.75 करोड़ रुपये (शिक्षा मंत्रालय – 4812.50 करोड़ रुपये, केनरा बैंक – 481.25 करोड़ रुपये) है। हेफा को ऋण या तो फ्लोटिंग बॉन्ड या सीधे ऋण के माध्यम से अतिरिक्त निधि जुटाने के लिए भी अधिकृत किया गया था।

एचईएफए की चुकता पूंजी 5293.75 करोड़ रुपये है (भारत सरकार 4,812.50 करोड़ रुपये; केनरा बैंक 481.25 करोड़ रुपये) वर्ष 2022 तक राइज़ के तहत हेफा के वर्ष 2022 तक 100,000 करोड़ रुपये होने की उम्मीद थी। तथापि, संचयी रूप से 31 दिसंबर 2023 तक एचईएफए द्वारा 49432.94 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को अनुमोदन किया गया है। जिसके लिए 38224.16 करोड़ रुपये की ऋण राशि स्वीकृत की गई है और 18987.91 करोड़ रुपये वास्तव में वितरित किए गए हैं।

हाल ही में व्यय वित्त समिति (ईएफ़सी) ने वर्ष 2023–24 से वर्ष 2025–26 की अवधि (15वें वित्त आयोग के साथ सह–समात्य) के लिए हेफा के माध्यम से राइज़ योजना को जारी रखने की सिफारिश की है। ईएफसी सिफारिशों के अनुसार एचईएफए विंडोज का नया वर्गीकरण नीचे दिया गया है:

विंडो	संस्थान का प्रकार	चुकौती अवधि	मूल भुगतान/व्यवहार्यता राजकीय सहायता अंतराल	ब्याज भुगतान/ब्याज पर राजकीय सहायता
I	वर्ष 2008 से पहले स्थापित तकनीकी संस्थान।	10 वर्ष	संस्थान द्वारा 100%	संस्थान द्वारा 10% और सरकार द्वारा 90%।
II	वर्ष 2008 और वर्ष 2014 के बीच स्थापित तकनीकी संस्थान	10 वर्ष	संस्थान द्वारा 25% और सरकार द्वारा 75%।	संस्थान द्वारा 10% और सरकार द्वारा 90%।
III (क)	वर्ष 2014 से पहले स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और गैर–तकनीकी संस्थान।	10 वर्ष	संस्थान द्वारा 10% और सरकार द्वारा 90%।	सरकार द्वारा 100%
III (क)	वर्ष 2014 के बाद स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और गैर–तकनीकी संस्थान।	15 वर्ष	संस्थान द्वारा 10% और सरकार द्वारा 90%।	सरकार द्वारा 100%
III (क)	वर्ष 2014 के बाद स्थापित तकनीकी संस्थान	15 वर्ष	संस्थान द्वारा 10% और सरकार द्वारा 90%।	संस्थान द्वारा 5% और सरकार द्वारा 95%।
IV	आईआईआईटी (पीपीपी) और आईआईएम	10 वर्ष	संस्थान द्वारा 100%	संस्थान द्वारा 100%

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए)

राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) की स्थापना वर्ष 1994 में एआईसीटीई अधिनियम की धारा 10 (i) के तहत इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी और वास्तुकला आदि में डिप्लोमा से स्नातकोत्तर स्तर तक तकनीकी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों की गुणात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए की गई थी। वर्ष 2010 में, एनबीए कार्यक्रमों की मान्यता के माध्यम से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता के सुनिश्चयन के उद्देश्य से स्वायत्त बन गया। वर्ष 2013 में, संगम ज्ञापन (एमओए) और एनबीए के नियमों को प्रशासनिक और वित्तीय रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए संशोधित किया गया था।

प्रत्यायन गुणवत्ता सुनिश्चयन और सुधार की एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा एक कार्यक्रम को यह सत्यापित करने के लिए गंभीर रूप से मूल्यांकन किया जाता है कि कार्यक्रम समय–समय पर नियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों को पूरा करना और / या उससे अधिक है। एनबीए उन संस्थानों को प्रत्यायित नहीं करता है, इसके बजाय वह उन तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रमों को प्रत्यायित करता है जिन्होंने कम से कम दो बैचों में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, मान्यता के लिए 1,823 कार्यक्रमों पर विचार किया गया, जिनमें से 1,588 कार्यक्रमों को मान्यता दी गई और शेष 235 कार्यक्रमों को मान्यता नहीं दी गई।

कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, 269 नए निर्धारित कार्यक्रम मूल्यांकनकर्ताओं (पीईवी) के लिए परिणाम–आधारित शिक्षा और प्रत्यायन पर चार अभिमुखीकरण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, बेंगलुरु में प्रत्यायन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसने 102 हितधारकों को लाभान्वित किया गया। स्नातक विशेषताओं और पेशेवर दक्षताओं (जीएपीसी 4.0) पर एक विशेष कार्यशाला प्रोफेसर केएस लॉक्स, अध्यक्ष, वाशिंगटन समझौते द्वारा दी गई थी। कार्यशाला में एनबीए के 80 से अधिक कार्यक्रम मूल्यांकनकर्ताओं ने भाग लिया। वाशिंगटन समझौते के तहत मान्यता प्रक्रिया में कार्यान्वयन के लिए यूनेस्को और इंटरनेशनल इंजीनियरिंग एलायंस (आईईए) द्वारा अनुमोदित जीएपीसी 4.0 को एनबीए की मान्यता प्रक्रिया में कार्यान्वयन के लिए अपनाया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ़)

इंडिया रैंकिंग एक वार्षिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न श्रेणियों और विषय गत क्षेत्र में भारत में उच्चतर शिक्षा के संस्थानों को श्रेणीकृत करने के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) का उपयोग किया जाता है। इंडिया रैंकिंग का पहला और नया संस्करण वर्ष 2016 में एक श्रेणी और तीन विषयों के गत क्षेत्र में जारी किया गया था। इसके बाद, वर्ष 2017 से 2023 तक एनआईआरएफ का उपयोग करते हुए इंडिया रैंकिंग के सात वार्षिक संस्करण जारी किए गए। इन सात वर्षों के दौरान अर्थात 2017 से 2023 तक प्रारंभिक एक श्रेणी और तीन विषय गत क्षेत्र में चार श्रेणियां और सात विषय गत क्षेत्र जोड़े गए। इंडिया रैंकिंग 2023 5 जून 2023 को डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, माननीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री द्वारा पांच श्रेणियों, अर्थात् समग्र, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और नवाचार और आठ विषय गत क्षेत्र, अर्थात् इंजीनियरिंग, प्रबंधन, फार्मेसी, चिकित्सा, वास्तुकला और योजना, कानून, दंत चिकित्सा और कृषि और संबद्ध विज्ञान में जारी की गई थी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए)

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की स्थापना शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक प्रमुख, विशेषज्ञ, स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन के रूप में की गई थी, जो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश/फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए मंत्रिमंडल के दिनांक 10.11.2017 के अनुमोदन के अनुसरण में की गई थी। एनटीए को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम

(1860) के तहत दिनांक 15.05.2018 को एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। एनटीए ने अपनी स्थापना के बाद से 179 परीक्षाएं आयोजित की हैं।

1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक एनटीए ने 1,32,76,190 उम्मीदवारों के लिए 50 परीक्षाएं आयोजित की हैं, जिनमें शामिल हैः जेईई (मेन), नीट (यूजी), यूजीसी नेट, सीयूईटी (यूजी), सीयूईटी (पीजी), सीएमएटी, जीपीएटी, संयुक्त सीएसआईआर यूजीसी नेट, आईसीएआर, एआईएपीजीईटी, एनसीएचएम–जेईई, स्वयं, एनसीईटी, पीएच.डी. स्नातकोत्तर/पीएचडी स्तर के पाठ्यक्रमों, फेलोशिप और भर्तियों में प्रवेश के लिए परीक्षा। सभी परीक्षाएं, नीट (यूजी), एआईएसएसईई, एचएसएस–सीईटी और यूपी सिविल कोर्ट स्टाफ केंद्रीकृत भर्ती परीक्षा (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) को छोड़कर, पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थीं, कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) मोड में आयोजित की गई थीं।

सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (यूजी)–2023, नीट (यूजी) 2023, जेईई (मेन) 2023, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन (एआईएसएसईई)–2023 और नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (एनसीईटी) 2023 का आयोजन 13 भाषाओं के माध्यम से किया गया।

वास्तुकला परिषद

वास्तुकला परिषद (सीओए) का गठन भारत सरकार द्वारा भारत की संसद द्वारा अधिनियमित वास्तुकला अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है, जो दिनांक 1 सितंबर 1972 को लागू हुआ था। इस अधिनियम में वास्तुकारों के पंजीकरण, शिक्षा के मानकों, मान्यता प्राप्त अर्हताओं और प्रेक्टिस के मानकों का प्रेक्टिस करने वाले वास्तुकारों द्वारा अनुपालन किए जाने का प्रावधान है। वास्तुकला परिषद को वास्तुकारों के रजिस्टर को बनाए रखने के अलावा पूरे भारत में व्यवसाय की शिक्षा और अभ्यास को विनियमित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस प्रयोजनार्थ, भारत सरकार ने नियम बनाए हैं और वास्तुकला परिषद ने भारत सरकार के अनुमोदन से वास्तुविद अधिनियम में किए गए प्रावधान के अनुसार विनियम तैयार किए हैं।

वास्तुकला का पंजीकरण

परिषद अधिनियम की धारा 25 के तहत एक वास्तुकार के रूप में एक व्यक्ति को पंजीकृत करती है, जो भारत में वास्तुकला के पेशे में रहता है या कार्य करता है और एक मान्यता प्राप्त वास्तुशिल्पीय योग्यता रखता है। पंजीकरण और शुल्क के लिए आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। दिनांक 21.11. 2023 की स्थिति के अनुसार, परिषद ने 13353 योग्य व्यक्तियों को नए वास्तुकारों के रूप में पंजीकृत किया है। इसके साथ ही दिनांक 21.11.2023 की स्थिति के अनुसार, कुल 164981 वास्तुविदों को परिषद के साथ वास्तुविद के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा, दिनांक 21.11.2023 की स्थिति के अनुसार, 117454 वास्तुविद के पास पूरे भारत में वास्तुकला परिषद के साथ वास्तुविद के पास के रूप में वैध पंजीकरण रखते हैं।

वास्तुकला संस्थान

वर्ष के दौरान रिपोर्ट के तहत 07 नई संस्थाओं को वास्तुकला स्नातक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था और 09 मौजूदा संस्थाओं को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान वास्तुकला परिषद ने 379 संस्थानों को अनुमोदन का विस्तार प्रदान किया जो देश में मान्यता प्राप्त वास्तुशिल्प योग्यता प्रदान कर रहे हैं।

समझौता ज्ञापन

वास्तुकला अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद ने दिव् यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ सभी स्तरों के रूप में वास्तुशिल्प पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम में एक मुख्य विषय

के रूप में सार्वभौमिक अभिगम्यता पर मैनुअल तैयार किया गया है। परिषद ने वास्तुविदों द्वारा ऊर्जा–दक्ष तरीकों और तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था (एईईई), नई दिल्ली के संवर्धन के लिए ऊर्जा–दक्ष अर्थव्यवस्था के लिए गठबंधन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया (एनबीटी–इंडिया), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन, 1957 में स्थापित किया गया था। एनबीटी इंडिया 60 से अधिक भारतीय भाषाओं (जनजातीय भाषाओं, बोलियों सहित) में सभी शैलियों और सभी आयु समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण पठन सामग्री प्रकाशित करता है। यह विभिन्न पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों के साथ–साथ विभिन्न सेमिनारों, कार्यशालाओं, पैनल चर्चाओं, पुस्तक विमोचन समारोहों, बच्चों के लिए गतिविधियों आदि के माध्यम से पुस्तक पढ़ने को भी बढ़ावा देता है। एनबीटी–इंडिया नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजक है – जो दुनिया के प्रतिष्ठित पुस्तक मेलों में से एक है, जो हर साल 1.5 मिलियन से अधिक लोगों को आकर्षित करता है।

प्रकाशन–व्यवसाय

एनबीटी–इंडिया सभी आयु समूहों के लिए सभी शैलियों में कथा साहित्य सहित पठन सामग्री प्रकाशित करता है, जिनमें से कुछ 33 से कम की श्रृंखलाएं जैसे; (क) भारत– भूमि और लोग (ख) लोकप्रिय विज्ञान (ग) लोकप्रिय सामाजिक विज्ञान (घ) लोकगीत (ङ) राष्ट्रीय जीवनी (च) भारतीयों की आत्मकथा जिन्होंने भारतीय समाज, संस्कृति, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राजनीति आदि के विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है (छ) नेहरू बाल पुस्तकालय (ज) सृजनात्मक शिक्षा (झ) नव–साक्षरों के लिए पुस्तकें (ञ) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" अभियान के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के रचनात्मक साहित्य के आदान–प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के लिए अभियान (ट) भारतीय साहित्य (ठ) भारतीय डायस्पोरा अध्ययन (ड) सामान्य श्रृंखला (ढ) ब्रेल पुस्तकें (ण) वीरगाथा श्रृंखला (त) महिला पायनियर्स (थ) नवलेखन माला (द) नवजागरण अग्रदूत (ध) कोरोना स्टडीज सीरीज (न) इंडिया/75 (प) पीएम–युवा श्रृंखला (फ) बौद्धिक विरासत का सृजन आदि शामिल हैं।

एनबीटी–इंडिया ने धुरबी, दोरली, गोंडी, खडिया, कुडुख, माटो, मुंडारी आदि जैसी कई छोटी भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन की दिशा में विशेष प्रयास भी शुरू किए हैं। वर्ष 2023 के दौरान, एनबीटी–इंडिया ने अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में 4217 शीर्षक प्रकाशित किए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स 11 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने देश भर में ज्ञान के आदान–प्रदान को बढ़ावा देने के लिए 11 भारतीय भाषाओं – तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ओडिया, असमिया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू और बंगाली में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स प्रकाशित की। पुस्तक छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को परीक्षा के तनाव कम करने के लिए मूल्यवान सलाह प्रदान करती है, परीक्षा के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण पर जोर देती है। इन पुस्तकों को परीक्षा पे चर्चा के छठे संस्करण से पहले लॉन्च किया गया था, जो 27 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में अपने–अपने राज्यों के गणमान्य व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया था।

पुस्तक इंडियाः द मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नया संस्करण प्रकाशित

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक पहल के हिस्से के रूप में, इंडियाः द मदर ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक का एक संशोधित संस्करण लाया गया है। पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा प्रकाशित

की गई है। पुस्तक विभिन्न विद्वानों द्वारा निबंधों का संकलन है और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है जो प्राचीन काल से भारत के अभिन्न अंग रहे हैं। पुस्तक "वसुधैव कुटुम्बकम" की अवधारणा को भी बताती है, जो जी–20 की अध्यक्षता के लिए भारत का विषय है।

बौद्धिक विरासत का निर्माण– नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के 'बौद्धिक विरासत कार्यक्रम' के तहत प्रमुख क्लस्टर संस्थानों और अनुसंधान भागीदारों में से एक के रूप में शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संवाद, प्रलेखन, अनुसंधान और प्रकाशन की योजना बनाई गई है और आयोजित की गई है। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने पांच पुस्तकों के संग्रह का अनावरण किया, जिनमें 'बियॉन्ड बाउंड्रीजः ए स्टडी ऑफ सोशल इम्पैक्ट ऑफ मन की बात; विकास, ज्ञान संसाधन और नया भारत बनानाः एक संवाद, प्रलेखन और अनुसंधान कार्यक्रम; गरीबों और सीमांत लोगों के लिए नीतियांः भारत में गरीब कल्याण योजनाओं का एक अध्ययन; नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनः भारत में हरित ऊर्जा और इसके सतत उपयोग का एक अध्ययन; और नए भारत की ओरः बुनियादी ढांचे, समुदाय और विकास का एक अध्ययन, एनबीटी–इंडिया द्वारा प्रकाशित और डॉ सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री और श्री के संजय मूर्ति, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की उपस्थिति में 30 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में दो दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 में शुभारंभ किया गया।

भारत चीन अनुवाद कार्यक्रम

भारत सरकार और चीन गणराज्य की सरकार ने एक महत्वाकांक्षी अनुवाद कार्यक्रम प्रस्तुत किया है जिसमें 25–25 शास्त्रीय और समकालीन साहित्यिक कृतियों का चीनी भाषाओं से हिंदी में और भारतीय साहित्यिक कृतियों का चीनी भाषाओं में अनुवाद शामिल है। नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने विदेश मंत्रालय के विदेश प्रचार और सार्वजनिक कूटनीति प्रभाग के साथ भारत सरकार की 25 चीनी रचनाओं का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। लगभग 20 चीनी साहित्यिक रचनाओं को अनुवाद के लिए सौंपा गया है, जिनमें से पांच पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और तीन पुस्तकें प्रकाशन के विभिन्न चरणों में हैं।

पुस्तक प्रकाशन में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

न्यास प्रकाशन उद्योग के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों का प्रतिभा पूल सृजित करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में पुस्तक प्रकाशन में अल्पावधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। न्याय ने 7 जनवरी से 9 अप्रैल 2023 और 28 अक्टूबर 2023 से 4 फरवरी 2024 तक पुस्तक प्रकाशन में दो ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए।

अनुवाद के लिए एनबीटी वित्तीय सहायता कार्यक्रम

विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए, ट्रस्ट ने अनुवाद के लिए एक वित्तीय सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के तहत, ट्रस्ट द्वारा विदेशी प्रकाशकों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो भारतीय पुस्तकों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करने के इच्छुक हैं।

साहित्यिक गतिविधियों जैसे सेमिनारों, कार्यशालाओं और पुस्तक विमोचन कार्यों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीटी–इंडिया ने 70 से अधिक साहित्यिक गतिविधियों जैसे सेमिनारों, लेखक से मिलने, कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, पुस्तक विमोचन कार्यों और विभिन्न विषयों पर पैनल चर्चाओं, सेमिनारों और व्याख्यानों सहित ऑनलाइन गोलमेज बैठकों का आयोजन किया। एनबीटी–इंडिया द्वारा अन्य भाषाओं

के अलावा अन्य भाषाओं में अनुवाद कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया है।

भारत की अध्यक्षता में एससीओ युवा लेखकों का सम्मेलन आयोजित किया गया

भारत ने अपनी एससीओ अध्यक्षता (2022–2023) के दौरान, शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के तहत 12–13 अप्रैल, 2023 को एससीओ युवा लेखकों के सम्मेलन की मेजबानी की। शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी थी, जो आधुनिक शिक्षा, प्रशिक्षण, उद्यमशीलता गतिविधियों और अभिनव परियोजनाओं पर एससीओ सदस्य देशों के युवाओं के बीच संवाद को बढ़ावा देने पर केंद्रित थी। इसका विषय 'एससीओ सदस्य राष्ट्रों के बीच सभ्यतागत संवादः युवा विद्वानों के परिप्रेक्ष्य' था, जिसमें इतिहास और दर्शन, अर्थव्यवस्था, धर्म, संस्कृति, साहित्य और विज्ञान और चिकित्सा जैसे उप–विषय शामिल थे।

एनबीटी–इंडिया के स्थापना दिवस का उत्सवः नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने 1 अगस्त 2023 को अपना 67वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर एनबीटी मुख्यालय, वसंत कुंज, नई दिल्ली में 'समकालीन समय में पुस्तकों और पठन की भूमिका' विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया गया। साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष प्रोफेसर कुमुद शर्मा ने व्याख्यान दिया।

राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र (एनसीसीएल)

राष्ट्रीय बाल साहित्य केंद्र (एनसीसीएल) की स्थापना एनबीटी–इंडिया द्वारा वर्ष 1993 में की गई थी। यह भारत की सभी भाषाओं में बच्चों के साहित्य को बढ़ावा देता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनसीसीएल ने देश के विभिन्न हिस्सों में लेखक से मिलने–जुलने वाले कार्यक्रमों, कहानी सुनाने के सत्रों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, रीडर्स क्लब ओरिएंटेशन कार्यक्रमों और बच्चों के अन्य कार्यकलापों के आयोजन के अलावा 648 रीडर्स क्लबों की स्थापना की, जिनकी संख्या बढ़कर 1.30 लाख हो गई। इसके अतिरिक्त, बच्चों में पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने के लिए एक द्विभाषी पत्रिका रीडर्स क्लब बुलेटिन के 3 तिमाही अंक भी डिजिटल फार्मेट में प्रकाशित किए गए। कुल मिलाकर, देश भर के विभिन्न स्थानों पर बच्चों के लिए लगभग 200 कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

एनईपी 2020 के अनुसार फाउंडेशन ऑफ लर्निंग (क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी)

नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) पर ध्यान केंद्रित करते हुए और विभिन्न क्षेत्रों में इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए, आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता विकसित करने के लिए कार्यपुस्तिका प्रारूप में अंग्रेजी और हिंदी में विशेष प्रकाशन तैयार किए। एनबीटी–इंडिया 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में 10 लाख से अधिक बच्चों तक पहुंच गया है।

एनबीटी–इंडिया प्रकाशनों की बिक्री और वितरण

एनबीटी–इंडिया की किताबें 14 शहरों – अगरतला, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, मुंबई, पटना और लखनऊ में एनबीटी–इंडिया–प्रबंधित 16 भौतिक बुकस्टोर्स में बेची जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एनबीटी–इंडिया की पुस् तकें दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद और बंगलौर के चुनिंदा बुक स्टोरों तथा चुनिंदा एयरपोर्ट स्टोरों पर भी उपलब्ध हैं। खरीदारों की सुविधा के लिए, एनबीटी–इंडिया की किताबें इसके वेब स्टोर www.nbtindia.gov.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं। एनबीटी–इंडिया ने अपने टाइटल को अन्य डिजिटल मार्केटप्लेस जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध कराया है। कैलेंडर वर्ष 2023 में, एनबीटी इंडिया ने अपने प्रकाशनों की लगभग 2.83 करोड़ प्रतियां बेचीं।

बुक क्लब

बुक क्लब योजना जनता के बीच पुस्तकों और पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। न्याय ने इस अवधि के दौरान 561 नए बुक क्लब सदस्यों को नामांकित किया। यह योजना एनबीटी इंडिया के सभी प्रकाशनों पर 20% की छूट प्रदान करती है।

पुस्तक संवर्धन गतिविधियों संबंधी वित्तीय सहायता कार्यक्रम

शिक्षा मंत्रालय ने पुस्तक संवर्धन गतिविधियों से संबंधित सेमिनार/प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/कार्यशालाएं/वार्षिक सम्मेलन/पुस्तक मेले आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक/निजी संगठनों को वित्तीय सहायता की योजना सौंपी है। वर्ष 2023 में, नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया द्वारा समर्थित 4 ऐसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं और स्वैच्छिक संगठनों को कुल 26.93 लाख रुपए प्रदान किए गए।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023

नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन किया। डॉ. राजकुमार रंजन सिंह, माननीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार ने मेले का उद्घाटन किया। महामहिम श्री इमैनुएल लेनैन, भारत में फ्रांस के राजदूत; श्री विन्सेंट मोंटेगने, अध्यक्ष, सिंडिकेट नेशनल डी ल'एडिशन, फ्रांस; सुश्री एनी एर्नौक्स, नोबेल पुरस्कार विजेता, फ्रांस; आईटीपीओ के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री प्रदीप सिंह खरोला और संयुक्त सचिव (एनआईटी) सुश्री सौम्या गुप्ता; इस अवसर पर एनबीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद प्रसाद शर्मा और एनबीटी–इंडिया के निदेशक श्री युवराज मलिक भी उपस्थित थे। एनडीडबल्यूएफ़बी 2023 का विषय 'आजादी का अमृत महोत्सव' था, जो स्वतंत्रता के 75 वर्षों और हमारे लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास का जश्न मनाता है। थीम मंडप का डिजाइन ज्ञान की नदी की अवधारणा में निहित था। मेले में फ्रांस गेस्ट ऑफ ऑनर देश था। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले की अन्य विशेषताओं में सीईओ पीक, एजुकेशन कॉन्क्लेव, नई दिल्ली राइट्स टेबल, चिल्ड्रन पैवेलियन, ऑथर्स कॉर्नर, फॉरेन पवेलियन, जी 20 पैवेलियन, एनईपी 2020 पवेलियन और पीएम–युवा राष्ट्रीय शिविर, डॉ बी आर अंबेडकर पर विशेष प्रदर्शनियां और भारत का संविधान और टॉल्स्टॉय–गांधी फोटो प्रदर्शनी शामिल थीं। पुस्तक मेले में 30 से अधिक देशों ने भाग लिया और भारत और विदेशों के 600 से अधिक प्रकाशकों ने भाग लिया। भारतीय प्रकाशकों ने मेले में 1400 से अधिक स्टालों पर बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मैथिली, मलयालम, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू सहित विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का प्रदर्शन किया।

नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में जी–20 मंडप

भारत की जी–20 अध्यक्षता (2022–23) के उपलक्ष्य में, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2023 में एक समर्पित जी–20 मंडप प्रदर्शित किया गया था। नौ जी–20 देशों के साहित्य का प्रदर्शन करते हुए, मंडप में फिक्शन, नॉन–फिक्शन, इतिहास, अर्थव्यवस्था और स्वदेशी संस्कृति जैसी शैलियां शामिल थीं। हाइलाइट्स में जी–20 की यात्रा का दस्तावेजीकरण करने वाली वॉल ऑफ हिस्ट्री, एक इमर्सिव अनुभव के लिए एक ध्वनि प्रसार और सदस्य देशों के साहित्य का पता लगाने के लिए एक स्थान शामिल था।

विदेशों में भारतीय पुस्तकों का संवर्धन

एनबीटी–इंडिया विभिन्न भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि भारतीय प्रकाशनों के क्रॉस–सेक्शन को प्रदर्शित करके विदेशों में भारतीय पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान एनबीटी–इंडिया ने 12 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लिया, जिनमें विश्व हिंदी सम्मेलन, लंदन पुस्तक मेला, अबू धाबी

अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, तेहरान अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, वलाडोलिड पुस्तक मेला, सियोल अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, कोलंबो अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, लिबर फेरिया अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला, दक्षिण एशिया अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला और सोफिया अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला शामिल हैं।

फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला 2023 में पहली बार भारत का स्टैंड

पहली बार नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया ने कैपेक्सिल और प्रकाशन प्रभाग, एआईसीटीई, साहित्य अकादमी और आईजीएनसीए सहित अन्य संस्थानों के सहयोग से फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले (18 से 22 अक्टूबर 2023) में भारत का राष्ट्रीय पक्ष रखा। यह पहली बार था कि राष्ट्रीय स्टैंड की एक छतरी के नीचे राष्ट्रीय निकायों के साथ–साथ निजी निकायों की भागीदारी ने ब्रांड इंडिया को इस तरह के एक प्रतिष्ठित व्यापार–उन्मुख अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत करने में पूरे सरकारी दृष्टिकोण पर जोर दिया। फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेला, सीजीआई फ्रैंकफर्ट के अधिकारियों, भारतीय प्रकाशकों और प्रतिभागियों और कई विदेशी प्रकाशकों की उपस्थिति में इंडिया नेशनल स्टैंड का उद्‌घाटन किया गया। इंडिया स्टैंड लगभग 300 वर्ग मीटर में फैला हुआ था जिसमें 35 से अधिक प्रदर्शकों और 50 प्रकाशकों ने सामूहिक प्रदर्शनी के माध्यम से भाग लिया था। स्टैंड को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, अहमदाबाद द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसने बहुभाषी भारत को 'नए भारत से कहानियां लाना' के नारे के साथ एक जीवित परंपरा के रूप में प्रस्तुत किया था। मेले के दौरान, कई साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया जैसे कि श्री लोथर पीर द्वारा 'आयुर्वेद के माध्यम से भारतीय लोकाचार को बढ़ावा देने के मेरे अनुभव' पर एक वार्ता; 'ट्रांसलेटिंग इंडियाः व्यूज़ फ्रॉम इंडिया एंड बियॉन्ड', 'इंडिया–फिलीपींस पब्लिशिंग डायलॉग', 'इंडिया–स्लोवेनिया पब्लिशिंग डायलॉग' पर एक पैनल चर्चा।

भारत में पुस्तक मेलों का आयोजन

समीक्षाधीन अवधि के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने 5 राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, 21 क्षेत्रीय पुस्तक मेलों का आयोजन किया, 126 स्थानीय पुस्तक मेलों और भारत के उत्सवों में भी भाग लिया।

उज्जैन पुस्तक मेला

राष्ट्रीय प्रस्तक न्यास, भारत ने दशहरा मैदान, उज्जैन (मध्य प्रदेश) में 1 से 6 सितंबर 2023 तक उज्जैन पुस्तक मेले का आयोजन किया। मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव ने पुस्तक मेले का उद्‌घाटन किया। देश भर के लगभग 30 प्रकाशकों/प्रदर्शकों ने मेले के दौरान भाग लिया और 50 स्टालों में विभिन्न विषयों पर अपनी पुस्तकें प्रदर्शित कीं। उज्जैन पुस्तक मेले की पूरी अवधि के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

लद्दाख पुस्तक पर्व

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने लेह, लद्दाख में साहित्यिक प्रेमियों और पुस्तक प्रेमियों के लिए अपनी तरह का पहला पुस्तक वर्व आयोजित किया। लद्दाख पुस्तक पर्व का उद्‌घाटन 12 जुलाई 2023 को माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने किया था। 5 दिवसीय पर्व का आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 तक संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के सहयोग से न्यू मल्टीपर्पस इंडोर स्टेडियम (एनडीएस मेमोरियल स्पोर्ट्स ग्राउंड), लेह में किया गया था। कार्यक्रम का उद्‌घाटन करते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने कहा, "पुस्तक लिखने की परंपरा हमारे देश की प्राचीन कला और साहित्य का हिस्सा है। पुस्तक पर्व के माध्यम से 50,000+ आगंतुकों के आगमन के साथ एक सफल समापन हुआ।

शिलांग पुस्तक पर्व

शिलांग पुस्तक मेले का आयोजन एनबीटी–इंडिया द्वारा 18 से 24 सितंबर 2023 तक राज्य केंद्रीय

पुस्तकालय, शिलांग (मेघालय) में कला और संस्कृति विभाग और मेघालय सरकार के शिक्षा विभाग के सहयोग से किया गया था। पुस्तक मेले का उद्‌घाटन यू सोसोथाम ऑडिटोरियम, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, शिलांग में माननीय शिक्षा मंत्री श्री रक्कम ए संगमा ने किया। शिलांग पुस्तक मेले में देश भर के लगभग 26 प्रकाशकों ने 50 स्टालों में भाग लिया। पुस्तक मेले की पूरी अवधि के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की गतिविधियां, साहित्यिक सत्र आदि आयोजित किए गए।

गोमती पुस्तक पर्व

एनबीटी–इंडिया द्वारा आयोजित, गोमती पुस्तक पर्व 2023 लखनऊ में नौ दिवसीय उत्सव था जो अपने अभिनव सत्रों, इंटरैक्टिव साहित्यिक चर्चाओं और विशेष बच्चों की गतिविधियों की एक श्रृंखला के लिए खड़ा था। 'राइटिंग ए न्यूजपेपर आर्टिकल', 'बिलियन बुक्स फॉर बिलियन रीडर्स' हैकथॉन, 'विश ए बुक', 'शब्द संसार' और 'रीडिंग ट्री' पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिन्होंने युवा पाठकों को सीखने और तलाशने के लिए एक मंच प्रदान किया। शिक्षा मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से, उत्सव में दृश्य विकलांगता वाले पाठकों को मुफ्त ब्रेल पुस्तकें वितरित करके समावेशिता का उदाहरण प्रस्तुत किया। महोत्सव ने एनसीसीएल द्वारा 'बुनो कहानी' और 'लिखो कहानी' प्रतियोगिताओं के साथ–साथ 'सुनो कहानी' (प्रसिद्ध कहानीकारों द्वारा जीवन कौशल और प्रसिद्ध कहानियों पर आधारित प्रसिद्ध कहानियों) की अनूठी पहल के माध्यम से पारंपरिक भारतीय मौखिक शिक्षण प्रणाली पर प्रकाश डाला, जहां बच्चों ने रचनात्मक लेखन, चित्र बनाने और सुलेख करने की कला का पता लगाया। पर्व में बुक स्ट्रीट पर 100 से अधिक स्टालों के साथ पाठकों की संख्या में वृद्धि देखी गई, जिससे 2 लाख से अधिक पाठक आकर्षित हुए।

पुणे पुस्तक पर्व

एनबीटी–इंडिया ने पुणे पुस्तक पर्व का आयोजन किया, जिसने चार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल करके एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। "पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत" के दृष्टिकोण को अपनाते हुए, माननीय प्रधान मंत्री के एक पठन राष्ट्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप, पर्व ने 14 दिसंबर को अपना पहला रिकॉर्ड बनाया, जहां 3066 माता–पिता ने अपने बच्चों को एक साथ पढ़ने की सबसे बड़ी गतिविधि में भाग लिया।

इस महोत्सव ने 15 दिसंबर को भारत के बहुभाषावाद के प्रदर्शन के साथ अपना दूसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जीता, 22 भाषाओं में एक पुस्तक की 7500 प्रतियों को "भारत'' शब्द बनाने के लिए व्यवस्थित किया गया था। साहित्यिक विविधता और समावेशिता के लिए पर्व की प्रतिबद्धता इस उपलब्धि के माध्यम से परिलक्षित हुई। तीसरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 16 दिसंबर को बनाया गया था, जब माननीय प्रधान मंत्री द्वारा पुस्तक "एग्जाम वॉरियर" के मराठी संस्करण की 18751 प्रतियों को प्रेरक शब्द जयतु भारत बनाने के लिए आयोजित किया गया था! साहित्यिक कौशल के इस प्रदर्शन ने भाषा और नेतृत्व दोनों का जश्न मनाया। पर्व की प्रशंसाओं को बढ़ाते हुए, 22 दिसंबर को एक प्रभावशाली चौथा रिकॉर्ड बनाया गया था, एक उल्लेखनीय 11,043 भारतीयों ने प्रतिभागियों के उत्साह और समर्पण को प्रदर्शित करते हुए 30 सेकेंड में एक पैराग्राफ पढ़ने वाले लोगों के सबसे बड़े वीडियो एल्बम का विश्व रिकॉर्ड बनाया है।

पुस्तक परिक्रमा– मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत पूरे देश में दूरदराज के क्षेत्रों में किताबें उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता रहा है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, एनबीटी–इंडिया ने अरुणाचल प्रदेश, असम, ओडिशा, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित स्थानों पर मोबाइल पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

नदी आधारित पुस्तक परिक्रमा

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने नदी–आधारित पुस्तक परिक्रमा का आयोजन किया, साहित्य में विविध अभिव्यक्तियों को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय और मुख्यधारा के लेखकों का समर्थन करने के लिए प्रमुख नदियों के किनारे राज्यों का दौरा किया। पांच परिक्रमा–कावेरी पुस्तक परिक्रमा (2 5 सितंबर से 21 अक्टूबर 2022), गंगा पुस्तक परिक्रमा। (3 अक्टूबर से 22 दिसंबर 2022), ब्रह्मपुत्र पुस्तक परिक्रमा (7 नवंबर से 24 दिसंबर 2022), कृष्ण पुस्तक परिक्रमा (12 दिसंबर 2022 से 24 जनवरी 2023), और महानदी नदी बेसिन पुस्तक परिक्रमा (20 जनवरी से 22 फरवरी 2023) अब तक आयोजित की गई हैं, जिससे वार्ता, रचनात्मक कार्यक्रमों और स्थानीय स्कूलों के साथ सहयोग के माध्यम से नदियों और साहित्यिक विरासत के बारे में जागरूकता पैदा की जा चुकी है।

पहल

विश्व का पहला फ्री एयरपोर्ट रीडिंग लाउंजः नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत ने वाराणसी में भारत का पहला निःशुल्क एयरपोर्ट रीडिंग लाउंज स्थापित किया, जो आगंतुकों को पुस्तकों के विविध संग्रह तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करता है। शहर के सार को दर्शाते हुए, लाउंज में सभी आयु वर्ग के पाठकों के लिए भारतीय संस्कृति, इतिहास, पारंपरिक ज्ञान और बहुत कुछ विषयों पर किताबें हैं। इसमें लंबी बेंच, बच्चों के लिए कम ऊंचाई वाले स्टूल, एलईडी स्क्रीन और एनबीटी–इंडिया की फ्लोटिंग लाइब्रेरी पहल से प्रेरित रीडिंग बोट जैसे तत्व भी शामिल हैं।

रीड इंडिया–लीड इंडिया अभियानः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, इंडिया द्वारा 'रीड इंडिया लीड इंडिया अभियान' का उद्घाटन तेलंगाना के माननीय राज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन ने 15 मई, 2023 को राजभवन, हैदराबाद में किया। इस अभियान में स्कूली छात्रों को राजभवन, हैदराबाद में इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग सत्र और करियर परामर्श में शामिल किया गया।

पुस्तकालय महोत्सव में सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रोटोटाइपः एनबीटी–इंडिया ने पुस्तकालय महोत्सव 2023 में पुस्तकालयों के विकास और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने और भारत में पढ़ने की संस्कृति विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप सार्वजनिक पुस्तकालयों के एक मॉडल का अनावरण किया। 'आजादी का अमृत महोत्सव' समारोह

के अनुरूप, मॉडल लाइब्रेरी ने तकनीकी पहलुओं, ऑडियोबुक और ई–पुस्तकों के लिए समर्पित खंड, ऑनलाइन इंटरैक्टिव कक्षाएं और विभिन्न भाषाओं में संग्रह प्रदर्शित किए। एनबीटी–इंडिया एक क्यूरेटेड पंचायत पुस्तकालय कैटलॉग के साथ–साथ गांवों और नगरपालिका वार्डों में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना पर एक श्वेत पत्र के साथ राज्यों को परामर्श सहायता प्रदान कर रहा है।

राजा राममोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर (आईएसबीएन)

अंतर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या (आईएसबीएन) किताबों, पर्चे, शैक्षिक किट, माइक्रोफॉर्म, सीडी–रोम और अन्य डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशनों जैसे मोनोग्राफिक प्रकाशनों के लिए एक अद्वितीय संख्यात्मक पहचानकर्ता है। दिनांक 1 जनवरी 2007 से, राष्ट्रीय आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसियां आईएसबीएन प्रदान कर रही हैं जिसमें 13 अंक होते हैं (पहले यह 10 अंक थे) जिसमें निम्नलिखित तत्व शामिल हैं:

1. जीएस1 तत्व
2. पंजीकरण समूह तत्व
3. पंजीकरण वस्तु
4. प्रकाशन तत्व
5. चेक डिजिट

आईएसबीएन ने लंबे ग्रंथ सूची वर्णनात्मक अभिलेख को संभालने की जगह ले ली है, जिससे समय और कर्मचारियों की लागत की बचत होती है और प्रतिलिपि बनाने की त्रुटियों में कमी आती है। आईएसबीएन का सही उपयोग किसी पुस्तक के विभिन्न उत्पाद रूपों और संस्करणों को स्पष्ट रूप से विभेदित करने की अनुमति देता है, चाहे वह मुद्रित हो या डिजिटल, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्राहकों को वह संस्करण प्राप्त हो जिसकी उन्हें आवश्यकता है। आईएसबीएन पुस्तक–व्यापार निर्देशिकाओं और ग्रंथ सूची डेटाबेस जैसे पुस्तकों–इन–प्रिंट के कैटलॉग के संकलन और अद्यतन की सुविधा प्रदान करता है। उपलब्ध पुस्तकों की जानकारी आसानी से मिल सकती है। एक पंजीकरण समूह के भीतर आईएसबीएन प्रणाली का प्रशासन आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी की जिम्मेदारी है और भारत के मामले में, यह आईएसबीएन (आरआरआरए) के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी है जो वर्तमान में जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली में स्थित है। आईएसबीएन पंजीकरण एजेंसी प्रकाशकों को वे सभी प्रकार के मार्गदर्शन प्रदान करती है जिनकी उन्हें आईएसबीएन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है.आईएसबीएन के लिए राजा राममोहन राय राष्ट्रीय एजेंसी प्रकाशकों, लेखकों, सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों आदि को आईएसबीएन आवंटित करती है, जो भारत में स्थित हैं।

समय के साथ, प्रकाशन उद्योग की वृद्धि और आईएसबीएन के बारे में जागरूकता के साथ, आईएसबीएन जारी करने के अनुरोधों में तेजी से वृद्धि हुई है। एजेंसी के प्रचालन को सुप्रवाही बनाने के लिए समय–समय पर प्रयास किए गए हैं जो पूरे देश के आवेदकों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। तदनुसार, प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, आईएसबीएन का आवंटन वेब पोर्टल http://isbn.gov.in के माध्यम से पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया गया है। इस प्रकार, 30 अप्रैल 2016 से, सभी आईएसबीएन आवेदनों को केवल ऑनलाइन पोर्टल के प्रक्रमित किया जा रहा है और प्रक्रिया को अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय आईएसबीएन एजेंसी, लंदन के मानदंडों के अनुरूप, मौजूदा पोर्टल को नया रूप दिया गया है और जुलाई 2023 से अस्तित्व में आया है। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान, पोर्टल पर 12178 से अधिक नए उपयोगकर्ता पंजीकृत किए गए हैं, आईएसबीएन जारी करने के लिए 25999 आवेदन प्राप्त हुए हैं और प्रकाशकों, लेखकों और सेमिनारों को उनके शीर्षकों के खिलाफ 362989 आईएसबीएन जारी किए गए हैं। आवश्यकता/उपयोग के आधार पर, 1 जनवरी 2023

से 31 दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के तहत आवंटित आईएसबीएन की संख्या इस प्रकार है:—

श्रेणी	विभिन्न श्रेणियों को आवंटित आईएसबीएन की संख्या/ आईएसबीएन/ब्लॉक
प्रकाशकों को 10 आईएसबीएन का ब्लॉक आवंटित किया गया	4297
प्रकाशकों को 100 आईएसबीएन का ब्लॉक आवंटित किया गया	247
प्रकाशकों को 1000 आईएसबीएन का ब्लॉक आवंटित किया गया	96
लेखकों द्वारा संगोष्ठियों और सम्मेलनों सहित स्वयं प्रकाशन	8239
प्रकाशकों के लिए एकल संख्या	1585

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड

एडसिल (इंडिया) लिमिटेड शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। एडसिल को भारत सरकार द्वारा श्रेणी – 1 मिनी–रत्न का दर्जा दिया गया है। एडसिल भारत और विदेशों में शिक्षा और मानव संसाधन विकास मूल्य श्रृंखला में परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। एडसिल ने पिछले पांच वर्षों में वित्त वर्ष 22–23 में 439 करोड़ रुपये तक पहुंचने वाले कारोबार में तेजी से वृद्धि दर्ज की है। उक्त अवधि के लिए पीएटी भी बढ़कर 64 करोड़ रुपये हो गया है। अपने कार्य सिद्धांतों, व्यवस्थित दृष्टिकोण और संबंधित क्रेडेंशियल्स के आधार पर, एडसिल ने आईएसओ 9001–2015 और 14001–2015 प्रमाणपत्र प्राप्त किए।

एडसिल के ग्राहक समूह में केंद्र और राज्य सरकार के विभाग, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय और राज्य पीएसयू और आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति सहित स्वायत्त निकाय शामिल हैं। कंपनी ने विदेशों में कई परियोजनाओं को निष्पादित किया है, जिसमें हाल ही में मॉरीशस के स्कूलों में कक्षा I, II, III और IV के बच्चों के लिए ईडीएलपी (अर्ली डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम) शामिल है, जो शुरू में भारत सरकार द्वारा और बाद में मॉरीशस सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

एडसिल वर्तमान में भारत में अध्ययन करने के लिए अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करने के लिए "स्टडी इन इंडिया" नामक भारत सरकार की प्रमुख योजना को कार्यान्वित कर रहा है। एडसिल ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईएम आदि सहित उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में सलाहकार तकनीकी सहायता सेवाएं प्रदान करने की मुख्य विशेषज्ञता का लाभ उठाया है। इसके अलावा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त संस्थानों और इसी तरह के संगठनों के लिए मूल्यांकन, परीक्षाओं और भर्ती से संबंधित परियोजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी तरीके से लागू किया जाएगा। सभी स्तरों पर भर्ती ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाती है जो समयबद्धता, पारदर्शिता और समानता के पहलुओं को संचालित करती है। एडसिल ने बड़े पैमाने पर स्कूल स्तर पर डिजिटल शिक्षा समाधानों जैसे स्मार्ट क्लासरूम, वर्चुअल क्लासरूम, आईसीटी लैब, लैंग्वेज लैब्स और व्यावसायिक प्रयोगशालाओं की आपूर्ति, स्थापना और स्थापना के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम समाधानों का उपयोग करके शिक्षा का लाभ उठाया है।

सर्विस स्पेक्ट्रम

एडसिल शिक्षा क्षेत्र में अवधारणा से प्रवर्तन तक टर्नकी आधार पर एंड–टू–एंड परियोजनाएं संचालित करता है और निरंतर निगरानी के माध्यम कर उद्देश्यों की पहचान से गतिविधियों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित है जिससे निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों की इष्टतम पूर्ति होती है।

एडसिल ने कंपनी के लिए एक मजबूत राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए तीन दशकों में प्राप्त विशेषज्ञता, मजबूत गठजोड़ और समर्पित टीमों की प्रतिबद्धता का लाभ उठाया है। इनसे शिक्षा और मानव संसाधन विकास के सभी क्षेत्रों में इसकी प्रमुख क्षमता सुदृढ़ हुई है। एडसिल की प्रमुख सेवाओं को वर्तमान में निम्नानुसार वर्गीकृत किया गया है:

- ऑनलाइन परीक्षण और मूल्यांकन सेवाएं (ओटीएएस)
- सलाहकार सेवाएं (एएस)
- डिजिटल शिक्षा सेवाएं (डीईएस)
- शैक्षिक खरीद सेवाएं (ईपीएस)
- विदेशी शिक्षा सेवाएं (ओईएस)
- तकनीकी सहायता समूह (टीएसजी)।

❖ ❖ ❖

05

योजनाएं और कार्यक्रम

योजनाएं और कार्यक्रम

विश्व स्तरीय संस्थान योजना

- **प्रतिष्ठित संस्थान**

  बजट घोषणा के अनुसार, सरकार ने 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 और निजी क्षेत्र से 10) को श्इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंसश नामक विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित करने/उन्नयित करने के लिए नियामक वास्तुकला प्रदान करने की योजना अनुमोदन किया। सार्वजनिक संस्थानों के लिए यूजीसी (सरकारी संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों के रूप में घोषणा) दिशानिर्देश, 2017, यूजीसी (इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) विनियम, 2017 और यूजीसी (इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज) (संशोधन) विनियम, 2021 के रूप में नियामक वास्तुकला प्रदान की गई है।

- **योजना की स्थिति**

  यूजीसी और अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (ईईसी) की सिफारिशों पर शिक्षा मंत्रालय ने इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (आईओई) के रूप में घोषणा के लिए कुल 20 संस्थानों (10 सार्वजनिक और 10 निजी) का चयन किया था। मंत्रालय ने अब तक 08 सार्वजनिक संस्थानों को उत्कृष्ट संस्थानों और 04 निजी संस्थानों को उत्कृष्ट सम–विश्वविद्यालय संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया है।

- **सहायता अनुदान जारी**

  वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, 08 प्रतिष्ठा सार्वजनिकसंस्थानोंअर्थातआईआईटी–दिल्ली, आईआईटी – बॉम्बे, आईआईएससी – बैंगलोर, आईआईटी – मद्रास, आईआईटी – खड़गपुर, हैदराबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए 1276.50 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

- **वैश्विक रैंकिंग**

  क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग–2024 में, 06 प्रतिष्ठित सार्वजनिक संस्थानों अर्थात् आईआईटी – बॉम्बे, आईआईटी – दिल्ली, आईआईएससी – बैंगलोर, आईआईटी – मद्रास, आईआईटी – खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय ने वैश्विक शैक्षणिक संस्थानों के शीर्ष –500 में रैंक हासिल की है।

भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस):

एआईसीटीई में शिक्षा मंत्रालय के आईकेएस प्रभाग की स्थापना भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के सभी पहलुओं पर अंतः विषय और ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान को बढ़ावा देने और आगे के शोध और सामाजिक अनुप्रयोगों के लिए आईकेएस ज्ञान को संरक्षित और प्रसारित करने के लिए की गई थी। आईकेएस प्रभाग आईकेएस केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है तथा वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है, और आईकेएस में अंतःविषय और ट्रांसडिसिप्लिनरी अनुसंधान, संकाय – विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, पाठ खनन और प्रलेखन परियोजनाओं के संचालन के अलावा कई प्रसार गतिविधियों के साथ अन्य संस्थानों की साझेदारी में स्नातक छात्रों लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित करता है।

Impact of the IKS Division of MoE

- **53 centers**
- **88 research projects**
- **5200+ Internships**
- **80+ FDPs/workshops/conferences**
- **100+ scholarly publications**
- **1800+ books digitized**
- **IKSWiki started**
- **75+ Videos and AIR programs**
- **100 scholars being trained**
- **1500 UG/PG students trained**
- **2500 teachers trained**
- **>400,000+ general public outreach**
- **24+ cities in 23 states covered**

अप्रचलित परंपराओं का कायाकल्पः

आईकेएस प्रभाग का दृष्टिकोण समकालीन विश्व के लिए आईकेएस का कायाकल्प करना और मुख्यधारा में लाना है। आईकेएस प्रभाग का प्राथमिक लक्ष्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों और समकालीन ज्ञान प्रणालियों के बीच की खाई को पाटना है। केवल भारतीय ज्ञान प्रणालियों के अस्तित्व को स्वीकार करना पर्याप्त नहीं है; उन्हें हमारी शिक्षा अनुसंधान पारिस्थितिकी के ताने—बाने में पुनर्जीवित, कायाकल्प और एकीकृत किया जाना चाहिए। ऐसा करके, आईकेएस डिवीजन का उद्देश्य एक जीवित परंपरा को विकसित करना है जो नए ज्ञान सृजन को बढ़ावा देता है और भविष्य के नवप्रवर्तनकों और विद्वानों के विकास को प्रेरित करता है। दूसरे शब्दों में, आईकेएस प्रभाग न केवल सुश्रुत, आर्यभाषा और अन्य आचार्यों पर चर्चा करके संतुष्ट है; बल्कि सक्रिय रूप से एक पारिस्थितिकी बनाने का प्रयास करता है जो कई और सुश्रुतों और आर्यभक्तों को जन्म देगा।

वर्ष 2023—24 के दौरान आईकेएस प्रभाग की मुख्य उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- प्रतिभागियों को आईकेएस के संदर्भ में स्पष्ट, प्रभावशाली शोध प्रश्नों, उद्देश्यों और कार्यप्रणाली को तैयार करने और अंतःविषय प्रस्ताव तैयार करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिभागियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के कौशल से सुसज्जित करने के लिए, आईकेएस डिवीजन ने दिल्ली, इंदौर, हरिद्वार, छत्तीसगढ़, तिरुपति और हैदराबाद में स्थित शैक्षिक संस्थानों में 6 प्रस्ताव लेखन कार्यशालाएं आयोजित की हैं।
- आईकेएस प्रभाग ने आईआईटी इंदौर, कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, वेद विज्ञान गुरुकुलम और आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम में आईकेएस विषयों के विभिन्न गत क्षेत्र पर कार्यशालाएं आयोजित की हैं ताकि प्रतिभागियों को पारंपरिक ज्ञान के साथ जुड़ने के लिए व्यावहारिक अनुभव मिल सके।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दौरा। नरेंद्र मोदी द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023, नई दिल्ली में आईकेएस स्टॉल का अवलोकन करते हुए।

- आईकेएस प्रभाग ने सीएसआईआर–टीकेडीएल के सहयोग से पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, बौद्धिक संपदा और लोगों के अधिकारों पर कार्यशालाएं आयोजित कीं।
- गहन अन्वेषण के माध्यम से आईकेएस के विशिष्ट पहलुओं के लिए प्रतिभागियों की समझ को गहरा बनाने के लिए, आईकेएस प्रभाग ने आईआईडब्ल्यूसी बेंगलुरु, नेशनल कॉलेज बेंगलुरु, रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी मुंबई और एआईसीटीई नई दिल्ली में 4 सेमिनार आयोजित किए।
- आईकेएस प्रभाग ने आंध्र प्रदेश हीलर्स एसोसिएशन तिरुपति, चाणक्य विश्वविद्यालय बेंगलुरु और डेक्कन कॉलेज, एमआईटी पुणे में आईकेएस के विभिन्न विषयों पर 4 सम्मेलन आयोजित किए।
- समकालीन सेटिंग्स में आईकेएस के लिए राजदूत बनने के लिए ज्ञान और कौशल के साथ युवाओं को सशक्त बनाने के लिए, आईकेएस डिवीजन ने चिन्मय विश्व विद्यापीठ कोच्चि और आईआईटी रुड़की में आईकेएस पर 2 राष्ट्रीय युवा सम्मेलन आयोजित किए।
- पारंपरिक ज्ञान की समृद्धि और विविधता की समझ बनाने के लिए आगंतुकों के लिए एक व्यापक अनुभव बनाने के लिए, आईकेएस डिवीजन ने चेन्नई, अमृतसर, भुवनेश्वर और पुणे में आयोजित जी 20 शैक्षिक/कार्य समूह की बैठकों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। साथ ही काशी तमिल संगम, अखिल भारतीय शिक्षा समागम में प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

डॉ. अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में माननीय शिक्षा मंत्री के साथ उच्चाधिकार प्राप्त समिति के सदस्य

एक भारत श्रेष्ठ भारत

सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में दिनांक 31 अक्टूबर, 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सतत और संरचित सांस्कृतिक संपर्क का विचार प्रस्तुत किया था। इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम (ईबीएसबी) दिनांक 31 अक्टूबर 2016 को शुरू किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के आदान–प्रदान पर आम जनता के बीच एक समन्वित पारस्परिक जुड़ाव प्रक्रिया के माध्यम से "एकता को साकार करने के लिए विविधता" के जश्न के रूप में मनाता है। देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को भाषा, साहित्य, भोजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन, खेल आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक संरचित जुड़ाव विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है।

एक भारत श्रेष्ठ भारत श्संपूर्ण सरकारश दृष्टिकोण का प्रतीक है जिसके द्वारा कार्यान्वयन विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ किया जाता है। जबकि उच्च शिक्षा विभाग ईबीएसबी के लिए नोडल एजेंसी है, 28 राज्यों, 8 संघ राज्य क्षेत्रों और 14 केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों ने ईबीएसबी के तहत विविध कार्यक्रमों और अभियानों में भाग लिया है।

उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (एचईआई), रूसा द्वारा वित्तपोषित राज्य विश्वविद्यालयों /कॉलेजों और एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों, यूजीसी–विनियमित विश्वविद्यालयों आदि के माध्यम से ईबीएसबी के अंतर्गत कार्यकलापों का संचालन करता है। संस्थान छात्र बातचीत/आदान–प्रदान, शिक्षक आदान–प्रदान, युवा उत्सव, भाषा सीखने की कार्यशालाओं, ईबीएसबी दिवस का उत्सव, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी/पेंटिंग/वाद–विवाद प्रतियोगिताओं, युग्मित राज्यों के विभिन्न पहलुओं पर वेबिनार आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इस वर्ष, साहित्यिक,

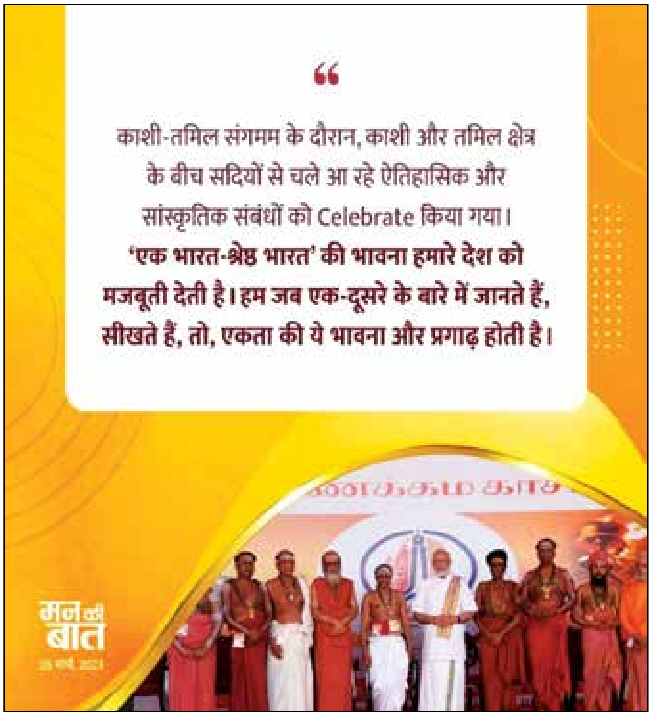

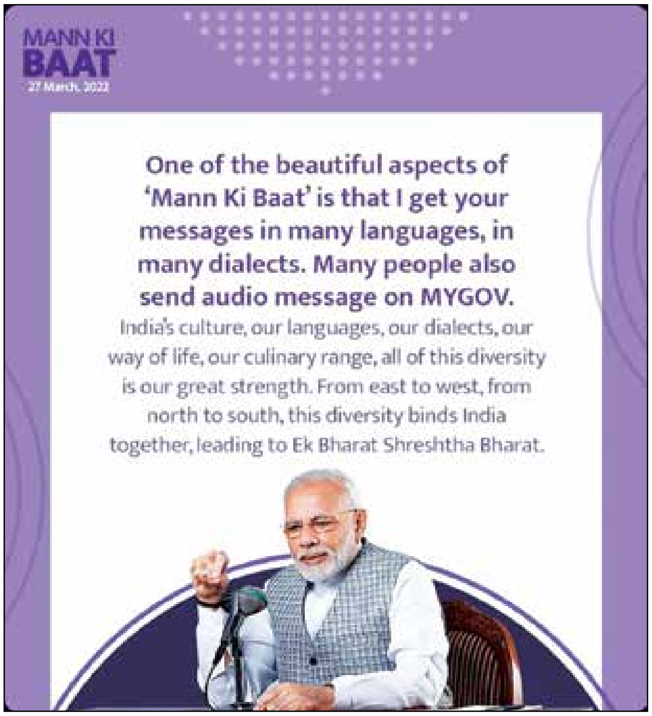

#MannKiBaat के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला।

सांस्कृतिक, खेल, पाक कला और छात्र आदान–प्रदान, ऑनलाइन गतिविधियों, क्विज़, वेबिनार, आदि की लगभग 150 गतिविधियों का संचालन एचईआई द्वारा पंद्रह हजार छात्रों की भागीदारी के साथ किया गया था।

2023 में ईबीएसबी के तहत की गई पहलों की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं:

युवा संगम

वर्ष 2023 में विभिन्न राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के युवाओं के बीच लोगों को मजबूत करने, जुड़ाव और सहानुभूति पैदा करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, सूचना; प्रसारण, युवा मामले; खेल, गृह मामले, उत्तर–पूर्व क्षेत्र विकास विभाग (डोनर) और आईआरसीटीसी जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत श्युवा संगमश पहल शुरू की।

अनुभवात्मक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने और भारत की समृद्ध विविधता के ज्ञान को प्रत्यक्ष आधार पर आत्मसात करने के साथ–साथ युवा संगम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 से जोड़ा गया है। यह अपने मूल में विविधता के उत्सव के साथ एक सतत सांस्कृतिक सह शैक्षिक आदान–प्रदान है जिसमें प्रतिभागियों को मेजबान राज्य में जीवन के विविध पहलुओं, प्राकृतिक भू–आकृतियों, विकास स्थलों, हाल की उपलब्धियों और युवा जुड़ाव का एक व्यापक अनुभव प्राप्त होता है। युवा संगम के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से युग्मित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 5–7 दिनों के प्रशिक्षा दौरा आयोजित किए जाते हैं। इन यात्राओं के दौरान, प्रतिभागियों को पांच व्यापक क्षेत्रों   पर्यटन (पर्यटन), परंपरा (परंपरा), प्रगति (विकास), उद्योग (प्रौद्योगिकी) और परस्पर संपर्क (लोगों से लोगों को जोड़ने) के तहत बहु–आयामी प्रदर्शन मिलता है।

युवा संगम के तीन चरण वर्ष 2023 में पूरे हो चुके हैं और दिनांक 31.12.2023 तक एक और चल रहा है। पहले चरण के दौरान, 1178 युवाओं और समन्वयकों ने 21 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 29 सांस्कृतिक–सह–शैक्षिक यात्राओं में भाग लिया। दूसरे चरण के दौरान, 983 युवाओं और समन्वयकों ने 23 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करने वाले 20 दौरों में भाग लिया। चल रहे चरण–III में, दिनांक 31.12. 2023 तक 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए 850 युवाओं और समन्वयकों की भागीदारी के साथ 17 दौरे पूरे हो चुके हैं।

काशी तमिल संगमम:

काशी तमिल संगमम (केटीएस 2.0) के दूसरे संस्करण का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2023 से दिनांक 30.12.2023 तक वाराणसी के नमो घाट पर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रालयों और विभागों की भागीदारी के साथ श्संपूर्ण सरकारश दृष्टिकोण के साथ किया गया था। इस आयोजन में रेल मंत्रालय, आईआरसीटीसी, संस्कृति, पर्यटन, कपड़ा मंत्रालय और देव आयुक्तों के माध्यम से हथकरघा और हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, एमएसएमई, कॉयर बोर्ड के माध्यम से एमएसएमई और केवीआईसी, एमएसडीई, आई एंड बी, और उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों और वाराणसी प्रशासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

केटीएस का प्राथमिक उद्देश्य शिक्षा की दो प्राचीन स्थलों   काशी और तमिलनाडु के लोगों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित और मजबूत करना था। केटीएस को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जोड़ा गया था, जो भारतीय संस्कृति में निहित रहते हुए 21 वीं सदी की मानसिकता के साथ संरेखित आधुनिक पीढ़ी की खेती के महत्व को रेखांकित करता है।

07 श्रेणियों के तहत तमिलनाडु के 1435 प्रतिनिधियों [(i) छात्र (ii) शिक्षक (iii) पेशेवर (iv) आध्यात्मिक गुरुओं (v) किसान और कारीगर (vi) लेखक और (vii) व्यापारी और व्यापारी] को 8 दिवसीय यात्रा (4 दिनों के यात्रा समय सहित) पर वाराणसी और आस–पास के क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चुना गया था। सभी

मंत्रालयों और विभागों ने दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, हथकरघा, हस्तशिल्प, भोजन, साहित्य आदि के प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी स्टाल लगाए। नमो घाट पर स्थानीय उद्यमियों, व्यापारियों, कलाकारों और शिल्पकारों द्वारा संचालित लगभग 70 स्टॉल लगाए गए थे। इस पखवाड़े के दौरान 22 लाख रुपये से अधिक की बिक्री हुई। 17 दिसंबर 2023 को उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया।

उद्घाटन समारोह की मुख्य विशेषताएं:

- काशी तमिल संगमम 2.0 का उद्घाटन करने के अलावा, माननीय प्रधान मंत्री ने हाल ही में शुभारंभ की गई कन्याकुमारी–वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई
- माननीय प्रधानमंत्री ने 46 ब्रेल पुस्तकों का शुभारंभ किया जिसमें प्राचीन तमिल व्याकरण और साहित्य के कुल 8,113 पृष्ठों के 109 खंड शामिल हैं जैसे कि तोल्काप्पियम, पथुप्पट्टू, एट्टुथोकाई, थिरुक्कुरल, तमिल सिलाप्पाथिकारम और मणिमेगालाई महाकाव्य। यह पहली बार है जब ब्रेल लिपि में समृद्ध प्राचीन तमिल साहित्य को प्रकाशित करने के लिए इस स्तर का काम किया गया था। केन्द्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी) नेत्रहीनों को ब्रेल पुस्तकें निशुल्क वितरित करने की योजना बना रहा है।
- तमिलनाडु के प्रतिनिधियों के लिए हिंदी में दिए गए माननीय प्रधानमंत्री के भाषण के एक हिस्से का तमिल में पहला, वास्तविक समय और निर्बाध अनुवाद एक और मील का पत्थर था। यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भाषिनी डिवीजन द्वारा विकसित भाषिनी पब्लिक एड्रेस सिस्टम (बीपीएएस) का उपयोग करके किया गया था, जो एक एआई– संचालित भाषा अनुवाद प्रणाली है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के बोलने वालों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करती है।

मानीय प्रधानमंत्री ने 17 दिसंबर, 2023 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2.0 के उद्घाटन में भाग लिया

17 दिसंबर, 2023 को केटीएस 2.0 का उद्घाटन समारोह

काशी और तमिल क्षेत्र के बीच प्राचीन सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए काशी–तमिल संगमम का आयोजन किया गया है, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को उजागर करता है।

- उद्घाटन समारोह में लगभग 3000 लोगों (तमिलनाडु के प्रतिनिधियों, काशी के स्थानीय तमिलों, वाराणसी की आम जनता सहित) ने भाग लिया।

इस अवधि के दौरान, विभिन्न टीएन प्रतिनिधि समूहों के लिए सात शैक्षणिक सत्र आयोजित किए गए थे। सभी शामों में तमिलनाडु और काशी की संस्कृतियों को दर्शाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय (एनबीटी) ने प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं, कहानी कथन सत्र, इंटरैक्टिव सत्र, पैनल चर्चा, कविता पाठ आदि का आयोजन किया, जिसमें दो हजार से अधिक स्कूली छात्रों ने भाग लिया। नमो घाट पर करीब 2 लाख लोगों ने केटीएस 2.0 का दौरा किया।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान ईबीएसबी पैविलियन

एक भारत श्रेष्ठ भारत मंडप जिसमें अमृत काल में देश को आकार देने में 'सांस्कृतिक विविधता' के सार का प्रसार किया, को भारत मंडपम, नई दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के

अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दूसरे संस्करण के दौरान माननीय ईएम द्वारा युवा संगम पर कॉफी टेबल बुक का शुभारंभ किया गया

अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दूसरे संस्करण के लिए स्वयंसेवकों के रूप में आमंत्रित युवा संगम प्रतिनिधियों के साथ माननीय शिक्षा मंत्री

दौरान प्रदर्शनी में रखा गया था। ईबीएसबी स्टॉल ने ईबीएसबी कार्यक्रम के तहत हाल की पहलों को दर्शाते हुए 'स्ट्रेंथ इन यूनिटी' और 'टेकिंग प्राइड इन अवर लिगेसी' (पंच प्राण के जुड़वां तत्व) का प्रतीक बनाया। यह स्टॉल आगंतुकों के लिए हमारे देश के सांस्कृतिक ताने–बाने को इंटरैक्टिव, आकर्षक और मजेदार तरीके से प्रतिबिंबित करने के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसने युवा संगम उत्पादों की एक समृद्ध विविधता का भी प्रदर्शन किया, जिसे विशेष रूप से युवा संगम के तहत भाग लेने वाले नोडल संस्थानों द्वारा छात्रों के लिए अनुकूलित किया गया था। सोशल मीडिया अभियान "एक भारत संस्कृति संगम" भी 29 जुलाई 2023 को स्टॉल परिसर में शुरू किया गया था।

पूरे भारत से चुने गए लगभग 200 युवा संगम प्रतिनिधियों ने स्वयंसेवकों के रूप में समागम में भाग लिया और भारत में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की लंबाई और चौड़ाई को कवर करने वाले विषयगत सत्रों में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने समागम के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और कई विचारकों के साथ सार्थक बातचीत की और उन्हें अत्याधुनिक विचारों और अनुसंधान के संगम से अवगत कराया गया। माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 30 जुलाई 2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम में युवा संगम एक्सपोजर टूर के दौरान युवाओं की यात्रा और अनुभवों को कैप्चर करने वाली एक कॉफी टेबल बुक भी लॉन्च की गई।

एक भारत संस्कृति संगम

'एक भारत संस्कृति संगम' (ईबीएसएस) अभियान एनईपी, 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत शुरू किया गया था, अर्थात 29 जुलाई, 2023 को 18–30 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की संस्कृतियों, परंपराओं, कला रूपों के विभिन्न पहलुओं को सीखने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए और इस प्रकार ऐसा करने की प्रक्रिया में। 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना का संचार करना। ईबीएसएस अभियान के तहत, 4 श्रेणियों में युवाओं से भागीदारी आमंत्रित की गई थी (i) नृत्य (ii) गायन (iii) पेंटिंग और (iv) फोटोग्राफी।

अभियान ने युवाओं के बीच महत्वपूर्ण कर्षण प्राप्त किया और देश की विविधता की उनकी समझ और सूझ–बुझ को बढ़ाने में उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया क्योंकि उन्हें अपने गृह राज्य के अलावा किसी भी राज्य की कला का प्रदर्शन करने की आवश्यकता थी। अपने 3 महीने के पूरे कार्यकाल के दौरान, अभियान ने ईबीएसबी के ट्विटर/फेसबुक/इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पेजों पर 2.16 लाख से अधिक अभिप्रेरणा और जुड़ाव और कुल 705 प्रविष्टियों पर ₹ 1 लाख लाइक/वोट देखे। देश भर के प्रतिभागियों ने ईबीएसएस अभियान में भाग लिया और 26 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के कला रूप/संस्कृति/विविधता/प्रतिष्ठित स्थानों को प्रदर्शित करने की चुनौती ली। विजेताओं को प्रमाण पत्र और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया और एक भारत श्रेष्ठ भारत के सोशल मीडिया हैंडल पर भी दिखाया गया।

स्वच्छ भारत अभियान

- उच्चतर शिक्षा विभाग स्वच्छ भारत अभियान को कार्यान्वित करने के लिए स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत विभिन्न उपाय करता है। स्वच्छता कार्य योजना के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा 681.45 लाख रुपये की कुल लागत से स्वच्छता से संबंधित प्रौद्योगिकियों के विकास से संबंधित चौदह परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2022–23 में इन परियोजनाओं के लिए ₹ 239.4 लाख रुपये जारी किए गए थे।
- उच्चतर शिक्षा विभाग, इसके स्वायत्त निकायों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में 1–15 सितंबर 2023 तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया, जिसमें 11,000 से अधिक छात्रों और संकाय/गैर–संकाय सदस्यों ने पखवाड़ा की गतिविधियों में भाग लिया।

- आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को श्एक तारीख एक घंटाश नामक एक अभियान का आयोजन किया गया था, जिसमें कचरा मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रमदान गतिविधियों में 1,37,602 छात्रों/संकाय/आम जनता की जनभागीदारी के साथ देश भर के उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा 1982 गतिविधियाँ आयोजित की गई।

आज़ादी का अमृत महोत्सव

वर्ष 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभाग के स्वायत्त निकायों, अधीनस्थ कार्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा 3,400 से अधिक गतिविधियों का संचालन किया गया। उदार गतिविधियों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे मेक इन इंडिया: ए पाथ फॉर अचीविंग इनक्लूसिव ग्रोथ, आत्मनिर्भर भारत–आत्मनिर्भर भारत का विजन आदि पर प्रकाशनों से लेकर हर घर तिरंगा अभियान में भागीदारी से लेकर होटल प्रबंधन संस्थान द्वारा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में चाट की अधिकतम किस्मों के पंजीकरण तक शामिल थे।

विभाग ने भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक राष्ट्रव्यापी और लोगों के नेतृत्व वाली "जन भागीदारी" पहल टैगलाइन मिट्टी को नामन, वीरों का वंदन के साथ "मेरी माटी मेरा देश (एमएमएमडी)" अभियान में भी भाग लिया। 184 उच्चतर शिक्षा संस्थानों के 40,000 से अधिक छात्रों और 3,000 शिक्षकों ने पौधे लगाने, स्वतंत्रता सेनानियों (वीरों का वंदन) को चर्चा, तात्कालिक और बहस के माध्यम से सम्मानित करने, पंच प्राण शपथ समारोह सहित कई गतिविधियों में भाग लिया।

अभियान की अवधि के दौरान आयोजित की जा रही 7,000 से अधिक गतिविधियों के साथ आजादी का अमृत महोत्सव समारोह में उच्चतर शिक्षा विभाग के योगदान को स्वीकार करते हुए, इस विभाग को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत पुरस्कार (सभी मंत्रालयों/विभागों में तीसरा) से सम्मानित किया गया।

उन्नत भारत अभियान

उन्नत भारत अभियान (यूबीए) को देश में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को समाज और गांवों से जोड़ने के लिए सितंबर 2014 में शुरू किया गया था। इससे उच्चतर शिक्षा संस्थानों के छात्रों और शिक्षकों को अकादमिक क्षेत्र में मिलने वाले किताबी ज्ञान के अतिरिक्त व्यावहारिक ज्ञान/पारंपरिक ज्ञान भी उपलब्ध होगा। ज्ञान परिवर्तन कुंजी है और यह योजना युवाओं तक हमारी समृद्ध संस्कृति की पहुंच सुनिश्चित करती है। चयनित उच्चतर शिक्षा संस्थान मौजूदा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों की पहचान और चयन पर भी काम करते हैं, प्रौद्योगिकियों के अनुकूलन को सक्षम करते हैं, या समाधान के नवाचार के लिए कार्यान्वयन विधियों को तैयार करते हैं, जैसा कि आम लोगों द्वारा आवश्यक है।

विजन: उन्नत भारत अभियान एक समावेशी भारत की वास्तुकला के निर्माण में मदद करने और देश के शैक्षणिक और अनुसंधान कार्यक्रमों में एक आदर्श बदलाव लाने के लिए स्थितियों में ज्ञान का लाभ उठाकर ग्रामीण विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तनकारी परिवर्तन की दृष्टि से प्रेरित है।

मिशन: उपर्युक्त दृष्टि के अनुसार, उन्नत भारत अभियान निम्नलिखित को आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा:

i. शैक्षिक संस्थानों, कार्यान्वयन एजेंसियों (जिला प्रशासन/पंचायती राज संस्थानों) और जमीनी स्तर के हितधारकों के बीच आवश्यक तंत्र और उचित समन्वय विकसित करना ताकि क्षेत्र स्तर पर प्रभावी उपाय किया जा सके।

ii. उपयुक्त ग्रामीण समूहों का चयन करें और पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ प्रौद्योगिकियों और स्थानीय संसाधनों का उपयोग करके इन समूहों के समग्र विकास में प्रभावी ढंग से भाग लें, इस प्रक्रिया में पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करें,

विविध सरकारी योजनाओं का उपयोग करें, मौजूदा प्रौद्योगिकियों का अनुकूलित उपयोग करें और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार ज्ञान का उपयोग करें।

iii. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में शैक्षिक पाठ्यचर्या और अनुसंधान कार्यक्रमों को पुनः उन्मुख करना ताकि उन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के साथ संरेखित किया जा सके ताकि समग्र विकास लाया जा सके और गांवों/समाज के मुद्दों के बारे में छात्रों के ज्ञान को समृद्ध किया जा सके।

यूबीए उपलब्धियां और शक्ति:

- आज तक 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 17000+ गांवों के साथ लगभग 3590+ प्रतिभागी संस्थानों के नेटवर्क को अपनाया गया है। आईआईटी दिल्ली कार्यक्रम का राष्ट्रीय समन्वय संस्थान है।
- विभिन्न राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा समन्वित विषय–विशिष्ट तकनीकी समाधान प्रदान करने के लिए 14 विषय विशेषज्ञ समूह (एसईजी) बनाए गए थे।
- वेब आधारित रिपो टग, पंजीकरण पोर्टल और अस्थायी एसईजी पोर्टल विकसित https://unnatbharatabhiyan.gov.in
- प्रतिभागी संस्थानों द्वारा गांव में 321 प्रौद्योगिकीय उपाय किए जा रहे हैं।
- वित्त वर्ष 2023–24 में 1752 नए/अनुकूलित एसईजी प्रस्ताव प्राप्त हुए और वर्तमान में उनका मूल्यांकन किया जा रहा है।
- देश भर में फैले 45 क्षेत्रीय समन्वय संस्थानों (आरसीआई) (प्रत्येक राज्य में कम से कम 1 या अधिक) का गठन किया गया।
- पिछले 5 वर्षों में, जिला प्रशासन के सहयोग से ग्रामीण आजीविका और समग्र विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रबंधन और सामाजिक उपाय के लिए एनसीयूआई, एमओआरडी एंड पीआर, सीएसआईआर, नेक्टर, ट्राइफेड, विभा, रोटरी, एफआईएसएस आदि के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- हाल ही में यूबीए के प्रयासों से, यूजीसी ने यूजी और पीजी छात्रों के लिए "कम्यूनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉसिबिलिटी" नामक दो–क्रेडिट पाठ्यक्रम को स्वीकृति दे दी है। इस पाठ्यक्रम के लिए देश भर में उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु सात क्षेत्रीय मास्टर प्रशिक्षण संस्थानों/विश्वविद्यालयों की पहचान की गई है।
- एआईसीटीई ने बी टेक डिग्री कोर्स के एक हिस्से के रूप में 100 घंटे की ग्रामीण इंटर्नशिप भी की है।

मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमएमटीटीपी)

पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी) की केंद्रीय क्षेत्र योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य हमारे शिक्षकों और शिक्षण में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देकर सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस योजना ने दिनांक 31.03.2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। इस योजना के तहत कुल 98 केंद्र/घटक (एआरपीआईटी, एलईएपी और एफआईपी कार्यक्रमों सहित) स्थापित किए गए हैं और इन संस्थानों को अब तक 434.78 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इस योजना के अंतर्गत कुछ उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- कुल विकसित बुनियादी ढांचा – 119 भवनों/प्रयोगशालाओं/स्टूडियो/कक्षाओं की स्थापना और खरीदे गए उपकरण।

एमएमटीटीपी (पूर्ववर्ती पीएमएमएमएनएमटीटी) का पुनः शुभारंभ 05.09.2023 को

- कुल लाभार्थी– 5737 शिक्षकों सहित 11.39 लाख संकायों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण मोड के माध्यम से एसओई पूर्व–सेवा कार्यक्रमों (बी.एड एवं एम.एड) से स्नातक किया गया है
- कवर किए गए पूर्वोत्तर राज्यों सहित कुल राज्य– 23
- टीचर इनोवेटर अवार्ड 2018 में शिक्षण–अधिगम क्षेत्र में उनके नवाचार के लिए पांच शिक्षकों को पुरस्कृत करने और सुविधा प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। इन शिक्षकों को देश से प्रतिस्पर्धी आधार पर चुना गया था। यह पुरस्कार योजना के नवाचार पुरस्कार घटक के तहत स्थापित किया गया था।
- कोविड समय के दौरान 1303 ऑनलाइन गतिविधियों ने विभिन्न ऑनलाइन कार्यशालाओं, वेबिनार, वीडियो व्याख्यान, संकाय विकास कार्यक्रमों, ऑनलाइन प्रशिक्षण, वेबिनार श्रृंखला, ऑनलाइन हैंड्स–ऑन ट्रेनिंग, वर्चुअल टॉक सीरीज, सर्टिफिकेट कोर्स, इंडक्शन ट्रेनिंग/फैकल्टी ओरिएंटेशन और वर्चुअल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 4.42 लाख प्रतिभागियों को लाभान्वित किया।
- अर्पित 2020 के लिए, 48 विषय–विशिष्ट पाठ्यक्रमों के लिए कुल नामांकन 80,328 है और कुल 6172 उम्मीदवारों ने सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूरा किया।

पीएमएमएमएमटीटी 3.0 योजना के मूल्यांकन का प्रस्ताव सभी हितधारकों के साथ उचित परामर्श के बाद स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) के विचार के लिए प्रस्तुत किया गया था। एसएफसी ने दिनांक 19.08.2021 को आयोजित अपनी बैठक में पीएमएमएमएमटीटी योजना को 493.68 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों अर्थात 2021–2022 से 2025–26 तक जारी रखने की सिफारिश की है।

अब, पीएमएमएमएनएमटीटी केंद्रों और यूजीसी एचआरडीसी को श्मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमश (एमएमटीटीपी) के रूप में इसके बदले हुए नामकरण के साथ एकीकृत करके पीएमएमएमएनएमटीटी योजना की फिर से परिकल्पना की गई है और वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2025–26 के लिए 361,59,20,880/– रुपये के कुल परिव्यय के साथ कौशल भवन, नई दिल्ली में दिनांक 05.09.2023 को फिर से शुरू किया गया है, जो पहले 493.68 करोड़ रुपये प्रस्तावित था। मिशन के तहत, मालवीय मिशन के एक भाग के रूप में 111 संस्थानों (66 एचआरडीसी

और 45 पीएमएमएमएमटीटी) की पहचान की गई है। इन केंद्रों को मालवीय मिशन केंद्र (एमएमसी) कहा जाएगा। कार्यक्रम को यूजीसी के सहयोग से निष्पादित किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान, उप–नोडल एजेंसियों को आगे संवितरण के लिए यूजीसी को 22.4 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा), जिसका नाम अब प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा) कर दिया गया है, एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) है, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा में रणनीतिक हस्तक्षेप शुरू करना है। यह मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों यानी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने और इक्विटी, पहुंच और उत्कृष्टता के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों को वित्त पोषित करने के लिए मिशन मोड में संचालित एक लक्षित योजना है। मंत्रालय से राज्य सरकारों के माध्यम से केन्द्रीय निधि संस्थाओं को जाता है। योजना के अंतर्गत निर्धारित मानदण्डों के आधार पर राज्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के महत्वपूर्ण मूल्यांकन के आधार पर राज्यों को सहायता का अनुमोदन किया जाता है।

योजना का पहला चरण (आरयूएसए 1.0) वर्ष 2013 में वर्ष 2013 से 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए शुरू किया गया था। योजना का दूसरा चरण (आरयूएसए 2.0) दिनांक 1.4.2017 से दिनांक 31 मार्च 2020 तक जारी रहा। अंतरिम विस्तार के आधार पर, योजना के पिछले चरणों की केवल प्रतिबद्ध देनदारियों की निर्मुक्ति 2023 के मध्य तक जारी रही। योजना के पिछले चरणों में, 14846.81 करोड़ रुपये की 2972 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से केंद्रीय हिस्सा 9867.33 करोड़ रुपये था।

उच्चतर शिक्षा के संदर्भ में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की महसूस की गई आवश्यकता की समीक्षा, योजना के कार्यान्वयन के दौरान उनके सामने आने वाले गुणों और मुद्दों की समीक्षा और एनईपी, 2020 के कार्यान्वयन की चल रही प्रकृति के आलोक में, योजना की भौतिक संरचना को संशोधित करने और योजना के कवरेज और दायरे को बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण 2023 के मध्य में शुरू किया गया है। पीएम–उषा की योजना को दिनांक 31 मार्च 2026 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को उनकी उच्चतर शिक्षा प्रणाली में पहुंच, इक्विटी और गुणवत्ता में सुधार के लिए सहायता करने के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया है।

पीएम–उषा को प्राथमिकता वाले जिलों जैसे योजना में पहचाने गए असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए संरचित किया गया है। राज्यों को प्राथमिकता वाले वाले जिलों की पहचान करने की छूट दी गई है। कम सकल नामांकन योजना, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या, महिला नामांकन आदि के आधार पर संकेन्द्रित जिलों के लिए सीमा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कुल जिलों का या तो 5 अथवा 50% है, इनमें से इनमें से जो भी अधिक हो। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच इसका निधियन पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में है और विधानमंडल वाले अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 का अनुपात है। विधानमंडल के बिना संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के तहत 100% केंद्रीय वित्त पोषित होंगे।

पीएम–उषा के उद्देश्य

1. मौजूदा राज्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों की समग्र गुणवत्ता में सुधार करने के लिए निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप उनकी अनुरूपता सुनिश्चित करना और गुणवत्ता आश्वासन ढांचे के रूप में मान्यता को अपनाना;

2. उच्चतर शिक्षा संस्थानों में स्वयं को अनुसंधान और नवाचारों के प्रति समर्पित करने के लिए अनुकूल वातावरण सृजित करना;

3. शहरी और अर्ध–शहरी क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले संस्थानों तक पहुंच बनाने और असेवित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में संस्थानों की स्थापना करके उच्च शिक्षा तक पहुंच में क्षेत्रीय असंतुलन को ठीक करना:

4. कम जीईआर, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), सीमावर्ती क्षेत्र के जिलों, आकांक्षी जिलों और उच्च एससी/एसटी आबादी वाले जिलों पर ध्यान केंद्रित करना; और

5. एसटीईएम, वाणिज्य और शिक्षा के मानविकी सहित बहु–विषयक शिक्षा पर ध्यान दें।

हाल ही में, परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की दो बैठकें आयोजित की गईं और पीएम–उषा के तहत उन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 5613.12 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिन्हें विभिन्न घटकों के तहत योजना के तहत शामिल किया गया है

राज्य में पीएम–उषा के रूप में आरयूएसए के तीसरे चरण के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुपालन पर शिक्षा मंत्रालय के साथ मेघालय सरकार की ओर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

पीएम–उषा के घटक:

क्र. सं.	घटक	इकाइयों की संख्या	इकाई लागत (रु. करोड़)	कुल राशि (रु. करोड़)
1	बहु–विषयी शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय (मे रु)	35 विश्वविद्यालय	100	3500
2	विश्वविद्यालयों को मजबूत करने के लिए अनुदान (मान्यता प्राप्त और गैर–मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय)	73 विश्वविद्यालय	20	1460
3	कॉलेजों (मान्यता प्राप्त और बिना मान्यता वाले कॉलेज) को मजबूत करने के लिए अनुदान	401 विश्वविद्यालय	5	2005
4	नया मॉडल डिग्री कॉलेज	40 नए मॉडल डिग्री कॉलेज	15	600
5	जेंडर समावेशन और समानता पहल	50 जिले	10	500
6	एमएमईआर अनुदान		राज्यों के लिए 1% और केंद्रीय एमएमईआर के लिए 1%	161.3

छात्रवृत्ति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 19.01.2022 के अपने निर्णय के तहत एक छात्र वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन [पीएम–यूएसपी, योजना] को दिनांक 31.03.2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृत दी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में तीन (3) केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं नामतः

- कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना;
- जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना;
- शिक्षा ऋण के लिए केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना और क्रेडिट गारंटी निधि योजना।

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक की अवधि की वित्तीय और वास्तिवक उपलब्धियों के साथ प्रत्येक योजना का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए पीएम–यूएसपी छात्रवृत्ति केंद्रीय क्षेत्र योजना

- **उद्देश्यः** इस योजना के तहत पात्र मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- **पात्रताः** वे छात्र आवेदन करने के पात्र हैं जो कक्षा XII में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20 प्रतिशत में आते हैं और जिनके परिवार की आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है।
- **कार्यक्षेत्रः** प्रत्येक वर्ष 82,000 नई छात्रवृत्तियाँ (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000) प्रदान की जाती हैं । इन्हें राज्य की 18–25 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है।
- **छात्रवृत्ति दरः** छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रति वर्ष तथा चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 20,000/– रुपये प्रति वर्ष है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** यह योजना दिनांक 1.1.2013 से डीबीटी के अंतर्गत शामिल है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में रु. वितरित की जाती है ।
- **ऑनलाइन पोर्टलः** सीएसएसएस ने दिनांक 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) शुरू कर दिया है। शैक्षणिक वर्ष 2015 से पात्र छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस वर्ष पोर्टल दिनांक 01.10.2023 को खोला गया था।
- **आरक्षणः** इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है। योजनागत मानदंडों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 15%, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें निर्धारित की गई हैं तथा बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों के लिए क्षैतिज आरक्षण दिया गया है।
- **नई पहलें**

  I. नोडल अधिकारियों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थान नोडल अधिकारियों/संस्थान प्रमुखों और राज्य नोडल अधिकारियों का बायोमेट्रिक अधिप्रमाणन किया जाएगा।

  II. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण के लिए लाभार्थियों का आधार मैपिंग अनिवार्य किया गया।

  III. वित्तीय वर्ष 2023–24 से सभी छात्रवृत्ति भुगतान आधार के माध्यम से किए जाएंगे।

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक छात्रवृत्ति के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है: –

सीएसएसएस के तहत वितरित छात्रवृत्ति (दिनांक 01–0.1–2023 से 31–12–2023 तक)			
क्र. सं.	**राज्य/बोर्ड का नाम**	**छात्रवृत्तियों की संख्या**	**राशि करोड़ में**
1	आंध्र प्रदेश	3855	5.49
2	असम	73	0.10
3	बिहार	10056	12.19
4	सीबीएसई	4852	6.35
5	छत्तीसगढ	1481	1.90
6	सीआईएससीई	49	0.06
7	गोवा	66	0.08
8	गुजरात	6072	7.49
9	हरियाणा	6269	8.03
10	हिमाचल प्रदेश	1329	1.61
11	जम्मू और कश्मीर	587	0.73
12	झारखंड	19	0.02
13	कर्नाटक	8167	9.99
14	केरल	5895	7.28
15	मध्य प्रदेश	9502	11.75
16	महाराष्ट्र	8159	10.20
17	मणिपुर	154	0.21
18	मेघालय	50	0.06
19	मिजोरम	1	0.00
20	नागालैंड	36	0.05
21	ओडिशा	3848	4.83
22	पुदुचेरी	93	0.13
23	पंजाब	2127	2.63
24	राजस्थान	10084	12.55
25	तमिलनाडु	9087	11.13
26	तेलंगाना	3219	4.36
27	त्रिपुरा	609	0.77
28	उत्तर प्रदेश	16513	20.33
29	उत्तराखंड	1195	1.51
30	पश्चिम बंगाल	8224	10.08
कुल:		**121671**	**151.91**

जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम–यूएसपी विशेष छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य:** जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (एस.एस.एस. फॉर जे. एंड.के. एंड लद्दाख) का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के युवाओं को इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर के शैक्षिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है,ताकि उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों से अंतक्रिया करने का अवसर मिलेगा,जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

- **पात्रता:** जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख के छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8.0 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है और जिन्होंने इन संघ राज्य क्षेत्रों से कक्षा 12वीं/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर या तो केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से आवंटित सीटों पर प्रवेश प्राप्त किया है, साथ ही जिन छात्रों ने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं ।

- **कार्यक्षेत्र:** प्रत्येक वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियाँ (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों को चुनने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अध्यधीन, सामान्य डिग्री की संख्या में कमी होने पर, स्लॉट की अंतर–परिवर्तनीयता का प्रावधान है।

- **छात्रवृत्ति दर:** ट्यूशन शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन

फीस के लिए छात्रवृत्ति की दर रु. 30,000 प्रति वर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए रु. 1.25 लाख प्रति वर्ष और मेडिकल पढ़ाई के लिए रु. 3.0 लाख प्रति वर्ष है। इस योजना के तहत सभी छात्रों को रु. 1.0 लाख प्रति वर्ष निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। इस योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख अंतर–मंत्रालयी समिति द्वारा की जाती है।

- **आरक्षणः** इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति को अपनाया गया है,अर्थात् अनुसूचित जाति के लिए 8%, अनुसूचित जनजाति के लिए 10% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 22%, आर्थिक और कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% और योजनाबद्ध मानदंडों के अनुसार बेंचमार्क विकलांगता वाले छात्रों के लिए और क्षैतिज आरक्षण निर्धारित है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** यह योजना डीबीटी के अंतर्गत आती है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में रु. वितरित की जाती है।
- **ऑनलाइन पोर्टलः** छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल– www.aicte-jk-scholarship.in/ ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- **नई पहलें:**
    1. एनआईटी, श्रीनगर द्वारा लाभार्थियों और उनके परिवारों पर योजना के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने के लिए प्रभाव अध्ययन शुरू किया गया है।
    2. एआईसीटीई द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान सभी इच्छुक छात्रों को सीयूईटी परीक्षा प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई और सीयूईटी जानकारी को शामिल करने के लिए पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन किए गए।
    3. छात्रों को एसएसएस छात्रों के लिए एनएसपी द्वारा आयोजित डी–डुप्लीकेशन प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया और छात्रों द्वारा दिए गए आवेदन पत्र में उनसे यह शपथ भी ली गई कि वे किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के प्राप्तकर्ता नहीं हैं।
    4. एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में सामान्य पाठ्यक्रमों की विविधता को शामिल करने के लिए, परिषद ने भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को इस योजना के तहत अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजे हैं।
    5. एआईसीटीई ने आधार अधिप्रमाणन के लिए सीडैक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान 7,123 छात्रवृत्तियाँ (नई + नवीकरण) प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को 211 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

पीएम–यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी और ऋण गारंटी योजना (सीएसआईएस)

- **उद्देश्य :** इस योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और दिव्यांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) का कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण से व्यावसायिक उच्चतर शिक्षा से वंचित न रहे कि वह गरीब है।

- **पात्रता** : राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआइ) द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक/तकनीकी कार्यक्रमों से व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे व्यावसायिक संस्थान/कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक निकाय से अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ब्याज सब्सिडी केवल एक बार अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है।
- **कार्यक्षेत्र** : इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस के उन सभी छात्रों को कवर करना है, जिनके माता–पिता/परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख प्रति वर्ष रुपये तक है।
- **लाभ** : इस योजना के तहत, भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से 10.0 लाख रुपए तक के शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।
- **डीबीटी** : ब्याज सब्सिडी दावों का वितरण छात्र के शिक्षा ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।
- **ऑनलाइन पोर्टल** : केनरा बैंक द्वारा सदस्य बैंकों को ब्याज सब्सिडी के दावे अपलोड करने में सक्षम बनाने के लिए प्रति वर्ष एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाता है।
- **नई पहलें** :

  1. बैंकों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब मासिक आधार पर खोला जाता है और दावों को समेकित किया जाता है। अभिलेखों के समेकन के बाद, सब्सिडी राशि समय पर जारी की जाती है। पोर्टल के पूरे वर्ष खुले रहने के कारण सब्सिडी का दावा न करने से संबंधित शिकायतों में भारी कमी आई है।
  2. सीएसआईएस 2022 के दिशा–निर्देशों के अनुसार, कुल ऋण सीमा को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये कर दिया गया है। इसलिए, इस वर्ष वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित दावों में 10.00 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं और बदले में योजना का कुल कवरेज बढ़ गया है।

सीएसआईएस योजना के तहत दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि तक लाभार्थी खातों में सफलतापूर्वक सं. वितरित कुल सब्सिडी निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

राज्य का नाम	कुल दावे	कुल सब्सिडी
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	56	0.11
आंध्र प्रदेश	12,240	27.83
अरुणाचल प्रदेश	18	0.03
असम	1,246	1.95
बिहार	16,609	36.35
चंडीगढ़	257	0.48
छत्तीसगढ	2,801	5.01
दादरा और नगर हवेली	9	0.02
दमन और दीव	10	0.02
दिल्ली	2,403	5.00
गोवा	527	1.55
गुजरात	4,101	9.93
हरियाणा	3,280	6.67
हिमाचल प्रदेश	1,654	2.70

राज्य का नाम	कुल दावे	कुल सब्सिडी
जम्मू और कश्मीर	4,086	6.52
झारखंड	5,782	12.59
कर्नाटक	68,657	105.74
केरल	64,434	108.43
लद्दाख	9	0.01
लक्षद्वीप	1	0.00
मध्य प्रदेश	17,467	35.34
महाराष्ट्र	34,364	54.87
मणिपुर	79	0.14
मेघालय	230	0.44
मिजोरम	44	0.09
नगालैंड	19	0.02
ओडिशा	9,882	17.82
पुदुचेरी	1,101	2.00
पंजाब	1,421	2.64
राजस्थान	7,061	15.90
सिक्किम	42	0.07
तमिलनाडु	67,419	96.73
तेलंगाना	3,235	7.04
त्रिपुरा	576	1.13
उत्तर प्रदेश	16,034	32.21
उत्तराखंड	2,633	4.75
पश्चिम बंगाल	8,688	18.68
कुल	**358,475**	**620.84**

शैक्षिक ऋण के लिए पीएम–यूएसपी क्रेडिट गारंटी फंड

यह योजना 17 सितंबर, 2015 को अधिसूचित की गई है। इस योजना के तहत, छात्रों द्वारा लिए गए अधिकतम 7.5 लाख रुपये के शिक्षा ऋण पर गारंटी बिना किसी संपार्श्विक सुरक्षा और तृतीय पक्ष की गारंटी के प्रदान की जाती है। यह निधि चूक की गई राशि के 75% तक गारंटी कवर प्रदान करती है। क्रेडिट गारंटी फंड के लाभ इस प्रकार हैं:

- इससे संस्थानों की गैर–निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) में कमी आएगी और अधिक तरलता उपलब्ध होगी, जिससे अधिक संख्या में उच्चतर शिक्षा के इच्छुक छात्र लाभान्वित होंगे, जिससे उच्च शिक्षा में जीईआर में वृद्धि में मदद मिलेगी।
- शैक्षिक उद्देश्य के लिए ऋण (आसान और लचीले ऋण सहित) देने में अधिक संस्थान आगे आएंगे और इससे सभी क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता आएगी।
- इससे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) में मामलों में भी कमी आएगी, हालांकि बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे क्रेडिट गारंटी फंड का आश्रय लेने से पहले सभी विकल्पों का आश्रय लें।

इस निधि की व्यवस्थापक, केंद्र सरकार है और नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) ट्रस्टी है। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान 200 करोड़ रुपये जारी किये जा चुके हैं।

नई पहलें

सीजीएफएसईएल के तहत 27 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को वित्तीय संस्थानों की सूची में शामिल किया गया है।

बाह्य छात्रवृत्ति:

शिक्षा मंत्रालय स्नातकोत्तर/अनुसंधान/पीएचडी करने के लिए सांस्कृतिक/शैक्षणिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के तहत विभिन्न देशों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति के लिए उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाता है। छात्रवृत्ति प्रस्ताव के प्रसार और व्यापक प्रचार के लिए, इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाता है और इसे यूजीसी, एआईसीटीई, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में भी प्रसारित किया जाता है। इच्छुक उम्मीदवारों को पोर्टल http://proposal.sakshat.ac.in@scholarship पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा ।

वित्तीय वर्ष 2022–23 में रु. चीनी सरकार छात्रवृत्ति प्रदान के लिए चयनित विद्वानों को हवाई टिकट प्रदान करने के लिए बाहरी छात्रवृत्ति के लिए 1.00 करोड़ रुपये (एक करोड़ रुपये) आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2023 (01.01.2023 से 31.12.2023 तक) के दौरान विभिन्न देशों/संस्थानों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति का विवरण नीचे दी गई तालिका में प्रदान किया गया है:

क्र. सं.	देश/संस्था का नाम	नामांकित उम्मीदवारों की संख्या	दानकर्ता देश/संस्था द्वारा चयनित
1.	चुलाभोर्न ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, थाईलैंड	3	*
2.	स्लोवेनियाई सरकार छात्रवृत्ति 2023/2024	1	1
3.	यूके	39	*

** दानकर्ता देश/संस्था द्वारा अभी तक सूचित नहीं किया गया*

उपर्युक्त छात्रवृत्तियों के लिए नामांकन के अतिरिक्त, मंत्रालय ने व्यापक प्रचार और भागीदारी के लिए अपने पोर्टल पर निम्नलिखित छात्रवृत्तियों की जानकारी भी प्रसारित की:

क्र. सं.	छात्रवृत्ति/फेलोशिप का नाम	निम्न के लिए उपलब्ध है
1.	इराक में अध्ययन कार्यक्रम 2023	एडवान्स्ड डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएचडी.
2.	अवर स्नातक, प्रौद्योगिकी महाविद्यालय और विशिष्ट प्रशिक्षण महाविद्यालय के लिए वर्ष 2024 के लिए जापानी सरकार (एमईएक्सटी) छात्रवृत्ति	जापान में पहले से ही अध्ययन कर रहे अवर स्नातक/कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी (केओएसईएन) के छात्र/जापान में किसी विशेष प्रशिक्षण कॉलेज में पोस्ट सेकेंडरी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्र
3.	शोध छात्रों के लिए वर्ष 2024 के लिए जापानी सरकार (एमईएक्सटी) छात्रवृत्ति	अनुसंधान/पीएचडी/मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम
4.	कासेत्सार्ट विश्वविद्यालय, बैंकॉक, थाईलैंड द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियाँ	स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएचडी.
5.	तुर्किये छात्रवृत्ति 2023	स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएचडी/अनुसंधान
6.	एसटीईएम में महिलाओं के लिए ब्रिटिश काउंसिल छात्रवृत्ति	केवल महिला आवेदकों के लिए एसटीईएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) विषयों में मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम
7.	चेक गणराज्य छात्रवृत्ति वर्ष 2023/2024	परास्नातक/पीएचडी.

नई पहलें

व्यापार संचालन की सहजता को ध्यान में रखते हुए छात्रवृत्ति प्रभाग ने रक्षा मंत्रालय के परामर्श से उन पाठ्यक्रमों के लिए उच्च अध्ययन हेतु, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं, विदेश जाने वाले सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए शिक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है।

भारत वापसी की प्रतिबद्धता नहीं (एनओआरआई)

जे–1 वीजा पर अमेरिका गए व्यक्ति को भारत वापसी की प्रतिबद्धता नहीं (एनओआरआई) प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। अमेरिकी अप्रवासन कानून के अनुसार, जे–1 वीजा धारकों को अपने एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम के अंत में कम से कम दो वर्ष के लिए अपने स्वदेश लौटना आवश्यक है। यदि कोई दो वर्ष की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्वदेश लौटने में असमर्थ है,तो उसे संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के दूतावास/वाणिज्य दूतावास से छूट प्राप्त करनी होगी। दूतावास को आप्रवासन के प्रयोजन के लिए "छूट प्रमाणपत्र" जारी करने में सक्षम बनाने के लिए, आवेदक के लिए मंत्रालय द्वारा संचालित किसी भी योजना के तहत किसी भी ऋण या छात्रवृत्ति या बांड के तहत किसी दायित्व के संबंध में शिक्षा मंत्रालय से 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' प्राप्त करना आवश्यक है।

दिनांक 27.02.2016 से आवेदकों को nori.ac.in पोर्टल पर 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने से पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा समय पर प्रदान की गई है। दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान, 1454 एनओसी जारी की गई हैं। व्यवसाय करने में सहजता में योगदान देने के अपने प्रयासों में, शिक्षा मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय दोनों को शिक्षा मंत्रालय से एनओआरआई प्रमाणपत्र जारी करने की आवश्यकता को खत्म करने के लिए लिखा है, जो केवल नॉन–मेडिकल और नो फार्मेसी श्रेणी के छात्रों के लिए जारी किया जाता है। रक्षा मंत्रालय इस पर सहमत हो गया है।

डिजाइन नवाचार के लिए राष्ट्रीय पहल (एनआईडीआई)

इस योजना का उद्देश्य देश भर के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, आईआईएससी, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों आदि में 20 डिजाइन नवाचार केंद्रों (डीआईसी), वन ओपन डिजाइन स्कूल (ओडीएस), एक राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क (एनडीआईएन) और प्रोजेक्ट ई–कल्प–III (2021) की स्थापना करके देश में डिजाइन और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना, उसका संपोषण करना और आगे बढ़ाना था, जिससे मानव जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण योगदान और सफलताएं मिलीं। इस योजना में हब और स्पोक मॉडल को अपनाया गया, जिसमें प्रमुख संस्थानों ने क्षेत्र स्तर पर संस्थानों की क्षमता का समन्वय और लाभ उठाते हुए मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया।

डिजाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी) – डीआईसी डिजाइन शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन डिजाइन में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को भी बढ़ावा देते हैं जो सामाजिक चुनौतियों, विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भव्य चुनौती वाले क्षेत्रों में के लिए नवीन समाधान तैयार करने के लिए उत्प्रेरक बन जाते हैं। उन्होंने फील्ड स्तर पर संस्थानों की क्षमता का समन्वय और लाभ उठाते हुए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करने वाले अग्रणी संस्थानों के साथ हब और स्पोक मॉडल को अपनाया।

ओपन डिज़ाइन स्कूल (ओडीएस) – ओडीएस विभिन्न सहयोगी शिक्षा कार्यक्रमों (शैक्षिक संस्थानों के व्यापक स्पेक्ट्रम को जोड़ते हुए) और इंटरनेट के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम निः शुल्क साझा करके देश में डिजाइन शिक्षा और अभ्यास की अधिकतम पहुंच सुनिश्चित करता है। आईआईटी बॉम्बे में ओडीएस की स्थापना की गई है।

राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार नेटवर्क (एनडीआईएन) – एनडीआईएन डिजाइन स्कूलों का एक नेटवर्क है जो उद्योग और शिक्षा जगत के अन्य अग्रणी संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और सरकार के साथ मिलकर काम करता है ताकि डिजाइन शिक्षा की पहुंच को बढ़ाया जा सके, सभी क्षेत्रों में डिजाइन नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और संस्थानों के बीच व्यापक सहयोगात्मक परियोजनाएं विकसित की जा सकें। आईआईएससी बैंगलोर में एनडीआईएन की स्थापना की गई है।

परियोजना ई–कल्प–III– 'ई–कल्प–III' परियोजना भारत में 'डिजाइन के लिए डिजिटल–शिक्षण वातावरण' बनाने के बारे में है और चार क्षेत्रों अर्थात विश्वविद्यालय, उद्योग, सरकार और अनौपचारिक क्षेत्र में ज्ञान संचय, भंडारण और प्रसार तथा शिक्षा पर केंद्रित है। ई–कल्प III परियोजना का मुख्य उद्देश्य शडिजाइन उपकरणश विकसित करना है जो छात्रों, शिक्षकों और पेशेवरों से युक्त डिजाइन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपयोगी हैं और अनौपचारिक क्षेत्र (जिनकी संख्या लाखों में है) के लोगों के डिजाइन कौशल को बढ़ाना है। आईआईटी बॉम्बे में 'ई–कल्प–III' की स्थापना की गई है।

वर्ष 2023 के दौरान :

- ''हेमाधार'' सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय में डीआईसी द्वारा विकसित पहली आयुर्वेदिक स्वामित्व वाली दवा है। यह दवा एनीमिया हेमनटिनिक, इम्युनिटी बूस्टर, रक्त शोधक, हेपेटोप्रोटेक्टिव, एंटी–ऑक्सीडेंट और एंटी–सिकलिंग के लिए है।
- जनजातीय लोगों के लिए बाइक एम्बुलेंस – डीआईसी– जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय– काकीनाडा द्वारा यह देखते हुए कि पारंपरिक चार पहिया एम्बुलेंस को दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए एक दोपहिया एम्बुलेंस डिजाइन की गई थी।
- योजना के एनआईडीआई डैशबोर्ड का विकास पूरा हो चुका है और मंत्रालय के अधिकारियों को इसका डेमो भी दिया जा चुका है।
- अखिल भारतीय डीआईसी मीट 2023 का आयोजन 6 फरवरी 2023 को डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में किया गया। इसमें छात्रों, संकायों, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों, अन्य मंत्रालयों के अधिकारियों सहित कुल प्रतिभागियों की संख्या लगभग 550 थी। इस बैठक में 18 डीआईसी हब, 28 स्पोक और 3 अन्य डीआईसी पहलों ने भाग लिया था।

    o **बैठक का एजेंडा:**

    - विभिन्न सरकारी पहलों (अर्थात एमएसएमई चैंपियन योजना, अटल इनोवेशन मिशन, उन्नत भारत अभियान, ग्रामीण प्रौद्योगिकी कार्य–समूह, जीआईएएन) के साथ जुड़े डीआईसी की प्रगति और विचारों का आदान–प्रदान।
    - कोविड के बाद डीआईसी की प्रगति और अन्य सरकारी योजनाओं डीआईसी के तालमेल का आकलन करना।
    - नवीन परियोजनाओं और स्टार्टअप्स की प्रदर्शनी।

    o बैठक में मंत्रालयों, विशेष रूप से मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों, विकास प्राधिकरणों सहित विभिन्न सरकारी संगठनों, शहरी स्थानीय निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अनुसंधान संस्थानों, बिजनेस हाऊसेस, कॉर्पोरेट्स, परामर्श संगठनों और उद्योग संघों सहित निजी संगठनों के अधिकारियों सहित 500 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

- डिज़ाइन इनोवेशन सेंटर (डीआईसी) स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, नई दिल्ली – ने 21 अगस्त 2023 को छात्रों, संकायों और कर्मचारियों के बीच एक आइडिया पिच–अप प्रतियोगिता आई.ई., "पिच कारी–2023" का आयोजन किया।
- डीआईसी, आरडी यूनिवर्सिटी, जबलपुर ने नीति आयोग से अटल कम्युनिटी इनक्यूबेशन सेंटर (एसीआईसी) परियोजना को सफलतापूर्वक प्राप्त किया, जिससे इसकी स्थिरता में योगदान मिला।
- रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (मध्य प्रदेश) में डीआईसी ने 2 पेटेंट प्रदान किए हैं :
  - एक नोबल एंडोफाइटिक फंगस "अल्टरनेरिया टेन्नुइसिमा" द्वारा सिल्वर नैनोकणों का हरित संश्लेषण पीजीएलरु 71– डॉ. हर्षिता शुक्ला और प्रोफेसर सरदूल सिंह संधू
  - "बीवरेजेस केटल" एक विशेष विद्युत उपकरण है जिसे मुख्य रूप से पानी को शीघ्र और कुशलता से गर्म करने के लिए बनाया गया है।

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन

यह शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहल है, जिसमें शुरू से ही बड़े पैमाने पर भागीदारी रही है। यह कल के नवोन्मेषकों या उद्यमियों के लिए आज से ही स्मार्ट इंडिया की ओर बढ़ने का दुनिया का सबसे बड़ा खुला मंच है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के विभिन्न संस्करणों से अब तक 20 लाख से अधिक छात्र प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं।

माननीय प्रधानमंत्री 19 दिसंबर, 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए

06

केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान

केंद्रीय विश्वविद्यालय और संस्थान

केंद्रीय विश्वविद्यालय

केंद्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त निकाय हैं जिनकी स्थापना अनुसंधान और शिक्षण सुविधाएं प्रदान करके, अंतःविषय अध्ययन और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में नवाचार प्रदान करके ज्ञान का सृजन और प्रसार करने के उद्देश्य से की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि ये विश्वविद्यालय स्वयं को उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में प्रदर्शित करेंगे और सामान्य रूप से समाज और उसके आसपास के शैक्षणिक संस्थानों के सर्वांगीण विकास में उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने संबंधित अधिनियम, संविधि और उसके तहत बनाए गए अध्यादेशों द्वारा शासित होते हैं।

वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के दायरे में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जिनमें तेलंगाना राज्य में नव स्थापित सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय भी शामिल है। उनमें से 46 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और लद्दाख में सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय को सीधे मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाता है।

तेलंगाना राज्य में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करके की गई है, जिसे दिनांक 07.12.2023 को लोकसभा और विशेष रूप से भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप भव्य चुनौती वाले क्षेत्रों में दिनांक 13.12.2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक को 17 दिसंबर 2023 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई और संबंधित अधिनियम, 2023 को भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खंड–1 में 18 दिसंबर 2023 को अधिनियम संख्या 36/2023 के रूप में प्रकाशित किया गया।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने भारत सरकार की विभिन्न पहलों जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत, परीक्षा पे चर्चा और स्वच्छ भारत अभियान, मेरी माटी मेरा देश और आज़ादी का अमृत महोत्सव – हर घर तिरंगा में सक्रिय रूप से भाग लिया है। इसके अलावा, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को समर्थ और स्वयम पहलों के सभी मॉड्यूल को लागू करने का भी निर्देश दिया गया।

केंद्रीय विश्वविद्यालय पूरी तरह से केंद्र सरकार के बजटीय समर्थन से वित्त पोषित हैं। वर्ष 2023–24 के दौरान (31.12.2023 तक) इग्नू को छोड़कर केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 8976.85 करोड़ रुपये (हेफा सहित) जारी किए गए। वर्ष 2023–24 के दौरान कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय और तेजपुर विश्वविद्यालय के कुलपतियों की नियुक्ति की गई।

इसके अलावा, वर्ष 2023–24 के दौरान, कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, असम विश्वविद्यालय, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, नागालैंड विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय और त्रिपुरा में भी कुलाधिपतियों की नियुक्तियां की गईं।

शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, विजयनगरम, आंध्र प्रदेश	2019
2		आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ट्रांजिट कैंपस जेएनटीयू आईटी इनक्यूबेशन सेंटर जेएनटीयू रोड अनंथपुरमु 515002	2019
3		राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति– 517507	2020
4	अरुणाचल प्रदेश	राजीव गांधी विश्वविद्यालय, रोनो हिल्स, पोस्ट ऑफिस दोईमुख, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश – 791 112	2007
5	असम	असम विश्वविद्यालय, पोस्ट ऑफिसः असम विश्वविद्यालय, सिलचर – 788 011	1994
6		तेजपुर विश्वविद्यालय, जिला सोनितपुर, पीबी नं.72, तेजपुर – 784 001	1994
7	बिहार	बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, बीआईटी परिसर, पी.ओ. – बी.वी. कॉलेज, पटना – 800 014	2009
8		महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कैंप कार्यालयः सर्किट हाउस के सामने, मोतिहारी, जिला – पूर्वी चंपारण, बिहार – 845 401	2016
9	छत्तीसगढ	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, मुख्य परिसर, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ – 495 009	2009
10	दिल्ली	जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, नई दिल्ली – 110025	1988
11		दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली – 110007.	1922
12		जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली – 110067	1969
13		इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – 110068	1985
14		केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जनकपुरी, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110058	2020
15		श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, कटवारिया सराय, कुतुब होटल के पास, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली–110067	2020
16	गुजरात	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, जलाराम मंदिर के पास, सेक्टर – 29, गांधीनगर – 382 029	2009
17	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नं. 21, धर्मशाला, जिला–कांगड़ा – 176215	2010
18	हरियाणा	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जांट–पाली गांव, महेंद्रगढ़, हरियाणा – 123 029	2009

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
19	झारखंड	झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय, रातू–लोहरदगा रोड, ब्राम्बे, रांची – 835 205, झारखंड।	2009
20	जम्मू और कश्मीर	कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय, ट्रांजिट कैंपसः सोनवार, जीबी पंत अस्पताल के पास, श्रीनगर – 190 005	2009
21		जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय, बगला (रहया.सुसुचानी), जिला सांबा, जम्मू – 181143, (जम्मू और कश्मीर)	2011
22	केरल	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, तेजस्विनी हिल्स, पेरिये, कासरगोड जिला, केरल 671316	2009
23	कर्नाटक	कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय, कदागांची, अलंद रोड, अलंद तालुक, गुलबर्गा – 585 311, कर्नाटक।	2009
24	लद्दाख	सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय	2022
25	मध्य प्रदेश	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मकालसदन, अमरकंटक – 484886	2007
26		डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर – 470003	2009
27	महाराष्ट्र	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, मानस मंदिर पीओ, वर्धा, महाराष्ट्र 442005	1997
28	मिजोरम	मिजोरम विश्वविद्यालय, पोस्ट बॉक्स नंबर 910, आइज़वाल – 796012	2000
29	मेघालय	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय, एनईएचयू कैंपस, शिलांग – 793022।	1973
30	मणिपुर	मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर, इंफाल – 795003	2005
31	नगालैंड	नागालैंड विश्वविद्यालय, परिसर कोहिमा – 797001, मुख्यालय लुमानी, नागालैंड	1989
32	ओडिशा	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय, सेंट्रल सिल्क बोर्ड बिल्डिंग, लैंडिगुडा, कोरापुट – 764 020	2009
33	पांडिचेरी	पांडिचेरी विश्वविद्यालय, आर. वेंकटरमन नगर, कालापेट, पुडुचेरी–605014	1985
34	पंजाब	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिटी कैंपस, मनसा रोड, बठिंडा–151 001	2009
35	राजस्थान	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनएच–8, बंदर सिंदरी, जिला–अजमेर – 305 801	2009
36	सिक्किम	सिक्किम विश्वविद्यालय, 6 वां माइल, समदुर, पीओ ताडोंग, गंगटोक –737102	2007
37	तमिलनाडु	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, नीलाकुडी परिसर, कंगलानचेरी (पोस्ट), तिरुवरुर – 610101	2009

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम	स्थापना वर्ष
38	तेलंगाना	हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद – 500046	1974
39		मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, गाचीबोवली, हैदराबाद – 500032	1998
40		अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय परिसर, हैदराबाद– 500007	2007
41		सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय	2023
42	त्रिपुरा	त्रिपुरा विश्वविद्यालय, सूर्यमणिनगर, अगरतला – 799130	2007
43	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ –202002.	1920
44		बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, विद्याविहार, रायबरेली रोड, लखनऊ – 226025	1996
45		बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी – 221 005.	1916
46		इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद – 211 002.	2005
47	उत्तराखंड	हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, गढ़वाल – 246 174	2009
48	पश्चिम बंगाल	विश्वभारती, शांतिनिकेतन – 731 235.	1951

मानित विश्वविद्यालय

मानित विश्वविद्यालय की अवधारणा की उत्पत्ति डॉ. एस. राधाकृष्णन आयोग की रिपोर्ट 1948–49 की सिफारिशों से हुई थी। इस अवधारणा के पीछे का विचार उन संस्थानों को बढ़ावा देना, मजबूत करना और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दायरे में लाना है और उनसे विश्वविद्यालयों की भांति व्यवहार करना है जो ऐतिहासिक या किसी अन्य कारण से विश्वविद्यालय नहीं हैं,फिर भी विश्वविद्यालय के बराबर विशिष्ट शैक्षणिक क्षेत्रों में उच्च मानकों का काम कर रहे हैं।

एक संस्थान को केंद्र सरकार द्वारा यूजीसी के परामर्श पर, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत, राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानित विश्वविद्यालय घोषित किया जाता है, जबकि अन्य विश्वविद्यालय या तो संसद के अधिनियम द्वारा या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दिनांक 24.01. 2024 तक, देश में 127 मानित विश्वविद्यालय संस्थान (आईडीटीबीयू) कार्य कर रहे हैं। 127 आईडीटीबीयू में से 35 सरकारी (केंद्र और राज्य) नियंत्रित और वित्तपोषित हैं, 90 निजी तौर पर नियंत्रित हैं और 2 पीपीपी मोड में हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में प्रभाग ने आईडीटीबीयू को 504.48 करोड़ रु. संस्वीकृत किए गए हैं। यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 को 2 जून 2023 को अधिसूचित किया गया है। इन विनियमों की प्रति और मानित विश्वविद्यालयों का राज्य–वार विवरण https://www.ugc.gov पर उपलब्ध है। यूजीसी (मानित विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 की अधिसूचना के बाद वित्तीय वर्ष 2023–24 (31 जनवरी 2024 तक) कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे दिए गए हैं:

1. **निम्नलिखित तीन संस्थानों को मानित विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया गया है**

    1. सर जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस, मुंबई

2. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल
3. सेंट अलॉयसस, मंगलूर

2. **जिन संस्थानों को विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है उन्हें निम्नलिखित संस्थानों तक बढ़ा दिया गया है:**

1. केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, चोगलामसर, लेह, लद्दाख
2. केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कोकराझार, असम
3. इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस (आईएसीएस),, जादवपुर, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल
4. अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर, कर्नाटक
5. समुद्री शिक्षा एवं प्रशिक्षण अकादमी, चेन्नई, तमिलनाडु
6. बीएलडीई, बीजापुर, कर्नाटक
7. चेन्नई गणितीय संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु
8. चेट्टीनाड एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड एजुकेशन, कांचीपुरम, तमिलनाडु
9. चिन्मय विश्वविद्यापीठ, एर्नाकुलम, केरल
10. क्राइस्ट, बैंगलोर, कर्नाटक
11. डीवाई पाटिल, नेरुल, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
12. आईआईएस, गुरुकुल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान
13. जैन, बैंगलोर, कर्नाटक
14. जेएसएस एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, मैसूर, कर्नाटक
15. कलासलिंगम एकेडमी ऑफ रिसर्च एंड हायर एजुकेशन, विरुधुनगर, तमिलनाडु
16. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा
17. कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, भुवनेश्वर, उड़ीसा
18. कर्पगम एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, कोयंबटूर, तमिलनाडु
19. करुणय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज, कोयंबटूर, तमिलनाडु
20. एमजीएम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज, नवी मुंबई, महाराष्ट्र
21. नेहरू ग्राम भारती, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
22. नूरुल इस्लाम उच्च शिक्षा केंद्र, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
23. पोन्नैया रामजयम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तंजावुर, तमिलनाडु
24. शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मेरठ, उत्तर प्रदेश
25. एसआरएम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, चेन्नई, तमिलनाडु
26. सेंट पीटर्स इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, आवडी, चेन्नई, तमिलनाडु
27. वेल्ज़ इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एडवांस्ड स्टडीज, चेन्नई, तमिलनाडु
28. कोनेरू लक्ष्मैया एजुकेशन फाउंडेशन, ग्रीनफील्ड्स, कुंचनपल्ली पोस्ट, गुंटूर
29. विज्ञान फाउंडेशन फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च, वडलामुडी, गुंटूर जिला, आंध्र प्रदेश (27 जुलाई 2023)

30. केएलई एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बेलगाम, कर्नाटक (27 जुलाई, 2023)

3. निम्नलिखित संस्थानों को नए मानित विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है:

1. एनसीईआरटी, दिल्ली
2. नेताजी सुभाष उच्चतर अनुसंधान संस्थान, पोर्ट ब्लेयर
3. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल
4. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कोलकाता
5. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़
6. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई
7. राष्ट्रीय उन्नत सामग्री प्रशिक्षण संस्थान, रांची
8. 11 एनआईईएलआईटी, जिनमें रोपड़ में मुख्य परिसर और 11 अन्य घटक इकाइयों शामिल हैं।
9. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, शिक्षा मंत्रालय (नवीकृत)
10. आयुष मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, बापू भवन, मातोश्री रमाबाई रोड, पुणे (महाराष्ट्र)
11. माधव प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, ग्वालियर
12. भारतीय जनसंचार संस्थान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की एलओआई की वैधता का विस्तरण।

4. निम्नलिखित मानित विश्वविद्यालय संस्थानों के ऑफ–कैंपस केंद्रों को विनियमित कर दिया गया है:

1. जैन, बेंगलुरु – कोच्चि में ऑफ–कैंपस
2. इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, मुंबई – जालना (मराठवाड़ा) और भुवनेश्वर में ऑफ–कैंपस
3. बीआईटी मेसरा – लालपुर, नोएडा, जयपुर, पटना और देवघर में ऑफ कैंपस और छात्रों की डिग्री का सत्यापन

5. यूपी के वाराणसी में एक ऑफ–कैंपस स्थापित करने के लिए होमी भाबा नेशनल इंस्टीट्यूट, मुंबई को आशय पत्र (एलओआई) जारी किया गया है।

6. सिम्बायोसिस इंटरनेशनल (मानित विश्वविद्यालय), पुणे को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में एक ऑफ–शोर कैंपस शुरू करने की अनुमति दी गई है।

निजी विश्वविद्यालय

निजी विश्वविद्यालय संबंधित राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। दिनांक 24.01.2024 तक देश में 472 राज्य निजी विश्वविद्यालय कार्यरत रहे हैं। निजी विश्वविद्यालय अपने संबंधित राज्य अधिनियम के अनुसार शासित किए जाते हैं। इन विश्वविद्यालयों को यूजीसी (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार यूजीसी द्वारा विनियमित किया जाता है। इन विनियमों की एक प्रति और निजी विश्वविद्यालयों का राज्य–वार विवरण https://www.ugc.gov.in पर उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में जयपुर राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, जयपुर को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में ऑफ–शोर कैंपस शुरू करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया है है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

- **विश्व स्तरीय तकनीकी शिक्षा:** उच्च कुशल तकनीकी मानवशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, आज देश में 23 आईआईटी कार्यात्मक हैं, जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में विश्व स्तरीय शिक्षा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में निर्दिष्ट इन आईआईटी को सरकार द्वारा 'आईआईटी को सहायता' योजना के तहत आवश्यक बजटीय सहायता से वित्त पोषित किया जाता है।

- **गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा का विस्तार:** देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने के लिए, सरकार द्वारा वर्ष 2014 और 2015 में छह नए आईआईटी स्थापित किए गए, जिनमें से एक–एक जम्मू, भिलाई, गोवा, धारवाड़, तिरुपति और पलक्कड़ में स्थापित किए गए। इन सभी नए आईआईटी ने अपने शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिए हैं। आईआईटी तिरुपति, आईआईटी धारवाड़ और आईआईटी भिलाई के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और आईआईटी जम्मू का काम अंतिम चरण में है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12.03.2023 को आईआईटी धारवाड़ को राष्ट्र को समर्पित किया गया।

- **अनुसंधान पर फोकस :** स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताएं विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्टअप संस्कृति के सृजन पर सरकार के नए सिरे से फोकस करने के लिए, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार कई कदम उठाए गए हैं: –

    (i) **अनुसंधान पार्क:** स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को विकसित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और देश में एक सफल स्टार्टअप संस्कृति बनाने पर सरकार के नए फोकस को पूरा करते हुए, विभिन्न आईआईटी/आईआईएससी में अनुसंधान पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। आईआईटी मद्रास में एक पूर्ण अनुसंधान पार्क पहले से ही कार्यात्मक है। अगस्त 2019 में आईआईटी खड़गपुर में अनुसंधान पार्क का उद्घाटन किया गया था। आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी हैदराबाद और आईआईएससी बैंगलोर में अनुसंधान पार्क के निर्माण का कार्य विभिन्न चरणों में हैं। आईआईटी गांधीनगर में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा एक अनुसंधान पार्क वित्त पोषित है और पूरा होने के करीब है। माननीय राष्ट्रपति द्वारा 2022 में आईआईटी दिल्ली में अनुसंधान पार्क का उद्घाटन किया गया था।

    (ii) **अनुसंधान नवाचार और प्रौद्योगिकी पर प्रभाव (इम्प्रिन्ट):** पूर्व में, वर्ष 2015 में इम्प्रिन्ट को सरकार की एक प्रमुख राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करना और 10 चयनित प्रौद्योगिकी डोमेन अर्थात स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, टिकाऊ आवास, नैनो प्रौद्योगिकी हार्डवेयर, जल संसाधन और नदी प्रणाली, उन्नत सामग्री, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सुरक्षा और रक्षा, और पर्यावरण विज्ञान और जलवायु परिवर्तन में ज्ञान को व्यवहार्य तकनीक में रूपांतरित करना है। इसके बाद, कार्यनीति में कतिपय परिवर्तन करते हुए

इम्प्रिन्ट–II तैयार किया गया था, जिसे इम्प्रिन्ट–I और यूएवाई को मिलाकर कुल 425 करोड़ रुपये की लागत से दिनांक 21.02.2018 को आयोजित ईएफसी की बैठक में मूल्यांकन किया गया था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया था। इम्प्रिन्ट–II के तहत परियोजनाओं को शिक्षा मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से 50:50 के अनुपात में एक संयुक्त कोष बनाकर वित्त पोषित किया जाएगा। इस योजना के तहत स्वीकृत कुल 184 परियोजनाओं में से 164 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और शेष परियोजनाएं क्रियान्वयन के अधीन हैं। वित्त वर्ष 2020–21 में योजना का तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन किया गया था और मंत्रालय द्वारा रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है।

(iii) उच्चतर अविष्कार योजना (यूएवाई): उच्च स्तर के नवाचार को बढ़ावा देने, जिससे सीधे उद्योग की जरूरतों को प्रभावित हो और इससे भारतीय विनिर्माण की प्रतिस्पर्धी क्षमता में सुधार हो, के लिए 6 अक्टूबर, 2015 को आयोजित आईआईटी परिषद की बैठक में यूएवाई की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में भारत के भीतर या बाहर शिक्षा जगत और उद्योग के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है। चयनित परियोजनाओं का वित्त पोषण पैटर्न 25% उद्योग द्वारा; 25% भाग लेने वाले विभाग/मंत्रालय द्वारा; और 50% शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में, शिक्षा मंत्रालय, भाग लेने वाले मंत्रालयों और उद्योग द्वारा संयुक्त वित्त पोषण के साथ कुल 360.50 करोड़ रुपये की लागत से 136 परियोजना निष्पादन में हैं। इस योजना के तहत, तब से 125 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इम्प्रिन्ट II के संबंध में 21.02.2018 को आयोजित ईएफसी की बैठक में यूएवाई को इम्प्रिन्ट II में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

- **प्रधानमंत्री अनुसंधान अध्येतावृत्ति:** पीएमआरएफ के दिशानिर्देशों के अनुसार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी, अधिमानतः राष्ट्रीय आवश्यकताओं को संबोधित करने वाले क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रतिभा को आकर्षित करने के लिए सभी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों / संस्थानों से अधिकतम 3,000 सबसे प्रतिभाशाली छात्रों को आईआईटी / आईआईएससी / आईआईएसईआर और चयनित सीयू / एनआईटी (एनआईआरएफ शीर्ष 25 में) में पीएचडी कार्यक्रम में दाखिला लेने के लिए चुना जाएगा और उन्हें पहले दो वर्षों के लिए 70,000 रुपये प्रति माह, तीसरे वर्ष के लिए 75,000 रुपये प्रति माह और चौथे और पांचवें वर्ष में 80,000 रुपये प्रति माह की आकर्षक दरों पर अध्येतावृत्ति प्रदान करके प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा , शोध पत्र प्रस्तुत करने की लागत को पूरा करने के लिए प्रत्येक फेलो को 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रति वर्ष 2.00 लाख रुपये का शोध अनुदान दिया जाएगा। इस योजना का मूल्यांकन ईएफसी द्वारा किया गया है तथा 07.02.2018 को आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। अब तक, इस योजना के तहत 3688 फेलो को प्रवेश दिया जा चुका है, जो देश के विभिन्न संस्थानों में पीएचडी कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं।

- **आसियान अध्येतावृत्ति योजनाः** माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 25 जनवरी, 2018 को नई दिल्ली में आयोजित आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र के दौरान की गई घोषणा और उसके बाद 25.07.2019 को आयोजित अपनी बैठक में स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने 300 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय पर 7 वर्षों (3 बैचों) अर्थात 2025–26 तक के लिए आईआईटी में एकीकृत पीएचडी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आसियान देशों के छात्रों को 1000 तक अध्येतावृत्ति देने की मंजूरी दी है। भर्ती होने वाले छात्रों को भारतीय छात्रों के समान दर पर फेलोशिप, साथ ही वार्षिक अनुसंधान अनुदान भी, जैसा लागू हो, प्रदान किया जाएगा। आईआईटी अपने संसाधनों से चयनित छात्रों के रहने के खर्च को कवर करने के लिए एक छोटा सा प्रावधान करेंगे। इस योजना का राष्ट्रीय समन्वयक आईआईटी, दिल्ली है। इस योजना के तहत अब तक तीन चरणों में 65 छात्रों का चयन किया गया है, लेकिन दुनिया भर में कोविड महामारी के कारण देश में केवल 36 छात्र ही अपने संबंधित संस्थानों में शामिल हो पाए हैं और अन्य छात्र या तो दाखिला लेने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके हैं या दाखिला ही नहीं ले पाए हैं।

- **नई योजना– कृत्रिम बुद्धिमत्ता में 3 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापनाः** बजट घोषणा 2023–24 के पैरा 60 के तहत घोषणा की गई है कि – "मेक एआई इन इंडिया एंड मेक ए आई वर्क फोर इंडिया" के विजन को साकार करने के लिए, शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता के तीन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योग घराने अंतःविषय अनुसंधान करने, कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और माप्य समस्या समाधानों को विकसित करने में भागीदार होंगे। यह एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगा और क्षेत्र में गुणवत्ता वाले मानव संसाधनों का पोषण करेगा।" उसी के अनुसरण में, सरकार ने वित्त वर्ष 2023–24 से वित्त वर्ष 2027–28 की अवधि में 990.00 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) में तीन उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) की स्थापना को मंजूरी दी है।

- **विदेशों में आईआईटी के परिसर की स्थापनाः** दिनांक 5–7–2023 को शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार, आईआईटी मद्रास और शिक्षा मंत्रालय और व्यावसायिक प्रशिक्षण (एमओईवीटी) जंजीबार–तंजानिया के बीच जंजीबार–तंजानिया में आईआईटी मद्रास का परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। आईआईटी मद्रास जंजीबार का उद्घाटन 6 नवंबर 2023 को हुआ और यह डेटा साइंस और एआई में बीएस और डेटा साइंस और एआई में एम.टेक के कार्यक्रम पेश कर रहा है। इसके अलावा, अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली का परिसर स्थापित करने के लिए 15 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार, आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग (संयुक्त अरब अमीरात) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। आईआईटी दिल्ली – अबू धाबी का पहला शैक्षणिक कार्यक्रम, अर्थात् ऊर्जा अंतरण और स्थिरता में एम.टेक.कार्यक्रम जनवरी 2024 से शुरू किया गया है।

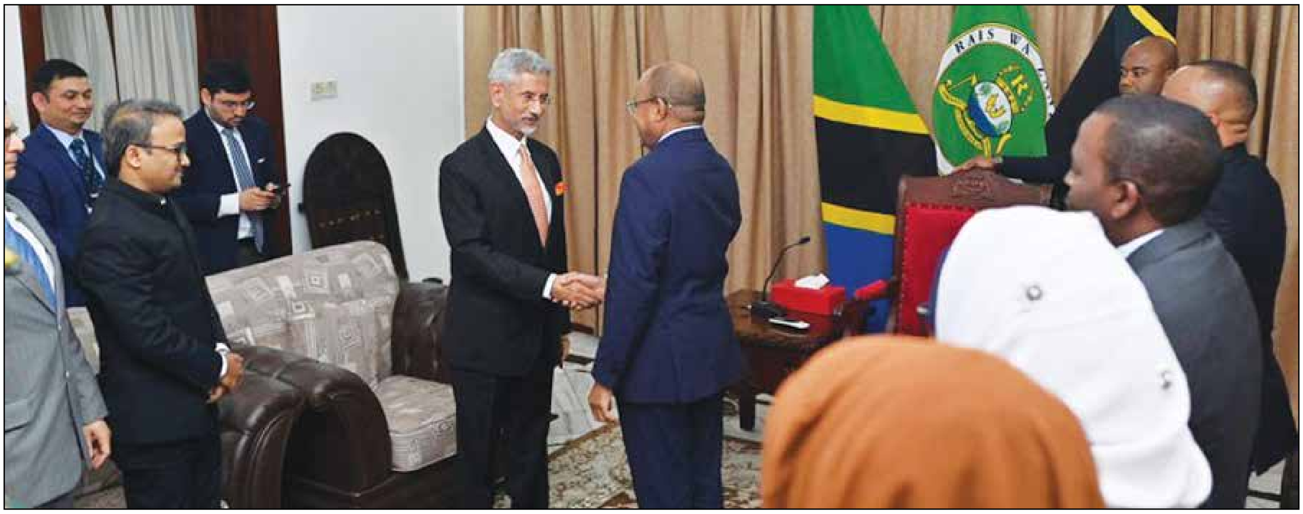

माननीय विदेश मंत्री ने जंजीबार के राष्ट्रपति महामहिम डॉ. हुसैन अली म्विनी से मुलाकात की। वे जंजीबार में आईआईटी मद्रास परिसर की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साक्षी बने।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (आईआईटी–दिल्ली) और अबू धाबी शिक्षा और ज्ञान विभाग (एडीईके) ने आईआईटी–दिल्ली का पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

माननीय प्रधानमंत्री ने आईआईटी दिल्ली – अबू धाबी के छात्रों के पहले बैच के साथ बातचीत की

भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु

भारतीय विज्ञान संस्थान (बेंगलुरु), वर्ष 1909 में धमार्थ अक्षय निधि विनियम, 1890 के अंतर्गत स्थापित, उच्च शिक्षा और विज्ञान का एक प्रमुख संस्थान है जिसे बाद में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की परिधि के अंतर्गत लाया गया। आईआईएससी परिषद द्वारा शासित, यह संस्थान औद्योगिक और सामाजिक लाभ के लिए विज्ञान और इंजीनियरिंग में बुनियादी ज्ञान की खोज के साथ–साथ इसके शोध निष्कर्षों के अनुप्रयोग पर संतुलित जोर देता है। इस संस्थान में देश में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में सबसे बड़ी कंप्यूटिंग सुविधाएं हैं और साथ ही विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ पुस्तकालय संग्रह है। इस संस्था के नैनो विज्ञान और अभियांत्रिकी केंद्र स्थापित किया है, जिसमें राष्ट्रीय नैनो फेब भी है जो शोध और विकास के लिए एक ऐसी सुविधा है जो विश्वभर में ऐसे शैक्षणिक सुविधाओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। आईआईएससी को राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) रैंकिंग 2022 की विश्वविद्यालय और अनुसंधान श्रेणी में शीर्ष भारतीय संस्थान का दर्जा दिया गया है और इसे इस रैंकिंग में द्वितीय दर्जा प्राप्त है।

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर)

भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का (आईआईएसईआर) की परिकल्पना विशेष तौर पर आधारभूत विज्ञान पर बल देते हुए विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान के नए संस्थान के रूप में की गई है। इन संस्थानों से विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने और स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण विज्ञान शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित है। आईआईएसईआर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीएसईआर) अधिनियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय महत्त्व का संस्थान घोषित किया गया है। ऐसे सात संस्थान कोलकाता (2006), पुणे (2006), मोहाली (2007), भोपाल (2008), तिरुवनंतपुरम (2008), तिरुपति (2015) और बरहामपुर(2016) में स्थापित किए गए हैं।

क्र. सं.	संस्थान का	स्थापना वर्ष	तैनात संकाय	तैनात गैर–संकाय	दाखिल छात्र
1	आईआईएसईआर कोलकोता	2006	128	89	1727
2	आईआईएसईआर पुणे	2006	137	134	1820
3	आईआईएसईआर मोहाली	2007	112	76	1665
4	आईआईएसईआर भोपाल	2008	145	104	2200
5	आईआईएसईआर टीवीएम	2008	96	71	1875
6	आईआईएसईआर तिरुपति	2015	50	38	1055
7	आईआईएसईआर बरहामपुर	2016	42	34	920
8	आईआईएससी बैंगलोर	1909	478	376	5590

शिक्षा मंत्रालय विश्व स्तरीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक स्थापित आईआईएसईआर पर प्रति वर्ष लगभग 180–190 करोड़ रु. खर्च करता है। माननीय शिक्षा मंत्री ने स्वास्थ्य और रोग में जीन फ़ंक्शन के लिए राष्ट्रीय सुविधा का उद्घाटन किया और आईआईएसईआर पुणे परिसर में डाटा विज्ञान विभाग की आधारशिला रखी। आईआईएसईआर पुणे ने रसायन विज्ञान, पृथ्वी और जलवायु विज्ञान और गणित विभागों में शैक्षणिक वर्ष 2022–2023 से शुरू होने वाला दो वर्षीय मास्टर ऑफ साइंस कार्यक्रम शुरू किया। इसके अलावा, कुछ आईआईएसईआर अपने संबंधित संस्थानों में निम्नलिखित विशेष शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रस्ताव करते हैं; उदाहरण के लिए, आईआईएसईआर तिरुवनंतपुरम एकीकृत और अंतःविषय विज्ञान में यूजी कार्यक्रम और जैविक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणितीय विज्ञान, भौतिक विज्ञान और डेटा विज्ञान में बीएस–एमएस कार्यक्रम और विज्ञान (जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिकी) और गणित में दो वर्षीय मास्टर ऑफ साइंस (एमएससी) कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, आईआईएसईआर पुणे डाटा विज्ञान में पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।

छात्र प्रवेश 2022–2023:

क्र. सं.	संस्थान का नाम	2022–23 में प्रवेश लेने वाले छात्र	अनुसूचित जाति छात्र	एसटी छात्र
1	आईआईएसईआर कोलकाता	350	48	23
2	आईआईएसईआर पुणे	356	38	21
3	आईआईएसईआर मोहाली	374	57	20
4	आईआईएसईआर भोपाल	532	41	29
5	आईआईएसईआर टीवीएम	491	58	27
6	आईआईएसईआर तिरुपति	220	36	14
7	आईआईएसईआर बरहामपुर	215	25	17
8	आईआईएससी बैंगलोर	1309	167	46

आईआईएसईआर और आईआईएससी में एससी/एसटी छात्रों का औसत प्रतिशत प्रतिनिधित्व (2022–23)

संस्थान का नाम	2021–22	2022–23
आईआईएस ईआर	एससी–13.64% एसटी–05.26%	एससी–11.93% एसटी–05.94%
आईआईएससी	एससी–12.24% एसटी–03.78%	एससी–12.75% एसटी–03.51%

आईआईएसईआर और आईआईएससी की रैंकिंग

एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर, पिछले छह वर्षों के लिए समग्र श्रेणी में आईआईएसईआर की रैंक नीचे दी गई है। यह रैंकिंग ''शिक्षण, सीखना और संसाधन,'' ''शोध और व्यावसायिक अभ्यास,'' ''स्नातक परिणाम,'' ''आउटरीच और समावेशिता,'' और ''सहकर्मी धारणा'' जैसे मापदंडों पर आधारित है।

क्र.सं.	संस्थान	वर्ष 2023
1.	आईआईएसईआर कोलकाता	43
2.	आईआईएसईआर पुणे	34
3.	आईआईएसईआर मोहाली	51
4.	आईआईएसईआर भोपाल	60
5.	आईआईएसईआर टीवीएम	-
6.	आईआईएसईआर तिरुपति	-
7.	आईआईएसईआर बरहामपुर	-
8.	आईआईएससी बैंगलोर	2

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

आईटी क्षेत्र में उच्च कुशल पेशेवरों की मांग को पूरा करने के लिए, ग्वालियर (मध्य प्रदेश), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), जबलपुर (मध्य प्रदेश), कांचीपुरम (तमिलनाडु) और कुरनूल (आंध्र प्रदेश) में पांच केंद्रीय वित्तपोषित भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए गए हैं।

भारतीय आईटी उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और स्वदेशी आईटी बाजार के विकास को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने गैर–लाभकारी सार्वजनिक निजी भागीदारी (एन–पीपीपी) मोड पर 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित किए हैं। सभी 20 आईआईआईटी इस योजना के तहत खोले गए हैं। ये हैं आईआईआईटी चित्तूर (आंध्र प्रदेश), आईआईआईटी रायचूर (कर्नाटक), आईआईआईटी गुवाहाटी (असम), आईआईआईटी धारवाड़ (कर्नाटक), आईआईआईटी कोट्टायम (केरल), आईआईआईटी तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), आईआईआईटी वडोदरा (गुजरात), आईआईआईटी पुणे (महाराष्ट्र), आईआईआईटी सेनापति (मणिपुर), आईआईआईटी अगरतला (त्रिपुरा), आईआईआईटी भोपाल (मध्य प्रदेश), आईआईआईटी सोनीपत (हरियाणा), आईआईआईटी लखनऊ (उत्तर प्रदेश), आईआईआईटी ऊना (हिमाचल प्रदेश), आईआईआईटी कल्याणी (पश्चिम बंगाल), आईआईआईटी कोटा (राजस्थान), आईआईआईटी सूरत (गुजरात), आईआईआईटी नागपुर (महाराष्ट्र), आईआईआईटी भागलपुर (बिहार) और आईआईआईटी रांची (झारखंड)।

आईआईआईटी

सीएफटीआई (केन्द्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थान) मोड में आईआईआईटी

1. आईआईआईटी इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
2. एबीवी–आईआईआईटी एंड एम ग्वालियर, मध्य प्रदेश
3. पीडीपीएम–आईआईआईटीडीएंडएम जबलपुर, मध्य प्रदेश
4. आईआईआईटीडी एंड एम कांचीपुरम, चेन्नई, तमिलनाडू
5. आईआईआईटीडी एंड एम कुरनूल, आंध्र प्रदेश

पीपीपी (सार्वजनिक निजीभागीदारी) मोड में आईआईआईटी

1. आईआईआईटी श्री सिटी चित्तूर आंध्र प्रदेश
2. आईआईआईटी गुवाहाटी, असम
3. आईआईआईटी वडोदरा, गुजरात

4. आईआईआईटी सोनीपत, हरियाणा
5. आईआईआईटी ऊना, हिमाचल प्रदेश
6. आईआईआईटी धारवाड़, कर्नाटक
7. आईआईआईटी कोट्टायम, केरल
8. आईआईआईटी सेनापति, मणिपुर
9. आईआईआईटी कोटा, राजस्थान
10. आईआईआईटी श्रीरंगम, तिरुचिपल्ली, तमिलनाडु
11। आईआईआईटी लखनऊ, उत्तर प्रदेश
12. आईआईआईटी कल्याणी, पश्चिम बंगाल
13. आईआईआईटी पुणे, महाराष्ट्र
14. आईआईआईटी रांची, झारखंड
15. आईआईआईटी नागपुर, महाराष्ट्र
16. आईआईआईटी भोपाल, मध्य प्रदेश
17. आईआईआईटी सूरत, गुजरात
18. आईआईआईटी भागलपुर, बिहार
19. आईआईआईटी अगरतला, त्रिपुरा
20. आईआईआईटी रायचूर, कर्नाटक

आईआईआईटी का सांख्यिकीय विवरण

पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय द्वारा जारी निधि की स्थिति निम्नानुसार है:

25 आईआईआईटी में छात्रों की कुल संख्या (दिसंबर, 2023 तक):

अवर स्नातक	6312
स्नातकोत्तर	934
पीएच.डी.	294
कुल	**7540**

25 आईआईआईटी में कुल संकाय (दिसंबर, 2023 तक):

स्वीकृत	1364
तैनात	676

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश), भोपाल (मध्य प्रदेश), कालीकट (केरल), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश), जयपुर (राजस्थान), जालंधर (पंजाब), जमशेदपुर (झारखंड), कुरुक्षेत्र (हरियाणा), नागपुर (महाराष्ट्र), राउरकेला (उड़ीसा), सिलचर (असम), श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), सूरत (गुजरात), सुरथकल (कर्नाटक), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु) और वारंगल (आंध्र प्रदेश) में स्थित

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	योजना का नाम	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (21.12.2023 तक)
1	आईआईआईटी को सहायता	259.40	167.31	195.16	240.34	262.52	229.32
2	पीपीपी मोड में 20 आईआईआईटी की स्थापना	168.80	154.75	144.02	167.00	220.18	141.25

तत्कालीन सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आरईसी) को वर्ष 2002 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) के रूप में उन्नत किया गया और इन एनआईटी का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण 14 मई 2003 से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद, केंद्र सरकार ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग – पटना, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज – रायपुर और त्रिपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज – अगरतला को भी क्रमशः वर्ष 2004, 2005 और 2006 में एनआईटी के रूप में उन्नत किया।

वर्ष 2007 में, उपर्युक्त बीस संस्थानों को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 के तहत 15 अगस्त, 2007 से 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' घोषित किया गया था। इस अधिनियम के तहत शक्तियों के प्रयोग में, इन संस्थानों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए 23 अप्रैल, 2009 से एनआईटी की प्रथम संविधियां तैयार और अधिनियमित की गई थीं।

इस के बाद पंचवर्षीय योजना के दौरान, सितंबर 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद गैर–एनआईटी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड में 10 नए एनआईटी स्थापित किए गए। इन 10 नए एनआईटी ने वर्ष 2010–2011 से अपना पहला शैक्षणिक सत्र शुरू किया। वर्ष 2015 में, नव विभाजित आंध्र प्रदेश राज्य के ताड़ेपल्लीगुड़ेम में भी एक एनआईटी स्थापित किया गया है और इसका पहला शैक्षणिक सत्र 2015–2016 से शुरू हुआ है। इस प्रकार, एनआईटी की संख्या 31 हो गई है, अर्थात सभी राज्यों और प्रमुख संघ राज्य क्षेत्रों दिल्ली, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और पुडुचेरी में क्रमशः एक–एक एनआईटी है।

इन सभी 11 नए एनआईटी को भी ''राष्ट्रीय महत्व के संस्थान'' घोषित किया गया है और उपयुक्त संशोधनों के माध्यम से उक्त अधिनियम के दायरे में लाया गया है, जिन्हें क्रमशः वर्ष 2012 और 2016 में अधिनियमित किया गया था। वर्ष 2012 में संशोधन पारित होने के परिणामस्वरूप एनआईटी अधिनियम, 2007 के लंबे शीर्षक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 में संशोधन किया गया।

आईआईईएसटी, शिबपुर

केंद्र सरकार द्वारा बंगाल इंजीनियरिंग एवं विज्ञान विश्वविद्यालय (बीईएसयू), शिबपुर (पश्चिम बंगाल), एक राज्य सरकार के स्वामित्व वाला विश्वविद्यालय भी अधिग्रहित कर भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) के रूप में उन्नत किया गया है और एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के तहत इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है। आईआईईएसटी, शिबपुर को अधिनियम के तहत शामिल करने के लिए आवश्यक संशोधनों को 4 मार्च 2014 को मंजूरी दी गई थी। एनआईटीएसईआर अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, एनआईटी और आईआईईएसटी–शिबपुर के विजिटर, भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं और माननीय शिक्षा मंत्री इन संस्थानों की परिषद, शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के अध्यक्ष हैं। एनआईटी/आईआईईएसटी के मामलों का प्रबंधन संबंधित संस्थान के शासी बोर्ड द्वारा किया जाता है।

एनआईटी और आईआईईएसटी में प्रवेश

एनआईटी और आईआईईएसटी में यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) द्वारा प्रति वर्ष आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) में छात्रों द्वारा प्राप्त वरीयता और उसके बाद संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जोसा) द्वारा की जाने वाली केंद्रीकृत काउंसलिंग और सीट आवंटन प्रक्रिया के आधार पर होता है। वर्तमान नीति के अनुसार, एनआईटी और आईआईईएसटी में 50% सीटों पर प्रवेश उस राज्य के छात्रों के लिए निर्धारित है, जहां एनआईटी/आईआईईएसटी स्थित हैं। शेष 50% सीटों पर प्रवेश अन्य राज्यों के उम्मीदवारों की अखिल भारतीय रैंक के आधार पर दिया जाता है।

इन संस्थाओं की भूमिका

यह प्रणाली देश के प्रतिभाशाली छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी शिक्षा प्रदान करने में सक्षम है। देश के सुदूर कोनों में इंजीनियरिंग शिक्षा के समान अवसर के दायरे का प्रसार करते हुए, एनआईटी देश के प्रमुख तकनीकी संस्थानों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड हैं, जो गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देते हैं। क्षेत्रीय और राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकी जनशक्ति प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दस नए एनआईटी की स्थापना के बाद, देश भर के छात्रों को राष्ट्रीय महत्व के इन संस्थानों में तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर मिल रहे हैं।

31 एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में छात्रों की कुल संख्या (अक्टूबर 2023 तक)

अवर स्नातक : 90182

पोस्ट ग्रेजुएट : 21863

पीएच.डी : 15822

कुल : 127867

31 एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में कुल संकाय

स्वीकृत : 7521

भरे गए : 6524 ख्5566 (नियमित) + 958 (अनुबंध),

31 एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर में मिशन मोड के तहत कुल भर्ती (01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

संकाय : 3264

गैर–संकाय : 1941

कुल : 5205 (संकाय + गैर–संकाय)

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों (आरईसी) की स्थापना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के रूप में उनका उन्नयन और बीईएसयू को भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर के रूप में उन्नयन किए जाने का वर्ष

मई 2003 तक, क्रम संख्या 1 से 17 तक सूचीबद्ध एनआईटी संबंधित राज्य सरकारों और भारत सरकार के संयुक्त उद्यम के तहत क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेज (आरईसी) के रूप में कार्य कर रहे थे। वर्ष 2002 के दौरान, 17 में से 14 आरईसी को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) के रूप में पुनः नामकरण किया गया और उन्हें मानित विश्वविद्यालयों का दर्जा दिया गया।

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	कार्यभार संभालने का वर्ष
1.	मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1961	2003
2.	मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल (मध्य प्रदेश)	1960	2003
3.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट (केरल)	1961	2003
4.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल)	1960	2003
5.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश)	1985	2003
6.	मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर (राजस्थान)	1963	2003
7.	डॉ– बी–आर–अंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जालंधर (पंजाब)	1986	2003
8.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर (झारखंड)	1960	2003

क्र. सं.	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	कार्यभार संभालने का वर्ष
9.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)	1963	2003
10.	विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नागपुर (महाराष्ट्र)	1960	2003
11.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राउरकेला (उड़ीसा)	1961	2003
12.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सिलचर (असम)	1977	2003
13.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	1960	2003
14.	सरदार वल्लभभाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूरत (गुजरात)	1961	2003
15.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक, सुरथकल (कर्नाटक)	1960	2003
16.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु)	1964	2003
17.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल (तेलंगाना)	1959	2003
18.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना (बिहार)	1886	2004
19.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रा;पुर (छत्तीसगढ़)	1956	2005
20.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, अगरतला (त्रिपुरा)	1965	2006
21-30	10 नए एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम और उत्तराखंड में स्थित होंगे।	2010*	2010*
31.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, आंध्र प्रदेश	2015	2015
32.	भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, शिबपुर (पश्चिम बंगाल) (मार्च, 2014 में आईआईईएसटी, शिबपुर के रूप में उन्नत)	1856	2014

**2010 में स्थापित किये गये नये एनआईटी (XI वीं पंचवर्षीय योजना)*

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान हैं। वर्तमान में, 21 आईआईएम हैं। इन आईआईएम को तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है अर्थात प्रथम पीढ़ी के आईआईएम, द्वितीय पीढ़ी के आईआईएम और तृतीय पीढ़ी के आईआईएम।

- **प्रथम पीढ़ी के आईआईएम:** ये आईआईएम कोलकाता (1961 में स्थापित), अहमदाबाद (1961), बैंगलोर (1973), लखनऊ (1984), इंदौर (1996) और कोझीकोड (1997) में स्थित हैं और अपने–अपने स्थायी परिसरों से कार्यात्मक हैं।
- **दूसरी पीढ़ी के आईआईएम:** उच्च गुणवत्ता वाले प्रबंधन संस्थानों के लिए सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए, देश में सात आईआईएम स्थापित किए गए, जिनमें शिलांग (मेघालय), रोहतक (हरियाणा), रायपुर (छत्तीसगढ़), रांची (झारखंड), तिरुचिरापल्ली (तमिलनाडु), काशीपुर (उत्तराखंड) और उदयपुर (राजस्थान) शामिल हैं। ये सभी अब अपने–अपने स्थायी परिसरों से कार्यात्मक हैं।
- **तीसरी पीढ़ी के आईआईएम:** वर्ष 2015–16 के दौरान, अमृतसर (पंजाब), बोधगया (बिहार), नागपुर (महाराष्ट्र), संबलपुर (ओडिशा), सिरमौर (हिमाचल प्रदेश) और विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश) में छह और आईआईएम स्थापित

किए गए। इन आईआईएम के शैक्षणिक सत्र, शैक्षणिक वर्ष 2015–16 में अपने अस्थायी परिसरों से शुरू हुए। जम्मू में एक और आईआईएम स्थापित किया गया है जिसने वर्ष 2016–17 में अपना शैक्षणिक सत्र शुरू किया। इन तीसरी पीढ़ी के आईआईएम में से, आईआईएम अमृतसर और आईआईएम सिरमौर को छोड़कर, सभी तीसरी पीढ़ी के आईआईएम अब अपने स्थायी परिसर से कार्यात्मक हैं।

- नवीनतम आईआईएम, आईआईएम मुंबई है, जो आईआईएम (संशोधन) अधिनियम, वर्ष 2023 के पारित होने के साथ 16 अगस्त 2023 से अस्तित्व में आया।
- वर्ष 2023–24 के दौरान आईआईएम में निम्नलिखित उद्घाटन किए गए हैं:
- भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 26 अक्टूबर 2023 को आईआईएम बैंगलोर की स्वर्ण जयंती पर स्थापना सप्ताह का उद्घाटन किया गया।
- भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने 1 मार्च 2023 को आईआईएम बैंगलोर के नए एमडीसी ब्लॉक का उद्घाटन किया ।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 15 नवंबर 2023 को आईआईएम रांची के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 3 फरवरी 2024 को आईआईएम संबलपुर (ओडिशा) के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया।
- भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के समर्थन से अपने नवाचार, ऊष्मायन और उद्यमिता केंद्र (सीआईआईई) के विस्तार के माध्यम से नवाचार–संचालित उद्यमिता का समर्थन करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) के शुभारंभ के लिए आईआईएम अहमदाबाद को बधाई देने के लिए संदेश भेजा।
- माननीय शिक्षा मंत्री ने 19 जनवरी 2024 को आईआईएम संबलपुर में संस्कृति और सतत प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए रंगाबती केंद्र का उद्घाटन किया ।

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक आईआईएम में छात्र प्रवेश, संकाय की स्थिति और आईआईएम को जारी धनराशि

क्र. सं.	आईआईएम का नाम	दिनांक 31.12.2023 तक छात्रों की संख्या		दिनांक 31.12.2023 तक संकाय पद	हेफा सहित जारी की निधि (01.01.2023 से 31.12.2023 तक) (रु. लाख में)
		पीजीपी	एफपीएम		
1.	आईआईएम अहमदाबाद	451	23	107	शून्य
2.	आईआईएम बैंगलोर	603	17	107	शून्य
3.	आईआईएम कलकत्ता	480	19	79	शून्य
4.	आईआईएम इंदौर	487	15	105	शून्य
5.	आईआईएम कोझिकोड	595	17	97	शून्य
6.	आईआईएम लखनऊ	617	19	87	शून्य

क्र. सं.	आईआईएम का नाम	दिनांक 31.12.2023 तक छात्रों की संख्या		दिनांक 31.12.2023 तक संकाय पद	हेफा सहित जारी की निधि (01.01.2023 से 31.12.2023 तक) (रु. लाख में)
		पीजीपी	एफपीएम		
7.	आईआईएम काशीपुर	321	9	46	शून्य
8.	आईआईएम रायपुर	383	8	42	शून्य
9.	आईआईएम रांची	377	3	62	शून्य
10.	आईआईएम रोहतक	265	14	41	शून्य
11.	आईआईएम शिलांग	390	17	36	शून्य
12.	आईआईएम तिरुचिरापल्ली	384	0	44	शून्य
13.	आईआईएम उदयपुर	334	8	46	शून्य
14.	आईआईएम अमृतसर	322	4	16	1741.55
15.	आईआईएम बोधगया	483	7	48	2058.60
16.	आईआईएम जम्मू	265	12	44	2124.65
17.	आईआईएम नागपुर	267	2	27	1898.40
18.	आईआईएम संबलपुर	319	6	27	2009.70
19.	आईआईएम सिरमौर	376	3	36	1962.55
20.	आईआईएम विशाखापत्तनम	310	6	34	2225.00
21.	आईआईएम मुंबई	477	15	51	5431.00
	कुल	**8506**	**224**	**1182**	**19451.45**

योजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए)

एसपीए दिल्ली

योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), नई दिल्ली की शुरुआत वर्ष 1941 में दिल्ली पॉलिटेक्निक के आर्किटेक्चर विभाग के रूप में हुई थी। वैश्विक स्तर का संस्थान, स्कूल भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्याधुनिक योजना, वास्तुकला और डिजाइन समाधान, और परामर्श तथा अनुसंधान वातावरण प्रदान करता रहा है। एसपीए की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने 1979 में स्कूल को "मानद विश्वविद्यालय" का दर्जा दिया।

इसने स्कूल को नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करके और महत्वपूर्ण शोध और परामर्श गतिविधियों को बढ़ावा देकर अपने शैक्षणिक क्षितिज को व्यापक और गहरा बनाने में सक्षम बनाया। योजना और वास्तुकला स्कूल (एसपीए) अधिनियम 2014 के तहत भारत सरकार द्वारा स्कूल को "राष्ट्रीय महत्व का संस्थान" घोषित किया गया था।

- **शैक्षणिक कार्यक्रम – स्कूल दो स्नातक कार्यक्रम प्रदान करता है:** बैचलर ऑफ प्लानिंग और बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। गौरतलब है कि स्कूल प्लानिंग, आर्किटेक्चर और डिजाइन में ग्यारह स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का भी प्रस्ताव करता है। ये स्नातकोत्तर कार्यक्रम हैं आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट प्लानिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, हाउसिंग, अर्बन डिजाइन, रीजनल प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, लैंडस्केप आर्किटेक्चर, इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ प्लानिंग और बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। इसके अलावा, स्कूल के सभी अध्ययन विभाग 1985 से डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, स्कूल ने बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर में 143 छात्रों, बैचलर ऑफ प्लानिंग में 41 और विभिन्न स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 233 छात्रों को प्रवेश दिया। वर्तमान समय में, लगभग 114 पीएचडी विद्वान योजना और डिजाइन में विषय क्षेत्रों की विविधता को कवर करने वाले अध्ययन के विभिन्न विभागों में काम कर रहे हैं।
- **शोध परियोजनाएँ और परामर्श** – इस स्कूल ने विभिन्न क्षेत्रों में शोध, विस्तार, दस्तावेज़ीकरण और ज्ञान के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और उन्नत अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय डिज़ाइन नवाचार पहल के तहत अभिनव उत्पादों और प्रक्रियाओं पर भी काम कर रहा है। स्कूल विभिन्न स्तरों पर राज्य और केंद्र सरकार और निजी क्षेत्र को भी अत्याधुनिक परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है। वर्ष के दौरान, एसपीए नई दिल्ली को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित कई परामर्श परियोजनाएँ प्रदान की गई। विभिन्न मंत्रालयों और योजना प्राधिकरणों के लिए परामर्श परियोजनाएँ शुरू की जाती हैं। वर्तमान में, 74 परामर्श परियोजनाएँ चल रही हैं। वर्ष 2023 के दौरान स्कूल को कुल 9,00,80,526.00 रुपये का परामर्श शुल्क प्राप्त हुआ।
- **शहरी योजना और डिजाइन में उत्कृष्टता केंद्र** – इस स्कूल को शहरी योजना और डिजाइन में भारत–विशिष्ट ज्ञान विकसित करने और इन क्षेत्रों में प्रमाणित प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शहरी योजना और डिजाइन में चार उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) में से एक के रूप में नामित किया गया है।
- **अनुमोदन और मान्यता** – इस स्कूल में शिक्षा के उच्चतम गुणवत्ता मानकों को निरंतर बनाए रखने के लिए, एसपीए दिल्ली के बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कार्यक्रम की नियमित रूप से दिल्ली की वास्तुकला परिषद द्वारा निगरानी की जाती है। इस स्कूल को 65.14 के स्कोर के साथ एनआईआरएफ रैंकिंग 2023 की वास्तुकला श्रेणी के तहत 5 वें स्थान पर भी रखा गया था।

एसपीए भोपाल

योजना और वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), भोपाल, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है, जो योजना, वास्तुकला और डिजाइन में उच्च शिक्षा प्रदान करता रहा है। एसपीए भोपाल हमेशा से ही टिकाऊ योजना, अभिनव डिजाइन और तकनीकी समाधानों के माध्यम से निर्मित पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने में अपना योगदान देने का प्रयास करता रहा है। एसपीए भोपाल

भविष्य के वास्तुकारों और योजनाकारों को पोषित करके उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में अग्रणी रहा है।

- **शैक्षणिक कार्यक्रम** – योजना और वास्तुकला विद्यालय, भोपाल वर्तमान में आठ विभागों के माध्यम से नौ शैक्षणिक डिग्री कार्यक्रम (स्नातक स्तर पर दो और स्नातकोत्तर स्तर पर सात) प्रदान करता है। इसके अलावा, संस्थान एक डॉक्टरेट कार्यक्रम भी प्रदान करता है। कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान, कुल 117 छात्रों को स्नातक कार्यक्रमों में, 108 छात्रों को स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में और 13 छात्रों को डॉक्टरेट कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया।

- **समझौता ज्ञापन/सहयोग** – वर्तमान में, एसपीए भोपाल कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उच्च ख्याति प्राप्त संस्थानों जैसे यूएन–हैबिटेट, जीआईजेड (जर्मनी), एनआईटीटीटीआर भोपाल, एनआईडी भोपाल, आईआईएसईआर भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन, डीजी रिसर्च सेल मध्य प्रदेश पुलिस (डीआरसी–एमपीपीए), एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र भोपाल, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल, राजीव गांधी विश्वविद्यालय अरुणाचल प्रदेश, फ्लोरेंस विश्वविद्यालय, एनटीएनयू नॉर्वे, केरल स्थानीय प्रशासन संस्थान, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुंबई, आदि के साथ मिलकर काम करता है। विभिन्न ख्याति वाले संस्थानों के साथ ये सहयोग सामाजिक रूप से जिम्मेदार गतिविधियों के प्रति ज्ञान साझा करने और संवर्धन को सक्षम बना रहा है।

- **अनुसंधान और परामर्श परियोजनाएँ** – वर्तमान में, संस्थान कुल 18 से अधिक अनुसंधान और परामर्श परियोजनाओं में लगा हुआ है। संस्थान के सम्मानित उपभोक्ताओं में एमपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन; नगर योजना विभाग, मणिपुर; एमपीटीबी; इस्पात मंत्रालय; नगर और ग्राम योजना, तमिलनाडु; ब्रिटिश काउंसिल; भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, एमओई; यूपी राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण; मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम; मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन बोर्ड; शिक्षा मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय; यूनिसेफ; एआईसीटीई, एमओई; एमओपीआर शामिल हैं।

एसपीए विजयवाड़ा

स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर विजयवाड़ा देश के तीन एसपीए में से एक है, जिसकी स्थापना 2008 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में की गई थी। एसपीए विजयवाड़ा वास्तुकला और योजना के क्षेत्र में दो स्नातक, आठ स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम प्रदान करता है। एसपीए विजयवाड़ा शिक्षा के ऐसे माहौल की सुविधा देता है जो सार्थक वैज्ञानिक प्रयोग और ज्ञान की उपस्थिति के स्तंभों पर अपनी नींव रखता है। हमारा बुनियादी ढांचा, पाठ्यक्रम, पाठ्येतर गतिविधियाँ, अनुसंधान और उद्योग संपर्क आत्म–सक्षमता और आत्म–खोज के मॉडल पर केंद्रित हैं। मूल्यांकन वर्ष 2023–24 में कई नई पहल की गई हैं जो एसपीए विजयवाड़ा को योजना और वास्तुकला के क्षेत्र में शैक्षणिक और अनुसंधान मानकों के उच्चतम स्तरों के लिए नए सिरे से प्रतिबद्धता के मार्ग पर ले जाती हैं।

- '**एनईपी** 2020 के साथ संरेखित **नए शैक्षणिक अध्यादेश 2023 की शुरूआत** एनईपी 2020 के साथ संरेखित शैक्षणिक अध्यादेश 2023 की शुरूआत में ऐसे कई पहलू कवर हो जाते हैं जिनसे छात्रों के प्रवेश, छात्र अधिगम और छात्रों की परीक्षा और मूल्यांकन के तरीके में उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट, क्रेडिट ट्रांसफर, इंटरडिसिप्लिनरी इलेक्टिव, पीएचडी के लिए व्यापक पात्रता और प्रोफेशनल

नेटवर्क तथा वर्धित उच्च अनुसंधान आउटपुट इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।

- **समझौता ज्ञापन (एमओयू)**– शैक्षणिक और शोध वातावरण को बेहतर बनाने के लिए सहयोगी शैक्षणिक, शोध और परामर्श गतिविधियों के लिए कई नए समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निष्पादित किए जाने वाले कुछ प्रमुख समझौता ज्ञापनों में यूनिवर्सिटी ऑफ लिली, फ्रांस, यूएन–हैबिटेट, बोस्टन कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, यूएसए, एनयूएस, सिंगापुर, इकोले ब्लू ग्लोबल डिजाइन, फ्रांस, आईआईटी तिरुपति, बीएमएस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर और केरल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन (केआईएलए) शामिल हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए)

शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) (मानद विश्वविद्यालय) न केवल भारत में बल्कि दक्षिण एशिया में भी शिक्षा की योजना और प्रबंधन में क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है।

लक्ष्य और उपलब्धियों के साथ कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

एनआईईपीए ने वर्ष 2007 से व्यापक अंतःविषय सामाजिक विज्ञान परिप्रेक्ष्य के साथ शैक्षिक योजना और प्रशासन में एम.फिल. और पीएचडी कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। तब से एनआईईपीए में, एम.फिल. के लिए 299 शोध विद्वान, पीएचडी कार्यक्रम के लिए 225 पंजीकृत हुए हैं। दिसंबर 2023 से तक 197 एम.फिल. और 44 पीएचडी डिग्री प्रदान की गई हैं। वर्ष 2023 में, 31 छात्र (29 प्रत्यक्ष और 02 अंशकालिक) एनआईईपीए में पीएचडी कार्यक्रम में नामांकित थे। एनआईईपीए ने वर्ष 2023 में मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट (एमएईडी) कार्यक्रम शुरू किया और 22 छात्रों ने इस कार्यक्रम में दाखिला लिया है। यह विश्वविद्यालय एम.फिल. और पीएचडी कार्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया और विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति का पालन करता है। यह सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों को भारत सरकार की शिक्षा नीतियों के मुद्दों से संबंधित शोध करने, सेमिनार आयोजित करने आदि के लिए अनुदान देता है, जिसमें सामाजिक रूप से वंचित समूहों, यानी एससी/एसटी और अल्पसंख्यकों की शिक्षा शामिल है। एनआईईपीए ने शिक्षा प्राप्ति के निम्न स्तर की असमानता को कम करने, गरीबी को कम करने और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए कई सर्वेक्षण, शोध अध्ययन और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाए हैं।

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक, 111 व्यावसायिक विकास कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं जिनमें वरिष्ठ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा नीति निर्माताओं, योजनाकारों और प्रशासकों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सेमिनार, सम्मेलन और बैठकें शामिल हैं। एनआईईपीए ने दिसंबर 2023 तक 52 कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अलावा, एनआईईपीए ने वर्ष 2023 में पांच बैचों (05) में आंध्र प्रदेश कमिश्नरेट ऑफ कॉलेजिएट एजुकेशन (एपीसीसीई), नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन (एनसीआईएसएम) (08) और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (01) के कॉलेज प्रधानाचार्यों के लिए 14 आउटसोर्स क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, एनआईईपीए प्रत्येक वर्ष दो डिप्लोमा कार्यक्रम भी आयोजित करता है (i) शैक्षिक योजना और प्रशासन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए), और (ii) शैक्षिक योजना और प्रशासन में अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमा (आईडीईपीए)। यह स्कूल नेतृत्व और प्रबंधन पर ऑनलाइन कार्यक्रम (पीएसएलएम) भी आयोजित करना है। इसके अलावा,

एनआईईपीए ने 2023 में शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में 06 शोध अध्ययन पूरे कर लिए हैं , 26 शोध अध्ययन प्रगति पर हैं, और जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान नए शोध प्रस्ताव प्राप्त/अनुमोदित नहीं हुए हैं।

एनआईईपीए देश में शैक्षिक नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में व्यापक जागरुकता पैदा करने के लिए शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों पर सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करने वाले संगठनों को अनुदान सहायता प्रदान करता है। इस अवधि के दौरान, एनआईईपीए ने अनुदान सहायता योजना के तहत शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों में सम्मेलन, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए शैक्षिक संस्थानों और संघों को अनुदान सहायता के रूप में 6 लाख रुपये संवितरित किए हैं।

एनआईईपीए ने 2023 के दौरान कई कार्यक्रम, जैसे कि 4–5 दिसंबर 2023 को वर्ष 2020–21 और 2021–2022 के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छे व्यवहारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना आयोजित की। एनआईईपीए ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा कॉलेजों के 550 धानी के लिए क्षमता विकास प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) के साथ सहयोग भी किया। एनआईईपीए ने 2023 में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक प्रशासकों के लिए एक क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

एनआईईपीए ने वर्ष 2023 में विभिन्न वार्षिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जैसे गणतंत्र दिवस, शहीद दिवस, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, एनआईईपीए स्थापना दिवस, एनएएसी द्वारा एनआईईपीए की मान्यता, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, स्वच्छता ही सेवा, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, फिट इंडिया सप्ताह, जी–20 परामर्शदात्री बैठक और विश्वविद्यालय संपर्क कार्यक्रम, राष्ट्रीय खेल दिवस, 2023, सेल्फी प्वाइंट की स्थापना, फिट इंडिया सप्ताह, निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन आदि।

वर्ष 2023 के दौरान अपनाई गई प्रमुख नीति/सुधार

राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर शोध और प्रशिक्षण कार्यक्रम चिंता का विषय हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं, जिनकी शिक्षा का स्तर बेहद कम है। उनके उत्थान के लिए भारत सरकार द्वारा कई पहल की गई हैं। एनआईईपीए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों पर सर्वेक्षण और शोध अध्ययन करता है और उनके शैक्षिक उत्थान के लिए कई कार्यक्रम विकसित किए गए हैं। यह आदिवासी क्षेत्रों में सेमिनार और क्षेत्र–आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

एनआईईपीए शिक्षा और संबद्ध क्षेत्रों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन/सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करता है। इस अवधि के दौरान संस्थान द्वारा आयोजित कुछ प्रमुख और कार्यक्रम विधियों का आयोजन इस प्रकार हैंः–

1. **वर्ष 2020–21 और 2021– 2022 के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छे व्यवहारों के लिए पुरस्कारों की राष्ट्रीय योजना**– राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (एनआईईपीए) ने 5 दिसंबर, 2023 को डॉ अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में जिला और ब्लॉक स्तरीय शिक्षा अधिकारियों के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छे व्यवहारों पर पुरस्कार समारोह का आयोजन किया, जिसमें शैक्षिक प्रशासन में नवाचारों और अच्छे व्यवहारों को स्वीकार करने पर बल दिया गया। इस आयोजन का उद्देश्य शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में क्षेत्र स्तर के शिक्षा अधिकारियों द्वारा अग्रणी पहलों के बारे में बताना और प्रसार करना था। पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल

विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान की गरिमामयी उपस्थिति से इस अवसर का गौरव बढ़ गया जिससे इन पुरस्कारों का महत्व और अधिक बढ़ गया।

माननीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर उपस्थित होकर पुरस्कार विजेताओं को आशीर्वाद दिया और सभी के उज्ज्वल भविष्य के लिए शैक्षिक प्रशासन में नवीन प्रथाओं को खोजने, पोषित करने और बनाने के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में दृष्टि का विस्तार करने की भूमिका सौंपकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने स्कूल प्रशासकों के सामने आने वाली चुनौतियों और शिक्षा प्रणाली के सुचारु संचालन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने एनआईईपीए के प्रयासों की सराहना की और इस आयोजन ने न केवल अनुकरणीय प्रयासों को सम्मानित किया, बल्कि भारत में शैक्षिक परिदृश्य में सहयोग, अधिगम और प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक का काम भी किया। एनआईईपीए के कुलाधिपति श्री महेश चंद्र पंत ने पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की।इन समारोह में प्रोफेसर शशिकला वंजारी, कुलपति, एनआईईपीए और प्रोफेसर कुमार सुरेश, कार्यक्रम निदेशक – इनोवेशन अवाड्र्स भी उपस्थित थे।

2. **एनआईईपीए स्थापना दिवसः** XVII एनआईईपीए स्थापना दिवस 8 अगस्त, 2023 को मनाया गया। इस समारोह की मुख्य अतिथि भारत सरकार की शिक्षा राज्य मंत्री सुश्री अन्नपूर्णा देवी थीं। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. आनंद भालेराव ने 'शिक्षा– आजीवन अधिगम' विषय पर व्याख्यान दिया।

3. **चौदहवां राष्ट्रीय शिक्षा दिवसः** मौलाना आजाद की याद में 10 नवंबर 2023 को चौदहवां राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आयोजित किया गया। प्रोफेसर चांद किरण सलूजा, निदेशक (अकादमिक), संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन ने वर्तमान शिक्षा में भारतीय ज्ञान को शामिल करने पर व्याख्यान दिया

4. **जी–20 और जी–20 और एनआईईपीए में गतिविधियां – भारत की जी20 अध्यक्षता और शिक्षा कार्यसूची पर 13–14 फरवरी, 2023:** को एक सलाहकार बैठक, एनआईईपीए ने जी20 शिक्षा कार्य समूह के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार को अपना समर्थन दिया। भारत की जी20 अध्यक्षता और शिक्षा एजेंडा पर दो दिवसीय सलाहकार बैठक, 13–14 फरवरी, 2023 को आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शिक्षा समूह के लिए पहचाने गए चार विषयगत क्षेत्रों पर इनपुट तैयार करना था। चर्चा करने और इनपुट प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया था। एनआईईपीए सलाहकार बैठक से इनपुट और प्रमुख सिफारिशें तैयार करने में सक्षम रहा है। सिफारिशों को तब से उच्चतर

शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा किया गया है।

5. **आंध्र प्रदेश के कॉलेज प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम (पांच बैच):** एनआईईपीए ने कॉलेजिएट शिक्षा आयुक्तालय, आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से जनवरी 2023–मार्च 2023 के बीच 5 बैचों में आंध्र प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के लिए नेतृत्व क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

6. **'भारत में सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों के आवधिक मूल्यांकन और मान्यता को सुदृढ़ करने के लिए परिवर्तनकारी सुधार' मसौदा रिपोर्ट पर चर्चा के लिए विशेषज्ञों की सलाहकार बैठक:** एनईपी 2020 में मूल्यांकन और मान्यता में सुधार सहित उच्च शिक्षा के विनियमन और शासन में सुधार का प्रस्ताव है। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। एनआईईपीए द्वारा दिनांक 06.06.23, 14.06.23 और 15.06.2023 को तीन सलाहकार बैठकें आयोजित की गईं। परामर्शी बैठकों में कुलपतियों, निदेशकों, डीन और विभागाध्यक्षों सहित वरिष्ठ शैक्षिक प्रशासकों ने भाग लिया। एक रिपोर्ट तैयार की गई और उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अवलोकन के लिए प्रस्तुत की गई।

7. **राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा पद्धति आयोग (एनसीआईएसएम) के सहयोग से आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के लिए क्षमता विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम** : शैक्षिक योजना और प्रशासन के क्षेत्र में एक प्रमुख और अद्वितीय संस्थान के रूप में एनआईईपीए के मौलिक योगदान के साथ–साथ शैक्षिक प्रशासकों और संस्थागत प्रमुखों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम प्रदान करने में इसकी विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय राष्ट्रीय चिकित्सा प्रणाली के आयोग (एनसीआईएसएम). आयुष मंत्रालय, भारत सरकार ने आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोगा–रिग्पा कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एनआईईपीए से संपर्क किया। कई चर्चाओं के बाद, जुलाई 2023 से मई 2024 के बीच 20 बैचों में 550 कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया। कार्यक्रम का पहला बैच जुलाई, 2023 के महीने में शुरू किया गया था. अब तक सात कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिनमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और सोवा–रिग्पा कॉलेजों के लगभग 200 प्रधानाचार्यों / प्रमुखों ने भाग लिया और कार्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा किया।

8. **केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रशासकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम:** एनआईईपीए ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू) के सहयोग से "केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के अकादमिक प्रशासकों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम" नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया। दोनों संस्थानों के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। यह कार्यक्रम 14–18 नवंबर, 2023 को एनआईईपीए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य समूह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू) के विभिन्न कॉलेजों के डीन/निदेशक/विभागाध्यक्ष थे। विश्वविद्यालय के लगभग 40 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में भाग लिया और सफलतापूर्वक पूरा किया।

9. शैक्षिक प्रशासकों के लिए पांचवां अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीईए)

10. शैक्षिक योजना और प्रशासन में दसवीं

स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईपीए) 2023–24

11. उच्चतर शिक्षा में विविधता और समावेशन पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 16–17 फरवरी, 2023 को आयोजित की गई

12. **संस्थागत स्तर पर नीतियों के अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रभाव को समझने संबंधी परामर्शी बैठकः** यूआइसी ने 28–30 नवंबर 2023 तक "भारत में उच्चतर शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरणः मुद्दे, चुनौतियां और समाधान" विषय पर एक सलाहकार बैठक का आयोजन किया। कार्यक्रम तीन दिनों तक चला और आभासी रूप में आयोजित किया गया था। प्रतिभागियों में केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू), मानद विश्वविद्यालयों (डीयू), राज्य विश्वविद्यालयों (एसयू), राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (आईएनआई) और निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के कार्यालय (ओआईए) के डीन / प्रमुख / निदेशक / समन्वयक शामिल थे। सलाहकार बैठक में 60 से अधिक संस्थानों ने भाग लिया।

13. **15 फरवरी 2023 को स्कूल नेतृत्व विकास पर मॉड्यूल के संकलन का शुभारंभ कार्यक्रमः** नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप, एनआईईपीए ने 15 फरवरी 2023 को शैक्षिक पदाधिकारियों के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर मॉड्यूल के दो स्व–निर्देशात्मक सार संग्रह प्रस्तुत किए। मॉड्यूल के इन दो स्व–निर्देशात्मक सार संग्रह का शीर्षक था–

(i) **निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए नेतृत्व समाधानः** स्कूल के नेताओं के लिए स्व–निर्देशात्मक मॉड्यूल का एक पैकेज

(ii) **स्कूल पारिस्थितिकी को सक्षम बनानाः** अधिगम की सहायता करने के लिए स्कूल नेतृत्व का पोषण करनाः नवोदय विद्यालय समिति के सहयोग से 7 मॉड्यूल का एक सेट विकसित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता एनआईईपीए के कुलपति प्रोफेसर सुधांशु भूषण ने की। इस अवसर पर नवोदय विद्यालय समिति के आयुक्त श्री विनायक गर्ग, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के संयुक्त सचिव श्री संदीप जैन और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा उपस्थित थे। प्रोफेसर रश्मि दीवान के नेतृत्व में एनसीएसएल ने शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में एनआईईपीए संकाय, एनसीएसएल–पीजीडीएसएलएम प्रतिभागियों और स्कूल नेतृत्व अकादमियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों की कुल संख्या 47 थी।

निपुण भारत मिशन– नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप ने एनआईईपीए, नई दिल्ली में 3 चरणों में निपुण भारत के लिए स्कूल नेतृत्व विकास पर कार्यशालाओं का आयोजन किया ताकि स्कूल नेतृत्व की भूमिका के संबंध में क्षेत्र से उभरने वाली विविध चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने, सामुदायिक समर्थन, संसाधन प्रबंधन और एनआईपीयूएन मिशन को सफल बनाने के लिए शैक्षणिक नेतृत्व की आवश्यकता को समझा जा सके।

नेटवर्किंग और संस्थागत निर्माण– केंद्र 29 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट सहयोग में काम करता है जहां इसने एससीईआरटी, एसआईईएमएटी, एमआईईपीए, एसआईएसएलईपी, डीआईईटी, डीईआरटी आदि जैसे मौजूदा सरकारी शिक्षा संस्थानों में स्कूल नेतृत्व अकादमियों की स्थापना की है। स्कूल नेतृत्व अकादमियां एनसीएसएल–एनआईईपीए के सह–भागीदारों के रूप में उभरी हैं, जिसमें स्कूल नेतृत्व पर संदर्भ–विशिष्ट मॉड्यूल और सामग्री (पाठ

और वीडियो आधारित) विकसित करना, समग्र शिक्षा, शिक्षा मंत्रालय के तहत प्रशिक्षण के माध्यम से स्कूल प्रमुखों और तंत्र पदाधिकारियों की क्षमता का निर्माण और सूक्ष्म शोध आयोजित करना शामिल है। इन प्रमुख कार्यों के माध्यम से, स्कूल नेतृत्व अकादमियां विभिन्न संदर्भों से स्कूल के नेताओं को अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एनसीएसएल, एनआईईपीए और इसके स्कूल लीडरशिप एकेडमी (एसएलए) के बीच सहक्रियात्मक संबंधों को मजबूत करने के लिए, नेशनल सेंटर फॉर स्कूल लीडरशिप ने 26 से 28 जुलाई 2023 तक इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय समीक्षा और योजना कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार ने किया। इस कार्यशाला में 25 एसएलए में से कुल 47 प्रतिभागी थे। राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य स्कूल नेतृत्व अकादमियों के प्रतिभागियों को स्कूल नेतृत्व के क्षेत्र में नवीन प्रथाओं, दृष्टिकोणों और अनुभवों के प्रसार के लिए एक मंच प्रदान करना था। एनसीएसएल ने प्रतिभागियों से प्रस्तुतियों के रूप में आवेदन भी आमंत्रित किया था जो अनुकरणीय नेतृत्व प्रथाओं और नवाचारों का वर्णन करती हैं जो उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित थी।

14. ''पूर्वोत्तर राज्यों में प्राथमिक स्तर पर स्कूल की भागीदारी और अधिगम में सुधार के लिए राज्य के प्रयास और सर्वोत्तम अभ्यास'' पर 01–03 नवंबर 2023 का परामर्शी बैठक

15. **9–12 जनवरी 2023 को ''समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वैश्विक शिक्षक शिक्षा नीतियों और प्रथाओं'', पर कार्यशाला:** 'समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए वैश्विक शिक्षक शिक्षा नीतियों और प्रचाओ पर पांच सहयोगी संस्थानों जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स, टीआईएसएस मुंबई, एयूडी दिल्ली, एनआईईपीए और जेएमआई के सहयोगी प्रयासों द्वारा एक माड्यूल को डिजाइन और विकसित किया गया है। फिर मॉड्यूल की गहन समीक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन किया गया है। डिजाइन करने की प्रक्रिया नियमित ऑनलाइन चर्चा, अनुसंधान की साहित्य समीक्षा, मसौदा लेखन, महत्वपूर्ण विश्लेषण और संशोधन से प्राप्त की गई। यह परियोजना नवंबर 2021 में शुरू हुई और 10 मार्च 2023 को पूरी हुई। इस मॉड्यूल में भाग लेने वाले संस्थानों से जुड़े 60 छात्रों को मॉड्यूल के माध्यम से 2 (दो) आमने–सामने कार्यशालाओं के माध्यम से पढ़ाया गया था और शेष भागों को आभासी मोड में आयोजित किया गया था। पहली कार्यशाला नवंबर 2022 में टीआईएसएस, मुंबई द्वारा आयोजित की गई थी। वर्तमान कार्यक्रम दूसरी कार्यशाला है जो 9–12 जनवरी, 2023 के दौरान एनआईईपीए, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जीटीईपीपी मॉड्यूल में यूनिट 4 और 5 के लिए प्रशिक्षण देना था। सभी संस्थानों के संकाय ने या तो ऑनलाइन मोड के माध्यम से या अपनी भौतिक उपस्थिति के माध्यम से भाग लिया। संस्थानों के बीच औपचारिक सहयोग ने शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर चर्चा के अवसर भी प्रदान किए हैं, जो विशेष रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अपनाने के बाद बड़े पैमाने पर ध्यान आकर्षित कर रहा है।

16. राज्य उच्चतर शिक्षा परिषदों (एसएचईसी) की दो दिवसीय परामर्शी बैठक 16 और 17 मार्च, 2023 को आयोजित की गई

17. 22–23 मार्च, 2023 को गुणात्मक अनुसंधान और विकास नीति पर एनआईईपीए–नीति आयोग की सहयोगी कार्यशाला।

18. इंडियन हैबिटेट संेटर, नई दिल्ली में 26–27 अक्टूबर, 2023 को ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: भारत में शिक्षक शिक्षा को परिवर्तितकरना'' पर राष्ट्रीय सलाहकार बैठक।

07

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान

अन्य तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) एनआईटीटीटीआर, भोपाल

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, भोपाल (पूर्व में तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल के रूप में ज्ञात) की स्थापना 1965 में भारत सरकार द्वारा सामान्य रूप से तकनीकी शिक्षा और विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार की कार्यरत योजना के एक भाग के रूप में की गई थी। संस्थान की शुरुआत तकनीकी शिक्षकों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के क्रम में हुई जिसमें जून 1966 के ईएफसी ज्ञापन सं. 23–24/65/टी.1 में शामिल व्यापक उद्देश्यों के अनुसार पॉलिटेक्निक शिक्षकों के बीच पेशेवर क्षमता विकसित करना शामिल है। संस्थान ने छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों और क्षेत्र के दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और सुधार के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया। संस्थान अब एक प्रमुख संसाधन संस्थान और देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली के समग्र विकास और विस्तार के लिए उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है और व्यापक विविध श्रम बाजार में योगदान करने की बड़ी जिम्मेदारी वहन करता है। पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों के अलावा यह व्यावसायिक संस्थानों, उद्योग, सार्वजनिक सेवा संगठनों, व्यावसायिक शिक्षा और समुदाय को मानव संसाधन विकास में उनकी व्युत्पन्न आवश्यकताओं के अनुसार बड़े पैमाने पर सेवा प्रदान करता है। संस्थान ने विकासशील देशों की तकनीकी शिक्षा प्रणाली के व्यापक प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है।

उद्देश्य

एनआईटीटीटीआर, भोपाल को पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेजों, व्यावसायिक और प्रबंधन शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षकों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण आयोजित करना, प्रशिक्षण में प्रासंगिकता विकसित करने के लिए तकनीकी शिक्षा प्रणाली पर व्यवस्थित अनुसंधान हेतु अधिदेशित किया गया है। तकनीकी शिक्षा और संस्थागत विकास से संबंधित नवाचारों और कार्यकलापों के लिए कार्रवाई अनुसंधान, मल्टी–मीडिया पैकेज डिजाइन और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए रणनीतियों का विकास करें। अधिगम के संसाधनों को तैयार करना और विपणन या प्रसार करना और दूरस्थ शिक्षा मोड में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। विदेशों से तकनीकी शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, विशेष रूप से आसियान और सार्क देश, सतत शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक विकास एजेंसियों और उद्योग के साथ सहयोग करना, और उद्योग, तकनीकी संस्थानों और संगठनों के लिए परामर्श और विस्तार गतिविधि शुरू करना। एनआईटीटीटीआर, भोपाल संवर्धित अधिदेश के आधार पर प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर अपने कार्यकलापों का एक कैलेंडर तैयार करता है।

राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर), भोपाल ने क्षमता विकास

के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सुधार करके, कार्यक्रम प्रदान करने की प्रक्रिया को सुदृढ़ करके, संसाधन विकास एवं प्रसार तथा आंतरिक सुधार करके अपनी आंतरिक क्षमता को सुदृढ़ करने की चुनौती स्वीकार की है। भविष्य की अपेक्षाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए, एनआईटीटीटीआर, भोपाल देश में अगली पीढ़ी के शिक्षकों की शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के केंद्र के रूप में खुद को फिर से स्थापित कर रहा है। एनआईटीटीटीआर, भोपाल राज्य निदेशालयों और बोर्डों, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों, उद्योग, फील्ड एजेंसियों और सामुदायिक पॉलिटेक्निकों को अपने अल्पकालिक कार्यक्रमों और कार्यशालाओं, पाठ्यक्रम विकास के माध्यम से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है जिसमें परीक्षण और परीक्षाएं, शिक्षा प्रबंधन, शैक्षिक अनुसंधान, अनुदेशात्मक संसाधन विकास, ई–सामग्री विकास, स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए एमओओसी के लिए वीडियो विकास, संस्थागत स्वायत्तता और कार्यक्रमों में लचीलेपन को बढ़ावा देना, व्यावसायिक शिक्षा, विस्तार सेवाएं, परामर्श और दीर्घकालिक कार्यक्रम शामिल है।

प्रस्तावित कार्यक्रम

1. लघु अवधि के कार्यक्रम

संस्थान क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को विविध आवश्यकता–आधारित कार्यक्रम संचालन करता है। वर्ष जनवरी–नवंबर 2023 के दौरान, तालिका 1 में विस्तृत रूप से पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, फार्मेसी और प्रबंधन संस्थानों और क्षेत्रीय संगठनों को कवर करने वाले विभिन्न लक्ष्य समूहों के लिए संपर्क मोड के माध्यम से 169 कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक भागीदारी के साथ आयोजित कार्यक्रमों के प्रकार तालिका 2 में दिए गए हैं।

माहवार कार्यक्रम (जनवरी 2023 से नवंबर 2023)

क्र. सं.	माह	कुल आयोजित कार्यक्रम	कुल प्रतिभागी
1	जनवरी–2023	20	340
2	फ़रवरी –2023	16	241
3	मार्च – 2023	14	168
4	अप्रैल– 2023	8	138
5	मई– 2023	14	345
6	जून– 2023	17	387
7	जुलाई– 2023	28	849
8	अगस्त–2023	13	317
9	सितंबर–2023	12	330
10	अक्टूबर–2023	16	364
11	नवम्बर –2023	11	370
	कुल	**169**	**3849**

अवधि के आधार पर कार्यक्रमों के प्रकार (जनवरी – नवंबर 2023)

क्र.सं.	कार्यक्रमों की अवधि	कार्यक्रमों की संख्या
1.	एक दिन	5
2.	दो दिन	3
3.	तीन दिन	13
4.	एक सप्ताह	127
5.	दो सप्ताह	21
	कुल	**169**

2. एमओओसी कार्यक्रम

एनआईटीटीटीआर भोपाल, पाठ्यक्रम, मान्यता, सतत शिक्षा और कौशल विकास के आधार पर

विभिन्न पाठ्यक्रमों की मेजबानी करने के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के स्वदेशी मंच स्वयं का उपयोग कर रहा है। इन कार्यक्रमों का विवरण तालिका 3 में दिया गया है।

स्वयं– एमओओसी के लिए प्रतिभागियों के ऑकड़े–जनवरी से नवंबर 2023 तक

क्र. सं.	शिक्षक प्रशिक्षण और एनआरसी एमओओसी	क्रेडिट्स	सजाह	2023-24
1	डिप्लोमा इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए मान्यता	3	8	497
2	स्नातक इंजीनियरिंग कार्यक्रम के लिए मान्यता	3	8	687
3	स्नातकोत्तर इंजीनियरिंग कार्यक्रमों के लिए मान्यता–	2	4	0
4	शिक्षण और अधिगम में आईसीटी	2	4	3476
5	अधिगम और निर्देश	2	4	0
6	बुनियादी शिक्षण विधियाँ	2	4	5203
7	निर्देशात्मक/शैक्षिक मीडिया	2	4	2320
8	उन्नत अनुदेशात्मक तरीके	2	4	3157
9	उच्चतर शिक्षा शिक्षकों के लिए पेशेवर नैतिकता	2	4	0
10	एनआरसी 1 – संज्ञानात्मक क्षेत्र अधिगम का आकलन	2	4	0
11	उच्चतर शिक्षा में एनआरसी 2– व्यावहारिक और सामाजिक कौशल का आकलन	2	4	0
	एआईसीटीई एनआईटीटीटी मॉड्यूल एमओओसी		**।**	**15340**
1	एआईसीटीई एनआईटीटीटी मॉड्यूल–2 पेशेवर नैतिकता और सतत विकास	3	8	4620
2	एआईसीटीई एनआईटीटीटी मॉड्यूल –4 निर्देशात्मक योजना और वितरण	3	8	4478
			ख	**9098**
			कुल क+ख	**24438**

गतिविधियाँ

- वर्तमान शैक्षणिक कॅलेण्डर में विभिन्न संस्थाओं से कुल 3849 प्रतिभागियों ने 169 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया। जनवरी 2023 से नवंबर 2023 तक, 859 प्रशिक्षण दिवस आयोजित किए गए। इनमें इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निकों में नए भर्ती हुए शिक्षकों के लिए 09 प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं।

- राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड (एसबीटीई), बिहार के लिए संस्थान द्वारा एक पाठ्यक्रम तैयार करने की परियोजना शुरू की गई है। वर्ष 2023 के दौरान, इस परियोजना में परिणाम आधारित पाठ्यक्रम को तैयार करने/पुननिर्मित करने और विकास करने के लिए, 18 डिप्लोमा कार्यक्रम।
- वर्ष 2023 के दौरान संकाय और विशेषज्ञों को शामिल करते हुए 25 वीडियोकार्यक्रम विकसित किए गए। 207 शिक्षकों के शिक्षण अभ्यास की रिकॉर्डिंग की गई।
- वर्ष के दौरान, 24438 प्रतिभागियों ने स्वयं मंच पर संस्थान के संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए गए वृद्ध मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण कराया।
- वर्ष 2023 के दौरान कुल 560 शिक्षण संसाधन विकसित किए गए, जिसमें वीडियो, सरकारी ग्राहकों के लिए वृत्तचित्र, आंतरिक निर्माण, सभी वीडियो के लिए स्क्रिप्ट और प्रस्तुतियां और अन्य कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तुतियाँ, और विभिन्न ई–सामग्री शामिल हैं। उपयोगी अनुदेशात्मक संसाधनों को विकसित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों, उद्योगों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के विशेषज्ञों ने अपनी विशेषज्ञता का योगदान दिया।
- संकाय/स्टाफ की नियुक्ति हेतु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण नीति लागू है।
- संस्थान, उद्योगों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के बीच एक मजबूत शैक्षणिक संबंध स्थापित किया गया है। योजना एवं वास्तुकला विद्यालय, भोपाल के साथ एलओआई/समझौता ज्ञापन को जारी रखने के अतिरिक्त, वर्ष 2023 के दौरान प्रमुख विश्वविद्यालयों और संगठनों के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर छात्रों और शिक्षकों के लिए अनुसंधान के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम और क्षमता निर्माण के लिए हस्ताक्षर किए गए।
- वर्ष 2023 के दौरान संस्थान में 20 से अधिक विशेष व्याख्यान आयोजित किए गए।

एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़

संस्थान इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक और उद्योग में कार्यरत संकाय पेशेवरों और कर्मचारियों के लिए आवश्यकता–आधारित और अनुकूलित संकाय विकास कार्यक्रम संचालन करता है। जनवरी 2023 से 6 दिसंबर 2023 तक कुल 48858 (23896+24962) प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। 295 अल्पकालिक कार्यक्रम (संपर्क मोड और आईसीटी मोड) आयोजित किए गए और 23896 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। इस अवधि के दौरान, संस्थान 03 एआईसीटीई एनआईटीटीटी मॉड्यूल का पुनः संचालन संचार कौशल, मोड और ज्ञान प्रसार, रचनात्मक समस्या समाधान, नवाचार और सार्थक अनुसंधान और विकास और संस्थागत प्रशासनिक प्रक्रियाएं और 06 स्वयं एमओओसी पाठ्यक्रमों– ग्राफिक्स और एनीमेशन विकास, तकनीकी शिक्षा में अनुसंधान, स्व–शिक्षण सामग्री विकास, शैक्षिक वीडियो उत्पादन और उद्यमिता विकास और संचार कौशल का 02 बार पुनः संचालन करना कुल 24962 (5743+12044+7175) प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। संस्थान ने 01 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी भी आयोजित की जिसमें 84 व्यक्तियों ने भाग लिया। संस्थान ने 30–31 मार्च 2023 तक "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स (आईसीएआईओटी 2023) पर 01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन" पर 01 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 102 व्यक्तियों ने भाग लिया। संस्थान ने 26 कार्यशालाओं का आयोजन किया और पूरे भारत से 1798 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया। दीर्घकालिक कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में, संस्थान नियमित और मॉड्यूलर मोड दोनों में इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर कार्यक्रम आयोजित करता है, जिसमें

2023–24 में 14 छात्रों (नियमित) और 57 छात्रों (मॉड्यूलर) को प्रवेश दिया गया। पीएचडी कार्यक्रम में 60 छात्र का नामांकन हैं और इस दौरान 10 छात्रों को सम्मानित किया गया है. विभिन्न प्रशिक्षणों में छात्रों की सहायता करने के लिए, 05 छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 136 छात्र इन छात्र प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लाभान्वित हुए।

इस अवधि के दौरान, संस्थान ने कुल 66 वीडियो फिल्में (एमओओसी वीडियो: 40 और अन्य वीडियो: 26) और एनसीटीईएल में 295 वीडियो फिल्में अपलोड की गईं। कुल 17 अन्य वीडियो फिल्मों को संपादित किया गया है। 02 पेटेंट "संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी के लिए वास्तविक समय गैर–संपर्क कंपन माप प्रणाली" और "भूकंप प्रतिरोधी विस्को–लोचदार ऊर्जा विसिपेटर लिंक तत्व" शीर्षक के रूप में प्रदान किए गए थे, 02 पेटेंट प्रकाशित किए गए, 01 पेटेंट दायर किए गए और 02 कॉपीराइट प्रदान किए गए। संकाय सदस्यों द्वारा 05 पाठ्य पुस्तक, 01 संपादित पाठ्य पुस्तक, 33 पुस्तक अध्याय प्रकाशित किए गए। संस्थान के संकाय ने एससीआई पत्रिकाओं में 61 शोधपत्र, गैर–एससीआई पत्रिकाओं में 48 शोधपत्र, राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 12 शोध पत्र और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में 31 पत्र प्रकाशित किए।

एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

1. संस्थान ने इस विषय"सतत विकास को सुदृढ़ करने में बिजनेस इनक्यूबेटरों की भूमिका: एक टीवीईटी परिप्रेक्ष्य'' पर सीपीएससी, मनीला, फिलीपींस के सहयोग से 4 से 8 सितंबर, 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के कुल 12 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
2. संस्थान ने विभिन्न दूतावासों के साथ संवाद करने के लिए एक नई पहल की थी। एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ के दो वरिष्ठ संकाय सदस्यों की एक टीम ने नई दिल्ली में विभिन्न दूतावासों का दौरा किया और अर्जेंटीना, इथियोपिया, साइप्रस, लाओ पीडीआर, वियतनाम, घाना, फिजी, सेशेल्स, श्रीलंका, गुयाना, रूस और अफ्रीकी एशियाई ग्रामीण विकास संगठन दूतावास के राजदूतों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विदेशी कार्यक्रमों/विदेशी शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संचालन के अवसरों का पता लगाने के लिए बातचीत की।

एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ के साथ उद्योग सहयोग

1. **06 सितंबर, 2023 को एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ में द्योग–अकादमिक एकीकरण और सतत विकास पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी:** कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज (सीपीएससी), फिलीपींस और आईआईटी रुड़की के सहयोग से एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ ने 06 सितंबर, 2023 को चंडीगढ़ में उद्योग–अकादमिक एकीकरण और सतत विकास पर एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों के 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिन्होंने उद्योग, शैक्षणिक एकीकरण और टिकाऊ उद्यमिता के व्यापक विषयों पर दस्तावेजी प्रस्तुतियां दीं। इसके अलावा, चंडीगढ़ और मोहाली उद्योग संघ के प्रतिनिधियों सहित क्षेत्र के 13 उद्योग प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।
2. उद्योग के साथ मजबूत संबंध विकसित करने की पहल के रूप में, संस्थान ने एनएसडीसी के सहयोग से 5 सितंबर 2023 से पूरे इंडिया के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिए दो महीने का कार्यक्रम शुरू किया है। 20–20 के दो बैचों में 40 स्वास्थ्य कर्मियों के एक समूह को

जर्मन भाषा में प्रशिक्षित किया जा रहा है. जर्मनी के चार प्रशिक्षक एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ में तैनात हैं और वे प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं. वर्तमान प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद, निर्माण, स्वास्थ्य सेवा, खुदरा, तेल और गैस, आतिथ्य और विनिर्माण के क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए नए बैच शामिल किए जाएंगे।

3. **5 सितंबर 2023 को उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल पर गोष्ठी का आयोजन:** संगोष्ठी में 21 वीं सदी के कौशल शोधार्थियों को अद्यतन करने के लिए 05 व्यापक सत्र (सभी विषयों में) थे जैसे साइबर सुरक्षा कौशल (अभ्यास सत्र), उद्योग में एआरः सफल संवर्धित वास्तविकता कार्यान्वयन (अभ्यास सत्र), शैक्षणिक संस्थानों में स्टार्टअप, और के लिए नीति निर्माताओं, संकाय, शिक्षा के लिए स्व–सतत स्टार्टअप इको–सिस्टम (एनईपी 2020 के अनुरूप) ।
4. संस्थान ने 27 सितंबर 2023 को आईबीएम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए।
5. संस्थान ने विभिन्न विभागों और उद्योगों के साथ 13 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। संस्थान ने इस अवधि के दौरान लगभग **927.18** लाख रुपए आईआरजी उत्पन्न किया।

अन्य गतिविधियाँ

- एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ द्वारा ईबीएसबी की पहल के तहत युवा संगम कार्यक्रम। चंडीगढ़ के छात्रों ने सिलचर, असम का दौरा किया और सिलचर, असम के छात्रों ने चंडीगढ़ का दौरा किया।

पंजाब के राज्यपाल माननीय श्री बनवारीलाल पुरोहित ने छात्र से मुलाकात की। छात्रों ने उनके साथ पूर्वोत्तर की संस्कृति साझा की।

- 30 से 31 मार्च 2023 तक "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन
- महिलाओं के लिए प्रतिकूल कार्य वातावरण के अंतर्निहित कारणों को समाप्त करते हुए एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ एक सुरक्षित जेंडर–जागरूकता कार्यस्थल है। इसके अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति गठित की जाती है।
- एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ के संकाय और युवा संगम के छात्रों ने 29 जुलाई 2023 को प्रगति मैदान में तीसरे वर्ष के एनईपी कार्यान्वयन के उत्सव में भाग लिया।
- एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ ने 5 सितंबर, 2023 को उद्योग 4.0, नवाचार और 21वीं सदी के कौशल पर एक गोष्ठी का आयोजन किया।
- सीपीएससी मनीला के सहयोग से 4 से 8 सितंबर 2023 तक "उद्योग–अकादमिक एकीकरण और सतत उद्यमिता" पर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यक्रम
- श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय शिक्षा मंत्री ने 27 सितंबर 2023 को डिजिटल कौशल और उभरती प्रौद्योगिकी में कौशल पर आईबीएम के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की अध्यक्षता की

- 5 अक्टूबर 2023 को, डॉ. सुभाष सरकार, माननीय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ ।

- 10—16 अक्टूबर, 2023 को नेहरू युवा केंद्र, चंडीगढ़ द्वारा 15 वें जनजातीय आदान—प्रदान कार्यक्रम का आयोजन जिसमें एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ द्वारा । हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हमें जनजातीय समाज से संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन के गुण सीखने चाहिएं ।

- संस्थान के संकाय, स्टाफ और छात्रों ने कलश में माटी लगाई । 15 अक्टूबर 2023 को, प्रो. बी. आर. गुर्जर, निदेशक, एनआईटीटीटीआर चंडीगढ़ ने श्रीमती मीता राजीवलोचन, आईएएस, सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारत सरकार को अमृत कलश देते हुए ।

- प्रो वी. जी. तलवार, माननीय अध्यक्ष, एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ के बीओजी का 31 अक्टूबर 2023 को दौरा किया
- स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर, 31 अक्टूबर 2023 को एनआईटीटीटीआर, चंडीगढ़ में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया गया।

एनआईटीटीटीआर, चेन्नई

1. अल्पकालिक पाठ्यक्रम – ऑनलाइन और संपर्क मोड

1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023			
क्र.सं.	**अल्पकालिक पाठ्यक्रम मोड**	**पाठ्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
1	संपर्क मोड	50	1208
2	ऑनलाइन मोड	91	2872

क्र.सं.	अल्पकालिक पाठ्यक्रम मोड	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1 जनवरी 2023 – 31 मार्च 2023			
1	संपर्क मोड	10	246
2	ऑनलाइन मोड	32	877
1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023			
3	संपर्क मोड	14	419
4	ऑनलाइन मोड	25	603
1 जुलाई 2023 – 30 सितंबर 2023			
5	संपर्क मोड	23	462
6	ऑनलाइन मोड	37	807
1 अक्टूबर 2023 – 30 नवंबर 2023			
7	संपर्क मोड	3	81
8	ऑनलाइन मोड	9	585
कुल		**141 पाठ्यक्रम**	**4080 प्रतिभागी**

2. अल्पकालिक पाठ्यक्रम– इंजीनियरिंग कॉलेज/उद्योग/सरकारी विभाग

क्र.सं.	अवधि	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	1 जनवरी 2023 – 31 मार्च 2023	12	459
2	1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023	06	191
3	1 जुलाई 2023 – 30 सितंबर 2023	08	307
4	1 अक्टूबर 2023 – 30 नवंबर 2023	08	120
1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023		**26 पाठ्यक्रम**	**1077 प्रतिभागी**

3. औद्योगिक प्रशिक्षण/कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित

क्र.सं.	अवधि	पाठ्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	1 जनवरी 2023 – 31 मार्च 2023	1	8
2	1 अप्रैल 2023 – 30 जून 2023	1	7
3	1 जुलाई 2023 – 30 सितंबर 2023	1	8
1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023		**3 पाठ्यक्रम**	**23 प्रतिभागी**

4. विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला/बूट शिविर

क्र.सं.	कार्यक्रम का शीर्षक	प्रतिभागियों की संख्या
1	ई–मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक वाहन इंजीनियरिंग पर गुणवत्तापूर्ण कार्यशाला	30
2	एआईसीटीई द्वारा आईडीई बूटकैंप	215

5. विकसित पाठ्यक्रम = 77

क्र.सं.	विकसित पाठ्यक्रम की कुल संख्या	संशोधित पाठ्यक्रम की कुल संख्या
1	76	154

6. दीर्घकालिक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन

क्र.सं.	कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रतिभागियों की कुल संख्या
1	5	105

7. स्नातकोत्तर/पीएचडी छात्रों के लिए पाठ्यक्रम = 118

8. वेबिनार/सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएं/संगोष्ठी/उद्योग बैठकें

क्र.सं.	कार्यक्रमों की कुल संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	33	3697

9. **स्वयं/एनआईटी/अन्य (प्रतिभागी) के तहत प्रस्तुत एमओओसी = 42798**

10. **शुरू किए गए अनुसंधान परियोजना और परामर्श कार्य (रूपए लाखों में) = 795 (लगभग)**

क्र.सं.	अवधि (पूर्ण/जारी)	गणना
1	चल रही परियोजना	14
2	पूर्ण हो चुकी परियोजना	3

क्र.सं.	परियोजना	लक्षित प्रतिभागी
1	पीएमकेवीवाई 4.0 टीओटी/टीओए	800
2	पीएमकेवीवाई 4.0 कौशल हब पहल	240

11. विकसित शिक्षण सामग्री (प्रशिक्षण और प्रयोगशाला मैनुअल, अनुदेशात्मक सामग्री / पाठ्यक्रम सामग्री, वीडियो, एमएमएलपी, पीजी / पीएचडी छात्रों के लिए नए पाठ्यक्रम सहित) = 161

12. राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में देश /विदेशों में, प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में अकादमिक बातचीत के लिए दौरा किया = 10

13. राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण पहल (एनआईटीटीटी) के प्रतिभागी = 16219

14. **हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन**

क्र.सं.	एमओयू की कुल संख्या
1	58

एनआईटीटीटीआर, कोलकाता

प्रशिक्षण उपलब्धि रिपोर्ट:

अवधि के दौरान (1 जनवरी 2023 से 30 नवंबर 2023), संस्थान ने 119 अल्पकालिक, इन–हाउस प्रशिक्षण और ई–लर्निंग (आईसीटी मोड) कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि देश भर में विभिन्न पॉलिटेक्निकों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य संगठनकों, स्टाफ के 7871 संकाय सदस्यों, अधिकारियों और स्टाफ सदस्यों, प्रशिक्षित किया जा सके।

कार्यशाला/गोष्ठि

संस्थान ने उभरते विषयों पर विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित कीं, जिनमें प्रतिभागियों और संक्षिप्त रिपोर्ट का विवरण नीचे दिया गया है।

कार्यशाला का नाम	प्रतिभागियों की संख्या
डेटा एनालिटिक्स, सुरक्षा और आईपीआर पर व्यावसायिक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	50
कार्यान्वयन के लिए एनईपी 2020 योजना	151
एनबीए की तैयारी	98
पाठ्याचर्या संशोधन कार्यशाला (मेघालय)	11
राष्ट्रीय क्रेडिट ढांचा (एनसीआरएफ) पर राष्ट्रीय कार्यशाला	9
पाठ्यचर्या संशोधन कार्यशाला (अरुणाचल प्रदेश)	6
एनबीए प्रत्यायन और एसएआर तैयार करना	45
एनआईटीटीटीआर कोलकाता के दृष्टिकोण और मिशन पर दोबारा ध्यान देने संबंधी कार्यशाला	32
कुल प्रतिभागी	**402**

संस्थागत कार्यक्रम

- **एनआईटीटीटीआर, कोलकाता का 59वां स्थापना दिवस कार्यक्रम**– एनआईटीटीटीआर कोलकाता का 59वां स्थापना दिवस 11 जनवरी 2023 को मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में आईआईईएसटी शिबपुर के पूर्व निदेशक प्रो अजय कुमार रे ने की। सम्मानित अतिथि डॉ. शाम अर्जुनवाडकर, अध्यक्ष, बीओजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएएमटी), रांची उद्घाटन सत्र में शामिल हुए। बीओजी के अध्यक्ष, पद्मश्री श्री हर्षवर्धन नेवतिया अपनी पूर्व व्यस्तता के कारण शामिल नहीं हो सके, लेकिन सभी कर्मचारियों को बधाई दी और अपनी शुभकामनाएं और बधाई भेजीं। संस्थान के निदेशक प्रो देबी प्रसाद मिश्रा, के नेतृत्व में, "समृद्ध भविष्य के लिए एनआईटीटीटीआर कोलकाता का कार्याकल्प" विषय पर एक पैनल चर्चा भी आयोजित की गई। संस्थान की सांस्कृतिक पत्रिका 'भारतीय कला और शिल्प' का उद्घाटन इस दिन अतिथियों ने किया।

- **नवाचार, इनक्यूबेशन और उद्यमिता विकास पर राष्ट्रीय संगोष्ठी**: एनआईटीटीटीआर कोलकाता ने 22 मार्च 2023 को नवाचार, इनक्यूबेशन और उद्यमिता विकास पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी (वेब) का आयोजन किया है। संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं, छात्रों, संकाय सदस्यों, तकनीकी कर्मचारियों और उद्योग कर्मियों को नवाचार, बौद्धिक संपदा अधिकार, इनक्यूबेशन और उद्यमिता विकास के क्षेत्र में अपने ज्ञान को साझा करने के लिए एक साथ लाना था। एनआईटीटीटीआर कोलकाता के माननीय निदेशक देबी प्रसाद मिश्रा, ने अतिथियों और प्रतिभागियों का स्वागत किया। स्वागत भाषण में, प्रो मिश्रा ने संगोष्ठी के उद्देश्य, शिक्षकों और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया और उद्यमिता के महत्व पर चर्चा की। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास पर बल दिया। मिश्रा ने आगे कहा कि देश को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाने और अगले 25 वर्षों में नेतृत्व करने की आवश्यकता है।

- **एनईपी–2020 के सफल कार्यान्वयन के 3 वर्षों पर कार्यशाला**: संस्थान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन का जश्न मनाने के लिए 26 जुलाई 2023 को उपरोक्त पर एक कार्यशाला आयोजित की। एनआईटीटीटीआर–कोलकाता के निदेशक प्रोफेसर देबी प्रसाद मिश्रा ने सभी प्रतिनिधियों और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और एनआईटीटीटीआर–कोलकाता की गतिविधियों के बारे में प्रकाश डाला. उनके अनुसार, एनईपी 2020 लोगों की नीति है। उन्होंने एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। एनआईटीटीटीआर–कोलकाता में कार्यान्वित किए गए कार्यक्रमों की कुछ विशेषताएं जैसे एनसीआरएफ के बारे में सुग्राहीकरण, उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में एनईपी का कार्यान्वयन, परामर्शदाता प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना, ई–एसटीटीपी को प्रस्तुत करना आदि। प्रोफेसर शांतनु चट्टोपाध्याय, निदेशक आईआईआईटी–कल्याणी, आईआईईएसटी शिबपुर के प्रोफेसर सुदीप कुमार रॉय, आईएसीएस कोलकाता के प्रोफेसर सुहृत घोष, विश्व भारती विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सरबजीत सेनगुप्ता विभिन्न महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों में से हैं।

राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)

स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमा धारकों (तकनीकी) और व्यावसायिक क्षेत्र में उत्तीर्ण होने वालों के संबंध

में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) मुंबई, कानपुर, चेन्नई और कोलकाता में शिक्षुता/प्रायोगिक (बीओएटी/बीओपीटी) के चार क्षेत्रीय बोर्डों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। एनएटीएस केन्द्रीय शिक्षुता परिषद (सीएसी) द्वारा निर्धारित नीतियों और दिशा–निर्देशों के अनुसार औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों में स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों (तकनीकी) को व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करता है जो प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत गठित एक शीर्ष सांविधिक निकाय है। इन बोर्डों, बीओएटी/बीओपीटी जो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन हैं, अपने–अपने क्षेत्रों में समय–समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के तहत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया है।

इस योजना का मूल उद्देश्य नए स्नातक इंजीनियरों और डिप्लोमा धारकों के अब तक व्यावहारिक/व्यावहारिक अनुभव में अंतर, यदि कोई हो, को पाटना और उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार नौकरी आमेलन में उनकी उपयुक्तता बनाने के लिए उनके तकनीकी कौशल को बढ़ाना भी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध् यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने राष् ट्रीय शिक्षुता योजना (एनएटीएस) के तहत वर्ष 2021–22 से 2025–26 (दिनांक 31–03–2026 तक) की अवधि के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षुओं को 3054 करोड़ रुपये की वजीफा सहायता के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम के छात्रों के अलावा मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के छात्रों को शामिल करने के लिए एनएटीएस के दायरे का भी विस्तार किया गया है। इस योजना का उद्देश्य कौशल पारिस्थितिकी को मजबूत करके कौशल स्तर के मानकों को बढ़ाना है और बाद में, अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख रोजगार उत्पन्न करने में मदद करेगी।

यह योजना स्किल इंडिया के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के साथ, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा में लाने की परिकल्पना की गई है, यह योजना एक दूसरे के साथ शिक्षा और रोजगार के अनुकूलन को बढ़ावा देगी. व्यावसायिक शिक्षा को अगले दशक में चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्चतर शिक्षा संस्थानों में एकीकृत किया जाएगा। यह योजना विनिर्माण के वर्तमान और उभरते क्षेत्रों में मानव संसाधनों की क्षमता निर्माण के लिए जिम्मेदार होगी, जिसकी पहचान 'प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव' (पीएलआई) और गतिशक्ति के तहत की गई है।

अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा दिया जाता है जिसे केन्द्र सरकार और नियोक्ता के बीच 50:50 के आधार पर बांटा जाता है। शिक्षुओं की विभिन्न श्रेणियों को देय वजीफा दरों का विवरण इस प्रकार है: –

प्रशिक्षुओं की श्रेणी	दिनांक 01.04.2021 की स्थिति के अनुसार संशोधित दरें
स्नातक प्रशिक्षु	9000/-
डिप्लोमा प्रशिक्षु	8000/-

एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा विकसित किया जा रहा नया एनएटीएस 2.0 पोर्टल अभी भी प्रगति पर है। इसकी निगरानी बीओएटी/बीओपीटी के माध्यम से की जाती है क्योंकि वे छात्रों/उद्योगों/संस्थानों जैसे अन्य हितधारकों के साथ अंतिम उपयोगकर्ता हैं।

एनएटीएस के तहत वर्ष 2023–24 के लिए वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

वित्तीय (रु. करोड़ में)

शीर्ष	बजट अनुमान				जारी की गई राशि (दिनांक 24.01.2024 तक)			
	ओएच–31	ओएच –35	ओएच –36	कुल	ओएच –31	ओएच –35	ओएच –36	कुल
स्थापना शीर्ष	12.20	2.12	20.31	34.63	9.25	1.30	10.76	21.31
छात्रवृत्ति शीर्ष	बजट अनुमान – 440 संशोधित अनुमान– 460				384.11			

वास्तविक

लक्ष्य	उपलब्धि (24.01.2024 तक)
400000 प्रशिक्षु	199101 प्रशिक्षु

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी हटिया, रांची, झारखंड

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी (एनआईएएमटी), रांची की स्थापना वर्ष 1966 में यूएनडीपी–यूनेस्को के सहयोग से भारत सरकार द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी (एनआईएफएफटी) के रूप में की गई थी। यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत है। संस्थान का प्रबंधन अध्यक्ष के साथ शासी मंडल में निहित है और इसके शीर्ष पर अध्यक्ष हैं और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), शिक्षा मंत्रालय, निजी और सार्वजनिक उद्यम, तकनीकी और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों से सदस्य लिए गए हैं।

अपनी स्थापना के बाद से, एनआईएएमटी (पूर्व में एनआईएफएफटी) को सार्वजनिक क्षेत्र और उद्योग द्वारा ढलाई तकनीकी, निर्माण तकनीकी और अन्य संबद्ध विनिर्माण विषयों के क्षेत्र में योग्य इंजीनियरों और सुप्रशिक्षित विशेषज्ञों को प्रदान करने वाले निकाय के रूप में देखा गया है. संस्थान ने तकनीकी शिक्षा प्रदान करने और इन इंजीनियरिंग विषयों में शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक अग्रणी संस्थान के रूप में ख्याति अर्जित की है। संस्थान प्रासंगिक क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास का दृढ़ता और सावधानीपूर्वक संचालन कर रहा है और उद्योगों को परामर्श और प्रलेखन सेवाएं प्रदान कर रहा है।

उद्देश्य:

भारत और विदेश में इस क्षेत्र में तेजी से बदलते आर्थिक और प्रौद्योगिकी परिदृश्य की चुनौतियों का सामना करने की दृष्टि के अनुरूप –

क) संवर्धित बौद्धिक और भौतिक बुनियादी ढाँचा

ख) स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रमों के लिए अत्यधिक लचीला और अद्यतन शैक्षणिक पाठ्यक्रम

ग) नवीनतम तकनीकी जानकारी के साथ सतत शिक्षा

घ) परामर्शी एवं तकनीकी सेवाएँ

ङ) अनुसंधान एवं विकास पैकेज और प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

च) दस्तावेज़ीकरण, सूचना पुनर्प्राप्ति सेवाएँ और कंप्यूटर नेटवर्किंग

छ) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उद्योगों/विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग

ज) मानव संसाधन विकास

झ) आत्मनिर्भरता की दिशा में आंतरिक संसाधन सृजन

प्रस्तावित कार्यक्रम: एनआईएएमटी (पूर्व में एनआईएफएफटी) में पांच अध्ययन विभाग हैं, अर्थात्:

1. फाउंड्री प्रौद्योगिकी
2. फोर्ज प्रौद्योगिकी
3. विनिर्माण इंजीनियरिंग
4. सामग्री और धातुकर्म इंजीनियरिंग
5. अनुप्रयुक्त विज्ञान और मानविकी

शैक्षणिक कार्यक्रम:

एनआईएएमटी (पूर्व में एनआईएफएफटी) निम्नलिखित नियमित कार्यक्रम संचालित करता है:

1. अनुसंधान स्तर

   क) डॉक्टोरल कार्यक्रम

2. स्नातकोत्तर स्तर [मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम.टेक.)]
   - क) फाउंड्री—फोर्ज प्रौद्योगिकी में एम.टेक
   - ख) विनिर्माण इंजीनियरिंग में एम.टेक
   - ग) पर्यावरण इंजीनियरिंग में एम.टेक
   - घ) सामग्री विज्ञान और इंजीनियरिंग में एम.टेक
3. स्नातक स्तर [प्रौद्योगिकी स्नातक (बी.टेक)]
   - क) विनिर्माण इंजीनियरिंग में बी.टेक
   - ख) धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरिंग में बी. टेक
4. उन्नत डिप्लोमा स्तर [उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एडीसी)]
   - क) फाउंड्री प्रौद्योगिकी में एडीसी
   - ख) फोर्ज प्रौद्योगिकी में एडीसी

वर्ष 2019—20 शैक्षणिक सत्र से निर्माण इंजीनियरिंग के स्थान पर यांत्रिक इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम प्रस्तावित है।

प्रवेश नीतिः छात्रों को सीसीएमटी के माध्यम से एम.टेक कार्यक्रम और सीएसएबी के माध्यम से बी. टेक कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। संस्थान उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम और डॉक्टरेट कार्यक्रम के लिए अपनी चयन प्रक्रिया आयोजित करता है. संस्थान अनुसंधान स्तर, स्नातकोत्तर और स्नातक डिग्री में डिग्री प्रदान करने के लिए रांची विश्वविद्यालय और झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से संबद्ध है। उन्नत डिप्लोमा संस्थान द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

गतिविधियांः

- **शिक्षा को जारी रखनाः** अंशकालिक अनुसंधान कार्यक्रमों, उद्योग के लिए स्थापित और उभरती प्रथाओं में पुनश्चर्या और विशेष पाठ्यक्रम जैसे सभी स्तरों पर शिक्षा को जारी रखना समाज के विकास में योगदान देने वाले संस्थान की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है। कार्यक्रम आमतौर पर 1—2 सप्ताह की अवधि के होते हैं जो ढलाई और निर्माण प्रौद्योगिकी, प्रदूषण नियंत्रण, ऊर्जा संरक्षण और प्रबंधन, विनिर्माण प्रक्रियाओं, सामग्री लक्षण वर्णन और औद्योगिक महत्व के अन्य क्षेत्रों को कवर करने वाले विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। गतिविधियों में उद्योगों या संगठनों के अनुरोध पर अल्पकालिक अवधि के यूनिट—आधारित कार्यक्रम भी शामिल हैं, जो उनकी आवश्यकता के अनुसार या तो उनके परिसर में या संस्थान में हैं। संस्थान को दक्षिण—पूर्व एशिया और अफ्रीका के अन्य विकासशील देशों के लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी विशेषाधिकार प्राप्त है। विगत वर्षों में बर्मा, श्रीलंका और नाइजीरिया जैसे देशों के छात्रों ने संस्थान में प्रशिक्षण लिया है। संस्थान ने नेपाली और श्रीलंकाई इंजीनियरों के लिए ढलाई प्रौद्योगिकी में यूनिट—आधारित कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं।
- **अनुसंधान गतिविधियाँः** संस्थान का एक मुख्य उद्देश्य ढलाई, निर्माण और संबंधित वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में औद्योगिक अनुसंधान और विकास कार्य करना है। अनुसंधान गतिविधियों को करने के लिए संस्थान में सभी अवसंरचनात्मक सुविधाएं मौजूद हैं. आर एंड डी कार्यक्रम पैटर्न डिजाईन और निर्माण, और प्रणाली तैयार करना, पिघलाना, कास्टिंग, निर्माण प्रक्रिया का अनुकरण, डाई अनुमान, स्नेहक के मूल्यांकन, सीएडी और सीएएम कास्टिंग और निर्माण, विफलता विश्लेषण, पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण, धातु मैट्रिक्स कंपोजिट और पाउडर धातु विज्ञान निर्माण जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं ।अधिकांश संकाय सदस्यों के पास पीएच.डी की डिग्री है। संकाय सदस्य अपने शोध कार्यों को प्रस्तुत करने के

लिए विभिन्न सेमिनारों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों में लगातार भाग लेते हैं। कई शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी प्रकाशित होते हैं।

- **परामर्शी सेवाएं:** संस्थान फाउंड्री, फोर्ज और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में उद्योगों को परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने, तकनीकी परियोजनाओं की तैयारी और निष्पादन, उपकरण और मशीनरी के चयन और मूल्यांकन, कच्चे माल के परीक्षण और उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण के रूप में परामर्शी सेवाओं का विस्तार किया जाता है।

वर्ष 2023–24 के वित्तीय ऑकड़े

एनआईएएमटी, रांची		(रु. करोड़ में)
वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान – 2023–24	जारी की गई कुल धनराशि (दिनांक 24.01.2024 तक)
ओएच –31	17.00	9.50
ओएच –35	09.00	6.50
ओएच–36	27.00	10.50
कुल	**53.00**	**26.50**

संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लोंगोवाल, पंजाब

संक्षिप्त पृष्ठभूमि: वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा स्थापित, संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने देश के पेशेवर संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच स्वयं के लिए एक अच्छा स्थान बनाया है। यह उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण पर जोर देने के साथ शिक्षा की मॉड्यूलर प्रणाली की एक नई अवधारणा को अपनाकर विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस संस्थान के शैक्षिक कार्यक्रम गैर–पारंपरिक, अभिनव हैं और व्यावहारिक अनुप्रयोगों पर उचित जोर देने के साथ उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विभिन्न विषयों में प्रमाण पत्र से डॉक्टरेट तक के कार्यक्रमों के साथ, संस्थान इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों में एक मजबूत आधार के साथ सभी स्तरों पर उच्च गुणवत्ता वाले लचीले इंजीनियरिंग कौशल का उत्पादन करता है। संचार, समूह कार्य और अंतर–विषयात्मक कार्य, योजना–लागत और उद्यमशीलता के विचार के विशेष कौशल सैद्धांतिक समझ, रचनात्मकता और नवाचार के साथ संश्लेषित होते हैं।

चार सौ एकड़ से अधिक में मौजूद यह संस्थान प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली से अद्भुत रूप से समृद्ध है। यह पर्यावरण और स्थितियों को वास्तविक रूप में प्रकट करके ताज़ा रंगों के माध्यम से व्यक्त होता है जिसे मानव आत्मा को सच्ची तृप्ति और आराम देने के लिए तैयार किया गया। संस्थान में वृहद स्तर पर किए गए वृक्षारोपण संस्थान को एक सजीव सौंदर्य प्रदान करते हैं। संस्थान विश्व में पक्षियों की कुछ दुर्लभ प्रजातियों की झलक देते हुए कई प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है। संस्थान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जो स्वयं को चिंताओं से दूर करता है, इच्छाओं का अभिसरण करता है और सोच और विश्लेषण के मूल्यों को बढ़ावा देता है. संस्थान में एक छात्र के पास शहरीकृत आवासों में प्रचलित सामान्य आकर्षण नहीं है, जो उसे शारीरिक, नैतिक और अकादमिक रूप से मजबूत बनाता है।

नवीनतम उपलब्धि – राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद द्वारा "क" ग्रेड के रूप में संस्थान का प्रत्यायन

वर्ष 2023–24 के वित्तीय ऑकड़े

एसएलआईईई, लोंगोवाल		(रु. करोड़ में)
वस्तु शीर्ष	बजट अनुमान – 2023–24	जारी की गई कुल धनराशि (24.01.2024 तक)
ओएच–31	26.00	10.00
ओएच –35	12.00	5.57
ओएच –36	73.00	36.00
कुल	**111.00**	**51.57**

गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), मालदा

गनी खान चौधरी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (जीकेसीआईईटी), मालदा की स्थापना एक बहुस्तरीय अंतर–विषयात्मक और अंतर–क्षेत्रीय कुशल, पेशेवर, तकनीकी जनशक्ति बनाने और शिक्षाविदों में तकनीकी क्षमता के विकास और हस्तांतरण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से की गई थी। संस्थान मुख्य रूप से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में लचीले, मॉड्यूलर, क्रेडिट–आधारित बहु–विषयक प्रवेश कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए स्थापित किया गया था और उद्यमशीलता के एक तत्व को प्रस्तुत करके, छात्रों को स्वरोजगार उद्यम लेने में मदद करने के लिए मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके सभी कार्यक्रमों में स्वरोजगार को बढ़ावा दिया। वर्तमान में संस्थान निम्नलिखित कार्यक्रम प्रदान करता है:

I. मकौत, पश्चिम बंगाल की संबद्धता के अंतर्गत 4 वर्षीय बीटेक एआईसीटीई–अनुमोदित कार्यक्रम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खाद्य प्रौद्योगिकी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल और पर्यावरण इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग) . सभी पाठ्यक्रम मकौत, पश्चिम बंगाल के तहत संबद्ध हैं।

II. डब्ल्यूबीएससीटी एंड वीई एंड एसडी, कोलकाता के तहत वर्ष 2018–19 के सत्र से सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3–वर्षीय डिप्लोमा एआईसीटीई अनुमोदित कार्यक्रम।

III. पीएमकेवीवाई–टीआई योजना/उत्कर्ष बांग्ला और कौशल संवर्धन और एआईसीटीई (कर्मा) योजना के पुनर्गठन मिशन के तहत कौशल विकास कार्यक्रम।

1. मकौत, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत जीकेसीआईईटी, मालदा में 4–वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम शुरू करने के बाद शैक्षणिक उपलब्धियाँ/सफलता

- डब्लूबीजेईई – 2023 काउंसलिंग के माध्यम से जीकेसीआईईटी, मालदा के 4–वर्षीय बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया।
- पश्चिम बंगाल और जेईई (मेन्स) – 2023 में अर्हता प्राप्त करने वाले छात्रों को छोड़कर पूर्वोत्तर राज्यों और अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए जेओएसएए/ सीएसएबी 2023 के माध्यम से जीकेसीआईईटी, मालदा के 4–वर्षीय बी.टेक कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया।

2. डबल्यूबीएससीटीएंडवीईएंडएसडी, कोलकाता के तहत जीकेसीआईईटी, मालदा में 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू करने के बाद शैक्षणिक उपलब्धियाँ/ सफलता

- जेएक्स्पो– 2023 काउंसलिंग के माध्यम से जीकेसीआईईटी, मालदा के 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त करने हेतु कार्यक्रम चलाया गया।
- पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के लिए जीकेसीआईईटी, मालदा के 3–वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अलग अखिल भारतीय परामर्श (जीकेसीआईईटी प्रवेश परीक्षा) परीक्षा आयोजित की गई।

3. जीकेसीआईईटी, मालदा में कौशल विकास कार्यक्रमों में शैक्षणिक उपलब्धियां

संस्थान को एआईसीटीई द्वारा कौशल ज्ञान प्रदाता (एसकेपी) के रूप में भी अनुमोदित

किया गया है। इसे पश्चिम बंगाल की उत्कर्ष बांग्ला योजना के तहत एक प्रशिक्षण भागीदार (टीपी) के रूप में भी मान्यता दी गई थी। जीकेसीआईईटी को एआईसीटीई (कर्म) योजना के कौशल संवर्धन और पुनर्गठन मिशन के तहत कुछ कौशल विकास पाठ्यक्रम चलाने के लिए एआईसीटीई से मंजूरी मिल गई है। एआईसीटीई ने डबल्यूबीएससीटीएंडवीईएंडएसडी, (दिसंबर 2022 से जून 2023) और खाद्य उद्योग क्षमता और कौशल पहल (एफ़आईसीएसआई) एसएससी, (जनवरी 2023 से दिसंबर 2023) के तहत अल्पकालिक पाठ्यक्रम (कर्म) को मंजूरी दे दी है।

वर्ष 2023—24 के लिए वित्तीय आंकड़े

जीकेसीआईईटी, मालदा		(रु. करोड़ में)
वस्तु शीर्ष	ब.अ.— 2023—24	जारी की गई कुल निधियाँ (24.01.2024 तक)
ओएच—31	5.00	4.00
ओएच —35	10.00	0.00
ओएच —36	14.00	11.00
कुल	**29.00**	**15.00**

कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज फॉर टेक्निशियन एजुकेशन (सीपीएससी), मनीला, फिलीपींस को सहायता

कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज फॉर टेक्निशियन एजुकेशन (सीपीएससी), मनीला कोलंबो योजना की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 5 दिसंबर, 1973 को वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में आयोजित कोलंबो योजना की 23वीं सलाहकार समिति की बैठक में की गई थी, ताकि कोलंबो योजना के सदस्य देशों की सहायता उनकी तकनीशियन शिक्षा प्रणालियों को विकसित और विस्तारित करने में की जा सके। इसने 1974 में सिंगापुर गणराज्य के साथ बारह वर्षों के लिए पहली मेजबान सरकार के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया था। 1986 में, सीपीएससी के कार्यालय का स्थान बदलकर मनीला, फिलीपींस हो गया। कोलंबो प्लान स्टाफ कॉलेज एक अनूठा संगठन है, जो एशिया—प्रशांत क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्ता सुधार से संबंधित मुद्दों के लिए कार्य करने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान है। स्टाफ कॉलेज का उद्देश्य तकनीकी शिक्षा में उन तकनीकी शिक्षक शिक्षकों और प्रशिक्षकों एवं वरिष्ठ कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करके कोलंबो योजना क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करना है, जो सेवाकालीन प्रशिक्षण और कर्मचारी विकास कार्यक्रम में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

❖ ❖ ❖

08

प्रौद्योगिकी समर्थकृत शिक्षा

प्रौद्योगिकी समर्थकृत शिक्षा

सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन

उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों में कभी भी किसी भी मोड में सभी शिक्षार्थियों के लिए इंटरनेट/इंट्रानेट पर उच्च गुणवत्ता वाले व्यक्तिगत और इंटरैक्टिव ज्ञान मॉड्यूल प्रदान करने में आईसीटी की क्षमता का लाभ उठाने के लिए 'सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन' (एनएमईआईसीटी) योजना का संचालन कर रहा है।

सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को कनेक्टिविटी प्रदान करके और देश के सभी शिक्षार्थियों को उच्च गुणवत्तायुक्त ई–सामग्री निःशुल्क प्रदान करके शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांत अर्थात पहुंच, समानता और गुणवत्ता प्राप्त किए जाएंगे। एनएमईआईसीटी में तीनों तत्व शामिल हैं।

मिशन के दो प्रमुख घटक हैं अर्थात : (क) ऑनलाइन शिक्षा और (ख) प्रचार–प्रसार जिसमें संस्थानों और शिक्षार्थियों के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करना शामिल है। यह उच्च शिक्षा क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण शिक्षकों / शिक्षार्थियों के बीच शिक्षण और अधिगम के उद्देश्य से कंप्यूटिंग उपकरणों का उपयोग करने के लिए डिजिटल डिवाइड, अर्थात कौशल में अंतर को पाटने का प्रयास करता है और उन लोगों को सशक्त बनाता है, जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। यह राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय (एनडीएल), ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विकास, रोबोटिक्स, ई–लर्निंग के लिए उपयुक्त शिक्षाशास्त्र, आभासी प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने, ऑनलाइन परीक्षण और प्रमाणन, शिक्षार्थियों को मार्गदर्शन और सलाह देने के लिए शिक्षकों की ऑनलाइन उपलब्धता, पाठ्यक्रमों के वितरण के लिए 24×7 आधार पर 34 डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) शैक्षिक चैनलों का शुभारंभ पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है।

एनएमईआईसीटी योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को कैसे साकार किया गया है:

वर्चुअल लैब्स:

वर्चुअल लैब्स को विज्ञान और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में सिमुलेशन–आधारित प्रयोगशालाओं तक दूरस्थ पहुँच प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये वर्चुअल लैब्स अवर स्नातक, परा स्नातक स्तर के साथ–साथ शोधार्थियों की जरूरतों को पूरा करती हैं। इसका एक अन्य उद्देश्य छात्रों की जिज्ञासा जगाना और उन्हें अपनी गति से सीखने की अनुमति देना है। यह छात्र – केंद्रित दृष्टिकोण सिमुलेशन–आधारित प्रयोग के माध्यम से बुनियादी और उन्नत अवधारणाओं को समझने की सुविधा प्रदान करता है। इंटरनेट आधारित प्रयोग से अतिरिक्त वेब संसाधनों, वीडियो व्याख्यान, एनिमेटेड प्रदर्शनों और स्व–मूल्यांकन का उपयोग किया जा सकता है। वर्चुअल प्रयोगशालाओं का उपयोग वास्तविक प्रयोगशालाओं के पूरक के रूप में किया जा सकता है। वर्चुअल प्रयोगशालाओं का उपयोग किसी भी स्थान, किसी भी गति, किसी भी समय और किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला से किया जा सकता है। यह छात्र–केंद्रित, ऑनलाइन शिक्षा में एक आदर्श बदलाव है। वर्चुअल लैब को उपयोगकर्ता के परिसर में प्रयोग करने के लिए किसी अतिरिक्त

आधारभूत संरचना की आवश्यकता नहीं होती है। दूर से प्रयोग करने के लिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर टर्मिनल ही काफी है। 120 से अधिक वर्चुअल लैब वर्तमान में उपयोग के लिए तैयार हैं और एक साझा वेबसाइट www.vlab.co.in- पर उपलब्ध हैं। वर्चुअल लैब्स की केंद्रीय वेबसाइट पर 900+ प्रयोग उपलब्ध हैं। लगभग 300 नए प्रयोग विकसित किए गए हैं, जिससे उपयोग के लिए तैयार प्रयोगों की समेकित संख्या 1200 से अधिक हो गई है।

कोविड–19 महामारी के कारण, अधिकांश शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया था और संस्थानों में प्रयोगशालाओं तक भौतिक पहुंच संभव नहीं थी। इसलिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रयोग करने की आवश्यकता को पूरा करने और ऑनलाइन प्रयोग के सफल संचालन के बाद लैब रिपोर्ट जमा करने के बाद छात्रों का मूल्यांकन करने में वर्चुअल लैब्स को बहुत उपयोगी पाया गया।

फिलहाल देश भर के **1400+ विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्चुअल लैब्स का उपयोग किया जा रहा है, जिनकी पहचान नोडल केंद्रों (एनसी)** के रूप में की गई है। उन सभी एनसी ने नामित नोडल केंद्र बनने के लिए वर्चुअल लैब्स परियोजना के किसी भी कंसोर्टियम संस्थान के लिए उस संस्था के प्रमुख द्वारा औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित एक अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) फॉर्म जमा किया है। उन अधिकृत नोडल केन्द्रों पर **11 हजार से अधिक ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यशालाएं** आयोजित की गई हैं। । कोविड के समय के दौरान और उसके बाद विश्व भर में **40+ लाख** उपयोगकर्ताओं से अब तक वर्चुअल लैब्स का **1 करोड़ से अधिक** प्रमाणित उपयोग दर्ज किया गया।

1 जनवरी 2020 से गूगल एनालिटिक्स पर 8 करोड़ से अधिक पेज व्यू दर्ज किए गए हैं, जिसकी **औसत सत्र अवधि 9 मिनट और 40 सेकंड है,** जिसे दुनिया भर के **85 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं** द्वारा एक्सेस किया गया है।

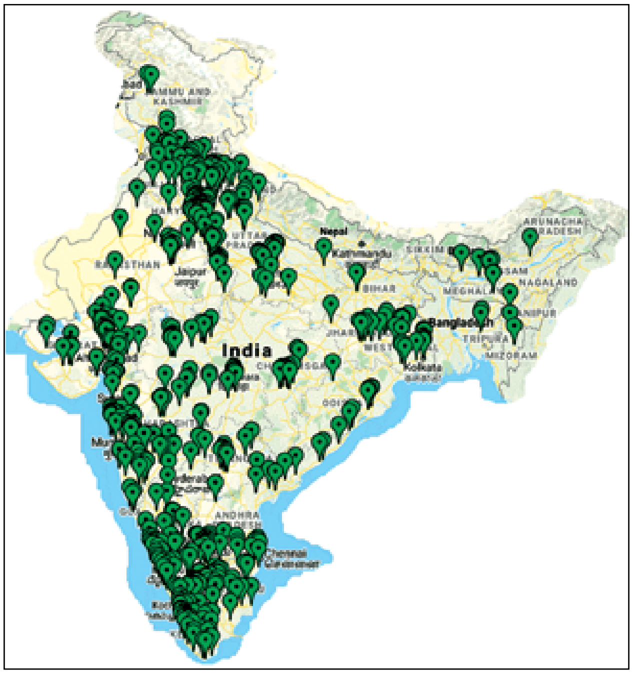

देश भर में स्थित नोडल केंद्र

वर्चुअल लैब्स का प्रसार करने और इंजीनियरिंग कॉलेजों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, और विज्ञान कॉलेजों/विश्वविद्यालयों सहित देश भर के सभी शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंचने के लिए एक नई परियोजना को आईआईटी दिल्ली द्वारा समन्वित वर्चुअल लैब्स कंसोर्टियम द्वारा तैयार किया जा रहा है और जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

वर्चुअल लैब्स का हिंदी में अनुवाद (प्रायोगिक)

वेबसाइट पर निःशुल्क उपयोग के लिए उपलब्ध लगभग 100+ वर्चुअल लैब्स में से विभिन्न डोमेन में शीर्ष तीन लोकप्रिय प्रयोगशालाओं से हिंदी भाषा में 30 प्रयोगों का अनुवाद करने के लिए एक प्रायोगिक कार्य पूरा कर लिया गया है। इन अनुदित प्रयोगशालाओं को Virtual Labs in Hindi लिंक के माध्यम से एक्सेस कियाजा सकता है।

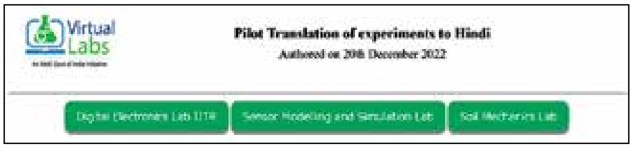

आईआईटी दिल्ली के नेतृत्व में वर्चुअल लैब्स कंसोर्टियम द्वारा सभी वर्चुअल लैब्स को 8–क्षेत्रीय

भाषाओं में अनुदित करने के लिए एक नई परियोजना तैयार की जा रही है और शिक्षा मंत्रालय के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

वर्चुअल लैब्स – एमएसबीटीई सहयोग

वर्चुअल लैब्स इंजीनियरिंग और विज्ञान पाठ्यक्रमों में सिमुलेशन–आधारित प्रयोग प्रदान करते हैं। पूरे देश में डिप्लोमा पाठ्यक्रमों द्वारा उपयोग करने के लिए लगभग 20% वर्चुअल प्रयोग उपलब्ध हैं। डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मौजूद लगभग 80% के इस अंतर को दूर करने के लिए, वर्चुअल लैब्स महाराष्ट्र राज्य बोर्ड तकनीकी शिक्षा (एमएसबीटीई) के साथ काम कर रहे हैं ताकि प्रायोगिक कार्य के रूप में महाराष्ट्र राज्य के सभी पॉलिटेक्निक कॉलेजों के साथ जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए विशेष रूप से उपयोगी नई प्रयोगशालाएँ बनाई जा सकें। राज्य भर में एमएसबीटीई द्वारा प्रदान किए गए सभी पाठ्यक्रमों के लिए योजना पहले ही तैयार कर ली गई है और पाया गया है कि संबंधित पाठ्यक्रमों में लगभग 20% प्रयोग मौजूदा वर्चुअल लैब्स के माध्यम से किए जाने वाले उनके पाठ्यक्रमों के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। शेष प्रयोग एमएसबीटीई द्वारा वर्चुअल लैब्स के दो कंसोर्टियम संस्थानों अर्थात आईआईटी बॉम्बे और कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग पुणे के समन्वय से विकसित किए जाएंगे। दोनों संस्थान एमएसबीटीई के डेवलपर समुदाय का मार्गदर्शन करेंगे और उनके पाठ्यक्रमों के लिए सिमुलेशन–आधारित प्रयोग बनाने में उनकी मदद करेंगे। इन कमी वाले क्षेत्रों की प्राथमिकता सूची को वर्चुअल लैब्स टीम के साथ साझा किया गया है और एमएसबीटीई द्वारा विकास समुदाय का गठन किया जा रहा है। उन प्रयोगों के सफल समापन के बाद, डिप्लोमा कॉलेज न केवल पूरे महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में भी अपने पाठ्यक्रमों के लिए वर्चुअल प्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं और प्रयोग के डिजिटल मोड के माध्यम से अधिगम को बढ़ा सकते हैं।

वर्चुअल लैब्स– एकेटीयू सहयोग

कोविड–19 महामारी के दौरान उपयोगकर्ता समुदाय के साथ वर्चुअल लैब्स का सहयोग सक्षम किया गया है और हम देश के अन्य हिस्सों से भी विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों की भागीदारी करवा रहे हैं। डॉ.ए.पी. जे. अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय (एकेटीयू) उत्तर प्रदेश ने वर्चुअल लैब्स के साथ सहयोग किया है और संबद्ध कॉलेजों के समूह में वर्चुअल लैब्स की अवधारणा का प्रसार करने और इंजीनियरिंग के विभिन्न विषयों में नए वर्चुअल प्रयोग विकसित करने के लिए एकेटीयू परिसर, लखनऊ (यूपी) में एक समर्पित वर्चुअल लैब्स सेल की स्थापना की है। इस संबंध में, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आरईसी बांदा के समन्वय से चार (04) बूटाथॉन कार्यक्रम (प्रत्येक 7 दिनों का) आयोजित किए गए हैं।

अन्य कार्यक्रम

उपर्युक्त सभी गतिविधियों के अलावा, कंसोर्टियम ने उपयोगकर्ता समुदाय में वर्चुअल लैब्स के बारे में जागरूकता फैलाने और महत्व समझाने के लिए कई अन्य विविध गतिविधियाँ और कार्यक्रम आयोजित किए हैं। कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

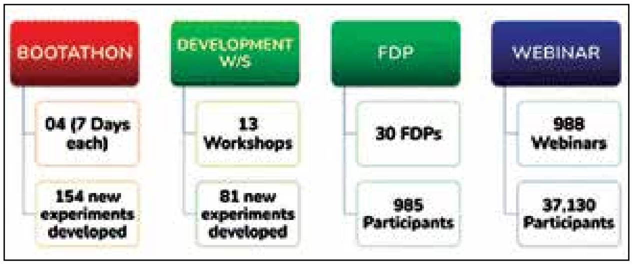

वर्चुअल लैब्स – उपलब्धियाँ [01.01.2023 – 31.12.2023]

- देश भर में 900+ संस्थानों को नोडल केंद्र के रूप में नामांकित किया गया था।
- वर्चुअल लैब्स के बारे में जागरूकता फैलाने और उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए देश भर में 2000 से अधिक कार्यशालाएँ आयोजित की गई हैं। देश भर में 26 लाख से अधिक उपयोग दर्ज किए गए हैं।

विभिन्न नोडल केन्द्रों पर कार्यशालाएँ

- वर्चुअल लैब्स परियोजना अंतराल क्षेत्रों को पूरा करने के लिए आक्रामक रूप से नए प्रयोग विकसित कर रही है। कुल 700+ नए प्रयोग विकास चरण में हैं, जिनमें से लगभग 500 प्रयोग परीक्षण चरण में हैं।
- आईओटी, एआई, ड्रोन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में भी प्रयोगशालाएं विकसित की जा रही हैं।
- वर्चुअल लैब्स प्रोजेक्ट को 22 जून 2023 को इनोवेशन, डिज़ाइन और एंटरप्रेन्योरशिप (आईडीई) बूटकैंप के उद्घाटन में प्रदर्शित किया गया था, जिसे शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल (एमआईसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा आयोजित किया गया था।
- माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी (शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार) और प्रोफेसर अनिल डी. सहस्रबुद्धे (एनईटीएफ के अध्यक्ष और एआईसीटीई, नई दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष) ने वर्चुअल लैब्स स्टॉल का दौरा किया।

आईडीई में वर्चुअल लैब्स, 22 जून 2023

- देश भर के विभिन्न संस्थानों में विभिन्न राज्य–स्तरीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई।
- ओडिशा, केरल और उत्तराखंड के विभिन्न पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए कार्यशालाएं भी आयोजित की गई।
- वर्चुअल लैब्स को सीएसआईआर, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सीएसआईआर के वन वीक वन लैब कार्यक्रम में भी प्रस्तुत किया गया था।

पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए कार्यशालाएँ

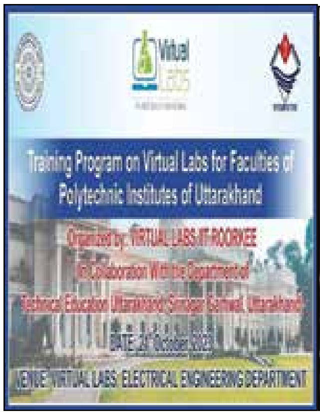

ई–यंत्रः

- **ई–यंत्र क्या है?**

  ई–यंत्र शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित और आईआईटी बॉम्बे द्वारा शुरू किया गया एक रोबोटिक्स आउटरीच कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य कृषि, विनिर्माण, रक्षा, स्मार्ट–सिटी रखरखाव और सेवा उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए युवा इंजीनियरों की प्रतिभा का दोहन करना है।

- **ई–यंत्र इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करता है?**

  ई–यंत्र परियोजना–आधारित शिक्षा के माध्यम से मौजूदा उच्च शिक्षा प्रणाली की पूर्ति करता है। छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों को प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वास्तविक समस्याओं को हल करने और एक नवाचार संस्कृति के निर्माण में प्रशिक्षित किया जाता है। कॉलेजों में ई–यंत्र प्रयोगशालाएं प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करती हैं और छात्रों और शिक्षकों को व्यापक नवाचार समुदाय से जोड़ती हैं। यह परियोजना प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के माध्यम से छात्रों को विभिन्न प्रकार के तकनीकी कौशल जैसे एंबेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स, एमएल, आरओएस, सिमुलेशन, कार्यात्मक प्रोग्रामिंग, नियंत्रण प्रणाली इत्यादि में प्रशिक्षित करती है।

- **प्रभाव?**

  पिछले दशक में ई–यंत्र से 220,210 से अधिक छात्रों को जटिल इंजीनियरिंग कौशल में प्रशिक्षित किया गया है। इसका परिणाम शीर्ष–दर प्लेसमेंट में देखा जा सकता हैं, कई उच्च डिग्री पाने के लिए उत्साहित हैं जबकि कुछ लोग प्राप्त व्यावहारिक ज्ञान के साथ स्वैच्छिक स्टार्टअप शुरू करते हैं। सभी जानते हैं कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के कई फाइनलिस्ट ई–यंत्र के पूर्व छात्र हैं। ई–यंत्र ने अपनी पहल के माध्यम से कई कॉलेज छात्रों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। मुख्य पहलों का वर्णन निम्नवत है:

- **ई–यंत्र रोबोटिक्स प्रतियोगिता (ईवाईआरसी 2023–24):**

  इस वर्ष की प्रतियोगिता समाज की वास्तविक समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ बहु–विषयक इंजीनियरों की भावी पीढ़ी तैयार करने पर केंद्रित है। यह इंजीनियरिंग/विज्ञान/पॉलिटेक्निक कॉलेजों के छात्रों के लिए एक अनूठी वार्षिक प्रतियोगिता है।

  पंजीकृत छात्रों की संख्या: **660 कॉलेजों से 10820 (2934 टीमें)**

  प्रशिक्षित छात्रों की संख्या: **9586 (2491 टीमें)**

  थीम्स की संख्या: **6**

थीम्स	**प्रौद्योगिकी स्टैक के लिए प्रशिक्षित**
एस्ट्रोटिंकर बॉट (एबी)	एफपीजीए, सी, वेरिलॉग, सीपीयू आर्किटेक्चर, बिल्ड–ए–बॉट, पैरेलल प्रोसेसिंग, सीरियल कम्युनिकेशन
कॉस्मो लॉजिस्टिक (सीएल)	रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम 2 (आरओएस 2), गज़ेबो, मूवइट 2, कंप्यूटर विज़न, गिट, आरवीज़ 2, एनएवी 2
जियोगाइड (जीजी)	मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, इमेज प्रोसेसिंग, रिमोट सेंसिंग, जीआईएस, बिल्ड–ए–बॉट, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम, वायरलेस कम्युनिकेशन
होलोग्लिफ़ बॉट्स (एचबी)	होलोनोमिक ड्राइव रोबोट की किनेमेटिक्स, कंट्रोल और वेप्वाइंट नेविगेशन, बॉट डिजाइनिंग और बिल्डिंग, इमेज प्रोसेसिंग।रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम 2 (आरओएस2, गज़ेबो सिमुलेशन, पाश्थन प्रोग्रामिंग, ओपनसीवी, फ्यूजन 360 (बेसिक)
ल्यूमिनोसिटी ड्रोन (एलडी)	ड्रोन बिल्डिंग, कंट्रोल सिस्टम्स, पोसिशन कंट्रोल और वेप्वाइंट नेविगेशन, इमेज प्रोसेसिंग। रोबोट ऑपरेटिंग सिस्टम (आरओएस), गज़ेबो सिमुलेशन, पायथन प्रोग्रामिंग, ओपनसीवी
लुनर स्काउट (एलएस)	रोबोट सिमुलेशन (कोपेलियासिम), कंट्रोल सिस्टम, यूलर–लैग्रेन्जियन मैकेनिक्स, पीआईडी नियंत्रण, लीनियर क्वाड्रैटिक रेगुलेटर, पायथन प्रोग्रामिंग, ऑक्टेव प्रोग्रामिंग, 3डी डिजाइनिंग

ईवाईआरसी 2022–23 के लिए मार्च 2023 में फाइनल में छात्रों की संख्या: 35 टीमें (137 छात्र)

फाइनलिस्ट छात्रों की संख्या: ईवाईआरसी 2023–24 का अंतिम दौर (फाइनल) मार्च 2024 में होगा जिसमें 30 टीमों (120 छात्र) के आने की आशा है।

- **ई–यंत्र इनोवेशन चैलेंज (ईवाईआईसी)**

  ई–यंत्र इनोवेशन चैलेंज (ईवाईआईसी) नवाचार और उद्यमिता कौशल के लिए एक मेंटरशिप कार्यक्रम है। ई–यंत्र ओपन–सोर्स सिमुलेशन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर किट्स का उपयोग करके ऑनलाइन प्रशिक्षण और परामर्श के माध्यम से वास्तविक समस्याओं के प्रोटोटाइप समाधान के निर्माण में तेजी लाता है। इस कार्यक्रम से छात्र समस्या–समाधान करना सीखते हैं, और व्यावहारिक प्रयोग एवं प्रतियोगिता कार्यक्रमों के माध्यम से "स्थानिक चुनौतियों के लिए छात्र नवप्रवर्तकों" के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। ईवाईआईसी 2022–23 में क्षेत्रीय सम्मेलनों के लिए 53 प्रस्तावों का चयन किया गया। इनकी समीक्षा मार्च में कोयंबटूर और पुणे में हुई थीं। इनमें से, 10 टीमों को अप्रैल में आईआईटी बॉम्बे में आयोजित ई–यंत्र फाइनल के लिए चुना गया था।

- **ई–यंत्र इनोवेशन चैलेंज (ईवाईआईसी 2023–24)**

  ईवाईआईसी छात्रों को किसी समस्या को स्पष्ट करने और उनके सपनों के स्टार्ट–अप को साकार रूप में देने में मदद करता है। इस वर्ष की थीम समावेशी शहर, आपदा प्रबंधन और कृषि हैं। इस प्रतियोगिता में स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी स्तर में किसी भी डिग्री कार्यक्रम या 10वीं कक्षा के बाद डिप्लोमा कार्यक्रम करने वाला कोई भी पूर्णकालिक छात्र भाग ले सकता है।

  पंजीकरण की संख्या: **2312**

  प्रशिक्षण के लिए नामांकित: **1117 (297 टीमें)**

  प्राप्त प्रस्ताव: **230**

  क्षेत्रीय फाइनल फरवरी–मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया जाएगा और राष्ट्रीय फाइनल अप्रैल 2024 के महीने में आईआईटी बॉम्बे में आयोजित किया जाएगा।

- **ई–यंत्र लैब सेटअप पहल (ईएलएसआई)–** ई–यंत्र कॉलेजों को उनके शैक्षणिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में रोबोटिक्स लैब/क्लब स्थापित करने में मदद करता है। 2023 तक पूरे भारत में 500+ प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। केवल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और टूल का उपयोग करके एंबेडेड सिस्टम और प्रोग्रामिंग की बुनियादी बातों के लिए ऑनलाइन/ऑफलाइन कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। (www.e-yantra.org)

भारत और भूटान में ई–यंत्र लैब

2022–23 के दौरान 3000 से अधिक प्रतिभागियों ने विभिन्न ऑनलाइन जागरूकता सत्रों के साथ–साथ ईएलएसआई द्वारा आयोजित कुछ वास्तविक कार्यशालाओं में भाग लिया।

दो दिवसीय एंबेडेड सिस्टम और रोबोटिक्स कार्यशाला

भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या– **653**

प्रशिक्षित प्रतिभागियों की संख्या– **2973**

उद्घाटन की गई प्रयोगशालाओं की संख्या – **57 (जनवरी–दिसंबर 2023 के बीच)।**

- **ई–यंत्र संगोष्ठी**

  ई–यंत्र संगोष्ठी एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन शिक्षा में टीम ई–यंत्र की उपलब्धियों का जश्न मनाता है। यह महामारी के बाद ई–यंत्र, आईआईटी बॉम्बे द्वारा आयोजित पहली व्यक्तिगत संगोष्ठी थी और तीन वर्षों के बाद व्यक्तिगत रूप से उपस्थित लोगों का स्वागत करना हर्ष का विषय था। इस कार्यक्रम में ई–यंत्र इनोवेशन चैलेंज फाइनलिस्टों द्वारा विकसित परियोजनाओं की प्रदर्शनियों के साथ–साथ शीर्ष 3 ई–यंत्र प्रयोगशालाओं से डिजाइन सोच गतिविधियां/कार्यशालाएं, मुख्य वक्ता, पैनल चर्चा और पोस्टर प्रस्तुतियां और सर्वोत्तम अभ्यास शामिल थे।

  कार्यक्रम दिनांकः **5–6 अप्रैल, 2023**

  स्थानः **वीएमसीसी ऑडिटोरियम, आईआईटी बॉम्बे**

  प्रतिभागियों की संख्या – **267**

मुख्य विशेषताएँ :

- श्री सुधांशु मणि के साथ **"बिल्डिंग वंदे भारत एक्सप्रेस"** पर मुख्य भाषण
- **पैनल चर्चा** –
  - o डॉ. विनोद मोहितकर (डीटीई), प्रो. पी. पंड्या, प्रो. दीपक फाटक, डॉ. राजन वेलुकर, श्री अशांक देसाई, डॉ. शुभा पंडित के साथ **"एनईपी 2020 का कार्यान्वयन"**
  - o विवेक पवार, श्री श्रीराम पार्थसारथी, किरण देशपांडे के साथ **"बिल्डिंग हाई–टेक स्टार्टअप"**
- डिजाइनअप टीम के साथ "डिजाइनर्स एंड इंजीनियर्स कॉन्क्लेव"।
- केरल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के ई–यंत्र कॉलेजों से अभिनव परियोजनाएं।

संवादः

- डॉ. रूपेश घ्यार – बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर (बीईटीआईसी), आईआईटी बॉम्बे द्वारा "टेकिंग आइडियाज टू प्रोडक्टस इन मेडटेक – ए बेटिक पेर्स्पेक्टिव "
- विवेक पवार (संस्थापक, संकल्प सेमीकंडक्टर्स) द्वारा **"हाई–टेक स्टार्टअप्स के निर्माण के लिए एक मॉडल"**
  - o **ई–यंत्र ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रमः**

    आईआईटी बॉम्बे में मई 2023 से जुलाई 2023 ई–यंत्र समर इंटर्नशिप कार्यक्रम (ईवाईएसआईपी 2023) तक 11वां संस्करण का आयोजित किया गया था। 44 कॉलेजों के 55 प्रशिक्षुओं ने 7 सप्ताह की अवधि के लिए विशेषज्ञ ई–यंत्र सलाहकारों के मार्गदर्शन में 26 परियोजनाओं पर काम किया। विवेचनात्मक सोच, टीम वर्क और संचार कौशल जैसे उनके सॉफ्ट कौशल के विकास के लिए बातचीत और एक कार्यशाला आयोजित की गई। 4 जून 2023 को "प्रॉडक्ट डिज़ाइन" पर एक कार्यशाला आयोजित की गई।
  - o **अंतिम प्रदर्शनी**

    इस वर्ष अंतिम प्रदर्शनी **7 जुलाई 2023** को आईआईटी बॉम्बे में आयोजित की गई थी, जिसके लिए सभी प्रशिक्षुओं ने आईआईटी संकाय और अतिथियों के सामने अपनी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शनी आईआईटी बॉम्बे के सीएसई विभाग के केआरईएसआईटी भवन में आयोजित की गई थी। चूंकि ई–यंत्र नौसेना और सेना के तकनीकी

प्रतिष्ठानों में प्रयोगशालाएं स्थापित करने में मदद कर रहा है, इसलिए कई नौसेना अधिकारियों ने दौरा किया।

शोध शुद्धिः

शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के बीच शैक्षणिक एकीकरण को बढ़ावा देने और और इसके संवर्धन के लिए, शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार ने "शोधशुद्धि" नामक अपनी पहल के माध्यम से केंद्रीय, राज्य, केंद्र द्वारा वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफ़टीआई), भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, सम और निजी विश्वविद्यालयों को 01 सितंबर, 2019 से साहित्यिक चोरी पर अंकुश लगाने के लिए साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ्टवेयर (पीडीएस) तक पहुंच प्रदान की है। तत्कालीन माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिल्ली में सीएबीई की बैठक के दौरान कार्यक्रम की शुरुआत की गई और इसे इन्फ्लिबनेट केंद्र, गांधीनगर द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। आरंभ में, यह परियोजना 10 लाख दस्तावेजों और 960+ संस्थानों को लक्षित करने वाले 3 लाख उपयोगकर्ताओं के साथ शुरू हुई थी। ओपन टेंडर के माध्यम से चयनित पीडीएस का नाम उरकुंड था, जिसे बाद में अन्य समान सॉफ्टवेयर के साथ मिलाकर औरिजिनल में बदल गया। केंद्र ने कोविड–19 के कारण 1 जून 2021 से 31 मई 2022 तक न्यूनतम 6 लाख दस्तावेजों की प्रतिबद्धता के लिए दूसरे वर्ष के अनुबंध को संशोधित किया, अन्य नियम और शर्तें समान रहीं। दूसरे वर्ष के अनुबंध को 1 जून 2022 से 31 मई 2023 तक एक और वर्ष के लिए नवीनीकृत किया गया था। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, अनुबंध को सितंबर 2023 तक नवीनीकृत किया गया था। पीडीएस सदस्यता के सितंबर 2023 में समाप्त होते ही, पीडीएस की खरीद के लिए एक नई निविदा जारी की गई थी। इसमें पहले की ही तरह तीन बोलियां शामिल हैं, अर्थात i) पूर्व–योग्यता मानदंड, ii) तकनीकी बोली, और iii) वेब–आधारित साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाले सॉफ़्टवेयर/टूल की आपूर्ति के लिए योग्य विक्रेता/डेवलपर्स/अधिकृत वितरकों से वाणिज्यिक बोली।

एक नए पीडीएस सॉफ्टवेयर की खरीदः मैसर्स ड्रिलबिटसॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित ईएसएस–उप समिति के मार्गदर्शन में ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) के माध्यम से, मेसर्स ड्रिलबिटसॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से नया पीडीएस सॉफ्टवेयर, अर्थात ड्रिलबिट–एक्सट्रीम की खरीद की गई और इसे 1100 से अधिक एचईआई (उच्च शिक्षण संस्थानों) को 10 लाख दस्तावेजों (एक दस्तावेज़) ए–4 आकार के 20 पेज या 60,000 अक्षर (3000 अक्षर × 20 पेज) के लिए प्रदान किया जा रहा है। माइग्रेशन अवधि के रूप में मानी गई अवधि अर्थात 1 अक्टूबर 2023 से इस सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान बिना ट्रायल एक्सेस दिया गया था)। इंस्टॉलेशन, ट्रांज़िशन और माइग्रेशन के लिए 30 दिनों की परीक्षण अवधि जो अनुबंध दिए जाने की तिथि या 01.10.2023 से शुरू हुई, के सफल समापन के बाद छह (06) महीने की अवधि के लिए 1 नवंबर 2023 से भुगतान के पश्चात एक्सैस दिया गया है। छह (06) महीनों की प्रारंभिक अवधि के दौरान, इन्फ्लिबनेट केंद्र तीन महीनों के लिए नए पीडीएस के प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। समीक्षा के बाद, निविदा नियम और शर्तों के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर अनुबंध की अवधि को अधिकतम तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

प्रमुख उपलब्धियां

उरकुंड/ऑरिजिनल के साथ अनुबंध में, कुल 1,49,699 उपयोगकर्ता बनाए गए, और 38,38,587 दस्तावेज़ साहित्यिक चोरी की जाँच के लिए स्कैन किए गए। शिक्षा मंत्रालय की योजना शोधशुद्धि के तहत 2019 से दिसंबर 2023 तक कुल 200,620 उपयोगकर्ता बनाए गए। 2023 में, अतिरिक्त 64,250 उपयोगकर्ता जोड़े गए और 2023 में 10,78,653 दस्तावेज़ स्कैन किए गए (107% लक्ष्य प्राप्त हुआ)।

सबमिशन का मासिक औसत साहित्यिक चोरी की जाँच

इस अवधि के दौरान (सितंबर 2019 – मई 2021), कुल 12,37,143 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए। इस अवधि में कोविड –19 के कारण विस्तारित अवधि (12+9) भी शामिल है, जबकि दूसरे वर्ष (जून 2021 – मई 2022) में 9,22,698 दस्तावेज जमा किए गए। तीसरे वर्ष (जून 2022 – मई 2023) में, चार महीने की विस्तारित अवधि (जून 2023 – सितंबर 2023) सहित, 13,79,914 दस्तावेज़ जमा किए गए।

पीडीएस, अर्थात ड्रिलबिट सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ड्रिलबिट एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर, जो 1 अक्तूबर 2023 को शुरू हुआ, 1121 उच्च शिक्षण संस्थानों को प्रदान किया जा रहा है। ड्रिलबिट एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर में परीक्षण अवधि (अक्टूबर 2023 – दिसंबर 2023) सहित तिमाही में कुल 2,98,832 दस्तावेज़ जमा किए गए, और क्रॉस–वेरिफ़ीकेशन के बाद लगभग 50,000+ उपयोगकर्ताओं को नए पीडीएस में जोड़ा गया है।

प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ों की औसत संख्या लगभग 89,000 प्रति माह है। वर्ष 2023 (जनवरी–दिसंबर) में कुल 10,78,653 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए, जो परियोजना के प्रारंभ के दौरान निर्धारित लक्ष्य से 100% अधिक है। दिसंबर 2023 में, शैक्षणिक संस्थानों द्वारा समानता जांच के लिए स्थापना के बाद से सबसे अधिक संख्या में अर्थात 1,26,794 दस्तावेज़ प्रस्तुत किए गए थे। इनके उपयोग में प्रगतिशील सुधार हुआ है, जो दर्शाता है कि अधिक से अधिक शोधकर्ता यूजीसी, एआईसीटीई आदि सहित विभिन्न उच्च शिक्षा शीर्ष निकायों के माध्यम से देश द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्रमाणिकता दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं। 30 लाख दस्तावेजों के नियोजित लक्ष्य के बजाए परियोजना में 30 लाख से अधिक का उपयोग होगा, जो 100% से अधिक होगा।

स्थापना के बाद से पीडीएस (उरकुंड/ऑरिजिनल/ड्रिलबिट) का वार्षिक उपयोग

माह/वर्ष	अवधि	वे दस्तावेज़ जिनकी साहित्यिक चोरी के लिए जाँच की गई
सितंबर 2019–मई 2021	प्रथम वर्ष के लिए उरकुंड + कोविड–19 के कारण विस्तारित अवधि	12,37,143
जून 2021–मई 2022	दूसरे वर्ष के लिए उरकुंड/ऑरिजिनल (साथ ही शेष राशि अग्रेषित)	9,22,698
जून 2022–मई 2023	तीसरे वर्ष के लिए ऑरिजिनल (जून 22022–मई 2023)	9,54,138
जून 2023–सितंबर 2023	4 महीने की विस्तारित अवधि (जून–सिसितंबर 2023) के लिए ऑरिजिनल	3,69,501
सितंबर 2023 तक	शुरुआत से सितंबर 2023 तक उपयोग (4 वर्ष)	35,39,671
1 अक्तूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक	1 अक्तूबर 2023 से नया पीडीएस (ड्रिलबिट एक्सट्रीम)।	2,98,832

शिक्षा मंत्रालय ने शोधशुद्धि/पीडीएस परियोजना के लिए वर्ष 2026 तक 10 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट के साथ 50 करोड़ रु. मंजूर किए हैं। एमआईआई, एमएसई और स्टार्ट–अप नियमों और विनियमों का पालन करके पीडीएस के लिए मंत्रालय से मंजूरी लेने के बाद ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी (जीटीई) के प्रकाशन की तैयारी करके अगली अनुबंध अवधि के लिए पीडीएस की खरीद शुरू की जाती है। 2021–22 से 2025–26 के लिए एनएमईआईसीटी चरण III के तहत शोधशुद्धि (पीडीएस) परियोजना के लिए ईएफसी और मंत्रिमंडल द्वारा निधियाँ स्वीकृत की गई हैं।

विवरण सार

		सितंबर 2019– मार्च 2020	अप्रैल 2020– मार्च 2021'	अप्रैल 2021– मार्च 2022	अप्रैल 2022– मार्च 2023	अप्रैल 2023– मार्च 2024
दस्तावेज़ों की संख्या (4 वर्षों में 40 लाख)	प्रस्तावित	2 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख	10 लाख
	प्राप्त (प्रस्तुत दस्तावेज़)	3,34,766	7,86,382	8,73,905	9,66,567	8,76,967 (दिसंबर '23 तक)
वित्तीय लक्ष्य	प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय (लाख में)	1000	1000	1000	1000	1000
	जारी निधि (लाख में)	1335.00		607.00	500.00	इंफलिबनेट को 735.00 ईएसएस को 477.00 वापस भुगतान किया जाता है

'कोविड–19 के कारण अवधि मई 2021 तक बढ़ाई गई। पहला वर्ष 12+9 महीने, दूसरा वर्ष 12 महीने, तीसरा वर्ष 12 महीने = कुल 45

विज्ञान और इंजीनियरिंग में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का समायोजन (एफओएसएसईई):

एफओएसएसईई (https://fossee.in) प्रोजेक्ट का फोकस फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देना है, और मुख्य रूप से शैक्षणिक संस्थानों में व्यावसायिक सॉफ्टवेयर पर निर्भरता कम करना है। यह काम स्थापित व्यावसायिक सॉफ्टवेयर के अच्छे ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर विकल्पों की पहचान करके और उन्हें बढ़ावा देकर किया जाता है। एफओएसएसईई टीम हजारों छात्रों और फैकल्टी को विभिन्न सॉफ्टवेयर पर इस सीमा तक प्रशिक्षित करती है कि वे स्वयं उपयोगी कोड और सामग्री बना सकें। यह ओपन–सोर्स सॉफ़्टवेयर के लिए दस्तावेज़ीकरण की कमी की समस्या का समाधान करता है। एफओएसएसईई की लोकप्रिय गतिविधियाँ पाठ्यपुस्तक साथी, लैब प्रवासन, केस स्टडी, हैकाथॉन, मैपाथॉन, कार्यशालाएँ और सम्मेलन हैं। एफओएसएसईई साइलैब, पायथन, डीडब्ल्यूएसआईएम, ओपन फोम, ओपन मॉडेलिका, आर, क्यूजीआईएस, ईसिम, ओसडैग,और अरुडिनो आदि को बढ़ावा देता है। ये सभी कार्यकलाप साल भर चलते हैं और बहुत सारे छात्र योगदान देते हैं। ये योगदान ओपन सोर्स पर जारी किए गए हैं और इन्हें एफ़ओएसएसईई वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। एफ़ओएसएसईई टीम विभिन्न सॉफ़्टवेयर पर कार्यशालाएं भी आयोजित करती है। वर्ष 2023 में हम इन कार्यकलापों के माध्यम से 1200 से अधिक संस्थानों तक पहुंच सके।

एफ़ओएसएसईई टीम ओपन–सोर्स सॉफ़्टवेयर भी विकसित करती है। कुछ सॉफ़्टवेयर जिन पर टीम वर्तमान में काम कर रही है, वे हैं क्लाउड पर ई सिम, क्लाउड पर आर्डूइनों और क्लाउड पर ओस्डैग। इन सॉफ़्टवेयरों के बीटा संस्करण तैयार हैं और हम प्रायोगिक कार्यशालाएँ आयोजित करने के लिए कुछ संस्थानों के साथ बातचीत कर रहे हैं। एक बार इनका परीक्षण हो जाने के बाद, इस सॉफ़्टवेयर को देश भर के विभिन्न संस्थानों द्वारा उपयोग के लिए लॉन्च किया जाएगा। इस सॉफ्टवेयर को सीखने के लिए वीडियो ट्यूटोरियल भी बनाए गए हैं। देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ बातचीत जारी है, ताकि उन्हें ओपन सोर्स में परिवर्तित करने में मदद मिल सके।

इन कार्यकलापों के अलावा, परियोजना ने एफ़ओएस एसईई ग्रीष्मकालीन फ़ेलोशिप और सेमेस्टर– लंबी इंटर्नशिप भी आयोजित की, जिसमें कई छात्रों ने पंजीकरण कराया। स्क्रीनिंग कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद 100 से अधिक छात्रों को इंटर्नशिप के लिए चुना गया। इन प्रशिक्षुओं/अध्येताओं का आईआईटी बॉम्बे के साथ–साथ वीआईटी चेन्नई, एसएएसटीआरए विश्वविद्यालय, शिव नादर विश्वविद्यालय, सीयूएसएटी, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय और आईआईटी गुवाहाटी के एफ़ओएसएसईई से जुड़े संकाय सदस्यों द्वारा मार्गदर्शन किया गया था।

2023 में, एफ़ओएसएसईई परियोजना ने आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी तिरुपति नवविष्कार I–हब फाउंडेशन (आईआईटीटीएनआईएफ़) के सहयोग से आईआईटीबी–एफ़ओएसएसईई मैपाथॉन का आयोजन किया। यह सभी भारतीय नागरिकों के लिए खुला था और उन्हें विभिन्न विषयगत क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मानचित्र के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्यूजीआईएस जैसे एफ़एलओएसएस का उपयोग करके सार्वजनिक रूप से उपलब्ध भू–स्थानिक डेटासेट से मानचित्र बनाने की अनुमति दी गई थी। इस आयोजन में 5000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। सभी प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया गया और विजेता 345 मानचित्रों को ओपन सोर्स पर जारी किया गया।

एफ़ओएसएसईई टीम की जीआईएस पहल के संबंध में एक लेख हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ था। उसे इस रिपोर्ट के अंत में संलग्न किया गया है। इस लेख को https://www.hindustantimes.com/cities/mumbai-news/how-amateur-mapmakers-are-solving-real-world-problems-101696138619348.html पर देखा जा सकता है। एफ़ओएसएसईई ने सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय परिसर (17 जून – 22 जून 2023 तक) और 6 जुलाई 2023 को आईआईटी बॉम्बे में आयोजित जी20 कार्यक्रमों में भाग लिया। ये कार्यक्रम जी–20, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), और मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान (एफएलएन) सुनिश्चित करने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किए गए थे। इन दोनों आयोजनों में एफ़ओएसएसईई स्टॉल पर अच्छी भीड़ रही। कई छात्रों और गणमान्य व्यक्तियों ने हमारे स्टॉल का दौरा किया। कृपया इस रिपोर्ट के अंत में दी गई तस्वीरें देखें।

एफ़ओएसएसईई ने दिसंबर 2023 में ओपनफोम हैकथॉन का आयोजन किया था। हैकथॉन का आयोजन cfd.fossee.in की रिपॉजिटरी में उपलब्ध केस स्टडीज को ओपनफ़ोम के नवीनतम संस्करणों में अपग्रेड करने के लिए किया गया था। हैकाथॉन के लिए 126 छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया था और उनमें से तीन छात्रों को चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया था।

भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस)

भारतीय अनुसंधान सूचना नेटवर्क प्रणाली (आईआरआईएनएस) सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र (इनफ्लिबनेट) द्वारा विकसित और एमओई द्वारा वित्त पोषित एक वेब आधारित अनुसंधान सूचना प्रबंधन और नेटवर्क प्रणाली है। पोर्टल शैक्षणिक, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों

को उनकी विद्वतापूर्ण संचार गतिविधियों को एकत्र करने, क्यूरेट करने और प्रदर्शित करने की सुविधा प्रदान करता है और एक विद्वतापूर्ण नेटवर्क बनाने का अवसर प्रदान करता है। यह संगठन को मौजूदा शैक्षणिक प्रणाली जैसे मानव संसाधन प्रणाली, अनुदान प्रबंधन प्रणाली, संस्थागत भंडार आदि को एकीकृत करने के लिए भी समर्थन करता है। इसे विद्वानों के प्रकाशनों और उद्धरण को पुनः प्राप्त करने के लिए ओआरसीआईडी आईडी, स्कोपस आईडी, रिसर्च आईडी, गूगल स्कॉलर आईडी जैसी शैक्षणिक पहचान के साथ एकीकृत किया गया है। आईआरआईएनएस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने शोध योगदान को साझा करने के लिए संकाय सदस्यों को अधिक महत्वपूर्ण जोखिम प्रदान करता है और बहु–विषयक अनुसंधान के लिए अधिक सहयोगियों को लाता है, और यह अनुसंधान मेटाडेटा गुणवत्ता में सुधार करता है और विभिन्न मूल्यांकन प्रणालियों के लिए दोहराव वाली डाटा प्रविष्टि को कम करता है। आईआरआईएनएस प्रशासक को वित्तपोषण, संकाय मूल्यांकन और संसाधन आवंटन पर बेहतर निर्णय लेने के लिए अनुसंधान रिपोर्ट, प्रदर्शन आकलन और कार्यनीतिक रूप से अनुसंधान प्रगति का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा, यह विशेषज्ञता के अपने संबंधित क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान करने और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण के अवसरों को बढ़ाने में संकाय सदस्यों का समर्थन करता है। आईआरआईएनएस परियोजना समीक्षा और अन्य राष्ट्रीय स्तर की सहयोगी परियोजनाओं के लिए एक विशेषज्ञ डेटाबेस प्रदान करके नीति निर्माताओं की सहायता करता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, 421 नए उदाहरण बनाए गए, 67001 नए प्रोफाइल जोड़े गए, और 6.77 लाख प्रकाशन मेटाडेटा को विभिन्न स्रोतों से पुनर्प्राप्त किया गया। समीक्षाधीन अवधि तक, 1082 उदाहरण तैयार किए गए और उन्हें 1.72 लाख विशेषज्ञ प्रोफाइल से जोड़ा गया है˙ विभिन्न स्रोतों से 24 लाख से अधिक प्रकाशन मेटाडेटा जमा किए।

डाटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड कुछ प्रदर्शन संकेतकों जैसे प्रकाशन, उद्धरण, सोशल मीडिया मेट्रिक्स आदि के साथ आईआरआईएनएस उदाहरणों के माध्यम से एकत्रित संकाय प्रोफाइल और विद्वानों की जानकारी का एक दृश्य प्रदर्शन है। विजुअल डैशबोर्ड अनुसंधान प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न टेबल, ग्राफ़, चार्ट प्रदान करता है और भाग लेने वाले संस्थानों की तुलना करता है। विश्लेषणात्मक डेटा डैशबोर्ड फंडिंग एजेंसी का समर्थन करता है, और नीति निर्माता एक संगठन और विभागों के अनुसंधान प्रदर्शन को एक दूसरे के साथ तुलना करके समझते हैं। डैशबोर्ड विभिन्न स्रोतों से विशेषज्ञों, प्रकाशनों और उद्धरणों के अपने क्षेत्रों से जुड़े संकाय की कुल संख्या प्रदान करता है।

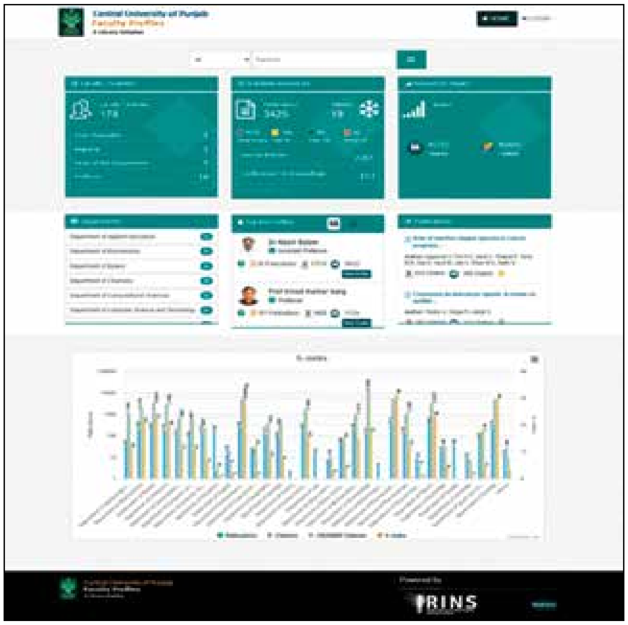

आईआरआईएनएस संस्थान प्रोफ़ाइल

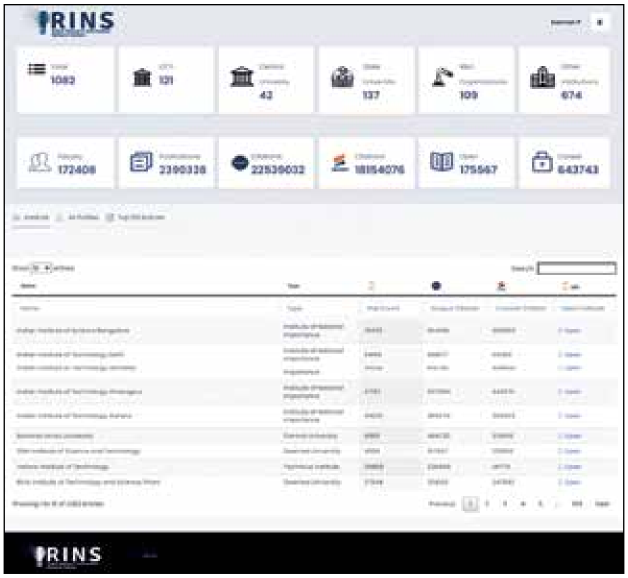

आईआरआईएनएस फंडिंग एजेंसी डैशबोर्ड

ईआरपी (समर्थ):

"समर्थ" परियोजना 2019 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के लिए एक विकासवादी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाना और प्रदान करना था, ताकि विविध परिसर कार्यों को एक सामंजस्यपूर्ण स्वचालन प्रणाली में एकीकृत किया जा सके, संस्थानों को संचालन और सेवाओं की योजना, प्रबंधन, वितरण और निगरानी के लिए डिजिटल माध्यम डिजिटल ढांचे के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके और डाटा–संचालित निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके तथा नीति–निर्माण और अभिशासन के लिए मंत्रालय और वैधानिक निकायों को वास्तविक समय केपीआई अवलोकन की सुविधा प्रदान की जा सके।

समर्थ उच्च शिक्षा में नीतियों और शासन के मानकों के साथ प्रौद्योगिकी का मिश्रण करता है और इसे संस्थान और इसके हितधारकों को कभी भी–कहीं भी डिजिटल इंटरफेस के माध्यम से उपलब्ध कराता है। समर्थ का उपयोग करते हुए, संस्थान अपने प्रावधान में शामिल कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को सहभागिता का इष्टतम उपयोग करके छात्रों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा अनुभव प्रदान कर सकते हैं।

2019 में अपने लॉन्च के बाद से, समथ्र को केंद्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर और राष्ट्रीय महत्त्व के अन्य संस्थानों सहित विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा बड़े पैमाने पर अपनाया गया हैं 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों और 440 जिलों में अखिल भारतीय उपस्थिति से, समर्थ संस्थानों के छात्रों और प्रशासकों के लिए विश्व–स्तरीय मगर समान अनुभव प्रदान करने वाले राष्ट्र–व्यापी फ्यूचर–रेडी डिजिटल परिसरों का नेटवर्क तैयार कर रहा है। फिलहाल, उपयोग 2800 से अधिक संस्थान अपने समर्थ का कार्यों को डिजिटल रूप से पूरा करने के लिए उपयोग कर रहे हैं।

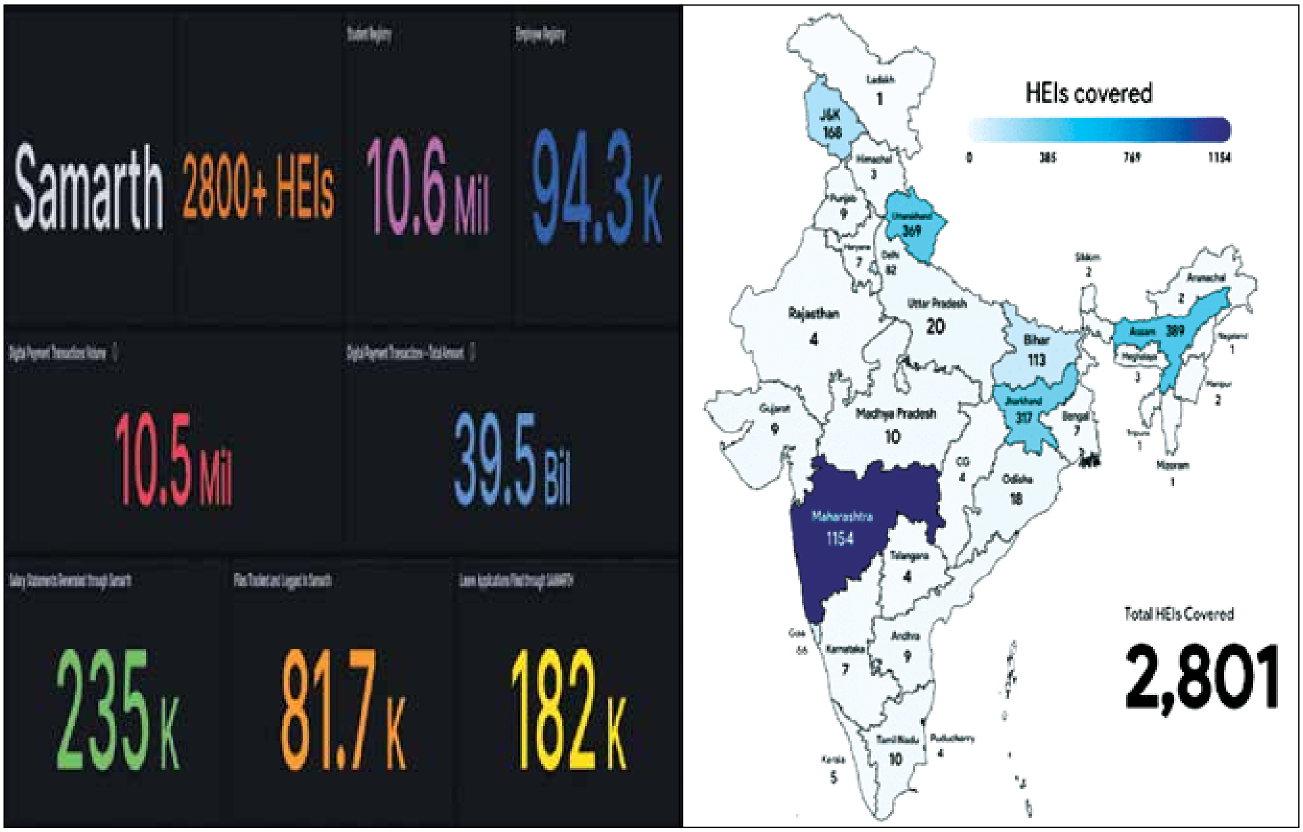

समर्थ स्केल और स्प्रेड 2023

बढ़ती रजिस्ट्रियां

- 1.06 करोड़ छात्र रिकॉर्ड
- 94.3 हजार छात्र रिकॉर्ड

समर्थ पर डिजिटल भुगतान

- 1.05 करोड़ डिजिटल भुगतान लेनदेन मात्रा
- डिजिटल भुगतान लेनदेन की कुल राशि 3950 करोड़ रुपए

शासन व्यवस्था में सुधार

- 2.35 लाख वेतन विवरण ऑनलाइन संसाधित
- 81.7 हजार फ़ाइलें लॉग और ट्रैक की गईं।
- 1.82 लाख छुट्टी आवेदन ऑनलाइन संसाधित किए गए।

समर्थ के माध्यम से भर्ती

- 68 उच्च शिक्षण संस्थानों ने शिक्षण के लिए 479 विज्ञापन प्रकाशित किए और 12,35,705 आवेदन संसाधित किए और 51 उच्च शिक्षण संस्थानों ने गैर–शिक्षण पदों के लिए 299 विज्ञापन प्रकाशित किए और 2,75,622 आवेदन संसाधित किए।
- हाल ही में शुरू किए गए सीयू–चयन पोर्टल के माध्यम से, 32 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने 1369 विज्ञापित रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, और लगभग 35 हजार आवेदन संसाधित किए गए हैं। मई 2023 में लॉन्च होने के बाद से एकीकृत भर्ती पोर्टल पर 47 हजार उम्मीदवार प्रोफाइल बनाए गए हैं।

समर्थ के माध्यम से प्रवेश और छात्र गतिविधियाँ

- राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा 2023 में भी आयोजित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) का प्रावधान, जिसमें 250 विश्वविद्यालयों ने भाग लिया। पोर्टल में 1.79 मिलियन पंजीकरण किए गए और 1.50 मिलियन आवेदन जमा किये गये।
- असम, जम्मू और कश्मीर और उत्तराखंड राज्यों के लिए एनईपी–आधारित प्रवेश पोर्टल का प्रावधान किया गया था।
- लगभग 20 लाख आवेदकों ने 2023 में विभिन्न विश्वविद्यालयों/एचईआई में समर्थ के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्चतर शिक्षा विभाग में समर्थ

- समर्थ पोर्टल को 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च शिक्षण विभागों द्वारा अपनाया गया था। असम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग), महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा में कार्यान्वयन प्रगति पर है और गोवा और उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है।
- असम, उत्तराखंड एवं जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए प्रवेश पोर्टलों में 1000 से अधिक संस्थानों के लिए प्रवेश आयोजित किए गए और अब शैक्षणिक प्रबंधन शुरू किया गया है।
- उत्तराखंड में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए, नवंबर 2023 में लॉन्च किए गए "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना" के तहत समर्थ अनुसंधान परियोजना प्रबंधन पोर्टल शुरू किया गया था।
- एचईडी यूके ने 119 कॉलेजों में अपने शिक्षण कर्मचारियों के लिए कैरियर उन्नति के लिए समर्थ पोर्टल का उपयोग किया है।

अन्य पहलः

- उम्मीदवारों के लिए आवेदन और भर्ती प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए यूजीसी दिशानिर्देशों के आधार पर एक एकीकृत पोर्टल "सीयू–चयन" का शुभारंभ किया गया था। यह पोर्टल भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए एकल बिन्दु के रूप में कार्य करता है।
- एनआईटी में भर्ती में सहायता करने के लिए एनआईटी (सीआरईएनआईटी) हेतु सामान्य भर्ती पोर्टल विकसित किया गया था।

- विश्वविद्यालय अधिनियमों और संशोधनों के प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत रिपाजिटरी बनाने के लिए शिक्षा मंत्रालय की आवश्यकताओं के आधार पर एक मॉड्यूल "अधीनस्थ विधान" डिजाइन किया गया था।
- समर्थ ईजीओवी सूट के कार्यान्वयन के संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय और असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा तथा उत्तर प्रदेश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापित डीएसीई (अंबेडकर सेंटर फॉर एक्सीलेंस) के लिए समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश और भर्ती आयोजित की जा रही हैं।
- शिक्षा मंत्रालय के बाह्य छात्रवृत्ति प्रभाग के लिए साक्षात छात्रवृत्ति पोर्टल पर 5 छात्रवृत्तियां शुरू की गई हैं।

जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम कार्यक्रम में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान (बीच में) के साथ पीआई, प्रोजेक्ट समर्थ (दाएं) ।

अक्तूबर 2023 में गोवा के माननीय मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत की उपस्थिति में दिल्ली विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग, गोवा के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स (स्वयम):

'स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स' (स्वयम) भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है और इसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों पहुंच, समता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे वंचितों सहित सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधनों को उपलब्ध कराना है। स्वयम उन छात्रों के लिए डिजिटल डिवाइड को पाटने का प्रयास करता है जो अब तक डिजिटल क्रांति से अछूते रहे हैं और ज्ञान अर्थव्यवस्था की मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पाए हैं।

यह एक स्वदेशी रूप से विकसित आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाता है जो 9वीं कक्षा से लेकर पोस्ट–ग्रेजुएशन तक कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी पाठ्यक्रमों की मेजबानी की सुविधा प्रदान करता है, जिसे किसी के द्वारा, कहीं भी, कभी भी एक्सेस किया जा सकता है। सभी पाठ्यक्रम संवादात्मक हैं, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों को तैयार करने में देश भर से 1,000 से अधिक विशेष रूप से चुने गए संकाय और शिक्षकों ने भाग लिया है।

स्वयम पर होस्ट किए गए पाठ्यक्रम 4 चतुर्थांशों में हैं

1. वीडियो लेक्चर
2. विशेष रूप से तैयार पठन सामग्री जिसे डाउनलोड/प्रिंट किया जा सकता है
3. परीक्षा और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से स्व–मूल्यांकन परीक्षण और
4. समस्या समाधान के लिए एक ऑनलाइन चर्चा मंच।

ऑडियो–वीडियो और मल्टीमीडिया व अत्याधुनिक शिक्षण/प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिगम अनुभव को समृद्ध करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सर्वोत्तम गुणवत्तायुक्त सामग्री का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करने के लिए 10 राष्ट्रीय समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। ये हैं, स्नातकोत्तर गैर–इंजीनियरिंग शिक्षा

के लिए यूजीसी, गैर–स्नातक गैर–इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए सीईसी, इंजीनियरिंग के लिए एनपीटीईएल, स्कूल शिक्षा के लिए एनसीईआरटी और एनआईओएस, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के लिए इग्नू, प्रबंधन अध्ययन के लिए आईआईएम बंगलोर, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए एनआईटीटीटीआर और स्व–चालित पाठ्यक्रमों के लिए एआईसीटीई, एआरपीआईटी पाठ्यक्रम और विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा। हाल ही में एनआईटी त्रिची को इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में जोड़ा गया है।

स्वयम को औपचारिक रूप से भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 09.07.2017 को शुरु किया गया था। अब तक, स्वयम के माध्यम से कुल 11772 पाठ्यक्रम प्रदान किए गए हैं और लगभग 1182 पाठ्यक्रम जनवरी 2024 सेमेस्टर में प्रदान किए जा रहे हैं। स्वयम प्लेटफॉर्म पर लगभग 1.21 करोड़ से अधिक अद्वितीय उपयोगकर्ता/पंजीकरण किए गए हैं और स्वयम के विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 4 करोड़ + नामांकन किए गए हैं। एआईसीटीई और यूजीसी द्वारा क्रेडिट अंतरण (अधिकतम 40% तक) की रूपरेखा आवश्यक नियमों को लाकर तैयार की गई है। इसके साथ, पारंपरिक संस्थानों/कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्र स्वयम पाठ्यक्रम के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को अपने शैक्षणिक रिकॉर्ड में स्थानांतरित कर सकते हैं। लगभग 295 संस्थानों/विश्वविद्यालयों ने क्रेडिट ट्रांसफर के लिए स्वयम पाठ्यक्रम को मान्यता दी है और अन्य कई ऐसा करने की प्रक्रिया में हैं।

स्वयम के माध्यम से संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) भी विकसित किया जा रहा है। स्वयम के माध्यम से दिए गए एनआईओएस के डीएलएड कार्यक्रम के तहत पंद्रह लाख अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। सरकार ने स्वयम के एमओओसी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 15 लाख उच्च शिक्षा संकाय के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास की एक प्रमुख और अनूठी पहल, शिक्षण में वार्षिक पुनश्चर्या कार्यक्रम (अर्पित) शुरू किया है। कार्यशालाओं और सेमिनारों के माध्यम से स्वयम पर जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालयों/संस्थानों में लगभग 6000+ स्थानीय चैप्टर बनाए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय ने स्वयम पोर्टल के माध्यम से पैन–अफ्रीकी छात्रों को ई–वीबीएबी (ई–विद्या भारती आरोग्य भारती) परियोजना प्रदान करने को सक्षम करने के लिए विदेश मंत्रालय के साथ भी करार किया है।

चरण–II स्वयम के तहत, वीडियो के ट्रांसक्रिप्शन सहित कुछ एमओओसी सामग्री का 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा, ताकि शिक्षार्थी अपनी पसंद की भाषा का चयन कर सकें और पाठ्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषा में बेहतर तरीके से सीख सकें। स्वयम पर दिए जाने वाले ऑनलाइन कोर्स डिजिटल डिवाइड को कम करने वाले हैं। यह एक विघटनकारी प्रौद्योगिकी के रूप में सामने आएगी और उच्च शिक्षा के वर्तमान व्यवसाय मॉडल को बदल देगी। चूंकि स्वयम पर एमओओसी पारंपरिक शिक्षा के साथ एकीकृत हैं, यह आने वाले दिनों में सीखने के जबरदस्त अवसर लाएगा और शिक्षा क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा।

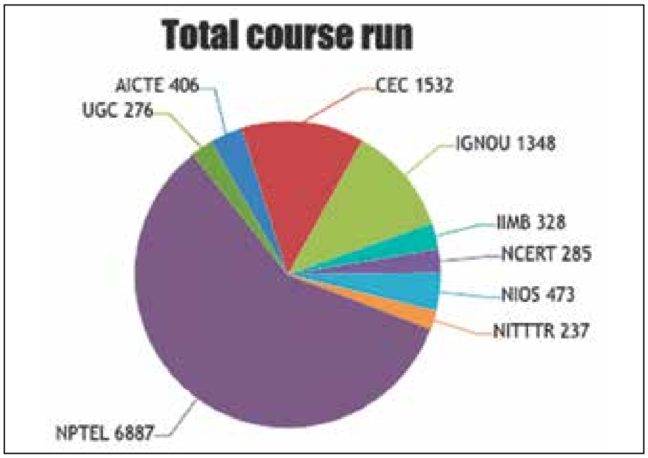

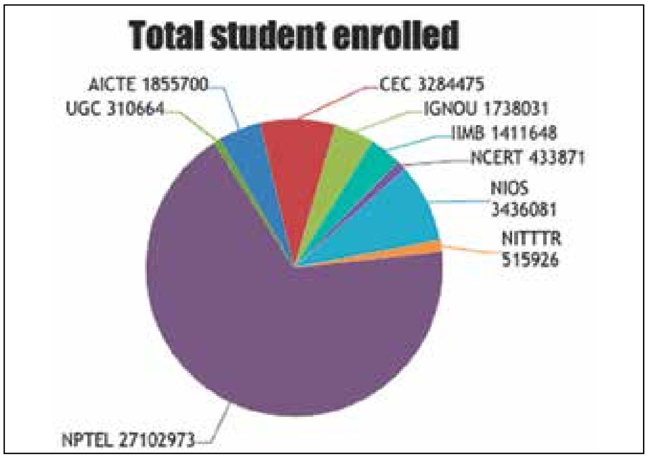

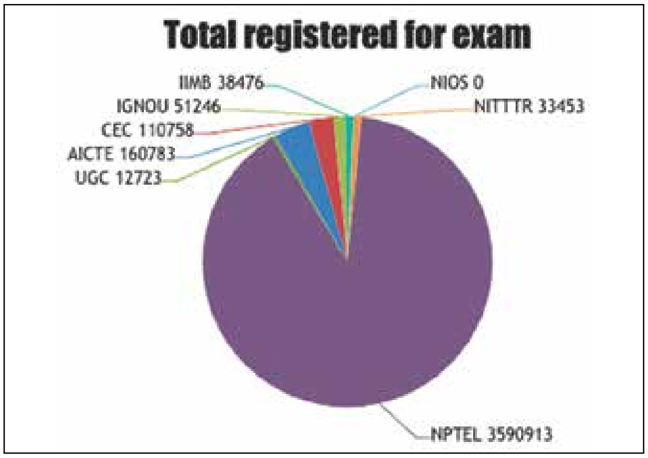

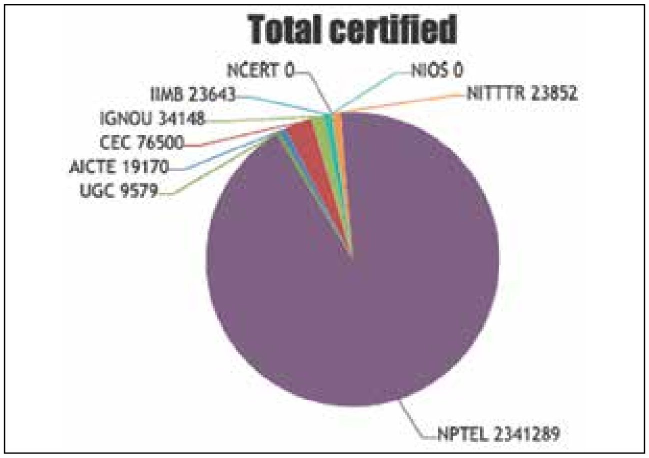

स्वयम प्लसः

छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से, स्वयम बोर्ड द्वारा संयुक्त पाठ्यक्रम विकसित करने और इसे स्वयम पोर्टल के माध्यम से स्वयम इंडस्ट्री वर्टिकल के रूप में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है, जो छात्रों को कौशल प्रदान करने, पुनर्कौशल प्रदान करने और कौशल उन्नयन करने के लिए समर्पित है।

यह कदम एनईपी 2020 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से है। इसके अलावा विभाग ने **विनिर्माण, ऊर्जा, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग/आईटी/आईटीईएस, प्रबंधन अध्ययन, अध्यापक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य और पर्यटन, सामाजिक विज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा, मीडिया और संचार, सहित उभरते क्षेत्रों के लिए उद्योग संबंधी ज्ञान और कौशल योग्यताओं का** लाभ उठाने के उद्देश्य से उद्योग जगत के प्रमुख नामों के साथ सहयोग किया है। 31 जनवरी 2024 तक, उच्चतर शिक्षा विभाग ने **16 उद्योग भागीदारों के साथ समझौता ज्ञापन** पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें एडोब, सिस्को, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, एलएंडटी, बजाज फिनसर्व, मेटा, टीसीएस, वाधवानी फाउंडेशन, मेडवर्सिटी, जीयूवीआई, अनादि फाउंडेशन, लैंक्विल, 360 डिजी, द जॉब प्लस, और स्मार्टब्रिज शामिल हैं।

साथी (प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व–मूल्यांकन, परीक्षण और सहायता) साथी (प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व–मूल्यांकन परीक्षण और सहायता), एक अभिनव ऑनलाइन शिक्षा मंच, शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर की एक संयुक्त पहल है। यह पहल पूरे भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्रों को सशक्त बनाने के लिए की गई है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में एक बड़े कदम का द्योतक है।

साथी स्टॉल पर माननीय शिक्षा मंत्री

पद्म श्री प्रोफेसर एच. सी. वर्मा द्वारा साथी विशेषज्ञ सत्र

साथी नीट और जेईई उम्मीदवारों के लिए संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। प्रदान किए जाने वाले कार्यक्रमों में आईआईटी के प्रसिद्ध संकायों के वीडियो व्याख्यान, मूल्यांकन मंच 'प्रूटर' शामिल हैं, जिसमें 60,000 से अधिक समस्याओं को विषय–वार अनुभागों और संपूर्ण मॉक टेस्ट, एक एआई–आधारित चैटबॉट और आईआईटी और एम्स के छात्रों से मार्गदर्शन में विभाजित किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म पर हाल ही में अंग्रेजी सहित 5 भाषाओं में 45–दिवसीय जेईई क्रैश कोर्स होस्ट किया, जिसका उद्देश्य जनवरी 2024 जेईई मुख्य परीक्षा से ठीक पहले गहन तैयारी और संशोधन प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, साथी ने पद्म श्री पुरस्कार विजेता और 'कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स' के लेखक प्रोफेसर एचसी वर्मा के साथ एक सप्ताह का जेईई–केंद्रित भौतिकी समस्या–समाधान सत्र आयोजित किया।

साथी एक वेब और डीटीएच–आधारित शिक्षण मंच है, जो देश भर के छात्रों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया है, जो जेईई, एनईईटी, सीएलएटी, आईसीएआर, एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। यह प्लेटफ़ॉर्म अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं सहित कई भाषाओं में वीडियो व्याख्यान, इंटरैक्टिव चैटबॉट, संदेह–समाधान सत्र और मेंटरशिप सहायता प्रदान करता है। साथी प्लेटफॉर्म को आईआईटी कानपुर के सीएसई विभाग के प्रोफेसर अमेय करकरे के मार्गदर्शन में विकसित किया गया है। आईआईटी कानपुर के पास गहन डोमेन ज्ञान और तकनीकी विशेषज्ञता के साथ संसाधन पूल है जो इस संपूर्ण लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम प्लेटफार्म में परिलक्षित होता है।

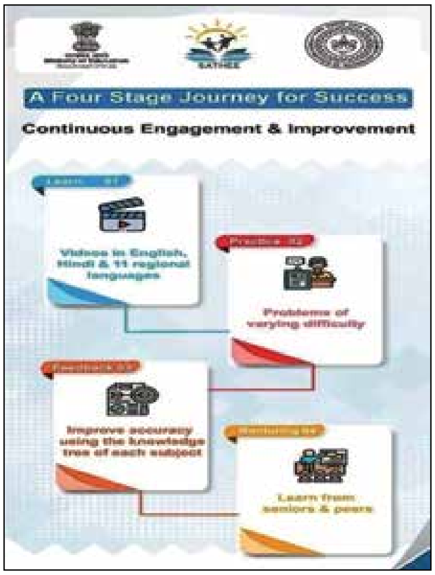

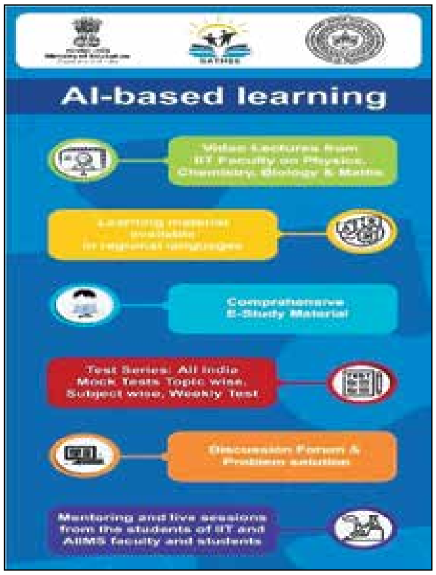

साथी विशेषताएं

इस परियोजना से शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि यह लाखों छात्रों को अपने करियर की आकांक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक सामग्री और मार्गदर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। यह प्रस्ताव भारत को शिक्षा और कौशल विकास में वैश्विक नेता बनाने के भारत के माननीय प्रधान मंत्री के विजन में भी योगदान देगा।

परियोजना गतिविधियाँः जून 2023 – दिसंबर 2023 के दौरान की गई प्रमुख गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:–

- वेब और डीटीएच प्रसार के लिए उपयुक्त 11 भारतीय भाषाओं में पीसीएमबी विषयों (कक्षा 11 और 12 के पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग और एनईईटी परीक्षाओं को लक्षित करने हेतु) के लिए 684 वीडियो का अनुवाद और डबिंग की गई। बीआईएसएजी से प्राप्त प्रतिक्रिया और समीक्षा के अनुसार डीटीएच ट्रांसमिशन से संबंधित सभी तकनीकी मुद्दों का समाधान किया गया। अंग्रेजी वीडियो के क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद/डबिंग के लिए टूल को अंतिम रूप दिया गया।
- पीसीएमबी कक्षा 11 और 12 विषयों के लिए 80,000+ प्रश्नों का एक ऑंकड़ाधार बनाया गया। भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीवविज्ञान (प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान) में विषयवार परीक्षाएं तैयार की गई हैं जो विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई हैं। ये परीक्षाएं छात्रों को उनकी तैयारियों का मूल्यांकन करने में मदद करेंगी। रिवीजन टेस्ट और मॉक टेस्ट के लिए समय सारणी तैयार की।
- डीटीएच के लिए क्यूआर कोड स्कैनिंग–आधारित संवाद हेतु एक ऐप विकसित किया गया। ऐप और वेब पोर्टल को डिजीलॉकर (एबीसी आईडी) के साथ एकीकृत किया गया।
- साथी के लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया। पोर्टल को चैटबॉट, डैशबोर्ड और फ़ोरम के साथ एकीकृत किया गया। चैटबॉट प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में सामान्य प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और छात्रों को उस विशिष्ट वीडियो और समय के बारे में बता सकता है जहां उनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। डैशबोर्ड छात्रों की प्रगति और प्रदर्शन दिखा सकता है। यह मंच छात्रों को बातचीत करने और प्रश्न पूछने में सक्षम बना सकता है।
- विस्तृत नोट्स बनाए गए जो छात्रों के लिए संदर्भ पुस्तक के रूप में काम कर सकते हैं। आईआईटी और एनईईटी छात्रों के नोट्स और प्रासंगिक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अध्यायों के लिंक प्रदान किए गए। 400 से अधिक वीडियो बनाए जो बताते हैं कि एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में समस्याओं को कैसे हल किया जाए। हल किए गए उदाहरणों के साथ और अधिक वीडियो तैयार करने पर काम चल रहा है।
- मंच के लिए 400 से अधिक आईआईटी और एनईईटी छात्रों को सलाहकार के रूप में भर्ती किया गया। वे लाइव ट्यूटोरियल आयोजित करेंगे, नोट्स साझा करेंगे, चरण–दर–चरण समाधान प्रदान करेंगे और फ़ोरम पर प्रश्नों का उत्तर देंगे। 40 से अधिक वीडियो बनाए जिनमें ये छात्र सलाहकार अपनी सफलता की कहानियां, टिप्स और प्रेरणा साझा करते हैं।
- वेबसाइट की कार्यक्षमता और स्वरूप में सुधार के लिए शिक्षा मंत्रालय के हितधारकों और वाधवानी फाउंडेशन के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें कीं। शिक्षा मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के कार्यालय में साथी वेब/पोर्टल विकास टीम से दो वरिष्ठ तकनीकी सदस्यों को नियुक्त किया गया। वे शिक्षा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों से बेहतर समन्वय, निगरानी और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया को शामिल करने की दिशा में काम कर रहे हैं। एनईपी

की तीसरी वर्षगांठ (29–30 जुलाई 2023) पर अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन (एबीएसएस) के दौरान प्रगति मैदान में हॉल 14 की पहली मंजिल पर एक स्टॉल लगाया गया। बड़ी संख्या में लोग आए और उपस्थित लोगों से बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली।

- केवी, जेएनवी, पीएम श्री स्कूल के छात्रों से जुड़े। 31 दिसंबर तक 1,50,000 से अधिक छात्रों ने मंच पर पंजीकरण कराया है।
- 15 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 तक जेईई मुख्य की तैयारी के लिए 45 दिनों का क्रैश कोर्स आयोजित किया गया। प्रोफेसर एच सी वर्मा द्वारा भौतिकी के लिए 7 दिनों का लाइव सत्र एक विशेष आकर्षण था।
- साथी पोर्टल के साथ एआई चैटबॉट का विकास और एकीकरण। एंड्रॉइड और आईओएस के लिए साथी मोबाइल ऐप

साथी मोबाइल एप

एआई चैट बोट

यह मंच अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने और पूरे भारत में लाखों छात्रों को उच्च गुणवत्तायुक्त शैक्षिक सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करने की ओर प्रयासरत है। यह मंच राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और समावेशिता को बढ़ाना है।

इनफ्लिबनेट केंद्र के ई–शोध सिंधु:

ई–शोध सिंधु उच्च शिक्षा ई–संसाधनों के लिए एक सहायता संघ है, जो शैक्षिक संस्थानों को सदस्यता की कम दर पर पूर्ण–पाठ, ग्रंथ सूची और तथ्यात्मक डाटाबेस सहित गुणात्मक इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच प्रदान करता है। ई–शोध सिंधु के प्रमुख लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

- ई–शोध सिंधु की स्थापना: उच्च शिक्षा ई–संसाधनों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित सहायता संघों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और कार्यकलापों का संवर्धिन और सुदृढ किया जाएगा।
- सतत पहुंच के आधार पर ई–जर्नल, ई–जर्नल आर्काइव, और ई–पुस्तकों का एक विशाल संग्रह विकसित करना।
- जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से भारत में सदस्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और तकनीकी संस्थानों में ई–संसाधनों के उपयोग की निगरानी और प्रचार करना।
- सभी शैक्षणिक संस्थानों को सदस्यता–आधारित विद्वानों की जानकारी (ई–पुस्तकें और ई–पत्रिकाओं) तक पहुंच प्रदान करना।
- सब्जेक्ट पोर्टल और सब्जेक्ट गेटवे के माध्यम से ओपन एक्सेस में उपलब्ध विद्वतापूर्ण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना।
- डिजिटल विभाजन को पाटना और सूचना–समृद्ध समाज की ओर बढ़ना;
- मुक्त विश्वविद्यालयों और एमओई–वित्तपोषित संस्थानों सहित अतिरिक्त संस्थानों को चयनित ई–संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना जो मौजूदा कंसोर्टिया के अंतर्गत नहीं आते हैं;
- अतिरिक्त गतिविधियों और सेवाओं को अपनाना जिनके लिए एक सहयोगी मंच अपेक्षित है और मौजूदा कंसोर्टिया द्वारा निष्पादित नहीं की जा रही है; और

- इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकों के प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकालय विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना।

इनफ्लिबनेट केंद्र को ई–शोध सिंधु के निष्पादन और संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ई–शोध सिंधु, यूजीसी अधिनियम की धाराओं 12 (ख) और 2 (च) के तहत कवर किए गए 217 से अधिक विश्वविद्यालयों और 4200+ कॉलेजों, 75 तकनीकी संस्थानों और आईआईएससी, एनआईटी, आईआईएम, आईआईएसईआर, आईआईआईटी आदि सहित 98 केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) को सेवा प्रदान करना जारी रखेगी। वर्ष 2023 के लिए, कंसोर्टियम ने पात्र विश्वविद्यालयों/सीएफटीआई के लिए केंद्रीय वित्त पोषण के माध्यम से 21 संसाधनों (10000+ पत्रिकाओं और चार डाटाबेस सहित) की सदस्यता ली, जिन्होंने ई–शोध सिंधु पोर्टल के माध्यम से अपनी आवश्यकताओं को पंजीकृत किया, शेष संसाधनों को अलग–अलग संस्थानों द्वारा कंसोर्टियम द्वारा अपने स्वयम की निधियों का उपयोग करके तय की गई दरों पर सब्सक्राइब किया जा सकता है। ई–शोध सिंधु की नेगोशिएशन कमेटी ने 44 प्रकाशकों/विक्रेताओं से 127 ई–संसाधन संग्रह के लिए सब्सक्रिप्शन की दरों और सब्सक्रिप्शन की न्यूनतम दरों को प्राप्त करने के लिए बातचीत की। कंसोर्टियम का कॉलेज घटक, जिसे एन–लिस्ट कहा जाता है, ने एन–लिस्ट कार्यक्रम के तहत 4200+ से अधिक कॉलेजों को 6,500+ पत्रिकाओं, 1,99,500+ ई–पुस्तकों और 6 लाख+ ई–पुस्तकों (एनडीएलआई के माध्यम से) तक पहुंच प्रदान करना जारी रखा।

ई–शोध सिंधु (ईएसएस) ने ई–संसाधनों तक निर्बाध पहुंच की सुविधा के लिए अतिरिक्त सुविधाओं को एकीकृत किया है जैसे:

क) इनफ्लिबनेट एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन (आईएनएफईडी) – शिबोलेथ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन ऑफ यूजर्स।

ख) संशोधित इंफीस्टैट्स – अतिरिक्त सुविधाओं और कार्यक्षमता के साथ सब्स्क्राइब्ड ई–संसाधनों के लिए काउंटर–अनुपालन उपयोग।

ग) दस्तावेज़ वितरण सेवा (डीडीएस) के लिए जेगेटप्लस, मेटा हारवेस्टिंग और डिस्कवरी सर्विसेज (डीएस)।

भारतीय का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय

शिक्षा मंत्रालय ने देश में शैक्षिक सामग्री तक पहुंच का लोकतंत्रीकरण करने के लिए एकल–विंडो खोज/ब्राउज़ सुविधा के साथ अधिगम संसाधनों के आभासी भंडार की 24×7 सेवा विकसित करने के लिए **'वन लाइब्रेरी – ऑल ऑफ इंडिया'** के विजन के साथ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से राष्ट्रीय

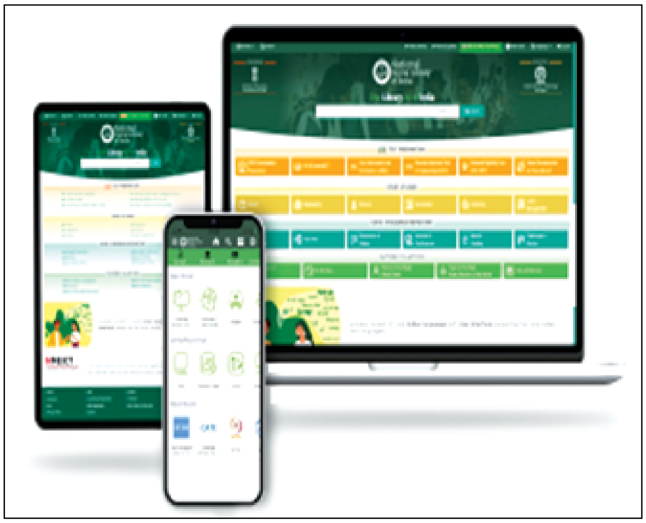

शिक्षा मिशन के तहत भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी (एनडीएलआई) (https://ndl.iitkgp.ac.in या https://www.ndl.gov.in) परियोजना शुरू की। इसे औपचारिक रूप से दिनांक 19.06.2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में शुरु किया गया था।

एनडीएलआई को आईआईटी खड़गपुर द्वारा तैयार किया गया है और यह एक राष्ट्रीय ज्ञान संपत्ति है जिसका उद्देश्य देश की शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी अर्थव्यवस्था के लिए प्रमुख प्रेरक शक्ति का निर्माण करना है। यह परियोजना शिक्षार्थियों के विभिन्न समूहों (केजी से पीजी), शोधकर्ताओं और जीवनपर्यंत शिक्षार्थियों को भूगोल और भाषा की बाधाओं को पार करने वाली पूरी आबादी के लिए एकल–विंडो पहुंच प्रदान करने के लिए शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों/निकायों में मौजूदा डिजिटलीकृत और डिजिटल सामग्री को एकीकृत करती है। एनडीएलआई सामग्री के मेटाडेटा को प्राप्त करता है और इन मेटाडेटा को एनडीएलआई सर्वर में स्टोर और सूचीबद्ध करता है ताकि सभी ई–सामग्री को एक ही विंडो के माध्यम से उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण टेक्स्ट में खोजा और एक्सेस किया जा सके।

एनडीएलआई ने अपनी "स्टडी–एट–होम" और "परीक्षा तैयारी" सेवाओं के माध्यम से महामारी के दौरान देश में अधिगम को जारी रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महामारी की अवधि के दौरान, शिक्षार्थियों ने एनडीएलआई पोर्टल से 12.4 करोड़ से अधिक सामग्री देखी/डाउनलोड की है (इसमें से लगभग 10 बार पेज व्यू)। एनडीएलआई ने दीपक नामक एक दिव्यांगता ज्ञान पोर्टल का शुभारंभ किया है। दीपक वर्तमान में दृष्टिहीनता, बधिरता और स्वलीनता से संबंधित सामग्री होस्ट करता है।

डिजिटल समाधानों की ओर बढ़ती दुनिया में, एनडीएलआई का मिशन महत्वपूर्ण है। 105 मिलियन अदद से अधिक सामग्री के आश्चर्यजनक संग्रह को होस्ट करते हुए, यह शैक्षिक समावेशन की दिशा में भारत की यात्रा में सबसे आगे है। लेकिन डिजिटल पुस्तकालयों के क्षेत्र में, केवल सामग्री एकत्र करना ही पर्याप्त नहीं है; यहाँ भागीदारी, पहुंच और सबसे महत्वपूर्ण बात, शिक्षार्थियों की बदलती जरूरतों के अनुरूप अनुकूलन भी करना होता है। इसे पर एनडीएलआई क्लब पहल क्रियाशील है। इस वर्ष 2021 में शुरू किया गया, यह क्लब इससे एक साल पहले भारत सरकार द्वारा रखी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की एक रणनीतिक प्रतिक्रिया है। शैक्षणिक संस्थानों में विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लबों के लिए एनईपी 2020 की सिफारिश एनडीएलआई के उद्देश्यों के साथ पूरी तरह मेल खाती है। ये क्लब केवल पाठ्येतर संग्रहणों से कहीं अधिक हैं; ये छात्रों की विशिष्ट रुचियों के लिए इनक्यूबेटर हैं, जो बाहुल्य में पूरक संसाधन, परामर्श और सहायता प्रदान करते हैं।

एनडीएलआई क्लब, जो इस पहल की डिजिटल विंग है, एक पारंपरिक क्लब के विचार को एक गतिशील, परस्पर संवादात्मक अनुभव में बदल देती है। इस मंच के माध्यम से, संस्थान एनडीएलआई रिपोजिटरी के विशाल संसाधनों का लाभ उठाते हुए, आसानी से अपने स्वयं के गतिविधि–आधारित क्लब बना सकते हैं। यह दृष्टिकोण न केवल क्लबों के प्रबंधन की व्यवस्था को सरल बनाता है, बल्कि भौगोलिक बाधाओं को भी दूर करता है, जिससे विचारों और संसाधनों का निर्बाध आदान–प्रदान संभव होता है।

एनडीएलआई देश भर के शैक्षणिक संस्थानों में **एनडीएलआई क्लब** स्थापित करके स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच सहयोगात्मक गतिविधि–आधारित शिक्षा में सबसे आगे बढ़ रहा है। अब तक 5200 से अधिक क्लब स्थापित किए जा चुके हैं जिनमें **14.5 लाख** से अधिक छात्र और शिक्षक क्लब के सदस्य हैं और इन क्लबों ने एनडीएलआई के संसाधनों का उपयोग करके **20 हजार से अधिक** शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए हैं। यह केवल आंकड़ों के बारे में नहीं है; यह एक ऐसी संस्कृति विकसित करने के बारे में है जहां एनडीएलआई, छात्रों और शिक्षकों के

लिए समान रूप से हर दिन सीखने की यात्रा का हिस्सा बन जाता है।

एनडीएलआई एनईपी–2020 के अनेक अधिदेशों के कार्यान्वयन के लिए प्रमुख सहायता प्रदान करता है। एनडीएलआई ने भारतीय पुस्तकालयों के लिए एक कॉपीराइट गाइड प्रकाशित की है, जिसे 12 अगस्त, 2021 को दिल्ली उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक रूप से लॉन्च किया गया था। एनडीएलआई ने अधिगम की सुविधा के लिए विशेषज्ञों के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों के लिए अनेक अत्यंत रुचिकर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किए हैं।

एनडीएलआई एक वेबसाइट (https://ndl.iitkgp.ac.in या https://www.ndl.gov.in) के साथ–साथ एक मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस) के रूप में उपलब्ध है और इसे उमंग (नए युग अभिशासन के लिए यूनिफाइड मोबाइल एप्लिकेशन) के साथ एकीकृत किया गया है। परियोजना के संबंध में भारत के नागरिकों को प्रत्येक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एनडीएलआई ने अधिक व्यवस्थित और उपयोग में आसान इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए अपनी परियोजना वेबसाइट **http://project.ndl.gov.in** को नए सिरे से तैयार किया है और इसका शुभारंभ किया है।

एनडीएलआई एक ऐसा मंच है जो सतत शिक्षा और ज्ञान–साझाकरण नेटवर्क सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। इसने हाल ही में एक नई सेवा शुरू की है जो इसे अपनी मौजूदा सामग्री का उपयोग करके विशिष्ट रूप से निर्मित डिजिटल पुस्तकालय बनाने की अनुमति देती है। इस सेवा का उपयोग विभिन्न राज्य सरकारों और विभागों द्वारा पहले ही किया जा चुका है। उदाहरण के लिए, तेलंगाना राजभवन, जम्मू–कश्मीर सरकार और बिहार सरकार के बीएसडीएमए को एनडीएलआई से विशेष रूप से तैयार किया गया डिजिटल पुस्तकालय प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एनडीएलआई अक्सर विशेष रूप से तैयार क्षेत्रीय संग्रह प्रदान करके विशेष अभियान भी शुरू करता है।

विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं के आधार पर कुछ विशिष्ट निर्मित 'डिजिटल पुस्तकालय'

- **जम्मू–कश्मीर सरकारः** https://ndl.iitkgp.ac.in/campaign/2023_jammu_kashmir@
- **तेलंगाना राजभवनः** https://ndl.iitkgpac-in/campaign/2023_telangana_raj_bhavan/
- **पूर्वोत्तर भारतः** https://ndl.iitkgp.ac.in/campaign/2022_northeast_en/
- **बीएसडीएमए, बिहारः** https://ndl.iitkgp.ac.in/campaign/2023_bsdma/
- तमिलनाडु के लिए चर्चा चल रही है।

भारत का राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय, जिसे एनडीएलआई के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा मंच है जो स्कूल छात्रों, स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान शिक्षार्थियों और आजीवन शिक्षार्थियों को सेवा प्रदान करता है। **इसमें सभी भारतीय भाषाओं के साथ–साथ 400 से अधिक विदेशी भाषाओं की सामग्री का विशाल संग्रह शामिल है।** ये सामग्री ई–पुस्तकें, ऑडियोबुक, व्याख्यान सामग्री, वीडियो व्याख्यान, पाठ्यक्रम, थीसिस, रिपोर्ट, लेख, जर्नल पेपर, प्रश्न पत्र, समाधान बैंक, डेटा सेट और सिमुलेशन टूल जैसे विभिन्न रूपों में उपलब्ध हैं। इस पुस्तकालय में विज्ञान, इतिहास और भूगोल, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, साहित्य, ललित और सज्जा कला, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, कानून और चिकित्सा सहित सभी विषय क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अब तक, **एनडीएलआई यूजर इंटरफेस 11 भाषाओं** (अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, गुजराती, उड़िया, मराठी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और असमिया) **में उपलब्ध है।**

400+ भाषाओं में 630+ स्रोतों से **10.5 करोड़ से अधिक सामग्री** एकत्र की गई।

1. **सामग्री की मात्रा**
   i. कुल सामग्री की संख्याः **दिसंबर 2023 तक 10.5 करोड़**
   ii. सुगम्य पूर्ण–पाठः
      - कुलः 8.84 करोड़
      - राष्ट्रीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त सामग्रीः 6.64 लाख
2. **सामग्री 637 स्रोतों से ली गई है**
3. **सामग्री का स्वरूप**
   i. पुस्तकेंः 79.8 लाख
   ii. लेख : 4.76 करोड़
   iii. जर्नल और कार्यवाहीः 5.5 लाख
   iv. थीसिसः 9.1 लाख
   v. प्रश्न, प्रश्न पत्र/सेट, क्विज़, अभ्यास और समाधानः 5.88 लाख
   vi. वीडियो लेक्चरः 5.38 लाख
   vii. वेब कोर्सः 1.8 हजार
   viii. सिमुलेशनः 8.2 हजार
   ix. प्रस्तुतिः 2.19 लाख
   x. अन्यः 4.20 करोड़
4. **सामग्री विषय**
   i. कंप्यूटर विज्ञान, सूचना और सामान्य कार्यः 1.74 करोड़
   ii. इतिहास और भूगोलः 13.04 लाख
   iii. भाषाः 2.17 लाख
   iv. साहित्य और भाषणः 10.4 लाख
   v. प्राकृतिक विज्ञान और गणितः 1.11 करोड़
   vi. दर्शन एवं मनोविज्ञानः 6.79 लाख
   vii. धर्मः 2.66 लाख
   viii. सामाजिक विज्ञाः 68.26 लाख
   ix. प्रौद्योगिकीः 1.48 करोड़
   x. ललित एवं साज–सज्जा कलाः 20.86 लाख
5. **सामग्री भाषा**
   i. सामग्री 427 भाषाओं में उपलब्ध है
   ii. अंग्रेजीः 8.48 करोड़
   iii. हिंदीः 2.37 लाख
   iv. बंगालीः 2.16 लाख
   v. तेलुगूः 46 हजार
   vi. तमिलः 39 हजार
   vii. मराठीः 28 हजार
   viii. गुजरातीः 60 हजार
   ix. कन्नड़ः 18 हजार
   x. मलयालमः 8.4 हजार
   xi. असमियाः 7.8 हजार
   xii. उड़ियाः 6.3 हजार
   xiii. पंजाबीः 3.2 हजार
   xiv. संस्कृतः 60 हजार
   xv. उर्दूः 58 हजार
6. **सामग्री का रूपः** पाठ, वीडियो, छवि, ऑडियो, प्रस्तुति, सिमुलेशन, एनीमेशन, अनुप्रयोग

दो प्रकाशकों वर्ल्ड ई–बुक लाइब्रेरी (77 लाख+ आइटम) (ई–बुक्स, वीडियो, ऑडियो) और साउथ एशिया आर्काइव (30 हजार+ आइटम) (जर्नल्स, लेख) की सामग्री राष्ट्रीय लाइसेंस के अंतर्गत थी और एनडीएलआई में उपलब्ध कराई गई थी। साउथ एशिया आर्काइव का लाइसेंस सर्वकालिक है। वर्ल्ड ई–बुक लाइब्रेरी का लाइसेंस नवीनीकृत नहीं किया गया है और इसलिए वर्ल्ड ई–बुक लाइब्रेरी से केवल 6.24 लाख ई–पुस्तकें स्थायी लाइसेंस के तहत एनडीएलआई उपयोगकर्ताओं के लिए सुगम (पूर्ण–पाठ) हैं।

कुल सामग्री में से 82% सामग्री को निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। बाकी प्रतिबंधित हैं या सदस्यता लेनी होती है।

बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के लिए पंजीकरण/लॉगिन वैकल्पिक है तथापि यह करना अच्छा होगा। अधिकांश पूर्ण–पाठ सामग्री को पंजीकरण/लॉगिन के बिना देखा/डाउनलोड किया जा सकता है।

- कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता: 84.8 लाख
- सक्रिय पंजीकृत उपयोगकर्ता: 44.4 लाख
- औसत दैनिक हिट: लगभग 3800,000
- भाग लेने वाले (पंजीकृत उपयोगकर्ता) संस्थान: 37,000 संस्थान
- एनडीएलआई के पास तीव्र अनूठी खोज सुविधा है, जहां उपयोगकर्ता प्रासंगिक संसाधनों की उपलब्धता के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करते हैं।
- एनडीएलआई ने अब तक लगभग 2500 पुस्तकालयाध्यक्षों को कार्यशालाओं के माध्यम से आईडीआर स्थापित करने के लिए लगभग 1075 संस्थानों को कवर करते हुए प्रशिक्षित किया है। एनडीएलआई ने 160 आईडीआर की स्थापना में सहायता की है और उन आईडीआर को एकीकृत किया है।
- एनडीएलआई एक ऐसा पुस्तकालय है जिसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को खुद को सशक्त बनाने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करके भारत में शिक्षा और अनुसंधान में आमूल–चूल बदलाव लाना है। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, पत्रिकाओं और 300 से अधिक अन्य प्रासंगिक रिपॉजिटरी से सामग्री तक ले जाने वाले लिंक का एक संग्रह होने के कारण, एनडीएलआई भारत के लिए एक एकल ज्ञान पोर्टल बनकर रहेगा।
- हर महीने 50 लाख से अधिक सामग्री देखी/डाउनलोड की जाती है (लगभग 5 करोड़ पेज व्यू के बराबर)।
- एनडीएलआई का मेटाडेटा समृद्ध है और इस प्रकार एनडीएलआई उपयोगकर्ता–उन्मुख सेवाएं प्रदान करने में सक्षम है जैसे संबंधित सामग्री का आसान नेविगेशन (सामग्री संग्रहण)
- एनडीएलआई ने क्यूरेटर की उत्पादकता में काफी सुधार के साथ बड़ी मात्रा में मेटाडेटा को क्यूरेट करने के लिए एक वर्कफ़्लो और एक स्वचालित डेटा क्यूरेशन टूल विकसित किया है। टूल ने हाल ही में **वर्ष 2022 एमराल्ड साउथ एशिया एलआईएस रिसर्च फंड अवार्ड के लिए प्रथम स्थान** प्राप्त किया है। प्रौद्योगिकी पहले से ही अच्छी तरह से निर्मित है और इसका आसानी से पुनः उपयोग किया जा सकता है।
- आईआईटी–जेईई, एनईईटी, केवीपीवाई जैसी राष्ट्रीय स्तर की कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं और सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, आईबीपीएस आदि जैसी नौकरी भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न और समाधान।
- एनडीएलआई के पास शैक्षिक सामग्री के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसमें सत्यजीत रे संग्रह, दक्षिण एशिया अभिलेखागार आदि जैसे विशेष आइटम हैं, जो सामाजिक विज्ञान से लेकर प्राचीन इतिहास तक के क्षेत्रों में सभी प्रकार के शोधकर्ताओं के लिए हैं। भारत के लिए एक एकल डिजिटल पुस्तकालय केवल डिग्री–उन्मुख लोगों के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के लिए है।
- एनडीएलआई क्लब स्कूलों और कॉलेजों में स्थापित किए जा रहे हैं जो एनडीएलआई के सामग्री आधार का उपयोग करते हुए व्याख्यान श्रृंखला, प्रश्नोत्तरी सत्र आयोजित करना, लेखन प्रतियोगिताएं, ओलंपियाड जैसी गतिविधियों का संचालन करते हैं। गतिविधियाँ/ कार्यक्रम वास्तविक या ऑनलाइन हो सकते हैं और ऑनलाइन कार्यक्रम एक क्लब, कई क्लबों या सभी क्लबों के लिए एक साथ हो सकते हैं।

एनडीएलआई ने क्लबों और क्लब सदस्यों को पंजीकृत करने और ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित करने के लिए एक पोर्टल (https://club.ndl.iitkgp.ac.in/) स्थापित किया है। एनडीएलआई नियमित रूप से जेईई और एनईईटी में सफलता की रणनीतियां, योग्यता–आधारित प्रश्न बनाना, लेखकों के साथ चर्चा, कॉपीराइट को समझना, सभी क्लबों को शामिल करते हुए अत्यधिक रूचिकर कार्यक्रमों का आयोजन करता है।

2023 में आयोजित प्रमुख कार्यक्रम

ओएसएसएलएम 2023 (पुस्तकालय प्रबंधन के लिए ओपन–सोर्स सॉफ्टवेयर पर अल्पकालिक पाठ्यक्रम) 24–29 जुलाई 2023 के दौरान https://library.iitkgp.ac.in/assets/pdf/osslm2023.pdf

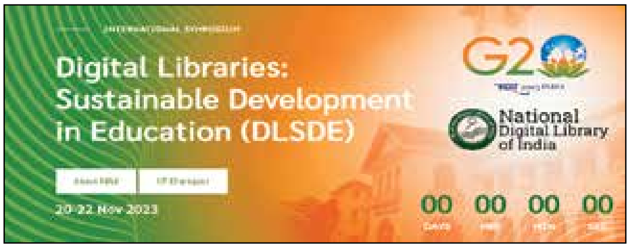

डिजिटल पुस्तकालयों पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी: शिक्षा में सतत विकास (डीएलएसडीई–2023): 20–22 नवंबर 2023 के दौरान http://iconf.ndl.gov.in/

आगामी विशेषताएं

एनडीएलआई अपना नवीनतम संस्करण एनडीएलआई 3.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। संगठन ने हाल ही में नए अत्याधुनिक सर्वर प्राप्त किए हैं, जिसे इसके नए संस्करण में उपयोग की जाने वाली नवीनतम उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग के लिए स्थापित किया जा रहा है। अपने नए अवतार के साथ एनडीएलआई 3.0 बहुत तेजए अधिक संवादात्मक और उपयोगकर्ता अनुकूल होगा। आगामी पोर्टल की प्रमुख विशेषताओं में सीएमएस का कार्यान्वयनए 10 भारतीय भाषाओं में खोज सुविधाएं और खोज अनुशंसाएं शामिल हैं।

स्वयं प्रभा– डीटीएच शैक्षिक चैनल:

शिक्षा मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित परियोजना स्वयं प्रभा का उद्घाटन 07 जुलाई 2017 को भारत के माननीय पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। यह 40 डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो जीसैट–15 उपग्रह का उपयोग करके 24×7 आधार पर उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समर्पित है और डीडी फ्री डिश/डिश टीवी पर उपलब्ध है।

इस प्रकार के कार्यक्रम को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करना है, विशेष रूप से उन छात्रों को जो नियमित रूप से अपने पाठ्यक्रमों में उपस्थित नहीं हो सकते हैं और दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं जहां संस्थानों और कॉलेजों तक पहुंच सुगम नहीं है। कार्यक्रम का उद्देश्य उन छात्रों तक पहुंचना भी है जिनके पास सीमित या कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। उपलब्ध सूचना के अनुसार 2022 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच अधिकतम 50% है। इसके अलावा, कई क्षेत्रों में हाई–स्पीड इंटरनेट की पहुंच नहीं हो सकती है, जो इंटरनेट–आधारित शैक्षिक सामग्री तक पहुंच के लिए आवश्यक होती है।

कई अग्रणी संस्थान (इग्नू, सीईसी, आईआईटी, आईआईएससी, यूओएच और कुछ अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय) संबंधित क्षेत्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों

(एसएमई) द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री बनाने के लिए समन्वय करते हैं। सूचना/पुस्तकालय भागीदार और प्रसारण एजेंसी के रूप में क्रमशः इनफ्लिबनेट और बीआईएसएजी के महत्वपूर्ण सहयोग के साथ, डीटीएच एसपी देश और बड़े पैमाने पर शिक्षार्थी समुदाय की भविष्य की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए सबसे बड़ी शैक्षिक परियोजनाओं में से एक है।

एसपी चैनल (उच्च शिक्षा):

एसपी को शुरुआत में 32 डीटीएच चैनलों के समूह के साथ लॉन्च किया गया था। अक्टूबर 2020 में, मौजूदा 32 चैनलों में से 12 स्वयं प्रभा चैनल स्कूल शिक्षा के लिए और शेष उच्चतर शिक्षा के लिए आवंटित करने का निर्णय लिया गया। दो अतिरिक्त चैनलों, इग्नू ज्ञान दर्शन और सीईसी व्यास के साथ, उच्चतर शिक्षा के लिए समर्पित कुल 22 चैनल तैयार किए गए। इनमें से 11 चैनल सीईसी (कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन) द्वारा प्रबंधित किए गए थे, 6 चैनल आईआईटी और आईआईएससी के सहयोग से एनपीटीईएल द्वारा, आईआईटी दिल्ली द्वारा विशेष रूप से 11वीं और 12वीं कक्षा के स्कूल छात्रों के लिए सीबीएसई पाठ्यक्रम–आधारित पाठ्यचर्या का 1 चैनल, जिसे आईआईटी पीएएल (प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग) कहा जाता है और इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय) द्वारा 4 चैनल प्रबंधित किए जाते हैं।

इसके बाद, 12 जून 2023 को, स्वयं प्रभा ने अपने दूसरे चरण **(स्वयं प्रभा 2.0)** में, 40 डीटीएच चैनलों तक विस्तार किया ताकि अध्ययन के व्यापक क्षेत्रों को समायोजित किया जा सके और इसे एक–चैनल–एक–विषय की अवधारणा के करीब ले जाया जा सके। इस विस्तार के साथ, अध्ययन के नए क्षेत्रों जैसे प्रदर्शन कला, स्वास्थ्य देखभाल, कौशल, डिजाइन, शिक्षक प्रशिक्षण और कुछ इंजीनियरिंग विषयों के लिए समर्पित नए चैनल शुरू किए गए। नए राष्ट्रीय समन्वय संस्थानों की भी पहचान की गई और उन्हें ऑन–बोर्ड किया गया। चैनलों और राष्ट्रीय समन्वयकों की वर्तमान व्यवस्था नीचे तालिका में दी गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह कोई कठोर व्यवस्था नहीं है और संसाधनों की उपलब्धता तथा एनसी संस्थानों को समय–समय पर आने वाली अन्य परिचालन बाधाओं के आधार पर इसे बदला जा सकता है।

सेक्टरों के साथ स्वयं प्रभा चैनल

क्र. सं.	राष्ट्रीय समन्वयक /संस्थान	चैनलों की संख्या	क्षेत्र
1	शैक्षिक संचार संकाय (सीईसी)	11	गैर–प्रौद्योगिकी यूजी/पीजी डिग्री कार्यक्रम
2	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	6	डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम
3	आईआईटी बॉम्बे	4	मूलभूत विज्ञान (भौतिकी और जीव विज्ञान) और इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी
4	आईआईटी दिल्ली	2	इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, कक्षा XI और XII (जेईई उम्मीदवारों के लिए सहायता)
5	आईआईटी गांधीनगर	1	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (सिविल)
6	आईआईटी कानपुर	5	डिज़ाइन, दृश्य संचार, मानविकी और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी
7	आईआईटी खड़गपुर	2	इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी (सीएस एएवं वास्तुकला)
8	आईआईटी मद्रास	6	इंस्ट्रुमेंटेशन और बायोमेडिकल, स्वास्थ्य विज्ञान, कौशल, ब्रिज पाठ्यक्रम और इंपेक्ट सीरीज और इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी
9	आईआईटी तिरूपति	2	मूलभूत विज्ञान (रसायन विविज्ञान और गणित)
10	हैदराबाद विश्वविद्यालय	1	प्रदर्शन कला

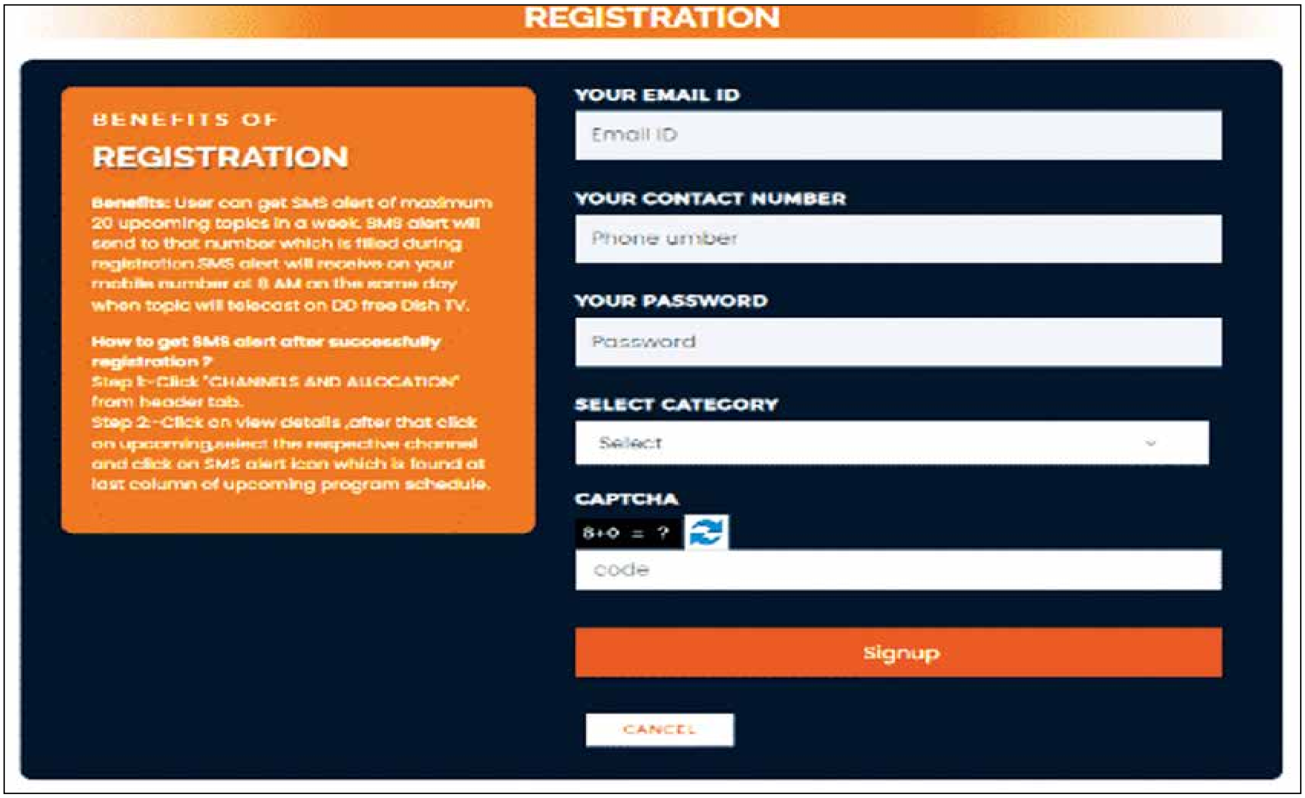

पंजीकरण विंडो का स्क्रीनशॉट

अभिगम्यता

पंजीकरण

इन चौनलों तक पहुंचने के लिए, स्वयं–प्रभा के तहत एक ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा भी उपलब्ध है। इसके लिए, संबंधित छात्रों को कुछ विवरण भरने होंगे। पंजीकरण के बाद, पंजीकृत छात्रों के मोबाइल नंबर/ई–मेल पर सेवाएं प्रदान की जाती हैं। छात्रों को अधिकतम 20 आगामी विषयों का एसएमएस अलर्ट मिल सकता है और अलर्ट उसी दिन सुबह 8 बजे प्राप्त होगा जब विषय डीडी फ्री डिश टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। एसएमएस अलर्ट के माध्यम से छात्र चौनलों में भाग लेने के लिए अपने अनुसार कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं। स्वयं प्रभा पोर्टल पर कुल पंजीकृत उपयोगकर्ता **2,72,432** हैं (31 दिसंबर, 2023 के अनुसार)। अधिक विवरण https://www.swayamprabha.gov.in/ पर उपलब्ध है।

खोज सुविधाः किसी भी कार्यक्रम के सफलता सूचकांक को मापने के लिए उपलब्धता, पहुंच और जवाबदेही तीन बुनियादी और मौलिक पैरामीटर हैं। उपलब्धता कार्यक्रम के अंतर्गत सामग्री की मात्रा दर्शाती है। दूसरे, पहुंच एक प्रमुख पैरामीटर है जो उपयोगकर्ताओं को समय बर्बाद किए बिना उपलब्ध सामग्री तक पहुंचने की स्वतंत्रता देता है। कई एजेंसियां इसे अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय बनाने के लिए इसी अवधारणा को अपना रही हैं क्योंकि उपयोगकर्ता (उपयोगकर्ताओं) के पास समय बहुत सीमित है। अंत में, जवाबदेही सामग्री की मौलिकता की ओर ले जाती है जो प्रस्तावित शैक्षणिक सामग्री के प्रति उपयोगकर्ताओं का विश्वास बनाती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए स्वयं–प्रभा कार्यक्रम को भी उसी पैटर्न पर अपनाया जा रहा है। कई अलग–अलग टूल्स प्रदान किए गए हैं; जिससे उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं और उपयुक्त समय अनुसार चैनल और सामग्री खोज सकते हैं।

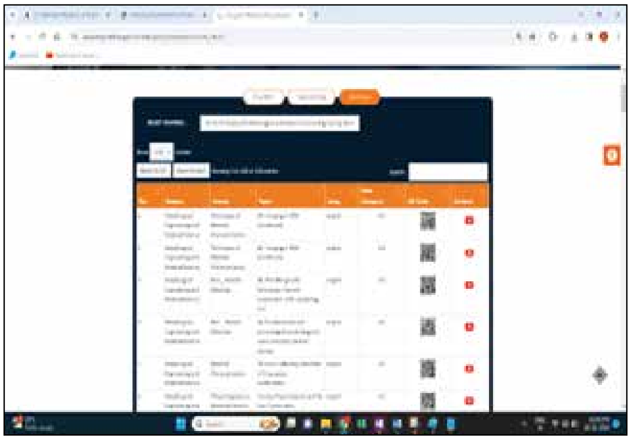

आकर्शिव वीडियो की नमूना सूची का स्क्रीनशॉट

आर्काइव वीडियो: आर्काइव वीडियो के रूप में एक अतिरिक्त सुविधा जिसमें प्रसारण वीडियो उन शिक्षार्थियों के लाभ के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं जो लाइव सत्र में शामिल नहीं हो सके। इस सुविधा से गैर–प्रसारित सामग्री (कार्यक्रम निर्धारण संबंधी बाधाओं के कारण) तक भी पहुँचा जा सकता है। इसके अलावा, आर्काइव वीडियो सुविधा उन क्षेत्रों में स्थित शिक्षार्थियों के लिए लाभप्रद है जहां नियमित आधार पर बुनियादी आईटी अवसंरचना और बिजली आपूर्ति की कमी है। इन वीडियो की जानकारी को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात वर्तमान, आगामी और सभी चैनलों का संग्रह।

स्वयम प्रभा पाठ्‌यक्रमों की रिपोजिटरी स्वयं प्रभा वेबसाइट और यूट्यूब पर उपलब्ध है। यह एसपी को मुक्त शैक्षिक सामग्री के लिए एक एकीकृत संसाधन बनाता है। जहां ग्रामीण और सीमित–इंटरनेट वाले क्षेत्रों में शिक्षार्थी डीटीएच सुविधा से लाभान्वित होते हैं, अर्ध–शहरी और शहरी क्षेत्रों में शिक्षार्थी अपनी सुविधा के अनुसार दोनों सेवाओं से लाभ उठा सकते हैं। यूट्यूब सेवाओं से संबंधित डाटा इनफलिबनेट द्वारा बनाए रखा जाता है। कुल **64,946,678** व्यूज और **1,201,385** सदस्यता दर्ज की गई। इनका वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष 2017 – 2020 के लिए यूट्यूब व्यूज /सदस्यता: 32 एसपी चैनल

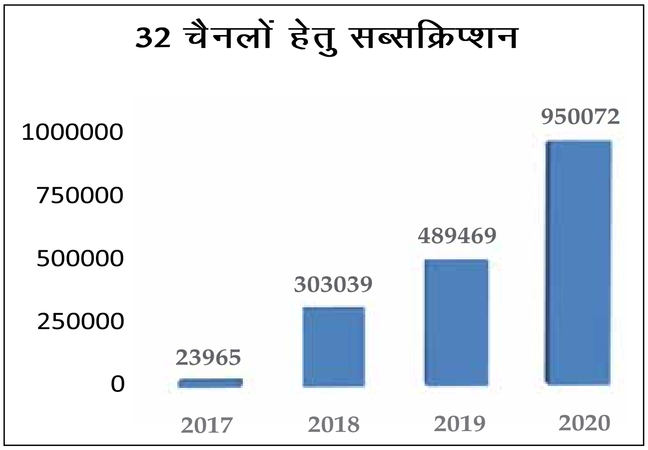

गौरतलब है कि 32 चैनलों के लिए व्यूज केवल 2020 तक ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं क्योंकि यह व्यवस्था केवल उस समय तक ही वैध थी। इसके बाद, उच्च शैक्षिक सामग्री को 22 चैनलों तक सीमित कर दिया गया, जिसके आंकड़े नीचे दिखाए गए हैं।

वर्ष 2021 – 2023 से सितंबर 2023 तक 22 एसपी चैनलों के लिए यूट्यूब व्यूज /सदस्यता

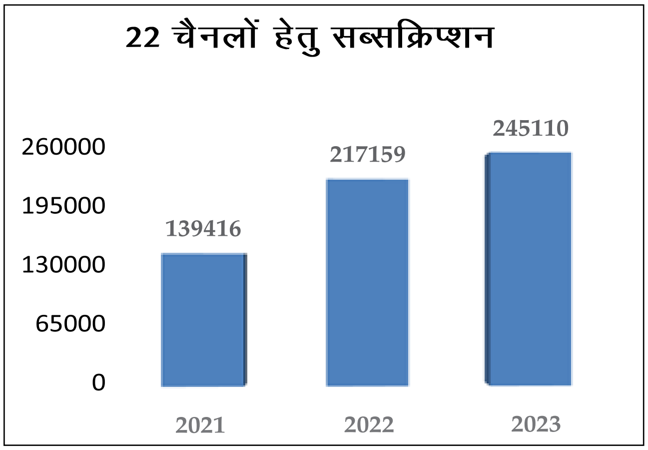

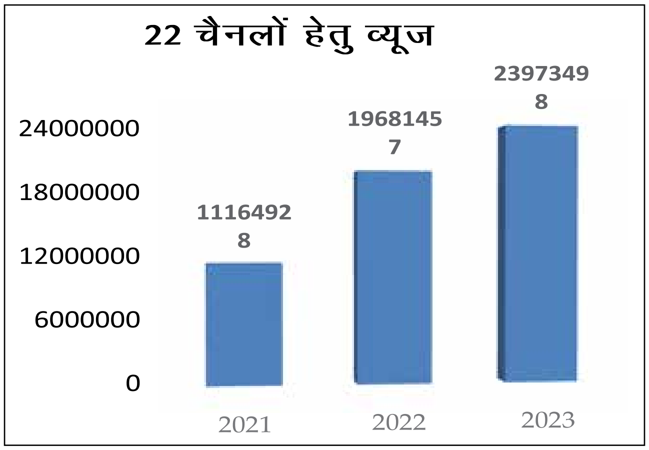

सितंबर 2023 में एसपी चैनलों की संख्या 22 से बढ़ाकर 40 कर दी गई। आंकड़े अलग–अलग वर्षों के लिए दिखाए जा रहे हैं और संचयी नहीं हैं। वर्ष 2023 की चौथी तिमाही के दौरान 40 चैनलों के कुल व्यूज इस प्रकार हैं।

वर्ष 2023 के लिए यूट्यूब/सदस्यता (अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर): 40 एसपी चैनल

वर्ष	व्यूज	सदस्यता
2023 (क्यू 4)	985918	6203

डीटीएच व्यूज़ के आँकड़े फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी प्रौद्योगिकी को अभी तक डीडी फ्री डिश द्वारा एम्बेड नहीं किया गया है। तथापि, प्रसार भारती के रिकॉर्ड के अनुसार, वर्ष 2023 तक, डीडी फ्री डिश के कम से कम 4.5 करोड़ घरेलू दर्शक हैं। इससे स्वयं प्रभा की आउटरीच का एक अनुमान लगाया जा सकता है। अधिक यथार्थवादी जानकारी प्राप्त करने के लिए और इंटरैक्टिविटी (एक सुविधा जिसकी संचार के डीटीएच मोड में अत्यधिक कमी है) प्रदान करने के लिए, एसपी ने हाल ही में दो सेवाएं शुरू की हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है।

अन्तरक्रियाशीलता

स्वयम प्रभा ने संचार के स्वाभाविक रूप से गैर–इंटरैक्टिव डीटीएच माध्यम को जीवंत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में दो इंटरैक्टिव सेवाएं शुरू की हैं। ये हैं (I) एसएमएस–आधारित चौनल और शेड्यूल रिटरीवल सेवा और (II) व्हाट्सएप/क्यूआर कोड–आधारित प्रतिक्रिया और क्वेरी सेवा।

एसएमएस कार्यक्षमता का उद्देश्य विभिन्न विषयों के शेड्यूल के बारे में कुशलतापूर्वक सूचना संप्रेषित करना है। एसएमएस सुविधा स्वयम प्रभा पोर्टल पर संचालित एआई–इंजन से संचालित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि यह सूचना व्यवस्थित तरीके से छात्रों के साथ संरचित और साझा की जाती है।

व्हाट्सएप और क्यूआर कोड सेवा शिक्षार्थी और विषय वस्तु विशेषज्ञ (एसएमई) के बीच सहभागिता को सक्षम बनाती है, और शेड्यूल की जानकारी भी प्रदान करती है।

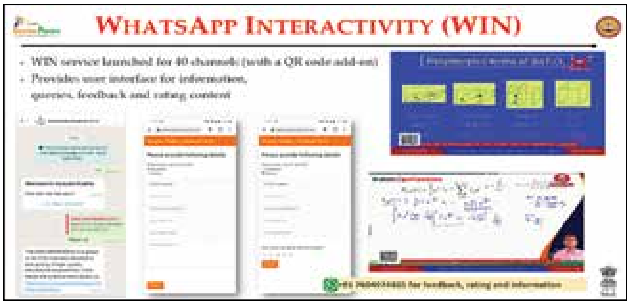

एसपी प्रचार गतिविधियाँ

प्रचार गतिविधियों के भाग के रूप में, एसपी ईमेल के माध्यम से डिजिटल मार्केटिंग का कार्य करता है, पूरे भारत में अभियान चला रहा है और कॉलेजों तक पहुंच रहा है ताकि विभिन्न विषयों में अध्ययन करने वाले शिक्षार्थियों तक पहुंच बनाई जा सके। कार्यक्रम की कार्यनीति यह है कि जब भी किसी नए पाठ्यक्रम को स्वयं प्रभा चौनलों के तहत प्रसारित करने की योजना बनाई जाए तो बड़ी संख्या में ईमेल भेजे जाएँ। इसके अलावा, जानकारी को मेटा, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।

डीआईडीएसी 2023: बीआईईसी, बेंगलुरु में स्वयं प्रभा बूथ स्थापित किया गया था:

स्वयं प्रभा चैनलों को बढ़ावा देने और परियोजना के परिप्रेक्ष्य को उन प्रतिभागियों के साथ साझा करना जो मुख्य रूप से शैक्षिक पृष्ठभूमि से हैं। लोगों को यह जानने में मदद करने के लिए कि सीखने और सिखाने के मामले में स्वयं प्रभा कितना प्रभावशील है और उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम व्याख्यान वीडियो को प्रसारित करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी का कितना अच्छा उपयोग किया जाता है जो शिक्षा और शिक्षण को जनता तक फैलाता है। स्वयं प्रभा के प्रचार के भाग के रूप में एक विशेष बूथ स्थापित किया गया था जहां एसपी कर्मचारियों ने आगंतुकों को डीटीएच परियोजना के बारे में बताया और एसपी से संबंधित पुस्तिकाएं वितरित कीं। साथ ही, डीटीएच चैनल 15 के माध्यम से शिक्षण सत्र के लाइव प्रसारण का डेमो भी दिया गया। कार्यक्रम के दौरान 15000 से अधिक आगंतुकों बूथ आए।

इग्नू एसएम टीम ने ट्विटर और फेसबुक पर भी एक अकाउंट बनाया। यह टीम अकाउंट का प्रबंधन कर रही है और नियमित रूप से सूचना अद्यतन कर रही है। अद्यतन सूचना को व्हाट्सएप ग्रुप में भी साझा किया जाता है।

11 फरवरी, 2023 को चिक्कन्ना गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, तिरुपुर में विशाल नौकरी मेला :

स्वयं प्रभा के प्रचार के भाग के रूप में एक बूथ स्थापित किया गया था, जहां एसपी कर्मचारियों ने आगंतुकों को परियोजना के बारे में बताया और एसपी पुस्तिकाएं वितरित कीं। इस एक दिवसीय नौकरी मेले में 100,000 से अधिक छात्रों + नौकरी ढूंढने वालों ने भाग लिया।

सामग्री निर्माण और प्रसारण

सामग्री निर्माण इंटरफेस

सामग्री निर्माण इंटरफ़ेस डीटीएच एसपी परियोजना के सभी प्रमुख प्रतिभागियों, अर्थात् मुख्य समन्वयक, एनसी, सीसी, एसएमई और समीक्षकों के लिए एक केंद्रीय वेब–आधारित इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करता है। यह सामग्री निर्माण के लिए संशोधित प्रक्रियाओं पर स्थापित किया गया है जिसमें दो विशेषज्ञों द्वारा पाठ्य प्रस्ताव और नमूना वीडियो दोनों की समीक्षा शामिल है। भूमिकाएँ पूर्व–निर्धारित हैं और इंटरफ़ेस को तदनुसार विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। मुख्य समन्वयक, एनसी और सीसी को त्वरित, लेकिन महत्वपूर्ण अवलोकन प्राप्त करने और विभिन्न प्रस्तावों की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक डैशबोर्ड प्रदान किया जाता है। एसएमई इस पोर्टल का उपयोग न केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बल्कि समीक्षा देखने के लिए भी करते हैं। इसके अलावा, डाटाबेस को फीड करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी इस पोर्टल से प्राप्त की जाती है। इसलिए, सभी सामग्री निर्माण प्रस्तावों (रिकॉर्ड किए गए और लाइव) को पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत, पुनरीक्षित और संसाधित किया जाना अनिवार्य है। स्वीकृत प्रस्ताव को एक सिस्टम–जनरेटेड कोड सौंपा गया है, जिसे एनसी द्वारा जारी चालान में उद्धृत किया जाएगा।

मुख्य समन्वयक का आईटी प्रकोष्ठ इस पोर्टल की विभिन्न विशेषताओं के माध्यम से सेटअप को समझने

और नेविगेट करने के लिए एनसी और चैनल समन्वयक को अपेक्षानुसार आवश्यक मैनुअल और प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

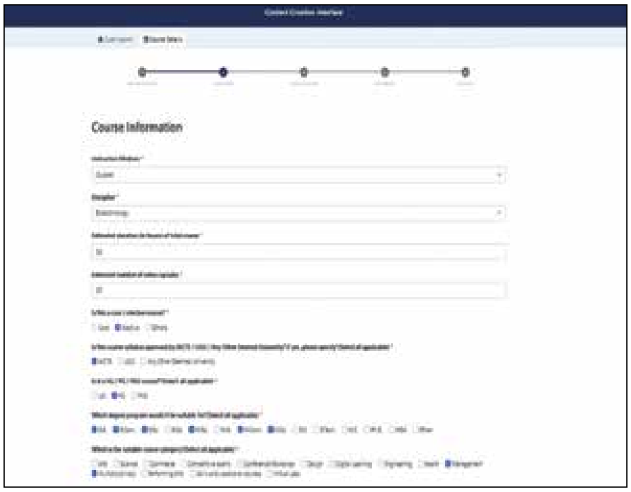

अनुवाद

स्वयं प्रभा पाठ्यक्रमों के लिए उपशीर्षक शुरू किया गया था और 429 घंटों के लगभग 30 पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी में लिखा जा रहा है। प्रथम वर्ष के यूजी/पीजी को कवर करने वाले पाठ्यक्रमों का चयन किया गया था और कार्य पूरा हो चुका है। पाठ्यक्रम भाषा, सामान्य विज्ञान, दर्शनशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, इतिहास, प्रबंधन, रसायन विज्ञान, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मानविकी की श्रेणी में आते हैं। लगभग **890+** वीडियो के आईआईटी पाल पाठ्यक्रमों को अंग्रेजी में प्रतिलेखित किया गया है। विचार यह था कि पहले पाठ्यक्रम अंग्रेजी में हों और फिर अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विस्तारित हों। शिक्षा मंत्रालय आठ प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं – बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल और तेलुगु में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए संदर्भ सामग्री का अनुवाद करने की दिशा में कार्य कर रहा है।

लाइव सत्र

इग्नू, नई दिल्ली द्वारा स्वयं प्रभा चैनल 11 – 14 और 16 में नियमित लाइव सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, पूर्व के 4 चैनलों (अध्याय 23–25 एवं अध्याय –32) के स्थान पर दिनांक 01 जुलाई 2023 को इग्नू को पुनः आवंटित स्वयं प्रभा चैनल (6) (अध्याय–11 से 16) का पुनर्गठन किया गया था। ये 6 चैनल इग्नू के 21 स्कूलों को सेवा प्रदान करते हैं, और चैनल जीसैट–15 उपग्रह का उपयोग करके 24×7 आधार पर रिकॉर्ड किए गए वीडियो के साथ–साथ इग्नू कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण भी कर रहे हैं। सभी 6 इग्नू एसपी चैनलों पर प्रसारित होने वाले 10–डिग्री कार्यक्रमों के लिए नामांकन की संख्या 591520 है। वर्ष 2023–2024 की पहली तिमाही से तीसरी तिमाही में आयोजित कुल लाइव सत्र 2,453 घंटे हैं, चौथी तिमाही के लिए अतिरिक्त 800 घंटे की योजना बनाई गई है। प्रत्येक सत्र 1 घंटे का है। किए गए सभी लाइव सत्रों को संपादित किया जाएगा और लाइव प्रसारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी कुछ समस्याओं को छोड़कर नियमित रिकॉर्डिंग में परिवर्तित किया जाएगा। वर्तमान में, विश्वविद्यालय 14 भाषाओं में लाइव सत्र आयोजित कर रहा है (मणिपुरी 27 नवंबर, 2023 से शुरू हुआ) प्रत्येक भाषा में 1 घंटे का सत्र, 5 चैनलों पर प्रति दिन कुल 14 घंटे और इसे इग्नू को उपलब्ध कराए गए 6 चैनलों पर प्रतिदिन 30 घंटे के कुल मिलाकर 15 (मिज़ोरम को जोड़ा जाएगा) भाषाओं में प्रत्येक भाषा में 2 घंटे के सत्र के साथ विस्तारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीईसी, नई दिल्ली द्वारा प्रबंधित एसपी चैनल 40, व्यास को प्रत्येक दिन 4 घंटे यूजीसी कार्यक्रम प्रसारित करता है, जो प्रतिवर्ष कुल 1440 घंटे है। इन सामग्रियों को उसी चैनल के भीतर संपादित और पुनर्निर्धारित किया जाता है।

एसपी पर मेडिकल पाठ्यक्रम:

स्वयं प्रभा ने जैविक जीवन विज्ञान विषय के 6 प्रमुख विषयों पर लगभग 220 घंटे की सामग्री के 398+ वीडियो भी बनाए हैं। ये पाठ्यक्रम एनाटॉमी, बायोकैमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और फिजियोलॉजी को पूरा करते हैं। विभिन्न राज्यों के लगभग 29 संस्थानों ने सामग्री निर्माण के लिए योगदान दिया है। यह पाठ्यक्रम सामग्री आईआईटी मद्रास द्वारा प्रबंधित स्वास्थ्य विज्ञान चैनलों में प्रसारित की जा रही

है। कृपया अधिक जानकारी के लिए, वेबसाइट https://dth.ac.in/medical/national.php पर देखें।

सामग्री सृजन+ सेमेस्टर सिंक्रनाइज़ेशनः

एसपी कला,विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करते हुए पाठ्यक्रम–आधारित स्नातकोत्तर और पूर्व स्नातक स्तर से संबंधित सामग्री बनाता है। यह काफी हद तक एआईसीटीई, यूजीसी जैसे सरकारी निकायों और/अथवा स्वायत्त संस्थानों द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम का पालन करता है। सेमेस्टर पाठ्यचर्या के साथ पाठ्यक्रमों का सिंक्रनाइज़ेशन प्रत्येक पाठ्यक्रम प्रस्ताव (पाठ्यक्रम प्रस्ताव समीक्षा के बाद प्रस्तुत) से जुड़े मेटा–दस्तावेज़ द्वारा सक्षम किया जाता है।

एसपी चैनल निम्नलिखित क्षेत्रों/पहलुओं को कवर करते हैं:

1. **उच्च शिक्षाः** कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि, आदि जैसे विविध विषयों को कवर करते हुए स्नातकोत्तर और पूर्व स्नातक स्तर पर पाठ्यचर्या–आधारित पाठ्यक्रम सामग्री। एमओओसी पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए विकसित किए जा रहे मंच स्वयं के माध्यम से सभी पाठ्यक्रम अपनी विस्तृत पेशकश में प्रमाणन के लिए तैयार होंगे।
2. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में **छात्रों (कक्षा 11वीं और 12वीं) की सहायता** करना।
3. **लाइव व्याख्यानः** सामग्री को संबंधित एनसी के विभिन्न स्टूडियो से लाइव प्रसारित किया जाता है। ये क्रेडिट और गैर–क्रेडिट आधारित दोनों पाठ्यक्रमों से संबंधित हो सकते हैं। इस मोड में शिक्षार्थी–एसएमई क्यूएनए सत्रों को सक्षम करना, इसका दीर्घकालिक विज़न है।
4. **ब्रिज पाठ्यक्रमः** विभिन्न प्रारंभिक स्तरों पर शिक्षार्थियों को एक समान लाने पर केंद्रित सामग्री
5. **कौशल और व्यावसायिक पाठ्यक्रमः** कौशल उद्योग और व्यावसायिक क्षेत्र में शिक्षार्थियों/आकांक्षियों के लिए पाठ्यक्रम। इन्हें डिजिटल स्किल्स अकादमी और अन्य उद्योगों जैसे कई भागीदारों के समन्वय से तैयार किया जाता है।
6. **नवाचार और उद्यमिता व्याख्यानः** मंत्रालय तथा नवाचार एवं संबंधित क्षेत्रों के अन्य निपुण नेताओं द्वारा प्रस्तुत, सामग्री का उद्देश्य स्टार्ट–अप और उद्यमिता के शिक्षार्थियों/आकांक्षियों को शिक्षित करना है।
7. **ट्यूटोरियल (प्रश्न पूछना)ः** ये रिकॉर्ड किए गए व्याख्यान हल की गई समस्याओं के माध्यम से और शिक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर देकर डीटीएच एसपी में मौजूदा पाठ्यक्रम के पूरक हैं।
8. **संगोष्ठी और प्रेरणादायक श्रृंखलाः** स्नातकोत्तर डिग्री के इच्छुक शोधकर्ताओं और छात्रों के प्रयोजनार्थ, भारतीय ज्ञान परंपराओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से चयनित शीर्ष गुणवत्ता वाले सम्मेलनों से रिकॉर्ड की गई सामग्री प्रसारित की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023–2024 के लिए कुल 215 पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है, जिसमें लगभग 4,400 घंटे और 3,200 घंटे के लाइव सत्र शामिल हैं। पाठ्यक्रम सामग्री को एक दस्तावेज़ द्वारा टैग किया गया है जिसमें सिंक्रनाइज़ेशन (जनवरी, 2323 में प्रस्तुत किए गए) के लिए सभी अपेक्षित जानकारी शामिल है। पिछली तीन तिमाहियों में निर्मित की गई कुल सामग्री **4881** घंटे है, चौथी तिमाही के लिए पाइपलाइन में 1500 घंटे की अतिरिक्त सामग्री है। दिसंबर, 2023 तक कुल 23098 घंटे की सामग्री निर्मित की गई है। वर्षवार सामग्री निर्माण विवरण नीचे दिया गया है।

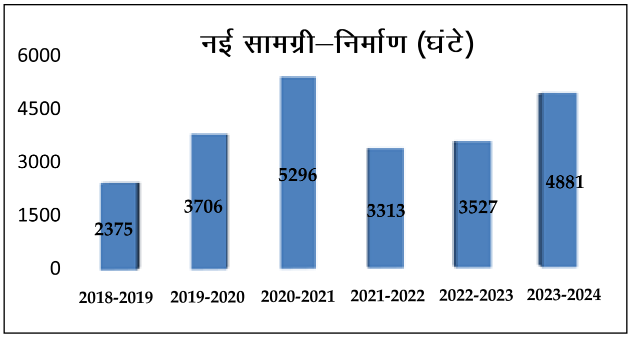

** वर्ष 2023–24 के लिए तीसरी तिमाही तक के घंटे गिने गए।*

डीटीएच स्वयं प्रभा की स्थापना

आम तौर पर सभी टीवी डीलरों के पास उपलब्ध डीडी फ्री डिश और सेट–टॉप बॉक्स को कॉन्फ़िगर करने और स्थापित करने की दो–चरणीय प्रक्रिया (मामूली राशि के लिए) इस प्रकार है:

- यहां दिए गए निर्देशों के अनुसार डीडी फ्रेश डिश इंस्टॉल करें: https://doordarhan.gov.in/dd-free-dish\page¾1
- स्वयं प्रभा चैनलों के लिए सेट–टॉप बॉक्स में निम्नलिखित पैरामीटर सेट करें
- 'डीडी स्वयं प्रभा' चैनलों को दिनांक 7 जून, 2023 से एमपीईजी2 से एमपीईजी4 तकनीक में अपग्रेड किया गया है।
- तदनुसार, 'डीडी स्वयं प्रभा' चैनलों के लिए प्राप्त पैरामीटर नीचे दिए गए अनुसार बदल दिए गए हैं:

एसपी हेतु पैरामीटर प्राप्त करना	
पैरामीटर प्राप्त करना	वैल्यू
उपग्रह/कक्षीय स्थिति	जीसैट–15 / 93.5ओ पूर्व
मॉडुलेशन	11630 मेगाहट्ज
ध्रुवीकरण	क्षैतिज
प्रतीक दर	29500 के.एस.पी.एस
एफईसी	3/4

अकादमिक नेटवर्क के लिए वैश्विक पहल (जीआईएएन)

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षकों तथा छात्रों को दीर्घकालिक सहयोग हेतु एक अभिसरण मंच प्रदान करके साझा शिक्षण और अनुसंधान इंटरैक्शन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को सक्षम करना।

- प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय संकाय के साथ संयुक्त शिक्षण कार्यक्रम।
- लघु (5 से 10 दिन), मध्यम (दो से तीन सप्ताह) और सेमेस्टर दीर्घ पाठ्यक्रम
- छोटी अवधि के लिए 8000$ और लंबी अवधि के लिए 12000$
- भारत और विदेश से उपस्थित लोग।
- राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से भविष्य को देखने के लिए रिपोजिटरी का निर्माण।
- एमओओसी के सृजन की संभावना।

प्रक्रिया

- ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रस्ताव प्रस्तुत करना
- प्रस्ताव 13 क्षेत्रों में से किसी से भी हो सकते हैं
- प्रख्यात शिक्षाविद् की अध्यक्षता वाली अनुभागीय समिति समीक्षा करेगी और सिफारिश करेगी।
- सचिव (एचई), शिक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में जीआईएएन कार्यान्वयन समिति द्वारा अंतिम अनुमोदन
- मेजबान संस्थान अनुमोदन प्राप्त करने के बाद पाठ्यक्रम का आयोजन करता है
- प्रतिभागियों का ऑनलाइन पंजीकरण
- पाठ्यक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है
- जहां भी संभव हो, इंटरनेट पर वेबकास्टिंग
- विदेशी विशेषज्ञों और प्रतिभागियों से नियमित प्रतिक्रिया

01.01.2023–31.12.2023 तक के आँकड़े

वितरित पाठ्चाहमों की कुल संख्या (पूर्ण)	101
जीआईएएन योजना के तहत पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए देश का दौरा करने वाले विदेशी संकायों की संख्या	99
भाग लेने वाले संस्थानों की कुल संख्या	49
एक सप्ताह के कोर्स के लिए आए विदेशी संकायों की संख्या	80
दो सप्ताह के पाठ्यक्रम के लिए आने वाले विदेशी संकायों की संख्या	19
एक या दो सप्ताह के पाठ्यक्रम के अलावा अन्य पाठ्यक्रम अवधि के लिए आए विदेशी संकायों की संख्या	2
देश में विदेशी संकायों की कुल संख्या।	28
सीधे तौर पर लाभान्वित छात्रों की संख्या	> 3436

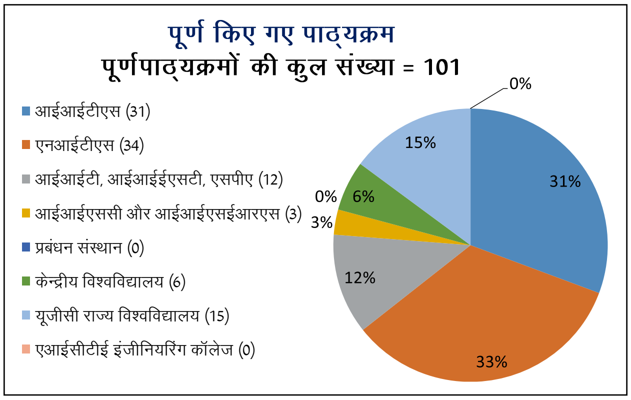

पूर्ण किये गये पाठ्यक्रम (संस्थान)

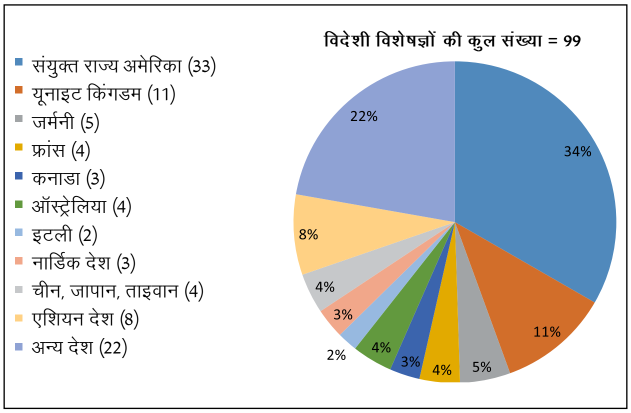

विदेश से आये विशेषज्ञ

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी)

अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी), राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप एक महत्वपूर्ण पहल, उच्च शिक्षा के परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय स्तर की सुविधा के रूप में परिकल्पित, एबीसी एक लचीले पाठ्यक्रम ढांचे का समर्थन करता है, जो उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) में छात्रों के बीच अंत:विषयक और बहु–विषयक शैक्षणिक गतिशीलता का पोषण करता है। इसके मूल में, एबीसी एक अभिनव "क्रेडिट ट्रांसफर" तंत्र द्वारा संचालित है, जो छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रक्षेप पथ को आकार देने में अद्वितीय लचीलापन प्रदान करता है।

दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरु किए गए, एबीसी ने पर्याप्त विकास किया है, जिससे देश भर में उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में लचीलेपन, अंत:विषयक शिक्षा और शैक्षणिक गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय समर्पित संस्थान के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई है।

संस्थागत जुड़ाव:

जनवरी 2024 तक, एबीसी 1,720 पंजीकृत संस्थानों के साथ एक मजबूत नेटवर्क का दावा करता है, जिसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, समविश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, स्वायत्त कॉलेज और विभिन्न अन्य शैक्षणिक निकाय शामिल हैं। इस सहयोगात्मक प्रयास के परिणामस्वरूप 10.42 करोड़ अद्वितीय शिक्षार्थी आईडी का सफल पंजीकरण हुआ है, जिनमें से 2.08 करोड़ उच्च शिक्षा संस्थानों से उत्पन्न हुए हैं।

संस्थान के प्रकार	कुल संस्थान	अब तक पंजीकृत संस्थान	कुल पंजीकृत छात्र
केंद्रीय विश्वविद्यालय	56	53	39,35,518
राज्य विश्वविद्यालय	481	400	1,35,05,037
समविश्वविद्यालय	127	117	6,49,544
निजी विश्वविद्यालय	458	395	11,38,707
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	156	120	1,20,206
स्वायत्त महाविद्यालय	893	388	7,53,583
अन्य संस्थान (स्टैंडअलोन, काउंसिल, तकनीकी और स्कूल बोर्ड, आदि)	555	247	7,01,187
सकल योग	2,725	1,720	2,08,03,782

राज्यवार आउटरीचः

एबीसी ने योजना को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हुए, वस्तुतः और भौतिक रूप से राज्यों में 2,433 जागरूकता अभियान चलाए हैं। विस्तृत राज्य–वार विवरण देश के हर कोने तक पहुंचने, जागरूकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए एबीसी टीम के समर्पण को दर्शाता है।

क्र. सं.	राज्य	बैठकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	74
2	अरुणाचल प्रदेश	17
3	असम	71
4	बिहार	69
5	चंडीगढ़	4
6	छत्तीसगढ़	81
7	दिल्ली	197
8	गोवा	5
9	गुजरात	179
10	हरियाणा	104
11	हिमाचल प्रदेश	10
12	जम्मू एवं कश्मीर	47
13	झारखंड	89
14	कर्नाटक	29
15	केरल	83
16	लद्दाख	1
17	मध्य प्रदेश	205

क्र. सं.	राज्य	बैठकों की संख्या
18	महाराष्ट्र	71
19	मणिपुर	9
20	मेघालय	14
21	मिजोरम	4
22	नागालैंड	17
23	ओडिशा	97
24	पुदुचेरी	7
25	पंजाब	36
26	राजस्थान	198
27	सिक्किम	12
28	तमिलनाडु	191
29	तेलंगाना	24
30	त्रिपुरा	13
31	उत्तर प्रदेश	200
32	उत्तराखंड	42
33	पश्चिम बंगाल	233
	कुल	**2433**

प्रमुख उपलब्धियां:

1. विशिष्ट शिक्षार्थी आईडी: 10 करोड़ से अधिक विशिष्ट शिक्षार्थी/छात्र आईडी पंजीकृत किए गए हैं, जो एबीसी योजना की व्यापक स्वीकृति और अपनाने का प्रमाण है।

2. एनटीए के साथ एकीकरण: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) के साथ निर्बाध एकीकरण ने छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं के लिए सफलतापूर्वक पंजीकरण करने में सक्षम बनाया है, जिससे उन्हें शैक्षणिक मान्यता के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान हुए हैं।

3. स्वयं के साथ सहयोग: एबीसी स्वयं के साथ एकीकृत होने की प्रक्रिया में है, जिससे क्रेडिट संचय की सुविधा मिल सके और छात्रों के लिए अधिक सामंजस्यपूर्ण अधिगम अनुभव सुनिश्चित हो सके।

4. स्किल इंडिया डिजिटल के साथ साझेदारी: स्किल इंडिया डिजिटल के साथ चल रहा एकीकरण शैक्षणिक गतिविधियों को व्यावहारिक कौशल विकास के अनुरूप बनाने, छात्रों को कार्यबल की गतिशील मांगों के लिए तैयार करने की एबीसी की प्रतिबद्धता का उदाहरण प्रस्तुत करता है।

5. समर्थ और ईआरपी विक्रेताओं के साथ एकीकरण: समर्थ और अन्य ईआरपी विक्रेताओं के साथ सफल एकीकरण परिणामों को वास्तविक समय आधार पर तैयार करना सुनिश्चित करता है, जिससे क्रेडिट संचय प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ती है।

6. एबीसी मोबाइल एप्लिकेशन: एबीसी मोबाइल एप्लिकेशन का विकास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के प्रबंधन के लिए एक उपयोगकर्ता–अनुकूल मंच प्रदान करता है।

7. एपीएआर आईडी का सृजन: शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यूडाइज़) के सहयोग से, एबीसी ने स्कूली छात्रों के लिए एपीएआर आईडी बनाई है, डाटा साझाकरण को सुव्यवस्थित किया है और व्यापक शैक्षणिक ट्रैकिंग सुनिश्चित की है।

भावी प्रयास:

एबीसी निरंतर विकास और प्रभाव की परिकल्पना करता है, जिसका लक्ष्य स्वयम और स्किल इंडिया डिजिटल सहित राष्ट्रीय शैक्षिक प्लेटफार्मों के साथ और अधिक एकीकरण करना है। ईआरपी विक्रेताओं के साथ चल रहा सहयोग और एपीएआर आईडी का सफल निर्माण एबीसी की नवाचार और समावेशिता के प्रति प्रतिबद्धता का संकेत है।

जैसा कि हम पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर विचार करते हैं, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एक गतिशील और अनुकूलनीय शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है, जो शिक्षार्थियों को अकादमिक उत्कृष्टता और कौशल विकास की दिशा में अपने विशिष्ट मार्ग को तय करने में सशक्त बनाता है।

❖ ❖ ❖

09

दूरस्थ शिक्षा

दूरस्थ शिक्षा

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा सभी सामाजिक वर्गों को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी। विश्वविद्यालय नवीन, कौशल–आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। विश्वविद्यालय पूरे देश में उचित दरों पर वंचित और सीमांत समूहों के लिए शिक्षा को समावेशी और सुलभ बनाकर शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करता है। इग्नू एक लचीले और रचनात्मक शिक्षण दृष्टिकोण को लागू करके आजीवन उच्च शिक्षा के अवसरों को उत्तरोत्तर बढ़ा रहा है जो छात्रों को शिक्षा से कार्यबल और कार्यबल से शिक्षा की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण देश की विविध आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है और देश के मानव संसाधनों का पूर्ण उपयोग करने और इसके जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने के लिए भी आवश्यक है।69 क्षेत्रीय केंद्रों के अपने नेटवर्क के माध्यम से जिसमें सेना, नौसेना और असम राइफल्स; उत्तर पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीय केंद्र (आरसी) और देश के शेष भागों में 48 आरसी के साथ 12 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्र शामिल हैं, विश्वविद्यालय ने प्रथम श्रेणी की मूलभूत सुविधाओं के साथ उच्च गुणवत्ता वाली दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। 15 देशों में फैले 25 विदेशी अध्ययन केंद्रों के अलावा, पूरे भारत में शिक्षार्थी सहायता केंद्रों का एक बड़ा नेटवर्क है। शिक्षा मंत्रालय के एक प्रभाग, उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी (एचईएफए) ने एक ऋण को अनुमोदित किया, जिससे तिरुवनंतपुरम, पुणे, पोर्ट ब्लेयर और राजकोट में क्षेत्रीय केंद्रों के विकास की अनुमति मिली, जिससे रिपोर्टिंग समय के दौरान छात्र सहायता नेटवर्क और भी मजबूत हो गया। विश्वविद्यालय ओडीएल अनुसंधान में एक राष्ट्रीय नेता है, जो इस प्रकार की शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले पहले विश्वविद्यालयों में से एक है। दूरस्थ शिक्षा का भारतीय प्रकाशन, संस्था द्वारा प्रकाशित एक अंतरराष्ट्रीय सहकर्मी–समीक्षित प्रकाशन, यूजीसी–केयर सूची में शामिल है।

विश्वविद्यालय ने अनुमान लगाया है कि कुल छात्र संख्या 3.4 मिलियन से अधिक है; इनमें से रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण के माध्यम से 13.1 हजार छात्रों की एक महत्वपूर्ण संख्या को जोड़ा गया था। नामांकन संबंधी डाटा विश्लेषण से पता चलता है कि इनमें से 49% महिलाएं हैं, लगभग 54% नामांकित शिक्षार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 52% एससी/एसटी वर्ग से हैं। विश्वविद्यालय वर्ष में दो बार सत्रांत परीक्षा (टीईई) आयोजित करता है। निर्धारित समय में लगभग 2,79,917 छात्रों ने डिग्री,

भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाती हुई।

डिप्लोमा अथवा प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक शर्तें सफलतापूर्वक पूरी कीं। अप्रैल, 2023 में हुए 36वें दीक्षांत समारोह में इन छात्रों को व्यक्तिगत रूप से अपनी डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्राप्त हुए। 36वें दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थीं।

अंतर्राष्ट्रीयकरण

विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश करने वाले इग्नू को अब उच्च शिक्षा के वैश्वीकरण के कारण एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से, खासकर दूरस्थ शिक्षा पद्धति के संबंध में देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय विदेशी शैक्षणिक संस्थानों और अंतर–सरकारी संगठनों के साथ नेटवर्क बनाता है तथा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित करता है। विश्वविद्यालय का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे की व्यवस्था करता है, प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण प्रदान करता है, और विदेश में संस्थान के संचालन के लिए संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करता है। 15 अन्य देशों में फैले 25 विदेशी अध्ययन केंद्रों के माध्यम से, संस्था विश्व स्तर पर अपने शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करती है। विश्वविद्यालय वर्तमान में 55 देशों में कई परियोजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से उपस्थिति बनाए हुए है। जनवरी और जुलाई 2023 प्रवेश सत्र के दौरान, संस्थान द्वारा 3,815 अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित किया गया था।

इग्नू और मुक्त विश्वविद्यालय केन्या (ओयूके) ने दिनांक 03 नवंबर 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

इग्नू ने अपने शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश के लिए केन्या के साथ एक रणनीतिक साझेदारी में प्रवेश किया। भारत के माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति, विलियम सामोई रुटो की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया गया। उच्च शिक्षा और अनुसंधान, शिक्षा मंत्रालय, केन्या के प्रधान सचिव और प्रोफेसर नागेश्वर राव, कुलपति, इग्नू, भारत ने समझौता ज्ञापन का आदान–प्रदान किया।

भारत सरकार की ई–विद्याभारती परियोजना का लक्ष्य अफ्रीकी छात्रों को वेब पोर्टल के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली, किफायती शिक्षा प्रदान करना है। इस साझेदारी के भाग के रूप में इग्नू 45 शैक्षणिक कार्यक्रमों सहित 12 क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से 19 अफ्रीकी देशों को टेली–शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है। उल्लिखित अवधि के दौरान इस परियोजना में कुल मिलाकर 4168 छात्र पंजीकृत हैं। इग्नू और गुयाना सरकार ने गुयाना ऑनलाइन एकेडमिक ऑफ लर्निंग (जीओएएल) प्रोजेक्ट पर सहयोग किया। गुयाना में छात्रों को तृतीयक स्तर की शिक्षा के लिए ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रमों तक पहुंच प्राप्त है। इस प्रयास के तहत विश्वविद्यालय में 1278 छात्रों का नामांकन हुआ। इसके अलावा इग्नू ने अन्य देशों के साथ भी सहयोग किया है जो इस प्रकार हैं:

- दिनांक 1 अक्टूबर, 2023 को रूस में बैकाल स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ एक वचनबद्धता ज्ञापन (एमओई) पर हस्ताक्षर किए गए।
- दिनांक 26 सितंबर, 2023 को मॉस्को, रूस में फाइनेंशियल यूनिवर्सिटी के साथ एक सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए गए।

एनईपी कार्यान्वयन

एनईपी–2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय ने एनईपी प्रकोष्ठ का गठन किया। क्षेत्रीय केंद्रों के अपने अखिल भारतीय नेटवर्क के साथ इग्नू ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की कई सिफारिशों को लागू किया है और वर्ष 2024 में **19वां**

चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) शुरु किया है। मार्च 2023 में, इग्नू ने मातृभाषा में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए इग्नू के एमबीए पाठ्यक्रमों को 12 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन किया। दी गई अवधि के दौरान एनईपी के अनुरूप अन्य पहलों में बहु–विषयक शैक्षणिक कार्यक्रम, कौशल–वृद्धि पाठ्यक्रम, एकाधिक प्रवेश और निकास तथा कुशल शिक्षण सहायता शामिल हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के लिए देश भर में आईसीटी का उपयोग करने की नीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में इग्नू शिक्षा मंत्रालय के स्वयं प्रभा मंच के चार चैनलों का समन्वय करता है। विश्वविद्यालय भारत सरकार के स्वयं कार्यक्रमों के तहत प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तर पर एमओओसी पाठ्यक्रमों के डिजाइन और वितरण के लिए राष्ट्रीय समन्वयक है। इग्नू को शिक्षा मंत्रालय के एनएमईआईसीटी के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में अभिज्ञात किया गया है।। एनएमईआईसीटी के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) इग्नू में स्थापित की जा रही है, जिसमें स्वयं, स्वयं प्रभा, एनडीएलआई, वर्चुअल लैब्स, ईशोध सिंधु आदि जैसी सभी प्रमुख परियोजनाएं शामिल हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इग्नू ने विभिन्न कार्यक्रमों की पेशकश की है। ये इस प्रकार हैं:

जनवरी 2023 में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम

- रूसी भाषा में कला स्नातकोत्तर (एमएमएआरयूएस)
- पर्यावरण अध्ययन में कला स्नातकोत्तर (एमएईवीएस)
- पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कला स्नातकोत्तर (एमएजेईएम)
- पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में कला स्नातकोत्तर (एमएजेडीएम)
- फ्रेंच में कला स्नातकोत्तर (एमएएफएल)
- प्रवासन एवं डायस्पोरा में कला स्नातकोत्तर (मामिडी)
- कला स्नातक (जेंडर अध्ययन) (बीएजीएस)
- कला स्नातक (अनुप्रयुक्त उर्दू) (बीएएयूडी)
- कला स्नातक (अनुप्रयुक्त संस्कृत) (बीएएएसके)
- कला स्नातक (अनुप्रयुक्त हिंदी) (बीएएएचडी)
- प्रारंभिक बाल्यवस्था और मूलभूत स्तर की शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीईसीएफई)
- जियो इंफॉर्मेटिक्स में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीजीआई)
- पर्यावरण प्रबंधन एवं विधि में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीईएमएल)
- वित्तीय प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईएफएम)
- विपणन प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईएमएम)
- मानव संसाधन प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईएचआरएम)
- संचालन प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईओएम)
- पत्रकारिता एवं जनसंचार में पीजी डिप्लोमा (पीजीजेएमसीओएल)
- विज्ञापन और एकीकृत संचार में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीएआईसी)
- भारतीय कालगणना में प्रमाणिक (सीबीकेजी)

जनवरी 2023 में शुरू किए गए ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम

- स्थिरता विज्ञान में कला स्नातकोत्तर (एमएएसएसओएल)
- विकास पत्रकारिता में कला स्नातकोत्तर (एमएडीजे)
- पत्रकारिता और जनसंचार तमिल में कला स्नातकोत्तर – (एमएजेएमसीटीओएल)

जुलाई 2023 में शुरू किए गए शैक्षणिक कार्यक्रम

- संस्कृत साहित्य में विग्गौ में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीएसकेटी)
- कला स्नातक (पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया) (बीएजेडीएम)

- सेवा प्रबंधन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीआईएसएम)
- (भूगोल) में विज्ञान स्नातकोत्तर (एमएससीजीजी)
- विज्ञान स्नातकोत्तर (अनुप्रयुक्त सांख्यिकी (एमएयसीएएसटी))
- (भौतिकी) में विज्ञान स्नातकोत्तर (एमएससीपीएच)
- विज्ञान स्नातकोत्तर (जियोइंफॉर्मेटिक्स) (एमएससीजीआई)
- हिंदू अध्ययन में कला स्नातकोत्तर (एमएएचएन)
- जनसंख्या और परिवार स्वास्थ्य अध्ययन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीपीएफएचएस)
- बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए)
- पर्यावरण अध्ययन में पीजी डिप्लोमा (पीजीडीईवीएस)
- परिधान विपणन में डिप्लोमा (डीएपीएमईआर)
- पर्यटन प्रबंधन में स्नातकोत्तर (अनुप्रयुक्त कौशल) (बीएएएसटीएम)
- कला स्नातक (अनुप्रयुक्त कौशल) (बीएएएस)
- कला स्नातक (अनुप्रयुक्त कौशल) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (बीएएएसएमएसएमई)
- बैचलर ऑफ साइंस (अनुप्रयुक्त कौशल) (बीएससीएएस)
- बैचलर ऑफ कॉमर्स (अनुप्रयुक्त कौशल) (बीसीओएमएएस)
- अपैरल मर्कंडाइजिंग में डिप्लोमा – अनुप्रयुक्त (डीएपीएमईआर)
- प्रारंभिक बाल्यवस्था विशेष शिक्षा सक्षम समावेशन में प्रमाणपत्र दृष्टिबाधिता (सीईएसईआईवीआई)

जुलाई 2023 में शुरु किए गए ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम:

- संस्कृत में कला स्नातकोत्तर (ऑनलाइन) (एमएसकेओएल)
- खाद्य एवं पोषण में प्रमाणपत्र (सीएफएनओएल)
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा (डीएनएचईओएल)

डिजिटल पहल

विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय के स्वयं (युवा आकांक्षी मन के लिए सक्रिय अधिगम का वेब अध्ययन) पहल के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य करता है, जिसमें आजीवन अधिगम से जुड़े कौशल–आधारित पाठ्यक्रमों सहित प्रमाणपत्र और डिप्लोमा स्तरों के लिए एमओओसी पाठ्यक्रम डिजाइन और वितरित करना शामिल है। लगभग 1.7 लाख नामांकितों के साथ विश्वविद्यालय जुलाई, 2023 प्रवेश सत्र के लिए 214 स्वयं पाठ्यक्रम प्रदान करता है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना, स्वयं प्रभा में 40 डीटीएच चैनल शामिल हैं, जो जीसैट–15 उपग्रह पर चौबीसों घंटे शीर्ष शैक्षणिक कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए समर्पित हैं। स्वयंप्रभा मंच के तहत इग्नू को चार डीटीएच (डायरेक्ट टू होम) चैनलों के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में सेवा करने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इनमें राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों, ज्ञान दर्शन, उदार कला और मानविकी, कृषि, व्यावसायिक और संबद्ध विज्ञान द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम शामिल हैं। स्वयं प्रभा पहल के तहत विश्वविद्यालय सक्रिय रूप से डीटीएच चैनलों के लिए टेली–व्याख्यान तैयार कर रहा है। प्रत्येक दिन छात्रों को कम से कम चार घंटे के लिए नई पाठ्यसामग्री तक पहुंच प्राप्त होगी, जिसे दिन के दौरान पांच बार दोहराया जाएगा, जिससे उन्हें वह समय चुनने में मदद मिलेगी जो उनके लिए सबसे अच्छा काम करेगा। ये चैनल अंग्रेजी सहित पंद्रह क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री पेश करते हैं। इनमें बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, मिज़ो, मणिपुरी, तमिल, तेलुगु और उर्दू शामिल हैं। दिनांक 1 नवंबर, 2023 तक 15 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए 5082 लाइव सत्र आयोजित किए गए थे।

मल्टीमीडिया सहायता

वर्ष 2020 में विश्वविद्यालय ने एक परीक्षण परियोजना के रूप में तीन ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए। आज, विश्वविद्यालय 45 ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें पांच स्नातक डिग्री, पंद्रह स्नातकोत्तर डिग्री, नौ स्नातकोत्तर डिप्लोमा, दो स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र, चार डिप्लोमा और तेरह

प्रमाणपत्र शामिल हैं। जुलाई, 2023 प्रवेश सत्र के माध्यम से 34,288 छात्र नामांकित हैं।

शिक्षण सामग्री के डिजिटल संस्करण मोबाइल फोन एप्लिकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। इग्नू द्वारा दी जाने वाली पाठ्यक्रम सामग्री इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। दी गई अवधि में विश्वविद्यालय के 8.6 लाख से अधिक छात्रों ने अपने स्मार्टफोन पर एप्लिकेशन डाउनलोड किया। इग्नू की राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी, ई–ज्ञानकोश का उपयोग संस्थान की डिजिटल शिक्षण सामग्री के प्रसार, साझाकरण, अनुक्रमण, अनुरक्षण एवं रखरखाव के लिए किया जाता है। विश्वविद्यालय ने दिव्यांग छात्रों के लिए एमबीए कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने के लिए ऑडियोबुक शुरू की है।

उल्लिखित अवधि के दौरान विश्वविद्यालय ने 30 सितंबर, 2023 तक 240 नए ऑडियो कार्यक्रम और 166 नए वीडियो कार्यक्रम तैयार किए, जिससे ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों की कुल संख्या क्रमशः 5083 और 6296 हो गई। दिनांक 31 सितंबर, 2023 तक ज्ञान दर्शन शिक्षा टीवी चैनल 500 लाइव टेलीकांफ्रेंस सत्र प्रसारित करता है। विश्वविद्यालय में एक एफएम शिक्षा संबंधित रेडियो ज्ञानवाणी (जीवी) है। जीवी (दिल्ली) एफएम रेडियो आम तौर पर दिन में बारह घंटे अपनी प्रोग्रामिंग प्रसारित करता है। अप्रैल 2021 से, ज्ञानवाणी एफएम रेडियो एनसीईआरटी के साथ साझेदारी में एक अतिरिक्त घंटे के लिए प्रसारण कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय से एचईएफए ऋण की सहायता से, संस्थान ने अपने तकनीकी मूलभूत ढांचे को उन्नत करना और अर्थ स्टेशन, वीडियो स्टूडियो, वीडियो सर्वर, ऑडियो–वीडियो लाइब्रेरी के डिजिटलीकरण और गैर–रेखीय संपादन सिस्टम के लिए उपकरण स्थापित करना शुरू कर दिया है।

क्षमता निर्माण

भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा विश्वविद्यालय को देश में उच्च शिक्षा के प्रशासकों और सामान्य चिकित्सकों को एनईपी–2020 पर दो–क्रेडिट (साठ घंटे) स्वयं पाठ्यक्रम प्रदान करने का निर्देश दिया गया था। माननीय शिक्षा और विदेश राज्य मंत्री, डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने दिनांक 1 फरवरी, 2023 को इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का शुभारंभ और कार्यान्वयन किया। अक्टूबर 2023 तक 10,743 लोगों ने पंजीकरण कराया, और उनमें से 4,225 ने 2–क्रेडिट पाठ्यक्रम पूरा किया।

अनुसंधान और नवाचार

एक मुक्त विश्वविद्यालय न केवल एक अद्वितीय संस्थान है, बल्कि शिक्षा प्रदान करने की एक अभिनव प्रणाली भी है। इग्नू संकाय द्वारा शुरू की जाने वाली प्रमुख/छोटी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था करके अनुसंधान को प्रोत्साहित करता है। विषय–आधारित अनुसंधान अध्ययन स्कूलों में आयोजित किया जाता है। अब तक **10** से अधिक सक्रिय बाह्य वित्त पोषित अनुसंधान परियोजनाएं हैं जो विभिन्न अध्ययन स्कूलों द्वारा संचालित की जा रही हैं। नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन (एनसीआईडीई) इग्नू के छात्रों और शिक्षकों के लिए नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप पर साप्ताहिक एक घंटे का फेसबुक लाइव सत्र प्रस्तुत करता है। इग्नू में छात्रों को इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल, स्टूडेंट एम्पावरमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट (एसईईडी), आइडियाबैंक/इग्नू और आइडियाज़ टू स्टार्टअप प्रोग्राम सहित कई तरह की सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त है।

इग्नू ने अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स (एआरआईआईए) की सीएफआई (गैर–तकनीकी) श्रेणी में पहला स्थान हासिल किया है और एनआईआरएफ–इनोवेशन रैंकिंग–2023 द्वारा 151–300 रैंकिंग बैंड में "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान और केंद्रीय विश्वविद्यालयों" की श्रेणी में शीर्ष 10 संस्थानों में भी स्थान दिया गया है।

❖ ❖ ❖

10

भाषा संस्थान

भाषा संस्थान

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल)

स्थापना के 54 वर्ष पूरे करने के बाद सरकार का प्रयास है कि संस्थान की गतिविधियों का विस्तार किया जाए, जैसा कि सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए आवश्यक है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल) ने एनईपी–2020 की कार्ययोजना के अनुरूप शैक्षणिक कार्यक्रमों और अनुसंधान गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया। संस्थान ने इस वर्ष भारतीय भाषाओं के लिए, भारतीय भाषाओं में और उनके माध्यम से प्रौद्योगिकी के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक उच्च स्तरीय तकनीकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया और विभिन्न तकनीकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों और उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले 1500 प्रतिनिधियों ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 75 दिवसीय भारतीय भाषा उत्सव का शुभारंभ भी हुआ। संस्थान की सभी योजनाओं, परियोजनाओं, क्षेत्रीय भाषा केंद्रों और शास्त्रीय भाषा केंद्रों ने भारतीय भाषा उत्सव को बड़े उत्साह के साथ मनाने के लिए शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। संस्थान ने फैलोशिप और छात्रवृत्ति योजना बहाल कर दी है और संस्थान जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय भाषाओं के उपयोग के समन्वय के लिए समझौता ज्ञापनों के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा विभागों और भाषा संस्थानों/केंद्रों के साथ परामर्श कर रहा है। संस्थान ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम में भाग लिया और भारतीय भाषा समिति को भाषा/अनुवाद सहायता प्रदान की। संस्थान ने भारत की कई भाषाओं और मातृभाषाओं के लिए प्राइमर और स्व–शिक्षण सामग्री तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। संस्थान के स्थापना दिवस के उत्सव में हिंदी पखवाड़ा, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस और भारतीय भाषा दिवस मुख्य आकर्षण हैं।

संस्थान की गतिविधियों का योजना/परियोजना–वार विवरण इस प्रकार है:

1. राष्ट्रीय परीक्षण सेवा–भारत (एनटीएस–I)

राष्ट्रीय परीक्षण सेवा भारत (एनटीएस–आई) ने शिक्षण–अधिगम सामग्री तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया तथा परीक्षण और मूल्यांकन पर कार्य करना शुरू किया। एनटीएस–I ने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से मिश्रित मोड (ऑनलाइन और ऑनसाइट) में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम सह कार्यशालाएं आयोजित कीं। यद्यपि इसका ध्यान हिंदी, उर्दू, तमिल और मलयालम पर केंद्रित था, तथापि इसने 22 अनुसूचित भाषाओं में ए1 और ए2 स्तर की प्रवीणता पाठों की तैयारी भी शुरू की। एनटीएस–I ने अपने डाटाबेस और शब्दावली–संबंधित संसाधनों का भी विस्तार किया। इसने कर्मचारी चयन आयोग और नवोदय विद्यालय समिति सहित विभिन्न एजेंसियों को भाषा दक्षता और परीक्षण तथा मूल्यांकन–आधारित परामर्श प्रदान किया।

2. भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई डाटा कंसोर्टियम (एलडीसी–आईएल)

एलडीसी–आईएल ने इस वर्ष भाषा प्रौद्योगिकी समुदाय के लिए 14 नए डाटासेट तैयार किए। इसमें हिंदी के अंतर्गत वर्गीकृत मातृभाषा छत्तीसगढ़ी के लिए एक नया डाटासेट शामिल

है। एलडीसी–आईएल के डाटा पोर्टल की मांग अधिक है और नए उपयोगकर्ता, ज्यादातर औद्योगिक और शैक्षणिक उपयोगकर्ता, दैनिक आधार पर पोर्टल पर पंजीकरण कराते रहते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य उन्मुख परियोजनाएं छह अनुसूचित भाषाओं नामतः असमिया, पंजाबी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, तेलुगु और अन्य में आयोजित की गई हैं। इस योजना ने वास्तविक और आभासी मोड में कई कार्यशालाएँ और सम्मेलन भी आयोजित किए। इस योजना ने विभिन्न भाषा विशेषज्ञों को अपने घरों से कार्य करने और विभिन्न तरीकों से अपनी भाषा के संग्रह में योगदान करने की अनुमति देने के लिए कुछ ऑनलाइन टूल भी विकसित किए। इसमें विभिन्न भारतीय भाषाओं में कार्य के सफल प्रबंधन की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए सुरक्षा और कार्यक्षमता की कई परतों के साथ एक भाषण मूल्यांकन उपकरण और एक टेक्स्ट डिजिटलीकरण प्लेटफ़ॉर्म की तैनाती शामिल है।

3. राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम)

राष्ट्रीय अनुवाद मिशन (एनटीएम) ने 22 अनुसूचित भाषाओं और उच्च शिक्षा के विभिन्न विषयों में ज्ञान ग्रंथों और शाब्दिक संसाधनों के अनुवाद लाने पर ध्यान केंद्रित किया। मिशन ने अनुवाद पर ध्यान केंद्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने के लिए अकादमिक संस्थानों के साथ सहयोग किया। एनटीएम ने अनुवादकों को सशक्त बनाने और देश में अनुवाद को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने के लिए कौशल–विकास कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। एनटीएम भारत के संविधान का आठवीं अनुसूची की 11 भाषाओं में अनुवाद और अद्यतनीकरण में लगा हुआ है। एनटीएम ने अपने डाटाबेस का विस्तार किया तथा विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी एजेंसियों को भाषा/अनुवाद परामर्श प्रदान किया। मिशन ने 50 पांडुलिपियाँ बनाई हैं जो मुद्रण/प्रकाशन के लिए तैयार हैं और द्विवार्षिक पत्रिका इस क्षेत्र में अग्रणी है।

4. शास्त्रीय भाषाओं का केंद्र

सीआईआईएल शास्त्रीय तेलुगु, शास्त्रीय कन्नड़, शास्त्रीय मलयालम और शास्त्रीय उड़िया को बढ़ावा देने के लिए शास्त्रीय केंद्रों को लागू करता है। इन केंद्रों ने कई ऑनलाइन सेमिनार आयोजित किए और छोटे प्रोजेक्ट के आधार पर भाषा के विद्वानों के साथ भी काम किया। तेलुगु, उड़िया और मलयालम के केंद्र आंध्र प्रदेश/ओडिशा और केरल के संबंधित राज्यों में परियोजना निदेशकों के साथ कुछ आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ स्थापित किए गए थे। संस्थान द्वारा विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं के प्रचार, जागरूकता और विकास के लिए वेबिनार, व्याख्यान श्रृंखला, सेमिनार, कार्यशालाएं आदि आयोजित की जाती हैं।

5. लुप्तप्राय भाषाओं के परिरक्षण और संरक्षण हेतु योजना (एसपीपीईएल)

इस योजना ने विशेष रूप से भारत की भाषाओं और मातृभाषाओं पर ध्यान केंद्रित किया और क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को अत्याधुनिक तकनीकों से लैस करने के लिए गहन प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस योजना ने समुदाय के सदस्यों को भी आमंत्रित किया तथा उन्हें दृश्य–श्रव्य भाषाई और सांस्कृतिक डाटा एकत्र करने के लिए रिकॉर्डिंग गतिविधियों में शामिल किया। एसपीपीईएल ने भाषा समुदाय के सदस्यों को डाटा संग्रह/डाटा विश्लेषण गतिविधियों में प्रशिक्षित करने का प्रयास किया और विभिन्न दूर स्थित भाषा समुदायों में फील्डवर्क भी किया।

6. भारतवाणी परियोजना (बीवीपी)

भारतवाणी ने भाषा के अधिगम संसाधनों के डिजिटलीकरण वेब–होस्टिंग पर ध्यान केंद्रित

किया और नई भाषाएँ/डिजिटल शब्दकोश जोड़े। भारतवाणी परियोजना ने बड़ी संख्या में खोजने योग्य शब्दकोश और ऑनलाइन लिप्यंतरण सेवाएं प्रदान कीं। बीवीपी ने सामग्री भागीदारों के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इसके लिए अनिवार्य भाषा संसाधनों के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया। बीवीपी द्वारा होस्ट की गई सामग्री की वेब और मोबाइल पहुंच बढ़ रही है।

7. क्षेत्रीय भाषा केंद्र (आरएलसी)

संस्थान के क्षेत्रीय भाषा केंद्रों ने 20 भारतीय भाषाओं में भाषा दक्षता और प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश किए तथा इन केंद्रों ने देश के नागरिकों के बीच बहुभाषावाद/राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सेवारत और भावी शिक्षकों एवं आम जनता को ऑनलाइन तथा ऑनसाइट प्रशिक्षण की पेशकश की। क्षेत्रीय भाषा केंद्र 20 भारतीय भाषाओं के लिए स्व–शिक्षण सामग्री तैयार करने में भी लगे हुए हैं। नवनिर्मित पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र (ईआरएलसी) के भवन का उद्घाटन दिनांक 17 नवंबर 2023 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। यूटीआरसी सोलन के लिए भवनों का निर्माण अंतिम चरण में है। एनईआरएलसी ने उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र (एनईआरएलसी) के नए परिसर को विकसित करने के लिए असम में 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है जो हमें एनईआर भाषा की प्रचार गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

i) माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा दिनांक 30.9.2023 को भाषा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन–

ii) माननीय कार्मिक मंत्री द्वारा दिनांक 1.10.2023 को भाषा शिखर सम्मेलन का समापन समारोह–

iii) दिनांक 17.11.2023 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केंद्र, भुवनेश्वर के नए भवन का उद्घाटन

केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी)

हिंदी भाषा के विकास के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के तहत दिए गए निर्देश इस प्रकार हैं–

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार

बढ़ाए, उसका विकास करे ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके तथा उसकी मौलिकता में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और अभिव्यक्तियों को आत्मसात करके तथा जहां आवश्यक या वांछनीय हो, उसके शब्द—भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत और गौणतः अन्य भाषाओं का उपयोग करके उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे।"

उपर्युक्त संवैधानिक निषेधाज्ञा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय की स्थापना दिनांक 01 मार्च, 1960 को शिक्षा मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय के रूप में की गई थी। निदेशालय के चार क्षेत्रीय कार्यालय चेन्नई, हैदराबाद, गुवाहाटी और कोलकाता में स्थित हैं। केंद्र सरकार की यह सर्वोच्च संस्था, अपने अस्तित्व में आने के बाद से हिंदी को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने, विभिन्न लोगों को इस भाषा के माध्यम से जोड़ने और वैश्विक स्तर पर इसे प्रतिष्ठा का स्थान दिलाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगातार लगा हुआ है।

निदेशालय हिंदी के विकास, प्रचार—प्रसार और संवर्धन से संबंधित कई महत्वपूर्ण योजनाएं और कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जैसे:

1. पत्राचार पाठ्यक्रम
2. पूरक शैक्षिक सामग्री
3. विस्तार कार्यक्रमः गैर—हिंदी भाषी नव—हिंदी लेखक शिविर, छात्र अध्ययन यात्रा, शोध छात्र यात्रा अनुदान, शिक्षक व्याख्यान श्रृंखला, राष्ट्रीय सेमिनार।
4. हिंदी के प्रचार—प्रसार के लिए स्वैच्छिक हिंदी संगठनों को वित्तीय सहायता योजना और हिंदी में प्रकाशन हेतु वित्तीय सहायता योजना।
5. प्रकाशन — भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला जैसे शब्दकोशों और पत्रिकाओं की तैयारी और प्रकाशन।
6. हिन्दी पुस्तकों का निःशुल्क वितरण।
7. पुस्तक प्रदर्शनियाँ और बिक्री।
8. विदेशी छात्रों के लिए बुनियादी हिंदी जागरूकता पाठ्यक्रम।

केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों की उपलब्धियाँ

योजना का नाम	उपलब्धियाँ
1. पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी शिक्षण	• विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 6774 छात्रों को प्रवेश दिया गया। • सभी पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री और पूरक सामग्री तैयार तथा प्रकाशित की गई। • परीक्षा में 2660 छात्र शामिल हुए। • निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वृत्तचित्रों की तैयारी, सभी पाठ्यक्रमों से संबंधित अध्ययन सामग्री के गहन संशोधन/आशोधन के लिए विशेषज्ञ समिति की बैठकें आयोजित की गई। • निम्नलिखित संवादात्मक मार्गदर्शिकाएँ और स्वयं शिक्षक प्रकाशित अर्थात्— • गुजराती—हिन्दी स्वयं शिक्षा। • उर्दू—हिन्दी—उर्दू वार्ता पुस्तिका • कोंकणी—हिन्दी—कोंकणी वार्तालाप पुस्तिका • दूसरी ओर स्वयं सीखी गई 02 पुस्तकों अर्थात् हिंदी स्वयंशिक्षक (असमिया माध्यम) और (बांग्ला माध्यम) की तैयारी अनुसूची के अनुसार।

योजना का नाम	उपलब्धियाँ
2. कैसेट के माध्यम से हिंदी	1. दिसंबर 2023 तक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। गुवाहाटी, कालीकट, माल बाजार, कोलकाता, भोपाल।
3. विस्तारित कार्यक्रम	2. त्रिवरुर (तमिलनाडु) त्रिपुरा, कोरापुट (ओडिशा), कश्मीर, जलगांव (महाराष्ट्र), भटिंडा (पंजाब) में गैर–हिंदी भाषी नव–हिंदी लेखक शिविर आयोजित किए गए हैं।
	3. प्राध्यापक व्याख्यान माला (05) • डॉ. शहाबुद्दीन शेख – रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ कल्याण पीजी कॉलेज भिलाई, छत्तीसगढ़ शहीद राजीव पांडे शासकीय महाविद्यालय, रायपुर, • डॉ. गोकुल शिरसागर, राजकीय महाविद्यालय जयपुर, राजस्थान सेंटर कॉलेज मोहनलाल शुकड़िया कॉलेज उदयपुर, • डॉ. रेखा अग्रवाल– लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली जयपुर, हंस कॉलेज पावटा, जयपुर राजस्थान, बहरोड़ पी.जी. कॉलेज कोटपुतली राजस्थान, • डॉ. सी. जे. पारसनकुमारी–इलाहाबाद सेंटर कॉलेज प्रयाग प्रो. राजेंद्र सिंह कॉलेज, प्रयाग, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज जामिया नई दिल्ली। • प्रोफेसर. मुकेश कुमार मिश्रा – कालीकट कॉलेज केरल, कोचीन टेक्नोलॉजी, कॉलेज, केरल कॉलेज, केरल
	4. शोध छात्र यात्रा अनुदान सीएचडी योजना के तहत 38 छात्रों को सम्मानित किया गया।
4. प्रकाशन की योजनाएँ (i) शब्दकोशों की तैयारी	• हिन्दी–फ्रेंच कोश प्रकाशित की गई। • हिन्दी–अरबी कोश प्रकाशित की गई। • हिन्दी डोगरी–कोश प्रकाशित की गई। • उर्दू–हिन्दी–कोश प्रकाशित की गई। • हिन्दी–नेपाली कोश का प्रथम प्रमाण की गई। • हिन्दी–चीनी संवादी मार्गदर्शिका का दूसरा प्रमाण प्रतीक्षित है। • हिन्दी चीनी कोश की पांडुलिपि प्रक्रियाधीन है। • हिन्दी बल्गेरियाई कोश–सीआरसी प्रतीक्षित है। • पोलिश–हिन्दी कोश की पांडुलिपि प्रक्रियाधीन है। • हिन्दी–व्युतपत्ति कोश प्रक्रियाधीन है। • हिन्दी मैथिली कोश का सीआरसी प्रकाशनार्थ भेजा गया।

योजना का नाम	उपलब्धियाँ
	<u>उपलब्धि</u> • हिंदी–संस्कृत, हिंदी–कश्मीरी और हिंदी–मैथिली संवादात्मक मार्गदर्शिकाएँ प्रकाशित की गई हैं। दूसरी ओर हिन्दी–विवर्णिका एवं तमिल, मलयालम एवं अंग्रेजी माध्यम की अध्ययन सामग्री, रिस्पॉन्स शीट, सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम तैयार एवं प्रकाशित किया गया। • **हिन्दी शब्द सिन्धु कोश** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से हिंदी शब्द हिंदी कोश तैयार किया जा रहा है। कोश का पहला भाग दिनांक 14 सितंबर 2022 को सूरत में हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया था। 14 सितंबर 2023 तक इस डिजिटल डिक्शनरी में 3,51,000 शब्दों के संकलन का लक्ष्य हासिल किया गया। • कश्मीरी–हिन्दी कोश सीआरसी प्रतीक्षित है।
(ii) **भाषा वार्षिकी एवं साहित्यमाला**	• 'भाषा' पत्रिका के 06 अंक प्रकाशित (जिसमें (राम तत्व मीमांसा विशेषांक एवं पूर्वोत्तर भाषा साहित्य एवं संस्कृति विशेषांक) नामक दो विशेषांक शामिल हैं) • हिंदी और गैर–हिंदी भाषी क्षेत्रों (केरल और ईटानगर) में दो राष्ट्रीय संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।
5 विदेशी छात्रों हेतु मूलभूत हिंदी जागरूकता पाठ्यक्रम	केंद्रीय हिंदी निदेशालय (सीएचडी) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के सहयोग से मूलभूत हिंदी जागरूकता पाठ्यक्रम शुरू किया गया तथा दिनांक 16.11.2022 से ऑनलाइन कक्षा शुरू हुई।

केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान, चेन्नई

भारत सरकार द्वारा तमिल को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के परिणामस्वरूप भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में चेन्नई में केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान (सीआईसीटी), चेन्नई की स्थापना की गई थी। सीआईसीटी तमिलनाडु सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1975 के तहत एक पंजीकृत सोसायटी है। तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री सीआईसीटी के अध्यक्ष हैं।

शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित यह संस्थान विशेष रूप से तमिल भाषा के शास्त्रीय चरण अर्थात प्रारंभिक काल से लेकर 600 ईस्वी तक से संबंधित अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। संस्थान की भूमिका बहुत अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन तमिल समाज पर शोध करता है और तमिलों की प्राचीनता से संबंधित या प्रतिबिंबित वस्तुओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण भी करता है। प्राचीन तमिलों और उनकी सभ्यता की प्राचीनता तथा विशिष्टता का अध्ययन करने के लिए 600 ईस्वी तक की अवधि से संबंधित 41 प्राचीन तमिल कार्यों की पहचान की गई है। शास्त्रीय तमिल को बढ़ावा देने के लिए सीआईसीटी द्वारा अल्पकालिक परियोजनाओं, सेमिनारों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आर्थिक रूप से समर्थन दिया जाता है। वर्ष 2023–24 के लिए सीआईसीटी को 14.20 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई। सीआईसीटी ने वाराणसी में काशी तमिल संगमम में विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। माननीय प्रधान मंत्री ने सीआईसीटी द्वारा अनुवादित 5 विदेशी भाषाओं सहित 15 भाषाओं

में 'तिरुक्कुरल' जारी किया। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्रेल में 46 प्राचीन तमिल साहित्य गौरव ग्रंथो का विमोचन किया गया। माननीय शिक्षा मंत्री ने दिनांक 29.07.2023 को नई दिल्ली में एनईपी समारोह के दौरान संस्थान के 10 प्रकाशन भी जारी किए।

सीआईसीटी ने 200 से अधिक प्रतिष्ठित विद्वानों, प्रोफेसरों और प्रतिनिधियों को विभिन्न शास्त्रीय तमिल विषयों पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया है और ये सभी कार्यक्रम यूट्यूब चैनलों पर अपलोड किए गए हैं। सीआईसीटी द्वारा 44 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जिनमें 1300 विद्वानों/छात्रों ने भाग लिया। सीआईसीटी द्वारा निबंध लेखन, ड्राइंग प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करके भारतीय भाषा उत्सव मनाया गया।

i) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 15 भाषाओं में तिरुक्कुरल के अनुवाद का विमोचन (दिनांक 17.12.23)

ii) माननीय शिक्षा मंत्री दिनांक 29.7.23 को सीआईसीटी प्रकाशन का विमोचन करते हुए

iii) तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल ने काशी तमिल संगमम के लिए सीआईसीटी पुस्तकों का विमोचन किया

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (एसएलबीएसएनएसयू)

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) की स्थापना की, जिसके संबंध में ज्ञान की शास्त्र परंपरा को संरक्षित करने, उच्च शिक्षा, शास्त्रों की व्याख्या, आधुनिक और शास्त्र विद्या में शिक्षकों का गहन प्रशिक्षण और आधुनिक संदर्भ में शास्त्रों की प्रासंगिकता स्थापित करने के लिए पूर्ववर्ती श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली को दिनांक 30 अप्रैल 2020 को अधिसूचना जारी की गई थी।

विश्वविद्यालय में अध्ययन के पांच स्कूल हैं: वेद–वेदांग की पाठशाला, दर्शनशास्त्र की पाठशाला, साहित्य और संस्कृति की पाठशाला, आधुनिक विद्या की पाठशाला और शिक्षा की पाठशाला। इन स्कूलों में 22 विभाग हैं जो शास्त्री (बी.ए.) से लेकर विद्यावारिधि (पीएचडी) तक विभिन्न शास्त्र पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। शास्त्र शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए, विश्वविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर, अनुसंधान और अंशकालिक पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को पर्याप्त अधिगम का वातावरण प्रदान करने का प्रयास करता है। शैक्षणिक कार्यक्रमों की नियमित रूप से संबंधित स्कूल ऑफ स्टडीज और विश्वविद्यालय की अकादमिक परिषद द्वारा समीक्षा की जाती है।

विज़न और मिशन

विज़न

- आधुनिक संदर्भ में समस्याओं की प्रासंगिकता स्थापित करके शास्त्रों की शास्त्रीय परंपरा और व्याख्या को संरक्षित करना।

उद्देश्य

- अत्यधिक विशिष्ट शाखाओं पर विशेष ध्यान देते हुए पारंपरिक संस्कृत विद्या में शिक्षा प्रदान करना।
- संस्कृत शिक्षा एवं भारतीय ज्ञान परंपरा में उच्च स्तरीय अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- संस्कृत में शास्त्रीय संस्कृत और समकालीन साहित्य का अध्ययन करना।
- अनुसंधान के माध्यम से संस्कृत विरासत के ज्ञान को समृद्ध करना।
- पारंपरिक और समसामयिक दृष्टिकोण के विशेष संदर्भ में शास्त्रों की व्याख्या करना।
- संस्कृत के सहायक घटकों अर्थात् ज्योतिष और वास्तु शास्त्र में उच्च अध्ययन के अवसर प्रदान करना।
- आलोचनात्मक विश्लेषण और चिंतन के लिए पांडुलिपियों को संरक्षित करना।
- स्कूली शिक्षा के लिए घटक संस्कृत शिक्षक तैयार करना।
- शिक्षाशास्त्र के लिए शिक्षक प्रशिक्षकों को तैयार करना।
- एक विशिष्ट चरित्र बनाने के लिए अपनी संस्कृत शिक्षा और विभिन्न विषयों में उत्कृष्टता प्राप्त करना

प्रस्तावित कार्यक्रम

विश्वविद्यालय पूर्णकालिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। इन पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार हैः—

स्कूल का नाम	कार्यक्रमों का नाम	विषय
वेद—वेदांग विद्यालय, दर्शनशास्त्र विद्यालय, साहित्य एवं संस्कृति विद्यालय	शास्त्री (बी.ए.) (तीन/चार वर्ष) बी.ए. योग (तीन/चार वर्ष) आचार्य (एम.ए.) (दो वर्ष) एम.ए. योग (दो वर्ष)	वेद, पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्व दर्शन, सांख्य योग, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जैन दर्शन, मीमांसा, साहित्य, पुराणेतिहास, प्राकृत और योग.
वेद—वेदांग विद्यालय, दर्शनशास्त्र विद्यालय, साहित्य और संस्कृति विद्यालय	आचार्य (एम.ए.) (दो वर्ष) एम.ए. योग (दो वर्ष)	वेद, पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तु—शास्त्र, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्व दर्शन, सांख्य योग, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जैन दर्शन, मीमांसा, साहित्य, पुराणेतिहास, प्राकृत और योग

स्कूल का नाम	कार्यक्रमों का नाम	विषय
वेद–वेदांग विद्यालय, दर्शनशास्त्र विद्यालय, साहित्य और संस्कृति विद्यालय	विद्यावरिधि (पीएचडी)	वेद, पौरोहित्य, धर्मशास्त्र, प्राचीन व्याकरण, नव्य व्याकरण, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, प्राचीन न्याय, नव्य न्याय, सर्व दर्शन, सांख्य योग, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत वेदांत, जैन दर्शन, मीमांसा, साहित्य, पुराणेतिहास, प्राकृत
आधुनिक विषय का विद्यालय	एम.ए. हिंदी, एम.ए. हिंदू अध्ययन, एम.ए. अंग्रेजी, एम.ए. समाजशास्त्र	
शिक्षा विद्यालय	शिक्षा शास्त्री (बी. एड.), शिक्षाचार्य (एम.एड.), विद्यावारिधि (पीएचडी)	
उपरोक्त पूर्णकालिक पाठ्यक्रमों के अलावा, विश्वविद्यालय स्व–वित्तपोषण कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है।		
शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान सभी पाठ्यक्रमों के तहत कुल 2097 छात्रों का नामांकन किया गया है।		

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सहायता अनुदान

क्र.सं.	विवरण	राशि (लाख में)
1	विश्वविद्यालय को यूजीसी से अनुदान सहायता प्राप्त हुई	5554.61
3	विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कुल व्यय	5341.51

शिक्षण एवं गैर–शिक्षण स्टाफ का विवरणः–

शिक्षण स्टाफ		
स्वीकृत पदों की संख्या	भरे गए पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
139	111	28
गैर–शिक्षण स्टाफ		
स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या	स्वीकृत पदों की संख्या
136	110	26

विश्वविद्यालय द्वारा संचालित योजनाएँः

क्र.सं.	योजना का नाम
1	महिला अध्ययन केंद्र
2	मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (एमएमटीटीसी)
3	ज्योतिष विभाग में विशेष सहायक कार्यक्रम (डीआरएस–III)
4	साहित्य विभाग में विशेष सहायता कार्यक्रम (डीआरएस– II)
5	व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रमः (एमओओसी)
6	एमओओसी पाठ्यक्रम में पुनर्प्रयोजनः भारतीय संस्कृति और इतिहास

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान आयोजित शैक्षणिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ

वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने परिसर में स्वामी विवेकानन्द की जयंती, राष्ट्रीय युवा दिवस, गणतंत्र

दिवस, सरस्वती पूजन मोहत्सव, कल्पदुरम सांस्कृतिक उत्सव, उत्कर्ष महोत्सव, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आँगनदान महोत्सव, हर घर तिरंगा महोत्सव, विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस, स्वतंत्रता दिवस, प्रौद्योगिकी और भारतीय भाषा शिखर सम्मेलन, स्वच्छता ही सेवा, गांधी जयंती और श्री लाल बहादुर जयंती, मेरी माटी मेरा देश, बाजरा दिवस, सतर्कता जागरूकता सप्ताह, दिवाली पूजन, जनजाति गौरव दिवस, सांप्रदायिक सद्भाव दिवस, संविधान दिवस, भारतीय भाषा उत्सव 2023, विकसित भारत 2047 आदि जैसे विभिन्न कार्यक्रम मनाए गए।

विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह

वर्ष के दौरान श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह दिनांक 5 दिसंबर 2023 को आयोजित किया गया था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और विशिष्ट अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान थे।

विश्वविद्यालय प्रकाशन

i. शोध प्रभा

ii. अनुसन्धान सम्पादन प्रगति

iii. शिशुपालवध महाकाव्यानुशीलनम्

iv. श्रीपदार्थदीपिका

v. हीरकगौरवम् (स्मारिका)

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी)

वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना 1 अक्टूबर 1961 को भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा की गई थी। सरकार का यह संकल्प संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड (4) के प्रावधानों के तहत गठित एक समिति की सिफारिशों के अनुसार था। 1960 के संकल्प के अनुसार आयोग के कार्य हैंः—

(क) 1960 के राष्ट्रपति आदेश के पैराग्राफ 3 में निर्धारित सिद्धांतों के आलोक में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा।

(ख) हिंदी और अन्य भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के विकास और समन्वय से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण।

(ग) संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से या उनके कहने पर वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली के क्षेत्र में राज्यों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए गए कार्यों का समन्वय और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में उपयोग के लिए शब्दावलियों का अनुमोदन जिसे संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) आयोग अपने द्वारा विकसित या अनुमोदित नई शब्दावली का उपयोग करके मानक वैज्ञानिक पाठ्यपुस्तकों की तैयारी, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दकोशों की तैयारी और विदेशी भाषाओं में वैज्ञानिक पुस्तकों का भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी कर सकता है।

जैसा कि ऊपर उल्लिखित है, समिति की सिफारिशों और उसके बाद जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेशों के उपरांत वर्तमान में सीएसटीटी के कार्यों और कर्तव्यों को निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता हैः—

आयोग के कर्तव्य एवं कार्यः

(क) हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को विकसित और परिभाषित करना और शब्दावलियाँ, परिभाषा शब्दकोश, विश्वकोश प्रकाशित करना।

(ख) यह देखना कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्वानों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचें।

(ग) उपयोगी फीडबैक प्राप्त करके (कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/ओरिएंटेशन कार्यक्रमों/सेमिनारों के माध्यम से) किए गए कार्यों का उचित उपयोग/आवश्यक अद्यतनीकरण/संशोधन/सुधार सुनिश्चित करना।

(घ) वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों पर सेमिनार/सम्मेलन/संगोष्ठी प्रायोजित करके हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन को प्रोत्साहित करना।

(ङ) हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में शब्दावली की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के साथ समन्वय करना। (राज्य सरकारों/ग्रंथ अकादमियों/विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों/शब्दावली क्लबों या अन्य एजेंसियों के माध्यम से)।

(च) मानक शब्दावली को लोकप्रिय बनाने और उपयोग के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं में पुस्तकों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना।

आयोग का कार्यक्रमः–

(i) अंग्रेजी – हिन्दी तकनीकी शब्दकोशों/शब्दावलियों की तैयारी और प्रकाशन

(ii) अंग्रेजी – क्षेत्रीय भाषा तकनीकी शब्दकोश/शब्दावली की तैयारी और प्रकाशन

(iii) त्रिभाषी शब्दावलियों की तैयारी और प्रकाशन

(iv) पारिभाषिक शब्दकोशों की तैयारी और प्रकाशन

(v) शिक्षार्थी की शब्दावलियों की तैयारी और प्रकाशन

(vi) विभागीय शब्दावलियों की तैयारी, अनुमोदन/प्रकाशन

(vii) बनाए गए और परिभाषित शब्दों का प्रचार, विस्तार और आलोचनात्मक समीक्षा

(viii) हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों का उत्पादन

(ix) मोनोग्राफ का प्रकाशन

(x) पत्रिकाओं का प्रकाशन

(xi) प्रकाशनों का निःशुल्क वितरण

(xii) प्रदर्शनियों का आयोजन

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

1. हिंदी में तकनीकी शब्दकोश/शब्दावली तैयार करनाः

कार्य प्रगति पर है

(i) गणित शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतन

(ii) अर्थशास्त्र की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(iii) न्यू मीडिया शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(iv) प्रशासनिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)– अद्यतन

(v) शिक्षा शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(vi) चिकित्सा विज्ञान की व्यापक शब्दावली (संस्कृत–अंग्रेजी–हिन्दी)

(vii) इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी)

(viii) साहित्य शास्त्र अवधारण कोश (अंग्रेजी–हिन्दी)

(ix) फिजियोलॉजी शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(x) इलेक्ट्रॉनिक्स की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) अद्यतनीकरण

(xi) प्रसारण की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी – हिन्दी) अद्यतनीकरण

(xii) गणित की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) अद्यतनीकरण

(xiii) पर्यावरण इंजीनियरिंग की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(xvi) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शब्दावली

(xv) विधिक मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(xvi) दर्शनशास्त्र की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(xvii) पत्रकारिता की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) –अद्यतन

(xviii) भाषाविज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) –अद्यतन

(xix) भारतीय ज्ञान की संकल्पनात्मक शब्दावली का शब्दकोश

2. **अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दकोश/शब्दावली तैयार करना – कार्य प्रगति पर है**

(i) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मणिपुरी**)

(ii) भूविज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मणिपुरी**)

(iii) पर्यावरण विज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मराठी**)

(iv) वनस्पति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**तमिल**)

(v) रसायन विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**तमिल**)

(vi) गणित की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**बांग्ला**)

(vii) भौतिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**तमिल**)

(viii) रसायन विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**गुजराती**)

(ix) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**तमिल**)

(x) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मराठी**)

(xi) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**बांग्ला**)

(xii) भौतिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**गुजराती**)

(xiii) कृषि की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संथाली**)

(xiv) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**संथाली**)

(xv) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**उर्दू**)

(xvi) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**कश्मीरी**)

(xvii) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मैथिली**)

(xviii) इतिहास की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**उर्दू**)

(xix) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**बांग्ला**)

(xx) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**पंजाबी**)

(xxi) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**गुजराती**)

(xxii) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**कन्नड़**)

(xxiii) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**उर्दू**)

(xxiv) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**असमिया**)

(xxv) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**तेलुगु**)

(xxvi) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**तमिल**)

(xxvii) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**मराठी**)

(xxviii) अर्थशास्त्र की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**संस्कृत**)

(xxix) मनोविज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**कन्नड़**)

(xxx) मनोविज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मलयालम**)

(xxxi) सूचना प्रौद्योगिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मैथिली**)

(xxxii) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**नेपाली**)

(xxxiii) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मराठी**)

(xxxiv) गणित की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी– **सिंधी**)

(xxxv) गणित की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी– **कोंकणी**)

(xxxvi) कृषि की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी– **कश्मीरी**)

(xxxvii) कृषि की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संस्कृत**)

(xxxviii) वनस्पति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**संस्कृत**)

(xxxix) वनस्पति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**नेपाली**)

(xL) इलेक्ट्रॉनिक्स की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**संस्कृत**)

(xLi) इलेक्ट्रॉनिक्स की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**तेलुगु**)

(xLii) इलेक्ट्रॉनिक्स की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**कश्मीरी**)

(xLiii) इलेक्ट्रॉनिक्स की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**कोंकणी**)

(xLiv) सूचना प्रौद्योगिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संस्कृत**)

(xLv) भौतिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी– **संथाली**)

(xLvi) भौतिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**गुजराती**)

(xLvii) भौतिकी की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संस्कृत**)

(xLviii) इंजीनियरिंग की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**उड़िया**)

(xLix) फार्मेसी की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**उड़िया**)

(L) प्राणीशास्त्र की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी– **संथाली**)

(Li) अर्थशास्त्र की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मैथिली**)

(Lii) पूंजी बाजार और उससे जुड़ी शब्दावली (अंग्रेजी–हिंदी–**संस्कृत**)

(Liii) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**मराठी**)

(Liv) मनोविज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी– **संथाली**)

(Lv) मनोविज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–**मलयालम**)

(Lvi) मनोविज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मलयालम**)

(Lvii) वाणिज्य की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संस्कृत**)

(Lviii) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**संस्कृत**)

(Lix) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**मैथिली**)

(Lx) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**सिंधी**)

(Lxi) पत्रकारिता की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिन्दी–**उड़िया**)

(Lxii) रसायन विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**मैथिली**)

(Lxiii) रसायन विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**सिंधी**)

(Lxiv) रसायन विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी– हिंदी–**संस्कृत**)

(Lxv) प्राणीशास्त्र की शब्दावली (अंग्रेजी–**कोंकणी**)

(Lxvi) वनस्पति विज्ञान की शब्दावली (अंग्रेजी–**कोंकणी**)

(Lxvii) रसायन विज्ञान की व्यापक शब्दावली (अंग्रेजी– **कोंकणी**)

(Lxviii) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**संस्कृत**)

(Lxix) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**कोंकणी**)

(Lxx) राजनीति विज्ञान की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**नेपाली**)

(Lxxi) इतिहास की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी–**नेपाली**)

3. पारिभाषिक शब्दकोशों की तैयारी – कार्य प्रगति पर है

(i) इलेक्ट्रॉनिक्स का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतनीकरण

(ii) राजनीति विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतनीकरण

(iii) भारतीय संविधान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी)

(iv) कृषि का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) अद्यतनीकरण

(v) ऑपरेशनल रिसर्च का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी)

(vi) रसायन विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतनीकरण

(vii) गणित का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतनीकरण

(viii) द्रव्यसुना का परिभाषाषिक शब्दकोश (संस्कृत–अंग्रेजी–हिन्दी)

(ix) अर्थशास्त्र का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी) – अद्यतनीकरण

(x) राजनीति विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–मलयालम)

(xi) राजनीति विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–तमिल)

(xii) राजनीति विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–तेलुगु)

(xiii) राजनीति विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–कन्नड़)

जलवायु विज्ञान का परिभाषाषिक शब्दकोश (अंग्रेजी–हिन्दी)

4. **विभागीय शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है।**

(i) परमाणु की विभागीय शब्दावली

(ii) सिविल इंजीनियरिंग की विभागीय शब्दावली (अंग्रेजी–हिन्दी)

(iii) रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स (सैन्य और नागरिक) की विभागीय शब्दावली

5. **शिक्षार्थियों की शब्दावलियाँ (हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाएँ) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है**

(i) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (गणित)

(ii) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (पर्यावरण विज्ञान)

(iii) माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–2 (कंप्यूटर विज्ञान और गणित)

(iv) माध्यमिक शिक्षार्थी की शब्दावली खंड–2 (विज्ञान)

(v) माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–2 (मानविकी और सामाजिक विज्ञान)

(vi) उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–3 (राजनीति विज्ञान)

(vii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–3 (गणित)

(viii) उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–3 (वाणिज्य)

(ix) उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–3 (मनोविज्ञान)

(x) उच्चतर माध्यमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–3 (पर्यावरण विज्ञान)

(xi) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (पर्यावरण विज्ञान) (अंग्रेजी–**संस्कृत**)

(xii) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (पर्यावरण विज्ञान) (अंग्रेजी–**गुजराती**)

(xiii) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (पर्यावरण विज्ञान) (अंग्रेजी–**मैथिली**)

(xiv) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (कंप्यूटर विज्ञान और गणित) (अंग्रेजी–**संस्कृत**)

(xv) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (कंप्यूटर विज्ञान और गणित) (अंग्रेजी–**गुजराती**)

(xvii) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (कंप्यूटर विज्ञान और गणित) (अंग्रेजी–**मैथिली**)

(xviii) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (पर्यावरण विज्ञान) (अंग्रेजी–**उड़िया**)

(xviv) प्राथमिक शिक्षार्थी शब्दावली खंड–1 (कंप्यूटर विज्ञान और गणित) (अंग्रेजी–**उड़िया**)

6. **मोनोग्राफ और पत्रिकाओं जैसे ज्ञान गरिमा सिंधु और विज्ञान गरिमा सिंधु के माध्यम से हिंदी में तकनीकी साहित्य का प्रकाशन – कार्य प्रगति पर है**

(i) खेल भारतीय सन्दर्भ–क्रिकेट पौराणिक पक्ष में

(ii) मानव स्वास्थ्य एवं पोषण

(iii) ज्ञान गरिमा सिंधु (अर्थशास्त्र पर विशेषांक खंड–60)

(iv) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–76)

(v) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–78–79)

(vi) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–102)

(vii) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–103)

(viii) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–107)

(ix) विज्ञान गरिमा सिंधु – (खंड–114)

(x) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–117)

(xi) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–118–119)

(xii) विज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–121–122)

(xiii) विज्ञान गरिमा सिंधु – (महासागर और ध्रुवीय विज्ञान पर विशेष अंक)

(xiv) विज्ञान गरिमा सिंधु (आयुर्वेद पर विशेष अंक)।

7. **प्रचार कार्यक्रम – कॉलेजों/विश्वविद्यालयों/वैज्ञानिक संस्थानों/पीएसयू और आयोग में वेबिनार, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से वर्ष के दौरान लगभग 2400 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।**

(i) गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर, पंजाब (10–11 मार्च 2023)

(ii) जेएनवीयू विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान (13–14 मार्च 2023)

(iii) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली (21 मार्च 2023)

(iv) आईसीएआर–भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, पालमपुर (हि.प्र.)) (27–28 अप्रैल 2023)

(v) पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात (27–29 मार्च 2023)

(vi) बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार (18–19 मई 2023)

(vii) एसवीटीयू, भिलाई (सी.जी.) (23–24 जून 2023)

(viii) शासकीय आरएमडी गर्ल्स पी.जी. कॉलेज, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़) (20–21 जुलाई 2023)

(ix) एसएसबी कॉलेज हापुड़ (यूपी) (09–10 अगस्त 2023)

(x) श्री श्री विश्वविद्यालय, कटक (16–18 अगस्त 2023)

(xi) केआईएसएस, भुवनेश्वर, ओडिशा (17–18 अगस्त 2023)

(xii) महाराजा रणजीत सिंह कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल साइंसेज, इंदौर (म.प्र.) (01–02 सितंबर 2023)

(xiii) टीआरसी लॉ कॉलेज,बाराबंकी (यूपी) (09–10 सितंबर 2023)

(xiv) पीएएचईआर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राजस्थान) (15–16 सितंबर 2023)

(xv) सीकेबी कॉलेज टेओक, जोरहाट (असम) (22–23 सितंबर 2023)

(xvi) हिंदी दिवस, सीएसटीटी, नई दिल्ली (29 सितंबर 2023)

(xvii) सीएसटीटी और भारतीय भाषाएं, सीएसटीटी, नई दिल्ली (10 अक्टूबर 2023)

(xviii) एचएनबीजी विश्वविद्यालय, श्रीनगर गडवाल (यू.के.) (12–13 अक्टूबर 2023)

(xix) एसजीआरआर विश्वविद्यालय, देहरादून (यूके) (27–28 अक्टूबर 2023)

(xx) एसएसएन कॉलेज, दिल्ली (08 नवंबर 2023)

(xxi) भाषा शब्दावली एवं संस्कृति, सीएसटीटी, नई दिल्ली (15 नवंबर 2023)

(xxii) संविधान दिवस वेबिनार, सीएसटीटी, नई दिल्ली (28 नवंबर 2023)

(xxiii) प्रशासनिक/तकनीकी हिंदी शब्दावली, सीएसटीटी, नई दिल्ली (29 नवंबर 2023)

8. **सहायता अनुदानः** आयोग अप्रत्यक्ष रूप से सहायता अनुदान प्रदान करके विभिन्न ग्रंथ शिक्षाविदों, विश्वविद्यालय कक्षों, पाठ्यपुस्तक उत्पादन बोर्डों के माध्यम से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की किताबें प्रकाशित करता है। इस वर्ष के स्वीकृत बजट की आवंटन राशि प्रक्रियाधीन है।

9. **ई–प्रकाशन/मुद्रण के अंतर्गत प्रकाशन (शब्दावली, पत्रिकाएँ आदि)**

   (i) विज्ञान गरिमा सिंधु – खंड 115

   (ii) विज्ञान गरिमा सिंधु – खंड 116

   (iii) विज्ञान गरिमा सिंधु – खंड 120

   (iv) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–64)

   (v) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–68. भारतीय विदेश नीति पर विशेष अंक।)

   (vi) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–70–71 एनईपी–2020 पर विशेष अंक)

   (vii) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–75)

   (viii) ज्ञान गरिमा सिंधु (खंड–77)

10. **प्रदर्शनीः– वर्ष 2023–24ः–**

   भारत के विभिन्न स्थानों पर पुस्तक–प्रदर्शनियाँ आयोजित की गई।

   (i) विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली (25 फरवरी– 05 मार्च 2023)

   (ii) पारुल विश्वविद्यालय, वडोदरा, गुजरात (27–29 मार्च 2023)

   (iii) एनबीटी, लेह (12–16 जुलाई 2023)

   (iv) एनबीटी, पुणे (14–15 सितंबर 2022)

   (v) विश्व पुस्तक मेला, नई दिल्ली, कोच्चि, केरल (01 –26 अक्टूबर 2023)

   (vi) उदिची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा (07–15 अक्टूबर 2022)

   (vii) आईबीसीसी, गोवा (27–29 अक्टूबर 2023)

   (viii) कलिंग पुस्तक मेला, भुवनेश्वर, उड़ीसा (17 नवंबर 26 नवंबर 2023)

11. **विभिन्न संगठनों/संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (वर्ष 2023–24)**

   (i) संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन (एसपीएफ)

   (ii) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे (आईआईटीबी)

समझौता ज्ञापन की मुख्य बातें

- सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली तैयार करने पर सहयोगात्मक रूप से कार्य करना
- शब्दावली की तैयारी में प्रौद्योगिकी का परिचय देना
- भारतीय भाषाओं में मशीन लर्निंग में शब्दावली का उपयोग करना

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (सीएसयू)

संस्कृत ने सभी भारतीय भाषाओं और यहां तक कि कुछ विदेशी भाषाओं के विकास और विशेष रूप से भारत और सामान्य रूप से विश्व की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग सभी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है और कोई भी भारतीय भाषा संस्कृत के भाषाई सहयोग के बिना समृद्ध नहीं हो सकती। सभी भारतीय भाषाएं संस्कृत की समृद्धता से विकसित और पल्लवित होती हैं। संस्कृत प्राचीन विज्ञानों का सैद्धान्तिक आधार भी प्रदान करती है। तथापि भारत के सर्वांगीण विकास के लिए संस्कृत का संरक्षण एवं प्रचार–प्रसार आवश्यक हो जाता है। इस उत्तरदायित्व के प्रति सचेत भारत सरकार ने संस्कृत भाषा, साहित्य और पारंपरिक शास्त्रों के प्रचार–प्रसार और संरक्षण व देश और विदेश में संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर, 1970 में सोसायटी

पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान की स्थापना की। यह सूचित किया जाता है कि भारत के माननीय, राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के बाद संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान (समवत विश्वविद्यालय) को अब केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के रूप में प्रख्यापित किया गया है और इसे दिनांक 30 अप्रैल, 2020 को भाषा प्रभाग, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत 17 अप्रैल, 2020 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. 1263 (ई) के माध्यम से लागू किया गया है। विश्वविद्यालय पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है और संस्कृत भाषा और संस्कृति से संबंधित सभी नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य संस्कृत अधिगम और अनुसंधान का प्रचार, विकास और प्रोत्साहन करना है। चूंकि संस्कृत हमेशा पाली और प्राकृत भाषाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए 2009–10 से, विश्वविद्यालय ने पाली और प्राकृत दोनों भाषाओं और उनके साहित्य को बढ़ावा देने का कार्य किया है। विश्वविद्यालय अपने सभी परिसरों के लिए केंद्रीय, प्रशासनिक और समन्वयक तंत्र के रूप में भी कार्य करता है। भारत सरकार ने संस्कृत शिक्षा के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम तैयार किए हैं और इन्हें केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्य एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित कर रही है और विश्वविद्यालय अपनी स्थिति के आधार पर, बहु–परिसर इकाई शास्त्रों, संस्कृत भाषा और साहित्य से संबंधित सभी प्रयासों के समन्वय के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और यूजीसी द्वारा 7 मई 2002 से समवत विश्वविद्यालय घोषित किया गया है।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय वर्तमान में इलाहाबाद (यूपी), पुरी (उड़ीसा), जम्मू (जम्मू और कश्मीर), त्रिशूर (केरल), जयपुर (राजस्थान), लखनऊ (यूपी), श्रृंगेरी (कर्नाटक), बलहार (हिमाचल प्रदेश), भोपाल (एमपी), मुंबई (एमएच), अगरतला (त्रिपुरा) और देवप्रयाग (उत्तराखंड) में स्थित अपने 12 परिसरों का प्रबंधन कर रहा है और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय कार्यालय है। परिसर विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं और आचार्य और शास्त्री स्तर पर विभिन्न संस्कृत विषयों में शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं। 10 परिसरों में शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) भी उपलब्ध है और शिक्षा आचार्य (एम.एड.) जयपुर, भोपाल और पुरी में 3 परिसरों में उपलब्ध है।

उच्चतम ग्रेडिंग ए++ से मान्यता प्राप्त एनएएसी पीयर टीम द्वारा दौरा 2023:–

राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी), बैंगलोर की सहकर्मी टीम ने 25 अप्रैल, 2023 से 27 अप्रैल, 2023 तक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, नई दिल्ली और उसके परिसरों का दौरा किया है। दौरे के बाद केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय को उसके सभी परिसरों के साथ उच्चतम ग्रेडिंग ए++ से मान्यता दी गई है।

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय शास्त्री (बीए) और आचार्य (एमए) स्तरों पर विभिन्न विषयों जैसे व्याकरण, साहित्य, फलित ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष, दर्शन, वेद, न्याय, मीमांसा, अद्वैत वेदांत, धर्म शास्त्र, वेदांत, सांख्य योग, पौरोहित्य, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, पुराणेतिहास, हिंदू अध्ययन और नाट्यशास्त्र में अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन के साथ पारंपरिक विषयों में शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, स्नातक स्तर पर एक आधुनिक विषय जैसे राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि के लिए ट्यूटोरियल सुविधा भी प्रदान की जाती है। शिक्षा शास्त्री (बी.एड.) और शिक्षा आचार्य (एम. एड.) के पाठ्यक्रम भी परिसरों में संचालित किए जाते हैं। परिसर में विद्यावारिधि (पीएचडी) की डिग्री के लिए अनुसंधान कार्यक्रम भी प्रदान किया जाता है।

विश्वविद्यालय में वर्तमान वर्ष के लिए लगभग 10,000 छात्रों का नामांकन किया गया।

मुख्य गतिविधियाँ

i. अखिल भारतीय रूपक महोत्सव :–

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री सदाशिव परिसर, पुरी में दिनांक 02.02.2023 से 04.02.2023 तक अखिल भारतीय संस्कृत रूपक महोत्सव का आयोजन किया गया। विभिन्न परिसरों के छात्रों ने विभिन्न नाटकों में भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी परिसरों सहित 22 आदर्श महाविद्यालयों ने भाग लिया। क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहे कैम्पस/आदर्श महाविद्यालय ने अखिल भारतीय स्तर के रूपक महोत्सव में भाग लिया।

ii. 60वीं अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता (अखिल भारतीय शास्त्री स्पर्धा) :–

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 60वीं अखिल भारतीय भाषण प्रतियोगिता 22–25 मार्च, 2023 तक काशी में आयोजित की गई। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के माध्यम से 320 छात्रों का चयन किया गया। कार्यक्रम का उद्‌घाटन काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रो नागेंद्र पांडे ने किया। यह आयोजन प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी की अध्यक्षता में हुआ। इस कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बीएचयू के कुलपति प्रो. विजय कुमार शुक्ल उपस्थित थे।

iii. 'याज्ञसेनी' राष्ट्रीय सम्मेलन 2023:–

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संगीत नाटक अकादमी और डब्ल्यू 20 के सहयोग से 27 से 28 जुलाई 2023 तक कमानी ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में 'याज्ञसेनी' पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा 'याज्ञसेनी' का संस्कृत अनुवाद जारी किया गया।

iv. संस्कृत सप्तोत्सवः –

विश्वविद्यालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, संस्कृत भारती और अन्य संगठनों के सहयोग से 08 से 14 अगस्त, 2023 तक संस्कृत सप्ताहोत्सव मनाया।

v. मेरी माटी मेरा देश उत्सवः –.

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने 17 अगस्त, 2023 को श्री सदाशिव परिसर, पुरी में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान का जश्न मनाया। माननीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे थे। माननीय कुलपति प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी भी 'मेरी माटी मेरा देश' के राष्ट्रीय मिशन को बढ़ावा देने के लिए छात्रों

और बुद्धिजीवियों के लिए गैलक्सी में उपस्थित थे।

vi. लक्ष्मीपुराण पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और श्री सदाशिव परिसर, पुरी का शिलान्यास समारोह, 100 करोड़ की विकास परियोजनाएँ: –

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री सदाशिव परिसर, पुरी ने दिनांक 18.11.2023 से 20.11. 2023 तक समानता, सशक्तिकरण और मुक्ति पर एक नया प्रवचन, बलराम दास के लक्ष्मीपुराण पर तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने 100 करोड़ रुपये तक की अनुमानित परिसर विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी।

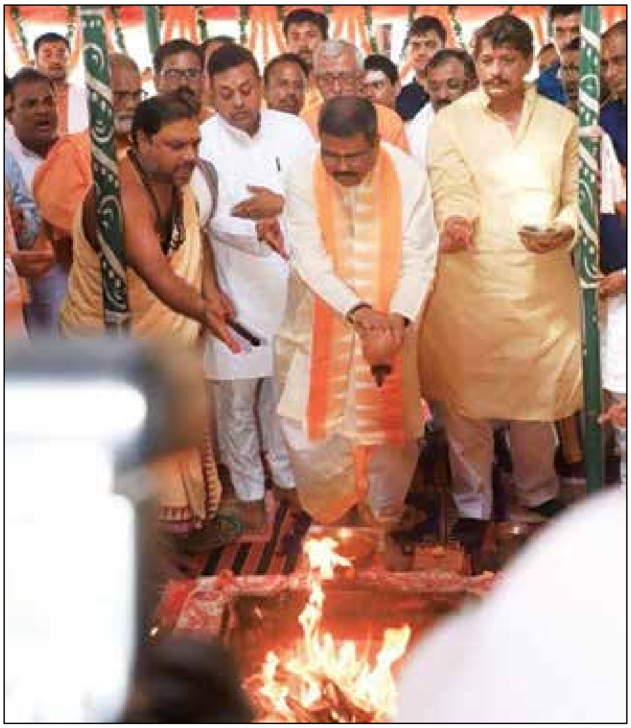

vii. ई–ऑफिस प्रणाली का कार्यान्वयन: –

विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के मुख्यालय कार्यालय और परिसरों में ई–ऑफिस प्रणाली लागू की है।

विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता

I. संस्कृत शिक्षण के लिए वित्तीय सहायताः

क) पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/संस्कृत महाविद्यालयों में संस्कृत शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत चयनित संगठनों को पारिश्रमिक के रूप में संस्कृत शिक्षकों को एक वर्ष में 12 महीनों के लिए 20,000/— रुपये प्रति माह, अंशकालिक शिक्षकों/कंप्यूटर शिक्षकों को एक वर्ष में 12 महीनों के लिए 10,000/— रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा रही है। छात्रों को आवासीय छात्रवृत्ति के मामले में 10 महीने के लिए 600/— रुपये प्रति माह।

ख) पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में आधुनिक विषय के शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/महाविद्यालयों में काम करने वाले आधुनिक विषय शिक्षकों को 20,000/— रुपये प्रति माह और अंशकालिक शिक्षकों के लिए 10,000/— रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक के साथ वर्ष में 12 महीनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

ग) राज्य सरकार के स्कूलों से संबंधित माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए संस्कृत शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत एक संस्कृत शिक्षक को 12 महीने के लिए 20,000/— रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जहां राज्य सरकार ऐसा करने के लिए संस्कृत शिक्षण सुविधाएं प्रदान करने में सक्षम नहीं है।

घ) चतुष्पथी के तहत संस्कृत शिक्षकों के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत चतुष्पथी संस्थानों में कार्यरत संस्कृत शिक्षकों को 12 महीने के लिए 5,000/— रुपये प्रति माह के पारिश्रमिक पर वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 2023—24 के दौरान संस्कृत शिक्षण के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत 498 संस्कृत संस्थानों/संगठनों को 2800 लाख रुपये की वित्तीय सहायता जारी की गई है।

II. विपन्न परिस्थितियों में प्रतिष्ठित संस्कृत पंडितों को सम्मान राशि के लिए वित्तीय सहायता।

योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के प्रख्यात संस्कृत विद्वानों को सम्मान राशि के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिन्होंने अपना जीवन संस्कृत को समर्पित कर दिया है, लेकिन उनके पास आय का कोई निश्चित स्रोत नहीं है। चयनित विद्वानों को अन्य स्रोतों से आय में कटौती किए बिना, प्रति वर्ष 60,000/— रुपये दिए जाएंगे। इस योजना से कुल 164 पंडित लाभान्वित हो रहे हैं।

III. संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों/गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली एनजीओ/संस्कृत विश्वविद्यालयों/विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा किए गए संस्कृत के विकास और प्रसार के लिए

विभिन्न कार्यक्रमों पर शत–प्रतिशत अनुमोदित व्यय को पूरा करता है। वर्ष 2023–24 के दौरान इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

IV. प्रख्यात शास्त्री विद्वानों या सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों (शास्त्र चूड़ामणि) की सेवाओं के उपयोग के लिए वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत पारंपरिक संस्कृत महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों और स्वैच्छिक संगठनों में प्रख्यात शास्त्री विद्वानों या सेवानिवृत्त संस्कृत विद्वानों की सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न केंद्रों पर विभिन्न शास्त्रों के गहन अध्ययन को संरक्षित करना है जहां पारंपरिक प्रणाली के साथ संस्कृत छात्रों को संस्कृत शिक्षा प्रदान की जाती है। योजना के अनुसार, पारंपरिक विद्वानों को विभिन्न संगठनों में नियुक्त किया जाता है। 41 विद्वानों को दो वर्ष की अवधि के लिए 20,000/– रुपये प्रति माह का भुगतान किया जा रहा है। सहायता अनुदान समिति की अनुशंसा पर नियुक्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

V. पारंपरिक संस्कृत पाठशालाओं/संस्थानों के छात्रों के लिए "व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम" संचालित करने के लिए पंजीकृत शैक्षणिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

इस योजना के तहत चयनित संगठनों को कार्यशाला का आयोजन करने और फैशन डिजाइन, प्रबंधन, मंदिर संस्कृति, प्राकृतिक भाषा प्रक्रिया, होटल प्रबंधन, पाका शास्त्र (भोजन बनाना), खेती, ऐप्स, पर्यटन, आतिथ्य, एमओओसी विकास, पांडुलिपि विज्ञान, कैटलॉगिंग, पेलोग्राफी, अनुष्ठान, संस्कृत टाइपिंग और शॉर्टहैंड, संस्कृत रचना और प्रूफ़ रीडिंग और एपिग्राफी, रत्न परीक्षा पाठ्यक्रम का संचालन करने के लिए प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 1,00,000/– रुपये की दर से वित्तीय सहायता जारी की जाती है। वर्ष 2023–24 के दौरान इस योजना के लिए 50.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

VI. संस्कृत छात्रवृत्ति–

संस्कृत/पाली/प्राकृत में छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्कृत पाठशाला/संस्कृत महाविद्यालय/ संस्कृत विश्वविद्यालय में पारंपरिक स्ट्रीम या स्कूल/कॉलेज/ विश्वविद्यालय आधुनिक स्ट्रीम में पूर्व–मध्यमा (प्रथम वर्ष)/9वीं कक्षा, पूर्व–मध्यमा (द्वितीय वर्ष)/10वीं कक्षा, उत्तर–मध्यमा/प्राकशास्त्री (प्रथम वर्ष)/11वीं कक्षा, उत्तर–मध्यमा/प्राक–शास्त्री (द्वितीय वर्ष)/12वीं कक्षा, शास्त्री/बी.ए. (प्रथम/ द्वितीय/तृतीय वर्ष), आचार्य/एम.ए. (प्रथम/ द्वितीय वर्ष), विद्यावारिधि/पीएचडी या उसके समकक्ष में मुख्य या वैकल्पिक विषय के रूप में नियमित रूप से संस्कृत/पाली/प्राकृत का अध्ययन करने वाले छात्रों को संस्कृत प्रोत्साहन योजनाओं के तहत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। छात्रवृत्ति की दरें इस प्रकार हैं:–

कक्षा	छात्रवृत्ति दर
• 9वीं और 10वीं या समकक्ष पाठ्यक्रम	= रु. 5000/– प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा
• 11वीं और 12वीं या समकक्ष पाठ्यक्रम	= रु. 6000/– प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा
• स्नातक या समकक्ष	= रु 8000/– प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा
• स्नातकोत्तर या समकक्ष	= रु. 10,000/– प्रति वर्ष प्रत्येक कक्षा
• पीएच.डी. या समकक्ष	= रु. 35,000/– प्रति वर्ष *(केवल तीन वर्षों के लिए)*

योजना के तहत प्रत्येक वर्ष प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है। समय–समय पर भारत सरकार की नीति के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाएगा। विश्वविद्यालय ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 1200 लाख रुपये आवंटित किए हैं, तदनुसार, पारंपरिक और आधुनिक विषयों के 17895 छात्रों को संस्कृत प्रोत्साहन योजना के तहत छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना गया है।

VII. अष्टदशी (18 परियोजनाएँ)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने संस्कृत दस वर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के विकास के लिए दीर्घकालिक विजन और रोडमैप का सुझाव देने के लिए श्री एन गोपालस्वामी, कुलाधिपति, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति की अध्यक्षता में एक तेरह (13) सदस्यीय समिति का गठन किया था। समिति की प्रमुख सिफारिशों में, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत के विकास इंजन को अपेक्षित बढ़ावा देने के लिए अष्टदशी योजना (18 परियोजनाएं) शुरू की है। इस योजना के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान 4.99 करोड़ रुपये की लागत से 49 संस्थानों/संगठनों/विश्वविद्यालयों/एनजीओ/कॉलेजों को लाभ मिल रहा है।

VIII. केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय 22 **आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों** और 4 **आदर्श शोध संस्थानों** को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित हैं। वर्ष के दौरान, एएसएम/एएसएस के लिए 4797.68 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई और इन 26 संस्थानों के 4337 छात्र लाभान्वित हुए।

IX. वर्ष के दौरान **अखिल भारतीय वाग्मिता प्रतियोगिता** के आयोजन के लिए इस योजना के लिए 90.00 लाख आवंटित किए गए हैं।

X. संस्कृत शब्दकोश परियोजना, पुणे – डेक्कन कॉलेज, स्नातकोत्तर और अनुसंधान संस्थान, पुणे ने ऐतिहासिक सिद्धांतों पर विश्वकोश संस्कृत शब्दकोश की तैयारी के लिए परियोजना शुरू की। इस परियोजना के व्यय का मुख्य स्रोत केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान इस परियोजना के लिए कुल 70.00/– लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

XI. पाली और प्राकृत विकास परियोजना – पाली और प्राकृत विकास परियोजना भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की पहल पर वर्ष 2009 में शुरू की गई थी। इस परियोजना को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली की नियमित योजना के रूप में शामिल किया गया है। इस परियोजना की गतिविधियाँ विश्वविद्यालय के मुख्यालय, नई दिल्ली और इसके जयपुर और लखनऊ परिसरों में की जाती हैं। परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए कार्यशालाएँ और सेमिनार आयोजित किए गए। पाली और प्राकृत साहित्य पर स्वाध्याय सामग्री और रचनाएँ प्रकाशित की गई हैं। उल्लेखनीय कार्य भी प्रकाशन हेतु प्रेस में हैं। इस वर्ष पाली एवं प्राकृत के विकास के लिए 100.00 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

XII. संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई–डेटा बैंक – सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते चलन को देखते हुए, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत के विकास के लिए ई–पुस्तकें और जर्नल विकसित किए हैं। ई–पुस्तकें विकसित की गई हैं ताकि छात्र/विद्वान अपने घर से आराम से इन पुस्तकों तक पहुंच सकें। ये पुस्तकें छात्रों/विद्वानों की आवश्यकता के अनुसार संस्कृत सीखने की सुविधा प्रदान करती हैं। 551 संस्कृत पुस्तकें हैं जो दुर्लभ हैं, उन्हें स्कैन किया गया

है। इसके अलावा, 117 ई–पुस्तकें और एक ई–जर्नल हैं जो वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को यूआरएल www.sanskrit.nic.in से एक्सेस किया जा सकता है। विश्वविद्यालय के संस्कृत वार्ता त्रैमासिक समाचार बुलेटिन और संस्कृत विमर्श ख्अर्धवार्षिक शोध जर्नल, को डिजिटल सामग्री के रूप में प्रकाशित और अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा, परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है (क) संस्कृत साहित्य का राष्ट्रीय ई–डेटा बैंक, (ख) पुस्तक अनुवाद, संस्कृत मोबाइल ऐप, मशीन अनुवाद और संस्कृत पर बिग बुक प्रोजेक्ट आदि जैसे विभिन्न विषयों पर प्रमुख और छोटी परियोजनाएं।

XIII. पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए विशेष प्रावधान– विश्वविद्यालय स्वैच्छिक संस्कृत संगठनों के शिक्षकों को वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय और एनईआर में विभिन्न सेमिनारों, राष्ट्रीय संस्कृत नाटक/महोत्सव के आयोजन के लिए अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 20 गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के छात्रों को 51.84 लाख रुपये की छात्रवृत्ति राशि आवंटित की गई है।

XIV. केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, दिल्ली भी प्रचालन में है

(1) दूरस्थ शिक्षा (डीई) – संस्थान

दूरस्थ शिक्षा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त है जिसमें 26 (छब्बीस) देशों से 9000 (नौ) हजार से अधिक छात्रों ने अपना पंजीकरण कराया है और इसका वर्तमान सत्र जनवरी 2024 से शुरू किया गया है। यहां यह उल्लेख करना बहुत महत्वपूर्ण है कि डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एडवांस सर्टिफिकेट और प्रवीणता स्तर जैसे 45 कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, साथ ही पारंपरिक तथा संस्कृत भाषा और इसकी शास्त्री ज्ञान अर्थव्यवस्था के वैश्विक प्रचार एवं प्रसार के लिए आधुनिक विषयों और कई क्षेत्रों से संबंधित यूजी और पीजी कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं।

(2) अनौपचारिक संस्कृत शिक्षा (एनएफएसई) – कार्यक्रम

इस तथ्य के अलावा एनएफएसई कार्यक्रम का मिशन मानक और सरल संस्कृत भाषा को विकसित करना है। 5000 (पांच) से अधिक छात्रों को गैर–औपचारिक संस्कृत शिक्षा (एनएफएसई) में प्रवेश मिला है जो कई केंद्रीय और राज्य स्तर के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों, आईआईटी और उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए खोला गया है।

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा (केएचएस)

केन्द्रीय हिंदी संस्थान, आगरा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय उपस्थिति वाला एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी और यह एक स्वायत्त संगठन, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा द्वारा अभिशासित है। मंडल अपने तत्वावधान में केंद्रीय हिंदी संस्थान चलाता है। संस्थान को **व्यावहारिक हिंदी भाषाविज्ञान और कार्यात्मक हिंदी में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए एक उन्नत केंद्र के रूप में मान्यता प्राप्त है।** इसके मुख्यालय में 08 शैक्षणिक विभाग हैं और 08 क्षेत्रीय केंद्र दिल्ली, मैसूर, हैदराबाद, गुवाहाटी, शिलांग, दीमापुर, भुवनेश्वर और अहमदाबाद में स्थित हैं। ये केंद्र शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, तुलनात्मक और विरोधाभासी भाषाविज्ञान में अनुसंधान और अनुभव क्षेत्र के हिंदी सीखने वालों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण सामग्री

तैयार करने में भाग लेते हैं। इसके अलावा, संस्थान के पास नागालैंड, मिजोरम और उत्तरी गुवाहाटी सरकार के स्वामित्व और अभिशासित 03 संबद्ध कॉलेज हैं।

संस्थान हिंदी शिक्षण एवं प्रशिक्षण के 16 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित करता है। संस्थान द्वारा 2022–23 तक **98895** से अधिक भारतीय और विदेशी छात्रों/शिक्षकों/छात्र–सह–शिक्षकों/सेवारत शिक्षकों और अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है। मुख्यालय और दिल्ली केंद्र में विभिन्न देशों के **7723** विदेशी छात्रों ने "विदेश में हिंदी प्रचार योजना" कार्यक्रम के तहत केएचएस से हिंदी सीखी है।

01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक सत्र 2023–24 के दौरान संस्थान का योजना–वार प्रदर्शन यहां दिया गया है: –

(ख) शिक्षण कार्यक्रम

1. **व्यावसायिक पाठ्यक्रम (शाम के कार्यक्रम)**– ये कार्यक्रम मुख्यालय और दिल्ली केंद्र पर आयोजित किए जाते हैं–

   (i) अनुवाद में डिप्लोमा: सिद्धांत और अभ्यास
   (ii) मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता में डिप्लोमा

   } कुल **43** छात्र

2. **विदेशियों के लिए हिंदी शिक्षण कार्यक्रम:**

   यह कार्यक्रम "विदेश में हिंदी का प्रचार–प्रसार" योजना के अंतर्गत प्रदान

(क) प्रशिक्षण कार्यक्रम (अध्यापक शिक्षा विभाग)

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	छात्रों की संख्या	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
1.	**हिंदी शिक्षण निष्णात (एम. एंड के समकक्ष)** यह कार्यक्रम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।	08	05
2.	**हिंदी शिक्षण पारंगत (बी. एंड के समकक्ष)** यह कार्यक्रम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है।	47	49
3.	**हिंदी शिक्षण प्रवीण (डी. एल. एंड के समकक्ष)** यह कार्यक्रम मुख्यालय में आयोजित किया जाता है	38	48
4.	नागालैंड के लिए तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम	18	

संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रम:

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	पाठ्यक्रम
1.	मिज़ोरम हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, आइज़वाल (मिज़ोरम)	हिंदी शिक्षण पारंगत, प्रवीण और हिंदी शिक्षक डिप्लोमा प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष।
2.	सरकारी हिंदी संस्थान दीमापुर (नागालैंड)	तीन वर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा (प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष)
3.	सरकारी हिंदी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, उत्तरी गुवाहाटी, असम	हिन्दी शिक्षण पारंगत

किया जाता है। वर्तमान वर्ष में 102 विदेशी छात्रों को प्रवेश दिया गया है, जिनमें से 84 आगरा मुख्यालय में तथा 18 दिल्ली केंद्र में हैं।

3. **लघु अवधि पाठ्यक्रम**

इस योजना के तहत, अल्पकालिक कार्यक्रम– अभिविन्यास, संवर्धन और भाषा जागरूकता कार्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। 01 जनवरी, 2023 से 31 दिसम्बर, 2023 तक 43 ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और अब तक 2095 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

(ग) **सेमिनारः** आगरा मुख्यालय, मैसूर, हैदराबाद, दिल्ली, गुवाहाटी, शिलांग, भुवनेश्वर, दीमापुर, अहमदाबाद केंद्र द्वारा 22 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किए गए हैं।

(घ) **शोध एवं भाषा विकास विभागः** रिपोर्टिंग सत्र के दौरान विभाग द्वारा संस्थान की त्रैमासिक शोध पत्रिका गवेषणा के कुल 2 अंक (अंक संख्या 131–132) प्रकाशित किए गए। इसके अतिरिक्त गवेषणा के संपादन अंक (अंक संख्या 133–134) का प्रकाशन कार्य प्रगति पर है।

(ङ) **पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सामग्री निर्माण विभाग की गतिविधियाँ**– रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान भारत की विभिन्न भाषाओं के हिंदी लोक साहित्य के निर्माण के लिए कुल 11 कार्यशालाएँ आयोजित की गई।

(च) **प्रकाशन** – संस्थान ने जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक निम्नलिखित शब्दकोश, पुस्तकें और पत्रिकाएँ प्रकाशित की हैं।

(I) पुस्तकें

1. मेरी लघु कथाएँ
2. सिंगापुर में भारत
3. जीवित रहेगी स्त्री
4. ऑस्ट्रेलिया से कहानियाँ
5. सांख्य योग दर्शन
6. डॉलर का नोट
7. चेहरो पर टंगी तख्तियां
8. तुम ना समझ
9. निरी लोक साहित्य
10. जमातिया लोक साहित्य
11. फिजी हिंदी का विश्वपटल
12. हिन्दी संताली शिक्षार्थी शब्दकोश

(II) पत्रिका एवं पत्रिकाएँ

1. प्रवासी जगत– खंड–5, अंक–1 अक्टूबर–दिसंबर, 2021
2. प्रवासी जगत– खंड–5, अंक–2– जनवरी–मार्च, 2022
3. प्रवासी जगत– खंड–5, अंक–3– अप्रैल–जून, 2022
4. प्रवासी जगत– खंड–5, अंक–4– जुलाई–सितंबर, 2022
5. शैक्षिक उन्मेष– खण्ड–4, अंक–4 जुलाई–सितम्बर, 2021
6. शैक्षिक उन्मेष– खंड–5, अंक–1 अक्टूबर–दिसम्बर, 2021
7. भावक– खंड–04, अंक–2 जनवरी–मार्च, 2022
8. भावक– खंड–04, अंक–3 अप्रैल–जून, 2022
9. भावक– खंड–04, अंक–4 जुलाई–सितंबर, 2022
10. भावक– खंड–05, अंक–1 अक्टूबर–दिसंबर, 2022
11. भावक– खंड–05, अंक–2 जनवरी–मार्च, 2023
12. गवेषणा अंक–129– जुलाई–सितंबर, 2022

13. गवेषणा अंक–130– अक्टूबर–दिसंबर, 2022
14. गवेषणा अंक–131– जनवरी–मार्च, 2023

(छ) पुस्तकालय

दिनांक 01 जनवरी 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक आगरा मुख्यालय में 2058 पुस्तकें खरीदी गईं। इन पुस्तकों का मूल्य 1456308.00 रूपये है।

महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन (एमएसआरवीवीपी)

राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की स्थापना जनवरी 1987 में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी। मई 1993 में प्रतिष्ठान का कार्यालय उज्जैन स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद, भारत सरकार द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से प्रतिष्ठान का नाम बदलकर 'महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान' कर दिया गया। प्रतिष्ठान को शिक्षा मंत्रालय से सीधे अनुदान सहायता मिलती है। वर्ष 2023–24 के लिए प्रतिष्ठान का वार्षिक बजट 137.50 करोड़ रुपये है।

उद्देश्य

प्रतिष्ठान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:–

(क) वैदिक अध्ययन की मौखिक परंपरा का संरक्षण, परिरक्षण और विकास;

(ख) मानव एजेंसी के माध्यम से स्वर–उच्चारण और वाचन की परंपरा को बढ़ावा देना;

(ग) पाठशालाओं के साथ–साथ अन्य माध्यमों और संस्थाओं के माध्यम से वेदों का अध्यापन और अध्ययन;

(घ) विलुप्त हो रहे सखाओं पर विशेष ध्यान देना तथा मानवीय एजेंसियों के माध्यम से उनका संरक्षण करना;

(ङ) अनुसंधान सुविधाओं का निर्माण और प्रचार ताकि वेदों में निहित ज्ञान की समृद्ध संपदा को सामने लाया जा सके और इसे समकालीन आवश्यकताओं से जोड़ा जा सके;

प्रस्तावित कार्यक्रम

प्रतिष्ठान को मंत्रालय की योजनाओं अर्थात वैदिक अध्ययन के प्रचार–प्रसार के लिए वैदिक पाठ की मौखिक परंपरा का संरक्षण को लागू करने की जिम्मेदारी दी गई है। इस उद्देश्य के लिए प्रतिष्ठान उत्तर–पूर्वी राज्यों सहित देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न वेद पाठशालाओं/विद्यालयों और गुरु शिष्य परंपरा (जीएसपी) इकाइयों को हर महीने वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दिनांक 1–1–2023 से 31–12–2023 की अवधि के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अनुमोदित वेद पाठशालाओं/विद्यालयों और जीएसपी इकाइयों का विवरण इस प्रकार है: –

वेद पाठशाला और गुरु शिष्य परम्परा (जीएसपी) योजना

वर्ष 2022–23	वित्तीय सहायता के लिए अनुमोदित संस्थानों की कुल संख्या	वेद एवं अन्य शिक्षकों की संख्या	आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त छात्रों की संख्या	दिसंबर, 2023 तक मंत्रालय द्वारा जारी कुल अनुदान (करोड़ रुपये में)
वेद पाठशाला के लिए	118	598	3452	47.92
जीएसपी इकाइयों के लिए	292	292	2234	

प्रतिष्ठान में वेदों/वेदों की शाखाओं अर्थात ऋग्वेद शाकल शाखा, शुक्ल यजुर्वेद माध्यंदिनी शाखा, शुक्ल यजुर्वेद कण्व शाखा, कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा, सामवेद कौथुम शाखा, सामवेद राणायनी शाखा, सामवेद जैमिनी शाखा, अथर्ववेद शौनक शाखा एवं अथर्ववेद पैप्पलाद शाखा का अध्ययन करने के लिए एक निर्धारित पाठ्यक्रम है।

प्रतिष्ठान एक पत्राचार पाठ्यक्रम **"घर बैठे वेदों की शिक्षा"** भी संचालित करता है। पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैदिक अध्ययन को बढ़ावा देना और लोगों को सभी चार वेदों, छह वेदांगों, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, भारतीय संस्कृति और दर्शन के महत्व और भूमिका के बारे में सामान्य ज्ञान प्रदान करना है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों को **"वेद निपुण"** का प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय

शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी से वर्ष 2018–19 से महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन के परिसर में एक राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय की स्थापना की गई थी।

वित्त मंत्रालय/शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से देश के पांच क्षेत्रों – उत्तरी क्षेत्र के लिए बद्रीनाथ के पास, दक्षिण क्षेत्र के लिए श्रृंगेरी के पास, पूर्वी क्षेत्र के लिए पुरी, पश्चिमी क्षेत्र के लिए द्वारका और उत्तर–पूर्व क्षेत्र के लिए गुवाहाटी में पांच नए राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। द्वारका और पुरी में दो आरएवीवी ने काम करना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा द्वारका, पुरी और गुवाहाटी आरएवीवी के लिए भी भूमि आवंटित की गई है।

महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड

एमएसआरवीवीपी, उज्जैन के तहत महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद संस्कृत शिक्षा बोर्ड (एमएसआरवीवीएसबी) की स्थापना के लिए शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है और बोर्ड को नियमित स्कूल बोर्डों के समकक्ष मान्यता एआईयू द्वारा प्रदान की गई है, जो समकक्षता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।

प्रवेश नीति

प्रतिष्ठान दो मुख्य पाठ्यक्रम अर्थात् **वेद भूषण** और वेद **विभूषण** चलाता है, पांचवीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र या पांचवीं कक्षा में प्रवीणता प्राप्त करने वाला छात्र **वेद भूषण पाठ्यक्रम** में प्रवेश ले सकता है । वेद भूषण में पांच वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद, छात्र दो वर्षीय **वेद विभूषण पाठ्यक्रम** में प्रवेश ले सकता है।

गतिविधियाँ

- **वृद्ध वेदपाठियों और नित्यग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता:** प्रतिष्ठान 65 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध वेदपाठियों, दिव्यांग वेदपाठियों और नित्यग्निहोत्रियों को 5000/– रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023–24 में 17 वृद्ध और दिव्यांग वेदपाठियों और 41 नित्यग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
- **वैदिक सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सभी के लिए वैदिक कक्षाएं, वेद ज्ञान सप्ताह समारोह और विभिन्न अन्य कार्यक्रमों का संगठन:** वैदिक सम्मेलन और सेमिनार, सभी के लिए वैदिक कक्षाएं और वेद ज्ञान सप्ताह समारोह प्रतिष्ठान के कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और देश में वैदिक अध्ययन और ज्ञान को लोकप्रिय बनाने का साधन हैं। दिनांक 1–1–2023 से 31–12–2023 की अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान ने उज्जैन, अहमदाबाद, तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, विजयवाड़ा, पटना, नई टेहरी, टेहरी गढ़वाल, चित्तौड़गढ़, जम्मू, चेन्नई में वैदिक सम्मेलन, कोलकाता नई दिल्ली, गुवाहाटी, मेदिनीपुर, छपरा, श्रीनगर–कश्मीर, होशियारपुर, सिलचर, में वैदिक सेमिनार, चित्तौड़गढ़, हुगली, उदयपुर, लखीमपुर–खीरी में वेद ज्ञान सप्ताह समारोह, उज्जैन, कोलकाता,

हुगली में सभी के लिए वैदिक कक्षाएं, वाराणसी में वेद जागरण यात्रा प्रतिष्ठित वैदिक संस्थानों के साथ सहयोग आयोजित किए थे।

- **प्रकाशनः** नए शोध को बढ़ावा देने और विद्वानों तथा आम लोगों को लाभान्वित करने के लिए, प्रतिष्ठान **हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं में "वेदविद्या" नामक अर्ध–वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है।**

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल)

राष्ट्रीय सिंधी भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीएसएल) की स्थापना 26.05.1994 को वडोदरा, गुजरात में पंजीकरण संख्या 1085 के तहत सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (धारा 21) के तहत शिक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त पंजीकृत संगठन के रूप में की गई थी। परिषद का मुख्यालय वर्ष 2006 से दिल्ली में है। परिषद का उद्देश्य सिंधी भाषा को बढ़ावा देना, विकसित करना और प्रचार करना है तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के ज्ञान के साथ–साथ विकसित विचारों का ज्ञान सिंधी में उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई करना है साथ ही आधुनिक संदर्भ में और सिंधी भाषा से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देना है।

❖ परिषद के उद्देश्य

- सिन्धी भाषा का प्रचार, विकास एवं प्रचार–प्रसार करना।
- वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली विकास के ज्ञान के साथ–साथ आधुनिक संदर्भ में विकसित विचारों के ज्ञान को सिंधी भाषा में उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई करना।
- सिंधी भाषा से जुड़े और शिक्षा से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार को परामर्श देना।
- सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार के लिए परिषद द्वारा उचित समझे जाने वाले अन्य कोई भी कार्यकलाप करना।

सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार एवं विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैंः–

- सिंधी भाषा से संबंधित चयनित प्रचार गतिविधियों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता;
- शैक्षिक संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों/ सार्वजनिक पुस्तकालयों आदि में निःशुल्क वितरण के लिए संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान प्रकाशित/निर्मित सिंधी से संबंधित सिंधी पुस्तकों/पत्रिकाओं/ ऑडियो–वीडियो कैसेटों की थोक खरीद;
- सिंधी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता;
- सिंधी भाषा सीखने की कक्षाएं संचालित करना; और
- साहित्यिक पुस्तकों के लिए सिंधी लेखकों को पुरस्कार।

❖ स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता

एनसीपीएसएल सिंधी भाषा से संबंधित कुछ प्रचार गतिविधियों के संबंध में पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों को तदर्थ वित्तीय सहायता प्रदान करता है। स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/ धर्मार्थ बंदोबस्ती/ट्रस्ट जो वर्तमान में प्रचलित प्रासंगिक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, वे इस योजना के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे।

बशर्ते कि ऐसा पंजीकरण ऐसी सहायता के लिए आवेदन की तारीख से कम से कम तीन पूर्ण कैलेंडर वर्ष पूर्व किया गया हो, और बशर्ते कि आवेदक संगठन ऐसा न हो कि वह पंजीकृत या निगमित हो या इस प्रकार कार्य करता हो कि उसकी गतिविधियों से उत्पन्न किसी भी प्रकार का लाभ उसके सदस्यों या शेयरधारकों के बीच

बोनस या लाभांश के रूप में वितरित किया जाता हो।

❖ थोक खरीद योजना

थोक खरीद योजना भारत में सिंधी भाषी लोगों के लिए उपयुक्त साहित्य और अन्य पढ़ने के साथ–साथ संदर्भ सामग्री प्रदान करने के उद्देश्य से सिंधी में मानक साहित्य के उत्पादन के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूलों/कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों को निःशुल्क उपहार के रूप में विवेकपूर्ण रूप से चयनित पुस्तकों और पत्रिकाओं की आपूर्ति करके सिंधी के अध्ययन में रुचि पैदा करना है जहां सिंधी का उपयोग शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाता है/या जहां इसे एक वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है।

सिंधी भाषा के प्रचार–प्रसार और लेखकों को मूल्यवान पुस्तकें/पत्रिकाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित करने और ऑडियो–वीडियो कैसेट/ सीडी/वीसीडी/डीवीडी आदि का उत्पादन करने के लिए तथा थोक खरीद समिति की सिफारिशों के बाद कार्यकारी बोर्ड के अनुमोदन के बाद, पूरे भारत में 150 स्कूलों/कॉलेजों/ पुस्तकालयों/शैक्षणिक संस्थानों में वितरण के लिए योजना के तहत चयनित पुस्तकों/ पत्रिकाओं/ऑडियो–वीडियो कैसेट/सीडी/ वीसीडी/डीवीडी की प्रतियां खरीदी जाती हैं।

❖ पुस्तकों/पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायतां

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार के प्रकाशन विचारार्थ योग्य हैं:

1. संदर्भ पुस्तकें जैसे विश्वकोश, ज्ञान की पुस्तकें, संकलन और संकलन, ग्रंथसूची और शब्दकोश;
2. दुर्लभ पांडुलिपियों की वर्णनात्मक सूची;
3. अन्य भाषा मीडिया में लिखित सिंधी भाषा के लिए स्वयं प्रशिक्षक;
4. भाषाई, साहित्यिक कृतियाँ, कथा, नाटक, कविता, वैचारिक, सामाजिक, मानवशास्त्रीय और सांस्कृतिक विषयों पर मौलिक लेखन;
5. अनुवाद के साथ या बिना अनुवाद के (अन्य भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी में) पुरानी पांडुलिपियों का आलोचनात्मक संस्करण और/या प्रकाशन;
6. पुस्तकों का सिंधी भाषा में अनुवाद एवं प्रकाशन;

स्वैच्छिक संगठन/सोसायटी/पुण्यार्थ विन्यास /न्यास, जो उस समय प्रचलित प्रासंगिक केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, साथ ही ऐसे व्यक्ति जो लेखक, संपादक, अनुवादक हैं या जो पुस्तक को प्रकाशित करने और विचाराधीन रखने का इरादा तथा तत्संबंधी कॉपीराइट रखते हैं (व्यावसायिक प्रकाशकों को छोड़कर), सहायता के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

योजना के तहत सहायता संबंधित प्रकाशन के लिए कुल अनुमोदित व्यय का 80% और दुर्लभ पांडुलिपियों की वर्णनात्मक सूची के लिए 100% से अधिक नहीं होगी। इस प्रयोजन के लिए, वर्णनात्मक कैटलॉग और अन्य प्रकाशनों के लिए एक प्रिंट ऑर्डर 500 प्रतियों तक सीमित है।

❖ सिंधी भाषा अधिगम पाठ्यक्रम

योजना का उद्देश्य उन लोगों के बीच सिंधी भाषा को लोकप्रिय बनाना और फैलाना है जिन्होंने स्कूलों में सिंधी भाषा का अध्ययन नहीं किया है। यह योजना एक शैक्षिक संस्थान, सामाजिक सेवा संगठनों/सिंधी पंचायतों, राज्य सिंधी अकादमियों और इस उद्देश्य के

लिए एनसीपीएसएल द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य उपयुक्त संगठन द्वारा कार्यान्वित की जाती है। एसएलएलसी तीन प्रकार के होंगे – प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और उन्नत डिप्लोमा पाठ्यक्रम। प्रत्येक पाठ्यक्रम 100 घंटे की अवधि का होगा और इसकी अवधि 12 महीने से अधिक नहीं होगी। एसएलएलसी परीक्षा प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है।

वर्ष 2023–24 के दौरान उपलब्धियां (01.01.2023 से 31.12.2023 तक)

- सिंधी भाषा अधिगम पाठ्यक्रम योजना के तहत वर्ष 2023–24 के दौरान एनसीपीएसएल के सर्टिफिकेट / डिप्लोमा / एडवांस डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 16784 छात्रों ने अपना नामांकन कराया है। देश के विभिन्न भागों में जहाँ बड़ी संख्या में सिंधी आबादी रहती है, वहाँ दिनांक 15.09.2023 से कक्षाएँ शुरू हो गई हैं और जनवरी, 2024 में परीक्षा आयोजित की जाएगी।
- वर्ष 2023–24 के दौरान शैक्षणिक संस्थानों/स्कूलों/कॉलेजों/पुस्तकालयों में निःशुल्क वितरण के लिए थोक खरीद योजना के तहत 148 पुस्तकों और 4 पत्रिकाओं को मंजूरी दी गई है।
- पुस्तकों/पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता योजना के तहत वर्ष 2023–24 के लिए सिंधी लेखकों की 42 पांडुलिपियों और 6 शोध पत्रिकाओं को मंजूरी दी गई है।
- 25 फरवरी से 5 मार्च, 2023 तक एनबीटी द्वारा नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला, 2023 में भाग लिया ।
- दिनांक 31.03.2023 को भोपाल में भारतीय सिंधु सभा द्वारा 'अमर शहीद हेमू कालानी जयंती' पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- एनसीपीएसएल द्वारा दिनांक 10.04.2023 को सिंधी भाषा दिवस मनाया गया।
- एनसीपीएसएल द्वारा 26.05.2023 को स्थापना दिवस मनाया गया।
- एनसीपीएसएल द्वारा 21.06.2023 को योग दिवस मनाया गया।
- सिंधु दर्शन यात्रा समिति द्वारा 26.06.2023 को लेह, लद्दाख में नमामि सिंधु साहित्य, भाषा, संस्कृति, समाज विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- शदानी सेवा मंडल, रायपुर द्वारा दिनांक 25–26 जून 2023 को "सिंधी भाषा एवं साहित्य पर विद्वानों की संगोष्ठी" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- जुलाई, 2023 तक एनबीटी द्वारा लेह, लद्दाख में आयोजित पुस्तक मेले, 2023 में भाग लिया ।
- दिनांक 15.07.2023 को उल्हासनगर में उदय अकादमी द्वारा "भारतीय प्रशासनिक सेवा में सिंधी युवा की भागीदारी" विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया।
- सिंधु एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 20–22 जुलाई, 2023 को उल्हासनगर में सिंधी युवाओं के बीच नाटक और फिल्म लेखन कौशल के विकास के लिए कार्यशाला और संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- दिनांक 27–31 जुलाई 2023 को बीकानेर में नवयुवक कला मंडल द्वारा "मसखरे जी दिल" पर सिंधी नाटक का आयोजन किया गया।
- दिनांक 29.07.2023 को हरिद्वार में "सिंधी भाषा के संवर्धन हेतु हरिद्वार में सिंधी संतो की संगोष्ठी" विषय पर संगोष्ठी।
- सिंधु सखा संगम सांस्कृतिक ट्रस्ट, उल्हासनगर ठाणे द्वारा 30.07.2023 को सिंधी नृत्य नाटक प्रतियोगिता – 'हिकु सोना जो रूपायो' आयोजित की गई।
- दिनांक 30.07.2023 को उदयपुर में विजन सिंधु चिल्ड्रेन एकेडमी द्वारा "उपलब्धियों और राष्ट्रीय

विकास के लिए सिंधी समुदाय का योगदान" विषय पर कार्यक्रम किया गया।

- दिनांक 02.08.2023 को सर्व सेवा समिति, ठाणे द्वारा महाराष्ट्र में "अमर शहीद हेमू कालाणी की जन्म शताब्दी" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- नवयुवक कला मंडल द्वारा 03.08.2023, 05. 08.2023, 06.08.2023 और 09.08.203 को श्रीगंगानगर, अनूपगढ़ और डूंगरगढ़ बीकानेर में 'मशखरे जी दिल' पर कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।
- 11.08.2023 को दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक शिक्षा एवं भारतीय भाषाएँ" विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- 14 अगस्त 2023 को "विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस" विषय पर कार्यक्रम भारतीय सिंधु सभा–कर्णावती द्वारा 13.08.203 को अहमदाबाद में आयोजित किया गया।
- सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा 22.08.2023 को सत्यवती कॉलेज, दिल्ली में ''राज्य भाषा की पहचान और राजनीति सिंधी भाषा के विशेष संदर्भ में'' विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
- भारतीय सिंधु सभा–कर्णावती द्वारा दिनांक 03.09.203 को सरदारनगर, भावनगर में ''नारी शक्ति'' विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- विजन सिंधु चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सिंधी बाल नाटक प्रतियोगिता पर 3 दिवसीय सेमिनार 03.09.2023 को अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा।
- सिंधु साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था द्वारा नाट्य–एक सशक्त माध्यम विषय पर सेमिनार का आयोजन दिनांक 10.09.2023 को अजमेर में किया गया।
- सुधार सभा, अजमेर द्वारा 16–17 अक्टूबर 2023 को ''100 वर्षों (1921–2021) के दौरान सिंधी भाषा संस्कृति और साहित्य के विकास में सुधार सभा का योगदान'' विषयक दो दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- दिनांक 20.10.2023 को जाकिर हुसैन कॉलेज, नई दिल्ली में भारतीय सिंधु सभा द्वारा ''सामाजिक समरसता और सिंधी समाज'' पर सेमिनार का आयोजन किया गया।
- भारतीय सिंधु सभा द्वारा 27.11.2023 को राजस्थान में ''अमर बलिदानी हेमू कालाणी जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में सिंधी लेखक, साहित्यकार, पत्रकार व कविताओं का राष्ट्रीय संगोष्ठी'' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया।
- एनसीपीएसएल दिनांक 1 से 10 दिसंबर , 2023 तक कोच्चि में अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक समिति द्वारा आयोजित पुस्तक मेले, 2023 में भाग लेगा।
- एनसीपीएसएल 9 से 17 दिसंबर 2023 तक एनबीटी द्वारा गोमती, लखनऊ में आयोजित पुस्तक मेले, 2023 में भाग लेगा।

एनसीपीएसएल की योजनाएं सिंधी समुदाय के दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी हैं और वे सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों आदि में भी भाग लेते हैं।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल)

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद, शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो देश में उर्दू, अरबी और फारसी भाषाओं के संवर्धन का कार्य देखता है तथा उर्दू भाषा से जुड़े तथा शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भारत सरकार को परामर्श देता है।

कंप्यूटर एप्लीकेशन और बहुभाषी डीटीपी केंद्रों की स्थापना: वर्ष 2023 के दौरान (31/12/2023 तक), एनसीपीयूएल ने कंप्यूटर एप्लीकेशन, बिजनेस अकाउंटिंग और बहुभाषी डीटीपी (सीएबीए—एमडीटीपी) में एक वर्षीय डिप्लोमा के लिए पंजीकृत एनजीओ के साथ 601 केंद्र जारी रखे। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एनआईईएलआईटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसमें 13411 लड़कियों सहित 30136 छात्रों को प्रवेश मिला ताकि उर्दू भाषी लड़कों और लड़कियों को रोजगार योग्य तकनीकी कार्यबल बनाने के लिए तकनीकी शिक्षा दी जा सके। कार्यान्वयन एजेंसी एनआईईएलआईटी के माध्यम से लगभग 1703 संकायों को 30136 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला।

सुलेख और ग्राफिक डिजाइन केंद्र: पारंपरिक सुलेख को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए 70 सुलेख और ग्राफिक डिजाइन केंद्र जारी रहे, जिसमें इस पाठ्यक्रम में पंजीकृत 2030 लड़कियों सहित लगभग 3500 छात्रों को पढ़ाने के लिए 210 (संकाय + परिचारक) को रोजगार मिला।

उर्दू प्रेस संवर्धन: एनसीपीयूएल समाचार प्रदाता एजेंसी की उर्दू सेवाओं का लाभ उठाने के लिए छोटे और मध्यम उर्दू समाचार पत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। लगभग 814 समाचार पत्रों ने डीएवीपी दर पर विज्ञापन दिये।

प्रकाशन गतिविधियाँ: एनसीपीयूएल भारत सरकार के तहत प्रमुख उर्दू प्रकाशन गृह है। वर्ष में किए गए प्रकाशन कार्य में 23 नए शीर्षक, 24 पुनर्मुद्रण, 60 पाठ्यक्रम पुस्तकें, मासिक पत्रिका उर्दू दुनिया के 12 अंक, 12 ख्वातीन दुनिया, 12 बच्चों की दुनिया और त्रैमासिक पत्रिका फ़िक्र—ओ—तहकीक के 04 अंक प्रकाशित हुए।

पुस्तक प्रचार: बिक्री और प्रदर्शनी के माध्यम से उर्दू पुस्तकों को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक राष्ट्रीय उर्दू पुस्तक मेले का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2023—24 के लिए पुस्तक मेला 06—14 जनवरी 2024 तक मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित किया जाना है। प्रदर्शनी वैन ऑन व्हील की 05 यात्राएँ स्थानीय स्तर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, केरल और तमिलनाडु में की गई हैं। अब तक विभिन्न राज्यों में 10 पुस्तक मेलों में भाग लिया गया है।

शैक्षिक परियोजनाएं/सहयोग: राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद (एनसीपीयूएल) ने शब्दकोश, विश्वकोश, शब्दावली, मोनोग्राफ, वेबसाइट और ई—पब के विकास सहित पुस्तकों के निर्माण की 53 शैक्षिक परियोजनाएं जारी रखीं। विषय पैनलों पर 04 कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार / सम्मेलन / कार्यशालाएं / सांस्कृतिक कार्यक्रम राष्ट्रीय संगोष्ठियाँ:

1. दिनांक 20 फरवरी 2023 को ए.आर. शेख असेंबली हॉल, आजम कैंपस, पुणे में 'द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम' पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
2. कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस अकाउंटिंग और बहुभाषी डीटीपी (सीएबीए—एमडीटीपी) केंद्रों के संबंधित संकायों का एक अभिविन्यास/प्रशिक्षण कार्यक्रम 20 से 23 फरवरी 2023 तक ए.आर. शेख असेंबली हॉल, आजम कैंपस, पुणे में आयोजित किया गया था।
3. दिनांक 17 मार्च 2023 को स्टेन ऑडिटोरियम, इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली में 'भारत की बहुभाषी संरचना में मातृभाषा का महत्व और इसका कार्यान्वयन' पर एक चर्चा आयोजित की गई थी।
4. दिनांक 20 जून, 2023 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, (आईआईसी), लोधी रोड, नई दिल्ली में

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम के सामाजिक और वैज्ञानिक विचार' पर एक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

5. दिनांक 25 से 28 अगस्त 2023 तक चार दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की सुलेख और ग्राफिक डिजाइन कार्यशाला सह प्रदर्शनी के दौरान 26 अगस्त 2023 को किशनगंज बिहार में 'बैत बाज़ी और दस्तूरे हिंद मोसाबेका' पर एक सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

6. दिनांक 30 अगस्त 2023 को 'उर्दू कथा साहित्य में भारत विभाजन की कहानी' पर एक ऑनलाइन चर्चा आयोजित की गई।

7. स्कूल ऑफ आर्ट्स, लैंग्वेजेज एंड लिटरेचर्स एंड मीडिया एजुकेशन अनुसंधान केंद्र, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर के सहयोग से कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर में 11 से 14 सितंबर 2023 तक 'कश्मीर घाटी और उसके आसपास के कामकाजी उर्दू पत्रकारों के लिए क्षमता निर्माण' की चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।

टीवी पर उर्दू दुनिया का निर्माण और प्रसारण— राष्ट्रीय स्तर पर उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए की गई गतिविधियों के बारे में उर्दू आबादी के बीच उर्दू भाषा की जागरूकता को बढ़ावा देने और लोकप्रिय बनाने के लिए, एनसीपीयूएल ने आधे घंटे के साप्ताहिक एपिसोड के निर्माण और प्रसारण के लिए न्यूज 18 टीवी (उर्दू) को नियुक्त किया। न्यूज 18 टीवी (उर्दू) द्वारा 04 एपिसोड का निर्माण और प्रसारण किया गया।

दूरस्थ शिक्षा (उर्दू): एनसीपीयूएल मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों के माध्यम से उर्दू पत्राचार पाठ्यक्रम चलाता है। 940 अध्ययन केंद्र चल रहे हैं और 601 सीएबीए—एमडीटीपी केंद्र हैं, जहाँ कंप्यूटर कोर्स करने वाले शिक्षार्थियों के लिए उर्दू डिप्लोमा अनिवार्य है। इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से लगभग 2230 अंशकालिक उर्दू शिक्षकों को 93996 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला है, जिनमें 45812 छात्राएँ हैं।

अरबी और फ़ारसी को बढ़ावा देना: उपर्युक्त के अतिरिक्त, एनसीपीयूएल को भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए शास्त्रीय भाषाओं अरबी और फ़ारसी को बढ़ावा देने की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। कार्यात्मक अरबी में दो वर्षीय डिप्लोमा और एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स मान्यता प्राप्त केंद्रों और प्रत्यक्ष शिक्षार्थियों के माध्यम से चलाया जाता है। अरबी के 971 अध्ययन केंद्र जिनमें 2546 अंशकालिक शिक्षकों को 64602 शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला है, जिनमें 30822 लड़कियां शामिल हैं, जिन्होंने दोनों पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। फारसी में एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स के लिए 114 केंद्र भी चल रहे हैं, जिनमें 190 अंशकालिक शिक्षकों को 3094 लड़कियों सहित 7249 पंजीकृत छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रम: हस्तशिल्प एवं कालीन क्षेत्र कौशल परिषद, नई दिल्ली के सहयोग से जम्मू—कश्मीर में 06 केंद्रों पर पेपर मशीन में छह महीने का सर्टिफिकेट कोर्स जारी है। इसके अलावा, इन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से 18 संकायों को 177 महिला छात्रों सहित 240 छात्रों को पढ़ाने के लिए रोजगार मिला है।

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति (एनएसयूटी)

राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 के माध्यम से स्थापित एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और दिनांक 30—04—2020 से लागू हुआ। विश्वविद्यालय 60 वर्षों से अधिक समय से संस्कृत अध्ययन, पारंपरिक शास्त्र और शिक्षाशास्त्र में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। विश्वविद्यालय तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) द्वारा पट्टे पर ली गई 55.08 एकड़ भूमि के क्षेत्र में स्थित है। विश्वविद्यालय में 100 शिक्षण कर्मचारी और 100 गैर—शिक्षण कर्मचारी हैं। विश्वविद्यालय 26

विभागों और 4 अध्ययन केंद्रों के माध्यम से सर्टिफिकेट से पीएचडी स्तर तक 31 नियमित कार्यक्रम प्रदान करता है। इसके अलावा, सात कार्यक्रम दूरस्थ और ऑनलाइन मोड के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान नियमित कार्यक्रमों के लिए 2258 छात्रों को प्रवेश दिया है।

शैक्षणिक वर्ष 2023–24 में, विश्वविद्यालय ने चार वर्षीय एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (बीएबीएड) शुरू किया और पहले बैच में 50 छात्रों को प्रवेश दिया। विश्वविद्यालय ने अगामा पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल आयोजित करने के लिए 'अगामा प्रयोगशाला' की स्थापना की। विश्वविद्यालय पुस्तकालय कोहा ओपन–सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम से स्वचालित है। पुस्तकालय ज्ञान संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए कोलन क्लासिफिकेशन (सीसी) प्रणाली का उपयोग कर रहा है। पुस्तकालय में कुल 1.20 लाख पुस्तकों और 166 (भारतीय और विदेशी) पत्रिकाओं का संग्रह है। पुस्तकालय ने विभिन्न विषयों में 14 ई–जर्नल्स की सदस्यता ली है।

अपनी आउटरीच गतिविधि के भाग के रूप में, विश्वविद्यालय तिरुपति और उसके आसपास के विभिन्न स्कूलों में बालगोकुलम कार्यक्रम (बच्चों के लिए संस्कृत सीखना) चला रहा है। तिरुपति और उसके आसपास के लोगों के लिए संस्कृत शिक्षा शिविर (प्रशिक्षण शिविर) आयोजित किए गए। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने इस विश्वविद्यालय को ''संत रामानुजाचार्य जी की 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में संत श्री रामानुजाचार्य जी से संबंधित पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, संपादन और प्रकाशन'' नामक प्रतिष्ठित परियोजना को मंजूरी दी है और यह कार्य प्रगति पर है।

❖ ❖ ❖

11

अनुसंधान परिषदें

अनुसंधान परिषदें

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की स्थापना वर्ष 1969 में भारत सरकार द्वारा देश में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। यह शिक्षा मंत्रालय के तहत भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित शीर्ष सामाजिक विज्ञान अनुसंधान निकाय है। भारत में उच्च शिक्षा के आकार और पैमाने और साथ ही एक बहुलतावादी समाज की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना आईसीएसएसआर की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आईसीएसएसआर विश्वविद्यालयों, शोध संस्थानों, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और कॉलेजों में कार्यरत संकायों/विद्वानों के सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को वित्त पोषित करता है। यह संकायों और शोधकर्ताओं को राष्ट्रीय, वरिष्ठ, पोस्ट–डॉक्टोरल और डॉक्टोरट फेलोशिप प्रदान करता है, सामाजिक विज्ञान और संबंधित नीति मामलों से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर शोध करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाएं आयोजित करता है, सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिकाओं को प्रकाशन सहायता प्रदान करता है, और प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत और विदेशों में अनुसंधान और नीति संस्थानों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भी कार्य करता है।

उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, आईसीएसएसआर के पास कई कार्यक्रम और योजनाएँ हैं जो इस प्रकार हैं:

1. रिसर्च फ़ेलोशिप (डॉक्टोरट, पोस्ट–डॉक्टोरल, वरिष्ठ और राष्ट्रीय फ़ेलोशिप)
2. अनुसंधान कार्यक्रम (अंतरविषयक/बहुविषयक /अंतर–संस्थागत)
3. अनुसंधान परियोजनाएं (प्रमुख, लघु और इम्प्रेस योजना के तहत)
4. संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, सेमिनारों/कार्यशालाओं, प्रकाशनों आदि जैसी गतिविधियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
5. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार
6. आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों के लिए सहायता
7. आईसीएसएसआर क्षेत्रीय केंद्रों के लिए सहायता
8. अनुसंधान पद्धति और क्षमता निर्माण कार्यक्रम
9. प्रकाशन और अनुसंधान सर्वेक्षण
10. व्यावसायिक संघों/संगठनों को पत्रिकाओं के प्रकाशन/संचालन तथा उनके विकास के लिए वार्षिक तदर्थ अनुदान सहायता
11. पुस्तकालय और दस्तावेज़ीकरण (एनएएसएसडीओसी) सेवाएँ
12. अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में पेपर प्रस्तुति के लिए सहायता
13. एक सुपरिभाषित अनुसंधान विचार और आवश्यकता के लिए विदेश में डेटा संग्रह हेतु सहायता

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम की परिकल्पना भारत और विदेशों में सामाजिक वैज्ञानिकों के बीच अकादमिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए की गई है। आईसीएसएसआर का विदेशों में प्रमुख सरकारी स्तर

के सामाजिक विज्ञान संगठनों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग है। भारतीय सामाजिक वैज्ञानिकों/विद्वानों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने और डेटा संग्रह के लिए वित्तीय सहायता (आंशिक/पूर्ण) प्रदान की जाती है। आईसीएसएसआर भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों के आयोजन को बढ़ावा देता है और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों को रखरखाव और विकास अनुदान प्रदान करता है और देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित अपने क्षेत्रीय केंद्रों को पूरी तरह से वित्त पोषित करता है। परिषद वर्तमान में 24 अनुसंधान संस्थानों, 6 क्षेत्रीय केंद्रों और 5 संस्थानों को आईसीएसएसआर–मान्यता प्राप्त संस्थानों की नई श्रेणी के तहत मान्यता प्राप्त है।

परिषद पहले ही पत्रिकाओं के अलावा, अच्छे महत्व के मुद्दों पर बड़ी संख्या में किताबें और मोनोग्राफ प्रकाशित कर चुकी है। आईसीएसएसआर अपने अनुसंधान परियोजनाओं, कार्यक्रमों, फेलोशिप, सेमिनार, सम्मेलन, संयुक्त परियोजनाओं आदि से उत्पन्न पुस्तकों का भी समर्थन करता है। यह अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और सामाजिक मानवविज्ञान, मनोविज्ञान और भूगोल जैसे विभिन्न सामाजिक विज्ञान विषयों में अनुसंधान का सर्वेक्षण भी प्रकाशित करता है। कुल 40 संघों/संगठनों को उनके सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पत्रिकाओं के प्रकाशन और उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान, आईसीएसएसआर ने विभिन्न सामाजिक विज्ञान अनुसंधान डोमेन पर पांच पुस्तकों के प्रकाशन का समर्थन किया है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक) शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना सहायता सेवाएँ प्रदान करता है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों, नीति निर्माताओं, सरकारी विभागों की योजना और अनुसंधान इकाइयों आदि में संकाय और अन्य विद्वान शामिल हैं। विद्वानों और बड़ी संख्या में आईसीएसएसआर अनुसंधान संस्थानों और अन्य अनुसंधान एजेंसियों के लाभ के लिए आईसीएसएसआर, नई दिल्ली के राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नैसडॉक) द्वारा लगभग 1449 नए प्रकाशन और 14 अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय–ई–संसाधनों को जोड़ा गया है।

पिछले वर्षों में प्रदान की गई निरंतर फैलोशिप और परियोजनाओं के अलावा, आईसीएसएसआर ने रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान 483 डॉक्टोरल फैलोशिप, 272 पोस्ट–डॉक्टोरल फैलोशिप, 34 वरिष्ठ फैलोशिप, 99 प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 15 सहयोगी अनुसंधान परियोजनाएं, 501 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार प्रदान किए। अनुसंधान परियोजना प्रभाग के तहत, आईसीएसएसआर ने भारत के अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति, इतिहास और भूगोल के अध्ययन के लिए 373 प्रमुख परियोजनाएं, 417 छोटी परियोजनाएं और 163 विशेष कॉल प्रदान किए। आईसीएसएसआर ने अल्पकालिक अनुभवजन्य अनुसंधान (2023–24) के लिए परियोजना प्रस्तावों के लिए विशेष कॉल के तहत 515 परियोजनाएं प्रदान की हैं।

वर्ष के दौरान, इन अनुसंधान संस्थानों ने 146 नई परियोजनाएँ शुरू कीं, 43 परियोजनाएँ पूरी कीं जबकि 289 परियोजनाएँ चल रही थीं। प्रकाशन की दृष्टि से उन्होंने 39 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। साथ ही, इन संस्थानों द्वारा विभिन्न विषयों पर कुल 315 सेमिनार और सम्मेलन आयोजित किए गए। उपरोक्त के अलावा, संस्थानों और केंद्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और कुल 115 कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें एकेएएम, जनजातीय गौरव दिवस, मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और राष्ट्रीय महत्व की अन्य गतिविधियों के विषय शामिल हैं।

वर्ष 2023 के दौरान आईसीएसएसआर, दिल्ली को अनुदान सहायता के रूप में 205.41 करोड़ रुपये (31 दिसंबर 2023 तक) जारी किए गए। अपेक्षित

आवश्यकता पर अनुमान आवश्यकता पड़ने पर और मांगे जाने पर प्रस्तुत किए गए हैं।

आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के अंतर्गत व्याख्यान श्रृंखला

भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उत्सव के भाग के रूप में आईसीएसएसआर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव (एकेएएम) के तहत स्वतंत्र भारत की उपलब्धि और अपने संबंधित क्षेत्रों में नेतृत्व करने वालो द्वारा सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रयासों के विभिन्न क्षेत्रों में भविष्य की संभावनाओं की समीक्षा करने के लिए व्याख्यानों की एक श्रृंखला शुरू की है।

कैलेंडर वर्ष 2023 में, पहला व्याख्यान 3 फरवरी, 2023 को "भारत में परमाणु ऊर्जा: पिछले 75 वर्षों की उपलब्धियाँ और अमृत काल के लिए संभावनाएं" विषय पर परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर अनिल काकोडकर द्वारा दिया गया था। दूसरा व्याख्यान श्री टी. सुवर्णा राजू, पूर्व सीएमडी, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, द्वारा 8 मई, 2023 को "भारत में वैमानिकी डिजाइन और निर्माण का विकास और अमृत काल की संभावनाएं" विषय पर दिया गया। । तीसरा व्याख्यान 27 जून 2023 को श्री नितिन गडकरी, माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग द्वारा "आजादी के बाद से राष्ट्रीय सड़क नेटवर्क के विकास में हमारी उपलब्धियां और अमृत काल के लिए योजनाएं और संभावनाएं" पर दिया गया था।

अमृत काल विमर्श व्याख्यान श्रृंखला

अमृत काल में सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक नीति पहलों के संबंध में कई पहल की गई हैं। विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को प्राप्त करने के लिए इस अमृत काल में संकल्प से सिद्धि एक मंत्र के रूप में सामने आया है। इन विकास कार्यों की प्रक्रियाओं, प्रभावों और परिणामों की समीक्षा करने और उन्हें विकसित भारत @2047 के संदर्भ में फिर से कल्पित करने के लिए अकादमिक जुड़ाव की आवश्यकता है। इसी संदर्भ में आईसीएसएसआर ने अपने क्षेत्रीय केंद्रों के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में कॉलेजों/विश्वविद्यालयों को "अमृत काल विमर्श: विकसित भारत @2047" विषय पर व्याख्यान श्रृंखला आयोजित करने में सहायता की। इस श्रृंखला के तहत, आईसीएसएसआर ने हमारे शैक्षणिक संस्थानों में राष्ट्र के विकास पर एक संवाद/संवाद संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिसमें संकाय और छात्र भारत में इन जमीनी परिवर्तनों और तेजी से बदलते विकास परिदृश्यों के इर्द–गिर्द एक सार्वजनिक क्षेत्र बना सकते हैं। आईसीएसएसआर ने देश भर में विभिन्न विषयों पर प्रतिष्ठित वक्ताओं द्वारा व्याख्यान आयोजित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसके माध्यम से शैक्षणिक समुदाय, छात्रों और युवाओं को विकसित भारत, हमारी विकासात्मक पहलों की सफलता की कहानियों और उनके सामाजिक प्रभावों के बारे में जानकारी मिलेगी।

इस श्रृंखला में, आईसीएसएसआर ने देश भर में 22 व्याख्यान आयोजित किए, जिनमें प्रतिष्ठित वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर व्याख्यान दिए, जिसके माध्यम से शैक्षणिक समुदाय, छात्रों और युवाओं को विकसित भारत, हमारी विकासात्मक पहलों की सफलता की कहानियों और उनके सामाजिक प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का अधिनियम XXI) के तहत 1972 में की गई थी। परिषद का मुख्य उद्देश्य ऐतिहासिक शोध को उचित दिशा देना और इतिहास के वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। परिषद के व्यापक उद्देश्य इतिहासकारों को एक साथ लाना, उनके बीच विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना, इतिहास की वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत प्रस्तुति व्याख्या को राष्ट्रीय दिशा देना, ऐतिहासिक शोध कार्यक्रमों और

परियोजनाओं को प्रायोजित करना और ऐतिहासिक शोध में लगे संस्थानों और संगठनों की सहायता करना है। परिषद इतिहास के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण रखती है, ताकि इसके दायरे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, कला, साहित्य, दर्शन, पुरालेख, मुद्राशास्त्र, पुरातत्व, सामाजिक–आर्थिक गठन प्रक्रियाओं और मजबूत ऐतिहासिक पूर्वाग्रह और सामग्री वाले संबद्ध विषयों का इतिहास शामिल हो।

01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के लिए लक्ष्य और उपलब्धियाँ दर्शाने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरणः–

क्र. सं.	कार्यक्रम	लक्ष्य	प्राप्त किये गये लक्ष्य
1.	अनुसंधान परियोजनायें	एनए	50
2.	वरिष्ठ शैक्षणिक फेलोशिप	10	09
3.	विदेश यात्रा अनुदान	एनए	एनए
4.	प्रकाशन सब्सिडी	एनए	17
5.	जूनियर रिसर्च फेलोशिप	80	एनए
6.	पोस्ट–डॉक्टोरल फेलोशिप	10	10
7.	अध्ययन–सह–यात्रा अनुदान	एनए	51
8.	इतिहासकारों के पेशेवर संगठनों द्वारा सेमिनार/संगोष्ठी/सम्मेलन आदि।	एनए	97
9.	राष्ट्रीय फेलोशिप	03	03
10.	गुरुकुल फेलोशिप	02	एनए

परिषद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विभिन्न विशेष परियोजनाओं को भी क्रियान्वित कर रही है जैसे (i) भारतीय शिलालेखों में सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक शब्दों का शब्दकोश। (ii) भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इतिहास। (iii) भारत में कस्बों और गांवों का ऐतिहासिक विश्वकोश। (iv) भारत पर विदेशी स्रोतों का अनुवाद। (v) यादवों के इतिहास के लिए स्रोत सामग्री का संग्रह– पश्चिमी क्षेत्र में पाए गए यादव शिलालेखों का प्रलेखन। (vi) सांस्कृतिक विरासत का प्रलेखन और भारत के परिधीय क्षेत्रों/गांवों में म्यूजियम कॉर्नर की स्थापना। (vii) भारत का पर्यावरण इतिहास। (viii) उन्नीसवीं सदी के अंत में भारत, उत्तरी और पश्चिमी भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक इतिहास पर प्रलेखनः जीवन की गुणवत्ता। (ix) पूर्वोत्तर भारत के अभिलेखीय स्रोतों का सर्वेक्षण, संग्रह, प्रलेखन और डिजिटलीकरण। (x) भारत का व्यापक इतिहास। (xi) पश्चिमी भारत में इतिहास की संस्थाएँ और संगठन। (xii) दक्कन के देवगिरि के यादवों के कन्नड़ और संस्कृत शिलालेखों के संग्रह की तैयारी। (xiii) दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट शिलालेखों का एक खंड में संकलन और संपादन। (xiv) भारत की सांस्कृतिक शिक्षा में गीता प्रेस, गोरखपुर का योगदान। राष्ट्रीय और एक आध्यात्मिक यात्रा (xv) हिमाचल प्रदेश का व्यापक इतिहास।

कुल स्वीकृत अनुदान 27.44 करोड़ रुपये में से 31 दिसंबर 2023 तक 27.42 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं.

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद को सोसायटी अधिनियम, 1860 के तहत मार्च 1977 में एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था, लेकिन इसने वास्तव में जुलाई 1981 में काम करना शुरू किया।

परिषद के उद्देश्यः

परिषद की स्थापना भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों और उद्देश्यों के साथ की गई थीः

1. समय–समय पर दर्शनशास्त्र में अनुसंधान की प्रगति की समीक्षा करना;
2. दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं या कार्यक्रमों को प्रायोजित या सहायता करना;

3. दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के संचालन में लगे संस्थानों और संगठनों को वित्तीय सहायता देना;

4. व्यक्तियों या संस्थानों द्वारा दर्शनशास्त्र में अनुसंधान परियोजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण के लिए तकनीकी सहायता या मार्गदर्शन प्रदान करना, और/या अनुसंधान पद्धति में प्रशिक्षण के लिए संस्थागत या अन्य व्यवस्थाओं को व्यवस्थित और समर्थन करना;

5. दर्शनशास्त्र में अनुसंधान गतिविधियों का समन्वय करना और अंतःविषयक अनुसंधान के कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना;

6. दर्शनशास्त्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सेमिनार, विशेष पाठ्यक्रम, अध्ययन मंडल, कार्य समूह/पार्टियाँ और सम्मेलन आयोजित करना, प्रायोजित करना और सहायता करना और इसी उद्देश्य के लिए संस्थान स्थापित करना;

7. दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के लिए समर्पित संकलनों, जर्नल्स, पत्रिकाओं और विद्वतापूर्ण कार्यों के प्रकाशन के लिए अनुदान देना और उनका प्रकाशन भी करना;

8. छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों द्वारा दर्शनशास्त्र में अनुसंधान के लिए फ़ेलोशिप, छात्रवृत्ति और पुरस्कार स्थापित करना और प्रशासित करना।

सरकार से अनुदान: वर्ष 2023–24 के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने 1855 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया है ।

फेलोशिप योजना: इस अवधि के दौरान, परिषद ने 4 वरिष्ठ फेलो (एसएफ), 15 सामान्य फेलो/पोस्ट डॉक्टोरल फेलो (जीएफ/पीडीएफ) और 60 जूनियर रिसर्च फेलो (जेआरएफ) प्रदान किए। वर्तमान में पिछले वर्षों से जारी फेलो की कुल संख्या: राष्ट्रीय फेलो (एनएफ)–4, एसएफ–8, जीएफ/पीडीएफ–30 और जेआरएफ–115 है।

सेमिनार, कार्यशाला आदि: परिषद ने 49 सेमिनारों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, 7 दर्शन संघों के वार्षिक सत्रों, 3 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/सेमिनारों और 5 शिक्षक सम्मेलनों के लिए वित्तीय सहायता का आयोजन/विस्तार किया।

परियोजनाएं: परिषद ने 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक वर्ष में 28 अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की। वर्ष 2020–21 में 38 अनुसंधान परियोजनाएं और पिछले वर्ष 2019–20 और 2019–20 की 6 अनुसंधान परियोजनाएं जारी हैं।

व्याख्यान कार्यक्रम: परिषद ने व्याख्यान कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद, संत सिरोमणि गुरु रविदास जी का समता दर्शन, विचारों में स्वराज पर 10 व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए। स्थानीय स्तर पर दर्शनशास्त्र को बढ़ावा देने के लिए आवधिक व्याख्यान आयोजित करने हेतु 59 महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई। विश्व दर्शन दिवस समारोह के लिए देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 40 विभागों को एक दिवसीय सेमिनार/संगोष्ठी/व्याख्यान आदि आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई। परिषद ने भारतीय दार्शनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाने के लिए क्रमशः 40 और 45 विश्वविद्यालयों/संस्थानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की। परिषद ने आजादी का अमृत 2022 के अंतर्गत 18 व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किए।

प्रकाशन: परिषद ने प्रकाशन के लिए 7 विद्वानों, 1 मोनोग्राफ और 8 पांडुलिपियों को प्रकाशन सब्सिडी की मंजूरी दी। जेआईसीपीआर के 1 खंड, आईसीपीआर के जर्नल और 1 आवधिक जर्नल को दिसंबर 2022 तक प्रकाशित किया गया था। लगभग 29 आईसीपीआर – प्रकाशित पुस्तकों का पुनर्मुद्रण प्रक्रिया में है।

अकादमिक केंद्र में गतिविधियाँ: परिषद ने सेमिनार, वेबिनार, विशेष व्याख्यान जैसे 10 ऑनलाइन/ऑफ़लाइन विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए।

परिषद की विशिष्ट दर्शन संदर्भ लाइब्रेरी में 37,645 से अधिक पुस्तकें, 60 प्रिंट जर्नल हैं और जेएसटीओआर की सदस्यता भी है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस), शिमला

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना 6 अक्टूबर 1964 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 (पंजाब संशोधन) अधिनियम 1957 के तहत की गई थी। शिमला के राष्ट्रपति निवास में स्थित यह संस्थान मुख्य रूप से मानविकी और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्रों में उच्च स्तर के शोध के लिए समर्पित है। संस्थान के शैक्षणिक समुदाय में मुख्य रूप से निवासी फेलो, विजिटिंग प्रोफेसर, विजिटिंग स्कॉलर्स और एसोसिएट्स आदि शामिल हैं, जो अपने व्यक्तिगत शोध को आगे बढ़ाते हैं और औपचारिक और अनौपचारिक रूप से एक–दूसरे के साथ परस्पर वार्ता करते हैं। राष्ट्रपति निवास और प्राकृतिक परिवेश जो इस रियासत का निर्माण करते हैं, मन अनुकूल जीवन जीने और मानवीय स्थिति के विभिन्न पहलुओं की खोज करने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करते हैं।

संस्थान का संगम ज्ञापन अनुसंधान पर अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है:

क) भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान की स्थापना, संचालन और प्रबंधन करना, जो जीवन और विचारों के मौलिक विषयों और समस्याओं की निःशुल्क और रचनात्मक जांच के लिए एक आवासीय केंद्र होगा।

ख) जांच के क्षेत्रों को अंतर–विषयक अनुसंधान को बढ़ावा देना चाहिए;

ग) चिह्नित किये गये क्षेत्रों का गहरा मानवीय महत्व होना चाहिए।

फ़ेलोशिप कार्यक्रम: फ़ेलोशिप कार्यक्रम संस्थान का प्रमुख कार्यक्रम है। राष्ट्रीय अध्येता/अध्येता/टैगोर अध्येता संस्थान में रहते हैं और अपने संबंधित अनुसंधान परियोजनाओं पर शोध करते हैं।

शैक्षणिक कार्यक्रम: रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान निम्नलिखित शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए:

1. **डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान:** 07 दिसंबर 2023 को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्र (आईआईसी), नई दिल्ली के सभागार में 26वां डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्मृति व्याख्यान आयोजित किया गया। डॉ. विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर), नई दिल्ली ने 'भारत की सॉफ्ट पावर क्षमता: चुनौतियां और जिम्मेदारियां' विषय पर व्याख्यान दिया।

2. **सेमिनार, सम्मेलन, संगोष्ठी, अध्ययन सप्ताह और गोलमेज सम्मेलन:**

   रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार/सम्मेलन/कार्यशालाएँ आयोजित की गई:

   (i) आईआईएएस में "न्याय और विश्व" पर अंत:विषयक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया (09–13 जुलाई 2023)

   (ii) विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन (वीआईएफ) नई दिल्ली और विकासशील देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) नई दिल्ली के सहयोग से "आयुर्वेद: विश्व के कल्याण का समग्र विज्ञान" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आईआईएएस (15–16 जुलाई 2023) में हाइब्रिड मोड पर आयोजित किया गया था।

   (iii) आईआईएएस में "भारतीय भाषाओं के अंतरसंबंध" पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया (06–08 अक्टूबर 2023)

(iv) 03–05 नवंबर 2023 को आईआईएएस, शिमला में "साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में: आधुनिक भारत में विद्वान समाज" विषय पर तीन दिवसीय (03 दिवसीय) अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

(v) 20–22 नवंबर 2023 को आईआईएएस में "भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के 75 वर्ष – अमृतकाल में आगे का रास्ता" विषय पर तीन दिवसीय (03 दिवसीय) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

(vi) आईआईएएस में 28–29 नवंबर 2023 को "भारत विभाजन की त्रासदी और भारतीय भाषाओं का साहित्य" विषय पर दो दिवसीय (02 दिवसीय) राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

3. **फेलो द्वारा साप्ताहिक सेमिनारः** फेलो नियमित रूप से साप्ताहिक सेमिनार प्रस्तुत करते हैं जो फेलो द्वारा किए जा रहे प्रोजेक्ट के विषयों से संबंधित होते हैं। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, संस्थान ने 39 साप्ताहिक सेमिनार आयोजित किए।

4. **यूजीसी अंतर–विश्वविद्यालय केंद्र में एसोसिएट्सः** एसोसिएट्स सेमिनार और सम्मेलनों में भी भाग लेते हैं। रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान तिरासी (83) आईयूसी एसोसिएट्स ने शोधपत्र प्रस्तुत किए।

5. **विजिटिंग प्रोफेसरों, विजिटिंग स्कॉलरों और विशेष आमंत्रितों द्वारा विशेष व्याख्यानः** आईआईएएस ने विजिटिंग प्रोफेसरों द्वारा दिए गए 3 व्याख्यान, विजिटिंग स्कॉलर द्वारा 1 व्याख्यान और संस्थान के दो विशेष आमंत्रितों द्वारा 2 विशेष व्याख्यान आयोजित किए।

6. **स्थापना दिवस समारोहः** संस्थान ने 20 अक्टूबर 2023 को अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। संस्थान के कर्मचारियों और फेलो द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

7. **प्रकाशनः** रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान, संस्थान ने 19 पुस्तकें 09 पत्रिकाएँ प्रकाशित कीं। 15 पुस्तकें और 04 पत्रिकाएँ प्रकाशन प्रक्रिया में हैं।

8. **आईआईएएस पुस्तकालयः** पुस्तकालय ने वर्ष भर में 1,50,000 से अधिक और 40,000 जिल्द वाली पत्रिकाओं का एक मजबूत संग्रह तैयार किया है। मुद्रित पुस्तकों और पत्रिकाओं के अलावा, इसके संग्रह में सीडी–रोम, ऑनलाइन डेटाबेस पांडुलिपियाँ, दुर्लभ पुस्तकें, माइक्रोफिल्म और रिपोर्ट आदि जैसे सभी प्रकार के दस्तावेज़ शामिल हैं।

9. **दुर्लभ पुस्तकों और कॉपीराइट पुस्तकों का डिजिटलीकरणः** चूंकि आईआईएएस लाइब्रेरी डिजिटल परिवर्तन को अपनाना जारी रखती है, 2023 डिजिटलीकरण रिपोर्ट सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, अनुसंधान को बढ़ावा देने और अकादमिक समुदाय के लाभ के लिए तकनीकी प्रगति को अपनाने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद (एमजीएनसीआरई), हैदराबाद

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद शिक्षा संबंधी महात्मा गांधी के क्रांतिकारी विचारों की तर्ज पर ग्रामीण उच्च शिक्षा को बढ़ावा दे रही है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के रूपांतरण के लिए सूक्ष्म नियोजन की चुनौतियों का सामना किया जा सके। एमजीएनसीआरई का उद्देश्य ग्रामीण संस्थानों को क्षेत्रीय विकास संस्थानों और ग्रामीण विश्वविद्यालयों के रूप में विकसित करना और

उभरते ग्रामीण व्यवसायों के इर्द–गिर्द तृतीयक स्तर पर विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करना है। परिषद ग्रामीण संस्थानों के आत्मनिर्भरता और क्षेत्र–उन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पहलों को बढ़ावा दे रही है।

उच्च शिक्षा संस्थानों का स्थानीय सरकारों, विकास एजेंसियों, ग्राम सभाओं और उद्योग के साथ जुड़ाव है ताकि ग्रामीण भारत के लिए प्रासंगिक मानव संसाधनों का तालमेल विकसित किया जा सके। इस कार्य में एमजीएनसीआरई उच्च शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अध्ययन का समर्थन करता है ताकि स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण मुद्दो के आध ाार पर ग्रामीण प्रबंधन और भागीदारी तंत्र में शिक्षा को बढ़ावा देकर विकास की जरूरतों और चुनौतियों का समाधान किया जा सके। इस कार्य में अंत:विषयक दृष्टिकोण को अपनाना और ग्रामीण आजीविका और उद्यमिता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यशालाओं के माध्यम से संकाय सदस्यों के साथ काम करना शामिल है। एमजीएनसीआरई के कार्यों में राज्य में प्रासंगिक व्यावसायिक शिक्षा आवश्यकताओं की पहचान करना भी शामिल है, जिन्हें स्थानीय जिला–स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों, मैनुअल, पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो–विजुअल संसाधन सामग्री तैयार करने में सहायता करना, व्यावसायिक शिक्षा पर आउटरीच गतिविधियों का आयोजन करना, संबंधित ग्रामीण व्यावसायिक पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए क्षेत्र कौशल परिषदों, सामाजिक उद्यम, उद्योग के साथ–साथ सेवा क्षेत्र और उच्च शिक्षण संस्थानों सहित उद्यमिता विकास एजेंसियों के साथ नेटवर्किंग करने के द्वारा पूरा किया जा सकता है।

संकाय विकास कार्यक्रम: एमजीएनसीआरई ने "प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण – कौशल प्रयोगशाला पद्धति के लिए सामाजिक कार्य पेशेवरों को कुशल बनाना" विषय पर एक 7 दिवसीय एफडीपी का आयोजन किया है।

इंटर्नशिप: देश भर के विभिन्न राज्यों के उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में महात्मा गांधी राष्ट्रीय इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत काम करने वाले 576 इंटर्न को सम्मानित किया गया है।

अनुसंधान एवं प्रमुख कार्यक्रम: स्कूल में अध्ययनरत छात्रों को उपलब्ध व्यावसायिक विकल्पों की बेहतर समझ प्रदान करने के लिए एससीईआरटी और विश्वविद्यालयों के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा पर 28 कार्य अनुसंधान परियोजनाएं। एमजीएनसीआरई ने 24 प्रमुख शोध परियोजनाएं और 25 लघु शोध परियोजनाएं (जो चल रही हैं) प्रदान कीं, जिससे रचनात्मक नीति निर्माण में सहायता मिलेगी। ग्रामीण भारत के मामलों पर अध्ययन के लिए 20 पीएचडी शोध फेलोशिप प्रदान की गई। एमजीएनसीआरई ने 30 एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट प्रदान किए।

कार्यशालाएँ: एमजीएनसीआरई ने सामाजिक कार्य पाठ्यक्रम में कौशल निर्माण और ज्ञानोदय प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का 7 दिवसीय आवासीय कार्यक्रम विषयों पर दो राष्ट्रीय कार्यशालाएँ कौशल प्रयोगशाला पद्ध ति के लिए एफडीसी एमजीएनसीआरई में आयोजित की गई। प्रतिभागियों में उस्मानिया विश्वविद्यालय, तेलंगाना विश्वविद्यालय, काकातिया विश्वविद्यालय और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के शिक्षक शामिल थे। यह विषय कौशल प्रशिक्षण और विकास, संचार, दृश्य–श्रव्य मीडिया, अभिनव मीडिया कार्यशालाओं, विधि प्रशिक्षण और परिवारों, व्यक्तिगत समूहों और समुदायों के साथ काम करने में प्रयोगशाला दृष्टिकोण को समझने के इर्द–गिर्द घूमता था। ज्ञानोदय संगोष्ठी की अध्यक्षता अध्यक्ष ने की, संसाधन व्यक्तियों ने राष्ट्रीय संस्थानों की स्थिरता ग्रेडिंग, संस्थागत व्यावसायिक शैक्षिक और सामाजिक कार्य कौशल प्रयोगशालाओं पर काम के साथ सफलता की कहानियाँ और चुनौतियाँ प्रस्तुत कीं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), नई दिल्ली

1925 में स्थापित एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) भारतीय उच्च शिक्षा के हितों को आगे बढ़ाने और सवंर्धन के लिए भारत के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को एक साझा मंच पर लाता है। एआईयू के मुख्य उद्देश्य हैं:

क) एक अंतर–विश्वविद्यालय संगठन के रूप में कार्य करना;

ख) सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करना और विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय और आपसी परामर्श की सुविधा प्रदान करना;

ग) विश्वविद्यालयों और सरकार (केंद्र और साथ ही राज्य सरकारों) के बीच एक संपर्क मंच के रूप में कार्य करना और सामान्य हित के मामलों में अन्य विश्वविद्यालयों या निकायों (राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय) के साथ सहयोग करना;

घ) भारतीय और विदेशी दोनों छात्रों को विदेशी योग्यताओं के लिए शैक्षणिक समकक्षता जारी करके सुविधा प्रदान करना ताकि वे उच्च शिक्षा/रोजगार प्राप्त कर सकें।

दिनांक 01–01–2023 से 31–12–2023 तक प्रभाग की गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: –

- छात्रों को लगभग 4,306 समकक्षता प्रमाण पत्र ऑनलाइन मोड में जारी किए गए;
- एआईयू विश्वविद्यालयों के दायरे से बाहर आने वाले गुणवत्ता वाले स्टैंड–अलोन संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए दो वर्षीय पूर्णकालिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) और 04 वर्षीय प्रबंधन में फैलोशिप कार्यक्रम (एफपीएम) को समकक्षता प्रदान करता है, उच्च अध्ययन में प्रवेश के उद्देश्य से उनके पीजीडीएम को भारतीय विश्वविद्यालय के क्रमशः मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और पीएचडी डिग्री के समान मानता है।
- भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने एआईयू को भारतीय स्कूल बोर्डों की योग्यता की समकक्षता प्रदान करने का भी अधिदेश दिया है।
- एआईयू उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश और केंद्रीय/राज्य सरकार के संगठनों/निकायों में रोजगार के उद्देश्य से भारत के केंद्रीय/राज्य स्कूल बोर्डों द्वारा आयोजित संबंधित परीक्षाओं/योग्यता/पाठ्यक्रमों के साथ विदेशी स्कूल बोर्डों के समकक्षता प्रदान करता है।
- **सदस्यता:** आज की तारीख में कुल 974 विश्वविद्यालय एआईयू के सदस्य हैं। इनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, राज्य निजी विश्वविद्यालय, सम विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान शामिल हैं। इसके अलावा, 16 अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी एआईयू के एसोसिएट सदस्य हैं।
- एआईयू ने वर्ष 2023–24 में पांच क्षेत्रीय कुलपति बैठकें और एक वार्षिक आम बैठक और कुलपतियों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है।
- लोकतंत्र की परंपरा को सुदृढ़ करने और उच्च शिक्षा क्षेत्र में महिला छात्र नेताओं को संसद के कामकाज की समझ विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए, एआईयू के तत्वावधान में पहली एआईयू राष्ट्रीय महिला छात्र संसद 14–16 मार्च, 2023 के दौरान डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, भोपाल में आयोजित की गई।

वित्तपोषण

सदस्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त वार्षिक अंशदान, प्रकाशनों और योग्यताओं की समकक्षता के माध्यम से उत्पन्न राजस्व द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित, एआईयू को 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय से 2.25 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्राप्त हुई।

❖ ❖ ❖

12

आईसीसी एवं यूनेस्को

आईसीसी एवं यूनेस्को

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ (आईसीसी)

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रकोष्ठ शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (ईईपी)/समझौता ज्ञापन (एमओयू)/सहयोग ज्ञापन (एमओसी)/आशय की संयुक्त घोषणा (जेडीआई)/आशय पत्र (एलओआई) आदि पर हस्ताक्षर करके शैक्षिक सहयोग और सहयोग के माध्यम से अन्य देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने में सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

1. जी20 शिक्षा कार्यकारी समूह (एडडब्ल्यूजी) और शिक्षा मंत्रियों की बैठक (ईएमएम)

भारत की जी–20 अध्यक्षता के तहत शिक्षा कार्य समूह (एडडब्ल्यूजी) ने शिक्षा के भविष्य के लिए ठोस, सहयोगात्मक और कार्रवाई–उन्मुख कार्यनीतियों और रोडमैप की दिशा में काम किया। चार चयनित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें शामिल हैं (i) मूलभूत शिक्षा को प्राथमिकता देना, (ii) तकनीक–सक्षम शिक्षा का उपयोग करना, (iii) काम के भविष्य के लिए आजीवन सीखने की आवश्यकता पर बल देना और (iv) जी–20 देशों में शैक्षणिक संस्थानों के बीच अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के माध्यम से शिक्षा कार्य समूह ने शिक्षा और प्रशिक्षण के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल किया, महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया और आम सहमति बनाई। कार्यकारी समूह ने पिछली अध्यक्षताओं के विचार–विमर्श के आधार पर शैक्षिक चुनौतियों से निपटने और विभिन्न संदर्भों और क्षेत्रों में बदलते शिक्षा परिदृश्य में अवसरों की खोज करने पर ध्यान केंद्रित किया। इन बैठकों में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार–विमर्श हेतु जी–20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों (यूनेस्को, यूनिसेफ और ओईसीडी) के मध्य गहन चर्चा और सहयागिता देखी गई।

शिक्षा कार्यकारी समूह ने चेन्नई, अमृतसर, भुवनेश्वर और पुणे में चार बैठकें कीं, जिसके बाद पुणे में जी–20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। चारों बैठकों से पहले प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र पर एक सेमिनार और मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें जी–20 सदस्य और आमंत्रित देशों ने भी भाग लिया। "शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की भूमिका" पर एक सेमिनार 31 जनवरी 2023 को चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 1–2 फरवरी 2023 को जी20 प्रथम शिक्षा कार्यकारी समूह (एडडब्ल्यूजी) की बैठक हुई थी।" समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना और नवाचार को बढ़ावा देना" पर एक सेमिनार 15 मार्च 2023 को अमृतसर, पंजाब में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 16–17 मार्च 2023 को जी20 द्वितीय शिक्षा कार्यकारी समूह (एडडब्ल्यूजी) का आयोजन किया गया था। 'भविष्य के कामकाज के संदर्भ में क्षमता निर्माण, आजीवन सीखने को बढ़ावा देना' विषय पर एक सेमिनार 26 अप्रैल 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 27–28 अप्रैल 2023 को जी20 तृतीय एडडब्ल्यूजी बैठक हुई थी। "मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान सुनिश्चित करना" विषय पर एक सेमिनार 19 जून, 2023 को पुणे में आयोजित किया गया था, जिसके बाद 20–21 जून, 2023 को पुणे

में जी20 की चौथी और आखिरी एडडब्ल्यूजी बैठक हुई।

जी20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 22 जून 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। जी20 एडडब्ल्यूजी और शिक्षा मंत्रियों की बैठक का समापन जी20 परिणाम दस्तावेज़ और अध्यक्ष के सारांश के रूप में हुआ। अध्यक्ष के सारांश ने प्रत्येक विषय के तहत जी20 देशों के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। परिणाम प्रलेखनों में शिक्षा कार्यकारी समूह की रिपोर्टः शिक्षा के माध्यम से एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य और जी20 देशों में शिक्षा नीतियों और कार्यक्रमों का संग्रह शामिल था। इन परिणाम प्रलेखनों में प्रत्येक देश की नीतियों और प्राथमिकताओं पर प्रकाश डाला गया, और प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र में चुनिंदा प्रमुख कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया, जिससे देशों के बीच ज्ञान साझा करने को बल मिला तथा चर्चा और कार्रवाई के लिए एक आम शिक्षा एजेंडा निर्धारित हुआ। जी20 शिक्षा कार्यकारी समूह और शिक्षा मंत्रियों की बैठक के अवसर पर यूएई, ओमान, मॉरीशस, यूनिसेफ, ओईसीडी, यूके, सऊदी अरब, जापान और स्पेन के साथ द्विपक्षीय बैठकें आयोजित की गईं।

जी20 को भारत के लोगों तक ले जाने के माननीय प्रधान मंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए, देश भर में विभिन्न 'जनभागीदारी' कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, निजी क्षेत्र, शिक्षा जगत और नागरिक समाज सहित जीवन के सभी क्षेत्रों से लगभग 5.25 करोड़ नागरिक इन जनभागीदारी कार्यक्रमों में शामिल हुए, जिन्होंने जी20 को एक सच्चे 'जन आंदोलन' में बदल दिया।

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 जून 2023 को वीडियो संदेश के माध्यम से पुणे में आयोजित जी20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया

माननीय प्रधान मंत्री 26 सितंबर, 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में भारत मंडपम में जी20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले के उद्घाटन पर संबोधित करते हुए

2. शिक्षा और कौशल विकास पर भारत–अमेरिका कार्यकारी समूह

जैसा कि भारत–अमेरिका 2+2 वार्ता 2022 के दौरान नेताओं द्वारा घोषणा की गई थी, शिक्षा और कौशल विकास पर भारत–अमेरिका कार्यकारी समूह को औपचारिक रूप से 22 मई 2023 को आभासी रूप में शुरू किया गया। कार्यकारी समूह ने भारत और अमेरिका के बीच शैक्षिक सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर विचार–विमर्श करने के लिए चार उप–समितियां नामतः (i) कौशल और व्यावसायिक शिक्षा, (ii) प्रमाणन और मान्यता, (iii) अमेरिकी और भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच मेलमिलाप और (iv) निजी क्षेत्र के साथ जुड़ाव बनाने का निर्णय लिया।

3. माननीय शिक्षा मंत्री का 01 से 03 नवंबर 2023 तक यूएई दौरा

भारत के माननीय शिक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा और कौशल क्षेत्र में पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग, भागीदारी और तालमेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 से 3 नवंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात का दौरा किया। यात्रा के दौरान, भारत गणराज्य की सरकार और संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के बीच शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने, छात्र और संकाय की गतिशीलता को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न अन्य पहलों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साथ ही, यह घोषणा की गई कि सीबीएसई इंडिया बेहतर प्रशासन और भारतीय प्रवासियों के लाभार्थ दुबई में एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री ने आईआईटी दिल्ली–अबू धाबी के अंतरिम परिसर का भी दौरा किया।

4. शिक्षा के क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के साथ भागीदारी।

ऑस्ट्रेलिया के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जेसन क्लेयर ने **27 फरवरी से 2 मार्च, 2023 तक भारत का दौरा किया,** जिसके परिणाम इस प्रकार हैं:

क) दोनों मंत्रियों द्वारा अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता संबंधी तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

ख) माननीय शिक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई जिसमें संस्थागत सहयोग, लंबित छात्र वीजा, अनुसंधान सहयोग और एक संयुक्त एकीकृत और कौशल ढांचे के गठन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई।

ग) ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा इंटरनेशनल एजुकेशन इनोवेशन फंड (आईईआईएफ) क्रिटिकल स्किल्स प्रोजेक्ट की घोषणा की गई थी, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई सरकार भारत में महत्वपूर्ण कौशल पाठ्यक्रमों के विकास पर एक परियोजना देने के लिए 2024 के मध्य तक 1.82 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर प्रदान करेगी।

घ) इस कार्यक्रम में 11 संस्थागत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और दोनों मंत्रियों के सामने आदान–प्रदान किया गया।

ङ) मंत्री ने दोतरफा गतिशीलता के माध्यम से संबंधों को गहरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र जुड़ाव कार्यक्रमों के लिए वेंकटेश्वर कॉलेज (डीयू) और केंद्रीय विद्यालय का दौरा किया।

च) मंत्री के साथ आए ऑस्ट्रेलियाई कुलपतियों के प्रतिनिधिमंडल ने **"भारत में उच्च शिक्षा का बदलता स्वरूप: भविष्य की दिशाएँ और अवसर"** पर चर्चा करने के लिए एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने एनईपी 2020 के तहत शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण की पहल पर चर्चा करने के लिए यूजीसी में एक गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया।

ऑस्ट्रेलिया के माननीय शिक्षा मंत्री श्री जेसन क्लेयर 5–8 नवंबर, 2023 तक पुनः भारत आए, जिसके परिणाम इस प्रकार हैं:

क) पहली **ऑस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा और कौशल परिषद (एआईईएससी) की बैठक** आईआईटी गांधीनगर में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, भारत, शिक्षा मंत्री, ऑस्ट्रेलिया सरकार और कौशल और प्रशिक्षण मंत्री, ऑस्ट्रेलिया सरकार ने संयुक्त रूप से की, और तीन प्रमुख क्षेत्रों अर्थात भावी कार्यबल को आकार देने, शिक्षा में संस्थागत भागीदारी को मजबूत करने और अंतर्राष्ट्रीयकरण के माध्यम से अनुसंधान प्रभाव को बढ़ाने पर चर्चा हुई। बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के उद्योग और शिक्षा जगत के लगभग 70 विशेषज्ञों ने भाग लिया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और ऑस्ट्रेलिया सरकार के शिक्षा विभाग तथा रोजगार और कार्यस्थल संबंध विभाग के बीच एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई।

ख) **माननीय शिक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री के बीच एक द्विपक्षीय बैठक** आयोजित की गई जिसमें अर्हताओं की पारस्परिक मान्यता, छठी ऑस्ट्रेलिया–भारत शिक्षा परिषद बैठक (एआईईसी) के परिणाम, उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के बीच सहयोग, अनुसंधान सहयोग , अनुसंधान विद्वानों और पीएचडी छात्रों के लिए वीजा मुद्दे, भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा कार्यनीति, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा में शिक्षकों के लिए संयुक्त डिग्री और भारत में महत्वपूर्ण कौशल पाठ्यक्रमों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

ग) कौशल, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग के लिए माननीय मंत्रियों के सामने पांच संस्थागत समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और उनका आदान–प्रदान किया गया।

घ) मंत्रियों ने सेंटर फॉर क्रिएटिव लर्निंग, आईआईटी गांधीनगर, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी (पीडीईयू) और विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके), अहमदाबाद का दौरा किया।

ङ) ऑस्ट्रेलियाई पक्ष ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय के परिसरों के उद्घाटन का उत्सव मनाते हुए एक कार्यक्रम आयोजित किया।

ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री, माननीय जेसन क्लेयर, सांसद, वोलोंगोंग विश्वविद्यालय (यूओडब्ल्यू) के कुलपति, प्रोफेसर पेट्रीसिया एम. डेविडसन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलियाई शिक्षा मंत्री, माननीय जेसन क्लेयर, सांसद, ने गिफ्ट सिटी में दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की

5. मई 2023 में माननीय शिक्षा मंत्री की सिंगापुर यात्रा

माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 29–31 मई 2023 तक सिंगापुर का दौरा किया। यात्रा के दौरान माननीय शिक्षा मंत्री ने सिंगापुर के निम्नलिखित मंत्रियों से भेंट की:

क) सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री, श्री लॉरेंस वोंग

ख) व्यापार एवं उद्योग मंत्री, श्री गान किम योंग

ग) वरिष्ठ मंत्री, श्री थर्मन शनमुगरत्नम

घ) सिंगापुर के विदेश मंत्री, डॉ. विवियन बालकृष्णन

ङ) सिंगापुर के शिक्षा मंत्री, श्री चान चुन सिंग

यात्रा के दौरान निम्नलिखित संस्थानों का भी दौरा किया गया:

क) फ्यूचर स्किल्स सिंगापुर

ख) स्पेक्ट्रा सेकेंडरी स्कूल

ग) नानयांग प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय

घ) तकनीकी शिक्षा संस्थान (आईटीई), सिंगापुर

ङ) सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड डिज़ाइन

6. भारत–सिंगापुर हैकथॉन

भारत–सिंगापुर हैकथॉन का तीसरा संस्करण जुलाई 2023 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), गांधीनगर में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम भारत के शिक्षा मंत्रालय के अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एनटीयू), सिंगापुर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। इसमें 600 से अधिक छात्रों, स्टार्ट–अप, निवेशकों, नीति निर्माताओं, कॉरपोरेट्स और शिक्षाविदों ने भाग लिया। भारत सरकार के शिक्षा, कौशल

विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान और सिंगापुर के उप प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री, श्री लॉरेंस वोंग ने हैकथॉन के विजेताओं को सम्मानित किया।

7. ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक

माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 जुलाई 2023 को दक्षिण अफ्रीका के मपुमलांगा प्रांत में आयोजित 10 वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। माननीय मंत्री ने बैठक के दौरान ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों से भी भेंट की।

8. इंडिया पोर्टल में अध्ययन

स्टडी इन इंडिया पोर्टल 3 अगस्त, 2023 को माननीय विदेश मंत्री, श्री एस.जयशंकर और माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा संयुक्त रूप से शुरु किया गया था। पोर्टल एक समर्पित वेबसाइट है जो एक व्यापक मंच प्रदान करती है, यह भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करता है और भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विदेशी छात्रों के लिए प्रवेश और वीज़ा आवेदन प्रक्रियाओं के लिए वन–स्टॉप विंडो है। पोर्टल की शुरुआत के साथ, अब भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश चाहने वाले प्रत्येक अंतरराष्ट्रीय छात्र के लिए शैक्षणिक सत्र 2023–24 के बाद से प्रत्येक पूर्णकालिक या अल्पकालिक पाठ्यक्रम के लिए एसआईआई पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। पोर्टल विदेशी छात्रों को उनके वीज़ा दायित्वों को पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करता है। जब कोई छात्र पोर्टल पर पंजीकरण करेगा तो एक विशिष्ट आईडी जनित होगी, और इस आईडी को वीज़ा आवेदनों के साथ उद्धृत करना होगा।

9. भारत ने वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट

'सबके विश्वास के साथ, सबके विकास के लिए एक साथ' विषय पर द्वितीय वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट सम्मेलन की मेजबानी की। माननीय शिक्षा मंत्री ने 'मानव संसाधनों को भविष्य के लिए तैयार करना' विषय पर विचार–विमर्श किया। ग्लोबल साउथ के 14 देशों – बोत्सवाना, ब्रुनेई दारुस्सलाम, जॉर्जिया, ट्यूनीशिया, ईरान, लाओ पीडीआर, मलावी, म्यांमार, पलाऊ गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ साओ टोमे और प्रिंसिपे, अल्बानिया, मलेशिया, जिम्बाब्वे, कैमरून के मंत्रियों/गणमान्य व्यक्तियों ने सत्र में आभासी रुप से भाग लिया और अपने विचार साझा किए। यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए जी–20 से प्राप्त लाभों को मजबूत करने और आगे बढ़ाने पर विचार–विमर्श करने और समावेशी और न्यायसंगत अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए साझा आकांक्षाओं को प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर था।

10. तंजानिया के राष्ट्रपति को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की गई

10 अक्टूबर, 2023 को तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉ. सामिया सुलुहू हसन को भारत–तंजानिया संबंधों को मजबूत बनाने, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय एकीकरण और बहुपक्षवाद में सफलता प्राप्त करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट (ऑनोरिस कौसा) की उपाधि प्रदान की गई।

केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान; विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर; और शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

जेएनयू के कुलाधिपति श्री कंवल सिब्बल, जेएनयू की कुलपति प्रो. शांतिश्री धुलीपुडी पंडित, तंजानिया का प्रतिनिधिमंडल, 15 अफ्रीकी मिशनों के प्रमुख, गणमान्य व्यक्ति, शिक्षाविद्, भारत में अध्ययन कर रहे तंजानिया के छात्र और मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए।

11. शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) चरण–III

शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) 2018 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय और/या अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता की समस्याओं का संयुक्त रूप से समाधान के लिए भारतीय संस्थानों और 28 चयनित देशों के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करके भारत के उच्च शैक्षणिक संस्थानों के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। अब तक योजना के दो चरण पूरे हो चुके हैं। चरण I (2018–2020, 2023 तक विस्तारित) में 392 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गईं और चरण II (2023–2025) में 266 अनुसंधान परियोजनाएं स्वीकृत की गईं।

तीसरे चरण (2024–2026) के लिए, हमारे अनुसंधान प्रयासों को जी20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा के अनुसार अनुसंधान प्राथमिकताओं के अनुरूप किए जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें उन्नत कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष और रक्षा, अगली पीढ़ी के संचार आदि सहित 12 चयनित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। चरण III प्राप्त हुए 755 प्रस्ताव वर्तमान में में मूल्यांकनाधीन हैं।

अब तक, स्पार्क में 465 विदेशी संकाय दौरे आयोजित किए गए हैं, साथ ही 130 भारतीय संकाय दौरे विदेश में किए गए हैं। 383 कार्यशालाएँ और 50 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए हैं। 154 मोनोग्राफ और 699 जर्नल लेख प्रकाशित किए गए हैं। 30 पेटेंट दायर किए गए हैं, जिनमें से 3 स्वीकृत किए गए हैं।

भारत और यूनेस्को

शिक्षा मंत्रालय संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) की गतिविधियों में सहयोग के लिए नोडल मंत्रालय है। 1946 में अपनी स्थापना के बाद से यूनेस्को का सदस्य होने के नाते, भारत सरकार ने 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए एक अंतरिम भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की। आईएनसीसीयू में शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में पांच उप–आयोग शामिल हैं (प्रत्येक उप–आयोग के लिए 10 "व्यक्तिगत" और 10 "संस्थागत सदस्य–कुल 100 सदस्य")। माननीय शिक्षा मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव (उच्चतर शिक्षा) इसके महासचिव हैं। आईएनसीसीयू का अंतिम बार पुनर्गठन 2020 में किया गया था।

यूनेस्को बजट में वार्षिक योगदान

यूनेस्को को भारत का वार्षिक योगदान लगभग 29 करोड़ रुपये (यूनेस्को के बजट का 1.349% हिस्सा) है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में यूनेस्को क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एक स्थायी भवन बनाया गया है। इसके अलावा, भारत महात्मा गांधी शांति और सतत विकास शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी) के पूरे बजट (3.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष) का समर्थन करता है, जो एशिया–प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला और एकमात्र यूनेस्को श्रेणी–I संस्थान है।

यूनेस्को के अंतर्गत आयोजित सम्मेलनों और बैठकों की मुख्य बातें :

कार्यकारी बोर्ड का 216वां सत्र

भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य मई 2023 में यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 216वें सत्र में राजदूत/भारत के स्थायी प्रतिनिधि (पीआरआई) श्री विशाल वी. शर्मा द्वारा दिया गया था। वक्तव्य में "वसुधैव कुटुंबकम" ("एक पृथ्वी – एक परिवार एक भविष्य") के सार पर जोर दिया गया था जो 20 के समूह (जी20) की भारत की अध्यक्षता का विषय था।

5वां असाधारण सामान्य सम्मेलन यूनेस्को

29–30 जून 2023 के दौरान यूनेस्को के 5वें असाधारण सामान्य सम्मेलन में, सदस्य राज्यों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पूर्ण सदस्यता विशेषाधिकारों के साथ संगठन में फिर से शामिल होने की अनुमति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रकार, अमेरिका जुलाई 2023 में यूनेस्को का 194 वां सदस्य बन गया।

कार्यकारी बोर्ड का 217 वां सत्र

राजदूत/पीआरआई ने अक्टूबर, 2023 में आयोजित कार्यकारी बोर्ड के 217 वें सत्र में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया। उन्होंने चंद्रयान–3 की सफलता की सराहना करते हुए इसे भारत के सार्वभौमिक दर्शन "विश्व एक परिवार है" या "वसुधैव कुटुम्बकम" के आधार पर समस्त मानवता की सफलता बताया।

यूनेस्को का 42 वां महासम्मेलनः

महा सम्मेलन का 42 वां सत्र 7 नवंबर, 2023 से 22 नवंबर, 2023 तक पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राजदूत/पीआरआई ने किया था और उन्होंने 10 नवंबर, 2023 को सामान्य नीति विचार–विमर्श में भारत का राष्ट्रीय वक्तव्य दिया था। सामान्य सम्मेलन द्वारा स्थापित समितियों, आयोगों और अन्य सहायक संगठनों के सदस्यों के लिए चुनाव हुए। भारत को अपने मूल देशों में सांस्कृतिक संपत्ति की वापसी को बढ़ावा देने या अवैध विनियोग (आईसीपीआरसीपी) के मामले में इसकी बहाली के लिए अंतर सरकारी समिति के लिए चुना गया और एशिया प्रशांत समूह से कार्यकारी बोर्ड की सम्मेलनों और सिफारिशों (सीआर) संबंधी समिति के लिए नामांकित किया गया।

विश्व धरोहर सम्मेलन की 24 वीं महासभा :

विश्व धरोहर सम्मेलन की महासभा का 24 वां सत्र 22 से 23 नवंबर 2023 तक यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित किया गया। आम सभा के दौरान विश्व धरोहर समिति का एक असाधारण सत्र आयोजित किया गया, जिसमें भारत को 2024 में दिल्ली, भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाले विश्व धरोहर समिति के अगले सत्र (46वें) के लिए निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। यह पहली बार होगा जब भारत इस प्रतिष्ठित समिति की अध्यक्षता कर रहा है।

प्रमुख उपलब्धियां और पुरस्कार

- विश्व धरोहर समिति ने 18 सितंबर 2023 को सऊदी अरब के रियाद में आयोजित अपने 45 वें विस्तारित सत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित एक शहर, और कर्नाटक में स्थित होयसला के पवित्र समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अंकित किया।
- केरल के कोझिकोड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर को क्रमशः साहित्य और संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए यूनेस्को के प्रतिष्ठित क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था। कोझिकोड, सार्वजनिक पुस्तकालयों के सघन संकेंद्रण के अलावा, वार्षिक केरल साहित्य महोत्सव का एक स्थायी स्थल है और कई पुस्तक महोत्सवों का आयोजन करता है। ग्वालियर में शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत, लोक संगीत और भक्ति संगीत सहित एक समृद्ध और विविध संगीत विरासत है। शहर में प्रतिष्ठित संगीत संस्थान भी हैं और लोकप्रिय त्योहारों का आयोजन भी होता है।
- गुजरात के प्रतिष्ठित गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में बोत्सवाना में अंतर सरकारी समिति के 18वें सत्र के दौरान प्रतिष्ठित यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर (आईसीएच) की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया था।

4. यूनेस्को का मिशेल बैटिस पुरस्कार 2023

तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी के बायोस्फीयर रिजर्व के निदेशक, श्री जगदीश बाकन को भारत में मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में जैव विविधता संरक्षण के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए 'हरित' नौकरियों और माइक्रो–क्रेडिट की शुरुआत के लिए बायोस्फीयर रिजर्व प्रबंधन के लिए 14 जून, 2023 को द्विवार्षिक मिशेल बैटिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

5. सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया–प्रशांत पुरस्कार 2023

भारत के केरल के कुन्नमंगलम भगवती मंदिर में कर्णिकारा मंडपम ने विशिष्ट पुरस्कार प्राप्त किया। हरियाणा, भारत में चर्च ऑफ एपिफेनी; मुंबई, भारत में डेविड सैसून लाइब्रेरी और रीडिंग रूम; और नई दिल्ली, भारत में बीकानेर हाउस को मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2023 में यूनेस्को के साथ सहयोग

- यूनेस्को भारत की अध्यक्षता में जी–20 शिक्षा कार्यकारी समूह के लिए एक प्रमुख ज्ञान साझेदार था। समूह की बैठकें 2023 के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित की गईं।
- यूनेस्को और एनसीईआरटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित कॉमिक बुक ''लेट्स मूव फॉरवर्ड'' का अगस्त 2023 में माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा विमोचन किया गया। ये कॉमिक पुस्तकें स्कूल स्वास्थ्य एवं कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुगम बनाने की दिशा में एक प्रयास है।
- 21 जून, 2023 को यूनेस्को मुख्यालय, पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। यह कार्यक्रम यूनेस्को प्रतिनिधिमंडलों के बीच व्यापक रुप से सफल रहा और इसमें 1000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

महात्मा गांधी शांति एवं शिक्षा संस्थान (एमजीआईईपी)

एमजीआईईपी यूनेस्को की श्रेणी 1 अनुसंधान संस्था है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह की पहली संस्था है, जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने, डिजिटल शिक्षाशास्त्र को नया रूप देने और युवाओं को सशक्त बनाने वाले कार्यक्रमों के माध्यम से एसडीजी 4.7 की दिशा में शिक्षा को रूपांतरित करने पर केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए संस्था का विज़न "बिल्डिंग काइन्डर ब्रेन्स" है जिसे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा (एसईएल) के साथ शिक्षा को रूपांतरित करके प्राप्त किया जा सकता है।

2023 में एमजीआईईपी की प्रमुख उपलब्धियां:

- एमजीआईईपी ने शिक्षार्थियों और युवाओं के लिए पाठ्यक्रमों का एक समूह विकसित और कार्यान्वित किया, जिसमें एसईएल पर जोर दिया गया और 255,000 से अधिक युवाओं और शिक्षार्थियों (48,537) ने पाठ्यक्रमों का लाभ उठाया।
- के–12 शिक्षार्थियों, शिक्षकों, युवाओं और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए नामांकन और प्रशिक्षण संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि। प्रशिक्षित किए गए कुल के–12 शिक्षार्थी 578,571 थे (सितंबर 2023 तक)।
- एमजीआईईपी ने अगले 5 वर्षों के लिए एमजीआईईपी के डिजिटल परिवर्तन (डीटी) और एसईएल पाठ्यक्रमों पर भारत में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
- एसईएल और शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों (27), सरकारी संगठनों (3 एनसीईआरटी, एनबीआरसी, नवोदय समिति), वैश्विक सामूहिक (7: जापान, मालदीव, किर्गिस्तान, क्यूबेक, भूटान, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका), सरकारों (आंध्र प्रदेश, सिक्किम, गुजरात, आईसीसीआर, खेल और युवा मंत्रालय) और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों (यूनिसेफ, यूएनओसीटी, यूएनएओसी) के साथ सहयोग।

ऑरोविले फाउंडेशन

'ऑरोविले' की स्थापना श्री अरबिंदो की आध्यात्मिक सहयोगी 'मदर' ने 28 फरवरी, 1968 को तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पुडुचेरी के बाहरी इलाके में एक अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक टाउनशिप के रूप में की थी, जहां भारत सहित 60 देशों के 3303 लोग एक समुदाय के रूप में एक साथ रहते हैं और मानव एकता के उद्देश्य से सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक और अन्य गतिविधियों में खुद को नियोजित करते हैं। यूनेस्को ने 1966, 1968, 1970, 1983, 2007 और 2017 में छह प्रस्तावों के माध्यम से ऑरोविले की परियोजना का समर्थन किया था। टाउनशिप 1980 से शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है और इसे भारत की संसद द्वारा पारित ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार प्रशासित किया जाता है।

ऑरोविले फाउंडेशन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार ऑरोविले की स्थापना, रखरखाव और विकास पर अपने खर्च को पूरा करने के लिए फाउंडेशन को अनुदान के रूप में आंशिक धनराशि प्रदान करती है। वर्ष 2023–24 के लिए ऑरोविले फाउंडेशन को 59 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

ऑरोविले फाउंडेशन के शासी बोर्ड का पुनर्गठन 6 अक्टूबर 2021 को चार वर्ष की अवधि के लिए सात नामांकित सदस्यों के साथ किया गया था। तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल आर.एन. रवि अध्यक्ष हैं और पुडुचेरी की माननीय उपराज्यपाल डॉ. तमिलिसाई सुंदरराजन नवगठित गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों में से एक हैं। इसके अलावा, ऑरोविले अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का भी 11 अक्टूबर 2021 को चार वर्ष की अवधि के लिए पांच नामांकित सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया गया था। डॉ. जयंती एस. रवि, आईएएस (जीजे:1991), वर्तमान में ऑरोविले फाउंडेशन के सचिव के रूप में कार्यरत हैं।

2023 में प्रमुख गतिविधियाँ

- **अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन**– अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 10 फरवरी से 13 फरवरी 2024 तक ऑरोविले के यूनिटी पैवेलियन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की परिकल्पना फरवरी 2023 में ऑरोविले में आयोजित शिखर सम्मेलन के अनुवर्ती के रूप में की गई थी, जिसका विषय विज्ञान, आध्यात्मिकता और मानव जागृति था। यह अनुवर्ती सम्मेलन सामूहिक स्तर पर चेतना परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के प्रयासों का पता लगाएगा– नए सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक मॉडल जो मानव एकता की अधिक भावना पैदा करते हैं और केवल भौतिक विकास के बजाय आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस सम्मेलन को पुडुचेरी की उपराज्यपाल डॉ. (श्रीमती) तमिलसाई सुंदरराजन ने संबोधित किया।

- **संस्कृत साहित्य महोत्सव** – संस्कृत साहित्य महोत्सव 7 से 8 फरवरी, 2024 तक ऑरोविले के यूनिटी पैवेलियन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन ऑरोविले फाउंडेशन द्वारा प्रसिद्ध और

सुप्रसिद्ध संस्कृत योगदानकर्ता डॉ. सम्पानंद मिश्रा के साथ मिलकर भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के विद्वानों, शिक्षकों और उत्साही लोगों को एक साथ लाना था ताकि संस्कृत के पुनरुद्धार पर चर्चा की जा सके और सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को पहचाना जा सके। इस बात पर ध्यान केंद्रित किया गया कि कैसे संस्कृत, एक भाषा के रूप में राष्ट्रों को एकजुट कर रही है, जबकि संस्कृतियों को समृद्ध कर रही है और प्रौद्योगिकी सहित जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका योगदान है।

- **श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन – 7 शहर 7 थीम** – श्री अरबिंदो अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन – 7 शहर 7 थीम का आयोजन, श्री अरबिंदो की 150 वीं जयंती समारोह के एक भाग के रूप में किया गया था। सम्मेलन परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, युवा मन से श्री अरबिंदो के ज्ञान से प्रेरित एक उज्जवल भविष्य के सह–निर्माताओं के रूप में अपनी क्षमता को अपनाने का आग्रह करता है।

- ऑरोविले के जैव–क्षेत्र में 'स्वच्छता अभियान' की सफाई – कचरा पृथक्करण, हठ योग कार्यक्रम, समूह गायन, वृक्षारोपण जैसी कई विकासात्मक गतिविधियाँ शुरू की गईं ।
- श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती मनाने के लिए राजभवन, चेन्नई, ऑरोविले, कोलकाता, दिल्ली, गुजरात, ओडिशा और भारत के अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम दिनांक 31.8.2024 तक जारी रहेंगे।

- शिक्षा और संस्कृति के महत्व पर जोर देते हुए संस्कृत शिक्षक आवासीय शिविर आयोजित किया गया था।
- ऑरोविले में रचनात्मकता और कलात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने वाली कला, फोटोग्राफी और हस्तशिल्प का जश्न मनाने वाली एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें भारी उत्साह देखा गया।
- भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 8 अगस्त 2023 को ऑरोविले का दौरा किया।

❖ ❖ ❖

भाग - II

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

01

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा

समग्र शिक्षा, प्री–स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक के स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम वर्ष 2017 में तैयार किया गया था, जिसमें तीन पूर्ववर्ती योजनाओं सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) को शामिल करके स्कूली शिक्षा के लिए समान अवसरों और समान अधिगम परिणामों के संदर्भ में स्कूल की प्रभावशीलता में सुधार लाने का व्यापक लक्ष्य रखा गया था। यह योजना शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी–4) के अनुरूप है।

समग्र शिक्षा योजना को राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 (एनईपीः 2020) की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है और इसे 2021–22 से बढ़ाकर 2025–26 कर दिया गया है। यह योजना स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि सभी बच्चों को एक समान और समावेशी कक्षा के माहौल के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, जिसमें उनकी विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं का ध्यान रखा जाए, जिससे वे अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बन सकें।

सरकार ने संशोधित समग्र शिक्षा योजना को पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 2,94,283.04 करोड़ रुपये है, जिसमें 1,85,398.32 करोड़ रुपये का केंद्रीय शेयर शामिल है। समग्र शिक्षा को पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप बनाया गया है।

1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक की गई गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः

1. समग्र शिक्षा के तहत बीआरसी में प्रत्येक ब्लॉक/यूएलबी में करियर काउंसलिंग के लिए एक अकादमिक संसाधन व्यक्ति के प्रावधान के लिए अगस्त 2023 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे, ताकि छात्रों को उनकी पसंद, आवश्यकताओं और शक्तियों के अनुसार उपलब्ध विभिन्न करियर अवसरों को जानने में सक्षम बनाया जा सके।
2. 21 अप्रैल 2023 को सिविल सेवा दिवस, 2023 के अवसर पर लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधान मंत्री पुरस्कार, 2022 आयोजित किया गया था। प्राथमिकता कार्यक्रम 'समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने' में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिए गए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), **2020 पहुँच, समता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पाँच मार्गदर्शक स्तंभों पर आधारित है।** यह हमारे युवाओं को वर्तमान और भविष्य की **विविध राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी। एनईपी 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा को एक एकल जैविक सातत्य के रूप में देखती है और 21 वीं सदी के कौशल** को आत्मसात करने पर जोर देने के साथ–साथ **भारतीय लोकाचार**

और संवैधानिक मूल्यों में निहित है। यह नीति महत्वपूर्ण विषयों/उप–समूहों के साथ–साथ इसके कार्यान्वयन के लिए सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के लिए अलग–अलग समय–सीमा प्रदान करती है। तदनुसार, विभाग ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के लिए कदम उठाने के लिए सूचित किया है।

प्रमुख उपलब्धियां:

- बुनियादी चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुवर्ती के रूप में,बुनियादी चरण के लिए जादुई पिटारा नामक शिक्षण–अधिगम सामग्री का एक संग्रह 20 फरवरी 2023 को शुरु किया गया।
- एनसीएफ–एफएस पर आधारित कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें, जिनमें खेल और अधिगम हेतु इंटरैक्टिव दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान दिया गया है, 5 जुलाई 2023 को जारी की गई।
- एनईपी 2020 के अनुसरण में, स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ–एसई) 23 अगस्त 2023 को जारी की गई। एनसीएफ–एसई के तहत, पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा के 5+3+3+4 डिजाइन पर बल दिया गया है। यह रूपरेखा आधारभूत से लेकर माध्यमिक स्तर तक की संपूर्ण शैक्षिक यात्रा हेतु समाधान दर्शाती है।
- **विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके)** – एनडीईएआर– अनुरूप वीएसके को एक संस्थागत एवेन्यू के रूप में शुरु किया गया था, जो अपने कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा कार्रवाई करने के लिए डेटा–आधारित निर्णय लेने को बढ़ाने के लिए एकीकृत और साझा रूप से 'देखना' सक्षम बनाता है। अभी तक, वीएसके एनसीईआरटी, सीबीएसई और 12 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, पंजाब, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय स्तर पर है।
- **परख:** मानदंडों, मानकों, दिशानिर्देशों की स्थापना करने और छात्र मूल्यांकन से संबंधित गतिविधियों के कार्यान्वयन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 8 फरवरी 2023 को एनसीईआरटी में एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण) की स्थापना की गई है।
- **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)** का उद्देश्य शिक्षकों के व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास को बेहतर बनाना है, ताकि उन्हें यह समझ मिल सके कि उनके प्रदर्शन के संदर्भ में क्या अपेक्षित है और इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है। एनसीटीई ने एक मार्गदर्शक प्रलेखन तैयार किया है जो उन योग्यताओं को रेखांकित करता है जो शिक्षकों के पास अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए होनी चाहिए।
- **राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम)** अल्पकालिक और दीर्घकालिक परामर्श/पेशेवर सहायता के महत्व को रेखांकित करता है। क्षेत्र विशेषज्ञों के साथ व्यापक परामर्श के बाद एक प्रारंभिक दस्तावेज 'एनएमएम पर ब्लूबुक' तैयार किया गया है, जो एक उर्ध्वगामी पहुंच के रूप में है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना है कि परामर्श अभ्यास शिक्षा प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग बन जाए।
- **डिजिटल पहल:** पीएम ई–विद्या के तहत, दीक्षा एक राष्ट्र, एक डिजिटल शिक्षा बुनियादी ढांचा है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दीक्षा में

शामिल किया गया है। यह डिजिटल बुनियादी ढांचा कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है और अत्यधिक मापनीय है। इस बुनियादी ढांचे का उपयोग 31 भारतीय भाषाओं और आईएसएल सहित 7 विदेशी भाषाओं में सक्रिय पाठ्यपुस्तकें बनाने के लिए भी किया जा रहा है। 400 रेडियो स्टेशनों (11 ज्ञानवाणी एफएम रेडियो स्टेशन, 257 सामुदायिक रेडियो स्टेशन) पर पाठ्यक्रम–आधारित रेडियो कार्यक्रमों (कक्षा 1–12) के 4,254 पीस प्रचारित/प्रसारित किए गए और आई–रेडियो और जियोसावन मोबाइल ऐप पर 3,757 लाइव सत्र आयोजित किए गए।

- **पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री):** पीएम श्री योजना की घोषणा बजट 2021 में की गई थी। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को प्रदर्शित करेगा और समय के साथ अनुकरणीय स्कूलों के रूप में उभरेगा और पड़ोस के अन्य स्कूलों को नेतृत्व भी प्रदान करेगा। पीएम श्री स्कूलों के चयन के पहले चरण में, केवीएस/एनवीएस के साथ–साथ 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 6,448 स्कूलों का चयन किया गया था। वित्तीय वर्ष 2023–24 की पहली किस्त के रूप में केवीएस/एनवीएस के साथ–साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6207 पीएम श्री स्कूलों को 630.11 करोड़ रुपये का केंद्रीय शेयर जारी किया गया है।
- **विद्यांजलि** देश भर में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्रालय का एक स्कूल स्वयंसेवक प्रबंधन कार्यक्रम है। यह पहल उद्योग सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के स्वयंसेवकों को जोड़ती है। दिनांक 7 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत से, 18.01.2024 तक, 682901 सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है और 445148 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराया है।

स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)

विभाग ने 21 अगस्त 2019 को प्राथमिक स्तर पर स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। कोविड महामारी के मद्देनजर और शिक्षकों को निरंतर सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म का उपयोग करके निष्ठा ऑनलाइन को अक्टूबर 2020 में शुरू किया गया था, जिसे अब सभी स्तर के शिक्षकों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया है।

वर्ष 2023 में, निष्ठा प्रारम्भिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) आयोजित किया गया था और इसे ईसीसीई के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। निष्ठा ईसीसीई का उद्देश्य मास्टर प्रशिक्षकों को तैयार करना है, उन्हें ईसीसीई चरण के लिए शैक्षणिक प्रथाओं से अवगत कराना है एवं यह सुनिश्चित करना है कि सभी शिक्षक/आंगनवाड़ी कार्यकर्ता खेल और गतिविधि–आधारित दृष्टिकोण का पालन करें जो बच्चों को कक्षा–1 के लिए तैयार करेगा और अंततः, विकासात्मक लक्ष्यों के माध्यम से छोटे बच्चों के समग्र विकास के लिए रणनीति प्रदान करेगा। निष्ठा ईसीसीई में छह पाठ्यक्रम नामतः प्रारंभिक वर्षों का महत्व; खेल–आधारित अधिगम माहौल की योजना बनाना; समग्र विकास के लिए खेल–आधारित गतिविधियाँ; माता–पिता और समुदायों के साथ साझेदारी; स्कूल तत्परता; और जन्म से तीन वर्ष तक–विशेष आवश्यकताओं के उपाय के लिए प्रारंभिक पहचान शामिल हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य मास्टर प्रशिक्षकों को उचित शिक्षण–अधिगम रणनीतियों के उपयोग को समझने में सहायता करना है जो बच्चों के समग्र विकास अर्थात फिजिकल–मोटर, भाषा और साक्षरता, संज्ञानात्मक, सामाजिक–भावनात्मक और रचनात्मक विकास को बढ़ावा देने में सहायता करते हैं।

इन मास्टर प्रशिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्री–स्कूल शिक्षकों/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके

प्री–स्कूल केंद्रों/आंगनवाड़ियों में शुरुआती अधिगम अवसरों को बढ़ाने में सहायता करेंगे। इससे उन्हें ईसीसीई पदाधिकारियों, सीडीपीओ और डीपीओ को यह मार्गदर्शन करने में सहायता मिलेगी कि प्रीस्कूल शिक्षा केंद्रों/आंगनवाड़ी में आदान–प्रदान प्रक्रियाओं में गुणवत्ता में सुधार लाने और प्रारंभिक बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रमों में गुणवत्ता लाने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कैसे उन्मुख और प्रशिक्षित किया जाए। 31 दिसंबर, 2023 तक, निष्ठा ईसीसीई ने असम, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर 30 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 6 पाठ्यक्रमों के साथ मास्टर ट्रेनर्स के प्रशिक्षण हेतु शुरुआत की। ईसीसीई के लिए 90,000 मास्टर प्रशिक्षकों के कुल लक्ष्य में से, अब तक 32648 को निष्ठा ईसीसीई के तहत प्रमाणित किया गया है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस):

भारत सरकार अधिगम की प्रणाली–स्तरीय समझ प्राप्त करने के लिए 2002 से तीन वर्ष की चक्र अवधि के साथ कक्षा III, V, VIII और X के लिए नमूना–आधारित राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) का एक कार्यक्रम लागू कर रही है। एनएएस 2021 दिनांक 12.11.2021 को आयोजित किया गया था और इसमें (क) सरकारी स्कूल (केंद्र सरकार और राज्य सरकार); सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल; और (ग) निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। कक्षा 3 और 5 के लिए भाषा, गणित और ईवीएस; कक्षा 8 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और कक्षा 10 के लिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अंग्रेजी विषय शामिल हैं।

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा– 3, 5, 8 और 10 के लिए दिनांक 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया
- कक्षा III, V, VIII और X के अंत में छात्रों के अधिगम परिणामों की उपलब्धि को कैप्चर करना।
- उपलब्धि परीक्षण में बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) शामिल हैं जो भाषा, गणित, पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के विषय क्षेत्रों में अधिगम परिणामों से जुड़े हैं। एमसीक्यू सावधानीपूर्वक विकसित और क्षेत्र–परीक्षित वस्तुओं के माध्यम से स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर छात्रों द्वारा प्राप्त दक्षताओं और कौशल का आकलन करते हैं।
- एनसीईआरटी द्वारा एमसीक्यू अर्थात कक्षा 3, 5, 8 और 10 के लिए अलग–अलग विषयों में उपलब्धि परीक्षण के साथ–साथ प्रश्नावली नामतः छात्र प्रश्नावली, शिक्षक प्रश्नावली और स्कूल प्रश्नावली को 22 अलग–अलग भाषाओं में विकसित और अनुदित किया गया था।
- एनएएस के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। छात्रों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए एकाधिक पुस्तिकाओं (विस्तार और कठिनाई के संदर्भ में समतुल्य) का उपयोग किया गया था।
- एनएएस 2021 में कुल 34,01,158 छात्र; 5,26,824 शिक्षक; और 720 जिलों के 1,18,274 स्कूलों ने भाग लिया।
- एनएएस हमारी शिक्षा प्रणाली की शैक्षिक गुणवत्ता का विश्लेषण करने के साधन के रूप में कार्य करता है और राज्य के अधिकारियों और शिक्षकों को यह समझने के लिए एक प्रणाली प्रदान करता है कि बच्चे को विभिन्न कक्षाओं में वास्तव में क्या सीखना चाहिए, कक्षा में अधिकांश छात्रों के लिए कठिन क्षेत्र क्या हैं, गतिविधियों के माध्यम से इसे कैसे सिखाएं और कैसे मापें और सुनिश्चित करें कि बच्चे अपेक्षित स्तर तक पहुंच गए हैं।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष:

- कक्षा–3 का समग्र प्रदर्शन 59%, कक्षा–5 का 49%, कक्षा–8 का 45% और कक्षा–10 का

38% है, जो कक्षा 3 से कक्षा 10 तक अधिगम रुझान में गिरावट दर्शाता है।

- छात्रों के प्रवीणता स्तर में प्रदर्शन को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है– 'बेसिक से कम', 'बेसिक', 'प्रवीण' और 'उन्नत'। प्रवीण और उन्नत स्तर के छात्रों में कक्षा–3 के 42% छात्र, कक्षा–5 के 33% छात्र, कक्षा–8 के 27% छात्र और कक्षा–10 के 22% छात्र हैं।

एनएएस प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार आयोजित किया गया है और अब अंतरिम वर्षों में भी आकलन करने के लिए राज्यों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। **इस वर्ष से, राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 3 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था।** इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भाषा और गणित पर मूल ध्यान देने के साथ प्रत्येक शैक्षिक चरण अर्थात मूलभूत, प्रारंभिक और माध्यमिक चरण के अंत में छात्रों की अधिगम दक्षताओं का आकलन करना है। सर्वेक्षण में 32 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (राज्यों नामतः दिल्ली, ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल को छोड़कर)ने भाग लिया। ब्लॉक स्तर तक के इस व्यापक सर्वेक्षण में देश भर के 5917 ब्लॉकों के 3 लाख स्कूलों के 80 लाख से अधिक छात्रों को शामिल किया गया। परख द्वारा आयोजित राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण, कक्षा 3, 6 और 9 में प्रत्येक चरण के मूलभूत, प्रारंभिक और माध्यमिक के अंत में छात्रों के लिए दक्षताओं के मानचित्रण के लिए आधार रेखा के रूप में काम करेगा। एनईपी 2020 के चरणों या 5+3+3+4 प्रणाली के अनुरूप, सर्वेक्षण शिक्षार्थियों के बीच कौशल और ज्ञान के विकास का व्यापक अवलोकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न दक्षताओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

निःशुल्क वर्दी एवं पाठ्यपुस्तकें:

निःशुल्क वर्दी हेतु वित्तीय परिव्ययः 2022–23 एवं 2023–24

समग्र शिक्षा के तहत, सरकारी स्कूलों में आरटीई पात्रता में कक्षा–VIII तक सभी बालिकाओं और एससी/एसटी/बीपीएल परिवारों के बच्चों के लिए प्रति वर्ष प्रति बच्चा 600 रुपये की औसत लागत पर दो सेट वर्दी देने का प्रावधान शामिल है। विगत तीन वर्षों के वित्तीय परिव्यय का विवरण इस प्रकार हैः

वर्ष	2022-23		2023-24	
	वास्तविक	वित्त (लाख में)	वास्तविक	वित्त (लाख में)
सभी लड़कियाँ	43993680	258145.19	45848378	268963.8810
एसटी लड़के	6133100	36155.40	6193966	36484.5030
एससी लड़के	10475443	61451.57	11016203	64627.1730
बीपीएल लड़के	18636952	110468.09	18692685	110630.1030
वर्दी (सर्दियों के कपड़े)	13344	133.44	13400	134
अन्य*	763	4.58	-	-
कुल	**79253282**	**466358.26**	**81764632**	**480839.66**

*स्रोतः प्रबंध पोर्टल **डेटा 09.01.2024 को जनरेट किया गया***

**अन्य में मेघालय राज्य के बीपीएल लड़कों संबंधित हैं*

नोटः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की लड़कियों सहित सभी लड़कियों को वर्दी के दो सेट निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।

निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के लिए वित्तीय परिव्ययः 2022–23 और 2023–24

समग्र शिक्षा के तहत, प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा 250 रुपये और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति बच्चा 400/– रुपये की औसत लागत पर राज्य पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सरकारी/स्थानीय निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों एवं इच्छुक मदरसों के सभी बच्चों के लिए आरटीई पात्रता के रूप में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रावधान है।

क्र. सं.	विवरण	(2022-23)		(2023-24)	
		वास्तविक	वित्त (लाख में)	वास्तविक	वित्त (लाख में)
1.	पाठ्यपुस्तकें (कक्षा I–II)	23058457	57080.24	24195093	60487.7325
2.	ब्रेल पुस्तकें (कक्षा I–II)	6088	15.18	8205	20.5120
3.	बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें (कक्षा I–II)	13147	32.68	12614	31.5345
4.	पाठ्यपुस्तकें (कक्षा III–V)	36763157	90918.64	39158312	97895.78
5.	ब्रेल पुस्तकें (कक्षा III–V)	10090	25.10	13001	32.5025
6.	बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें (कक्षा III–V)	30770	76.24	33009	82.5215
7.	पाठ्यपुस्तकें (कक्षा VI–VIII)	39162227	152303.39	40705967	162823.8680
8.	ब्रेल पुस्तकें (कक्षा VI–VIII)	10326	40.95	12115	48.46
9.	बड़े प्रिंट वाली पुस्तकें (कक्षा VI–VIII)	37439	145.76	39341	157.3640
10.	पाठ्य पुस्तकों की प्रतिपूर्ति	-	-	1	6931.4270
	कुल	**99091701**	**300638.19**	**104177658**	**328511.702**

स्रोतः प्रबंध पोर्टल डेटा 09–01–2024 को जनरेट किया गया

**कक्षा 1 से 8 तक के एससी/एसटी छात्रों सहित सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जाती हैं।*

राज्यों के लिए शिक्षण–अधिगम और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स)

सिंहावलोकनः

राज्यों के लिए शिक्षण–अधिगम और परिणामों का सुदृढीकरण (स्टार्स) परियोजना को अक्तूबर 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसे केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना था। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, स्टार्स परियोजना 23 फरवरी 2021 को पांच वर्ष की अवधि के लिए अर्थात वित्त वर्ष 2024–25 तक प्रभावी हो गई। स्टार्स परियोजना छह चिन्हित राज्यों नामतः हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल में कार्यान्वित की जा रही है। स्टार्स कार्यक्रम समग्र शिक्षा से बनाया गया है, जिसमें योजना के उन तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो स्कूल शिक्षा संवर्धन में सीधे तौर पर सहायता करेंगे।

प्रमुख उद्देश्यः

इस परियोजना में चयनित राज्यों में छात्र परिणामों और भारत में स्कूल शिक्षा के शासन में सुधार की परिकल्पना की गई है। परियोजना के लक्षित लाभार्थी 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे (प्री–स्कूल से कक्षा XII तक), शिक्षक और शैक्षणिक संस्थान हैं। स्टार्स दो प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती हैं: एक राष्ट्रीय घटक और पांच उप–घटकों वाला एक राज्य घटकः

राष्ट्रीय घटकः राष्ट्रीय स्तर पर, स्टार्स प्रतिधारण, ट्रांजिशन और पूर्णता दर संबंधी मजबूत और प्रामाणिक डेटा प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय डाटा

प्रणाली को सुदृढ़ करने में शिक्षा मंत्रालय की सहायता करेगी। राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) के माध्यम से राज्यों को संवितरण से जुड़े संकेतक प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और सहायता दी जाती है। स्टार्स अंतर्राष्ट्रीय छात्र मूल्यांकन कार्यक्रम (पीआईएसए) में भारत की सहभागिता हेतु बहु–वर्षीय सहायता भी प्रदान करेगा। स्टार्स राष्ट्रीय घटक द्वारा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) को भी सहायता दी जा रही है।

स्टार्स राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) की स्थापना मे सहायता करेंगी। एनईपी 2020 में दिए गए अधिदेश के अनुसार, सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए एक मानक–निर्धारण निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) स्थापित किया जाएगा।

राज्य घटकः राज्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी मैनुअल के अनुसार) के माध्यम से सहायता दी जा रही है:

1. **प्रारंभिक वर्षों की शिक्षा को सुदृढ़ करना:**

    क) मानकीकृत शिक्षण अधिगम सामग्री (टीएलएम) द्वारा समर्थित विकासात्मक रूप से उपयुक्त पाठ्यक्रम।

    ख) ईसीई और मूलभूत शिक्षा के महत्व के बारे में अभिभावक सहभागिता रणनीतियाँ जैसा कि एनईपी पैरा संख्या– 1.3 में व्यक्त किया गया है

    ग) बच्चों में अनुकूल एवं सकारात्मक व्यवहार के लिए आयु–उपयुक्त जीवन कौशल में सुधार हेतु क्षमता विकास

2. **राज्य शिक्षण मूल्यांकन प्रणालियों में सुधार:**

    क) प्रत्येक राज्य में मूल्यांकन कक्ष/केंद्र की स्थापना।

    ख) ऑनलाइन आइटम बैंक, ऑनलाइन लैब, गेम, हैकथॉन आदि विकसित करना (एनईपी पैरा संख्या–24.4)

    ग) विकिपीडिया, गिटहब, स्टैक एक्सचेंज आदि जैसे ऑनलाइन ज्ञान बैंक बनाने के लिए विचारों की क्राउड सोर्सिंग।

    घ) सभी छात्रों हेतु एक ट्रैकिंग प्रणाली का विकास। (एनईपी पैरा 3.3)

    ङ) अधिगम अनुभव को बढ़ाने के लिए संवर्धित वास्तविकता और वर्चुअल वास्तविकता जैसी तकनीकों का उपयोग [एनईपी पैरा संख्या–24.4 (घ)]।

    च) स्कूल शिक्षा बोर्डों की कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं को और दक्षता–आधारित बनाने के लिए उनकी बाहरी समीक्षा के माध्यम से परीक्षा सुधार करना।

3. **शिक्षक विकास और स्कूल नेतृत्व के माध्यम से कक्षा निर्देश और सुधार को सुदृढ़ करना:**

    क) शिक्षा प्रबंधन में सुधार हेतु आईसीटी–सक्षम दृष्टिकोण विकसित करना। (एनईपी 2020 का पैरा 23.5 और 24.1)

    ख) शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों की डिजिटल दक्षताओं का आकलन करना [एनईपी पैरा 24.4(छ)]।

    ग) अधिगम परिणामों में अंतराल की पहचान के आधार पर राज्य के संदर्भ के अनुसार अधिगम संवर्धन की रणनीतियों को सुदृढ़ करना। (एनईपी 2020 पैरा संख्या–4.6)

    घ) महामारी में हाल ही में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों को तैयार करना, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, मौजूदा डिजिटल प्लेटफार्मों और क्रियान्वित

आईसीटी–आधारित शिक्षा पहलों को अनुकूल करना जैसा कि एनईपी 2020 पैरा संख्या– 24.1 में बल दिया गया है।

ङ) कोविड–19 के बाद के परिदृश्य के लिए, अधिगम परिणामों को बेहतर बनाने के लिए छोटे समूह/सहकर्मी अधिगम, वैकल्पिक स्कूल शिक्षा, ब्रिज कोर्स और कक्षा से बाहर शिक्षण की रूपरेखा विकसित की जाएगी।

4. **बेहतर सेवा वितरण के लिए शासन और विकेंद्रीकृत प्रबंधनः**

क) एनईपी अध्याय संख्या 5 में उल्लिखित शिक्षक भर्ती, तैनाती और मूल्यांकन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्रभावी शिक्षक प्रबंधन।

ख) एक राष्ट्रीय व्यापक फ्रेमवर्क का विकास और विभिन्न मॉडलों के माध्यम से गैर–राज्य कर्ताओं के साथ साझेदारी के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना

ग) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना (एनईपी पैरा संख्या 23.5)।

घ) राज्यों में सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली के लिए संचार और ब्रांडिंग योजना विकसित करना।

ङ) स्कूल प्रबंधन और शैक्षणिक संवर्धन में समुदाय और पंचायती राज संस्थानों की सहभागिता के लिए फ्रेमवर्क और मॉडल का विकास

5. **स्कूल–से–कार्य क्षेत्र तक ट्रांजिशन संबंधी रणनीतियाँः**

क) एआई, कोडिंग और रोबोटिक्स सहित सॉफ्ट स्किल्स और एसटीईएम/एसटीईएएम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित) से संबंधित कौशल संबंधी प्रशिक्षण (एनईपी पैरा संख्या 4.24 और 4.25)।

ख) कैरियर मार्गदर्शन और काउंसिलिंग का सुव्यवस्थित प्रावधान।

ग) छात्रों की योग्यता, व्यक्तित्व और रुचियों का आकलन करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

घ) इंटर्नशिप के माध्यम से नौकरी के अनुभव के साथ उद्यमशीलता को बढ़ाना और प्रशिक्षुता के लिए संपर्क विकसित करना। व्यावसायिक शिक्षा में नामांकित बच्चों के लिए, यह समुदाय कार्यक्षेत्र की दुनिया में प्रथम–स्तरीय अनुभव हेतु मूल्यवान अवसर प्रदान कर सकता है।

ङ) माध्यमिक स्तर पर स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए कौशल विकास के अवसर।

च) स्वयं सहायता समूहों की सहभागिता हेतु रूपरेखा और मॉडल का विकास और अधिगम और जीवन कौशल संवर्धन के लिए व्यावसायिक शिक्षा और अन्य गतिविधियों को सुदृढ़ करने में उनके ज्ञान और कौशल का उपयोग करना

उपलब्धियां

राज्यों को विश्व बैंक से मिलने वाला वित्तपोषण विश्व बैंक के पीफॉरआर (परिणामों के लिए कार्यक्रम) साधन पर आधारित है, अर्थात, निधियां निर्दिष्ट मापनीय परिणामों (डिस्बर्समेंट लिंक्ड इंडिकेटर्स–डीएलआई) की उपलब्धि के आधार पर वितरित की जाएगी। अब तक विश्व बैंक से कुल 182 मिलियन अमरिकी डॉलर (500 डॉलर में से) पहले ही वितरित किए जा चुके हैं और अतिरिक्त 13 मिलियन डॉलर के वितरण दावे को

विश्व बैंक द्वारा प्राधिकरण के लिए अनुमोदन दे दिया गया है। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

डीएलआई–वार उपलब्धियाँ

डीएलआई	प्राप्त लक्ष्य	राशि (मिलियन डॉलर)
डीएलआई–1 चयनित राज्यों में कक्षा 3 भाषा में न्यूनतम दक्षता प्राप्त करने वाले छात्रों में वृद्धि	प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 3 का लक्ष्य (एनएएस–2021 के मूल्यांकन परिणामों का विश्लेषण, प्रकाशन किया गया और प्रत्येक चयनित राज्य के लिए समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के लिए का उपयोग किया गया)	$20 मिलियन
डीएलआई–2 चयनित राज्यों में माध्यमिक विद्यालय पूर्णता दर में सुधार	प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 5 का लक्ष्य (प्रत्येक चयनित राज्य में बेसलाइन से 2.0 प्रतिशत अंक का सुधार) प्राप्त कर लिया गया है।	$30 मिलियन
डीएलआई–3 चयनित राज्यों में अभिशासन सूचकांक स्कोर में सुधार	प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 5 का लक्ष्य (शासन प्रत्येक चयनित राज्य में सूचकांक स्कोर बेसलाइन से कम से कम 10 अंक बेहतर) पहले ही प्राप्त कर लिया गया है।	$20 मिलियन
डीएलआई–4 सुदृढ़ अधिगम मूल्यांकन प्रणाली	राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र (परख) को शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया और एनसीईआरटी के एक घटक निकाय के रूप में स्थापित किया गया।	$8 मिलियन
राज्यों के बीच क्रॉस–लर्निंग की सुविधा के लिए डीएलआई–5 साझेदारी विकसित की गई	शिक्षा मंत्रालय अंतरराज्यीय अधिगम साझेदारियों की पहचान करता है और उनकी स्थापना करता है और प्रत्येक अंतरराज्यीय अधिगम साझेदारी के तहत 2 कार्यशालाएँ आयोजित करता है	$6 मिलियन
डीएलआई–6 राज्य स्तरीय बेहतर सेवा वितरण	राज्य प्रोत्साहन अनुदान (एसआईजी) के तहत राज्यों द्वारा प्राप्त लक्ष्य।	$111 मिलियन
कुल		**$195 मिलियन**

वर्ष 2023–24 के दौरान स्टार्स योजना के तहत कुल व्यय 419.96 करोड़ रुपये है जो परियोजना के संशोधित अनुमान 2023–24 का 60% है। व्यय में स्टार्स के तहत राज्यों को जारी निधियां और राष्ट्रीय घटक संबंधी व्यय शामिल है। स्टार्स परियोजना के तहत संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय निम्न तालिका में दिए गए हैं:

संशोधित अनुमान और स्टार्स के तहत वास्तविक व्यय

(लाख रुपये में)

वर्ष	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय/रिलीज़
2020-21	111.79	91.17
2021-22	340.00	282.30
2022-23	480.00	473.45
2023-24 (18.01.2024 तक)	700.00	419.96

एनईपी–4.41 की सिफारिश के अनुसार एनसीईआरटी के एक घटक निकाय के रूप में परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण) नामक एक स्वतंत्र राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया गया है। इसे परियोजना कार्यान्वयन वर्षों के दौरान स्टार्स परियोजना द्वारा सहायता दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, स्टार्स के तहत आने वाले राज्यों ने स्टार्स परियोजना के कार्यान्वयन में अच्छा प्रदर्शन किया है। स्टार्स परियोजना के डीएलआई और एसआईजी मैनुअल के तहत राज्यों की कुछ विशिष्ट उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

i. सभी राज्यों में विद्या समीक्षा केंद्र स्वीकृत किए गए हैं और चार राज्यों ने पहले ही सीएसके की स्थापना को अधिसूचित कर दिया है।
ii. प्रत्येक स्टार्स राज्य में बेसलाइन की तुलना में अभिशासन सूचकांक स्कोर में कम से कम 10 अंक का सुधार हुआ।
iii. प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल (ईसीई) पर राज्यों द्वारा शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।
iv. केरल, राजस्थान और एमपी द्वारा मानकीकृत ईसीई टीएलएम पैकेज/किट विकसित किए गए हैं। एचपी मौजूदा किटों की समीक्षा कर रहा है।
v. कैरियर मार्गदर्शन कार्यक्रम व्यापार–विशिष्ट हैं और शैक्षिक स्तर–विशिष्ट सूचना राज्यों द्वारा तैयार की जाती है।
vi. शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्टार्स के तहत 2 राज्यों को प्रत्येक राज्य से जोड़कर 12 अंतरराज्यीय शिक्षण साझेदारियों की पहचान और स्थापना की गई है।

प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री):

मंत्रिमंडल ने 7 सितंबर 2022 को पीएम श्री नामक एक नई केंद्र–प्रायोजित योजना को अनुमोदित किया है। ये स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन को निरूपित करेंगे और समय के साथ उदाहरणपरक स्कूलों के रूप में उभरेंगे, और पास पड़ोस के अन्य स्कूलों का मार्गदर्शन भी करेंगे। वे एक ऐसे समान, समावेशी और आनंदपूर्ण स्कूल परिवेश में उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने में अपने अपने क्षेत्रों की अगुआई करेंगे जो बच्चों की विविध पृष्ठभूमि, बहुभाषी आवश्यकताओं और विभिन्न शैक्षणिक क्षमताओं पर ध्यान देता है और उन्हें एनईपी 2020 के विजन के अनुसार अपनी स्वयं की अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाता है।

इस योजना के तहत, केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित स्कूलों में से मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके **14500 से अधिक पीएम श्री स्कूल** (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) की स्थापना का प्रावधान है। पीएम श्री स्कूलों का चयन तीन–चरणीय 'चुनौती पद्धति' के माध्यम से किया जाता है, जिसमें स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनने हेतु सहायता के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए पोर्टल पर स्वयं आवेदन करना होता है।

पीएम–श्री स्कूलों की चयन प्रक्रिया का प्रथम चरण पहले ही पूर्ण हो चुका है और कुल 6,207 स्कूलों का पीएम–श्री स्कूलों के रूप में चयन किया गया है। वित्त वर्ष 2023–24 के लिए परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक में केविसं/नविस के साथ 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 6,207 पीएम श्री स्कूलों के लिए कुल 3395.15 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए वित्त वर्ष 2023–24 के लिए 630.11 करोड़ रुपये के केंद्रीय शेयर की प्रथम किस्त सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ केविसं/नविस को जारी कर दी गई है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):

समग्र शिक्षा के तहत, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) का प्रावधान है। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित बालिकाओं के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय हैं। केजीबीवी की

स्थापना का उद्देश्य आवासीय विद्यालयों की स्थापना करके स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतर को कम करके वंचित समूहों की बालिकाओं तक पहुंच और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। केजीबीवी की स्थापना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों (ईबीबी) में की जाती है जहां महिला ग्रामीण साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। इनमें शैक्षणिक रूप से पिछड़े प्रत्येक ब्लॉक में कक्षा VI–XII की बालिकाओं के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय या राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हैं।

दिनांक 30.09.2023 तक, केजीबीवी के विलय/अभिसरण को ध्यान में रखते हुए, 5639 केजीबीवी स्वीकृत है। इनमें से 691304 बालिकाओं के नामांकन के साथ 5074 केजीबीवी कार्यात्मक हैं। नामांकित 691304 बालिकाओं में से 189696 अनुसूचित जाति की बालिकाएं, 178568 अनुसूचित जनजाति की बालिकाएं, 249517 अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाएं, 27194 मुस्लिम बालिकाएं और 46195 बीपीएल श्रेणी की बालिकाएं हैं। (स्रोतः प्रबंध). समग्र शिक्षा के तहत, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा केजीबीवी और माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास को कक्षा XII तक की बालिकाओं को आवासीय और स्कूल शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित/एकीकृत किया जा रहा है। केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था और 30 सितंबर 2023 तक कुल 2615 केजीबीवी को अपग्रेड किया गया है, जिनमें से कक्षा X तक के 351 केजीबीवी और कक्षा XII तक के 2264 केजीबीवी हैं।

समग्र शिक्षा के तहत "पुस्तकालय घटक":

समग्र शिक्षा योजना के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर पुस्तकालय और पुस्तकों का प्रावधान शामिल है। इसमें कक्षा I से XII तक के सरकारी स्कूलों में पुस्तकालयों हेतु अनुदान प्रदान करना शामिल है। इस घटक का दृष्टिकोण स्कूल पुस्तकालयों को अधिगम स्थानों के रूप में विकसित करना है जो आजीवन पाठकों और ज्ञान साधकों का पोषण करते हैं और प्रासंगिक, आयु–उपयुक्त, विविध और आकर्षक पुस्तकों और अन्य पठन सामग्री के माध्यम से पढ़ने की क्षमता को बढ़ावा देता हैं। समग्र शिक्षा के घटक 'मौजूदा विद्यालयों का सुदृढ़ीकरण' के तहत जिन विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध नहीं हैं, वहां पुस्तकालय कक्ष उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। जिनके विद्यालयों में पुस्तकालय कक्ष नहीं हैं, उन विद्यालयों में पुस्तकालय कक्षों की स्वीकृति वार्षिक कार्य योजना में प्रस्तावित की जा सकती है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बजट प्रस्तावों पर विचार किया जा सकता है। प्रस्ताव में सिविल कार्य, फर्नीचर, अलमारी, रैक, फिक्सिंग और फिटिंग की लागत शामिल हो सकती है।

समग्र शिक्षा योजना के तहत, पुस्तकालय अनुदान के लिए निधि स्कूल की श्रेणी के आधार पर 5000/– रुपये से 20000/– रुपये तक है। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान के उपयोग के संबंध में पूर्व में जारी दिशानिर्देश काफी हद तक खरीद तक ही सीमित थे। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों के लिए पुस्तकालय अनुदान के तहत 673.95 करोड़ रुपये के परिव्यय को मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2020–21 और 2021–22 हेतु एससी और एसटी का जीईआर नीचे दिया गया है:

वर्ष	प्रारम्भिक (I-VIII)			माध्यमिक (IX-X)			उच्च माध्यमिक (XI-XII)		
	समस्त	एससी	एसटी	समस्त	एससी	एसटी	समस्त	एससी	एसटी
2020-21	99.1	108.6	102.7	79.8	84.8	78.6	53.8	56.1	45.2
2021-22	100.1	109.7	103.4	79.6	84.9	78.1	57.6	61.5	52.0

(स्रोतः यूडाइज़)

सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी वर्तमान दिशानिर्देशों में पुस्तकालयों के विकास, पुस्तकालय की पुस्तकों के चयन और खरीद के अलावा समग्र रूप से पढ़ने को बढ़ावा देने पर बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, वर्तमान इन दिशानिर्देशों को तैयार करते समय नई शिक्षा नीति, 2020 की सिफारिशों पर भी विचार किया गया। दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन में https://samagra.education.gov.in/library.html लिंक पर उपलब्ध है।

समग्र शिक्षा के तहत "खेल अनुदान" घटकः

समग्र शिक्षा की एकीकृत योजना में प्री–स्कूल से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा की परिकल्पना की गई है और इसका उद्देश्य सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना में खेल और शारीरिक शिक्षा घटक सम्मिलित है जिसके तहत सभी सरकारी स्कूलों में इनडोर और आउटडोर खेलों हेतु खेल सामग्री संबंधी अनुदान का प्रावधान किया गया है।

बच्चों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को समझते हुए, समग्र शिक्षा के तहत खेल, शारीरिक गतिविधियों, योग, पाठ्येत्तर गतिविधियों आदि को प्रोत्साहन देने के लिए पहली बार खेल और शारीरिक शिक्षा घटक शुरू किया गया है। राजकीय स्कूलों को खेल कूद सामग्री हेतु प्राथमिक विद्यालयों के लिए 5000 रुपये, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 10,000 रुपये और माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए 25,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से अनुदान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2023–24 के दौरान राजकीय स्कूलों के लिए खेल अनुदान के तहत 812.42 करोड़ रुपये का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

मंत्रालय ने खेल अनुदान का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को एनईपी, 2020 की सिफारिशों के अनुसार खेल अनुदान के लिए संशोधित दिशानिर्देश अगस्त 2023 में जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सरकारी स्कूलों के लिए आयु–उपयुक्त खेल उपस्करों की एक सांकेतिक सूची शामिल है। खेल के मैदान आदि की उपलब्धता सहित स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर स्कूलों द्वारा खेल–विशिष्ट उपस्कर भी चुने जा सकते हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कूलों को अपने–अपने राज्य/क्षेत्र के पारंपरिक/क्षेत्रीय खेलों/स्वदेशी खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करें। प्रत्येक स्कूल में एक जिम्मेदार व्यक्ति/शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी)/ प्रभारी शिक्षक को खेल उपकरणों की देखभाल करने और उनके स्टॉक की स्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी जाएगी। संशोधित दिशानिर्देश सार्वजनिक डोमेन में https://samagra.education.gov.in/docs/revized_samagra_sports.pdf लिंक पर उपलब्ध है।

i) **स्कूलों के लिए फुटबॉलः** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (फीफा) के सहयोग से देश भर के स्कूल छात्रों के लिए फीफा का महत्वाकांक्षी फुटबॉल फॉर स्कूल्स (एफ4एस) कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के सहयोग से फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों को शिक्षा प्रणाली में निर्बाध रूप से एकीकृत करते हुए, स्कूल प्रणाली में प्रत्येक जेंडर के छात्रों के लिए फुटबॉल की पहुंच का व्यापक विस्तार करना है। इस कार्यक्रम के तहत, 11 लाख से अधिक फीफा फुटबॉल को चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में वितरित किया जाना है। इस कार्यक्रम से 1.50 लाख से अधिक स्कूल लाभान्वित होंगे। कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए, इस विभाग ने हाल ही में 3 स्थानों नामतः संबलपुर, पुणे और बेंगलुरु में एक मास्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया है, जहां पूरे भारत के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केविसं, नविस और एआईएफएफ के लगभग

शारीरिक शिक्षा के 300 शिक्षकों/प्रशिक्षुओं ने सर्वश्रेष्ठ से सीखने और इस क्षेत्र में और अधिक क्षमता निर्माण करने के लिए राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में अपने प्रशिक्षण और कौशल का उपयोग करने के उद्देश्य से भाग लिया। फुटबॉल के वितरण की शुरुआत माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा 2 दिसंबर 2023 को जनवि कटक, ओडिशा से की गई थी। इसके अतिरिक्त, फुटबॉल को दिसंबर 2023 माह में ओडिशा के कटक, अंगुल, ढेंकनाल और गोवा राज्य के उत्तरी गोवा और दक्षिण गोवा जिलों में वितरित किया गया था।

ii) **फिट इंडिया मूवमेंटः**— माननीय प्रधान मंत्री ने शारीरिक फिटनेस को जीवन का एक तरीका बनाने के उद्देश्य से 29 अगस्त 2019 को "फिट इंडिया मूवमेंट" का शुभारंभ किया। फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य व्यवहार परिवर्तन है— गतिहीन जीवनशैली से लेकर दिन—प्रतिदिन के जीवन में शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके तक। फिट इंडिया तभी सफल होगा जब यह जन आंदोलन बनेगा। यह देश को फिटनेस और तंदुरुस्ती के मार्ग पर ले जाने वाला अभियान है। यह स्वस्थ भारत की दिशा में काम करने का एक अनूठा और रोमांचक अवसर प्रदान करता है। आंदोलन के भाग के रूप में, व्यक्ति और संगठन अपने स्वयं के स्वास्थ्य और कल्याण के साथ—साथ साथी भारतीयों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए विभिन्न प्रयास कर सकते हैं। कार्यक्रम भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई), खेल विभाग द्वारा संचालित और प्रशासित किया जाता है। कार्यक्रम के तहत, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा एसएआई, खेल विभाग के सुझाव और सिफारिश के अनुसार देश भर के केविसं, नविसं और संबद्ध सीबीएसई स्कूलों सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों में फिट इंडिया मूवमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस विभाग द्वारा स्कूल स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियां फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया क्विज, फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया स्कूल रेटिंग, फिट इंडिया फिटनेस मूल्यांकन हैं। कार्यक्रम का अधिक विवरण http://fitindia-gov.in लिंक पर उपलब्ध है।

योगः

बच्चों के सर्वांगीण विकास की आवश्यकता को समझते हुए योग और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसके तहत स्कूल जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर योग गतिविधियां और ओलंपियाड आयोजित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सहित सभी योग—संबंधी गतिविधियों के लिए नोडल मंत्रालय है।

आयुष मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पूरे भारत के स्कूलों में समग्र शिक्षा के स्कूल में योग घटक से संबंधित कार्य करता है। यह विभाग प्रत्येक वर्ष देश भर में विभिन्न स्तरों पर एनसीईआरटी के माध्यम से योग ओलंपियाड का आयोजन करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए विभिन्न आधारभूत गतिविधियों/प्रतियोगिताओं में छात्रों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सीबीएसई, केविसं और नविस द्वारा छात्रों, अभिभावकों, स्कूल शिक्षकों आदि के लिए योग कार्यशालाएँ भी आयोजित की जाती हैं। आईडीवाई में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सीबीएसई अपने संबद्ध स्कूलों में संभावित गतिविधियां भी आयोजित करता है। इस संबंध में, आयुष मंत्रालय से प्राप्त दिशानिर्देशों/परामर्शिका के अनुसार, यह विभाग आयुष विभाग के एबी सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित करता है।

सकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम 2023

जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) 2014 से "विज्ञान में जापान—एशिया युवा आदान—प्रदान

कार्यक्रम" क्रियान्वित कर रही है, जिसे "सकुरा विज्ञान कार्यक्रम" के रूप में भी जाना जाता है। भारत को 2015 से सकुरा कार्यक्रम में जोड़ा गया था। कार्यक्रम का उद्देश्य जापान और शेष एशिया के युवाओं के बीच आदान–प्रदान बढ़ाना है। सक्षम एशियाई युवाओं को जापान की अल्पकालिक यात्रा की सुविधा प्रदान करते हुए उद्योग–अकादमिक–सरकार के विशेष सहयोग के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के भावी क्षेत्रों में ये युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम के तहत, जेएसटी एशिया से उत्कृष्ट हाई स्कूल छात्रों को एक सप्ताह के लिए आमंत्रित करता है और उन्हें जापान की सबसे उन्नत वैज्ञानिक तकनीक देखने और उत्कृष्ट वैज्ञानिकों के साथ चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। शिक्षा मंत्रालय ने अप्रैल 2016 में पहली बार इस कार्यक्रम में भाग लिया।

वर्ष 2023 के दौरान 121 मेधावी छात्रों और 14 पर्यवेक्षकों ने दो बैचों अर्थात एक बैच जुलाई में (57 छात्र और 6 पर्यवेक्षक) और दूसरा, दिसंबर में (64 छात्र और 8 पर्यवेक्षक) में जापान का दौरा किया।

पहल/गतिविधियां:

क) स्कूल शिक्षा में आईसीटी: समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना के आईसीटी और डिजिटल पहल घटक में छठी से बारहवीं कक्षा वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। इस घटक के तहत स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023–24 के लिए 16727 आईसीटी लैब और 21881 स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी दी गई है।

ख) विशेष अभियान 3.0 के तहत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की सुविधा के लिए शास्त्री भवन में मौजूदा क्रेच को 'हमारी बालवाटिका' में बदल दिया है। इसका उद्देश्य कमरा नंबर 501–डी, 5वीं मंजिल, शास्त्री भवन में 10 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करना और एनईपी 2020 के अनुसार बच्चों को सीखने का आनंदमय माहौल देना है। 'हमारी बालवाटिका' का उद्घाटन दिनांक 08.11.2023 को माननीय केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया।

ग) पुणे में जी–20 ईडीडब्ल्यूजी बैठक के एक साइड इवेंट के रूप में स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 17 और 18 जून 2023 को "आजीवन अधिगम हेतु आधार तैयार करना" शीर्षक पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया था। इसके बाद सोमवार, 19 जून 2023 को "मिश्रित मोड के संदर्भ में मूलभूत साक्षरता और संख्याज्ञान" पर एक सेमिनार और 17 से 22 जून 2023 तक सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में प्रदर्शनी आयोजित की गई। 1.5 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों आदि ने प्रदर्शनी का दौरा किया, जिसमें टीएलएम और एफएलएन तथा अन्य प्रौद्योगिकी पहलों में राज्यों द्वारा सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया। इन आयोजनों के दौरान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धियों को साझा किया गया। एनईपी, 2020 और अमृत काल में जी–20 की अध्यक्षता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 1 से 15 जून 2023 तक स्कूलों और जिले के स्तर पर जनभागीदारी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जनभागीदारी कार्यक्रम एक बड़ी सफलता थी जिसमें माता–पिता, बच्चों, शिक्षकों और समुदाय के सदस्यों जैसे 5.25 करोड़ से अधिक हितधारकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

घ) निपुण भारत मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए "निपुण भारत मिशन: हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ" नामक एक दस्तावेज़ तैयार किया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझा किया गया है।

सामुदायिक गतिशीलता और स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) तथा स्कूल प्रबंधन और विकास समिति (एसएमडीसी) गतिविधियाँः

सामुदायिक गतिशीलताः सामुदायिक गतिशीलता का उद्देश्य स्कूलों में समग्र शिक्षा संबंधी पहलों की प्रभावी योजना तथा कार्यान्वयन और समुदाय द्वारा समग्र शिक्षा की प्रभावी निगरानी,मूल्यांकन और स्वामित्व के लिए समुदाय के सदस्यों की गहन भागीदारी है। समुदाय की सक्रिय भागीदारी पारदर्शिता, जवाबदेही भी सुनिश्चित करती है और स्कूलों के बेहतर कार्यकरण के लिए समुदाय के संचयी ज्ञान का लाभ उठाने में मदद करती है। सामुदायिक गतिशीलता एक ऐसी प्रक्रिया है जो समुदाय के सदस्यों के बीच एक संवाद शुरू करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि कौन, क्या और कैसे मुद्दों पर निर्णय लिया जाता है, और साथ ही स्कूल के कामकाज को प्रभावित करने वाले निर्णयों में भाग लेने के लिए सभी को अवसर प्रदान करती है। इसमें योजना की एक इकाई के रूप में आवास सहित योजना बनाने के लिए समुदाय–आधारित दृष्टिकोण की परिकल्पना की गई है। यह प्रभावी विकेंद्रीकरण के माध्यम से स्कूल–आधारित कार्यकलापों का सामुदायिक स्वामित्व प्रदान करता है। स्कूल ईसीसीई/एफएलएन/प्रारंभिक/माध्यमिक स्तर के लिए सामुदायिक संवेदीकरण, अभिभावकों का पक्ष समर्थन और एक संसाधन के रूप में अभिभावकों की क्षमताओं का लाभ उठाने का कार्य करेंगे।

एनईपी 2020: एनईपी 2020 में प्रत्येक बच्चे को उचित रूप से सीखने और अधिगम के परिणामों की उपलब्धि में मदद करने के लिए समुदाय और माता–पिता की भागीदारी पर बल दिया गया है। साक्षरता और संख्याज्ञान की एक सशक्त नींव विकसित करने के लिए यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि बुनियादी स्तर पर बच्चे घर पर अधिक समय बिताते हैं।

सामुदायिक जुड़ाव की प्रमुख गतिविधियों में जागरूकता सृजन, अभिभावकों की सहभागिता, पोर्टलों पर डाटाबेस का संग्रह, पूर्व छात्र संघ का गठन आदि शामिल हैं।

स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी)/स्कूल प्रबंधन और विकास समिति (एसएमडीसी): आरटीई अधिनियम के अनुसार एक स्कूल प्रबंधन समिति/स्कूल प्रबंधन और विकास समिति (एसएमसी/एसएमडीसी) में स्थानीय अधिकारियों के प्रतिनिधि, शिक्षाविद, विषय विशेषज्ञ, अधिकारी, वंचित समूहों के प्रतिनिधि, महिलाएं और छात्रों के माता–पिता/अभिभावक शामिल होते हैं। एसएमसी/एसएमडीसी की दो उप समितियाँ हैंः

- **विद्यालय निर्माण समितिः** स्कूल भवन समिति निर्माण, नवीनीकरण, मरम्मत और रखरखाव और अन्य संबंधित सिविल कार्यों से संबंधित योजना, अनुमान, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।
- **शैक्षणिक समितिः** शैक्षणिक समिति यूडाइज़+ के लिए योजना, प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और डाटा संग्रह सहित सभी शैक्षणिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। यह गुणवत्ता में सुधार, समानता सुनिश्चित करने, सामाजिक–आर्थिक–बाधाओं को कम करने, जेंडर और दिव्यांगता, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श के लिए शिक्षकों की सिफारिश करने, छात्रों की उपलब्धियों, पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियों और छात्रों और शिक्षकों के समग्र शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास को सुनिश्चित करने के लिए भी उत्तरदायी है।

राष्ट्रीय आविष्कार अभियान (आरएए)

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए) एक केंद्राभिमुख रूपरेखा है जिसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में जिज्ञासा और रचनात्मकता, विज्ञान और गणित के प्रति प्रेम और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग की भावना को प्रोत्साहित करना है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट पहल की योजना बना

रहे हैं, जिसमें सामुदायिक संवेदीकरण और जुड़ाव, स्कूल विज्ञान सुविधाओं में सुधार, शिक्षक सहायता प्रणाली, प्रभावी कक्षा संव्यवहार और मूल्यांकन और छात्र क्लबों और प्रतियोगिताओं का पोषण शामिल है।

कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य हैं:

- अवलोकन, प्रयोग, निष्कर्ष निकालने, मॉडल निर्माण, युक्तिसंगत तर्क और परीक्षण क्षमता के माध्यम से बच्चों को विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी (एसएमटी) में प्रेरित करना और उनकी रुचि बढ़ाना।
- विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में स्कूल के बच्चों में जिज्ञासा, उत्साह और अन्वेषण का सृजन करना।
- सोचने, आविष्कार करने और कार्य करने की संस्कृति का निर्माण करना
- स्कूलों में पूछताछ–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना।
- विज्ञान और गणित में अध्ययन की कक्षा के लिए उपयुक्त अधिगम स्तर को प्राप्त करना।
- स्कूलों को इनोवेशन इनक्यूबेटर बनने के लिए प्रोत्साहित करना और उनका विकास करना।

इन उद्देश्यों के अनुसार, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी में नवाचार और उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट पहल की योजना बना सकते हैं, जिसमें सामुदायिक संवेदनशीलता और सहभागिता, स्कूल विज्ञान सुविधाओं में सुधार, शिक्षक सहायता प्रणाली, प्रभावी कक्षा शिक्षण–अधिगम एवं मूल्यांकन और छात्र क्लब विकसित करना तथा प्रतियोगिताएं शामिल है।

वर्ष 2023–24 में आरएए के तहत अनुमोदित कार्यकलापों का विवरण निम्नलिखित है:

अनुमोदित परिव्यय 2023–24 (लाख रुपये में)			
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	**वास्तविक**	**वित्तीय**
	(प्रारम्भिक)		
1	विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला	2593	705.63004
2	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	5430195	2224.35752
3	राज्य के बाहर एक्सपोज़र विजिट	13982	711.58
4	विज्ञान किट	62207	5524.01092
5	राज्य के भीतर छात्रों के लिए भ्रमण यात्रा	751421	4302.02
6	गणित किट	104643	2513.80778
7	उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा स्कूलों का मार्गदर्शन	54057	429.7289
8	विज्ञान और गणित ओलंपियाड में सहभागिता	559292	3242.78545
9	विज्ञान/गणित क्लबों का गठन	107838	4728.807
10	छात्रों के लिए उच्च संस्थानों की अध्ययन यात्रा (राज्यों के मध्य)	30697	92.091
11	स्कूलों के साथ जुड़ना	4461	8.922
12	विज्ञान पार्क	16	32
13	क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र के साथ सहयोग	13000	71.5

अनुमोदित परिव्यय 2023–24 (लाख रुपये में)			
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	**वास्तविक**	**वित्तीय**
14	कार्यशाला/संगोष्ठी	214	0.428
15	विज्ञान प्रयोगशाला	616	1291.68424
16	प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गणित और विज्ञान गतिविधियाँ	107	6.42
17	विभिन्न स्तरों पर कबाड़ से जुगाड़ कार्यशालाएँ	183	36.6
18	चयनित जिलों में प्रदर्शन	33	6.6
19	विज्ञान और गणित अधिगम में सहायक गतिविधियाँ	5379	376.53
20	वैदिक गणित	7370	22.11
21	गणित प्रयोगशाला	616	310.4948
22	विज्ञान कार्यक्रम	3486	174.3
23	सामाजिक विज्ञान कार्यक्रम	52	104
24	गणित कार्यक्रम	3486	174.3
25	छात्र आदान–प्रदान कार्यक्रम	2000	20
26	खोजी बक्सा	33	8.58
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (प्रारंभिक) का योग		**27119.29**
(माध्यमिक)			
1	विज्ञान प्रदर्शनी/पुस्तक मेला	3008	1073.1084
2	प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	60684	258.54751
3	छात्रों के लिए उच्च संस्थानों की अध्ययन यात्रा (राज्यों के मध्य)	1330771	6322.32446
4	राज्य के बाहर एक्सपोज़र विजिट	25930	1405.5744
5	गणित किट	45733	3279.91025
6	विज्ञान किट	45520	4594.02075
7	टिंकरिंग लैब	1001	3930.5
8	विज्ञान/गणित क्लबों का गठन	39727	2215.975
9	बाल विज्ञान कांग्रेस में सहभागिता	76026	235.2557
10	विज्ञान और गणित ओलंपियाड में सहभागिता	134946	595.2467
11	उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा स्कूलों का मार्गदर्शन	20311	821.74
12	गणित ग्रीष्मकालीन शिविर	923	27.69
13	कार्यशाला	192	0.384
14	तकनीकी महोत्सव	1	4

अनुमोदित परिव्यय 2023–24 (लाख रुपये में)			
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान	वास्तविक	वित्तीय
15	कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए वैदिक गणित	7376	22.128
16	राज्य के अंदर छात्रों के लिए भ्रमण यात्रा	41620	83.24
17	गणित सप्ताह के दौरान गणित मेला	3	3
18	खगोल विज्ञान क्लब की स्थापना	43	3.44
19	प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु गणित और विज्ञान गतिविधियाँ	96	3.84
20	विज्ञान और गणित अधिगम में सहायता के लिए गतिविधियाँ	3377	337.7
21	गणित प्रदर्शनी	23	23
22	प्रतिरूप समस्याओं की पुस्तकें	3377	67.54
23	विज्ञान और गणित शिक्षक मंडलों को बढ़ावा	358	53.7
24	राज्य में एक्सपोजर विजिट	14032	42.096
25	शास्त्रपथम – विज्ञान कार्यक्रम	1241	124.1
26	गणित कार्यक्रम	14	42
27	विज्ञान पार्क की स्थापना	16	48
28	बीआईएस मानकीकृत क्लब	630	12.6
29	हाइड्रोपोनिक तकनीक पर कार्यशाला	100	25
30	कोडिंग पर कार्यशाला	260	390
31	जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी	4	1
32	राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी	1	5
33	विज्ञान शिक्षक का क्षमता निर्माण	200	20
34	प्रौद्योगिकी मेला	285	8.25075
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (माध्यमिक) का योग		**26079.91**
(वरिष्ठ माध्यमिक)			
1	भौतिक विज्ञान किट	5114	2358.8325
2	रसायन विज्ञान किट	5114	526.10388
3	जीवविज्ञान किट	5114	1213.14308
4	गणित किट	900	189.297
5	उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा मार्गदर्शन	6398	959.7
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (वरिष्ठ माध्यमिक) का योग		**5247.08**
	राष्ट्रीय अविष्कार अभियान का योग		**58446.28**

समग्र शिक्षा के तहत टिंकरिंग लैब्सः

राष्ट्रीय अविष्कार अभियान (आरएए) के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा के कार्यकलाप के तहत प्रति स्कूल 10.00 लाख रुपये की दर से टिंकरिंग लैब प्रदान की जाती हैं। राष्ट्रीय अविष्कार अभियान को एक अभिसरण फ्रेमवर्क के रूप में शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में पूछताछ और रचनात्मकता की भावना, विज्ञान और गणित के प्रति प्रेम और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य छात्रों को अवलोकन, प्रयोग, निष्कर्ष निकालना, युक्तिसंगत तर्क आदि के माध्यम से विज्ञान, गणित और प्रौद्योगिकी (एसएमटी) से जोड़ना है।

समग्र शिक्षा के तहत, वर्ष 2023–24 में निम्नलिखित विवरण के अनुसार कुल 1728 टिंकरिंग लैब स्वीकृत किए गए हैं:

I. 2023-24

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पीएबी अनुमोदन	
		वास्तविक	वित्तीय (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	70	700.00
2	अरुणाचल प्रदेश	2	20.00
3	असम	66	660.00
4	दमन और दीव–दादर और नगर हवेली (परियोजना नवाचार)	6	72.00
5	कर्नाटक (परियोजना नवाचार माध्यमिक)	106	848.00
6	कर्नाटक (आरएए)	106	212.00
7	महाराष्ट्र (परियोजना नवाचार)	491	4910.00
8	मणिपुर	104	1040.00
9	मेघालय (परियोजना नवाचार)	50	500.00
10	मिजोरम (परियोजना नवाचार)	10	100.00
11	पुदुचेरी	500	2.50
12	पंजाब	117	836.00
13	त्रिपुरा	100	1000.00
कुल योग		1728	10900.50

बालिकाओं हेतु आत्मरक्षा प्रशिक्षणः

बालिकाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने और उन्हे स्कूल में या स्कूल के बाद किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का सामना करने के लिए तैयार करने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग सरकारी स्कूलों की कक्षा छठी से बारहवीं तक की बालिकाओं को समग्र शिक्षा के "रानी लक्ष्मी बाई आत्मा रक्षा प्रशिक्षण" के तहत आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। मार्शल आर्ट और आत्मरक्षा प्रशिक्षण पहले से ही सरकारी स्कूलों और केजीबीवी में दिए जाते हैं। यह प्रशिक्षण बालिकाओं को हमले के खतरे से निपटने और उनके आत्म–सम्मान और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाने में सहायता करता है। वर्ष 2023–24 में 203146 प्रारम्भिक और 87531 माध्यमिक राजकीय

स्कूलों को स्कूलों में आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु अनुमोदित किया गया।

विद्यांजलि:

विद्यांजलि पोर्टल स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। इसका प्रयास स्कूलों में सरकार के अलावा अन्यत्र उपलब्ध संभावनाओं का दोहन करके ज्ञान/कौशल/मानव संसाधन और अवसंरचना से संबंधित कमियों को कम करना है। यह सरकार की जिम्मेदारी को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं है, बल्कि सर्वोत्तम संभव तरीके से अंतिम मील तक पहुंचने के सरकारी प्रयासों की पूर्ति, अनुपूर्ति और सुदृढीकरण के लिए है।

विद्यांजलि की सहायता से– शैक्षिक संस्थानों के पूर्व छात्र, सेवारत और सेवानिवृत्त शिक्षक, वैज्ञानिक, सरकारी/अर्ध–सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त सशस्त्र बल कर्मी, स्व–नियोजित और वेतनभोगी व्यावसायिक, गृहिणी, भारतीय प्रवासी और किसी अन्य संगठन/समूह के व्यक्ति या कंपनी अपने ज्ञान और कौशल को साझा करके या संपत्तियों/सामग्री/उपकरण का योगदान करके अपनी पसंद के स्कूलों में स्वेच्छा से भाग ले सकते हैं।

स्कूलों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर, कोई भी स्वयंसेवक, अपनी विशेषज्ञता/रुचि के क्षेत्र अथवा संपत्ति और सामग्री के आधार पर, या सेवाओं के रूप में स्कूलों के अनुरोध पर आंशिक/पूर्ण योगदान देता है। अब तक 6,85,555 स्कूल जुड़ चुके हैं और 4,47,701 स्वयंसेवकों ने विद्यांजलि पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। स्वयंसेवकों ने कई क्षेत्रों में रुचि व्यक्त की है जैसे विषय सहायता, प्रतिभाशाली बच्चों को परामर्श, व्यावसायिक कौशल सिखाना, स्कूलों के लिए प्रोजेक्टर, लैपटॉप और पुस्तकालय प्रायोजित करना आदि। स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी के साथ, यह कार्यक्रम देश भर में 60,94,113 छात्रों को प्रभावित करने में सफल रहा है।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम:

'आकांक्षी जिला परिवर्तन कार्यक्रम' का उद्देश्य 112 चिन्हित जिलों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार करना है। कार्यक्रम के तीन मुख्य सिद्धांत हैं– अभिसरण (केंद्रीय और राज्य योजनाओं का), सहयोग (जिला दलों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नागरिकों और पदाधिकारियों के बीच), और जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा। मुख्य रूप से राज्यों द्वारा संचालित, यह पहल प्रत्येक जिले की क्षकता पर ध्यान केंद्रित करती है, और तत्काल सुधार के लिए प्राप्य परिणामों को प्राथमिकता देती है।

शिक्षा क्षेत्र समग्र सूचकांक का 30% हिस्सा बनता है। 8 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की पहचान की गई है जो अधिगम परिणामों (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक और बाद में माध्यमिक स्कूल शिक्षा तक ट्रांजिशन दर, गणित और भाषाओं में औसत अंक आदि) के साथ–साथ अवसंरचना (बालिकाओं के लिए शौचालय तक पहुंच, पेयजल, बिजली आपूर्ति) और संस्थागत संकेतक (आरटीई अनिवार्य छात्र–शिक्षक अनुपात, पाठ्यपुस्तकों की समय पर उपलब्धता) पर केंद्रित हैं। समग्र शिक्षा योजना के माध्यम से आकांक्षी जिलों में शैक्षिक अवसंरचना की परिपूर्णता पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (एबीपी):

माननीय प्रधान मंत्री ने 7 जनवरी, 2023 को आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एबीपी भारत के दुर्गम और कम विकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार पर ध्यान केंद्रित करेगा। एबीपी प्रमुख क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कृषि और जल संसाधन, वित्तीय समावेशन और कौशल विकास, बुनियादी ढांचा और समग्र सामाजिक विकास के तहत वर्गीकृत प्रमुख सामाजिक–आर्थिक संकेतकों की निगरानी पर ध्यान

केंद्रित करेगा। 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में 500 पिछड़े ब्लॉक फैले हुए हैं, जिनमें 313 जिले शामिल हैं, (जिनमें से 112 आकांक्षी जिले हैं), और 500 में से 160 ब्लॉक आकांक्षी जिलों से हैं।

- इन ब्लॉकों में स्कूल शिक्षा में प्रगति की निगरानी के लिए 11 प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) की पहचान की गई है।
- इन 500 ब्लॉकों में उत्पन्न असाधारण उत्साह को प्रसारित करने के लिए, 03 से 09 अक्टूबर 2023 तक सभी 500 एबीपी ब्लॉकों को कवर करने वाले स्कूलों में एक 'संकल्प सप्ताह' आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 30 सितंबर 2023 को भारत मंडपम में किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, केपीआई के आधार पर पहचान किए गए 100 सबसे कम विकसित आकांक्षी ब्लॉकों को अंतिम रूप दिया गया और इसे नीति आयोग के साथ साझा किया गया।
- एबीपी में केपीआई को सम्मिलित करने के लिए कार्य योजना के अनुसार, समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्य योजना और बजट, 2024–25 और 2025–26 में आकांक्षी ब्लॉकों/जिलों के प्रस्तावों को शामिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 24 नवंबर 2023 को एक अ.शा. पत्र भी जारी किया गया था।

एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान:

एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा एकता दिवस (31 अक्तूबर 2015) को सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के अवसर पर भाषाई, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेल, पर्यटन और लोगों के बीच अन्य प्रकार के जनसम्पर्क के माध्यम से राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय मंत्रालयों, शैक्षणिक संस्थानों और आमजन के बीच एक समन्वित पारस्परिक संपर्क प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क को सक्रिय रूप से बढ़ाना है। लोगों के बीच संवाद के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को भारत के दूसरे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के साथ युग्मित किया गया है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी) कार्यक्रम को लागू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग द्वारा एनईपी 2020 के अनुसार स्कूलों में की जाने वाली प्रस्तावित गतिविधियों की एक उदाहरणात्मक सूची तैयार की गई है और राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और संबंधित संगठनों के साथ साझा की गई है। ईबीएसबी के तहत, वर्ष 2023 के दौरान देश भर से कुल मिलाकर **2 करोड़** छात्रों ने नियमित ईबीएसबी गतिविधियों में भाग लिया है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान ओडिशा, गुजरात, तेलंगाना, केंद्रीय विद्यालय और सीबीएसई आदि स्कूलों में **4 लाख** से अधिक ईबीएसबी क्लब बनाए गए हैं।

व्यावसायिक शिक्षा:

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग समग्र शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना लागू कर रहा है। समग्र शिक्षा योजना के तहत व्यावसायिक शिक्षा एक घटक है। इस योजना का उद्देश्य सभी माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में सामान्य शैक्षणिक शिक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा को एकीकृत करना; छात्रों की रोजगार और उद्यमशीलता क्षमताओं को बढ़ाना, कार्य माहौल का एक्सपोजर प्रदान करना; विभिन्न कैरियर विकल्पों के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता पैदा करना है ताकि वे अपनी योग्यता, क्षमता और आकांक्षाओं के अनुसार चयन करने में सक्षम हो सके।इस योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को शामिल किया गया है। इस योजना में कक्षा VI से VIII के छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान है, जिसका

उद्देश्य छात्रों को एक क्षेत्र में विभिन्न व्यवसायों के लिए अपेक्षित कौशल के साथ स्वयं को उन्मुख करने के अवसर प्रदान करना और उच्चतर कक्षाओं में अपने विषयों का चयन करते समय उन्हें सूचित विकल्प चुनने के लिए तैयार करना है।

'समग्र शिक्षा' के व्यावसायिक शिक्षा घटक के तहत, योजना के अंतर्गत आने वाले स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को एनएसक्यूएफ–अनुरूप व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता है, जिसे राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ) के साथ जोड़ा गया है। माध्यमिक स्तर अर्थात कक्षा IX और X में, छात्रों को एक अतिरिक्त विषय के रूप में व्यावसायिक मॉड्यूल प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अर्थात कक्षा XI और XII में, व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनिवार्य (वैकल्पिक) विषय के रूप में प्रदान किए जाते हैं। स्कूल छात्रों हेतु व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन निर्धारित घंटों, आयु और शैक्षिक योग्यता और उपयुक्तता के आधार पर किया जाता है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को अन्य शैक्षणिक विषयों के समान माना जाए और विषयों की योजना में समान दर्जा प्रदान किया जाए।

एनईपी के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, समग्र शिक्षा की मौजूदा योजना को नया रूप दिया गया है और व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न नई गतिविधियों को शामिल किया गया है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- व्यावसायिक शिक्षा के दायरे को बढ़ाकर उसमें सरकारी स्कूलों के अतिरिक्त सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को भी शामिल किया गया है।
- हब एवं स्पोक मॉडल का प्रावधान किया गया है। इस मॉडल के तहत, हब स्कूलों में उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए नजदीकी स्कूलों (स्पोक स्कूलों) के छात्रों द्वारा किया जाएगा। आईटीआई, पॉलिटेक्निक आदि को भी हब के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हब एंड स्पोक मॉडल के तहत 1111 हब स्कूलों और 1150 स्पोक स्कूलों को मंजूरी दी गई है।
- समग्र शिक्षा के नवाचार घटक के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा, इंटर्नशिप, बैगलेस डे आदि को शामिल किया गया है। वर्ष 2023–24 तक 53823 स्कूलों में उच्च प्राथमिक छात्रों हेतु व्यावसायिक शिक्षा को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत 15,20,773 छात्रों को एक्सपोजर दिया गया है।

पीएबी 2023–24 तक, योजना के तहत 23132 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से अब तक 21,54,306 छात्रों के नामांकन के साथ 17617 स्कूलों में यह योजना लागू की गई है। वर्ष 2022–23 तक व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 63 जॉब रोल्स वाले 19 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। वर्ष 2022–23 से, व्यावसायिक शिक्षा में और अधिक अन्वेषण करने के लिए स्कूलों हेतु 3 नए क्षेत्र और 25 जॉब रोल्स शुरू किए जाएंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अब राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कौशल अंतर विश्लेषण के अनुसार 22 क्षेत्रों और 88 नौकरी भूमिकाओं में से चयन कर सकते हैं। समग्र शिक्षा के कोई घटक के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए राज्य प्रस्ताव के अनुसार आवर्ती एवं और आवर्ती गतिविधियों के लिए 240035.63 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

इस विभाग द्वारा राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) को स्वीकार कर लिया गया है और स्कूलों में एनसीआरएफ के कार्यान्वयन के लिए 13 दिसंबर 2023 को सभी हितधारकों के साथ एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला भी आयोजित की गई थी। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में एनसीआरएफ को लागू करने के लिए सीबीएसई ने एसओपी विकसित किए हैं। सीबीएसई द्वारा एक मॉडल के रूप में विकसित एसओपी का संदर्भ देते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से एनसीआरएफ के संदर्भ में अपने स्वयं के एसओपी विकसित करने का अनुरोध किया गया है।

सांख्यिकी:

वर्ष 2020–21 एवं 2021–22 के लिए सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) इस प्रकार है:

वर्ष	प्रारम्भिक (I-VIII)			माध्यमिक (IX-X)			उच्च माध्यमिक (XI-XII)		
	समस्त	एससी	एसटी	समस्त	एससी	एसटी	समस्त	एससी	एसटी
2020-21	99.1	108.6	102.7	79.8	84.8	78.6	53.8	56.1	45.2
2021-22	100.1	109.7	103.4	79.6	84.9	78.1	57.6	61.5	52.0

1. **भारत के सभी स्कूलों से डाटा के ऑनलाइन संग्रह के लिए यूडाइज़+ पारिस्थितिकी तंत्र'':** ''शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस (यूडाइज़+)'' पूरे भारत में शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर सांख्यिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा विकसित स्कूल शिक्षा का एक प्रमुख डाटाबेस है। प्रभावी रूप से, यूडाइज़+ स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में वास्तव में "एक राष्ट्र एक डाटाबेस" बन गया है। यूडाइज़+ पोर्टल इनबिल्ट सत्यापन जांच के साथ स्कूल स्तर पर डाटा को ऑनलाइन अपलोड करने की सुविधा देता है और उसके बाद ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर डाटा सत्यापन, डाटा की विश्वसनीयता और समय पर पूर्णता सुनिश्चित करता है। यूडाइज़+ के माध्यम से वर्ष 2021–22 तक प्रत्येक स्कूलों में नामांकन पर संचयी डाटा एकत्र किए गए थे, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों पर विचार करते हुए वर्ष 2022–23 से पहली बार ड्रॉपआउट, अधिगम परिणाम, अकादमिक क्रेडिट, स्वास्थ्य रिकॉर्ड आदि के लिए प्रत्येक छात्रों की ट्रैकिंग की सुविधा के लिए यूडाइज़+ आवेदन को प्रत्येक छात्र–वार विवरण प्राप्त करने के लिए पुनः शुरू किया गया है। वर्ष 2022–23 के लिए 94.83 लाख शिक्षकों और 25.18 करोड़ छात्रों को कवर करने वाले कुल 14.66 लाख स्कूल यूडाइज़+ पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा रहे हैं। इन सभी 25.18 करोड़ छात्रों लिए, भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट आईडी (एपीएएआर) विकसित की जा रही है, जो सही लाभार्थी की पहचान करने में सहायता करेगी और फर्जी छात्रों को बाहर निकालने में मदद करेगी, जिससे सरकार को महत्वपूर्ण बचत होगी, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर व्यय प्रबंधन और सुशासन होगा। रिपोर्ट के साथ यूडाइज़+ पारिस्थितिकी तंत्र को https://udiseplus.gov.in/#/Publication पर एक्सेस किया जा सकता है।

2. **प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक (पीजीआई) – राज्य और संघ राज्य क्षेत्र:** डीओएसईएल ने स्कूल शिक्षा के विभिन्न डोमेन जैसे अधिगम परिणाम, पहुंच परिणाम, अवसंरचना, सुविधाएं, इक्विटी परिणाम एवं दूसरी श्रेणी में उपस्थिति, शिक्षक पर्याप्तता, प्रशासनिक पर्याप्तता, प्रशिक्षण, जवाबदेही और पारदर्शिता आदि, से 70 संकेतकों को जोड़कर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) विकसित किया है, जिनका कुल भार 1000 अंक है। पीजीआई की परिकल्पना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षकों की ऑनलाइन भर्ती और स्थानांतरण, छात्रों और शिक्षकों की इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति आदि जैसी कुछ कार्यों को करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एक टूल के रूप में की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की पहल के साथ सामंजस्य बिठाने और इष्टतम लक्ष्य प्राप्त करने वाले मौजूदा संकेतकों को बदलने हेतु, वर्ष 2021–22 से पीजीआई–राज्य संरचना को संशोधित किया गया है और इसका नाम बदलकर पीजीआई 2.0 कर दिया

गया है। नई पीजीआई संरचना में 73 संकेतक हैं, जो डिजिटल पहल और शिक्षक शिक्षा को शामिल करने के साथ ही गुणात्मक मूल्यांकन पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक के लिए पीजीआई–राज्य रिपोर्ट अब तक जारी की जा चुकी है और इसे https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home पर देखा सकता है। तथापि, 2022–23 हेतु पीजीआई 2.0 रिपोर्ट शीघ्र ही जारी की जाएगी।

3. **प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक जिला (पीजीआई–डी)**: राज्य पीजीआई के सफल कार्यान्वयन के आधार पर, पीजीआई को जिलों तक विस्तारित किया गया है और इसे पीजीआई–डी कहा जाता है, जिसमें 83 संकेतकों में 600 अंकों का कुल भार शामिल है, जिन्हें 6 श्रेणियों नामतः परिणाम, प्रभावी कक्षा संचालन, अवसंरचना सुविधाएं और छात्रों के अधिकार, स्कूल सुरक्षा और बाल संरक्षण, डिजिटल अधिगम और शासन प्रक्रिया में बांटा गया है। पीजीआई–डी जिलों को दस ग्रेडों में वर्गीकृत करता है, अर्थात, प्राप्त उच्चतम ग्रेड को दक्ष कहा जाता है, जो उस श्रेणी में या कुल मिलाकर 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जिलों के लिए है। पीजीआई–डी में सबसे निचले ग्रेड को आकांक्षी–3 कहा जाता है जो कुल अंकों के 10: तक के स्कोर के लिए होता है। पीजीआई–डी का अंतिम उद्देश्य जिलों को स्कूल शिक्षा गतिविधियों के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में सहायता करना है और इस प्रकार उच्चतम ग्रेड तक पहुंचने में सुधार करना है। पीजीआई–डी राज्यों को जिला स्तर पर डाटा निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वर्ष 2018–19 से 2021–22 के लिए पीजीआई–डी रिपोर्ट जारी की जा चुकी है और इसे https://pgi.udiseplus.gov.in/#/home पर देखा जा सकता है। वर्ष 2022–23 के लिए पीजीआई जिला रिपोर्ट अंतिम चरण में है और शीघ्र जारी की जाएगी।

4. **पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) में स्कूलों की सहभागिता**: पीएम गति–शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाकर निर्बाध और एकीकृत लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग पहला विभाग है जिसने 14.66 लाख स्कूलों के लिए आवश्यक और वांछित 15 डाटा परतों को शामिल किया है, जिसमें पीएम गति–शक्ति पोर्टल पर विभिन्न स्कूल प्रकार और श्रेणियां शामिल हैं जिन्हें अन्य मंत्रालयों/विभागों और राज्यों के साथ उनकी संबंधित परियोजनाओं या निर्णय लेने के लिए साझा किया जा सकता है। पीएम गति–शक्ति एनएमपी पोर्टल पर उपलब्ध स्कूलों की सटीक पहचान योग्य जियोटैग लोकेशन स्कूलों को परिवहन सुविधा, स्कूलों में छात्रों की मेडिकल जांच सहित स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम और पीएम पोषण योजना के तहत बच्चों को भोजन की आपूर्ति करने में सहायता करेगी।

5. **डाटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई)**: नीति आयोग ने केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संबंध में मंत्रालयों/विभागों की डाटा तैयारियों का आकलन करने के लिए 2020 में डीजीक्यूआई प्लेटफॉर्म विकसित किया है। इसके लिए, मंत्रालयों द्वारा साक्ष्य–आधारित योजना और प्रौद्योगिकी के उपयोग का आकलन करने के लिए 630 से अधिक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं/केंद्र प्रायोजित योजनाओं/गैर–योजनाबद्ध कार्यों के लिए 74 मंत्रालयों/विभागों का चयन किया गया है। डीजीक्यूआई भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों का आकलन 0 से 5 के समान पैमाने पर करता है। डीजीक्यूआई 1.0 (2021) में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का स्कोर 5 में से 2.95 था, जिसे डीजीक्यूआई 2.0 (2022) में 4.28 तक सुधारा गया गया और डीजीक्यूआई (2023)

में उल्लेखनीय रूप से सुधार करके 4.71 कर दिया गया, जिससे यह सभी मंत्रालयों/विभागों में छठा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बन गया।

6. **राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) के लिए नमूना डिजाइन तैयार करने के लिए एनसीईआरटी को तकनीकी सहायताः** राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में बच्चों के आवधिक मूल्यांकन के लिए, परख ने कक्षा 3, 6 और 9 के छात्रों को कवर करते हुए एक नमूना–आधारित राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण (एसईएएस) आयोजित किया। इस अध्ययन के लिए, सांख्यिकी ब्यूरो, डीओएसईएल ने वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया अर्थात् स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग के माध्यम से छात्रों और स्कूलों के चयन के लिए एक नमूना फ्रेम तैयार करके परख को तकनीकी सहायता प्रदान की, जिसमें 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लगभग 2.86 लाख स्कूल, 1.12 करोड़ छात्र शामिल हैं।

7. **देश भर के सभी केंद्रीय और राज्य बोर्डों से परीक्षा परिणामों का संकलनः** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग देश में 62 परीक्षा बोर्डों द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के परिणामों संबंधी डाटा का समेकन करता है। सूचना का प्रसार माध्यमिक और उच्च माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए बोर्ड परीक्षा परिणामों को दर्शाने वाले एक समग्र डाटासेट के दृष्टिकोण से किया जाता है। यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो विभिन्न बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं की गुणवत्ता तय करने में एक प्रमुख कारक है। वर्ष 2022 के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा के परिणाम संबंधी रिपोर्ट डीओएसईएल द्वारा प्रकाशित की गई है, जो https://www.education.gov.in/statistics-new लिंक पर उपलब्ध है।

8. **वैश्विक सूचकांक और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 4):** स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसई और एल) "मानव विकास सूचकांक (एचडीआई)" और "मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआई)" संबंधी प्रकाशन एजेंसियों के अद्यतन डाटा की निगरानी और आपूर्ति के लिए एक नोडल विभाग है और वैश्विक एजेंसियों द्वारा प्रकाशित लगभग 15 अन्य प्रमुख वैश्विक सूचकांकों के लिए शैक्षिक संकेतकों पर डाटा प्रदान करने के लिए एक रापुरूष विभाग के रूप में भी कार्य करता है। इसके अतिरिक्त, समय पर डाटा की रिपोर्टिंग और बेहतर डाटा कवरेज विभिन्न वैश्विक सूचकांकों में देशों के प्रदर्शन को तय करने में प्रमुख कारक हैं। इसलिए डीओएसईएल दृढ़ता से सभी हितधारकों जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), उच्चतर शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय से यूआईएस को समय पर आंकड़ों समन्वय, एकत्र करते है और प्रदान करने में शामिल है। यूआईएस को वर्ष 2022–23 का डाटा भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे सभी वैश्विक सूचकांकों में भारत के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद है। सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का लक्ष्य 4 एसडीजी चार्टर में शिक्षा के बारे में है और डीओएसई एंड एल ने भारत द्वारा अपनाए गए 15 संकेतकों पर यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स (यूआईएस) को कोविड महामारी के बाद बेंचमार्क निर्धारण सहित नवीनतम सूचना प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, भारत उन शीर्ष देशों में से एक है जिसने एनएएस 2021 के पूरा होने और वर्ष 2022–23 तक के नवीनतम नामांकन डाटा के बाद सक्रिय रूप से वर्ष 2025 और 2030 के लिए बेंचमार्क निर्धारित किया है।

❖ ❖ ❖

02

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रमुख योजनाएँ

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की प्रमुख योजनाएँ

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) योजना

पृष्ठभूमि

नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण में वृद्धि करने और साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से, दिनांक 15 अगस्त 1995 को एक केंद्र प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम (एनपी–एनएसपीई)' शुरू की गई थी। वर्ष 2008–09 में, इस योजना का विस्तार बढ़ाकर उसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया था और इस योजना का नाम बदलकर 'राष्ट्रीय स्कूल मध्याह्न भोजन कार्यक्रम' कर दिया गया था। आर्थिक कार्य संबंधी केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने केंद्र सरकार से ₹ 54061.73 और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन से ₹ 31733.17 करोड़ के वित्तीय परिव्यय के साथ वर्ष 2021–22 से 2025–26 की पांच वर्ष की अवधि के लिए स्कूलों में प्रधान मंत्री पोषण शक्ति निर्माण (पीएम पोषण) को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। पीएम पोषण योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बालवाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) और I–VIII कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी स्कूली बच्चों को शामिल किया गया है।

योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना का उद्देश्य भारत में अधिकांश बच्चों के लिए दो प्रमुख समस्याओं अर्थात भूख और शिक्षा का निम्नलिखित रूप से समाधान करना है:

i. सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा I से VIII और सरकारी प्राथमिक स्कूलों में बाल वाटिका (कक्षा I से ठीक पहले) में पढ़ने वाले बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार करना।

ii. वंचित वर्गों से संबंधित गरीब बच्चों को नियमित रूप से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें कक्षा की गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता करना।

iii. गर्मी की छुट्टियों के दौरान सूखा प्रभावित क्षेत्रों में प्रारंभिक स्तर के बच्चों को पोषण सहायता प्रदान करना।

औचित्य

i. कक्षा के दौरान लगने वाली भूख: समाज के वंचित वर्गों से संबंधित कई बच्चे खाली पेट स्कूल पहुंचते हैं। यहां तक कि स्कूल जाने से पहले भोजन करने वाले बच्चों को भी दोपहर तक भूख लग जाती है और वे पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। पीएम पोषण योजना उन परिवारों के बच्चों की मदद कर सकती है जो लंच बॉक्स नहीं खरीद सकते हैं या स्कूलों से दूर रह रहे हैं, ताकि "कक्षा के दौरान लगने वाली भूख" पर नियंत्रण किया जा सके।

ii. स्कूल की भागीदारी को बढ़ावा देना: पीएम पोषण योजना से न केवल रजिस्टर में अधिक बच्चों को नामांकित करने के मामले में बल्कि दैनिक आधार पर नियमित छात्र उपस्थिति के मामले में भी स्कूल की भागीदारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

iii. **बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनाना:** पीएम पोषण योजना बच्चों के स्वस्थ विकास को सुगम बनाने हेतु "पूरक पोषण" के नियमित स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकती है।

iv. **आंतरिक शैक्षिक मूल्य:** एक सुव्यवस्थित पीएम पोषण योजना का उपयोग बच्चों को विभिन्न अच्छी आदतें (जैसे खाने से पहले और बाद में हाथ धोना) सिखाने के अवसर के रूप में और उन्हें स्वच्छ पानी, बेहतर सफाई और अन्य संबंधित मामलों के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

v. **सामाजिक समानता को बढ़ावा देना:** पीएम पोषण योजना समतावादी मूल्यों के प्रसार में मदद कर सकती है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमि के बच्चे एक साथ बैठते हैं और एक साथ भोजन करना सीखते हैं। विशेष रूप से, पीएम पोषण योजना स्कूली बच्चों के बीच जाति और वर्ग की बाधाओं को तोड़ने में मदद कर सकती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों के रसोइयों को नियुक्त करना बच्चों को जातिगत पूर्वाग्रहों को दूर करना सिखाने का एक और तरीका है।

vi. **जेंडर समानता को बढ़ाना:** स्कूल की भागीदारी में जेंडर अंतर कम होता है, क्योंकि पीएम पोषण योजना लड़कियों को स्कूल जाने से रोकने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। यह योजना महिलाओं के लिए रोजगार का एक उपयोगी स्रोत भी प्रदान करती है और कामकाजी महिलाओं को दिन में घर पर खाना पकाने के बोझ से मुक्त करने में मदद करती है। इन और अन्य तरीकों से, महिलाओं और बालिकाओं की पीएम पोषण योजना में विशेष हिस्सेदारी है।

vii. **मनोवैज्ञानिक लाभ:** शारीरिक अभाव से आत्म–सम्मान में कमी, परिणामी असुरक्षा, चिंता और तनाव होता है। पीएम पोषण योजना इनका समाधान करने में सहायता कर सकती है और संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक विकास की सुविधा प्रदान कर सकती है।

कवरेज

वर्ष 2023–24 के दौरान, देश के 10.67 लाख पात्र स्कूलों में बाल वाटिका और कक्षा I–VIII में पढ़ने वाले 11.67 करोड़ बच्चों को इस योजना के तहत कवर किया गया था। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–I** में दिया गया हैं।

पीएम–पोषण योजना के लिए मानदंड

i. **गर्म पके हुए भोजन का कैलोरी महत्व**

प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, पके हुए पीएम पोषण भोजन में प्रति बच्चा 100 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं/पोषक तत्वों से भरपूर अनाज), 20 ग्राम दालें, 50 ग्राम सब्जियां और 5 ग्राम तेल/वसा हैं जो 450 कैलोरी ऊर्जा और 12 ग्राम प्रोटीन प्रदान करते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए, इसमें प्रति बच्चा 150 ग्राम खाद्यान्न (गेहूं/चावल/पोषक तत्व युक्त अनाज), 30 ग्राम दालें, 75 ग्राम सब्जियां और 7.5 ग्राम तेल/वसा शामिल हैं जो 700 कैलोरी ऊर्जा और 20 ग्राम प्रोटीन प्रदान करते हैं।

ii. खाना पकाने की लागत में दालें, सब्जियां, खाना पकाने के तेल, मसाले, ईंधन आदि पर होने वाला खर्च शामिल है। पिछले 5 वर्षों में से प्रत्येक में (वर्ष 2016–17 में 7% को छोड़कर) खाना पकाने की लागत में 7.5% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2017–18 में खाना पकाने की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई। खाना पकाने की लागत में वर्ष 2018–2019 के दौरान 5.35%, 2019–20 के दौरान 3.09% और 2020–21 के दौरान 10.99% की वृद्धि हुई थी। योजना को जारी रखने का अनुमोदन करते हुए, सीसीईए ने नीति आयोग, व्यय विभाग,

राष्ट्रीय पोषण संस्थान, महानिदेशक कार्यालय, श्रम ब्यूरो, श्रम मंत्रालय, कुछ राज्य सरकारों के सचिव, एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के खाद्य और पोषण विभाग के विभागाध्यक्ष/प्रोफेसर आदि से लिए गए सदस्यों वाली विशेषज्ञों की एक समिति गठित करके स्कूल शिक्षा और सक्षरता विभाग ने खाना पकाने की लागत की समीक्षा को मंजूरी दे दी। तदनुसार, माननीय शिक्षा मंत्री के अनुमोदन से, एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति (एनएलईसी) का गठन किया गया। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने पीएम पोषण योजना के तहत सामग्री लागत में संशोधन के संबंध में राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति (एनएलईसी) की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। तदनुसार, 1 अक्तूबर, 2022 से वर्ष 2022–2023 के लिए मौजूदा सामग्री लागत के अतिरिक्त सामग्री लागत में 9.6: की वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए खाना पकाने की लागत क्रमशः 5.45 रुपये और 8.17 रुपये प्रति बच्चा प्रति दिन है।

खाना पकाने की लागत केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों के साथ–साथ विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) के बीच 90:10 के आधार पर, बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के आधार पर साझा की जाती है। विगत वर्षों, वर्तमान वर्ष के दौरान भोजन पकाने की लागत के मानदंड और केन्द्र और राज्यों के बीच साझाकरण पैटर्न निम्नानुसार है:

वर्ष	स्तर	कुल लागत प्रति भोजन (रुपये में)	केंद्र–राज्य शेयरिंग			
			गैर–एनईआर राज्य (75:25)		एनईआर राज्य (90:10)	
2013-14	प्राथमिक	3.34	2.51	0.83	3.01	0.33
	उच्च प्राथमिक	5.00	3.75	1.25	4.5	0.50
2014-15	प्राथमिक	3.59	2.69	0.90	3.23	0.36
	उच्च प्राथमिक	5.38	4.04	1.34	4.84	0.54
संशोधित फंडिंग पैटर्न		**बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (100%)**	**60:40 (गैर एनईआर) और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र**		**एनईआर और 3 हिमालयी राज्य (90:10)**	
2015-16	प्राथमिक	3.86	2.32	1.54	3.47	0.39
	उच्च प्राथमिक	5.78	3.47	2.31	5.20	0.58
2016-17	प्राथमिक	4.13	2.48	1.65	3.72	0.41
	उच्च प्राथमिक	6.18	3.71	2.47	5.56	0.62
2017-18	प्राथमिक	4.13	2.48	1.65	3.72	0.41
	उच्च प्राथमिक	6.18	3.71	2.47	5.56	0.62
2018-19	प्राथमिक	4.35	2.61	1.74	3.91	0.44
	उच्च प्राथमिक	6.51	3.91	2.60	5.86	0.65

फंडिंग पैटर्न		100% बिना विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र	60:40 (गैर एएनईआर) और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (एनसीटी दिल्ली एवं पुडुचेरी)		एनईआर और 2 हिमालयी राज्य और जम्मू–कश्मीर अर्थात विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (90:10)	
2019-20	प्राथमिक	4.48	2.69	1.79	4.03	0.45
	उच्च प्राथमिक	6.71	4.03	2.68	6.04	0.67
2020-21	प्राथमिक	4.97	2.98	1.99	4.47	0.50
	उच्च प्राथमिक	7.45	4.47	2.98	6.70	0.75
2021-22	प्राथमिक	4.97	2.98	1.99	4.47	0.50
	उच्च प्राथमिक	7.45	4.47	2.98	6.70	0.75
2022–23 (01.10.2022 से प्रभावी)	प्राथमिक	5.45	3.27	2.18	4.91	0.54
	उच्च प्राथमिक	8.17	4.90	3.27	7.35	0.82
2023-24	प्राथमिक	5.45	3.27	2.18	4.91	0.54
	उच्च प्राथमिक	8.17	4.90	3.27	7.35	0.82

iii) रसोइया–सह–सहायक की नियुक्ति और उनका मानदेय:

25 छात्रों के लिए एक रसोइया–सह–सहायक, 26 से 100 छात्रों वाले स्कूलों के लिए दो रसोइया–सह–सहायक और हर बार 100 से अधिक छात्र बढ़ने की स्थिति में एक अतिरिक्त रसोइया–सह–सहायक की नियुक्ति की जा सकती है। उनमें से प्रत्येक प्रति माह 1,000 रुपये के न्यूनतम मानदेय का हकदार है। तथापि, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से रसोइयों–सह–सहायकों को निर्धारित न्यूनतम से अधिक अतिरिक्त मानदेय देने के लिए स्वतंत्र हैं।28 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र न्यूनतम अनिवार्य राज्य शेयर **(अनुलग्नक–II)** के अतिरिक्त अपने स्वयं के संसाधनों से अतिरिक्त मानदेय प्रदान कर रहे हैं। रसोइया–सह–सहायकों के मानदेय के लिए व्यय को केंद्र और पूर्वोत्तर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और जम्मू और कश्मीर अर्थात विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र के बीच 90:10 के आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60:40 के आधार पर साझा किया जाता है। सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड–पीएम पोषण ने 2023–24 के दौरान योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 25.70 लाख रसोइया–सह–सहायकों की नियुक्ति को मंजूरी दी। **(अनुलग्नक–III)**।

iv) रसोई–सह–भंडार का निर्माण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को रसोई–सह–भंडार के निर्माण के लिए केंद्रीय सहायता प्लिंथ क्षेत्र मानदंडों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित दरों की राज्य अनुसूची के आधार पर जारी की जा रही है। इस विभाग ने 100 बच्चों वाले स्कूलों में किचन–कम–स्टोर के निर्माण के लिए 20 वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र निर्धारित किया है। हर बार 100 बच्चें बढ़ने की स्थिति में, अतिरिक्त 4

वर्ग मीटर प्लिंथ क्षेत्र जोड़ा जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर 100 बच्चों के स्लैब को संशोधित करने की छूट है। रसोई–सह–भंडार के निर्माण की लागत केंद्र और एनईआर राज्यों और 2 हिमालयी राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर) के बीच 90:10 के आधार पर, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और अन्य राज्यों और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी) के बीच 60:40 के आधार पर साझा की जाती है।

वर्ष 2006–07 से 2022–23 तक 9.75 लाख रसोई–सह–भंडार के निर्माण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8441.51 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी, इसमें से 9.06 लाख रसोई–सह–भंडारों (93%) का निर्माण किया जा चुका है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार विवरण **अनुलग्नक–IV** में हैं।

v) **विशेष श्रेणी के राज्यों में परिवहन सहायता:**

10 विशेष श्रेणी के राज्यों (अर्थात असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, उत्तराखंड और त्रिपुरा) और 2 संघ राज्य क्षेत्रों (अर्थात जम्मू और कश्मीर और लद्दाख) में परिवहन सहायता इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रचलित पीडीएस दरों के बराबर देय है। अन्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, खाद्यान्न का परिवहन उनकी पीडीएस दरों के बराबर दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 150/– रुपये प्रति क्विंटल है।

vi) **एफसीआई को जिला स्तर पर खाद्यान्न की लागत के भुगतान का विकेंद्रीकरण:**

खाद्यान्न की लागत का भुगतान, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत किया गया था, उसे दिनांक 01.04.2010 से जिला स्तर पर विकेंद्रीकृत कर दिया गया है ताकि खाद्यान्नों को शीघ्र उठाना सुनिश्चित करने और भारतीय खाद्य निगम को समय पर भुगतान में जिला अधिकारियों की भूमिका और अधिक हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सके, जिसके परिणामस्वरूप एफसीआई को भुगतान करने में लगने वाले समय में कमी आई है।

विकेंद्रीकृत खरीद योजना नौ राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में शुरू की गई है। इस योजना के तहत, राज्यों को पीएम–पोषण योजना के तहत उपयोग के लिए स्थानीय रूप से उत्पादित खाद्यान्न खरीदने की अनुमति दी गई है।

केंद्रीय सहायता का पैटर्न

पीएम–पोषण योजना के तहत, केंद्र सरकार खाद्यान्न, परिवहन लागत और निगरानी प्रबंधन एवं मूल्यांकन (एमएमई) की पूर्ण लागत वहन करती है।

खाना पकाने की लागत और रसोइया–सह–सहायकों को मानदेय केंद्र और एनईआर राज्यों और हिमालयी राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (जम्मू और कश्मीर) के बीच 90:10 के आधार पर, विधानमंडल रहित संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100%, अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी) के बीच 60:40 के आधार पर साझा किया जाता है। इसी प्रकार, रसोई–सह–भंडार, रसोई–उपकरणों की खरीद/प्रतिस्थापन और दस वर्ष पुराने रसोई उपकरणों की मरम्मत के लिए अनावर्ती केंद्रीय सहायता केंद्र और एनईआर राज्यों और हिमालयी राज्यों के बीच 90:10, संघ राज्य क्षेत्रों को 100: और अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों (एनसीटीटी दिल्ली और पुडुचेरी) के साथ 60:40 के अनुपात में साझा की जाती है।

निधि जारी करने की प्रक्रिया: वर्ष 2022–23 से पीएफएमएस के तहत निधि जारी करने की नई प्रक्रिया

के संबंध में वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार निधि जारी की जाती है। योजना के तहत, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी)—पीएम पोषण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी एंड बी) को मंजूरी देता है। केंद्रीय सहायता वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुपालन के अधीन पीएबी—पीएम पोषण के अनुमोदन के आधार पर जारी की जाती है। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करना आवश्यक है:

i. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीएम पोषण योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग के सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीएफआर—12सी के निर्धारित प्रारूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) जमा करना।

ii. खाद्यान्न आवंटन, उसकी लिफ्टिंग एवं उपयोग की जानकारी निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना।

iii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केंद्रीय शेयर की सम्पूर्ण राशि और उसके अनुरूप राज्य शेयर को राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) के खाते में स्थानांतरित करना।

iv. भारत की समेकित निधि (सीएफआई) में केंद्रीय शेयर के लिए अर्जित ब्याज को जमा करना।

v. निधियां जारी करते समय राज्य के शेयर सहित एसएनए खाते में उपलब्ध निधियां जारी की जाने वाली संभावित किश्त (केंद्रीय शेयर + राज्य शेयर) के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi. पीएम पोषण योजना के तहत केंद्र और राज्य के शेयर के लिए अलग—अलग बजट लाइन राज्य की विस्तृत अनुदान मांग (डीडीजी) में खोली जानी चाहिए।

vii. राज्य द्वारा जारी निधियों का कम से कम 75: उपयोग किया जाना चाहिए (केंद्रीय शेयर और संबंधित राज्य शेयर दोनों)।

viii. एसएनए के साथ सभी कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) की मैपिंग।

पीएम—पोषण योजना का कार्यान्वयन

i. पात्र बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक पात्र स्कूल में सम्पूर्ण, पौष्टिक और पका हुआ भोजन नियमित रूप से परोसा जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी लॉजिस्टिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाएं। इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास जैसे कि रसोई—सह—भंडार का निर्माण, और योजना के तहत उपलब्ध कराए गए धन के माध्यम से रसोई उपकरणों की खरीद, और अन्य विभागों या राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के बजटीय समर्थन के अन्य विकासात्मक कार्यक्रमों के साथ अभिसरण के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाना शामिल है। समग्र शिक्षा, पेयजल मिशन और संपूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम के अनुरूप पेयजल और शौचालय सुविधाओं का निर्माण किया जाना है।

ii. खाद्यान्न आवंटन अग्रिम रूप से किया जाता है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के पास तिमाही आवंटन एक बार में उठाने की छूट होती है। एफसीआई उत्तर पूर्व क्षेत्र के मामले में अपने डिपो और प्रमुख वितरण केंद्रों में पर्याप्त खाद्यान्न की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। प्रत्येक स्कूल/खाना पकाने वाली एजेंसी को एक महीने की आवश्यकता के लिए खाद्यान्न का बफर स्टॉक बनाए रखना है।

खाना पकाने का कार्य

i. दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है कि जहां तक संभव हो, खाना पकाने/पके हुए भोजन की आपूर्ति की जिम्मेदारी स्थानीय महिलाओं/माताओं के स्वयं

सहायता समूह या नेहरू युवा केंद्रों से संबद्ध स्थानीय युवा क्लब या किसी स्वैच्छिक संगठन या एसएमसी/वीईसी/एसएमडीसी/पीटीए/ ग्राम पंचायत/नगर पालिका द्वारा सीधे तौर पर नियुक्त किए गए कार्मिकों को सौंपी जानी चाहिए।

ii. शहरी क्षेत्रों में, जहां किचन शेड के निर्माण के लिए जगह की कमी है, स्कूलों के समूह के लिए केंद्रीकृत रसोई के उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। खाना पकाने का काम एक केंद्रीकृत रसोई में किया जा सकता है और पके हुआ गर्म भोजन को एक विश्वसनीय परिवहन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न स्कूलों में स्वच्छता के साथ ले जाया जा सकता है। बच्चों की संख्या और सेवा प्रदाताओं की क्षमता के आधार पर शहरी क्षेत्र में एक या एक से अधिक ऐसे नोडल किचन हो सकते हैं।

गरम पके हुए भोजन की गुणवत्ता

i. भोजन की गुणवत्ता काफी हद तक खाद्यान्न की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। सर्वोत्तम उपलब्ध गुणवत्ता के खाद्यान्न प्रदान करने की जिम्मेदारी एफसीआई को सौंपी गई है, जो किसी भी मामले में कम से कम उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) का होगा। पीएम–पोषण कार्यक्रम के तहत खाद्यान्न आपूर्ति में विभिन्न समस्याओं का ध्यान रखने के लिए एफसीआई प्रत्येक राज्य के लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। जिला कलेक्टर/जिला पंचायत के सीईओ यह सुनिश्चित करते हैं कि कम से कम एफएक्यू का खाद्यान्न एफसीआई और कलेक्टर और/या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत के नामिती दल द्वारा संयुक्त निरीक्षण और उनके द्वारा कम से कम एफ़एक्यू मानदंडों के अनुरूप होने की पुष्टि के बाद कम से कम एफ़एक्यू गुणवत्ता वाला खाद्यान्न उठा लिया जाता है।

ii. केंद्र सरकार ने विभिन्न स्तरों पर पीएम पोषण योजना के लिए एक प्रभावी प्रबंधन संरचना स्थापित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं; इसमें बच्चों को भोजन परोसे जाने से पहले कम से कम एक शिक्षक सहित 2–3 वयस्कों द्वारा भोजन का अनिवार्य परीक्षण; स्कूलों में सामग्री का सुरक्षित भंडारण और आपूर्ति; महाराष्ट्र की तर्ज पर ब्रांडेड और एग–मार्क गुणवत्ता वाली दालों और सामग्री की खरीद और आपूर्ति शामिल हैं।

iii. पीएम–पोषण के तहत स्कूल स्तरीय रसोई के लिए खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर विस्तृत दिशानिर्देश दिनांक 13.02.2015 को जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों में खाद्य पदार्थों की खरीद, भंडारण, तैयारी, परोसने और अपशिष्ट निपटान के सुरक्षा पहलुओं के साथ–साथ छात्रों और भोजन पकाने और परोसने में शामिल लोगों की व्यक्तिगत स्वच्छता के मुद्दों को शामिल किया गया हैं। इसके अतिरिक्त, दिनांक 21.12.2022 को पीएम पोषण योजना पर जारी व्यापक दिशानिर्देशों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता पर उपर्युक्त दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है।

iv. जिले के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन;

v. **प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस):** योजना की प्रभावी ऑनलाइन निगरानी के लिए वेब–सक्षम पीएम पोषण–एमआईएस को शुरू किया गया है। यह पोर्टल श्रेणीवार नामांकन, शिक्षक (पीएम पोषण की देखभाल करने वाले) विवरण, सामाजिक संरचना के साथ रसोइया–सह–सहायकों का विवरण, रसोई– सह–भंडार और रसोई उपकरण

ों जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, खाना पकाने का तरीका, पेयजल, प्रसाधन सुविधाओं जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों के संबंध में वार्षिक आधार पर सूचना एकत्रित करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भी पोर्टल में मासिक डाटा फीड कर रहे हैं, जो पीएम–पोषण के महत्वपूर्ण घटकों/संकेतकों जैसे कि परोसे गए भोजन की संख्या, खाद्यान्न का उपयोग और खाना पकाने की लागत,रसोइया–सह–सहायकों को भुगतान किया गया मानदेय, स्कूल निरीक्षण विवरण आदि की निगरानी में मदद करता है।

vi. **स्वचालित निगरानी प्रणाली (एएमएस)**: इस विभाग ने पीएम पोषण योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए डेटा संग्रह की एक स्वचालित प्रणाली स्थापित की है। इस तरह के डेटा (उस विशेष दिन पर परोसे गए भोजन की संख्या और यदि भोजन नहीं परोसा गया तो कारण) को स्कूल के प्रधानाध्यापक/शिक्षक से बिना किसी लागत के स्कूलों से प्राप्त किया जा रहा है। स्वचालित निगरानी प्रणाली के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने दैनिक आधार पर स्कूलों से डाटा संग्रह (अर्थात इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस)/एसएमएस/ मोबाइल एप्लिकेशन/वेब एप्लिकेशन) की एक उपयुक्त प्रणाली स्थापित की है और इसका उपयोग निगरानी और समय पर अनुवर्ती कार्रवाई के उद्देश्य से किया जाता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वास्तविक समय के आधार पर एनआईसी द्वारा अनुरक्षित केंद्रीय सर्वर पर पूर्वनिर्धारित प्रारूप में विशिष्ट क्षेत्रों संबंधी डाटा भेज रहे हैं। केन्द्रीय स्तर पर डाटा के विश्लेषण एवं प्रदर्शन हेतु एक केन्द्रीय पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। एकत्रित आंकड़ों के आधार पर, राष्ट्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर पर योजना की वास्तविक समय निगरानी के लिए विभिन्न ड्रिल–डाउन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्यो संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिदिन ईमेल अलटै भेजा जाता है, जिसमें उन स्कूलों की संख्या के सारे में जानकारी दी जाती है जिन्होंने उस विशेष तिथि पर आकड़े उलबंब्ध कराए हैं तथा जिन स्कूलों में भोजन नही परोसा गया है।

vii. चिकित्सीय आपातकाल हेतु आकस्मिकता योजनाः राज्य/सीएसओ/एनजीओ के पास किसी भी अप्रिय घटना के लिए एक आकस्मिक योजना होनी चाहिए। नजदीकी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, एम्बुलेंस, पुलिस, फायर–ब्रिगेड के नाम और दूरभाष नंबर प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएं।

viii. हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु **शिकायत निवारण तंत्र**।

क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना और आसानी से सुलभ बनाया जाना चाहिए।

ख) उपर्युक्त के अतिरिक्त, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र लोक शिकायत निवारण के लिए समर्पित तंत्र भी विकसित करेंगे, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना और आसानी से सुलभ (जैसे टोल–फ्री कॉल सुविधा आदि) बनाया जाना चाहिए।

निगरानी तंत्र

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने पीएम–पोषण योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक व्यापक और विस्तृत तंत्र निर्धारित किया है। निगरानी तंत्र में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **स्थानीय स्तर पर निगरानी की व्यवस्थाः** ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों,

एसएमसी, वीईसी, पीटीए, एसडीएमसी के सदस्यों के साथ–साथ मातृ समितियों से अपेक्षा की जाती है कि वे (i) बच्चों को परोसे जाने वाले गर्म पके हुए भोजन की नियमितता और पौष्टिकता, (ii) खाना पकाने में स्वच्छता और गर्म पका हुआ भोजन परोसना, (iii) अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री, ईंधन आदि की खरीद में समयबद्धता, (iv) विविध व्यंजन–सूची का कार्यान्वयन, (v) दैनिक आधार पर सामाजिक और जेंडर समानता आदि की निगरानी करें।

ii. **सूचना का प्रदर्शन**: कार्यक्रम की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी स्कूलों और केंद्रों, जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, को आम जनता की सूचना के लिए परिसर में एक स्पष्ट स्थान पर निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करना आवश्यक है:

क) प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा, प्राप्ति की तिथि।

ख) उपयोग किए गए खाद्यान्न की मात्रा

ग) खरीदी गई, उपयोग की गई अन्य सामग्री

घ) भोजन लेने वाले बच्चों की संख्या।

ई) दैनिक व्यंजन–सूची

च) पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए समुदाय के सदस्यों का रोस्टर।

iii. **ब्लॉक स्तरीय समिति**: एक व्यापक– आधार वाली संचालन–सह–निगरानी समिति भी ब्लॉक स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

iv. **राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण**: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के राजस्व, ग्रामीण विकास, शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास, खाद्य, स्वास्थ्य आदि विभागों जैसे अन्य संबंधित क्षेत्रों से संबंधित अधिकारियों को भी उन स्कूलों और केंद्रों का निरीक्षण करना होता है जहां कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। यह सिफ़ारिश की गई है कि हर तिमाही में 25% स्कूलों का दौरा किया जाए।

v. **जिला स्तरीय समिति**: जिला स्तरीय संचालन – सह–निगरानी समिति के अतिरिक्त, योजना की निगरानी के लिए जिले के वरिष्ठतम संसद सदस्य की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति का गठन तिमाही आधार पर किया गया है।

vi. **आवधिक विवरणी**: राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को (i) बच्चों और संस्थाओं के कवरेज, (ii) स्कूल दिवसों की संख्या (iii) केंद्रीय सहायता के उपयोग में प्रगति (iv) स्कूलों में आवश्यक अवसंरचना की उपलब्धता, (v) किसी अप्रिय घटना आदि के बारे में सूचना प्रदान करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार को आवधिक विवरणियां प्रस्तुत करनी होती हैं।

vii. **शिकायत निवारण**: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को लोक शिकायत निवारण के लिए एक समर्पित तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है, जिसे व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना चाहिए और सुलभ बनाया जाना चाहिए।

viii. **राज्य स्तरीय निगरानी**: राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को भी योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर एक संचालन–सह–निगरानी समिति का गठन करना आवश्यक है। योजना के मूल्यांकन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्वतंत्र संस्थानों को नियुक्त किया है।

ix. **राष्ट्रीय स्तर की निगरानी**:

(क) योजना के कार्यान्वयन में पहुंच, सुरक्षा, स्वच्छता और गुणवत्ता पहलुओं की निगरानी के लिए माननीय मंत्री, शिक्षा

मंत्रालय की अध्यक्षता में पीएम पोषण संबंधी अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है; योजना की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा तंत्र मौजूद है; योजना में सामुदायिक भागीदारी और इसकी प्रभावी निगरानी के लिए तंत्र मौजूद है।

(ख) शिक्षा मंत्रालय के माननीय मंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समग्र शिक्षा मिशन (एसएस) की कार्यकारी परिषद भी पीएम–पोषण योजना की समीक्षा करती है।

(ग) राष्ट्रीय स्तर की संचालन–सह–निगरानी समिति (एनएसएमसी), सचिव (एसई एंड एल) की अध्यक्षता में, कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) भी निगरानी करता है।

(घ) योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शिक्षा सचिवों के साथ राष्ट्रीय बैठकें और क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

x. **संयुक्त समीक्षा मिशन** ने 2018–19 के दौरान 5 राज्यों नामतः आंध्र प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का दौरा किया। वर्ष 2019–20 के दौरान असम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में 12वें संयुक्त समीक्षा मिशन का दौरा प्रस्तावित था। देशभर में कोविड–19 महामारी के कारण स्कूल बंद थे, इसलिए संयुक्त समीक्षा मिशन ने केवल छत्तीसगढ़ और कर्नाटक राज्यों का दौरा किया। वर्ष 2020–21 और 2021–22 के दौरान देश भर में कोविड–19 महामारी के कारण स्कूलों के बंद होने के कारण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा नहीं किया जा सका। 13वें संयुक्त समीक्षा मिशन ने 4 राज्यों नामतः असम, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल का दौरा किया।

xi. **पीएम–पोषण योजना की सामाजिक लेखापरीक्षा और इसकी स्थिति** : "सामाजिक लेखा परीक्षा" का अर्थ उस प्रक्रिया से है जिसमें लोग सामूहिक रूप से किसी कार्यक्रम या व्यवस्था की योजना और कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करते हैं। विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचित किया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की धारा 28 के प्रावधानों के तहत योजना की सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य है। पीएम पोषण दिशानिर्देशों के अनुसार, योजना के तहत कवर किए गए कम से कम 2% स्कूलों या 20 स्कूलों, सभी जिलों में जो भी अधिक हो, में सामाजिक लेखा परीक्षा करना अनिवार्य है। विभाग ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से पीएबी बैठकों और संयुक्त समीक्षा मिशन, समीक्षा बैठकों, कार्यशालाओं, क्षेत्रों का दौरा आदि जैसे विभिन्न अन्य मंचों पर नियमित आधार पर सभी स्कूलों में पीएम–पोषण योजना की अनिवार्य रूप से सामाजिक लेखापरीक्षा कराने और इंगित की गई कमियों के मामले में सुधारात्मक उपाय करने का अनुरोध किया है। योजना के अंतर्गत सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।

वर्ष 2023–24 के दौरान, 33 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के 761 जिलों के 41591 स्कूलों में सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित की जा रहीं हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा 6 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूर्ण हो चुकी है और 25 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक लेखापरीक्षा के आयोजन की स्थिति **अनुलग्नक–VI** में दी गई है।.

xii. **स्कूल पोषण (रसोई) उद्यान:** योजनांतर्गत लगभग सभी स्कूलों में स्कूल पोषण (रसोई) उद्यान विकसित किए जा रहे हैं। स्कूल पोषण किचन–गार्डन स्कूल के मैदान का उपयोग करके छात्रों को प्राकृतिक दुनिया से फिर से जोड़ने और उन्हें अपने भोजन के वास्तविक स्रोत के बारे में जागरूक करने का एक शानदार माध्यम है, जिससे वे मूल्यवान बागवानी और कृषि अवधारणाओं और कौशलों को सीखते है जो कई विषयों जैसे गणित, विज्ञान, कला, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा, और सामाजिक अध्ययन, साथ ही व्यक्तिगत और सामाजिक जिम्मेदारी सहित कई शैक्षिक लक्ष्यों के साथ एकीकृत होते हैं। स्कूल पोषण किचन–गार्डन छात्रों को बागवानी अवधारणाओं की समान सीख का पालन करने और अपने घरों में शुरू करने का अवसर प्रदान करते हैं। स्कूलों में इस तरह के किचन–गार्डन की स्थापना का उद्देश्य छात्रों को आजीवन कौशल प्रदान करना है और उन्हें स्कूल में सीखे गए अपने ज्ञान का उपयोग करके घर में जहां भी जगह उपलब्ध हो वहां अपना बगीचा शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। देश भर के 4.11 लाख से अधिक स्कूलों में स्कूल पोषण गार्डन स्थापित किए गए हैं। **(अनुलग्नक–VI)**

योजना का प्रभाव

(i) कई अध्ययनों से पता चला है कि पीएम–पोषण योजना ने कक्षा के दौरान लगाने वाली भूख को रोकने; स्कूल की भागीदारी को बढ़ने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने तथा जेंडर समानता को बढ़ाने मे सहायता की है जिससे बच्चों के समग्र स्वस्थ विकास में मदद मिली है। उच्चतम न्यायालय आयुक्त का कार्यालय क्षेत्र के दौरों के माध्यम से विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की व्यापक समीक्षा करता है। उन्होंने पाया है कि पीएम–पोषण को व्यापक रूप से भारत सरकार की सबसे सफल पात्रता योजनाओं में से एक के रूप में स्वीकार किया गया है और इसके परिणामस्वरूप प्रारंभिक कक्षाओं में बच्चों के नामांकन और प्रतिधारण में वृद्धि हुई है।

(ii) **योजना की निगरानी एवं मूल्यांकन**

इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना उचित है कि नीति आयोग ने वर्ष 2019–2020 के दौरान पीएम–पोषण योजना का स्वतंत्र तृतीय पक्ष मूल्यांकन किया है। प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

i. यह योजना सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) 2 और 4 के साथ–साथ 'स्कूल शिक्षा में समावेश' के राष्ट्रीय विकास एजेंडा के लिए प्रासंगिक है।

ii. पीएम–पोषण छात्रों के लिए दिन के महत्वपूर्ण भोजन में से एक है और कुछ मामलों में दिन के पहले भाग के लिए एकमात्र भोजन है।

iii. यह योजना प्रभावी है क्योंकि इसमें लाभार्थी दृष्टिकोण के आधार पर अच्छी सुपरिभाषित, यथार्थवादी लक्ष्य हैं।

iv. व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण (2016–2018) के अनुसार एमडीएम प्राप्त करने वाले छात्रों के पोषण स्तर में सुधार बताया गया है।

v. यह विशेष रूप से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा क्षेत्र की जरूरतों और परिणामों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और उन्हें पूरा करता है।

vi. यह योजना विशेष रूप से वंचित पृष्ठभूमि (सामाजिक और आर्थिक रूप से दोनों) के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है।

ये निष्कर्ष राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एनआईएन) के नेतृत्व में 2017–18 में आयोजित 20 राज्यों और संघ

राज्य क्षेत्रों के 70 जिलों में योजना के पहले आयोजित तृतीय पक्ष के मूल्यांकन के अनुरूप हैं। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

i. स्कूलों में उपस्थित होने वाले 92% छात्र एमडीएम का लाभ उठा रहे थे;
ii. 87% विद्यार्थियों को एमडीएम का स्वाद पसंद आया;
iii. 72% बच्चों ने कहा कि एमडीएम ने उन्हें कक्षा के अध्ययन में अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद की;
iv. 96% माता–पिता ने कहा कि एमडीएम उनके बच्चों के लिए फायदेमंद है।
v. 80% से अधिक माता–पिता ने कहा कि एमडीएम से नामांकन और उपस्थिति में वृद्धि हुई है, और उनके बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ;
vi. 96% शिक्षकों ने उल्लेख किया कि एमडीएम से स्कूली बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार हुआ है।
vii. 92% शिक्षकों ने कहा कि एमडीएम से नामांकन में वृद्धि हुई है और उपस्थिति में सुधार हुआ है।
viii. 86% शिक्षकों ने यह भी कहा कि एमडीएम ने स्कूल छोड़ने की दर को कम करने में मदद की।

सिफारिशें:

i. जो राज्य पहले से ही दोपहर के भोजन के समय एमडीएम के अलावा अंडा/दूध/नाश्ता आदि जैसी चीजें प्रदान कर रहे हैं, वे उन्हें सुबह नाश्ते के रूप में प्रदान कर सकते हैं।
ii. एमडीएम भोजन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए 'रसोई उद्यान' विकसित करने की सिफारिश की गई है।
iii. एमडीएम में शिक्षकों की भूमिका यह पर्यवेक्षण करने की होनी चाहिए कि रसोइया–सह–सहायक भोजन तैयार करें, बच्चों को परोसने से पहले भोजन के स्वाद की जांच करें और यह भी सुनिश्चित करें कि एमडीएम के सेवन की पूरी प्रक्रिया मध्यावकाश अवधि के भीतर व्यवस्थित तरीके से पूरी हो जाए।
iv. अंतर–राज्य, अंतर–जिला यात्राओं के माध्यम से अच्छी प्रथाओं को साझा करना।
v. रसोइया–सह–सहायकों का क्षमता निर्माण।
vi. चूंकि, रसोइया–सह–सहायक आधे से अधिक दिन (4–5 घंटे/दिन) काम कर रहे हैं, इसलिए पूरी क्षमता से काम करने के लिए उनके मानदेय को पर्याप्त रूप से संशोधित किया जाए।
vii. एक डेटाबेस विकसित करने के लिए, पीएम–पोषण लाभार्थियों के मानवमितीय मापों को समय–समय पर एकत्र करने और पीएम–पोषण के प्रभाव और उनके पोषण की स्थिति में समय के रुझान की निगरानी करने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए स्थानीय गृह विज्ञान महाविद्यालयों और पोषण अनुसंधान संस्थानों को नियुक्त किया जाए।
viii. केवल आधे स्कूलों के पास आग, चिकित्सा आदि जैसी आपात स्थितियों पर कार्रवाई करने की आकस्मिक योजना थीं, इसलिए सभी स्कूलों के पास अपनी आकस्मिक योजनाएँ होनी चाहिए।
ix. पीएम–पोषण का व्यापक प्रभाव मूल्यांकन किया जाए।
x. पीएम–पोषण निष्पादन, निगरानी, पर्यवेक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण के विशेष संदर्भ में सभी पदाधिकारियों को स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।
xi. आवधिक तृतीय–पक्ष मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाए।

उपलब्धियां

वर्ष 2023–24 के लिए बजट अनुमान 11600 करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान 10000.00 करोड़ रुपये था। विगत पांच वर्षों के दौरान योजना के वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों की वर्षवार उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:–

कवरेज और व्यय रुझान

घटक	2018-19	2019-20	2020-21	2021--22	2022-23	2023-24
लाभार्थी की संख्या (करोड़ रुपये में)	12.03	11.98	11.80	12.21	12.16	11.65
आवंटित खाद्यान्न (लाख मीमीट्रिक टन में)	26.94	26.90	34.45#	30.95	29.68	26.77
बजट आवंटन (करोड़ रुपये में)	10500	11000	12900	10233.75	12800	10000
जारी (करोड़ रुपये में)	9518.08	9705.94	12882.11	10233.75	12681.03	4074.11*

 # खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया गया

** 06.02.2024 तक*

वित्त वर्ष 2023—24 के लिए घटक—वार संशोधित बजट आवंटन 10000 करोड़ रुपये है:

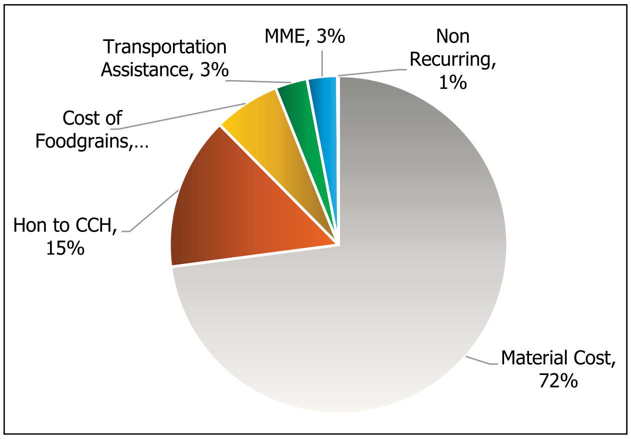

प्रशिक्षण के माध्यम से रसोइया—सह—सहायकों का क्षमता निर्माण

पीएम—पोषण योजना के तहत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन तैयार करना स्कूलों में भोजन उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त कर्मचारियों और रसोइया—सह—सहायकों के ज्ञान और कौशल पर निर्भर है। स्वयं सहायता समूह और रसोइया—सह—सहायक जो पीएम—पोषण योजना के स्तंभ हैं, मुख्य रूप से समाज के वंचित वर्गों से आते हैं, जहां उन्हें पोषण, खाना पकाने की प्रक्रिया, स्वास्थ्य और स्वच्छता, कच्चे अनाज और सब्जियों की तैयारी, व्यंजनों, सेवा कौशल आदि के बारे में सीमित जानकारी है। इसलिए, यह आवश्यक है कि क्षेत्र स्तर पर कार्यबल की क्षमता निरंतर आधार पर बढ़ाई जाए। तदनुसार, शिक्षा मंत्रालय ने राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में होटल प्रबंधन संस्थान, खाद्य शिल्प संस्थानों और खाद्य एवं पोषण संस्थानों के सहयोग से रसोइया—सह—सहायकों के प्रशिक्षण के संचालन करने का कार्य सौंपा है।

योजना में सुधार

विगत कुछ वर्षों में, इस योजना में कई सुधार देखे गए हैं जैसा कि नीचे बताया गया है:

i. खाना पकाने की लागत में वार्षिक वृद्धि मुद्रास्फीति सूचकांक से जुड़ी हुई है।

ii. एनएफएसए दर पर पोषणयुक्त चावल की आपूर्ति

iii. गैर—विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 75 रुपये प्रति क्विंटल की परिवहन दर से पीडीएस दर (अधिकतम 150 रुपये प्रति क्विंटल) में संशोधन।

iv. कुल स्वीकार्य आवर्ती केंद्रीय सहायता के 2% से 3% तक प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई) दर में संशोधन।

v. नामांकन के आधार पर रसोई उपकरणों के लिए सहायता को 5,000 रुपये प्रति स्कूल के स्थिर

दर से बढ़ाकर 10,000 रुपये से 25,000 रुपये प्रति स्कूल कर दिया गया है।

vi. 10 वर्ष से अधिक पुराने रसोई–सह–भंडार की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये का एक नया घटक शुरू किया गया है।

vii. व्यवस्थित रूप से खाद्य पदार्थों को पोषणयुक्त बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

viii. जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति को मौजूदा दिशानिर्देशों में मामूली संशोधनों के साथ योजना को लागू करने की शक्ति का प्रत्यायोजन।

ix. राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शिक्षा मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन से उनकी वार्षिक कार्य योजना और नए कार्यकलापों के लिए बजट का 5% उपयोग करने की छूट दी गई है।

x. तिथि भोजन के रूप में सामुदायिक भागीदारी की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाएगा जिसके तहत समुदाय के लोग पीएम–पोषण योजना में योगदान देकर बच्चे के जन्म, विवाह, जन्मदिन आदि जैसे महत्वपूर्ण दिनों का जश्न मनाएंगे।

xi. स्कूल पोषण उद्यान (जिसे किचन–गार्डन भी कहा जाता है) की स्थापना एक समान लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है क्योंकि यह एक ऐसा स्थान और गतिविधि दोनों ही है जहां बच्चे अपना भोजन उगाने का कौशल सीखते हैं।

xii. नई–नई व्यंजन सूचियों को बढ़ावा देने के लिए ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर पाक कला प्रतियोगिताओं का आयोजन।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पीएम–पोषण नियम, 2015 की अधिसूचना:

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पीएम–पोषण नियम, 2015 को 30.09.2015 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। विनियमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:–

i. कक्षा I से VIII में पढ़ने वाले छह से चौदह वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को, जो सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकाय स्कूलों और मदरसों और मकतबों में दाखिला लेते हैं, उन्हें स्कूल की छुट्टी को छोड़कर हर दिन प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए क्रमश: 450 कैलोरी और 700 कैलोरी के साथ–साथ 12 ग्राम और 20 ग्राम प्रोटीन कैलोरी युक्त गर्म पका हुआ भोजन प्रदान किया जाएगा।

ii. स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को स्कूल में पीएम–पोषण योजना को जारी रखने के उद्देश्य से अस्थायी रूप से स्कूल में किसी भी निधि का उपयोग करने का अधिकार होगा।

iii. यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन पीएम–पोषण नियमों द्वारा निर्धारित पोषण मानकों और गुणवत्ता को पूरा करता है, राज्य का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग गुणवत्ता का पालन सुनिश्चित करने के लिए यादृच्छिक रूप से चयनित स्कूलों से नमूने एकत्र कर सकता है।

योजना के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त वस्तुएं:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य सामग्री का नाम	आवृति
1	आंध्र प्रदेश	अंडा	सप्ताह में 5 दिन
		अतिरिक्त व्यंजन	सप्ताह में 6 दिन
		चिक्की	सप्ताह में 3 दिन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य सामग्री का नाम	आवृति
2	अरुणाचल प्रदेश	–	–
3	असम	–	–
4	बिहार	अंडा/फल	सप्ताह में एक बार
5	छत्तीसगढ	–	–
6	गोवा	–	–
7	गुजरात	तेल	दैनिक
		सुखडी	एक सप्ताह में एक बार
		दूध (12 जिले और 26 ब्लॉक)	सप्ताह में 5 दिन
8	हरियाणा	दूध	सप्ताह में 3 दिन
9	हिमाचल प्रदेश	–	–
10	झारखंड	अंडा/मौसमी फल	सप्ताह में 2 दिन अर्थात सोमवार और शुक्रवार
11	कर्नाटक	गरम दूध	सप्ताह में 5 दिन
12	केरल	अंडा/केला	1 प्रति सप्ताह
		दूध	प्रति सप्ताह दो बार
13	मध्य प्रदेश	–	–
14	महाराष्ट्र	केला, सोया बिस्कुट, राजगीर लड्डू, चिक्की	निधि की उपलब्धता के अनुसार साप्ताहिक कोई भी
15	मणिपुर	–	–
16	मेघालय	–	–
17	मिजोरम	सब्जी, फल, अंडे, दूध	एक सप्ताह में एक बार
18	नागालैंड	सब्ज़ियाँ	द्वि साप्ताहिक
19	ओडिशा	अंडा	हफ्ते में दो बार
20	पंजाब	मीठी खीर	सप्ताह में एक बार
21	राजस्थान	मौसमी फल	साप्ताहिक
		गर्म दूध	दैनिक
22	सिक्किम	दालें, सब्जियां, तेल और वसा	शून्य
23	तमिलनाडु	अंडा/केला	दैनिक
24	तेलंगाना	अंडा	सप्ताह में तीन बार
25	त्रिपुरा	–	–
26	उत्तर प्रदेश	मौसमी ताजे फल	सप्ताह में एक बार

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	खाद्य सामग्री का नाम	आवृति
27	उत्तराखंड	अंडा/फल/दूध/गुड़पापडी/रामदाना के लड्डू	सप्ताह में एक बार
28	पश्चिम बंगाल	अंडा, पनीर, मशरूम	1 दिन/सप्ताह
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	उबले हुए अंडे	सप्ताह में तीन बार
		पका हुआ केला	सप्ताह में दो बार
30	चंडीगढ़	–	–
31	दमन दीव और दादर नगर हवेली	सुखडी, लापसी	एक–एक दिन छोड़कर
32	दिल्ली	–	–
33	जम्मू एवं कश्मीर	–	–
34	लद्दाख	अंडा/फल/दूध/गुड़पापड़ी/रामदाना के लड्डू	हफ़्ते में एक बार
35	लक्षद्वीप	अंडा, मछली, चिकन, सेब, आम, केला, संतरा, तरबूज	दो दिन/स्थानीय बाजार में सामग्री की उपलब्धता के अनुसार
36	पुदुचेरी	गर्म दूध	दैनिक
		अंडा	सप्ताह में दो बार

प्रौढ़ शिक्षा (उल्लास)

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में गैर–साक्षरों की कुल संख्या 25.76 करोड़ (9.08 करोड़ पुरुष और 16. 68 करोड़ महिलाएं) है। मार्च 2018 तक पूर्ववर्ती साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत 7.64 करोड़ प्रमाणित साक्षर व्यक्तियों की प्रगति को ध्यान में रखते हुए, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्तमान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 18.12 करोड़ वयस्क अभी भी गैर–साक्षर हैं। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस), पढ़ना लिखना अभियान (पीएलए), वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान देश के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू करने के लिए वर्ष 2020 में कोविड–19 महामारी के दौरान अनुमोदित की गई थी। पीएलए का मुख्य उद्देश्य देश में 5 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के 57.00 लाख गैर–साक्षरों को व्यावहारिक साक्षरता (पढ़ना, लिखना और संख्या ज्ञान) प्रदान करना था। पीएलए योजना का कार्यान्वयन एक वर्ष के विस्तार के साथ 31.03.2022 को समाप्त हो गया था।

उल्लास – नवभारत साक्षरता कार्यक्रम

भारत सरकार ने नवभारत साक्षरता कार्यक्रम नामक एक केंद्र प्रायोजित अभिनव योजना को मंजूरी दी है, **जिसे आम तौर पर उल्लास: समाज में सभी के लिए आजीवन सीखने की समझ के नाम से जाना जाता है।** यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमि के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को सशक्त बनाना है, जिन्हें उचित स्कूली शिक्षा नहीं मिल सकी और उन्हें समाज के साथ मुख्यधारा में लाना है ताकि वे देश की विकास गाथा में अधिक योगदान करने में सक्षम हो सकें।

वित्त वर्ष 2022–23 से 2026–27 तक कार्यान्वयन हेतु योजना का बजट 1037.90 करोड़ रुपये है। इस योजना के पाँच घटक हैं, नामत;

क) मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान,

ख) महत्वपूर्ण जीवन कौशल,

ग) बुनियादी शिक्षा,

घ) व्यवसायपरक कौशल,

ङ) सतत शिक्षा।

कार्यान्वयन कार्यनीति

इस योजना को स्वयंसेवा के माध्यम से लागू किया जाना है। यह परिकल्पना की गई है कि "स्वयंसेवक" यूजीसी के तहत स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थाओं और एनसीटीई के तहत शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के छात्र होंगे। इसके अतिरिक्त, योगदान करने के इच्छुक साक्षर व्यक्ति जैसे कि एनवाईएसके, एनएसएस, एनसीसी, सीएसओ, समुदाय के सदस्यों, गृहिणियां, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और शिक्षकों को सक्रिय रूप से शामिल किया जा रहा है। यह एक जीवंत शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए स्वयंसेवा की भावना का उपयोग करते हुए अधिगम के ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों को **मिश्रित** करते हुए एक मिश्रित दृष्टिकोण अपनाता है। स्वयंसेवकों की सामूहिक विशेषज्ञता और समर्पण के माध्यम से, इस योजना का उद्देश्य वयस्कों को ज्ञान और कौशल के साथ सशक्त बनाना है, जनभागीदारी के प्रति सामुदायिक जुड़ाव की एक सुदृढ़ भावना को बढ़ावा देना है।

योजना का कार्यान्वयन **सामाजिक चेतना केंद्रों** के माध्यम से किया जाता है जो यूडाईज के तहत पंजीकृत सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में स्थापित किए जाते हैं। शैक्षिक और संसाधन सहायता प्रदान करने के लिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के भाग के रूप में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र (सीएनसीएल) हेतु एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। सीएनसीएल ने एक व्यापक प्राइमर विकसित किया है जिसका उपयोग स्वयंसेवी शिक्षक (वीटी) प्रौढ़ शिक्षार्थियों को आजीवन अधिगम हेतु उनके पढ़ने और लिखने के कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से एक संरचित और प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए कर रहे हैं।

अखिल भारतीय शिक्षा समागम के दौरान शुभारंभ

माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिनांक 29.07.2023 को अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का लोगो, नारा: जन–जन साक्षर, लोकप्रिय नाम और मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया।

लोगो:

नारा/टैगलाइन : जन जन साक्षर

उल्लास मोबाइल ऐप: इस योजना के तहत, शिक्षार्थियों को सीएनसीएल, एनसीईआरटी के दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्थानीय भाषाओं में ऑनलाइन सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अपनी स्थानीय भाषाओं में सामग्री के उपयोग से, शिक्षार्थी बेहतर समझ, जुड़ाव, सांस्कृतिक प्रासंगिकता, भाषा विकास, समावेशिता और उच्च विचार कौशल के विकास का अनुभव कर सकते हैं।

भाषा सीखने का यह व्यापक दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के समग्र अधिगम परिणामों को बढ़ाने में योगदान देता है।

साक्षरता सप्ताह का आयोजन

दिनांक 1 सितंबर से 8 सितंबर, 2023 तक साक्षरता सप्ताह का राष्ट्रव्यापी उत्सव आयोजित किया गया, जिसका समापन दिनांक 8 सितंबर, 2023 को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह के साथ हुआ। साक्षरता सप्ताह के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई।

- उल्लास मोबाइल ऐप पर लघु फिल्में और इसके उपयोग।
- स्वयंसेवी शिक्षकों और शिक्षार्थियों के लिए उल्लास प्रतिज्ञा।
- उल्लास यूट्यूब चैनल का शुभारंभ।
- सीएनसीएल, एनसीईआरटी द्वारा विकसित उल्लास संबंधी संक्षिप्त प्राइमर का शुभारंभ।
- साक्षरता सप्ताह के दौरान 2.95 करोड़ से अधिक जनभागीदारी (भागीदारी) दर्ज की गई।

मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (एफ़एलएनएटी)

(क) योजना के प्रभाव का आकलन पंजीकृत गैर–साक्षर शिक्षार्थियों के मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान कौशल के प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जा रहा है। इस संबंध में, वर्ष 2022–23 के लिए पहली मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (एफ़एलएनएटी) दिनांक 19 मार्च, 2023 को 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ऑफ़लाइन मोड में हुई। मूल्यांकन इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सरकारी/सहायता प्राप्त स्कूलों में किया गया था। 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 22,36,190 शिक्षार्थी मूल्यांकन परीक्षा में उपस्थित हुए, जिनमें से 20,40,346 शिक्षार्थियों (91.23%) ने एफ़एलएनएटी उत्तीर्ण की और प्रमाणित साक्षर घोषित किए गए।

(ख) उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वित्त वर्ष 2023–24 के लिए पहली मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान आकलन परीक्षा (एफ़एलएनएटी) दिनांक 24 सितंबर, 2023 को 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित की गयी थी, जिसमें 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 18,39,427 शिक्षार्थी इस परीक्षा में उपस्थित हुए और इसके परिणाम की प्रतीक्षा है।

उपलब्धियां/पहलें:

- उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता प्राप्त करने के लिए सभी संघ राज्य क्षेत्रों तथा सिक्किम, गोवा और मिजोरम राज्यों को दिनांक 31.08.2023 का एक पत्र संख्या 5–6/2023–एई–2 भेजा गया था। इस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के अंत तक उपर्युक्त राज्यों में 100% साक्षरता हासिल करने की पहल की है।
- योजना को बढ़ावा देने और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम हेतु एक समर्पित फेसबुक पेज बनाया गया है, जिसके तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की उपलब्धियों और जारी कार्यान्वयन गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया है।
- लिंकः https://www.facebook.com/people/ULLAS-Nav-Bharat-Saaksharta-Karyakram/100092449066375/?mibextid=kLQQJ4d
- नव–साक्षरों को कौशल प्रदान करने के लिए, सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) और सचिव (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय) का दिनांक 17.11.2023 का एक संयुक्त अ.शा.

पत्र नव–साक्षरों को बेहतर रोजगार और उत्पादकता के अवसरों के लिए शिक्षा और कौशल के अभिसरण हेतु 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के शिक्षा और कौशल विकास के सभी सचिवों को भेजा गया था।

- एनईपी 2020 के अधिदेश के संदर्भ में, मार्च, 2021 में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र (प्रकोष्ठ) की स्थापना की गई थी। योजना के सुचारू कार्यान्वयन और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचने के लिए, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य साक्षरता केंद्र (एससीएल) स्थापित करने का प्रस्ताव है, योजना के अनुसार, उल्लास–नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत एससीएल, एससीईआरटी संबंधी अनुमोदित दिशानिर्देश सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजे गए हैं। एससीएल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उल्लास को लागू करने के लिए शैक्षणिक, संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए निदेशक, एससीईआरटी के निदेशों के तहत काम करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारः

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रथम बार 1958 में युवामन के साथ–साथ उनके भविष्य को आकार देने में शिक्षकों की उत्कृष्टता और प्रतिबद्धता को पहचानने के लिए शुरु किए गए थे। 60 के दशक के मध्य से, 5 सितंबर भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में समारोह के लिए निश्चित तिथि हो गई। इस पुरस्कार का उद्देश्य प्रारम्भिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रतिभाशाली शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता प्रदान करना था।

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के दिशा–निर्देशों को वर्ष 2023 में संशोधित किया गया था। मूल आधार यह है कि नई योजना पारदर्शी, निष्पक्ष और प्रतिभाशाली शिक्षकों को पुरस्कृत करने वाली होनी चाहिए ताकि वे अन्य शिक्षकों के लिए उदाहरण और प्रेरणास्रोत बन सकें। नई योजना की विशेषताएं इस प्रकार हैः

i. संशोधित दिशा–निर्देशों में शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन स्व–नामांकन का प्रावधान है जिसे https://nationalawardstoteachers.education.gov.in/ पर किया जाता है।

ii. निम्नलिखित श्रेणियों के तहत मान्यता प्राप्त प्राथमिक/मध्य/उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत स्कूल शिक्षक और स्कूल प्रमुखः

   क) राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा संचालित स्कूल, स्थानीय निकायों द्वारा संचालित स्कूल, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूल।

   ख) केंद्रीय सरकारी स्कूल अर्थात केंद्रीय विद्यालय (के.वि.), जवाहर नवोदय विद्यालय (ज.न.वि.), रक्षा मंत्रालय (एमओडी) द्वारा संचालित सैनिक स्कूल, परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसाइटी (एईईएस) द्वारा संचालित स्कूल और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा संचालित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)।

   ग) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से सम्बद्ध स्कूल (उपर्युक्त (क) और (ख) को छोड़कर)

   घ) काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल्स सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (सीआईएससीई) से संबद्ध स्कूल (उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) के अतिरिक्त।

iii. केवल न्यूनतम दस वर्ष की सेवा वाले नियमित शिक्षक और स्कूलों के प्रमुख ही पात्र हैं।

iv. सामान्यतः सेवानिवृत्त शिक्षक पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन वे शिक्षक जिन्होंने कैलेंडर वर्ष के एक भाग (कम से कम चार महीने यानी जिस वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार संबंधित हैं, उस वर्ष 30 अप्रैल तक) में सेवा की है, यदि वे अन्य सभी शर्तें पूरी करते हैं तो उनके नाम पर विचार किया जा सकता है।

v. वर्ष 2018 में पुरस्कारों की संख्या को तर्कसंगत बनाकर 47 (45+2) कर दिया गया और 2023 में फिर से 50 (48+2) कर दिया गया, जबकि पहले यह संख्या 378 थी, जिससे पुरस्कारों की प्रतिष्ठा बहाल हुई।

vi. इसके अतिरिक्त, विशेष श्रेणी के अंतर्गत 2 शिक्षकों का चयन दिव्यांग शिक्षकों आदि यदि कोई हों, में से किया जा सकता है।

vii. अंतिम चयन में किसी भी राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या संगठन का कोटा नहीं होता। यह उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार हेतु प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।

viii. अंतिम चयन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और संगठनों से प्राप्त नामांकनों में से एक स्वतंत्र निर्णायक मंडल द्वारा किया जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि नई योजना के तहत इन एजेंसियों की भूमिका कम नहीं हुई है।

ix. नामांकित शिक्षक अंतिम चयन के लिए निर्णायक मंडल के समक्ष एक प्रस्तुति देते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि उन सभी को उनके द्वारा किए गए कार्यों को साझा करने का अवसर दिया जाए।

पुरस्कारों की तर्कसंगत संख्या ने पुरस्कारों की प्रतिष्ठा को बहाल किया और चयन प्रक्रिया की बढ़ी हुई पारदर्शिता और शुचिता के साथ शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार को गम्भीरता एवं सम्मान से लेना शुरु किया है।

वर्ष 2018 से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के इतिहास में पहली बार, पुरस्कार विजेताओं में से प्रत्येक द्वारा किए गए अनुकरणीय कार्यों पर एक मिनट की उच्च गुणवत्ता वाली फिल्में बनाई जा रही हैं। इन फिल्मों की शूटिंग पुरस्कार विजेताओं के संबंधित स्कूलों में मौके पर कला और रंगमंच के माध्यम से आनंदमयी शिक्षा को बढ़ावा देने, समुदाय से संसाधन जुटाने, निःशुल्क शैक्षिक ऐप और आईसीटी का उपयोग करने, स्कूल पोषण उद्यान का विकास करने आदि जैसी नवीन गतिविधियों के व्यापक विस्तार को कलात्मक रूप से और संक्षेप में कैप्चर करते हुए की जाती है।

वर्ष 2023 के लिए, जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय चयन प्रक्रिया के बाद ऑनलाइन स्व–नामांकन प्रक्रिया के बाद, भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 5 सितंबर, 2022 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 50 पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। दूरदर्शन पर कार्यक्रम के सीधे प्रसारण के दौरान 50 पुरस्कृत शिक्षकों में से प्रत्येक पर एक वृत्तचित्र फिल्म भी दिखाई गई।

वर्ष 2023 से एनएटी के दायरे में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अतिरिक्त उच्चतर शिक्षा विभाग और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के शिक्षकों को भी शामिल किया गया है। अब पुरस्कारों की कुल संख्या 100 हो गई है, जिसमें स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के 50 पुरस्कार, उच्चतर शिक्षा विभाग के 25 और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के 25 पुरस्कार शामिल हैं।

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस):

केंद्रीय क्षेत्र योजना की 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करना है। योजना के तहत राज्य

सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन हेतु हर साल नौवीं कक्षा के चयनित छात्रों को एक लाख नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और दसवीं से बारहवीं कक्षा में उनकी निरंतरता/उनका नवीनीकरण किया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि 12000/– रुपये प्रति वर्ष है।

सरकार ने कुल 1827 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ इस योजना को वित्त वर्ष 2021–22 से 2025–26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।

पात्रता मापदंड:

जिन छात्रों के माता–पिता की सभी स्रोतों से आय 3,50,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु चयन परीक्षा में उपस्थित होने के लिए छात्रों के सातवीं कक्षा की परीक्षा में न्यूनतम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए 5% की छूट) होना चाहिए। छात्रों को सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूलों में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन करना चाहिए। एनवीएस, केवीएस और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्रवृत्ति के हकदार नहीं हैं। आरक्षण, राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार है।

नए पुरस्कार विजेता छात्रों का चयन:

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों के चयन हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी स्वयं की परीक्षा आयोजित करता है। परीक्षा आठवीं कक्षा के स्तर पर आयोजित की जाती है। पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों को एनएमएमएसएस परीक्षा के तहत दोनों परीक्षाओं, अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षा (एमएटी) और शैक्षणिक योग्यता परीक्षा (एसएटी) में कुल मिलाकर कम से कम 40% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। **एससी/एसटी छात्रों के लिए यह कटऑफ 32% अंक है।**

नवीनीकरण पुरस्कार विजेता छात्रों का चयन:

पुरस्कार विजेताओं को अगली उच्च कक्षाओं में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए दसवीं कक्षा में न्यूनतम 60% अंक **(अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 5% की छूट)** प्राप्त होने चाहिए। कक्षा X और XII में छात्रवृत्ति जारी रखने के लिए, पुरस्कार विजेताओं को प्रथम प्रयास में कक्षा IX से कक्षा X और कक्षा XI से कक्षा XII में स्पष्ट प्रोन्नति मिलनी चाहिए।

छात्रवृत्ति का वितरण:

यह योजना वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पूरी तरह से उपलब्ध है। मंत्रालय सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) द्वारा छात्रों को छात्रवृत्ति सीधे उनके बैंक खातों में वितरित करने की योजना के कार्यान्वयन बैंक एसबीआई को जारी करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान से धनराशि स्वीकृत करता है।

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस) के तहत स्वीकृत छात्रवृत्ति की संख्या और राशि का विवरण।

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	छात्रवृत्तियों की संख्या (नई + नवीनीकरण)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1.	2022-23	259524	299.91

**एनएमएमएसएस को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर रखा गया है, जो आवेदनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रत्येक वर्ष जुलाई से दिसंबर तक संचालित होता है। अंतिम तिमाही में छात्रवृत्ति राशि की मंजूरी और संवितरण हेतु सभी प्रकार से पूर्ण अंतिम रूप से सत्यापित आवेदनों पर विचार किया जाता है।*

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता योजना:

एनईपी 2020 बहुभाषावाद और भाषाओं की शक्ति पर

बल देता है। इसमें कहा गया है कि बच्चे 2 से 8 साल की उम्र के बीच बहुत तेजी से भाषा सीखते हैं और बहुभाषावाद से छोटे बच्चों को काफी संज्ञानात्मक लाभ होता है, इसलिए बच्चों को बुनियादी स्तर से ही विभिन्न भाषाओं से अवगत कराया जाएगा। सभी भाषाओं को मनोरंजक और परस्पर संवादात्मक शैली में भरपूर संवादात्मक बातचीत के साथ पढ़ाया जाएगा।

भाषा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु वित्तीय सहायता घटक का उद्देश्य स्कूलों में हिन्दी और उर्दू भाषा शिक्षण शुरू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना में इस घटक के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- हिंदी शिक्षकों के लिए मानदेय सहायता 30,000/– रुपये प्रति माह तक सीमित है, लेकिन राज्यों में नियमित भाषा शिक्षकों को भुगतान की जाने वाली वेतन राशि से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान सभी वर्गों को शामिल करते हुए केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र और गैर हिन्दी भाषी राज्यों तक सीमित है।
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षकों को मानदेय सहायता 30,000/– रुपये प्रति माह तक सीमित है किंतु नियमित भाषा शिक्षकों को दी जाने वाली वेतन राशि से अधिक नहीं है। यह प्रावधान केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों तक सीमित है जहां प्रति कक्षा 15 या अधिक छात्र भाषा का विकल्प चुनते हैं।
- भाषा शिक्षक वाले स्कूलों के लिए 150 रुपये प्रति छात्र की व्यवस्था की गई है ताकि द्विभाषी शिक्षण–अधिगम सामग्री और पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भाषा शिक्षक की नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हताएं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के मानकों और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हताओं के अनुसार हों।
- शिक्षकों के निरंतर व्यवसायपरक विकास के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का प्रावधान समग्र शिक्षा के अंतर्गत सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण के मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम:

(i) एक केंद्र प्रायोजित योजना 'जीवंत ग्राम कार्यक्रम', दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को अरुणाचल प्रदेश के एक सीमावर्ती गांव किबिथू में शुरू की गई थी। जीवंत ग्राम कार्यक्रम (वीवीपी) का उद्देश्य उत्तरी सीमा से सटे गांवों का व्यापक विकास करना है, जिससे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के चिह्नित सीमावर्ती गांवों के निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। इस कार्यक्रम में 2,963 गांव शामिल हैं, जिनमें से 662 को पहले चरण में कवर करने की योजना है।

(ii) इस कार्यक्रम में विभिन्न मंत्रालयों के साथ मिलकर संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाकर इन गांवों में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति की परिकल्पना की गई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) जीवंत ग्राम कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है और शिक्षा मंत्रालय उन मंत्रालयों में से एक है जो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की मौजूदा योजना के अभिसरण के माध्यम से इन क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए कुछ सक्रिय उपाय करने के लिए भाग ले रहा है।

(iii) इन जीवंत गांवों में शैक्षिक प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अनुपूरक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) के दिनांक 28.11.2023 के कार्यवृत्त के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के लिए ₹ 2367.00 लाख, हिमाचल

प्रदेश के लिए ₹ 124.21 लाख, लद्दाख के लिए ₹ 1017.59 लाख और सिक्किम के लिए ₹ 3473.00 लाख स्वीकृत किए हैं। साथ ही, दिनांक 18 जनवरी, 2024 के परिशिष्ट के माध्यम से, संबंधित राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वर्ष 2023–24 के लिए फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुसार समग्र शिक्षा योजना के तहत उपलब्ध मौजूदा धन से इस खाते पर होने वाले खर्च को पूरा करें। प्रत्येक परियोजना का विवरण राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिनांक 18 जनवरी, 2024 को ईमेल के माध्यम से सूचित किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम–जनमन)

(i) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 15 नवंबर, 2023 को प्रधान मंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम–जनमन) का शुभारंभ किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय पीएम–जनमन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। पीएम–जनमन अभियान में 18 राज्यों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास की परिकल्पना की गई है। इस अभियान में 11 पहलों/गतिविधियों के लिए 9 मंत्रालयों के साथ अभिसरण में संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण अपनाते हुए इन गांवों में शिक्षा सहित बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति की परिकल्पना की गई है।

(ii) शिक्षा मंत्रालय अभियान में भाग लेने वाले मंत्रालयों में से एक है और पीएम–जनमन को इस विभाग की स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना–समग्र शिक्षा के अभिसरण में लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रावास सुविधा प्रदान करके और मौजूदा स्कूलों के साथ उन्हें जोड़कर असेवित पीवीटीजी बस्तियों को शामिल करना है।

(iii) इस अभियान की अवधि वर्ष 2023–24 से 2025–2026 तक तीन वर्ष है। पीएम–जनमन अभियान में वर्ष 2023–24 से 2025–26 तक₹ 1375 करोड़ (समग्र शिक्षा योजना के फंड शेयरिंग पैटर्न के अनुसार केंद्र और राज्य के हिस्से सहित) के अनुमानित परिव्यय के साथ 500 छात्रावासों के निर्माण की सिफारिश की गई है। तदनुसार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2023–24 के दौरान 100 छात्रावासों के निर्माण को मंजूरी दी है।

❖ ❖ ❖

03

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

स्कूल शिक्षा के लिए संस्थागत सहायता

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.)

केंद्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) की योजना को केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए दूसरे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर नवंबर 1962 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। नतीजतन, केंद्रीय विद्यालय संगठन को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की एक इकाई के रूप में शुरू किया गया था। प्रारंभ में, 20 रेजिमेंटल स्कूल, जो तब रक्षा कर्मियों की बड़ी संख्या वाले स्थानों पर कार्यात्मक थे, को शैक्षणिक वर्ष 1963–64 के दौरान केंद्रीय विद्यालयों के रूप में ले लिया गया था।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन को 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम (1860 का XXI) के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत और विदेशों में स्थित केंद्रीय विद्यालयों (सेंट्रल स्कूल) का प्रावधान करना, उन्हें स्थापित करना, उनका बंदोबस्त करना, रखरखाव करना, उन्हें नियंत्रित करना और प्रबंधित करना है। भारत सरकार संगठन को पूरी तरह से वित्तपोषित करती है। इन वर्षों में, दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों की संख्या लगातार बढ़कर 1254 हो गई, जिसमें विदेश में स्थित तीन केवि (काठमांडू, मास्को, तेहरान) शामिल हैं। डबल शिफ्ट में चलने वाले के.वि. की संख्या 70 है। 1254 के.वि. में से 113 के.वि. पूर्वोत्तर में कार्यात्मक हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं

उपर्युक्त उद्देश्यों के अनुसरण में, केन्द्रीय विद्यालय प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं और मानदंड हैं:

1. सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए सामान्य पाठ्यपुस्तकें और शिक्षण का द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) माध्यम।
2. सभी केन्द्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध हैं।
3. सभी केन्द्रीय विद्यालय सह–शैक्षिक, समग्र विद्यालय हैं।
4. कक्षा छठी से आठवीं तक तीन भाषाओं – अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य है। कक्षा IX और X में, अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में से किन्हीं दो भाषाओं को चुना जा सकता है। संस्कृत को +2 चरणों में वैकल्पिक विषय के रूप में भी लिया जा सकता है।
5. एक आदर्श और अद्यतन कार्यप्रणाली के माध्यम से, के.वि.सं. शैक्षणिक गतिविधियों में उत्कृष्टता बनाए रखने का प्रयास करता है।

के.वि.सं. प्रशासन

माननीय शिक्षा मंत्री केन्द्रीय विद्यालय संगठन और शासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं। शिक्षा मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री संयुक्त अध्यक्ष हैं। आयुक्त संगठन के कार्यकारी प्रमुख हैं। के.वि.सं. के 25 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक का नेतृत्व एक उपायुक्त करता है जो क्षेत्र के सभी केन्द्रीय विद्यालयों के कामकाज की निगरानी करता है। 5 कार्यात्मक जेडआईईटी (जोनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग) हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक निदेशक द्वारा किया जाता है जो उपायुक्त के पद पर है। केन्द्रीय विद्यालयों का नेतृत्व प्रधानाचार्य/प्राचार्य ग्रेड–II द्वारा किया जाता है जो विद्यालय के कामकाज का प्रबंधन करते हैं।

1254 के.वि. का क्षेत्रवार वितरण (दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार) इस प्रकार है:

क्र. सं.	क्षेत्र	के.वि. की संख्या
1	उच्च शिक्षण संस्थाएं	350
2	परियोजनाएं	748
3	विदेश	40
4	कुल	113
5	विदेश	03
	कुल	**1254**

के.वि. में प्रवेश

केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के प्राथमिक उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। इसलिए प्रवेश में प्राथमिकता केंद्र सरकार के कर्मचारियों, राज्य सरकार के कर्मचारियों और निजी कर्मचारियों के बच्चों को उसी क्रम में दी जाती है। प्रवेश पाने वाले बच्चों की अन्य श्रेणियों में, यदि सीटें उपलब्ध हैं, केंद्र सरकार के गैर–स्थानांतरणीय कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्थानांतरणीय और गैर–स्थानांतरणीय कर्मचारी, राज्य सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारी और अस्थायी आबादी के बच्चे शामिल हैं। आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत प्रवेश के अतिरिक्त, सरकारी मानदंडों के अनुसार एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है। दिनांक 30.09.2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विद्यालयों में कुल 14,00,632 छात्र पढ़ रहे हैं जिनमें 7,49,155 लड़के और 6,51,477 लड़कियां हैं। शैक्षणिक सत्र 2016–17 से, कक्षा I में प्रवेश देश भर में एक ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का उपयोग करके किया जा रहा है जो पूरी तरह से स्वचालित है। एनईपी 2020 के कार्यान्वयन के कारण शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से कक्षा I में प्रवेश हेतु प्रवेश आयु 6+ वर्ष (पहले 5+ वर्ष) कर दी गई है। एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुसार एक अच्छा छात्र–शिक्षक अनुपात बनाए रखने के लिए के.वि. में कक्षा की संख्या से अधिक प्रवेश हेतु कुछ विशेष प्रावधान वापस ले लिए गए हैं।

(क) बालिका शिक्षा को सशक्त बनाना

के.वि. में एकल बालिका हेतु प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान है: प्राथमिकता श्रेणी के आधार पर कक्षा I से आगे तक प्रति अनुभाग 2 सीटें। ये सीटें स्वीकृत कक्षा क्षमता के अतिरिक्त उपलब्ध हैं।

(ख) एससी/एसटी और ओबीसी की शिक्षा

सभी केंद्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी–एनसीएल) के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं।

(ग) दिव्यांग छात्रों का शैक्षिक विकास

नव प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध सीटों में से 3% सीटें दिव्यांग बच्चों के लिए क्षैतिज रूप से आरक्षित की जा रही हैं। स्कूल में इन बच्चों की सुविधा सुनिश्चित करने हेतु सभी केंद्रीय विद्यालयों में विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए शौचालय और रैंप अनिवार्य किए गए हैं। सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान शिक्षकों को शारीरिक और साथ ही अधिगम अक्षमता वाले छात्रों की देखभाल के लिए लगातार उन्मुख किया जा रहा है।

(घ) पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम

कोविड–19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत कक्षा की संख्या से अधिक के प्रवेश हेतु विचार किया जाता है। प्रवेश संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सूची के आधार पर प्रति के.वि. 10 बच्चों और प्रति कक्षा अधिकतम 02 बच्चों के आधार पर किया जाता है। इन बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक फीस (ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फंड और वीवीएन) के भुगतान से छूट दी गई

है। वर्तमान में 31.12.2023 तक की स्थिति के अनुसार पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के तहत 254 छात्र के.वि.सं. में पढ़ रहे हैं।

शैक्षणिक प्रदर्शन

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा X और कक्षा–XII परीक्षाओं में पिछले 5 वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन का प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दिया गया है

वर्ष	2019		2020		2021		2022		2023	
कक्षा	X	XII	X	XII	X	XII	X	XII	X	XII
के.वि.सं.	99.47	98.54	99.23	98.62	99.47	98.54	99.23	98.62	98.03	92.57

उत्कृष्टता की ओर बच्चों को केंद्रित करना:

एक प्रमुख शैक्षिक संगठन के रूप में, केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अपने कार्यक्रमों की योजना बनाते और उन्हें लागू करते समय हमेशा बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सुसंरचित शैक्षिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त, बच्चे के व्यक्तित्व के समग्र विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी स्कूलों में कई अन्य सह–शैक्षिक कार्यक्रमों की भी योजना बनाई गई है। सभी केंद्रीय विद्यालय सीबीएसई से संबद्ध हैं और कक्षा I से XII तक शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं (चयनित 495 के.वि. भी बालवाटिका कक्षा (कक्षाएं) चला रहे हैं)। कक्षा एक से पांच तक हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। साथ ही कक्षा VI से VIII तक हिंदी और अंग्रेजी के साथ संस्कृत को एक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है। छात्र कक्षा IX से XII में संस्कृत को एक भाषा के रूप में भी चुन सकते हैं। के.वि.सं. ने बच्चे को प्रमुख दक्षताओं से युक्त करने और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए रटने की बजाय योग्यता–आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता की पुष्टि की। इस पुष्टि को साकार करने के लिए, के.वि.सं. सभी के.वि. में योग्यता–आधारित शिक्षा (सीबीई) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मूल्यांकन को सीबीई के अनुरूप बनाना, सीबीई शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन पर शिक्षकों और छात्रों के लिए संसाधनों के उदाहरण विकसित करना और शिक्षक क्षमता निर्माण जारी रखना शामिल है। समय–समय पर जारी सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन:

एनईपी–2020 ने स्कूली शिक्षा के लिए एक नई संरचना का प्रस्ताव किया है जो विकास के विभिन्न चरणों में शिक्षार्थियों की विकासात्मक आवश्यकताओं और हितों के अनुरूप हो। तदनुसार, इनमें से प्रत्येक चरण के लिए अलग–अलग शैक्षणिक कार्यनीतियाँ सुझाई गई हैं। विभिन्न आंतरिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों के माध्यम से, शिक्षकों को एनईपी–2020 में विशेष रूप से सुझाए गए शैक्षणिक बदलावों को अपनाने के लिए समर्थ बनाया जा रहा है। एनईपी–2020 द्वारा अनुशंसित मिडिल स्कूल चरण के टेस्ट और परीक्षाओं तथा बहु–विषयक परीक्षाओं में योग्यता–आधारित प्रश्नों को शामिल करना शुरू किया गया है। एनईपी 2020 के तहत निम्नलिखित पहल की गई हैं:

(क) केन्द्रीय विद्यालयों में बालवाटिका कक्षाएं

एनईपी 2020 के अनुरूप, केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने प्रायोगिक आधार पर चिह्नित किए गए 50 केन्द्रीय विद्यालयों में क्रमशः 3+, 4+ और 5+ वर्ष की आयु के बच्चों के लिए तीन बालवाटिका कक्षाओं का एक सेक्शन खोला। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र

2023–24 में 445 केन्द्रीय विद्यालयों में 5+ वर्ष के बच्चों के लिए बालवाटिका–3 का एक सेक्शन खोला था। बालवाटिका कक्षाओं में प्रवेश केन्द्रीय विद्यालय संगठन प्रवेश दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। एनसीईआरटी द्वारा उपलब्ध कराए गए शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जा रहा है। इन बालवाटिका कक्षाओं में छात्रों की भागीदारी मुख्य रूप से खेल–आधारित और मनोरंजक शिक्षण गतिविधियों के माध्यम से होती है। शैक्षणिक सत्र के पूरा होने पर, बालवाटिका कक्षाओं के बच्चे स्वतः अगली उच्च कक्षा में प्रोन्नत होंगे। बालवाटिका कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। सभी 495 केन्द्रीय विद्यालयों में 22,000 से अधिक छात्र नामांकित हैं।

(ख) विद्या प्रवेश का कार्यान्वयन

शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में प्राथमिक विद्यालय पाठ्यक्रम के साथ कक्षा– I में प्रवेश करने वाले बच्चों के अधिगम और समायोजन को सहायता प्रदान करने के लिए एनसीईआरटी द्वारा विकसित तीन महीने का खेल–आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से सभी केन्द्रीय विद्यालयों में लागू किया गया है।

(ग) केन्द्रीय विद्यालयों में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान को सुदृढ़ करने की पहल

पढ़ना, लिखना और संख्याओं के साथ बुनियादी क्रियाएं करने की क्षमता सभी भविष्य की स्कूली शिक्षा और आजीवन अधिगम हेतु एक आवश्यक आधार और एक अनिवार्य शर्त है। वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में कई अध्ययनों से पता चलता है कि, एक बार जब छात्र मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान में पीछे रह जाते हैं, तो वे वर्षों तक सीखने के उस स्तर से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और बाद में उस स्तर की प्राप्ति में असमर्थ रहते हैं। बहुत से सक्षम छात्र इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का सामना करते हैं और इससे उभर नहीं पाते हैं। कई छात्रों के लिए, यह स्कूल न जाने या पूरी तरह से पढ़ाई छोड़ देने का एक प्रमुख कारण बन गया है। इसलिए, मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने को निपुण भारत नाम से एक राष्ट्रीय मिशन घोषित किया गया है। मिशन निपुण भारत में कहा गया है कि–

''के.वि.सं. स्कूलों को मिशन मोड में ग्रेड 3 (अब ग्रेड 2) तक के सभी छात्रों द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, के.वि.सं. प्राथमिक स्तर पर योग्यता आधारित शिक्षा शुरू करने और एनसीईआरटी द्वारा विकसित अधिगम परिणाम मैट्रिक्स को अपनाने में अग्रणी होगा। इसलिए, जहां भी संभव हो, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लिए के.वि.सं. में प्रदर्शन कक्षाएं प्रदान की जाएंगी, और के.वि.सं. में सभी प्राथमिक शिक्षकों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान तथा विभिन्न शिक्षण पद्धतियों के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे कि प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखने और सीबीएसई और एनसीईआरटी के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने के लिए एक सुदृढ़ निगरानी तंत्र के माध्यम से वर्ष 2026–2027 तक सभी बच्चे मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त कर लें।''

चूंकि निपुण भारत दस्तावेज़ में दिए गए उपरोक्त बयान ने विशेष रूप से इस महान कार्य में के.वि.सं. की अनूठी भूमिका पर प्रकाश डाला है, के.वि.सं. मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अग्रणी बनने और दूसरों के लिए सहायता प्रदान करने हेतु भी आवश्यक पहल कर रहा है। चूंकि मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान लक्ष्यों

की प्राप्ति सभी छात्रों के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसलिए छात्रों की प्रगति और विकास की निगरानी आवश्यक है। इसलिए, प्रवेश स्तर के मूल्यांकन के अतिरिक्त, सभी छात्रों के लिए छात्रों की क्षमताओं का मध्य–वर्ष और वर्ष के अंत का मूल्यांकन किया गया और केंद्रीय विद्यालय संगठन के पीआईएमएस पोर्टल से जुड़े एक वेब–आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से दर्ज किया गया। मूल्यांकन ने मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में केंद्रीय विद्यालयों के निष्ठापूर्ण प्रयासों को प्रतिबिंबित और प्रदर्शित किया। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु छात्रों का प्रवेश स्तर पर आकलन करने से पहले शिक्षकों द्वारा तीन सप्ताह की अवधि के लिए कई गुणात्मक अवलोकन किए गए।

(घ) केन्द्रीय विद्यालयों में पूर्व–व्यवसायपरक और कौशल शिक्षा

व्यवसायपरक शिक्षा के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और बच्चों की स्कूल अवधि के दौरान उनमें कौशल विकसित करने के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कक्षा आठवीं से सभी के.वि. में व्यवसायपरक कौशल विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कक्षा नौवीं और दसवीं में, छात्रों को वैकल्पिक विषयों के रूप में व्यवसायपरक विषय प्रदान किए जा रहे हैं। एनईपी 2020 के पैरा 4.26 के अनुसार पूर्व–व्यवसायपरक शिक्षा कार्यक्रम को शैक्षणिक वर्ष 2022–23 से छठी से आठवीं कक्षा के लिए मनोरंजक पाठ्यक्रम के रूप में शुरू किया गया है। के.वि. कौशल के साथ शिक्षा के एकीकरण के लिए सभी पहल कर रहे हैं।

एनईपी 2020 में यथापरिकल्पित व्यवसायपरक शिक्षा को सामान्य शिक्षा के साथ एकीकृत करने के लक्ष्य की दिशा में, शिक्षा मंत्रालय और एमएसडीई ने शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र से चिह्नित किए गए देश भर के कौशल केंद्रों में कौशल प्रशिक्षण की कल्पना की है। वर्तमान वर्ष 2023–24 में, देश भर में 350 केन्द्रीय विद्यालयों का उपयोग कौशल भारत केंद्रों (एसआईसी) के रूप में किया जा रहा है और पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत इन–एजुकेशन (अपने स्कूल) और स्कूल न जाने वाले/शिक्षा न पाने वाले युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। कौशल पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 6100 अभ्यर्थी पहले ही नामांकित हो चुके हैं।

(ङ.) केन्द्रीय विद्यालयों में योग्यता आधारित शिक्षा

के.वि.सं. ने बच्चे को प्रमुख दक्षताओं से युक्त करने और 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए रटने की बजाय योग्यता–आधारित शिक्षा की ओर बढ़ने की आवश्यकता की पुष्टि की। इस पुष्टि को साकार करने के लिए, के.वि.सं. सभी के.वि. में योग्यता–आधारित शिक्षा (सीबीई) प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसमें मूल्यांकन को सीबीई के अनुरूप बनाना, सीबीई शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन पर शिक्षकों और छात्रों के लिए संसाधनों के उदाहरण विकसित करना और शिक्षक क्षमता निर्माण जारी रखना शामिल है। समय–समय पर जारी सीबीएसई के दिशानिर्देशों के अनुसार परीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

(च) पीएम श्री स्कूल योजना

पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पहल का उद्देश्य के.वि.सं. और न.वि.स. सहित केंद्र सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों को विकसित करना है, जहां प्रत्येक छात्र का स्वागत और देखभाल की जाती है, जहां एक सुरक्षित और प्रेरक अधिगम का माहौल मौजूद है, जहां व्यापक अधिगम अनुभवों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की जाती है, और जहां सभी छात्रों के अधिगम हेतु

बेहतर भौतिक अवसंरचना व उपयुक्त संसाधन उपलब्ध हैं। यह छात्रों को इस तरह से पोषित करेगा कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यथापरिकल्पित एक समतापूर्ण, समावेशी और बहुलवादी समाज के निर्माण में सहयोगी, उपयोगी और योगदान देने वाले नागरिक बनें।

पहले चरण में, एनईपी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए देश भर के 730 स्कूलों को चुनौती पद्धति के माध्यम से पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुना गया है। उन्नत अवसंरचना, नवीन शिक्षण पद्धति और प्रौद्योगिकी के साथ, ये पीएम श्री स्कूल अनुकरणीय स्कूल होंगे। पीएम श्री स्कूलों में एनईपी 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करने के लिए 21वीं सदी के कौशल से युक्त समग्र और कुशल व्यक्तियों का सृजन और पोषण होगा। ये पीएम श्री स्कूल अपने आसपास के अन्य स्कूलों को सलाह और नेतृत्व प्रदान करेंगे। वर्ष 2023–24 के लिए इस योजना हेतु कुल 590.71 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, जिसमें आवर्ती और गैर–आवर्ती व्यय के लिए क्रमशः 292.71 करोड़ रुपये और 298.0 करोड़ रुपये का प्रावधान है। के.वि.सं. को कुल 147.7 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिनमें से 73.2 करोड़ रुपये आवर्ती और 74.5 करोड़ रुपये गैर आवर्ती व्यय के लिए हैं। माह दिसंबर 2023 तक किया गया व्यय 44.66 करोड़ (प्रतिशत में: 30.24%) है। पीएम श्री योजना की प्रगति की निगरानी के लिए एक इन–हाउस पोर्टल अर्थात https://pmshri.kvsindia.in विकसित किया गया है।

(छ) के.वि.सं. पीएम ई–विद्या डीटीएच चैनल

पीएम ई–विद्या एक व्यापक पहल है जो शिक्षा तक मल्टी–मोड पहुंच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन–एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पीएम ई–विद्या कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा के लिए पीएम ई–विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से शैक्षिक वीडियो सामग्री के प्रसारण के संबंध में के.वि.सं. और एनसीईआरटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस प्रकार, के.वि.सं. का अपना पीएम ई–विद्या चैनल है जिसे डीडी फ्री डिश डीटीएच चैनल नंबर 16 और यूट्यूब पर के.वि.सं. पीएम ई–विद्या के नाम से देखा जा सकता है। इस चैनल के लिए सामग्री के.वि. शिक्षकों द्वारा विकसित की गई है और वीडियो की रिकॉर्डिंग सीआईईटी, एनसीईआरटी के सहयोग से की गई है। अब तक, दिल्ली, गुरुग्राम, आगरा और चंडीगढ़ क्षेत्र के शिक्षकों ने इस चैनल हेतु कक्षा 1 से 12 के लिए 350 वीडियो सामग्री तैयार की है। अन्य क्षेत्रों के शिक्षकों को भी सामग्री तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। चैनल का यूट्यूब लिंक: https://www.youtube.com/channel/UCW8_s0dBUWwFUNfnnkSNqCA

विद्यांजलि पोर्टल विद्यांजलि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश भर के स्कूलों में सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। यह पहल स्कूलों को भारतीय प्रवासियों के विभिन्न स्वयंसेवकों नामतः युवा पेशेवरों, सेवानिवृत्त शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत्त पेशेवरों, गैर सरकारी संगठनों, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, कॉर्पोरेट संस्थानों और कई अन्य लोगों से जोड़ेगी। विद्यांजलि पोर्टल पर 1249 केंद्रीय विद्यालय जुड़े हुए हैं। सभी विद्यालय सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं।

(ज) विद्यांजलि शिक्षा मंत्रालय

भारत सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में सामुदायिक एवं निजी क्षेत्रों की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों का सुदृढ़ीकरण करना है।

यह पहल भारतीय प्रवासियों के विभिन्न स्वयं सेवियों जैसे युवा पेशेवरों, सेवानिवृत शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत पेशेवरों, सेनानिवृत शिक्षकों, सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों, सेवानिवृत पेशेवरों, एनजीओ, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, कॉर्पोरेट संस्थानों और कई अन्य को एक साथ जोड़ेगा। विद्यांजलि पोर्टल पर 1249 केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं। सभी विद्यालय कार्यक्रम में पूरी सक्रियता के साथ उस उद्देश्य से भागीदारी कर रहे है ताकि सामुदायिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से स्कूलों का सुदृढीकरण हो सके।

(झ) राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन (एनएमएम)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 15. 11 का उद्देश्य उत्कृष्ट पेशेवरों का एक बड़ा वर्ग स्थापित करके एक ज्ञान प्रणाली को विकसित करना है, जो स्कूल के शिक्षकों को अल्पकालिक और दीर्घकालिक पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। एनईपी 2020 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में काम करते हुए, एनसीटीई को राष्ट्रीय परामर्शदाता मिशन (एनएमएम) के तौर–तरीकों को विकसित करने और उन्हें तैयार करने का काम सौंपा गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् ने प्रायोगिक आधार पर विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के 16 शिक्षकों को परामर्शदाताओं के रूप में और 15 केन्द्रीय विद्यालयों को परामर्शग्रहीताओं के रूप में पंजीकृत किया है। ये परामर्शदाता शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नियमित सत्र आयोजित कर रहे हैं।

केन्द्रीय विद्यालयों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

पाठ्यचर्या के भाग के रूप में विज्ञान शिक्षण के अतिरिक्त केन्द्रीय विद्यालयों में विभिन्न अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। उपायों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

(क) राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस (एनसीएससी)

एनसीएससी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। एक मार्गदर्शक शिक्षक की देखरेख में छात्रों द्वारा किए गए इस विषय–आधारित शोध परियोजना में, प्रतिभागी (10 से 14 और 14+ से 17 आयु वर्ग के छात्र) मौखिक और पोस्टर प्रस्तुतियां देते हैं और उनकी परियोजनाओं का मूल्यांकन उनकी मौलिकता, व्यावहारिक प्रयोज्यता और लाभों के आधार पर किया जाता है।

एनसीएससी 2023 का विषय निम्नलिखित उप–विषयों के साथ स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना था:

- अपने पारिस्थितिकी तंत्र को जानना
- स्वास्थ्य, पोषण और कल्याण को बढ़ावा देना
- पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक क्रियाएं
- आत्मनिर्भरता के लिए पारिस्थितिकी तंत्र आधारित दृष्टिकोण
- पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य के लिए तकनीकी नवाचार

एनसीएससी का 31वां के.वि.सं. (राज्य) राष्ट्रीय स्तर का आयोजन के.वि. 1 (एएफएस) आगरा में दिनांक 23.11.2023 से 25.11.2023 तक किया गया, जहां कुल 448 प्रदर्शनियां लगाई गईं। इनमें से 42 प्रदर्शनियों को राष्ट्रीय स्तर

के एनसीएससी के लिए चुना गया। इसके अतिरिक्त, केवी नंबर 1 जलाहल्ली, बेंगलुरु की लक्ष्मी केपी द्वारा प्रोजेक्ट "मोथ–द अनसंग पोलिनेटर" को 27 से 31 जनवरी 2023 तक साइंस सिटी, अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित 30 वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में 'उत्कृष्ट' परियोजनाओं में से एक घोषित किया गया था।

(ख) राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी 2023

देश के बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने, लोकप्रिय बनाने और उनमें विकसित करने के उद्देश्य से एनसीईआरटी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करता है जहां बच्चे विज्ञान और गणित में अपनी प्रतिभा और हमारे रोजमर्रा के जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में अपने अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करते हैं।

श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स महालुंगे, बालेवाड़ी, पुणे, महाराष्ट्र–411045 में दिनांक 26 से 31 दिसंबर 2023 तक आयोजित 50वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी (आरबीवीपी), 2023 के लिए केंद्रीय विद्यालयों से 06 छात्रों की परियोजनाओं का चयन किया गया था।

क्र.सं.	डेवलपर छात्र का नाम	स्कूल का नाम	प्रदर्शनी का शीर्षक	मार्गदर्शक शिक्षक का नाम
1	नवीन गुप्ता	केन्द्रीय विद्यालय नंबर 1, गांधीनगर, जम्मू	कुडुज सॉफ्टवेयर	महेश्वर देव
2	गणेश चौधरी	केन्द्रीय विद्यालय मनेन्द्रगढ़	इलेक्ट्रॉनिक स्वचालन प्रणाली	संदीप कुमार पटेल
3	आदर्श. डी	केन्द्रीय विद्यालय नौसेना बेस, कोच्चि	मच्छर लार्वा के प्रबंधन के लिए कसावा के पत्तों से पृथक जैव–कीटनाशक	श्री अजित.एस.आर, पीजीटी (बायो)
4	एस क्वाजा अहमद हुसैन	केन्द्रीय विद्यालय मैसूरु	ग्रे रेवोल्यूशन	श्रीमती सीनियामोल एम वी
5	एस निशांत	केन्द्रीय विद्यालय डीआरडीओ, बैंगलोर	निक: बिन बॉट	श्रीमती सीतालक्ष्मी
6	नित्यांश कर	केन्द्रीय विद्यालय सेक्टर–8 आरके पुरम	परिधीय दृष्टि असामान्यताओं की एआई मॉडलिंग	श्रीमती लता कपिल

(ग) इंस्पायर अवार्ड मानक योजना

इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च (इंस्पायर) योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भारत सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है। इंस्पायर अवार्ड्स – मानक (मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज), जिसे डीएसटी द्वारा नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन – इंडिया (एनआईएफ), डीएसटी के एक स्वायत्त निकाय के साथ निष्पादित किया जा रहा है, का उद्देश्य कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले 10–15 वर्ष के आयु वर्ग के छात्रों को प्रेरित करना है। योजना का उद्देश्य स्कूली बच्चों के

बीच रचनात्मकता और नवीन सोच की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित दस लाख मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करना है। योजना के तहत वर्ष 2022–23 में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए केवीएस से 710 छात्रों का चयन किया गया है।

इसके अतिरिक्त, 10वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी इंस्पायर मानक 2021–22 दिनांक 8 से 11 अक्टूबर 2023 के बीच आयोजित की गई थी जिसमें निम्नलिखित विजेता थे:

क्र. सं.	छात्र का नाम	के.वि. का नाम	परियोजना
1	औरव राजपूत	के.वि. सीआई, एसएफ भिलाई (छत्तीसगढ़)	हैंड पावर जल शोधक
2	निधि श्रीवास्तव	के.वि. किरंदुल (छत्तीसगढ़)	भूसी निकालने की मशीन
3	शुभ सक्सेना	के.वि. 1 सागर कैंट (एमपी)	शिशुओं के लिए पोर्टेबल पालना

(घ) जिज्ञासा

केन्द्रीय विद्यालय संगठन (के.वि.सं.) और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली के बीच दिनांक 06 जुलाई 2017 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम को जिज्ञासा नाम दिया गया है। छात्रों/अध्यापकों ने जिज्ञासा कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। जिज्ञासा कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- युवा मानस में 'वैज्ञानिक प्रवृत्ति' विकसित करने के लिए सीएसआईआर संस्थानों को स्कूली छात्रों के साथ जोड़ना।
- वैज्ञानिक प्रवृति विकसित करना एक ऐसा तंत्र है जिसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने में छात्रों की क्षमता में वृद्धि होती है जिसमें प्रश्न पूछना, भौतिक वास्तविकता का अवलोकन करना, परिकल्पना का परीक्षण करना, विश्लेषण करना और संचार करना शामिल है।
- इससे छात्रों के वैज्ञानिक भाग को विकसित करने में सहायता मिलेगी।
- के.वि.सं. सीएसआईआर के साथ मिलकर केंद्रीय विद्यालयों के साथ 38 केंद्रीय प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सहयोग कर रहा है ताकि जिज्ञासा और अनुसंधान की भावना पैदा हो सके।

(ङ) सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम

के.वि.सं. के छात्रों ने शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) के साथ 'द सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम' में भाग लिया। जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी (जेएसटी) 'जापान–एशिया यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस' को लागू कर रही है, जिसे जापान और शेष एशिया के युवाओं के बीच आदान–प्रदान बढ़ाने के लिए 'सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम इन साइंस' के रूप में भी जाना जाता है। सकुरा एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत 34 छात्र और 03 शिक्षक 09–15 जुलाई 2023 तक जापान गए तथा विज्ञान और सांस्कृतिक आदान–प्रदान के विकास के बारे में जानने के लिए ओसाका और क्योटो का दौरा किया। कार्यक्रम के तहत 03 छात्रों ने दिनांक 10–16 नवंबर 2023 तक जापान का भी दौरा किया।

(च) अटल टिंकरिंग लैब्स

राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति, आयोग) नई दिल्ली, भारत सरकार ने छात्रों के बीच रचनात्मकता और वैज्ञानिक स्वभाव

को बढ़ावा देने के लिए अटल नवाचार मिशन (एआईएम) की स्थापना की है। इस कार्यक्रम के तहत देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में 340 लैब अटल टिंकरिंग स्थापित की गई हैं। अटल टिंकरिंग लैब को युवा उद्यमियों को सामुदायिक समस्याओं का समाधान खोजने में सहायता हेतु, एप्लिकेशन–आधारित स्व–शिक्षा के माध्यम से, स्कूली पाठ्यपुस्तकों से परे विज्ञान को खेल–खेल में सीखने के लिए एक कार्यक्षेत्र रूप में परिकल्पित किया गया है।

(छ) विज्ञान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण

उच्च क्रम और प्रौद्योगिकी संचालित प्रयोगों का अवसर देकर वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच रुचि उत्पन्न करने की पहल है। 928 केंद्रीय विद्यालयों की मौजूदा विज्ञान प्रयोगशालाओं का चार चरणों में आधुनिकीकरण किया गया है।

• प्रथम चरण में कवर किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 211
• द्वितीय चरण में कवर किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 200
• तृतीय चरण में कवर किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 363
• चतुर्थ चरण में कवर किए गए केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या	: 154
	928

केन्द्रीय विद्यालयों में कला, मूल्यों, संस्कृति और लोकाचार को बढ़ावा देना:

(क) आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएम)

भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव (आकाम) के तहत कई कार्यक्रमों के माध्यम से भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। महोत्सव का उद्घाटन 12 मार्च 2021 को साबरमती आश्रम, अहमदाबाद से पदयात्रा (स्वतंत्रता मार्च) को झंडी दिखाकर किया गया और यह 15 अगस्त 2023 को 75वीं वर्षगांठ के एक साल बाद समाप्त होगा और 15 अगस्त 2023 तक जारी रहा। एकेएम के तहत कार्यक्रम 5 स्तंभों के इर्द–गिर्द घूमते हैं, जैसे स्वतंत्रता संग्राम, 75 पर विचार, 75 पर उपलब्धियां, 75 पर कार्य, और 75 पर संकल्प। केंद्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) ने आजादी का अमृत महोत्सव (एकेएम) के तहत बहुत सारी गतिविधियों का आयोजन किया।

भारत की संस्कृति और लोकाचार के लिए छात्रों में सम्मान, गुमनाम नायकों के लिए आदर और सम्मान, स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं द्वारा बड़े पैमाने पर योगदान के लिए सम्मान की भावना को पैदा करने के लिए गतिविधियों को पूरे वर्ष आयोजित किया गया है। वर्ष 2023 में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियां आयोजित की गईः

i. **निबंध प्रतियोगिताः** 13163 छात्रों ने फरवरी 2023 के महीने में "**मैं एक राष्ट्र की संकल्पना के निर्माण में कैसे योगदान दे सकता हूं**" विषय पर निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया।

ii. **आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी** – के.वि. एसपीजी द्वारका में 10वीं कक्षा की छात्रा **सुश्री गरिमा गुप्ता** ने **जिज्ञासा आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी** में दूसरा पुरस्कार प्राप्त करके हमें गौरवान्वित किया। उनकी अद्भुत उपलब्धि को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा पुरस्कृत किया गया।

iii. **हर घर तिरंगा** – हमारे राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करने के लिए, भारत सरकार ने दिनांक 13 से 15 अगस्त 2023 तक "**हर घर तिरंगा**" अभियान चलाया। इसके पीछे का विचार नागरिकों के

दिलों में देशभक्ति की भावना जगाना और हमारे राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। देश भर के केंद्रीय विद्यालयों में हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया, इस विभाग में काम करने वाले सभी अधिकारी/कर्मचारी, छात्र और उनके परिवार दिनांक 13—15 अगस्त 2023 तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। देशभर में केंद्रीय विद्यालयों के कुल 9,59,732 छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने दिनांक 13 से 15 अगस्त 2023 तक अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। हर घर तिरंगा संबंधी क्रिएटिव केवीएस सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किए गए और मॉर्निंग असेंबली के दौरान छात्रों को हर घर तिरंगा अभियान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अभियान के विषय में स्कूली छात्रों को उचित शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान किया।

iv. **विभाजन विभीषिका स्मृति दिवसः** शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने और 200 के.वि. में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल प्रदर्शनी लगाने की अपील की गई। के.वि.सं. ने न.वि.सं और अन्य सीबीएसई स्कूलों द्वारा शामिल किए गए जिलों को छोड़कर 200 के.वि. में डिजिटल प्रदर्शनी का अवलोकन और संचालन किया। यथा निर्देशित, सभी चयनित के.वि. ने विभाजन प्रभावित लोगों के कष्टों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 10 अगस्त से 14 अगस्त 2023 तक प्रदर्शनी लगाई। के.वि. ने अतिथियों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया। प्रदर्शनी की तस्वीरें के.वि. के सोशल मीडिया हैंडल पर भी डाली गईं।

v. **मेरी माटी मेरा देशः** के.वि.सं. ने मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया था जिसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के समापन कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित किया गया था। देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए इसे **9 अगस्त से 15 अगस्त और 1 सितंबर 2023 से 30 अक्टूबर 2023** तक दो चरणों में आयोजित किया गया था। के.वि. में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जैसे 'मेरी माटी मेरा देश' विषय पर विशेष प्रातः कालीन सभाएं जिसमें छात्रों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों द्वारा पंच प्राण प्रतिज्ञा दिलाई गई। छात्रों और शिक्षकों ने मिट्टी के साथ सेल्फी ली और उन्हें मेरी माटी मेरा देश का उपयोग करके समर्पित वेबसाइट के साथ—साथ सोशल मीडिया हैंडल पर अपलोड किया। देश भर के कई केंद्रीय विद्यालयों में 75 पौधों के साथ अमृत वाटिका विकसित की गई। के.वि. अभियान को लोकप्रिय बनाने के लिए अपने सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करते हैं ताकि यह सभी तक पहुंच सके। स्कूल पत्रिकाओं में विशेष फीचरः छात्रों को स्कूल पत्रिकाओं में मेरी माटी मेरा देश पर विशेष फीचर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

vi. **खादी महोत्सवः** खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामोद्योग, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) और अन्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में खादी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, के.वि. से अनुरोध किया गया कि वे तीनों प्रतियोगिताओं, अर्थात निबंध प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का व्यापक प्रचार करें और अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करें।

vii. **जनजातीय गौरव दिवसः** केंद्रीय विद्यालयों ने प्रसिद्ध आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती मनाने के लिए दिनांक 15 नवंबर 2023 से 26 नवंबर 2023 तक तीसरे जनजातीय गौरव दिवस का आयोजन किया। छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने भगवान बिरसा मुंडा के योगदान को सम्मान देने के लिए वाद–विवाद, भाषण, पोस्टर मेकिंग, क्विज़, समूह नृत्य, रोल प्ले प्रतियोगिता और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसी गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

viii. देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में संविधान दिवस (संविधान दिवस) मनाया गया। कुल 8,71,006 छात्रों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी, 3,17,820 छात्रों ने वार्ता में भाग लिया और 66,182 छात्रों ने सेमिनारों में भाग लिया और 23,160 छात्रों ने संविधान दिवस (संविधान दिवस) पर भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों संबंधी वेबिनार में भाग लिया। शिक्षक वार्ता आयोजित की गई, जिसके दौरान शिक्षकों ने संविधान की आवश्यकता, संविधान का इतिहास, भारत के संविधान के पीछे के लोग, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार और कर्तव्य और संविधान की प्रस्तावना जैसे कई दिलचस्प तथ्य बताए। सभी छात्रों और शिक्षकों ने शपथ लेकर भारतीय संविधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। शिक्षकों ने एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र देश होने के महत्व पर भी चर्चा की। इस अवसर पर विद्यार्थियों में देशभक्ति का जोश चरम पर था। बच्चों से संविधान का पालन करने और एक महान देश का नागरिक होने पर गर्व महसूस करने का आग्रह किया गया। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया।

(ख) एक भारत श्रेष्ठ भारत (ईबीएसबी)

इस कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की जोड़ी की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद और आपसी समझ को बढ़ावा देना है। राज्य, भाषा को सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और व्यंजन, खेल और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने आदि के क्षेत्रों में एक सतत और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां आयोजित करते हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल के दर्शन पर आधारित 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' छात्रों और शिक्षकों को प्रदर्शन और दृश्य कला में अपनी प्रतिभा व्यक्त

करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। केवीएस के सभी 25 क्षेत्रों को उनके अपने राज्य से अलग राज्य के साथ जोड़ा गया है। छात्र उन्हें आवंटित राज्य की संस्कृति, रीति–रिवाजों, पोशाक, कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था, जलवायु और स्थलाकृति आदि पर परियोजनाएं/प्रदर्शनी तैयार करते हैं। इससे उन्हें जोड़े गए राज्यों की कला और संस्कृति को समझने का अवसर मिलता है, इस प्रकार उन्हें विभिन्न संस्कृतियों के प्रति परस्पर सम्मान को आत्मसात करने में मदद मिलती है। छात्र विभिन्न स्तरों– विद्यालय/क्लस्टर और क्षेत्र, पर प्रतिस्पर्धा करते हैं।

छात्रों द्वारा निम्नलिखित गतिविधियाँ की गईः

1. सहयोगी राज्य की संस्कृति एवं इतिहास, परंपरा पर **वेबिनार**
2. **भाषा संगम** – छात्र प्रतिपक्ष राज्य की भाषा में 100 वाक्य बोलते, लिखते और प्रदर्शित करते हैं।
3. सहयोगी राज्य की भाषा में **समान मुहावरों की पहचान, अनुवाद**
4. **भाषा सीखो अभियान**
5. भागीदारी राज्य की भाषा में **शपथ** (स्वच्छता/प्लास्टिक का एकल उपयोग/जल संरक्षण)
6. **टॉकिंग ऑवर** (भागीदार राज्यों पर समाचार)
7. भागीदार राज्य के छात्रों के साथ **वीडियो कांफ्रेंसिंग**
8. **स्टोरी टेलिंग** (आवंटित प्रदेश के प्रमुख साहित्यकारों की लोककथाएं एवं कहानियां)।
9. **लोकनृत्य** (प्रतिपक्ष राज्य का)
10. **प्रश्नोत्तरी** (प्रतिपक्ष राज्य के बारे में व्यापक ज्ञान से संबंधित)
11. **एकल गीत** (प्रतिपक्ष राज्य का लोकगीत)
12. **राज्य परियोजना नोटबुक** (भागीदारी राज्य पर)
13. **ई–न्यूजलेटर** (की गई गतिविधियों पर)
14. **ऑन–द–स्पॉट पेंटिंग**– त्यौहार/ऐतिहासिक घटनाएं, समकक्ष राज्य की कोई अन्य विशेषता।

(i) **भारतीय भाषा उत्सवः** भारतीय भाषा उत्सव का आयोजन देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में विषय "भाषाएँ अनेक, भाव एक'' के साथ दिनांक 28 सितंबर से 11 दिसंबर 2023 तक भाषा सीखने को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अधिक प्रसार सुनिश्चित करने और भाषाई विविधता का जश्न मनाने के लिए किया गया था। इसके अतिरिक्त केवीएस को अनुवादिनी– वॉयस एंड डॉक्यूमेंट एआई ट्रांसलेशन टूल्स के बारे में भी सूचित किया गया है, जिसे भारतीय भाषा उत्सव के दौरान सभी अनुवाद उद्देश्यों के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिए एआईसीटीई द्वारा 22 भारतीय और विदेशी भाषाओं में विकसित किया गया है।

(ii) **राष्ट्रीय एकता दिवसः** केवीएस ने सोशल मीडिया हैंडल और वेबसाइटों पर कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाकर हमारे देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के लिए दिनांक 31.10.2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया। देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालयों की प्रातः कालीन सभाओं में अभियान के बारे में जागरूकता पैदा की गई। छात्रों को सरदार वल्लभभाई पटेल और राष्ट्र की एकता के प्रति उनके दृष्टिकोण के बारे में शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में 804351

छात्रों, 33129 शिक्षकों और 19472 समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया। छात्रों और उनके परिवारों ने 'रन फॉर यूनिटी' में भाग लिया और पड़ोस के इलाकों में छात्रों और शिक्षकों द्वारा 'रन फॉर यूनिटी' अभियान चलाया गया। **761243 प्रतिभागियों ने कुल 4403 किलोमीटर की दूरी तय की।** प्रातःकालीन सभा में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। अधिकांश के.वि. ने इस कार्यक्रम को सोशल मीडिया–ट्विटर (अब X) हैंडल पर रुरन फॉर यूनिटी के साथ लोकप्रिय बनाया। सरदार वल्लभभाई पटेल के योगदान को प्रदर्शित करने के लिए के.वि. में प्रदर्शनियां आयोजित की गई।

(iii) **कला उत्सवः** कला उत्सव देश में स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा का विकास और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की एक पहल है। कला उत्सव 2022 की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता एनसीईआरटी द्वारा दिनांक 3 जनवरी से 7 जनवरी 2023 तक आरआईई भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के चार छात्रों ने पुरस्कार जीते, विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	छात्र का नाम	कला का प्रकार	परिणामी स्थान
1	प्रोद्युम्नो सील	वाद्य संगीत (मधुर) पुरुष	प्रथम पुरस्कार
2	रक्षित वाहने	शास्त्रीय नृत्य (पुरूष)	दूसरा पुरस्कार
3	बार्बी राजकुमारी सोनोवाल	नृत्य लोक (महिला)	तीसरा पुरस्कार
4	आरोही सिंह	दृश्य कला 3डी (महिला)	तीसरा पुरस्कार

खेलकूद, योग, एनसीसी, स्काउट्स और गाइड तथा अन्य संवर्धन

केन्द्रीय विद्यालय संगठन छात्रों को उनके समग्र विकास में सहायता हेतु विभिन्न अवसर प्रदान कर रहा है। साप्ताहिक समय सारिणी के अनुसार नियमित पाठ्यचर्या संव्यवहार के अतिरिक्त, खेलकूद, योग, स्काउट और गाइड, एनसीसी, युवा संसद जैसी कुछ अन्य आवधिक गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं जिनमें चयनित छात्रों को स्कूल स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर भाग लेने के अवसर मिलते हैं।

(क) खेल–कूद का संवर्धन

खेल–कूद एक ऐसी गतिविधि है जो लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए कई स्तरों पर की जाती है। एक स्तर पर चयनित छात्र अगले स्तर पर मीट में भाग लेते हैं, जैसे स्कूल क्लस्टर/क्षेत्रीय स्तर पर भाग लेते हैं, क्षेत्र केवीएस राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और केवीएस टीमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) की बैठकों में भाग लेती हैं।

आयोजनों में एथलेटिक्स, तैराकी, तीरंदाजी, योग, शतरंज, मुक्केबाजी, जूडो, तायक्वोंडो, स्केटिंग, शूटिंग और रस्सी कूदने के साथ–साथ कबड्डी, खो–खो, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन जैसे टीम खेलों में व्यक्ति और टीम दोनों की भागीदारी शामिल है।

52वीं केवीएस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं (सत्र 2023–24) विभिन्न स्थानों जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुरुग्राम, हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और रांची क्षेत्रों में आयोजित की गई। इन बैठकों में लड़कों और लड़कियों के विभिन्न आयु वर्गों के लिए कुल 22 खेल विषय शामिल थे। इन कार्यक्रमों और विभिन्न स्थानों में लगभग 20,000 छात्रों ने भाग लिया। इन आयोजनों के चिह्नित व्यक्ति और टीमें सत्र 2023–24 के लिए

आगामी एसजीएफआई कार्यक्रमों में केवीएस का प्रतिनिधित्व करेंगी।

i) **राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता**

अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लेने से पहले अंडर–14 और 17 के लड़कों के लिए केवीएस नेशनल प्री–सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट, 2023 का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ क्षेत्र ने दिनांक 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 तक लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, फगवाड़ा (पंजाब) में लड़कों के अंडर–17 के लिए प्री–सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। लखनऊ क्षेत्र ने दिनांक 01 से 5 अगस्त 2023 तक के.वि. एएमसी लखनऊ (यूपी) में अंडर–17 लड़कियों के लिए प्री–सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। कोलकाता क्षेत्र ने दिनांक 1 से 5 अगस्त 2023 तक के.वि. नंबर 2, रेलवे, खड़गपुर (डब्ल्यूबी) में लड़कों (अंडर–14) के लिए प्री–सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया। विजेता के.वि. ने सितंबर और अक्टूबर 2023 में आयोजित 62वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया:

प्री–सुब्रतो कप फुटबॉल के विजेता के.वि.	प्रतियोगिता स्थल
प्रथम के.वि. लोकहारा, गुवाहाटी (लड़के अंडर–17)	नई दिल्ली
प्रथम के.वि. आईएमए देहरादून (लड़के अंडर–14)	बेंगलुरु
प्रथम के.वि. आईएमए, देहरादून (लड़कियां अंडर–17)	नई दिल्ली

ii) **राष्ट्रीय खेल दिवस, 2023**

मेजर ध्यानचंद "हॉकी के महान जादूगर" का जन्मदिन देश भर के सभी के.वि. में दिनांक 21 अगस्त से 29 अगस्त 2023 तक "राष्ट्रीय खेल दिवस" 2023 के रूप में मनाया गया, जिसका विषय "एक समावेशी और फिट समाज के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेल" था, जो युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। अधिकांश के.वि. ने भाग लिया और दिनांक 21.08.2023 से 29.08.2023 तक 21,56422 बच्चों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

iii) **फिट इंडिया फ्रीडम रन, क्विज और फिट इंडिया वीक**

फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0, 2023 दिनांक 10.10.2023 से 30.10.2023 तक केवीएस में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया/मनाया गया। 9,51,518 छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने भाग लिया और दौड़ के दौरान 2074902 किलोमीटर की दूरी तय की और 887 के.वि. ने 1471 टीमों के साथ फिट इंडिया क्विज़, 2023 के तीसरे संस्करण में भी भाग लिया, और 2841 छात्र फिट इंडिया क्विज़ 3.0 में नामांकित हुए। फिट इंडिया स्कूल वीक के 5 वें संस्करण की गतिविधियां वार्षिक खेल दिवस, फिटनेस का महत्व–वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी, निबंध लेखन, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता, स्वदेशी खेल, मोबाइल ऐप के माध्यम से फिटनेस मूल्यांकन, योग और ध्यान, शिक्षकों, छात्रों और उनके माता–पिता द्वारा फिटनेस प्रतिज्ञा जैसी थीं। फिट इंडिया पेरेंट्स टीचर्स मीट का आयोजन दिनांक 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2023 के बीच सभी के.वि. में उनकी आकस्मिकता के अनुसार 4–6 दिनों के लिए किया गया जिसमें 7,87559 छात्रों ने भाग लिया।

iv) **वर्ष 2023 में खेलो इंडिया और अन्य खेल–कूद आयोजनों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ**

1. के.वि. तिरुमलागिरी में कक्षा 8 वीं की छात्रा कुमारी मोक्षिता ने हैदराबाद के बोरामपेट में खेलो इंडिया दस का दम खेल प्रतियोगिता में 50 मीटर बटरफ्लाई और 50 मीटर फ्रीस्टाइल में 2 स्वर्ण पदक और 100 मीटर फ्रीस्टाइल में 1 रजत पदक जीता।

2. केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 फरीदाबाद की छात्रा कुमारी जिया सिंह ने खेलो इंडिया आयोजन में आइस स्केटिंग में कांस्य पदक जीता।

3. केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सिरसा की छात्रा कुमारी तानिया रानी ने दिनांक 5 से 7 मार्च 2023 तक गंगटोक, सिक्किम में आयोजित 5वें खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता।

4. केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 जीसीएफ जबलपुर की कुमारी रिया ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के तहत योग में स्वर्ण पदक जीता।

5. केंद्रीय विद्यालय सीएमएम जबलपुर के मास्टर रुद्रजीत ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स–2023 के तहत बॉक्सिंग में रजत पदक जीता।

6. केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एसटीसी जबलपुर की कुमारी इशिता पांडे ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में खेलो इंडिया महिला जूनियर नेशनल वुशु लीग में रजत पदक जीता।

7. केंद्रीय विद्यालय बैरागढ़ के छात्र वल्लूरी अजय बाबू ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीतकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया।

8. केंद्रीय विद्यालय एनईएचयू के छात्र देवराज मोहापात्रा ने एसएआई एसटीसी शिलांग में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा आयोजित द्वितीय एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट–2023 में सब जूनियर रिकर्व (लड़के) में कांस्य पदक जीता। उन्होंने ऑल इंडिया 3 रैंक भी हासिल की।

9. के.वि. एएफएस बमरौली, प्रयागराज की छात्रा कुमारी संचिता यादव ने राष्ट्रीय एमेच्योर चेस चैंपियंस प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया। उन्हें 'वर्ल्ड एमेच्योर चेस चैंपियनशिप–2023' के लिए चुना गया है।

10. केंद्रीय विद्यालय हाई ग्राउंड्स, चंडीगढ़ के छात्र, ताइक्वांडो खिलाड़ी कुमार सक्षम यादव ने वर्ल्ड रैंकिंग जी2 यूएई 10वीं फुजैराह ओपन 2023 में जूनियर अंडर 44 किग्रा में रजत पदक जीता।

(ख) योग का प्रचार

बच्चों के व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शिक्षा के साथ–साथ खेल, शारीरिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा को भी समान महत्व दिया है। प्रत्येक बच्चे को स्कूल स्तर पर इन–हाउस प्रतियोगिताओं के माध्यम से पसंद के विभिन्न खेल–कूद/योग गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और अवसर दिया जाता है। के.वि. में कक्षा तीन से योग सिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त, योग को बढ़ावा देने के लिए छात्रों ने विभिन्न स्तरों पर विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं में भाग लिया। कुछ उल्लेखनीय प्रतियोगिताएँ इस प्रकार हैं:

i) **9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई), 2023**

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे **21 जून को दुनिया भर में** बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष, आयुष मंत्रालय ने "वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग" थीम बनाई है। स्थिरता और वैश्विक विकास के लिए योग समुदाय को सक्रिय और प्रेरित करने के लिए थीम का चयन किया गया था। **योग की भावना और दिन–प्रतिदिन के जीवन में इसके महत्व के अनुरूप, के.वि.सं. ने अपने सभी स्टाफ सदस्यों और छात्रों के लिए हर दिन प्रातः कालीन सभा में योग को एक दैनिक दिनचर्या बना दिया है। इसके अतिरिक्त, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (आईडीवाई) का जश्न मनाने के लिए योग अभ्यास कराया गया। के.वि.सं. ने शिक्षा मंत्रालय और आयुष मंत्रालय, एनसीईआरटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन किया।** 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023, सात दिवसीय योग गतिविधियाँ/ कार्यक्रम के.वि.सं. द्वारा तैयार किया गया था, और इसे दिनांक 15 से 21 जून 2023 तक सभी के.वि. में 40–50 मिनट के लिए दैनिक रूप से आयोजित किया गया था। योग शिक्षकों/शारीरिक शिक्षा शिक्षकों/योग प्रशिक्षकों/योग विशेषज्ञों/योग–आचार्यों की मदद से सभी केंद्रीय विद्यालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न योग गतिविधियों के साथ 9वां आईडीवाई महोत्सव मनाया गया। कुल 8,83,989 छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने भाग लियाः दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कार्यस्थल पर कर्मचारियों द्वारा तरोताजा, तनाव मुक्त और पुनः ध्यान केंद्रित करने के लिए योग प्रोटोकॉल (वाई–ब्रेक) के तहत योग गतिविधियां आयोजित की जाती हैं।

ii) **राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2023**

पिछली केवीएस राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के विजेताओं ने राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 में भाग लिया, जो 18 से 20 जून तक आरआईई, भोपाल में आयोजित की गई थी। समूह प्रतियोगिता में कुल 16 छात्रों ने भाग लिया और जीते गए पदकों का विवरण नीचे दिया गया हैः

राष्ट्रीय योग ओलंपियाड, 2023 का समूहवार परिणाम

1. मिडिल ग्रुप (कक्षा छठी से आठवीं) लड़के –

क्र.सं.	नाम	के.वि. का नाम	क्षेत्र	उपलब्धि
1	सयान बाउरी	के.वि.सीआरपीएफ दुर्गापुर	कोलकाता	**दूसरा स्थान**
2	चर्याणं दीक्षित पुजारी	के.वि. नंबर 1, तेजपुर	गुवाहाटी	
3	प्रीतम पॉल	के.वि. कुंभीरग्राम	सिलचर	
4	आयुष जना	के.वि. खड़गपुर (रेलवे)	कोलकाता	

2. **मिडिल ग्रुप (कक्षा छठी से आठवीं) लड़कियां–**

क्र.सं.	नाम	के.वि. का नाम	क्षेत्र	उपलब्धि
1	जे तनुश्री	के.वि. ओसीएफ अवदी	चेन्नई	**दूसरा स्थान**
2	याशिका चेवली	के.वि. 2 वास्को डी गामा	मुंबई	
3	आर तमीज़िनी	के.वि. ओसीएफ अवदी	चेन्नई	
4	रिंकी कश्यप	के.वि. सीयू तेजपुर	गुवाहाटी	

3. **सीनियर ग्रुप (कक्षा IX से X) लड़के –**

क्र.सं.	नाम	के.वि. का नाम	क्षेत्र	उपलब्धि
1	रेयान आलम	के.वि. ओएनजीसी अगरतला	सिलचर	**प्रथम स्थान**
2	प्रंशात बैंसला	के.वि. पलवल	गुरूग्राम	
3	एन जी रोशन कुमार	के.वि. सिलचर	सिलचर	
4	सन्नी तंवर	के.वि. 3 फ़रीदाबाद	गुरूग्राम	

4. **सीनियर ग्रुप (कक्षा IX से X) लड़कियां –**

क्र.सं.	नाम	के.वि. का नाम	क्षेत्र	उपलब्धि
1	ए एस राजश्री	केवी एचवीएफ अवदी	चेन्नई	**दूसरा स्थान**
2	नंदिनी कुमारी	केवी सीएमईआरआई दुर्गापुर	कोलकाता	
3	एस नवनीता	केवी अवदी	चेन्नई	
4	याशिका बारापात्रो	केवी अगिनी (दूसरी पाली) नागपुर	मुंबई	

ग. के.वि.सं. में भारत स्काउट्स और गाइड गतिविधियाँ

के.वि.सं. भारत स्काउट्स और गाइड्स गतिविधियों में अग्रणी रहा है। प्रवेश/प्रथम सोपान/कोमल पंख/रजत पंख/प्रथम चरण/द्वितीय चरण के लिए विद्यालय स्तरीय परीक्षण शिविर आयोजित किए गए। क्षेत्रीय स्तर पर द्वितीय एवं तृतीय सोपान परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। राज्य स्तरीय राष्ट्रपति स्काउट/गाइड प्रमाणपत्र परीक्षा परीक्षण शिविर में सभी क्षेत्रों से 761 स्काउट्स एवं 554 गाइड्स ने भाग लिया।

- प्रधानमंत्री शील्ड प्रतियोगिता 2023–24 के लिए 356 स्काउट और 314 गाइड इकाइयों ने पंजीकरण कराया।
- वर्ष 2022 में 2775 बालकों और 2510 बालिकाओं को गोल्डन एरो अवार्ड मिला। गोल्डन एरो अवार्ड–2023 के लिए 3264 बालकों और 3099 बालिकाओं को पंजीकृत किया गया है।
- दिनांक 21.08.2023 से 25.08.2023 तक क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित राज्य पुरस्कार परीक्षण शिविर–2023 में 4358 स्काउट्स और 3675 गाइड (कुल 8033) उत्तीर्ण हुए।

(घ) के.वि.सं. में एनसीसी

एनसीसी का लक्ष्य के.वि. के छात्रों को आवश्यक सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करना और उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।

वर्तमान में, केन्द्रीय विद्यालयों के 21227 छात्र एनसीसी गतिविधियों में भाग लेते हैं। एनसीसी को 1970 के दशक के आरंभ में 107 केन्द्रीय विद्यालयों में शुरू किया गया था। 31 मार्च, 2023 तक, विभिन्न क्षेत्रों के 339 केवी हैं जहां एनसीसी आवंटित किया गया है और प्रशिक्षण चल रहा है। लगभग 49 के.वि. ने अपने नजदीकी एनसीसी यूनिट से संपर्क कर एनसीसी शुरू करने के लिए आवेदन किया है। वर्तमान में, देश भर के 339 के.वि. में 21227 कैडेट (12445 लड़के और 8782 लड़कियां) हैं।

(ड.) युवा संसद

संसदीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से केंद्रीय विद्यालयों में 1988 से प्रत्येक वर्ष युवा संसद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता रहा है। युवा संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ करना, युवा मन में अनुशासन, सहिष्णुता की स्वस्थ आदतें विकसित करना और उन्हें संसदीय प्रक्रियाओं और प्रथाओं के ज्ञान से युक्त करना है। यह योजना छात्रों को सामाजिक आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता विकसित करने तथा स्वतंत्र और स्पष्ट बहस व चर्चा के बाद निर्णय लेने की आदत विकसित करने के लिए एक मंच भी प्रदान करती है। युवा संसद प्रतियोगिताएं स्कूल, क्षेत्रीय और आंचलिक स्तर पर आयोजित की गई हैं। आंचलिक स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों के प्रदर्शन के आधार पर, संसदीय कार्य मंत्रालय ने परिणाम घोषित किए हैं। श्रृंखला में 33वीं प्रतियोगिता 2022–23 के दौरान केंद्रीय विद्यालय संगठन के 25 क्षेत्रों में फैले 150 केंद्रीय विद्यालयों के बीच आयोजित की गई थी। सितंबर 2023 में, केवी नंबर 1 छिंदवाड़ा जबलपुर क्षेत्र को केवीएस के लिए 33वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2022–23 के विजेता के रूप में चुना गया। इसने देश में पहला स्थान हासिल करते हुए नेहरू रनिंग शील्ड और ट्रॉफी जीती है।

के.वि.सं. में महत्वपूर्ण दिनों, आयोजनों और कार्यक्रमों का उत्सव

(क) के.वि.सं. का हीरक जयंती समारोह

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने दिनांक 15 दिसंबर, 2023 को अपना हीरक जयंती वर्ष मनाया। दिनांक 15 दिसम्बर, 1963 को 20 रेजिमेंटल स्कूलों का अधिकार लिया गया था, जिनका नाम सेंट्रल स्कूल और सेंट्रल स्कूल ऑर्गेनाइज़ेशन रखा गया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन को दिनांक 15 दिसंबर, 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था और देश भर में 1256 केन्द्रीय विद्यालयों तथा विदेश स्थित 03 केन्द्रीय विद्यालयों के साथ यह गौरवशाली यात्रा जारी है। हीरक जयंती समारोह में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन के.वि. नंबर 2 दिल्ली कैंट के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में किया गया था। श्री सुभाष सरकार, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय; श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय; डॉ. राज कुमार रंजन सिंह, राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय ने सम्मानित अतिथि के रूप में अपनी शुभ उपस्थिति से पूरे केवीएस समुदाय को सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार मेहरा, ओलंपियन सुश्री दीपा मलिक और भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

कार्यक्रम का क्रम इस प्रकार था–

क) मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का आगमन

ख) दिल्ली क्षेत्र के के.वि. के स्काउट–गाइड की रंगीन पार्टी और के.वि. सेक्टर–2

आर.के.पुरम और के.वि. गोल मार्केट के स्कूल बैंड द्वारा स्वागत।

ग) मार्च पास्ट/परेड निरीक्षण – तीन विंगों के एनसीसी कैडेट – के.वि. नंबर 2 दिल्ली कैंट का सेना विंग, केवी पीतमपुरा का वायु सेना विंग और डॉ. राजेंद्र प्रसाद के.वि. का नौसेना विंग।

घ) प्रदर्शनी–18 स्टॉल– इन स्टॉलों के माध्यम से केवीएस के गौरवशाली साठ वर्षों और विभिन्न गतिविधियों को प्रदर्शित किया गया। सुलभ संदर्भ हेतु स्टालों के विषयों की सूची यहां संलग्न है।

ड.) केवीएस के गौरवशाली साठ वर्षों को दर्शाती कला प्रदर्शनी – दिल्ली क्षेत्र के प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों (एई) द्वारा 55 पेंटिंग और 04 मूर्तिकला का प्रदर्शन किया गया।

च) मुख्य सभागार में मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का आगमन

छ) मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्ज्वलन– के. वि. के छात्रों द्वारा वेद मंत्रों का जाप।

ज) श्रीम गवद गीता श्लोक पाठ–51 के.वि. नंबर 3 दिल्ली कैंट के छात्रों ने श्लोकों का जाप किया।

झ) मेडले–राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हुए देश की सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाने वाला लोक नृत्य–दिल्ली क्षेत्र के के.वि. के 100 छात्र।

ञ) के.वि. के पूर्व छात्रों की उपस्थिति–एयर वाइस मार्शल मनोज कुमार मेहरा और सुश्री दीपा मलिक ओलंपियन।

ट) के.वि.सं. गीत–भारत का स्वर्णिम गौरव–के.वि. ज.न.वि. के 55 छात्रों द्वारा।

ठ) के.वि.सं. पर लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

ड) कॉफी टेबल बुक, जीआईजीडब्ल्यू अनुरूप नई वेबसाइट और पूर्व छात्र वेब पोर्टल का विमोचन।

मुख्य अतिथि श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय मंत्री, शिक्षा मंत्रालय ने हीरक जयंती समारोह के अवसर पर पूरे केवीएस समुदाय की प्रशंसा की। कार्यक्रम के बाद एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया जिसमें संगीत शिक्षकों और कला उत्सव के विजेताओं ने शास्त्रीय गीतों और नृत्य के रूप में सांस्कृतिक आयोजन का समापन किया। कार्यक्रम में 900 विद्यार्थी, शिक्षक, प्रधानाचार्य एवं अतिथि उपस्थित थे।

ख. परीक्षा पर चर्चा का छठा संस्करण

परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण दिनांक 27 जनवरी 2023 को तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ संवाद किया और सभी हितधारकों को अपने बहुमूल्य सुझाव/इनपुट दिए। इस कार्यक्रम का कई टीवी चैनलों और यूट्यूब चैनलों द्वारा सीधा प्रसारण किया गया।

केन्द्रीय विद्यालयों ने उक्त कार्यक्रम के सुचारू और उल्लेखनीय निष्पादन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए थे: –

1. भारत के माननीय प्रधान मंत्री के सीधे संबोधन को देखने/सुनने के लिए के.वि. के सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए प्रत्येक के.वि. में डीटीएच/वर्चुअल कनेक्शन के साथ टीवी की व्यवस्था और बिजली सुविधाओं की निरंतर आपूर्ति की गई थी।

2. टीवी प्रसारण के अतिरिक्त, देखने की सुविधा को एडुसैट के माध्यम से इंटरनेट एक्सेस डिवाइस (कंप्यूटर/लैपटॉप/मोबाइल आदि) पर व्यवस्थित किया गया था और वेब लिंक तदनुसार साझा किया गया था।

3. यह कार्यक्रम परीक्षाओं में आने वाले कुछ प्रमुख प्रश्नों पर केंद्रित था। के.वि. से छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया।

4. सभी के.वि. ने हितधारकों को सूचित करने के लिए विद्यालय के परिसर, कार्यालयों, सोशल मीडिया हैंडल के साथ–साथ वेबसाइट के सभी प्रमुख स्थानों पर परीक्षा पे चर्चा–2023 के बारे में बैनर प्रदर्शित किए। के.वि. ने https://www.mygov.in पोर्टल पर वीडियो और तस्वीरें भी अपलोड की हैं।

5. के.वि. के छात्रों ने कुछ राज्यों में राज्यपाल के घर से माननीय प्रधान मंत्री जी के संवाद का संबोधन भी देखा।

6. केन्द्रीय विद्यालय के तीन छात्रों ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिनका विवरण इस प्रकार है:
   - मास्टर आशीष कुमार वर्मा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद के.वि. दिल्ली
   - सुश्री ब्रह्मचरिमायुम निष्ठा, के.वि. नंबर 1 इम्फाल
   - सुश्री मेनका कुमारी, के.वि. सिमडेगा

718110 विद्यार्थियों, 42337 कर्मचारियों और 88544 अभिभावकों ने पीपीसी–2023 का लाइव कार्यक्रम देखा। छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का संवाद सभी के लिए प्रेरणादायक, विचारोत्तेजक था।

परीक्षा पे चर्चा 2023 से पहले दिनांक 23.01.2023 को देशभर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को उन प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए धैर्य के साथ काम करने के लिए प्रेरित करना था, जिनसे नेताजी गुजरे थे और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विशेष प्रातःकालीन सभा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों और आदर्शों पर आधारित नारा लेखन प्रतियोगिता और माईजीओवी मंच के माध्यम से कविता रचना, पोस्टर प्रतियोगिता, निबंध लेखन, सेल्फी प्रतियोगिता जैसी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई।

23 जनवरी 2023 को पराक्रम दिवस पर देशभर के 500 केंद्रीय विद्यालयों में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लिखित "एग्जाम वॉरियर्स" पुस्तक में परीक्षा के तनाव को कम करने के मंत्र दिए गए। कार्यक्रम में 47164 छात्रों ने भाग लिया, जिसमें के.वि. से 11664 छात्र, ज.न.वि. से 4080 छात्र, सीबीएसई स्कूलों से 20631 छात्र और राज्य बोर्ड स्कूलों से 10789 छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग किया गया।

(ग) जी–20 जन भागीदारी और जागरूकता अभियान

ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी (जी20) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अभिशासन को आकार देने व सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के पास

दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता रही। अध्यक्षता भारत को आर्थिक और विकास संबंधी अनेक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अभिशासन को आकार देने और व सुदृढ़ करने के लिए एक संस्थागत मंच प्रदान करता है। जी–20 के बारे में जागरूकता विकसित करने में अपनी अनूठी भूमिका निभाने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और सीबीएसई द्वारा डिजाइन की गई विभिन्न गतिविधियों का आयोजन कर रहा है ताकि इस कार्यक्रम को संवेदनशील बनाया जा सके और इसके बारे में रोचक और आयु उपयुक्त तरीके से जानकारी प्रदान की जा सके। केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी 25 क्षेत्रों ने छात्रों को जी–20 के बारे में जागरूक करने के लिए प्रश्नोत्तरी, भाषण प्रतियोगिता, निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिताओं आदि जैसी गतिविधियों का आयोजन किया है।

केंद्रीय विद्यालयों द्वारा देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में प्रश्नोत्तरी, भाषण, पेंटिंग, जी20 पर व्याख्यान, निबंध और नारा लेखन प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक 'चौपाल की चर्चा', शिक्षक वार्ता, प्रिंसिपल वार्ता, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रमुख स्थान पर जी20 का लोगो, जी–20 के सभी सदस्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज पर विशेष कार्यक्रम, प्रातः कालीन सभा में शिक्षकों और छात्रों का संवाद, पेंटिंग, भाषण आदि जैसी विभिन्न गतिविधियों के आयोजन के माध्यम से जागरूकता पैदा की जा रही है। इसके अतिरिक्त केंद्रीय विद्यालयों ने दिनांक 01.06.2023 से 15.06.2023 तक देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में भौतिक/वर्चुअल मोड में मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, जी–20 के बारे में जागरूकता के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न गतिविधियां आयोजित कीं। विद्यार्थियों ने उपयुक्त कक्षाओं (कक्षा III से XII) के कार्यक्रमों में भाग लिया।

- एफएलएन, डिजिटल शिक्षा और जी20 पर केंद्रित ग्रीष्मकालीन शिविर/से. मिनार/समारोह/कार्यशाला/खेल आयोजन/सांस्कृतिक कार्यक्रम/मेला आदि।
- पीटीएम/एसएमसी/पीआरआई और स्कूलों में सामुदायिक बैठकों के माध्यम से जी20, एनईपी 2020 और एफएलएन के प्रति संवेदनशीलता के माध्यम से छात्रों, अभिभावकों और समाज के अन्य हितधारकों में जागरूकता पैदा करना।
- स्कूल नोटिस बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम के उद्देश्य का संचार।
- पोस्टर मेकिंग, नारा लेखन प्रतियोगिताएं, निबंध, प्रश्नोत्तरी और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।
- एफएलएन (आयु–उपयुक्त) के लिए श्रव्य–दृश्य सहायक उपकरण के उपयोग से जुड़ी गतिविधियां।
- कहानी सुनाना, कहानी बनाना, रंगोली, कठपुतली और वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियां।
- रैलियों, साइकिल रैलियों और प्रभात फेरी का आयोजन।
- कला और शिल्प प्रतियोगिताएं, दीवार चित्रकला नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि।
- यूट्यूब लिंक के माध्यम से तीन एफएलएन फिल्मों की स्क्रीनिंग।
- जनभागीदारी के सभी कार्यक्रमों को स्थानीय और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रचारित किया गया ताकि अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकतम सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(घ) स्वच्छता पखवाड़ा

स्वच्छता पखवाड़ा 2023 दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2023 तक देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में मनाया गया, जिससे लंबी अवधि में स्कूलों में स्वच्छता, सफाई और अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए छात्रों, शिक्षकों और सभी हितधारकों की केंद्रित भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। देशभर के केंद्रीय विद्यालयों द्वारा दिवस–वार गतिविधियां आयोजित की गईं। छात्रों ने विद्यालय स्तर पर आयोजित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया, जैसे प्रतिज्ञा लेना, जागरूकता अभियान, स्कूल प्रदर्शनियाँ, हाथ धोना आदि। इस अभियान को एक जन आंदोलन बनाने तथा छात्रों और अन्य में जागरूकता विकसित करने के लिए स्वच्छता शपथ दिवस, स्वच्छता जागरूकता दिवस, सामुदायिक आउटरीच दिवस, ग्रीन स्कूल ड्राइव डेज और स्वच्छता भागीदारी दिवस आदि जैसे विभिन्न दिवस भी मनाए गए।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा नशीली दवाओं और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने के लिए दिनांक 26.06.2023 को "नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) का आयोजन किया गया। विद्यालयों द्वारा आयोजित कुछ गतिविधियों में नुक्कड़ नाटक, सेमिनार, वेबिनार या कार्यशालाएँ, छात्रों और शिक्षकों के साथ नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर प्रतिज्ञा लेने वाली विशेष सभाएं शामिल थीं। स्कूल क्षेत्रों के आस–पास सिगरेट पर प्रतिबंध के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक उप–अभियान चलाया गया जिसमें नारा लिखना या जिंगल बनाना आदि शामिल है।

(च) राष्ट्रीय शिक्षा दिवस

दिनांक 11.11.2023 को देशभर के सभी के.वि. में प्रातः कालीन सभा में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। छात्रों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के महत्व पर भाषण दिया गया और वर्ष 2023 के लिए "एम्ब्रेसिंग इनोवेशन" विषय पर बल दिया गया। अबुल कलाम आजाद के जीवन और कार्यों पर छात्रों द्वारा एक विशेष प्रस्तुति दी गई। शिक्षक वार्ता, अबुल कलाम आज़ाद पर चित्रकला एवं पेंटिंग तथा शिक्षा संबंधी नारा लेखन का ऑनलाइन आयोजन किया गया। शिक्षा और राष्ट्रीय एकता की शक्ति का प्रदर्शन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, पोस्टर मेकिंग, प्रातः कालीन सभा में भाषण, शिक्षा के महत्व पर चर्चा, मौलाना अबुल कलाम आजाद के चित्र पर माल्यार्पण, महिला शिक्षा पर निबंध लेखन प्रतियोगिता, शिक्षा में नवीन प्रौद्योगिकियों पर शिक्षकों के लिए इन–हाउस कार्यशाला, मौलाना अबुल कलाम आजाद पर छात्रों द्वारा वीडियो तैयार करने का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस में 6 लाख से अधिक छात्रों ने भाग लिया।

(छ) मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह

शिक्षा मंत्रालय की एक पहल "मनोदर्पण" के तहत 4 से 10 अक्टूबर 2023 तक देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह मनाया गया। छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के लिए कुछ गतिविधियाँ आयोजित की गईं। राष्ट्रीय टोल–फ्री टेली–काउंसलिंग सेवाएं (844–844–0632) सोमवार से रविवार, सुबह 8.00 बजे से रात 8.00 बजे तक प्रदान की जाती हैं लाइव परस्पर संवादात्मक सत्र 'सहयोग' (सोमवार से शुक्रवार, शाम 5:00

बजे से शाम 5:30 बजे) और 'परिचर्चा' (प्रत्येक शुक्रवार, दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:00 बजे) पीएम ई–विद्या चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं और 'एनसीईआरटी आधिकारिक' यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध हैं। 'स्कूली छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण–एक सर्वेक्षण' (2022), छठी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए आयोजित किया गया, सर्वेक्षण रिपोर्ट और हैंडबुक दोनों को अकादमिक संसाधन के तहत केवीएस (मुख्यालय) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता और जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न हितधारकों (स्कूल प्रशासकों, शिक्षकों, आदि) के लिए सत्र और सम्मेलन आयोजित किए गए। क्षेत्रीय स्तर की कार्यशालाओं की भी योजना बनाई जा रही है।

(ज) अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023

एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ का आयोजन भारत मंडपम, प्रगति मैदान में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने एनईपी 2020 की तीसरी वर्षगांठ पर भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 का उद्घाटन किया।

(झ) दिनांक 23.08.2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान– 3 की लैंडिंग का दृश्य

चंद्रमा पर भारत के चंद्रयान –3 की लैंडिंग एक स्मरणीय अवसर है जो न केवल जिज्ञासा को बढ़ाता है बल्कि हमारे युवाओं के मन के भीतर अन्वेषण के लिए जुनून भी जगाता है। यह कार्यक्रम दिनांक 23 अगस्त, 2023 को 17.27 बजे आईएसटी से लाइव प्रसारित किया गया था। इसरो की वेबसाइट (https://www.isro.gov.in) और डीडी नेशनल टीवी चैनल सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से लाइव कवरेज उपलब्ध था।

इस संबंध में, केवीएस ने देश भर के सभी के. वि. को निर्देश जारी किया है कि वे दिनांक 23.08.2023 को शाम 5.30 बजे से शाम 6.30 बजे तक छात्रों और शिक्षकों की एक विशेष सभा बुलाएं ताकि चंद्रमा पर चंद्रयान–3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग सामूहिक रूप से देखी जा सके।

केंद्रीय विद्यालयों के 8 लाख से अधिक छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों ने चंद्रमा पर चंद्रयान–3 की लैंडिंग की लाइव स्ट्रीमिंग देखी। इस ऐतिहासिक क्षण ने छात्रों और शिक्षकों को भी अंतरिक्ष के विषय में जानने और इस महान मिशन में इसरो के वैज्ञानिकों के लगातार प्रयासों की सराहना के लिए प्रेरित किया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालयों ने भी भाग लिया।

दिनांक	कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या	कार्यक्रम में भाग लेने वाले शिक्षकों की संख्या	कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभिभावकों की संख्या	कार्यक्रम में भाग लेने वाले आगंतुकों की संख्या
29.07.2023	2478	733	54	3265
30.07.2023	2341	532	36	2909

के.वि.सं. द्वारा विभिन्न संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

(क) कौशल संसाधनों को बढ़ाने पर आईबीएम और के.वि.सं. के बीच समझौता ज्ञापन

आईबीएम और के.वि.सं. के बीच एक सुदृढ़ शिक्षा और कौशल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर कौशल संसाधनों और प्लेटफार्मों को बढ़ाने के लिए साझेदारी के गठन संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो महत्वपूर्ण विचारकों, समस्या–समाधानकर्ताओं और अगली पीढ़ी के नवप्रवर्तकों का निर्माण करता है।

आईबीएम अपने कार्यान्वयन भागीदारों (हाई स्कूल के छात्रों के लिए स्किल्सबिल्ड हेतु एनपीओ भागीदार) के माध्यम से केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ साझेदारी करेगाः

- ऑनलाइन/व्यक्तिगत कार्यशालाओं, वेबिनारों आदि के माध्यम से छात्रों, प्रशिक्षकों/शिक्षकों आदि को डिजिटल सामग्री/स्किल्सबिल्ड प्लेटफॉर्म और संबंधित प्रशिक्षण तक पहुंच प्रदान करना।
- परियोजना से संबंधित सभी मामलों में समन्वय के लिए एकल संपर्क बिंदु (एसपीओसी) को नामांकित करना
- बैनर, स्टैंडी, फ़्लायर्स, ब्रोशर, प्रमाणपत्र आदि जैसी ब्रांडिंग सामग्री के अनुमोदन के लिए आईबीएम उत्तरदायी होगा।

(ख) रूपांतर कार्यक्रम के लिए श्री अरबिंदो सोसायटी और केवीएस के बीच समझौता ज्ञापन

श्री अरबिंदो सोसाइटी (एसएएस) और केवीएस के बीच रूपांतर कार्यक्रम के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जो निम्नलिखित कार्यक्रमों को सुविधाजनक बनाकर/आयोजित करके बेहतर अधिगम परिणाम प्राप्त करने में मदद करेगाः

- योग्यता–आधारित शिक्षा
- परियोजना समावेशन
- ऑरो विद्वान
- मूल्यांकन–सहायता

इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये जायेंगेः

- सभी छात्रों के शैक्षिक अनुभव व अधिगम परिणामों में वृद्धि, और
- के.वि.सं. शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में सहायता प्रदान करना।

(ग) सड़क सुरक्षा पर सियाम और केंद्रीय विद्यालय संगठन के बीच समझौता ज्ञापन

दिनांक 2 अगस्त 2023 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) और केवीएस के बीच सड़क सुरक्षा पहल कार्यक्रम (सुरक्षित यात्रा) पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसका उद्देश्य केंद्रीय विद्यालयों के छात्रों के लिए सड़क सुरक्षा ऑनलाइन शैक्षिक सत्र का निष्पादन करना है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवा मन में जिम्मेदार सड़क व्यवहार को विकसित करना और सड़क सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देना है। माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मुख्य अतिथि के रूप में इस व्यापक जागरूकता पहल के शुभारंभ समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव श्री संजय कुमार, सियाम के अध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में संयुक्त सचिव श्रीमती प्राची पांडे के साथ–साथ केवीएस के आयुक्त तथा केवीएस और शिक्षा मंत्रालय के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य स्कूली छात्रों के साथ सियाम को जोड़ना है ताकि जागरूकता फैलाई जा सके और सड़क सुरक्षा के मुद्दों पर

ज्ञान बढ़ाया जा सके तथा उन्हें और दूसरों को हमारी सड़कों पर सुरक्षित बनाया जा सके। इस कार्यक्रम को 'सुरक्षित यात्रा' का नाम दिया गया है। प्रभावी सड़क सुरक्षा शिक्षा हेतु, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच), भारत सरकार के साथ–साथ सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), जो सभी प्रमुख वाहन और वाहन इंजन निर्माताओं का प्रतिनिधित्व करने वाला एक गैर–लाभकारी शीर्ष राष्ट्रीय निकाय है, के.वि. के छात्रों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा शिक्षा श्रृंखला आयोजित करेगा।

(घ) **समर्पित पीएम ई–विद्या चैनल के लिए केवीएस और एनसीईआरटी के बीच समझौता ज्ञापन:**

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के पीएम ई–विद्या कार्यक्रम के तहत स्कूल शिक्षा के लिए पीएम ई–विद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से शैक्षिक वीडियो सामग्री के प्रसारण के संबंध में केवीएस और एनसीईआरटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

पुरस्कार और उपलब्धियां

छात्रों, केन्द्रीय विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों को विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए भारत सरकार के संगठन द्वारा पुरस्कार और अवार्ड से सम्मानित किया गया है:

(क) **प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार–2023:** के.वि. सीसीआई बोकाजन, असम की छात्रा कुमारी श्रेया भट्टाचार्जी को कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी असाधारण उपलब्धि के लिए प्रधान मंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।

(ख) **राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार–2022:** राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस, अर्थात 5 सितंबर को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। श्री मुजीब रहमान केयू, लाइब्रेरियन, केंद्रीय विद्यालय कांजीकोड, पुडुसरी, मालमपुझा, पलक्कड़, केरल और सुश्री चेतना खंबेटे, पीजीटी (जीव विज्ञान), केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 बीएसएफ इंदौर, मध्य प्रदेश, को भारत के राष्ट्रपति द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उनके सराहनीय योगदान के लिए दिनांक 5 सितंबर 2023 को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

(ग) **ग्रीन स्कूल पुरस्कार:** ग्रीन स्कूल प्रोग्राम पुरस्कार समारोह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जहां देश भर के शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को उनके उद्यम और नवीन कौशल के लिए पुरस्कृत किया जाता है। इसका उद्देश्य इस प्रयास को स्वीकार करना है, और अधिक स्कूलों को आगे आकर इस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। फरवरी 2023 में, 707 स्कूलों में से दो केन्द्रीय विद्यालयों ने निम्नलिखित श्रेणियों में ग्रीन स्कूल पुरस्कार जीता:

स्टर्लिंग स्कूल पुरस्कार: (स्कूलों को लगातार पांच वर्षों तक 'हरित' दर्जा दिया गया)– केन्द्रीय विद्यालय डब्ल्यूसीएल, न्यू माजरी, चंद्रपुर, महाराष्ट्र

जीएसपी ऊर्जा प्रबंधक पुरस्कार: डॉ. राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय विद्यालय, मध्य दिल्ली, नई दिल्ली

के.वि.सं. में डिजिटल/आईसीटी पहल

केन्द्रीय विद्यालय संगठन गति–निर्धारक संगठन है और इसने देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की हैं जिनमें विभिन्न श्रव्य/वीडियो

उपकरण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का अनुप्रयोग शामिल है।

(क) ई–क्लासरूम

वर्ष 2014–15 से केन्द्रीय विद्यालयों में कुल 13011 ई–क्लासरूम स्थापित किए गए हैं। ये ई–क्लासरूम एप्पल आई–पैड, स्ट्रीमिंग डिवाइस, इंटरएक्टिव बोर्ड/पैड, विजुअलाइज़र, डेस्कटॉप कंप्यूटर और मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर से युक्त हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की पीएमजेवीके योजना के तहत 12 डबल शिफ्ट केवी (कुल 277) सहित 265 केंद्रीय विद्यालयों में कनेक्टेड क्लासरूम सॉल्यूशन का उपयोग करके व्यक्तिगत शिक्षण की एक इकाई स्थापित की गई है। प्रत्येक इकाई में 40 लैपटॉप और एक मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर शामिल है।

इसके अलावा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की पीएमजेवीके योजना के तहत अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में 238 केंद्रीय विद्यालयों में 2310 ई–लर्निंग संसाधन स्थापित किए गए हैं। ई–लर्निंग संसाधन की प्रत्येक इकाई स्टाइलस स्ट्रीमिंग डिवाइस, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, स्कूल मैनेजर, मोबाइल डिवाइस प्रबंधन, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली और देशी ऐप्स, किताबें, मेल कैलेंडर, नोट्स आदि के साथ इंटरएक्टिव टैबलेट से सुसज्जित है।

(ख) डिजिटल भाषा प्रयोगशाला

स्व–अध्ययन की गति से छात्रों के संचार कौशल को बढ़ाने के लिए कुल 376 डिजिटल भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। डिजिटल भाषा प्रयोगशाला व्यापक और परस्पर संवादात्मक डिजिटल सामग्री के लिए एक मंच है, जो एक प्रेरणादायक प्रयोगशाला वातावरण का उपयोग करते हुए सुनने और बोलने का कौशल प्रदान करता है। यह चार कौशलों की पूर्ति करता है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। यह एक सुविधा प्रदान करता है जो छात्र को मॉडल उच्चारण सुनने, दोहराने और रिकॉर्ड करने, उनके प्रदर्शन को सुनने और मॉडल के साथ तुलना करने और आत्म–मूल्यांकन करने में सक्षम बनाता है। यह डिजिटल भाषा प्रयोगशाला अंग्रेजी भाषा में किसी के भाषण का अभ्यास और आकलन करने के लिए एक बहुत ही उपयोगी उपकरण है।

(ग) ई–ऑफिस

एनआईसी ई–ऑफिस के माध्यम से ई–गवर्नेंस परियोजना के तहत केवीएस (मुख्यालय) में ई–ऑफिस लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में कागज रहित माहौल स्थापित करना, मौजूदा मैनुअल, कागज–संचालित प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक वर्कफ़्लो में बदलना है। विभिन्न सेवाओं और अनुप्रयोगों के लिए उपयोगकर्ता जानकारी का संगठन–स्तरीय सामान्य भंडार, डेटा सुरक्षा और डेटा अखंडता, स्थानीय भाषा हेतु यूनिकोड–अनुरूप सहायता सुनिश्चित करने के लिए अंतर/अंतरा–सरकारी सूचना साझाकरण को बढ़ावा देते हुए पारदर्शिता बढ़ाता है। सभी 04 फ़ाइल, ज्ञान, अवकाश और यात्रा प्रबंधन प्रणालियाँ लागू की गई हैं। अब ई–ऑफिस का विस्तार क्षेत्रीय कार्यालयों और ज़ेडआईईटी तक कर दिया गया है।

(घ) ऑनलाइन प्रवेश

शैक्षणिक सत्र 2016–17 से देशभर में कक्षा एक की प्रवेश प्रक्रिया क्लाउड–आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से की गई है। कुल मिलाकर, 122850 सीटें ऑनलाइन प्रवेश पोर्टल द्वारा भरी गईं। इनमें से कक्षा एक में 109280 सीटें और बालवाटिका कक्षा में 13570 सीटें भरी गईं।

(ङ) ऑनलाइन कक्षा अवलोकन

कक्षा अवलोकन और पर्यवेक्षण हेतु एक

ऑनलाइन एप्लिकेशन विकसित किया गया है और संगठन में सभी तीन स्तरों पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया की नियमित निगरानी के लिए पीआईएमएस पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है।

(च) दिनांक 31.12.2023 तक केवीएस में आईसीटी अवसंरचना

क्र.सं.	मद	संख्या
1	कार्यात्मक के.वि. की कुल संख्या	1254
2	के.वि. में उपलब्ध कंप्यूटरों की कुल संख्या	75499
3	के.वि. में छात्रों की कुल संख्या (30.09.2023 तक)	1400632
4	छात्र–कंप्यूटर अनुपात	18:1
5	कंप्यूटर लैब सहित के.वि. की संख्या	1245 (99.28%)
6	इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले के.वि. की संख्या	1250 (99.68%)
7	ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी वाले के.वि. की संख्या	1224 (97.60%)
8	अपनी स्वयं की वेबसाइट रखने वाले के.वि. की संख्या	1254 (100%)

के.वि.सं. में क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण) कार्यक्रम

केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपने शिक्षकों की सभी श्रेणियों के लिए ज्ञान और शिक्षण पद्धति को अद्यतन करने तथा नवीन पद्धतियां अपनाने के लिए क्षमता निर्माण पर उचित बल देता है। एक गति–निर्धारक और सक्रिय संगठन होने के नाते, केवीएस शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में क्रांतिकारी रुझानों को अपनाने और लागू करने में हमेशा अग्रणी रहा है। इस प्रकार, कोविड–19 महामारी संकट जैसी स्थिति में, इसने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों को जल्दी से संशोधित और अनुकूलित किया, जो शुरू में ऑफ़लाइन मोड में थे उन्हें ऑनलाइन मोड में किया गया था। केवीएस में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य विषय एनईपी 2020, एनसीएफएसई 2023 और एनसीएफएफएस 2022 के प्रावधानों के अनुरूप है और इसे मुख्यतः निम्नलिखित क्षेत्रों मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान, अनुभवात्मक शिक्षा हेतु शैक्षणिक कार्य और योग्यता आधारित शिक्षा (सीबीएल) पर आधारित मूल्यांकन में विभाजित किया गया है। केवीएस ने एनईपी 2020 में अनिवार्य रूप से शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए 50 घंटे की सीपीडी हेतु 50 दिशानिर्देशों को भी अपनाया और अधिसूचित किया। वर्ष 2022–23 और 2023–24 (31.12.2023 तक) में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के बाद, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी/एचएम के लिए 21 दिवसीय सेवाकालीन पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सत्र 2022–23 जहां 567 शिक्षकों के प्रशिक्षण के साथ–साथ कला शिक्षक, कार्य अनुभव, लाइब्रेरियन और संगीत शिक्षकों जैसे 625 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जेडआईईटी, क्षेत्रीय कार्यालयों और ज्ञान भागीदारों के साथ अल्पकालिक कार्यशालाएं (एसडीडब्ल्यू) आयोजित की गईं जिसमें 41458 ने भाग लिया। विवरण नीचे दिया गया है:

अल्पावधि कार्यशालाएँ/प्रशिक्षण (इन–हाउस एवं आउटसोर्स)

क्र. सं.	एजेंसी	पाठ्यक्रमों की संख्या	भागीदारी की सं.
1	ज़ेडआईईटी	98	3448
2	क्षेत्रीय कार्यालय	367	27681
3	नॉलेज पार्टनर्स– एनसीईआरटी, सीबीएसई, श्री अरबिंदो सोसाइटी आदि।	156	10329
	कुल	**621**	**41458**

केवीएस के कुछ ज्ञान भागीदार हैं: एनसीईआरटी, सीबीएसई, श्री अरबिंदो सोसाइटी (एसएएस), अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय, एचबीसीएसई, मुंबई, आईएमएससी चेन्नई, एसआईएनपी कोलकाता, एनआईएसईआर+एलओपी, भुवनेश्वर, आईआईएसईआर मोहाली, आईआईटी गांधी नगर, एनआईपीसीसीडी, एचबीसीएसई, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एजेएनआईएफएम)।

दिनांक 01.01.2023 से दिसंबर, 2023 तक खोले गए नए केंद्रीय विद्यालय

वर्ष 2023 के दौरान कुल 03 केन्द्रीय विद्यालय खोले गए हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन दिनांक 7 फरवरी, 2024 तक विदेश में स्थित तीन (मॉस्को, काठमांडू और तेहरान) सहित 1254 केंद्रीय विद्यालयों की एक विशाल श्रृंखला है।

क्र. सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	राज्य
1.	दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण, गांधीधाम, जिला कच्छ	गुजरात
2.	एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, जोटे जिला पापुम पारे	अरुणाचल प्रदेश
3.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, घुद्दा, जिला– भटिंडा	पंजाब

के.वि.सं. में भर्ती

कोविड के दौरान उत्पन्न रिक्तियों को भरने के लिए सीबीएसई के माध्यम से बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चलाया गया। भारत सरकार के मिशन भर्ती अभियान के तहत रोजगार मेले के माध्यम से दिसंबर 2023 तक 12,554 सीधी भर्ती से चयनितों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए। इसके साथ ही सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के माध्यम से 2902 रिक्त पदों को भरा गया।

नव निर्मित भवन

तीन केंद्रीय विद्यालयों अर्थात **के.वि. झाझा** (बिहार), **के.वि. कोनी** (केरल) और **के.वि. एसएसजी सीआईएसएफ सूरजपुर** ग्रेटर नोएडा (यूपी) के भवन अप्रैल, 2023 से दिसंबर, 2023 तक पूरे हो चुके हैं।

वित्त

केवीएस पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) द्वारा वर्ष 2016–17 तक गैर–योजना और योजना शीर्षों के तहत केवीएस को स्वीकृत बजट और उसके बाद भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय द्वारा राजस्व और पूंजी शीर्षों के तहत केवीएस को स्वीकृत बजट निम्नानुसार हैं:

वित्त: केवीएस को स्वीकृत बजट

(रु. करोड़ में)

वर्ष	गैर योजना	योजना
2015-2016	2403-47	380-00
2016-2017	2884-54	476-73
	राजस्व	**पूंजी**
2017-18	4323-01	674-24
2018-19	4775-40	231-35
2019-20	4868-10	143-90
2020-21	6162-68	275-00
2021-22	6300-00	500-00
2022-23	6761-00	700-00
ब.अ.– 2022-23	7412-98	951-00

केवीएस प्रकाशन

केवीएस ने 2023 में संगठन की विभिन्न गतिविधियों, पहलों और योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए निम्नलिखित पुस्तकें और पत्रिकाएँ प्रकाशित की हैं:

1. केवीएस वार्षिक लेखे (2022–2023)
2. वार्षिक रिपोर्ट (2022–2023)

3. शाला ध्वनि– जी–20 जनभागीदारी संबंधी विशेषांक–जी–20 में भारत की अध्यक्षता का जश्न
4. शाला ध्वनि–'परीक्षा पे चर्चा–2023' पर विशेषांक
5. शाला ध्वनि– अप्रैल–जून 2023 अंक)
6. शाला ध्वनि– जुलाई–सितंबर 2023 अंक)
7. काव्य पुस्तक 'काव्य मंजरी'– केवीएस हीरक जयंती संबंधी विशेषांक
8. उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक पुस्तक–I का हिंदी संस्करण, शीर्षक–प्रेरणा
9. उद्देश्यपूर्ण शैक्षणिक पुस्तक का दूसरा संस्करण जिसका शीर्षक है– कसिलय
10. केवीएस हीरक जयंती संबंधी एक कॉफी टेबल बुक
11. केवीएस कैलेंडर–2024

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस):

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के साथ उत्कृष्टता प्रदान करने के उद्देश्य से आवासीय नवोदय विद्यालयों की स्थापना की परिकल्पना की गई थी। इसके परिणामस्वरूप, नवोदय विद्यालय समिति को 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना मूल्यों, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, साहसिक गतिविधियों और शारीरिक शिक्षा के सुदृढ़ घटक सहित अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालयों की स्थापना करने के उद्देश्य के साथ एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं।

शिक्षा का नवोदय मॉडल:

- सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूदगी।
- आवासीय व्यवस्था और शिक्षकों के साथ रहना।
- आधुनिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कम लागत का संचालन।
- प्रतिबद्ध कर्मचारी।
- छात्रों के साथ गहन बातचीत।
- व्यक्तिगत प्रभावशीलता और मानवीय मूल्यों की एकाग्रता के साथ सभी जीवन कौशलों का प्रदर्शन।
- छात्र अपनी लगभग सभी व्यक्तिगत गतिविधियाँ करते हैं।
- सभी परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन।
- पूर्व छात्रों की पहचान उनके स्कूल से प्राप्त व्यक्तिगत मूल्य से होती है।
- लड़कियों, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की भागीदारी अधिक है।

जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की प्रक्रिया/मानदंड

जवाहर नवोदय विद्यालय का खोला जाना एक सतत् प्रक्रिया है। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से व्यय, संस्वीकृत संख्या आदि से संबंधित प्रस्ताव के विधिवत अनुमोदन के बाद नए जिलों में नए जवाहर नवोदय विद्यालयों को प्रचालनात्मक बनाया जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को लगभग 30 एकड़ निःशुल्क तथा सभी दायित्वों से मुक्त उपयुक्त भूमि उपलब्ध करानी होती है। राज्य सरकार को तीन से चार वर्षों के लिए अथवा जब तक समिति स्थायी स्थल पर अपने स्वयं के भवनों का निर्माण नहीं कर लेती तब तक 240 छात्रों और कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए निःशुल्क पर्याप्त अस्थायी भवन/आवास और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं भी प्रदान करनी होंगी।

स्वीकृत एवं कार्यात्मक जनवि की स्थिति:

वर्ष 1985–86 के दौरान झज्जर (हरियाणा) और अमरावती (महाराष्ट्र) में स्थापित दो जनवि से शुरुआत करते हुए, तमिलनाडु राज्य जिसने अभी तक नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है, को छोड़कर, अब तक 27 राज्यों और 08 संघ राज्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा कुल 661 जनवि को मंजूरी दे दी गई है। देश में स्वीकृत कुल 661 जनवि में से 650 जनवि वर्तमान में कार्यात्मक हैं।

जनवि में छात्रों को प्रवेश:

जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार और आयोजित चयन परीक्षा के आधार पर किया जाता है। चयन परीक्षा गैर–मौखिक और वर्ग तटस्थ है और यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चे बिना किसी नुकसान का सामना किए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। केवल संबंधित जिले के उम्मीदवार जहां जवाहर नवोदय विद्यालय खोला गया है, प्रवेश के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। तथापि, जिस जिले में जनवि खोला गया है और बाद की तारीख में वह जिला विभाजित किया गया है तो उस नए विभाजित जिले में नया जनवि शुरू नहीं किए जाने तक जनवि में प्रवेश हेतु पात्रता के उद्देश्य से उसकी पुरानी सीमाओं को माना जाता है। जनवि सह–शैक्षणिक आवासीय विद्यालय हैं जिनमें छठी से बारहवीं तक की कक्षाएं होती हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जनविएसटी) के माध्यम से कक्षा VI, IX और XI में प्रवेश दिए जाते हैं। जेएनवीएसटी के लिए पंजीकृत और वर्ष 2023 में चयनित छात्रों के सांख्यिकीय आंकड़े इस प्रकार हैं:

कक्षाओं हेतु जनविएसटी	पंजीकृत	उपस्थित हुए	चयनित
VI	24,67,347	19,21,824	47,252
IX	1,81,006	1,07,619	2,572
XI	58,434	26,499	5,692

जनवि में छात्रों के प्रवेश के लिए आरक्षण नीति:

- किसी जिले में कम से कम 75% सीटें संबंधित जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अनंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों द्वारा भरी जाती हैं। शेष सीटें खुली हैं, जो संबंधित जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों से भरी जाती हैं।
- संबंधित जिले में वास्तविक जनसंख्या के अनुसार एससी और एसटी के लिए आरक्षण न्यूनतम राष्ट्रीय औसत (अर्थात एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5%) के अध्यधीन है, लेकिन दोनों श्रेणियों (एससी और एसटी) के लिए कुल मिलाकर अधिकतम 50% के अध्यधीन है।
- सीटों का 1/3 भाग छात्राओं हेतु आरक्षित है।
- दिव्यांग बच्चों (अर्थात् अस्थि विकलांग, श्रव्य बाधित और दृष्टिबाधित) के लिए 80 सीटों में से 3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- ओबीसी उम्मीदवारों हेतु 27% आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी उम्मीदवारों के लिए आरक्षण समय–समय पर लागू केंद्रीय सूची के अनुसार है।

5. दिनांक 30.11.2023 तक जनवि में छात्रों का नामांकन

कुल	बालक	बालिकाएँ	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी
2,88,022	1,66,347	1,21,675	2,57,579	30,443	51,576	1,08,311	69,585	58,550
:	57.75	42.25	89.43	10.57	17.91	37.61	24.16	20.33

भर्ती:

भर्ती एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि रिक्तियां सेवानिवृत्ति, पदोन्नति, त्यागपत्र, मौजूदा जनवि को उच्च कक्षाओं में क्रमोन्नत करने, नए विषय क्षेत्रों को मंजूरी देने, कर्मचारियों के निधन आदि के कारण उत्पन्न होती रहती हैं। जनवि की रिक्तियों को भरने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। छात्रों के शैक्षणिक हितों की रक्षा के लिए, रिक्त पदों, यदि कोई हों, के सापेक्ष शिक्षकों को नियमित शिक्षकों की भर्ती होने तक अल्पकालिक संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है।

चयन प्रक्रिया में एकरूपता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए समिति निम्नलिखित को अंगीकृत रही है:

- "केंद्रीकृत भर्ती" प्रक्रिया का सहारा लेना।
- पारंपरिक ओएमआर शीट/लिखित परीक्षा को हटाकर कंप्यूटर आधारित टेस्ट का सहारा लिया जा रहा है।
- नविस की आधिकारिक वेबसाइट पर "उत्तर पत्रक/प्रतिक्रिया पत्रक" के साथ "उत्तर कुंजी" प्रदर्शित की जाती है और अंतिम परिणाम प्रकाशित करने से पहले आपत्तियों, यदि कोई हों, का समाधान किया जाता है।
- मेरिट की स्थिति और रिक्ति की उपलब्धता के अध्यधीन उम्मीदवार द्वारा चुने गए विकल्प के आधार पर तैनाती दी जाती है।

वर्ष 2023 के दौरान, 2,008 शिक्षण कर्मचारियों और 1,626 गैर–शिक्षण कर्मचारियों को सीधी भर्ती अभियान के माध्यम से भर्ती किया गया है और 681 शिक्षण कर्मचारियों और 511 गैर–शिक्षण कर्मचारियों को पदोन्नति अभियान के माध्यम से पदोन्नत किया गया है।

ज.न.वि का प्रदर्शन:

ज.न.वि लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जैसा कि पिछले कई वर्षों से सीबीएसई द्वारा घोषित परिणामों से स्पष्ट है:

वर्ष	कक्षा– X	कक्षा– XII
2018	97.15	97.08
2019	98.57	96.62
2020	98.66	98.70
2021	99.97	99.94
2022	99.71	98.93
2023	99.14	97.51

सीबीएसई परीक्षा 2022–23 में छात्रों का प्रदर्शन:

विवरण	कक्षा– XII	कक्षा– X
ज.न.वि की संख्या	563	633
उपस्थित छात्रों की संख्या	35772	45911
उत्तीर्ण छात्रों की संख्या	34882	45515
उत्तीर्णता का प्रतिशत (%)	97.51	99.14
प्रथम श्रेणी प्रतिशत (%)	89.24	85.05

विवरण	कक्षा– XII	कक्षा– X
100 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	310	1155
100% उत्तीर्णता(%) वाले ज.न.वि. की संख्या	302	477
90% से अधिक वाले छात्रों की संख्या	2114 (5.91%)	5746 (12.52%)
औसत अंक	73.37	74.64

प्रतियोगी परीक्षाओं 2023 में उपलब्धियाँः

क्र.स.	प्रतियोगी परीक्षा	उपस्थित छात्रों की संख्या	पात्र छात्र	पात्र छात्रों का प्रतिशत
01.	जेईई मेन्स	11,458	4,726	41.25
02.	जेईई एडवांस	3,796	1,228	32.30
03.	नीट	23,360	17,809	76.24

अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में बच्चों का प्रवेशः टाटा ट्रस्ट और ऐसे अन्य समर्थकों द्वारा समर्थित कर्ता पहल फाउंडेशन द्वारा आयोजित सीएसआर सहायता की मदद से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उच्च अध्ययन के लिए सहायता हेतु नवोदय विद्यालय समिति द्वारा एक नई पहल की गई है। निम्नलिखित छात्रों ने 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त किया हैः

क्र. स.	विश्वविद्यालय और देश	छात्रों की संख्या						
		2017	2018	2019	2021	2022	2023	कुल
1	इंपीरियल कॉलेज लंदन, यूके	01	-	01	-	-	-	02
2	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूके	01	01	-	02	02	02	08
3	ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूके	01	-	-	-	-	-	01
4	यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूके	01	-	-	-	01	-	02
5	मैकगिल विश्वविद्यालय, कनाडा	-	01	-	-	01	-	02
6	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूके	-	-	02	-	-	-	02
7	ह्यूरॉन विश्वविद्यालय, कनाडा	-	-	01	-	02	01	04
8	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	-	-	01	-	02	02	05
9	क्वींस विश्वविद्यालय – किंग्स्टन, कनाडा	-	-	01	01	04	03	09
योग		**4**	**2**	**6**	**3**	**12**	**08**	**35**

वर्ष 2017 से अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने वाले छात्रों का विवरणः

क्र. स.	छात्रों के नाम	जनवि [जिला]	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिस विश्वविद्यालय में चयन हुआ	विषय / पाठ्यक्रम	वर्ष
1	सुश्री दीप्ति आर राप्टे	पालघर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	जैविक विज्ञान	2017
2	श्री शिवम ए. दुबे	पालघर	महाराष्ट्र	इंपीरियल कॉलेज, यूनाइटेड किंगडम	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	2017
3	श्री सदानंद एच. उगले	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन, यूनाइटेड किंगडम	अंक शास्त्र	2017
4	श्री आदेश डी. वैद्य	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	जीव रसायन	2017
5	सुश्री नेशमा मेहतर	दक्षिण गोवा	गोवा	मैकगिल विश्वविद्यालय, कनाडा	कला और विज्ञान	2018
6	सुश्री अनुजा खुरे	लातूर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	भौतिक विज्ञान	2018
7	सुश्री विशाखा पुजारी	लातूर	महाराष्ट्र	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	एप्लाइड साइंसेज और इंजीनियरिंग	2019
8	सुश्री सहाना नायक	हावेरी	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	विज्ञान	2019
9	श्री अजिंक्य हरुगाडे	पालघर	महाराष्ट्र	ह्यूरन कॉलेज, वेस्टर्न विश्वविद्यालय, कनाडा	प्रबंधन और संगठनात्मक अध्ययन	2019
10	श्री उत्कर्ष मॉल	दक्षिण गोवा	गोवा	इंपीरियल कॉलेज, यूना. इटेड किंगडम	पृथ्वी और ग्रह विज्ञान	2019
11	श्री मृत्युंजय अंगदि	हावेरी	कर्नाटक	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	पृथ्वी विज्ञान	2019
12	सुश्री सृष्टि पल्क्षप्पा	चिक्कामगलुरु	कर्नाटक	ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	जीव रसायन	2019
13	श्री अभय मौर्य	पालघर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	कंप्यूटर विज्ञान और गणित	2021

क्र. स.	छात्रों के नाम	जनवि [जिला]	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिस विश्वविद्यालय में चयन हुआ	विषय / पाठ्यक्रम	वर्ष
14	श्री अक्षय देसले	पालघर	महाराष्ट्र	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	कम्प्यूटिंग	2021
15	सुश्री संध्या बेहरा	पालघर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	जैविक विज्ञान	2021
16	सुश्री वत्सला	हावेरी	कर्नाटक	मैकगिल विश्वविद्यालय, कनाडा	वाणिज्य	2022
17	सुश्री दीप्ति धावड़े	अहमदनगर	महाराष्ट्र	यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनाइटेड किंगडम	गणित और कंप्यूटर	2022
18	सुश्री मान्यता केदार	अहमदनगर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	बायोमेडिकल साइंसेज	2022
19	श्री सचिन म्हाशा	पालघर	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	भूगर्भ शास्त्र	2022
20	सुश्री श्रीरक्षा	उडुपी	कर्नाटक	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	कंप्यूटर विज्ञान	2022
21	श्री मोहम्मद शिहान	चिक्कामगलुरु	कर्नाटक	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	जैविक विज्ञान	2022
22	सुश्री रोहिणी वाघ	जलना	महाराष्ट्र	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	विज्ञान	2022
23	सुश्री अर्चना एस.ए.	हावेरी	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	अभियांत्रिकी	2022
24	सुश्री सिंधु एच. डी.	शिमोगा	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	स्वतंत्र कला	2022
25	श्री विकास एच.के.	चिक्कामगलुरु	कर्नाटक	ह्यूरॉन विश्वविद्यालय, कनाडा	विज्ञान	2022
26	सुश्री राधिका जे.	शिमोगा	कर्नाटक	ह्यूरॉन विश्वविद्यालय, कनाडा	प्रबंधन और संगठनात्मक अध्ययन	2022
27	श्री अजय ज़िरे	पालघर	महाराष्ट्र	ह्यूरॉन विश्वविद्यालय, कनाडा	मनोविज्ञान	2022

क्र. स.	छात्रों के नाम	जनवि [जिला]	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिस विश्वविद्यालय में चयन हुआ	विषय / पाठ्यक्रम	वर्ष
28	सुश्री नंदिता के.ए.	शिमोगा	कर्नाटक	ह्यूरॉन विश्वविद्यालय, कनाडा	प्रबंध	2023
29	सुश्री केतकी कर्वे	रत्नागिरि	महाराष्ट्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	समाजशास्त्र और मनो. विज्ञान	2023
30	सुश्री मोनिशा के.जे.	चिकमंगलूर	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	बीएससी	2023
31	सुश्री चिन्मयी हेब्बर	चिकमंगलूर	कर्नाटक	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	फोरेंसिक विज्ञान	2023
32	श्री अभिषेक जाधव	पालघर	महाराष्ट्र	टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा	सामाजिक विज्ञान में ऑनर्स	2023
33	श्री मनु एम. एस.	हसन	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	अभियांत्रिकी	2023
34	श्री आर्य भण्डारी	चिकमंगलूर	कर्नाटक	क्वींस विश्वविद्यालय, कनाडा	अभियांत्रिकी	2023
35	श्री अभनव सी. जी.	माहे	पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	एडिनबर्ग विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम	समाज शास्त्र	2023

सिविल सेवाओं में ज.न.वि. के पूर्व छात्रों का चयन: यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से प्रत्येक वर्ष लगभग 25 से 30 छात्रों का सिविल सेवा में चयन होता है। वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

वर्ष	न.वि.सं. के पूर्व छात्रों की संख्या
2018	25
2019	24
2020	27
2021	28
2022	23

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा – 2022 में उत्तीर्ण एनवीएस के पूर्व छात्रों का विवरण

क्र. स.	पूर्व छात्र का नाम	जनवि (जिला)	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अखिल भारतीय रैंक (एआईआर)
1	श्री संदीप कुमार झा	मधुबनी	बिहार	24
2	सुश्री दिव्या	महेंद्रगढ़	हरियाणा	105
3	श्री ऋषिकेश हनमंत शिंदे	रत्नागिरि	महाराष्ट्र	183
4	श्री हर्ष	कैथल	हरियाणा	194
5	श्री महेश कुमार कामताम	कामारेड्डी (तत्कालिन निज़ामाबाद)	तेलंगाना	200
6	श्री मनिल बेजोत्रा	कांगड़ा	हिमाचल प्रदेश	314
7	सुश्री मीनाक्षी आर्य	नैनीताल	उत्तराखंड	444
8	श्री जे. भानु प्रकाश	चामराजनगर	कर्नाटक	448
9	सुश्री शालू	जौनपुर	उत्तर प्रदेश	453
10	श्री सरजीत काजला	झुंझुनूं	राजस्थान	455
11	श्री स्वप्निल बागल	हिंगोली	महाराष्ट्र	504
12	श्री प्रशांत सुरेश डगले	नासिक	महाराष्ट्र	535
13	श्री आलोक कुमार	गोड्डा	झारखंड	549
14	श्री जीतेन्द्र प्रसाद कीर	अजमेर	राजस्थान	569
15	श्री करण नरेंद्र मोरे	सतारा	महाराष्ट्र	648
16	सुश्री पल्लवी विजयवंशी	बालाघाट	मध्य प्रदेश	730
17	श्री ऑस्टिन तायेंग	पूर्वी सियांग	अरुणाचल प्रदेश	747
18	श्री मिथलेश कुमार मीना	सवाई माधोपुर	राजस्थान	826
19	श्री केयूर कुमार पारगी	दाहोद – I	गुजरात	867
20	सुश्री भावनाबेन वाढेर	सुरेंद्र नागर	गुजरात	904
21	सुश्री नेहा कुमारी	मधेपुरा	बिहार	916
22	श्री पद्मनाभ एच. एस.	मंड्या	कर्नाटक	923
23	सुश्री अनुप्रिया राय	चम्पावत	उत्तराखंड	(आरएल)*

** आरक्षित सूची के माध्यम से चयन किया गया*

ज.न.वि. छात्रों के लिए समिति द्वारा अपनाई गई प्रवासन नीतिः

नवोदय विद्यालय योजना की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत की संस्कृति और लोगों की विविधता तथा बहुलता की समझ को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष भाषाई क्षेत्र में एक जवाहर नवोदय विद्यालय से दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय तक कक्षा –IX के स्तर पर वर्ष के लिए छात्रों का आदान–प्रदान किया जाता है।

नविसं. वर्ष 1985–86 के दौरान संगठन की स्थापना के बाद से भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अनुरूप राष्ट्रीय एकता में अग्रणी रही है। मौजूदा शैक्षणिक सत्र अर्थात 2023–24 के दौरान सभी कार्यात्मक ज.न.वि. के कक्षा–9 के कुल 11,638 छात्रों को प्रवासित किया गया है।

जनवि में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर:

- सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में कंप्यूटर समर्थित शिक्षा है।
- 554 जवाहर नवोदय विद्यालयों में से प्रत्येक में कम से कम 2 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर प्रदान किए गए हैं।
- अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थित 99 जवाहर नवोदय विद्यालयों की सभी 1173 मौजूदा कक्षाओं को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की "**प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके)**" परियोजना के तहत स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया गया है।
- 550 जवाहर नवोदय विद्यालयों (प्रत्येक जनवि में 2) की मौजूदा 1100 कक्षाओं को भी स्मार्ट कक्षाओं में परिवर्तित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 6 एनएलआई (प्रत्येक एनएलआई में एक) में 14 स्मार्ट वर्चुअल कक्षाएं और 4 उत्कृष्टता केंद्र (प्रत्येक सीओई में दो) भी स्थापित किए गए हैं।
- दिनांक 5 जनवरी, 2024 तक, स्मार्ट बोर्ड, लैपटॉप/टैबलेट, प्रिंटर, वाई–फाई, राउटर आदि की अपेक्षित सुविधा के साथ कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के तहत 616 जवाहर नवोदय विद्यालयों में स्मार्ट कंप्यूटर लैब स्थापित की गई हैं।
- सभी ज.न.वि. के पास आईसीटी उपकरणों संबंधी रखरखाव और मार्गदर्शन हेतु कम से कम 40 कंप्यूटर, एफसीएसए हैं; कंप्यूटर छात्र अनुपात 1:6 है।
- सभी ज.न.वि. के लिए टीजीटी (कंप्यूटर साइंस) का पद स्वीकृत है।
- वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के जनवि में पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) का पद स्वीकृत है।
- शैक्षणिक सत्र 2022–23 के दौरान सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों के ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए 68,940 समर्पित डिजिटल डिवाइस (डिजिटल टैबलेट) 561 जेएनवी में प्रदान किए गए हैं।
- देश भर में चयनित ज.न.वि में पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब (72), स्मार्ट क्लासरूम (75), अटल टिंकरिंग लैब (08), स्किल लैब (45) और लैंग्वेज लैब्स [अंग्रेजी (98) और हिंदी (81)] का कार्यान्वयन।
- **क्षेत्रीय कार्यालयों में ई–ऑफिस का कार्यान्वयन:** क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ और पुणे में ई–ऑफिस को लागू किया गया है। इन क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए नामित मास्टर प्रशिक्षकों को प्रबंधन एवं कार्यात्मकता संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।
- **केंद्रीकृत आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली:** एनवीएस (मुख्यालय/क्षे.का./एनएलआई/जनवि) की सभी इकाइयों में सीएबीएस को लागू किया गया है। उक्त प्रणाली पारदर्शिता, समय की पाबंदी और दक्षता सुनिश्चित करेगी।

जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों के लिए सुविधाएं:

जवाहर नवोदय विद्यालयों में रहने और खाने के साथ–साथ वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, बेडिंग आइटम स्टेशनरी, दैनिक उपयोग के आइटम, परीक्षा शुल्क तथा

आधिकारिक अकादमिक गतिविधियों में सहभागिता हेतु यात्रा पर खर्च (टीए/डीए) आदि सहित शिक्षा सभी छात्रों के लिए निःशुल्क है। तथापि, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), छात्राओं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों के बच्चों को छोड़कर कक्षा IX से XII के छात्रों से प्रति माह 600/– रुपये (केवल छह सौ) का मामूली शुल्क "**विद्यालय विकास निधि (वीवीएन)**" के रूप में एकत्रित किया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के संबंध में, छूट प्राप्त श्रेणी (कक्षा छठी से आठवीं के छात्रा, सभी एससी, एसटी और छात्राएं, सीडब्ल्यूएसएन और बीपीएल परिवारों के बच्चे) के अलावा, वीवीएन या तो 1500/– रुपये (एक हजार पांच सौ केवल) प्रति माह या माता–पिता द्वारा प्रति माह प्राप्त वास्तविक बाल शिक्षा भत्ता, जो भी कम हो, का भुगतान किया जाना है। यदि प्राप्त बाल शिक्षा भत्ता 1500/– रुपये प्रति माह से कम है तो ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अपने संगठन में स्वीकार्य बाल शिक्षा भत्ते का उल्लेख करते हुए नियोक्ता द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तथापि, वीवीएन शुल्क प्रति छात्र प्रति माह 600/– रुपये से कम नहीं होगा। वर्ष 2022–23 के लिए प्रति छात्र प्रति वर्ष औसत परिचालन व्यय 1,43,044/– रुपये (केवल एक लाख तैंतालीस हजार और चवालीस) था।

प्रशिक्षण एवं विकासः

क) प्रशिक्षण अवसंरचनाः

नवोदय विद्यालय समिति नवोदय नेतृत्व संस्थानों (एनअलआई), क्षेत्रीय कार्यालयों और बाहरी एजेंसियों के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करती है। वर्तमान में नवोदय विद्यालय समिति के पास अमृतसर, गोवा, कामरूप, नोएडा, रंगारेड्डी, पुरी और उदयपुर, में नवोदय नेतृत्व संस्थानों (एनएलआई) के रूप में स्थापित 7 प्रशिक्षण संस्थान हैं।

नवोदय विद्यालय समिति प्रधानाचार्यों के लिए कई अभिविन्यास पाठ्यक्रम आयोजित करती है और विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। नवोदय विद्यालय समिति ने संगठन में अपनी क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सुविधाओं का विकास शुरू कर दिया है। विगत पांच वर्षों में आयोजित प्रशिक्षणों में वृद्धि हुई है। तथापि, प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर अधिक जोर दिया गया और तदनुसार अवसंरचना में महत्वपूर्ण सुधार किया गया।

क. जिन विद्यालयों में 2014–15 तक 5 स्थानों पर कुछ समय के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं, वहां उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अस्थायी व्यवस्था के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित किए गए हैं। नवोदय विद्यालय समिति (नविस) ने अपने शिक्षण और गैर–शिक्षण कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए अपने सात नवोदय नेतृत्व संस्थान (एनएलआई) की स्थापना की है। ये संस्थान नविस के कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देने के लिए बुनियादी ढांचे और सुविधाओं से सुसज्जित हैं। एनएलआई को विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने और उनके प्रदर्शन को बढ़ाने तथा संगठन की वृद्धि एवं विकास में योगदान करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। एनएलआई प्रधानाचार्यों और अन्य स्टाफ सदस्यों को शिक्षा और प्रबंधन में नवीनतम विकास के साथ अद्यतित रखने के लिए विभिन्न अभिविन्यास पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रदान करते हैं।

ख. वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर नई शिक्षा नीति–2020 की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

ग. कर्मचारियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण देने के लिए, नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) ने सभी सात नवोदय नेतृत्व संस्थानों (एनएलआई)

में कार्यबल सहायता का सृजन किया है। विगत चार वर्षों में, एनवीएस ने एनएलआई में गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करने में सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर 70 पद सृजित किए हैं। इन पदों पर योग्य और अनुभवी पेशेवर कार्यरत हैं जिनके पास एनवीएस कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने और प्रदान करने की विशेषज्ञता है। इन पदों के सृजन के साथ, एनवीएस ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार किया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि, कर्मचारियों को अपना काम प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्राप्त हो। प्रशिक्षण को परिणाम आधारित बनाया गया है जहां आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशाला से वास्तविक लाभ प्राप्ति हेतु कौशल परीक्षण दो बार प्रशिक्षण शुरू होने से पहले और प्रशिक्षण के अंत में किया जाता है। इसका अनुसरण आंतरिक और बाह्य परीक्षा के परिणामों के साथ भी किया जाता है और इसे प्रशिक्षण प्रक्रियाओं से भी जोड़ा जाता है।

ख) एनएलआई के माध्यम से एनवीएस में प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम:

- ❖ नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए प्रवेश कालिक कार्यक्रम (12 / 05 दिन)
- ❖ नव पदोन्नत कर्मचारियों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम (10 / 05 दिन)
- ❖ नव पदोन्नत शिक्षकों के लिए विषय संवर्धन कार्यक्रम (10 दिन)
- ❖ गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (03/05 दिन)
- ❖ टीजीटी हेतु रचनात्मक शिक्षाशास्त्र संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (03 दिन)
- ❖ रचनात्मक शिक्षकों के लिए सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम (05 दिन).
- ❖ उभरती व्यावसायिक दक्षताओं पर विशेष विषय आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम (02 / 03 दिन)
- ❖ हाउस मास्टर्स के लिए सुरक्षा एवं संरक्षा/मार्गदर्शन एवं परामर्श संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम (03 / 05 दिन)

ग) प्रशिक्षण संबंधी आंकड़े:

- ❖ **वर्ष 2022–23 के दौरान आयोजित कुल प्रशिक्षण:**

क्र.स	एनएलआई / बाहरी एजेंसी	कुल प्रशिक्षण	कुल प्रशिक्षुक
1	एनएलआई	77	3,040
2	बाहरी एजेंसियां	173	15,215
3	क्षेत्रीय कार्यालय स्तरीय प्रशिक्षण	34	980
	कुल >>>	**284**	**19,235**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020:

i. विषयों के चयन में छूट के साथ अनुभवात्मक अधिगम:

- कक्षात्मक संव्यवहार में कला/खेल/खिलौना/कहानी आधारित अध्यापन का एकीकरण
- एकीकृत अध्यापन में विभिन्न विषयों में 2459 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।
- एनआईईपीए के सहयोग से प्रशिक्षित प्रधानाध्यापकों द्वारा प्रत्येक ज.न.वि. के लिए वार्षिक शैक्षणिक योजना तैयार की जा रही है।
- वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कौशल विषयों के अतिरिक्त सभी तीन विषय क्षेत्रों (मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य) में छात्रों को विषयों का विकल्प प्रदान किया जाता है।

- कक्षा छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी छात्रों के लिए बिना बैग 10 दिन की अवधि।
- विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लबों (जैसे इको–क्लब, खगोल विज्ञान, पर्यटन, विज्ञान, ललित कला, प्रदर्शन कला, भाषा/साहित्यिक क्लब आदि) का गठन और प्रत्येक छात्र को इन क्लबों से जोड़ा गया।
- कक्षा के अतिरिक्त अनुभवात्मक अधिगम हेतु खुले क्षेत्रों में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान पार्कों की स्थापना।

ii. परिवर्तनकारी मूल्यांकनः

- सभी आंतरिक मूल्यांकनों में 50% योग्यता–आधारित प्रश्नों को शामिल करके स्मरण–आधारित से योग्यता–आधारित परिवर्तनकारी मूल्यांकन।
- स्कूल–आधारित मूल्यांकन के भाग के रूप में विषय संवर्धन, परियोजना, पोर्टफोलियो, समूह कार्य, प्रश्नोत्तरी आदि।
- प्रत्येक कक्षा हेतु सीबीएसई, ब्रिटिश काउंसिल, एनसीईआरटी आदि के सहयोग से सभी विषयों के लिए मॉडल प्रश्न पत्र तैयार करना।
- विषय संबंधी शिक्षक सीसीटी आधारित आइटम बैंक तैयार कर रहे हैं।

iii. शिक्षा में कौशल एकीकरणः

- विभिन्न स्तरों पर प्रत्येक बच्चे के लिए कौशल पाठ्यक्रमों का अवसर प्राप्त होना।
- मिडिल और माध्यमिक स्तर पर प्रत्येक में पांच कौशल विषयों का प्रावधान एवं वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर छात्रों की पसंद के अनुसार 12 कौशल विषयों का प्रावधान।
- इंटर्नशिप/विजिट के लिए ज.न.वि. के साथ स्थानीय उद्योगों को जोड़ना।
- ज.न.वि. में 235 कौशल केंद्र पहल स्थापित की गई हैं, जिसमें ज.न.वि. के आसपास शिक्षा से इतर महिला उम्मीदवारों के लिए 34 जॉब रोल्स हैं। कुल 3,919 महिला अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। दिनांक 5 जनवरी, 2024 तक 184 कौशल हब पहलों में मूल्यांकन पूरा हो चुका है।
- विभिन्न स्तरों पर कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य समकालीन कौशल पाठ्यक्रम शुरू किए गए।
- 25 जवाहर नवोदय विद्यालयों में ऑटोमोटिव स्किल लैब की स्थापना की जा रही हैं।

iv. भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति का संवर्धनः

- भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र अर्थात क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी।
- सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में त्रिभाषा सूत्र के एक भाग के रूप में 17 क्षेत्रीय भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं।
- एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षण, परीक्षण और मूल्यांकन पर सीआईआईएल मैसूर के सहयोग से सभी क्षेत्रीय भाषा शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाता है।
- क्षेत्रीय भाषा के मातृ राज्य से संबंधित कला और संस्कृति की 20% सामग्री को तीसरी भाषा के शिक्षण और मूल्यांकन में एकीकृत किया गया।

- क्षेत्रीय भाषाओं की कला एवं संस्कृति सामग्री द्विभाषी तैयार की जा रही है।

परीक्षा पे चर्चा: परीक्षा पे चर्चा का छठा संस्करण 27.01.2023 को आयोजित किया गया था, जिसका विवरण इस प्रकार है:

- जेएनवी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) और जेएनवी रुद्रप्रयाग (उत्तराखंड) के 2 छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा – 2023 में भाग लिया।
- 8 छात्रों ने कला और विज्ञान प्रदर्शनी में भाग लिया और माननीय प्रधान मंत्री के साथ संवाद किया।
- जेएनवी राजसमंद (राजस्थान) के 23 छात्रों ने तालकटोरा स्टेडियम में छठे परीक्षा पे चर्चा –2023 में सांस्कृतिक कार्यक्रम में भवई नृत्य का प्रदर्शन किया।
- जेएनवी के कुल 3,06,756 छात्रों और कर्मचारियों ने परीक्षा पे चर्चा 2023 का सीधा प्रसारण देखा।

अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड– 2023: सुश्री रिगज़िन ल्हामो, कक्षा दसवीं, जेएनवी लेह (लद्दाख) ने जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड – 2023 में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने पूरे भारत से 8 सदस्यों वाली एक टीम के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया और बेंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड–2023 में एक स्वर्ण और एक रजत पदक जीता।

सह–पाठ्यक्रम और तारतम्य–निर्धारण गतिविधियाँ:

शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के अतिरिक्त, नवोदय विद्यालयों का उद्देश्य अपने छात्रों को खेल और कला के माध्यम से आत्म–विकास और रचनात्मक अभिव्यक्ति के अवसर देना भी है। जवाहर नवोदय विद्यालयों में आयोजित इन गतिविधियों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- **राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता:** प्रत्येक क्षेत्र में अलग–अलग स्तरों पर खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं नामतः क्लस्टर प्रतियोगिता, क्षेत्रीय प्रतियोगिता और राष्ट्रीय प्रतियोगिता।
- **स्काउट्स और गाइड:** कुल 19,000 स्काउट्स एवं 19,013 गाइड्स एनवीएस के रोल पर हैं।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। 113 जनवि की एनएसएस इकाइयों के लिए कुल 9,876 छात्र नामांकित हैं।
- **राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी):** एनसीसी निदेशालय की सहायता से 356 जवाहर नवोदय विद्यालयों में एनसीसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और कुल नामांकित कैडेट्स की संख्या 24,566 है। अन्य जनवि के लिए भी प्रयास किये जा रहे हैं।
- **छात्र पुलिस कैडेट (एसपीसी):** भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार 125 जनवि में स्टूडेंट पुलिस कैडेट कार्यक्रम लागू किया गया है।
- **म्यूजियम कॉर्नर:** इस कार्यक्रम के तहत, जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र अपनी सांस्कृतिक विरासत की कल्पना कर सकते हैं और सार्वभौमिक मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं। सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में म्यूजियम कॉर्नर स्थापित किए गए हैं।
- **मल्टी–जिम:** इस कार्यक्रम में गतिविधियों का उद्देश्य फिटनेस और शारीरिक एवं स्नायु–पेशी कौशल विकसित करना है। 548 जनवि में मल्टी–जिम स्थापित किए गए हैं।
- **क्षेत्रीय विज्ञान सम्मेलन:** क्षेत्रीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन व्यापक गतिविधियों के साथ प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है ताकि ज.न.वि. के छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति को विकसित किया जा सके और वैज्ञानिक प्रतिभा को बढ़ावा दिया जा सके।

- **युवा संसदः** लोकतंत्र की जड़ों को सुदृढ़ करने, अनुशासन की अच्छी आदतों को विकसित करने, दूसरों के विचारों के प्रति सहिष्णुता और छात्र समुदाय को संसद और विधायिका के कामकाज के बारे में सक्षम बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय युवा संसद कार्यक्रम प्रतिवर्ष संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श से आयोजित किया जाता है। हर साल 80 जनवि युवा संसद प्रतियोगिता में भाग लेते हैं।
- **शिक्षा में कलाः** शिक्षा गतिविधियों में कला के हिस्से के रूप में स्वदेशी कला रूपों पर अतिरिक्त ध्यान देने के साथ समुदाय के पारंपरिक और समकालीन कलाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र से 20 जेएनवी (कुल 160 जेएनवी) एक वर्ष में कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं और उसके बाद क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की बैठकें आयोजित करते हैं।

वर्ष के दौरान की गई विशेष शैक्षणिक गतिविधियाँः

i. कैरियर के रूप में वैज्ञानिक अभिरुचि और विज्ञानः

- जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के लिए **क्लस्टर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी** का आयोजन।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों में विज्ञान ज्योति ज्ञान केन्द्रों का विस्तार।
- एनसीईआरटी के राष्ट्रीय बाल विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम में भागीदारी।
- होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, टीआईएफआर द्वारा कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों छात्रों के लिए आयोजित विज्ञान और गणित ओलंपियाड में भागीदारी।
- विद्यार्थी विज्ञान मंथन कार्यक्रम में भागीदारी।
- विद्यालयों में विज्ञान क्लबों का निर्माण।
- 20 जनवि में खगोल विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना।
- छात्रों द्वारा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का दौरा और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत।
- प्रत्येक वर्ष क्षेत्रवार आयोजित क्षेत्रीय विज्ञान कांग्रेस में 800 से अधिक बच्चे वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों में भाग लेते हैं।
- **भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के वैज्ञानिकों का जनवि का दौराः** बार्क वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने छात्रों में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक अभिरुचि और जागरूकता विकसित करने के लिए परमाणु ज्योति कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक सत्र 2022 – 23 और 2023–24 के दौरान पूरे देश में क्रमशः 111 और 48 जनवि का दौरा किया। इस दौरान वैज्ञानिकों/इंजीनियरों ने अनौपचारिक माहौल में छात्रों के साथ खुलकर बातचीत की, जिससे जनवि के बच्चों को प्रेरणा मिली और प्रतिभाशाली युवा छात्रों को परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बुनियादी जानकारी से अवगत कराया।
- जापान विज्ञान और प्रौद्योगिकी एजेंसी द्वारा सकुरा साइंस हाई स्कूल कार्यक्रम के तहत शैक्षणिक वर्ष 2022–23 के दौरान जापान में विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं के ऑनलाइन दौरों में 100 छात्रों ने भाग लिया।
- विज्ञान प्रतिभा में भागीदारीः विज्ञान प्रतिभा कार्यक्रम के तहत वैज्ञानिकों का विद्यार्थियों से सीधा संवाद।

ii. रचनात्मकता और नवाचार का संवर्धन:

- अटल टिंकरिंग लैब्स **(133 जनवि)** की स्थापना।
- इंटेल के सहयोग से जनवि पलवल (हरियाणा) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोगशाला की स्थापना।
- जनवि के शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एंबेसडर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लबों (जैसे इको–क्लब, खगोल विज्ञान, पर्यटन, विज्ञान, ललित कला, प्रदर्शन कला, भाषा/साहित्यिक क्लब आदि) का गठन और प्रत्येक छात्र को इन क्लबों से जोड़ा गया।

iii. समकालीन क्षेत्रों/विषयों से परिचय:

- एनएसई की सहायता से वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण।
- एनडीआरएफ के सहयोग से आपदा प्रबंधन।
- टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस–छत्तीसगढ़ के ज.न.वि. के प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों के सहयोग से समकालीन शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम को एमआईटी, यूएसए से तकनीकी सहायता प्राप्त है।

ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस:

- नियुक्तियों तक भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन और फेसलेस कर दिया गया है। नियुक्ति पत्र उम्मीदवारों द्वारा अपने लॉगिन पासवर्ड का उपयोग करके भी डाउनलोड किए जाते हैं।
- कक्षा –VI प्रवेश परीक्षा "जेएनवीएसटी" हेतु आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी की आवेदन प्रक्रिया तक बेहतर पहुंच हो सके। पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या 2014 में 18.80 लाख से बढ़कर जेएनवीएसटी–2024 में 25 लाख हो गई है। फेसलेस प्रवेश प्रक्रिया के परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता और कम से कम भ्रष्टाचार हुआ है।
- स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और प्रक्रिया समय पर पूरी हुई है।
- सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के जेएनवी में ऑनलाइन शिक्षण के लिए माइक्रोसॉफ्ट टीमों को लगाया गया है।
- एनवीएस मुख्यालय में ई–ऑफिस लागू किया गया है।
- केंद्रीकृत व्यक्तिगत सूचना प्रणाली (पीआईएस) विकसित की गई है जिसमें एनवीएस के सभी कर्मचारी पंजीकृत हैं और ऑनलाइन एपीएआर और संपत्ति घोषणा भर रहे हैं।
- एनवीएस पूर्व छात्रों के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने और पूर्व छात्रों को जेएनवी से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन "पूर्व छात्र पोर्टल" विकसित किया गया है। यह पोर्टल पूर्व छात्र निर्देशिका प्रदान करता है जिसके माध्यम से पूर्व छात्र एक–दूसरे से आसानी से जुड़ सकते हैं।
- एनवीएस ने अपना स्वयं का शिकायत निवारण तंत्र (एनवीएस–जीआरएम) विकसित किया है, जिसमें कर्मचारी और छात्रा/अभिभावक संबंधित प्रिंसिपल/क्षेत्रीय कार्यालय में त्वरित निपटान के लिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उद्यमिता कौशल:

- ज.न.वि. के छात्रों को व्यवसायपरक शिक्षा प्रदान की जाती है।

- ऑटोमोटिव स्किल लैब्सः टाटा मोटर्स लिमिटेड (टीएमएल) के सीएसआर सहयोग के तहत 25 जनवि में ऑटोमोटिव स्किल लैब स्थापित की जा रही हैं।
- कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य समकालीन कौशल पाठ्यक्रम विभिन्न स्तरों पर शुरू किए गए हैं।

अधिगम अनुभवों में वृद्धिः

- विषय–केंद्रित और परियोजना–आधारित क्लबों (जैसे इको–क्लब, खगोल विज्ञान, पर्यटन, विज्ञान, ललित कला, प्रदर्शन कला, भाषा/साहित्यिक क्लब आदि) का गठन और प्रत्येक छात्र को इन क्लबों से जोड़ा गया।
- जनवि में मुक्त शैक्षिक पार्क खोलनाः अनुभवात्मक और व्यावहारिक अधिगम को बढ़ावा देने और छात्रों में वैचारिक समझ विकसित करने के लिए, जेएनवी में 449 मुक्त शैक्षिक पार्क (गणित – 192, विज्ञान – 175 और सामाजिक विज्ञान – 82) स्थापित किए गए हैं, जिनमें गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान अवधारणाओं के साथ–साथ बुनियादी सिद्धांतों को प्रदर्शित करने वाली हर मौसम के लिए उपयुक्त प्रदर्शनियां लगाई गई हैं।
- कला और व्यावसायिक शिल्प से जुड़ी विभिन्न प्रकार की संवर्धन गतिविधियों के लिए अकादमिक योजना के माध्यम से एक वर्ष में 10 बैगलेस दिन शामिल किए गए हैं।
- ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन महत्व के स्थानों/स्मारकों का दौरा, स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों से मिलना और उच्च शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करके स्कूल के बाहर की गतिविधियों का अनुभव।

समावेशी शिक्षाः

- दिनांक 30.11.2023 तक ज.न.वि. में 3085 (1.08%) दिव्यांग (सीडब्ल्यूएसएन) छात्र नामांकित हैं।
- नाट्य विद्यालयों के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
- एनवीएस में विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों के लिए खेल प्रतिभा खोज शिविर एवं खेलकूद प्रतियोगिता, राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।

मूल्य अभिविन्यासः

सभी कार्यात्मक ज.न.वि. में शिक्षकों और छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन की सहायता से जागृत नागरिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आरआईएमएसई मैसूर में अधिकारियों/प्रधानाचार्यों/उपप्रधानाचार्यों के लिए मूल्य शिक्षा में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

- जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्र डिजिटल नागरिकता और साइबर वेलनेस क्विज में भाग लेते हैं।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों में योग सत्र आयोजित किए जाते हैं।

मार्गदर्शन और परामर्शः

- मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक जवाहर नवोदय विद्यालय में अनुबंध के आधार पर दो योग्य परामर्शदाताओं (एक पुरुष और एक महिला) का प्रावधान।
- क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, एनसीईआरटी के 01 वर्षीय मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम हेतु शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है। 2023 तक 476 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर के माध्यम से मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।
- एनवीएस टोल–फ्री नंबर 1800–180–7992 के माध्यम से छात्रों और अभिभावकों को परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

समाज में योगदान:

- जवाहर नवोदय विद्यालयों की सह–पाठ्यचर्या गतिविधियों में पड़ोसी विद्यालयों के छात्रों की भागीदारी।
- जनवि में प्रकृति संरक्षण, सड़क सुरक्षा, प्राथमिक चिकित्सा, स्वच्छता, नागरिक भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों एवं वैज्ञानिक अभिरुचि जैसे मुद्दों संबंधी जागरूकता हेतु पड़ोसी स्कूलों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत अन्य स्कूलों की छात्राओं को जनवि में प्रशिक्षित किया जाता है।
- पड़ोस के स्कूलों के साथ शैक्षणिक और सह–पाठ्यचर्या संबंधी प्रतियोगिताओं में भागीदारी और आयोजन।
- जनवि चयन परीक्षा की तैयारी के लिए ग्रामीण बच्चों को कोचिंग प्रदान की जाती है।
- जनवि में टीकाकरण शिविर, स्वास्थ्य जांच शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर, प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छता अभियान और साक्षरता अभियान आदि आयोजित किए जाते हैं।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों द्वारा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, जनसंख्या शिक्षा और संतुलित आहार संबंधी जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं।

स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा:

- प्रवेश स्तर पर छात्रों की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच की जाती है।
- छात्रों के उचित शारीरिक विकास की निगरानी के लिए एक शैक्षणिक सत्र में दो बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है।
- छात्रों के स्वास्थ्य एवं कल्याण हेतु प्रत्येक जनवि में एक स्टाफ नर्स उपलब्ध है।
- नियमित रूप से जेएनवी का दौरा करने और बीमार छात्रों को चिकित्सा सलाह प्रदान करने के लिए प्रत्येक जेएनवी द्वारा एक योग्य चिकित्सक को मानदेय के आधार पर नियोजित किया जाता है।
- प्रत्येक जनवि में बुनियादी दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता के साथ एक चिकित्सा निरीक्षण कक्ष है।
- हाउस मास्टर्स और एसोसिएट हाउस मास्टर्स के मार्गदर्शन और देखरेख में छात्राओं की देखभाल के लिए संविदा के आधार पर मैट्रन को नियोजित किया गया है।
- मल्टीटास्किंग स्टाफ का उपयोग लड़कों के छात्रावास के लिए केयरटेकर के रूप में किया जा रहा है। वे हाउस मास्टर्स और एसोसिएट हाउस मास्टर्स की देखरेख में कार्यवाहक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।
- साफ–सफाई और स्वच्छता की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक जनवि में आउटसोसिंग के माध्यम से एक पुरुष और एक महिला सफाई कर्मचारी को नियोजित किया गया है।
- सुबह के समय क्रमावर्ती आधार पर योग कार्यक्रम अनिवार्य है।
- शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से योग में प्रशिक्षित किया गया है।
- जनवि के सामान्य क्षेत्रों/संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।
- सैनिटरी पैड/नैपकिन के उचित निपटान के लिए भस्मक उपलब्ध कराए गए हैं।
- पूरे जनवि परिसर में चौबीस घंटे निगरानी रखने के लिए जनवि में 06 सुरक्षा कर्मी नियोजित किए जाते हैं।
- छात्रों के लिए प्रतिदिन कम से कम एक समय

भोजन में श्री अन्न आधारित व्यंजनों को शामिल करने का निर्देश जनवि को दिया गया है।

- एनवीएस द्वारा 609 जनवि में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए रैंप और शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं।

सेनेटरी नैपकिन बनाने की पहलः

वर्ष 2022 के दौरान, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दो चिन्हित जवाहर नवोदय विद्यालयों में सैनिटरी नैपकिन बनाने की इकाई स्थापित की गई। परियोजना की सफलता को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 2023 के दौरान 15 और ज.न.वि. में सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली इकाइयां स्थापित की गई हैं।

छात्राओं के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग परियोजनाः

नवोदय विद्यालय समिति ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के सहयोग से 250 जवाहर नवोदय विद्यालयों में विज्ञान ज्योति ज्ञान केंद्रों की स्थापना की है जिसका उद्देश्य अधिक संख्या में छात्राओं को विज्ञान को अपने कैरियर के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस कार्यक्रम के तहत, एसटीईएम, भविष्य के संभावित और कैरियर परामर्श में केंद्रित सहायता देने के उद्देश्य से जवाहर नवोदय विद्यालय और पड़ोसी क्षेत्र में स्कूल प्रणालियों की नौवीं से बारहवीं कक्षा की छात्राओं को सहायता प्रदान की जाती है। डीएसटी के तहत कक्षा–9 की कुल 50 लड़कियों और कक्षा–11 की 50 लड़कियों के पंजीकरण का अधिदेश है। एसटीईएम में व्याख्यान की श्रृंखला, विशेष आवश्यकता आधारित कक्षाएं, विज्ञान में महिलाओं के रोल मॉडल के साथ छात्र इंटरफ़ेस, प्रयोगशाला कार्य, छोटी परियोजनाएं, अनुसंधान एवं विकास (आर एंड डी) प्रयोगशालाओं का दौरा, वैज्ञानिकों के साथ लगातार बातचीत, अभिभावक परामर्श आदि इस कार्यक्रम के तहत शामिल हैं। कवर किए गए छात्राओं को मासिक वजीफा सहित सहायता प्रणाली की पूरी लागत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत वर्तमान सत्र तक कुल 24,000 छात्राओं का पंजीकरण किया गया है।

अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम):

नीति आयोग का प्रमुख कार्यक्रम, अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) नवाचार और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। इसका उद्देश्य विश्व स्तर के नवाचार हब, बड़ी चुनौतियों, स्टार्ट–अप व्यवसायों और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में विशेष रूप से प्रौद्योगिकी संचालित क्षेत्रों में कार्य करना है।

एआईएम ने 133 जवाहर नवोदय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) की स्थापना की है. इस योजना का उद्देश्य युवा मन में जिज्ञासा, रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देना; और तैयार किए गए माइंड सेट, कम्प्यूटेशनल थिंकिंग, अनुकूली शिक्षा, शारीरिक कंप्यूटिंग आदि जैसे कौशल विकसित करना है। अटल टिंकरिंग लैब्स (एटीएल) एक ऐसा कार्यक्षेत्र है जहां युवा दिमाग 'डू–इट–योरसेल्फ' मोड पर हाथों के माध्यम से अपने विचारों को आकार दे सकते हैं और नवाचार कौशल सीख सकते हैं/विकसित कर सकते हैं।

इंस्पायर मानक पुरस्कारः

02 न.वि.सं. छात्रों मास्टर विश्वास गौड़ा, जेएनवी हसन (कर्नाटक) और केयू लालमिंगसंगी, जेएनवी चंपाई (मिजोरम),की परियोजनाओं को इंस्पायर मानक अवार्ड के तहत राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता (एनएलईपीसी)– 2023 के दौरान सम्मानित 60 परियोजनाओं में से चुना गया था।

शैक्षणिक प्रोत्साहनः

- राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों की सिफारिश की जाती है।

- श्री रवि कांत मिश्रा, पीजीटी रसायन विज्ञान, ज.न.वि. दतिया (मध्य प्रदेश) को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया।
- निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने वाले शिक्षकों को योग्यता प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं।

फिट इंडिया गतिविधियां:

युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार मार्च 2021 से फिट इंडिया कार्यक्रमों के तहत जवाहर नवोदय विद्यालयों में माहवार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।

- **फिट इंडिया क्विज** – राज्य स्तरीय फाइनल: एनवीएस की 14 टीमें (16 छात्र) फिट इंडिया क्विज 2022 के स्टेट राउंड के लिए चुनी गईं।
- **खेलो इंडिया:** भारतीय खेल प्राधिकरण, युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार ने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल के 3 ज.न.वि. को स्वीकृति दी है। खेलो इंडिया केन्द्रों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में कुल 13 जवाहर नवोदय विद्यालयों का चयन किया गया है।

खेल और क्रीड़ा:

- जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों के लिए प्रतिदिन सुबह अनिवार्य शारीरिक प्रशिक्षण (पीटी) और शाम को 1 घंटा 45 मिनट के लिए खेलकूद आयोजित किए जाते हैं।
- एक वर्ष में दो बार सभी छात्रों का शारीरिक मूल्यांकन।
- एसजीएफआई के स्तर तक क्लस्टर, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं।
- जवाहर नवोदय विद्यालय, करनाल (हरियाणा) और वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में खेलों के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) स्थापित किए गए हैं।

पैरा खेलों में सीडब्ल्यूएसएन की उपलब्धियां:

जवाहर नवोदय विद्यालय, रंगारेड्डी जिले को बोडिंग और लॉजिंग और उनके प्रशिक्षण और अभ्यास के मामले में छात्रों को रसद सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र के रूप में निर्धारित गया है। इस पहल का दृष्टिकोण दिव्याङ्ग छात्रों के लिए एक उज्ज्वल खेल कैरियर देखना और उनके आत्मविश्वास का निर्माण करना है। निम्नलिखित छात्रों ने शैक्षणिक सत्र 2023–2024 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लिया है:

1. **राइफल में राष्ट्रीय पैरा–शूटिंग चयन परीक्षण 4 वें और 5 वें:**

   सुश्री खुशबू, कक्षा आठवीं, जवाहर नवोदय विद्यालय मेरठ (उत्तर प्रदेश) ने 10 मीटर की खिताबी निशानेबाजी में भाग लिया और उन्होंने चौथे ट्रायल में दूसरा स्थान और 622.50 अंक हासिल किए। 5 वें परीक्षण में उसने 622.70 स्कोर के साथ प्रथम रैंक हासिल की।

2. **चौथी जोनल पैरा–शूटिंग चैंपियनशिप (मिश्रित श्रेणी):**

   यह कार्यक्रम 13 और 14 सितंबर 2023 को डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। सीडब्ल्यूएसएन के छात्र बनोथ पवानी, कक्षा XI, ज.न.वि. खम्मम (तेलंगाना) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और 354/400 के स्कोर के साथ मिश्रित श्रेणी में तीसरा स्थान हासिल किया।

3. जेएनवी खम्मम (तेलंगाना) की छात्र सुश्री बनोथ पावनी ने भी पैरा खेलों में (मिश्रित श्रेणी पुरुष और महिला) में भाग लिया और डॉ. कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर, 2023 तक आयोजित चौथी जोनल पैरा निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता।

4. **यूपी पैरा स्टेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 दिनांक 24.09.2023 को कानपुर में आयोजित की गई:** मास्टर समीर चौधरी ने दूसरा स्थान प्राप्त किया और मास्टर उमर मोहम्मद ने ओपन कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया।

5. **अखिल भारतीय प्रथम विश्व बधिर युवा चयन परीक्षण:** यह आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण, बैंगलोर द्वारा 7 और 8 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित किया गया था। भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है:
   - सुश्री हर्षा जी.बी., कक्षा VIII, बैडमिंटन में।
   - सुश्री नंदिनी पी.वी., कक्षा IX, बैडमिंटन में।
   - सुश्री कृष्णा कुमारी, कक्षा VIII, एथलेटिक्स में ।
   - श्री सूर्यांश, कक्षा IX टेबल टेनिस में।

6. **वर्ल्ड एबिलिटी स्पोर्ट गेम्स 2023, नखोन रत्चासिमा, थाईलैंड:** यह कार्यक्रम 1 से 8 दिसंबर, 2023 तक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। जवाहर नवोदय विद्यालयों के 5 सीडब्ल्यूएसएन छात्रों की भागीदारी का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	छात्र का नाम	कक्षा	कार्यक्रम	उपलब्धि
1.	सुश्री खुशबू	VIII	निशानेबाजी	रजत पदक
2.	सुश्री ज्योति	IX	1. डिस्कस थ्रो 2. जेवलिन थ्रो • शॉटपुट	1. कांस्य पदक 2. रजत पदक • कांस्य पदक
3.	सुश्री एच. यू. शिवानी	IX	1. जेवलिन थ्रो • शॉटपुट	1. स्वर्ण पदक • स्वर्ण पदक
4.	श्री जानू रावत	X	जेवलिन थ्रो	कांस्य पदक
5.	श्री शिव तेवतिया	X	1. शॉटपुट • जेवलिन थ्रो	1. रजत पदक • स्वर्ण पदक

छात्रों पर खर्च:

जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों के भोजन और आवास पर सभी खर्चों के साथ–साथ वर्दी, स्टेशनरी आदि पर केंद्र सरकार द्वारा खर्च वहन किया जाता है। दिनांक 01.04.2023 से प्रति वर्ष प्रति छात्र संशोधित/लागू दरें निम्नानुसार हैं:

श्रेणियाँ	कठिन और जटिल क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में स्थित ज.न.वि.	कठिन और जटिल क्षेत्रों में स्थित ज.न.वि.	जेएनवी* अत्यधिक कठिन और जटिल क्षेत्रों में स्थित
क. भोजनालय व्यय (प्रति छात्रा प्रति माह)	रु. 2,134	रु. 2,425	रु. 2,545
ख. वर्दी (प्रति वर्ष)	रु. 2,640	रु. 3,300	रु. 3,696
ग. अन्य व्यय (प्रति वर्ष)	रु. 3,480	रु. 3,480	रु. 3,480
घ. स्कूल बैग	रु. 396	रु. 396	रु. 396
ङ. यात्रा व्यय (9 महीने)	रु. 234	रु. 234	रु. 234
च. दैनिक भत्ता (प्रति दिन)	रु. 330	रु. 330	रु. 330

** 11 ज.न.वि. अर्थात् कारगिल, लेह, लाहौल और स्पीति, कार निकोबार, उत्तर और मध्य अंडमान, मिनिकॉय (लक्षद्वीप), तवांग, अंजाव, दिबांग घाटी, जैसलमेर और कच्छ अत्यधिक कठिन और कठिन क्षेत्रों में स्थित हैं।*

जवाहर नवोदय विद्यालयों भवनों का निर्माण:

जवाहर नवोदय विद्यालय के स्कूल भवन का निर्माण 03 चरणों में किया जाता है। इन सुविधाओं में स्कूल भवन, शयनगृह, स्टाफ क्वार्टर, रसोईघर और भोजन कक्ष, चारदीवारी, खेल के मैदानों का विकास और आंतरिक सड़कों, विद्युतीकरण आदि जैसे अन्य विकास कार्य शामिल हैं। निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी)/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू)/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (एसपीएसयू) आदि को सौंपा गया है।

इस समय 609 जवाहर नवोदय विद्यालयों को उनके स्थायी भवनों/परिसरों में स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य 41 जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। अस्थायी परिसर से चल रहे 41 जवाहर नवोदय विद्यालयों के निर्माण की वर्तमान स्थिति:

- प्रगति > 50% : 09
- 50% तक प्रगति : 21
- निविदा कार्य के तहत : 07
- डीपीआर तैयारी करने के तहत : 01
- हस्तांतरण के तहत भूमि : 03

वर्ष 2023 के दौरान निर्माण गतिविधियों का विवरण:

- 12 जवाहर नवोदय विद्यालयों को उनके स्थायी भवन/स्थल पर स्थानांतरित कर दिया गया है।
- 07 जवाहर नवोदय विद्यालयों का निर्माण कार्य (चरण–क) पूरा कर लिया गया है।
- 46 जवाहर नवोदय विद्यालयों में आवर्धन कार्य पूरा कर लिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण:

1) **जल संरक्षण:** संस्थागत योजना के स्तर पर नवोदय विद्यालय समिति की जल संरक्षण योजना का आरंभ और प्रयोग किए गए जल का दूसरे विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग करना सराहनीय रहा है। ज.न.वि. गति निर्धारक संस्थान होने के कारण हमेशा पर्यावरण अनुकूल पहलों के प्रति ग्रहणशील और सक्रिय रहे हैं। देश भर में जवाहर नवोदय विद्यालयों की अवस्थिति और छात्र संख्या को ध्यान में रखते हुए, जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान के तहत विभिन्न कार्य प्रस्तावित हैं। 145 जवाहर नवोदय विद्यालयों ने वर्षा जल संचयन के लिए कदम उठाए हैं। प्रति जवाहर

नवोदय विद्यालय में वार्षिक औसत जल की बचत 50,000 लीटर है और कुल वार्षिक जल बचत लगभग 6.4 मिलियन लीटर होने की आशा है। इसके अलावा जवाहर नवोदय विद्यालयों में समग्र शिक्षा, जल सुरक्षा अभियान भी शुरू किया गया है। इको–क्लबों के माध्यम से छात्रों और अन्य हितधारकों के बीच जागरूकता लाई जा रही है और उनके सुझावों को समय की आवश्यकता पर विचार करते हुए सभी ज.न.वि. में अभ्यास किया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर दिन प्रत्येक छात्र द्वारा कम से कम एक लीटर जल बचाने का लक्ष्य है।

2) **अपशिष्ट जल का पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग:** पर्यावरण के अनुकूल उपचार प्रणाली के माध्यम से जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर में अपशिष्ट जल का पुनर्नवीनीकरण और पुनः उपयोग 10 जवाहर नवोदय विद्यालयों में लागू किया गया है और 20 अन्य जवाहर नवोदय विद्यालयों में कार्य प्रगति पर है। पानी की वार्षिक बचत लगभग 42 मिलियन लीटर होने की आशा है।

3) **वृक्षारोपण:** जवाहर नवोदय विद्यालय विशेष रूप से बरसात के मौसम के दौरान जवाहर नवोदय विद्यालय परिसरों में और उसके आसपास वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान लगाए गए वृक्षों की संख्या निम्नानुसार है:

शैक्षणिक सत्र	लगाए गए पौधों की संख्या
2016 – 2017	3,18,647
2017 – 2018	4,41,867
2018 – 2019	2,25,827
2019 – 2020	2,39,755
2022 – 2023	1,23,062

सत्र 2020–21 और 2021–2022 के दौरान, कोविड–19 प्रतिबंधों के कारण वृक्षारोपण अभियान नहीं चलाया जा सका।

4. **हाउस किचन गार्डन:** जवाहर नवोदय विद्यालयों में हाउस किचन गार्डन विकसित किए जा रहे हैं जहां छात्र स्वयं को शिक्षकों के मार्गदर्शन में विभिन्न गतिविधियों जैसे स्थानीय रूप से उपलब्ध सब्जी पैंट के पौधे लगाना, पानी देना, छंटाई करना, मिट्टी की जुताई करना आदि में संलग्न करते हैं ।

5. **सौर पहल:** एमएनआरई के निर्देशन में रूफ टॉप ग्रिड कनेक्शन सौर ऊर्जा परियोजना 12.07 मेगावाट के समग्र बिजली उत्पादन के साथ 169 जवाहर नवोदय विद्यालयों में लागू की गई है।

6. भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के सहयोग से पर्यावरण आधारित शिक्षा का आयोजन किया गया है।

7. जवाहर नवोदय विद्यालय विज्ञान और पर्यावरण केंद्र(सीएसई) की पहल में भाग ले रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप छात्रों में प्रकृति और संसाधनों के संरक्षण के बारे में बेहतर जागरूकता उत्पन्न हो रही है।

8. पारंपरिक सेप्टिक टैंक के स्थान पर 2018 में इको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) प्रस्तुत किया गया है।

9. सभी जवाहर नवोदय विद्यालयों में एलईडी लाइट का उपयोग किया जा रहा है।

10. भारत वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के सहयोग से जवाहर नवोदय विद्यालयों में पर्यावरण आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है।

11. जवाहर नवोदय विद्यालय विज्ञान और पर्यावरण केंद्र(सीएसई) की पहल में भाग ले रहे हैं, जिसके

परिणामस्वरूप छात्रों में प्रकृति और संसाधनों के संरक्षण के बारे में बेहतर जागरूकता उत्पन्न हो रही है।

12. जवाहर नवोदय विद्यालयों को मौजूदा पर्यावरण अनुकूल मानदंडों के आधार पर रेटिंग दिलाने की पहल चरणबद्ध तरीके से की गई है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी):

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) भारत सरकार द्वारा वर्ष 1961 में स्थापित एक शीर्ष संगठन है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से स्कूल शिक्षा और शिक्षक शिक्षा में केंद्र और राज्य सरकारों को उनकी नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन में सहायता और सलाह दे सकें। यह स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अकादमिक और तकनीकी सहायता प्रदान करता है और शैक्षिक अनुसंधान, विकास, प्रशिक्षण, विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, प्रकाशन और प्रसार से संबंधित कार्यक्रम भी कार्यान्वित करता है।

1. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के शुभारंभ के बाद, परिषद को चार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा के विकास का काम सौंपा गया है, जिसमें स्कूल शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, और वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा शामिल है। एनसीईआरटी ने नीचे से ऊपर का दृष्टिकोण अपनाकर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से इनपुट प्राप्त करके और 25 क्षेत्रों में लक्षित समूहों के स्थिति पत्र तैयार करके चार एनसीएफ विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की। एनसीएफ टेक प्लेटफॉर्म को 13 दिसंबर 2021 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाइव कर दिया गया था। प्रारम्भिक स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 20 नवंबर 2022 को शुरू किया गया है और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा (एनसीएफ–एसई) 23 अगस्त 2023 को जारी की गई है। अध्यापक शिक्षा तथा प्रौढ़ एवं वयस्क शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे का विकास प्रक्रियाधीन है। एनसीईआरटी ने एससीईआरटी, डीआईईटी आदि में इसका प्रसार शुरू कर दिया है। नई पीढ़ी की पाठ्यपुस्तकों को एनईपी–2020 और एनसीएफ–एफएस 2022 के आधार पर विकसित किया गया है। सभी संबंधित विषयों में कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें; हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और गणित में 4 जुलाई 2023 को जारी की गयी हैं। विषय क्षेत्रों में कक्षा 3–12 के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों के विकास हेतु, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ओवर साइट कमेटी (एनओसी) और नेशनल सिलेबस एंड टीचिंग–लर्निंग मटेरियल कमेटी (एनएसटीसी) का गठन किया गया है। एनएसटीसी के तहत, विज्ञान, गणित, व्यावसायिक शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणालियों, सामाजिक विज्ञान, कला शिक्षा, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, कल्याण, शारीरिक शिक्षा और खेलकूद, नवाचारी शिक्षाशास्त्र और टीएलएम के क्षेत्रों में पाठ्यचर्या क्षेत्र समूह गठित किए गए हैं जो पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

2. परख

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र– परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण एनसीईआरटी में एनसीईआरटी की एक स्वतंत्र घटक इकाई के रूप में स्थापित किया गया था ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के पैरा 4.4.1 द्वारा अनिवार्य अन्य कार्यों के साथ छात्र मूल्यांकन से संबंधित मानदंडों, मानकों, दिशानिर्देशों को स्थापित करने और गतिविधियों को लागू करने के बुनियादी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। परख के के तीन प्रमुख क्षेत्र हैं:

1. समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन
2. बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण
3. स्कूल बोर्डों की समानता

राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, परख के तहत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की गई हैं।

(i) समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित मूल्यांकन

- **बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड का विकास और प्रसार**

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण की विशेषता है कि यह अधिगम और आकलन के पारंपरिक ज्ञान अधिग्रहण मॉडल से हटकर योग्यता आधारित शिक्षा और मूल्यांकन की ओर अग्रसर है। आकलन अब रटकर सीखने से नहीं बल्कि अधिगम की प्रक्रिया के माध्यम से हासिल की गई दक्षताओं के समग्र मूल्यांकन की विशेषता है। 360—डिग्री समग्र प्रगति कार्ड विकसित किए गए हैं ताकि मूल्यांकन को प्रकृति में अधिक व्यापक और समग्र बनाकर योग्यता—आधारित अधिगम—शिक्षण के मूल्यांकन में सहायता मिल सके।

परख ने बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों के लिए समग्र प्रगति कार्ड (एचपीसी) का विकास पूरा कर लिया है। वर्तमान में, योग्यता आधारित और समग्र मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए माध्यमिक चरण के लिए एचपीसी विकसित करने के प्रयास चल रहे हैं। ये एचपीसी व्यापक दस्तावेज हैं जो न केवल छात्र की शैक्षणिक उपलब्धियों की निगरानी करते हैं बल्कि उनके सामाजिक—भावनात्मक विकास और रचनात्मकता को भी शामिल करते हैं।

इसके अलावा, परख राष्ट्रीय/राज्य और जिला स्तर पर हितधारकों/कार्यकर्ताओं के साथ कार्यशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों के लिए एचपीसी के प्रसार पर काम कर रहा है।

- **परियोजना विद्यासागर**

पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स (पीएचडीसीसी) के सहयोग से परख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 (एनसीएफ, 2023) के अनुसार बुनियादी, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक स्तरों पर अधिगम की दक्षताओं के प्रसार के लिए भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यशालाओं की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य शिक्षक—प्रशिक्षकों और शिक्षकों को शैक्षणिक और नीतिगत परिवर्तनों से परिचित कराना है जो एनसीएफ 2023 के साथ प्रस्तुत किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योग्यता—आधारित अधिगम—शिक्षण के कार्यान्वयन में अंतराल को कम किया जा सके। श्रृंखला में तीन कार्यशालाएं पहले ही जम्मू—कश्मीर, पटना और गुजरात में आयोजित की जा चुकी हैं।

(ii) बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण

परख को देश के उपलब्धि स्तर की आवधिक निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए बड़े पैमाने पर उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अधिदेश के एक हिस्से के रूप में, ग्रेड 3, 6 और 9 के शिक्षार्थियों का आकलन करते हुए मूल्यांकन की इकाइयों के रूप में शैक्षिक ब्लॉकों के साथ बुनियादी, प्रारंभिक और मध्य चरणों के अंत में मूलभूत साक्षरता, मूलभूत संख्यात्मकता, भाषा और गणित में दक्षताओं का आकलन करने के लिए परख ने 3 नवंबर, 2023 को राज्य शैक्षिक

उपलब्धि सर्वेक्षण आयोजित करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ काम किया। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित, मूल्यांकन में 8 मिलियन शिक्षार्थियों का अनुमानित नमूना शामिल था।

राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023

राज्य शैक्षिक उपलब्धि सर्वेक्षण 2023 का आयोजन भाषा और गणित में कक्षा 3, 6 और 9 में प्रत्येक चरण (आधारभूत, प्रारंभिक और मध्य) के अंत में ब्लॉक स्तर पर छात्र की उपलब्धि के लिए सीखने की दक्षताओं का मानचित्रण करने, शैक्षिक परिणामों को प्रभावित करने वाले कारकों को समझने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से पृष्ठभूमि डेटा एकत्र करने के लिए भविष्य के सर्वेक्षणों के साथ मूल्यांकन परिणामों की वैद्यता एवं उपयुक्तता सुनिश्चित करने, साक्ष्य–आधारित निर्णय लेने के लिए शैक्षिक नीति निर्माताओं को सुझाव देने और "दक्षता आधारित मूल्यांकन" में प्रत्येक चरण (प्रारंभिक, आधारभूत और मध्य) के अंत में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्यों के साथ किया गया था।

(iii) स्कूल बोर्डों की समतुल्यता

परख परीक्षा सुधारों से संबंधित सिफारिशें करने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्डों के साथ काम कर रहा है। एक बार जब भारत के सभी बोर्डों में समानता आ जाएगी, तो सभी प्रकार की शिक्षा के लिए क्रेडिट अंक आवंटित करना संभव हो जाएगा, चाहे वह शैक्षणिक, व्यावसायिक या अनुभवात्मक हो।

समतुल्यता लाने हेतु परख ने जून और अगस्त 2023 के बीच क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की हैं। इन कार्यशालाओं में, प्रशासन, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन और बुनियादी ढाँचे के क्षेत्रों में बोर्डों से डेटा एकत्र किया गया है। डेटा एकत्र करने के लिए, दो उपकरणों का उपयोग किया गया, अर्थात्, समतुल्यता प्रश्नावली और प्रश्न पत्र टेम्पलेट विश्लेषण। एकत्रित डेटा का विश्लेषण करने के बाद, समतुल्यता प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट तैयार की गई। नवंबर और दिसंबर 2023 के महीनों में सभी बोर्डों को शामिल करके रिपोर्ट साझा करने और उस पर प्रासंगिक सुझाव और टिप्पणियाँ देने के लिए दो राष्ट्रीय–स्तरीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इस तरह के विचार–विमर्श के बाद, समतुल्यता के लिए नीतिगत सिफारिशों का मसौदा तैयार किया जा रहा है।

3. मनोदर्पण

मनोदर्पण "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के हिस्से के रूप में शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को कोविड–19 और उसके बाद के समय में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। इसका उद्घाटन 21 जुलाई, 2020 को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा किया गया था। इस पहल के तहत, शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट (https://manodarpan.education.gov.in/) पर एक वेबपेज बनाया गया था और छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक मुद्दों के समाधान के लिए टेली–काउंसलिंग प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय टोल–फ्री हेल्पलाइन (8448440632) स्थापित की गई थी। मनोदर्पण पहल के तहत परिकल्पित कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनसीईआरटी में

मनोदर्पण सेल की स्थापना की गई थी, जिसमें एमओई द्वारा गठित कार्य समूह के सदस्य और एनसीईआरटी के संकाय सदस्य शामिल थे।

शैक्षणिक संस्थानों और हितधारकों के सहयोग से विकसित उम्मीद दिशानिर्देशों का उद्देश्य स्कूल जाने वाले बच्चों में आत्महत्या को रोकना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इन दिशा–निर्देशों को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए खुला रखा गया था। इसमें आत्महत्या को समझना, मिथकों को दूर करना, जोखिम और सुरक्षात्मक कारकों की पहचान करना, चेतावनी के संकेतों को पहचानना और स्कूल स्तर पर एक व्यापक रोकथाम योजना को लागू करना जैसे विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों, अभिभावकों और समुदाय को शामिल करते हुए एक समग्र दृष्टिकोण पर जोर देते हुए, ये दिशा–निर्देश स्कूलों में एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को अधिक दूर करने के लिए, सोमवार से शुक्रवार तक 'सहयोग' सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिसमें कक्षा VI–XII के छात्रों के लिए अभ्यास करने वाले परामर्शदाताओं के साथ लाइव बातचीत की सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, शुक्रवार को 'परिचर्चा' वेबिनार में मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर चर्चा करने वाले विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें पीएम ई–विद्या चैनलों और 'एनसीईआरटी सरकारी' यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाता है। अप्रैल और सितंबर 2023 के बीच, 126 सहयोग और 26 परिचर्चा सत्रों ने स्कूल शिक्षा में हितधारकों के लिए मूल्यवान संसाधन प्रदान किए।

जुलाई 2020 में शुरू की गई मनोदर्पण टेली–काउंसलिंग हेल्पलाइन (8448440632) छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक–सामाजिक सहायता प्रदान करना जारी रखती है। अगस्त 2023 में शुरू किए गए अपने पांचवें चक्र में, 80 प्रशिक्षित परामर्शदाता स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करते हैं, जो पूरे सप्ताह सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक निरंतर सहायता सुनिश्चित करते हैं। क्षेत्र और भाषा प्राथमिकताओं के आधार पर चुने गए परामर्शदाताओं को आईवीआरएस के माध्यम से टेली–काउंसलिंग के लिए उन्मुख किया गया था।

शिक्षक कल्याण के क्षेत्र में, सितंबर से अक्टूबर 2023 तक शिक्षक कल्याण सर्वेक्षण आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य देश के सभी शैक्षणिक चरणों और क्षेत्रों में स्कूली शिक्षकों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को समझना था। 71,635 शिक्षकों के प्रतिभागी पूल के साथ, शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से साझा किए गए गूगल फ़ॉर्म के माध्यम से डेटा संग्रह किया गया था। वर्तमान में, एकत्रित डेटा का विश्लेषण चल रहा है, जो शिक्षा क्षेत्र में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए एक व्यापक प्रयास को दर्शाता है।

4. डिजिटल शिक्षा

i. **दीक्षा:** दीक्षा (नॉलेज शेयरिंग के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर) स्कूल शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय मंच है, जो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के तत्वावधान में एनसीईआरटी की एक पहल है। वर्ष 2017 में शुरू की गई दीक्षा को सीबीएसई और एनआईओएस सहित लगभग सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय स्वायत्त निकायों/बोर्डों द्वारा अपनाया गया है। देश भर में शिक्षार्थी और शिक्षक दीक्षा का उपयोग कर सकते हैं, और यह वर्तमान में 38 भाषाओं की सहायता करता है। दीक्षा पर कुल 532+ करोड़ शिक्षण सत्र देखे गए, जो 6,226+ करोड़ मिनट की पूर्ण शिक्षा के अनुरूप है। दीक्षा पर देखे गए पेज हिट की कुल संख्या (पिछले वित्त वर्ष के दौरान) 200+ करोड़ थी और पिछले वर्ष औसत पेज हिट 1.23+ करोड़ थी। दीक्षा ने जनवरी 2024 की स्थिति के अनुसार, 495 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों और ईटीबी सहित क्यूआर कोड के साथ सक्रिय 6,780 से अधिक पाठ्यपुस्तकों की मेजबानी की। दीक्षा पर

3,50,547 से ज़्यादा डिजिटल सामग्री उपलब्ध थी, जिसमें ऑडियो–विजुअल सामग्री, पठन और अभ्यास सामग्री, इंटरैक्टिव संसाधन और पाठ योजनाएँ शामिल थीं। ये ई–सामग्री 38 भाषाओं में उपलब्ध थी। शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में सहायता के लिए डिजिटल सामग्री के लिए, एनसीईआरटी/सीबीएसई/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विभिन्न सामग्री संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यादान के अंतर्गत सीएसआर के तहत स्कूलों/व्यक्तिगत शिक्षकों, सामग्री साझेदारों, गैर सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट्स द्वारा विविध संसाधनों का एक समृद्ध भंडार उपलब्ध कराया गया। वर्तमान में विद्यादान के तहत 2,43,253 से अधिक सामग्री का योगदान दिया गया। वर्ष 2023–2024 के लिए ई–कंटेंट विकास पर एसआरजी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 634 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया।

एससीईआरटी नागालैंड के लिए सीआईईटी–एनसीईआरटी द्वारा दीक्षा और इसके उपयोग पर आयोजित 5 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र की झलकियाँ

ii. **भारतीय सांकेतिक भाषा में दिव्यांगों के लिए ई–कंटेंट:** समावेशिता को बढ़ाने और देश के दिव्यांग शिक्षार्थियों की अधिगम जरूरतों को पूरा करने के लिए, एनसीईआरटी ने आईएसएलआरटीसी (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसके तहत संयुक्त रूप से सांकेतिक भाषा वीडियो तैयार किए गए थे। लगभग 4,247 आईएसएल वीडियो रिकॉर्ड किए गए और दीक्षा पर अपलोड किए गए और पीएमईविद्या चैनलों पर प्रसारित किए गए। लगभग 4,525 ऑडियोबुक अध्याय तैयार किए गए और दीक्षा पर अपलोड किए गए। स्कूलों के लिए दिव्यांगता जांच चेकलिस्ट के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप प्रशस्त में 7,44,543 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे।

iii. **वीएसके/एनडीईएआर:** एनडीईएआर विद्या समीक्षा केंद्र (वीएसके) एक संस्थागत मार्ग है जो अपने कार्यक्रमों की सफलता के लिए प्रमुख हितधारकों द्वारा कार्य को आगे बढ़ाने के लिए डेटा–आधारित निर्णय लेने को की क्षमता बढ़ाने के लिए एकीकृत और साझा 'देखने' को सक्षम बनाता है। वीएसके सीबीएसई, दिल्ली और निम्नलिखित 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों: गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, नागालैंड, दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में लाइव और चालू है। शेष राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य वीएसके तैयार करने के लिए संघ राज्य क्षेत्रों /राज्यों के साथ मिलकर काम करने का प्रयास किया गया। वीएसके 2.0 का उद्घाटन 1 सितंबर 2023 को भारत सरकार के माननीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा एनसीईआरटी में किया गया था।

वीएसके 2.0 का उद्घाटन 1 सितंबर, 2023 को एनसीईआरटी में माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा किया गया।

iv. **दीक्षा पर वर्चुअल लैबः** वर्तमान में दीक्षा पर वर्चुअल लैब की कुल संख्या 264 है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वर्चुअल लैब को एकीकृत करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण और ऑनलाइन सत्र पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर आयोजित किए गए थे। दीक्षा प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल लैब के लिए एक वर्टिकल बनाया गया था। वर्चुअल लैब में कुल मिलाकर लगभग 1,48,792 बार प्ले किया गया, जिसमें दीक्षा प्लेटफॉर्म पर 1,93,297 मिनट का प्लेटाइम प्राप्त हुआ। वर्चुअल लैब पर लगभग 36 घंटे का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसका एक साथ पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों और एनसीईआरटी ऑफिशियल पर सीधा प्रसारण किया गया। वर्चुअल लैब पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को लगभग 4,97,854 यूट्यूब व्यूज प्राप्त हुए।

v. **स्कूल, प्रारंभिक बचपन और शिक्षकों के लिए नया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढांचा और संबंधित एनसीएफ तकनीकी मंचः** एनसीएफ के गठन के निचले स्तर के दृष्टिकोण को सुविधाजनक बनाने के लिए, एनईपी 2020 (https://ncf.ncert.gov.in/रु/web/home) की सिफारिशों के अनुसार एक तकनीकी मंच लॉन्च किया गया था। एनसीएफएफएस–2022 और एनसीएफएसई 2023 दस्तावेज तकनीकी प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिए गए हैं। राज्यों के साथ उनके राज्य पाठ्यक्रम ढांचे के विकास के लिए समन्वय नियमित अंतराल पर किया जा रहा है। अब तक, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों ने एससीएफएफएस तैयार किया है। सूचीबद्ध डीआईएसएएनसी (मोबाइल ऐप) आउटरीच कार्यनीति का विवरण नीचे दिया गया हैः

क) लगभग 12,77,061 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई

ख) इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के संपर्क डेटाबेस में उपयोगकर्ताओं को 28 करोड़ ईमेल भेजे गए

ग) एनआईसी डेटाबेस में मोबाइल नंबरों पर 10 करोड़ एसएमएस भेजे गए

vi. **पीएम ईविद्या और आईवीआरएस के माध्यम से मनोसामाजिक सहायताः मनोदर्पण और सहयोगः** कोविड महामारी और उसके बाद छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, भारत सरकार के एमओई द्वारा मनोदर्पण पहल शुरू की गई है। जनवरी 2024 तक, आईवीआरएस कॉल पर 61,947 कॉल प्राप्त हुईं और कॉल करने वालों को टेली–परामर्श दिया गया। पीएम ईविद्या चैनलों पर 214.5 घंटे के लगभग 144 वेबिनार सत्र प्रसारित किए गए। आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से एक लाइव योग श्रृंखला आयोजित की गई, जिसमें प्रति सप्ताह 5 लाइव इंटरैक्टिव सत्र पीएम ईविद्या चैनलों पर प्रसारित किए गए, जिसमें कुल 03 घंटे 45 मिनट (प्रत्येक 45 मिनट) शामिल थे।

vii. **दीक्षा पर सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रमः** दीक्षा पर चार जेनेरिक सीपीडी पाठ्यक्रम पेश किए गए, जिनमें हजारों की संख्या में पंजीकरण हुए। ''दीक्षा पर वर्चुअल लैब का शिक्षा शास्त्री परिप्रेक्ष्य'' और ''ई–सामग्री का विकास इंटरएक्टिव संसाधन'' विषय पर दो ऑनलाइन प्रशिक्षण क्रमशः 11 से 15 दिसंबर 2023 और 25 से 29 दिसंबर 2023 तक आयोजित किए गए।

viii. **स्वयं पर स्कूल एमओओसीः** एनसीईआरटी ने ग्यारहवीं–बारहवीं कक्षा के लिए स्वयं पोर्टल के माध्यम से 11 विषयों को कवर करते हुए 28 पाठ्यक्रमों की पेशकश की। पाठ्यक्रम चार–चतुर्थांश दृष्टिकोण के साथ डिज़ाइन

किए गए हैं। अक्टूबर, 2023 में शुरू हुए स्वयं पर इन 28 पाठ्यक्रमों के 12वें चक्र में लगभग 13,925 छात्रों ने नामांकन किया था।

ix. **ईपाठशाला के माध्यम से डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता:** ईपाठशाला वेब पोर्टल (https://epathsala.nic.in/) और मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड, आईओएस, विंडोज) का उपयोग करके, छात्र, शिक्षक, शिक्षक, प्रशिक्षक और अभिभावक 377 से अधिक डिजिटल पुस्तकों/ई पाठ्यपुस्तकों (कक्षा I से XII) और एनसीईआरटी के 6664 ऑडियो और वीडियो, विभिन्न भाषाओं (हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और उर्दू) के मुक्त संसाधनों तक पहुंच सकते हैं। ई–पाठशाला (https://epathsala.nic.in/) पोर्टल पर जनवरी 2024 तक लगभग 20.40 करोड़ विजिटर और 4.5 मिलियन ऐप डाउनलोड थे।

x. **निष्ठा:** महामारी के दौरान, बड़े पैमाने पर शिक्षक व्यावसायिक विकास कार्यक्रम निष्ठा (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) को दीक्षा के माध्यम से ऑनलाइन लॉन्च किया गया था। इस पहल के हिस्से के रूप में निष्ठा ईसीसीई बैच 3 (2023–24) के तहत दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में 6 पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए। निष्ठा एफ़एलएन बैच 3 (2023–24) के तहत तीन भाषाओं (अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू) में 12 पाठ्यक्रम लॉन्च किए गए। एनसीईआरटी ऑनलाइन मोड के माध्यम से निष्ठा, प्रारम्भिक, एफएलएन, माध्यमिक और ईसीसीई की पेशकश कर रहा है, और अब तक 60 लाख से अधिक शिक्षकों ने दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा मॉड्यूल पूरा कर लिया है। एनईपी और ई–कंटेंट डेवलपमेंट पर आयोजित सभी 11 ऑनलाइन प्रशिक्षणों में लगभग 3,83,620 शिक्षार्थियों को प्रमाणित किया गया। इसमें के.वी.एस., स.वि.सं. और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के शिक्षक और स्कूल प्रमुख भी शामिल हैं।

xi. **पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनल:** माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 12 मई 2020 को घोषित आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत आंदोलन के हिस्से के रूप में पीएम ईविद्या पहल की घोषणा माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार द्वारा 17 मई, 2020 को की गई थी। पीएम ईविद्या 12 डीटीएच टीवी चैनलों के लिए कुल 6,805 से अधिक कार्यक्रम तैयार किए गए हैं और इन्हें दीक्षा पर अपलोड किया गया है।

पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर लाइव प्रसारण: कक्षा 1 से 10 तक के लाइव कार्यक्रम: 30 मिनट के 3,486 लाइव इंटरैक्टिव सत्र कक्षा–आधारित चैनलों (1 से 10) पर प्रसारित किए गए हैं। इसमें लगभग 10 घंटे का प्रसारण शामिल था। कक्षा 11 और 12 के लाइव कार्यक्रम: कक्षा–आधारित चैनलों (11 और 12) के आधार पर 60 मिनट के 343 लाइव इंटरैक्टिव सत्र प्रसारित किए गए हैं। इसमें लगभग 343 घंटे का प्रसारण शामिल था।

पीएम ईविद्या आईवीआरएस और ई–मेल–आधारित सहायता: पीएम ईविद्या के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण के बारे में पूछताछ करने के लिए आईवीआरएस पर 61947 कॉल प्राप्त हुईं। पाठ्यक्रम–आधारित रेडियो कार्यक्रमों (कक्षा 1–12) की 4,275 सामग्री भी 400 रेडियो स्टेशनों के माध्यम से प्रसारित की गई। सभी 200 पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों का परीक्षण 29 जुलाई, 2023 से शुरू हो गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों द्वारा कार्यक्रमों के प्रसारण के नियमित शेड्यूल के साथ जारी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/स्वायत्त निकायों ने उन्हें आवंटित प्रत्येक पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनल के लिए यूट्यूब चैनल बनाए हैं। अब तक, अपने डीटीएच टीवी चैनलों के एक साथ प्रसारण के लिए 72 यूट्यूब चैनल बनाए गए हैं। तमिलनाडु और

पुडुचेरी को छोड़कर, अन्य सभी 34 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और एनआईएमआई, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार ने चैनलों के संचालन के लिए एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गुणवत्ता और आकर्षक वीडियो सामग्री तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ छह चरणों में आयोजित की गई हैं, जिसमें 38 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों और 239 प्रतिभागियों को आमने–सामने मोड में शामिल किया गया है। पीएम ईविद्या के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया जा रहा है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के फीडबैक के साथ डिपस्टिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी तैयार की गई।

पीएम ईविद्या के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों /स्वायत्त निकायों के प्रतिनिधियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं सीआईईटी, एनसीईआरटी में 6 चरणों में आयोजित की गईं।

गुणवत्तापूर्ण ई–सामग्री के विकास और विभिन्न भाषाओं में और विभिन्न हितधारकों के लिए पीएमईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों के माध्यम से इसके प्रसार के लिए एनसीईआरटी और स्कूल शिक्षा विभाग, झारखंड सरकार के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।

xii. **बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी:** एंड्रॉइड ऐप का बीटा संस्करण परीक्षण और अंतिम रूप देने के लिए प्रतिबंधित पहुंच के साथ गूगल प्ले स्टोर में प्रकाशित किया गया था। वेब संस्करण निर्माणाधीन था और यह जनवरी 2024 तक डेमो के लिए तैयार हो सकता है। इसके अलावा, एनडीएल मोबाइल ऐप का आईओएस भी प्रक्रियाधीन है। एनडीएल डेटाबेस पर 19 भाषाओं, 13 शैलियों और 33 प्रकाशकों की कुल 803 पुस्तकें अपलोड की गईं। बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक मिशन के तहत, जो 'सभी के लिए शिक्षा' की वकालत करता है, दीक्षा पर 2409 सामग्री अपलोड की गई और 396 सोशल मीडिया पोस्ट किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शैक्षिक पहल प्रत्येक बच्चे तक पहुंचे।

xiii. **दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा:** 7 दिसंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर एक इंटरैक्टिव प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। दृश्य और श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए भी ई–सामग्री तैयार की गई थी। श्रवण बाधितों के लिए, दीक्षा पर 954 पाठ्यपुस्तक–आधारित आईएसएल वीडियो अपलोड किए गए, जिनमें बरखा

श्रृंखला के तहत 40 वीडियो और 32 ई–कॉमिक पुस्तकें शामिल हैं। लगभग 4,525 ऑडियोबुक अध्याय तैयार किए गए और दीक्षा पर अपलोड किए गए। लगभग 4,250 आईएसएल वीडियो (एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों, शब्दों और शब्दकोश पर आधारित) नियमित रूप से 24×7 आधार पर पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर प्रसारित किए गए और दीक्षा पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से अपलोड और प्रसारित किए गए। प्रशस्त ऐप – अब 22 भाषाओं में उपलब्ध है– जनवरी 2024 तक 7,44,543 उपयोगकर्ताओं द्वारा पंजीकृत किया गया। समावेशी कक्षाओं को बढ़ावा देने के लिए, 'समावेशी कक्षाओं के लिए शिक्षण–अधिगम उपाय' के 352 लाइव सत्र लाइव प्रसारित किए गए, जो लगभग 354.5 घंटे तक चले। अनिवार्य आईएसएल दुभाषिया के साथ एसएलडी पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण (16 से 20 अक्टूबर 2023) भी पिछले साल पूरा हुआ था।

5. प्रारंभिक शिक्षा

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में एनसीईआरटी द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम चलाए गए–

- **जादूई पिटारा:** कार्यक्रम का उद्देश्य बुनियादी चरण के लिए उम्र के अनुरूप अधिगम और शिक्षण सामग्री (एलटीएम) तैयार करना; जादूई पिटारा में रखी सामग्री का उपयोग करने में शिक्षकों और अभिभावकों की मदद करने के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल और ट्यूटोरियल वीडियो प्रदान करना; और एनसीएफ–एफएस के पाठ्यचर्या लक्ष्यों, दक्षताओं और अधिगम के परिणामों के अनुरूप गतिविधियों के संचालन के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षक मैनुअल प्रदान करना है। जादूई पिटारा टीएलएम का एक संग्रह है जिसे एनईपी 2020 और एनसीएफ–एफएस, 2022 की सिफारिशों के आधार पर बुनियादी चरण लिए तैयार किया गया है। इस जादुई पिटारा में पिक्चर रीडिंग पोस्टर, खिलौने, गुड़िया, कठपुतलियाँ, गतिविधि कार्ड, प्रशिक्षक हैंडबुक ग्रेडेड रीडिंग श्रृंखला बरखा और एक उपयोगकर्ता मैनुअल शामिल है। जादूई पिटारा में विकास के सभी पांच क्षेत्रों के लिए एलटीएम प्रदान किया गया है, जो कई अन्य गतिविधियों के साथ–साथ खिलौनों और खेलों के माध्यम से अधिगम के खेल–तरीकों को एकीकृत करने की का अवसर उपलब्ध कराता है जो बच्चों को महत्वपूर्ण सोच और समस्या–समाधान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। जादूई पिटारा का उपयोगकर्ता मैनुअल उपयोगकर्ताओं को सामग्री, इसके उद्देश्यों और बच्चों के साथ इसके उपयोग की विधि के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करता है। जादुई पिटारा की सभी डिजिटल सामग्री को दीक्षा पोर्टल पर 13 भाषाओं में अपलोड किया गया है।

शिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को जादूई पिटारा की सामग्रियों से परिचित कराने और एलटीएम के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए, फरवरी से मार्च, 2023 के दौरान पांच प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।

मास्टर प्रशिक्षकों को एनसीएफ–एफएस से परिचित कराने के लिए पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों और केवी और सीबीएसई के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए आमने–सामने मोड में मई से जून, 2023 के बीच सात क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। बुनियादी चरण के लिए, मास्टर प्रशिक्षकों को जादूई पिटारा की सामग्री की जानकारी दी गई; और सामग्रियों के उपयोग का प्रदर्शन किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में एनसीएफ–एफएस की प्रमुख सिफारिशों और कक्षाओं में शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के लिए इसके निहितार्थ संबंधी सत्र शामिल थे। अपने संदर्भ के अनुसार स्थानीय सामग्री से अपना जादूई पिटारा कैसे तैयार किया जाए, इस पर भी सत्र आयोजित किए गए।

- **कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें और शिक्षक पुस्तिकाएँ:** विकास गतिविधि का उद्देश्य एनईपी–2020 और एनसीएफ–एफएस 2022 की सिफारिश के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और गणित में कक्षा 1 और 2 के लिए पाठ्यपुस्तकें तैयार करना; और पाठ्यक्रम के संचालन में शिक्षकों की सहायता के लिए शिक्षक पुस्तिका तैयार करना है। खेल–आधारित, खोज आधारित और कहानी–आधारित शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके एनईपी–2020 और एनसीएफ–एफएस 2022 की सिफारिशों के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और गणित में पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। पाठ्यपुस्तकें सरल, रोचक और आकर्षक तरीके से योग्यता–आधारित सामग्री प्रदान करने का प्रयास करती हैं, जो बच्चे के स्थानीय संदर्भ, सुदृढ़ता और समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करती हैं।

- **कक्षा 1 और 2 के लिए नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर ऑनलाइन अभिमुखीकरण कार्यक्रम:** अभिमुखीकरण कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों को कक्षा 1 और 2 के लिए नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक पर अभिमुख करना था। जुलाई 2023 में पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों और केवी और सीबीएसई के लिए कक्षा 1 और 2 के लिए नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों पर शिक्षकों, मास्टर प्रशिक्षकों, अभिभावकों और अन्य हितधारकों के लिए ऑनलाइन मोड में सात क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। हिंदी, अंग्रेजी, गणित और उर्दू की पाठ्यपुस्तकों पर चर्चा की गई। इस बात पर प्रकाश डाला गया कि कैसे नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें अब खेल आधारित, कहानी आधारित और गतिविधि–आधारित दृष्टिकोण अपनाती हैं, जो कि बुनियादी चरण के लिए एनसीएफ–एफएस में उल्लिखित पाठ्यचर्या लक्ष्यों, दक्षताओं और अधिगम के परिणामों के अनुरूप है।

- **आरआईई, भोपाल में शिक्षा के बुनियादी और प्रारंभिक चरणों के लिए खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र (टीबीपी) को लोकप्रिय बनाने और एकीकृत करने के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन:** महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव सहित पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक क्षेत्रीय सम्मेलन 26 से 27 नवंबर 2023 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल के परिसर में आरआईई, भोपाल के सहयोग से प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अलावा सम्मेलन में राज्यों के प्रतिभागियों, डिमॉन्स्ट्रेशन मॉडल स्कूल के शिक्षकों और छात्राध्यापकों ने भी भाग लिया। सम्मेलन का उद्देश्य प्रतिभागियों के सामने चर्चा करना और मॉडल तैयार करना था कि कैसे वैकल्पिक शिक्षाशास्त्र, विशेष रूप से खिलौना और खेल आधारित शिक्षाशास्त्र, बुनियादी और प्रारंभिक चरणों में अवधारणाओं को समझने में सहायक हो सकते हैं। दो दिनों की अवधि में

सम्मेलनों का मुख्य आकर्षण कार्यशालाएँ थी जो स्वदेशी खिलौनों और खेलों की प्रदर्शनी और स्थानीय कारीगरों द्वारा खिलौना तैयार बनाने पर आयोजित की गई थीं। प्रत्येक राज्य के प्रतिभागियों को अपने स्थानीय और स्वदेशी खिलौने लाने और प्रदर्शनी में प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। पद्मश्री रमेश परमार और शांति परमार ने स्वदेशी खिलौना तैयार करने का प्रदर्शन करने के लिए प्रतिभागियों के साथ व्यावहारिक सत्र आयोजित किया। भोपाल के कुशल कारीगर श्री महेंद्र ने खिलौना निर्माण का प्रदर्शन किया और प्रतिभागियों को बांस से खिलौने बनाने का अवसर प्रदान किया। कुल मिलाकर खिलौनों और अवधारणाओं को जोड़ना ही वह विषय था जो सभी गतिविधियों के इर्द–गिर्द घूमता रहा।

बांस से बने खिलौने

प्रदर्शनी की झलक – पद्मश्री रमेश परमार और शांता परमार द्वारा आयोजित कार्यशाला

6. कौशल शिक्षा

एनसीईआरटी की एक घटक इकाई, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान, भोपाल ने भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की योजना के तहत पहचानी गई नौकरी की भूमिकाओं के लिए छात्रों की पाठ्यपुस्तकें तैयार कीं। एनईपी 2020 के आलोक में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में व्यावसायिक शिक्षा को मजबूत करने के लिए, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड, बिहार, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के प्रमुख पदाधिकारियों के लिए नवंबर 2023 तक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गुजरात, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, बिहार, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षाशास्त्र पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, देश के दक्षिणी और उत्तर–पूर्वी क्षेत्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा के लिए पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार कौशल पर शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, जॉब रोल के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष के दौरान ऑटोमोबाइल क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और परिधान निर्मित उत्पाद और होम फर्निशिंग क्षेत्र, खुदरा क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में भूमिकाएँ निभाई गईं।

एयरोस्पेस और विमानन, कृषि, मोटर वाहन, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, हस्तशिल्प और कालीन, आईटी–आईटीईएस, दूरसंचार,

परिवहन, रसद और भंडारण, प्रबंधन और उद्यमिता, मीडिया और मनोरंजन, नलसाज़ी, निजी सुरक्षा और यात्रा एवं पर्यटन,जैसे विभिन्न नौकरी क्षेत्रों के उभरते परिदृश्य में, व्यापक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट मांगों और कौशल आवश्यकताओं को विशेष रूप से पूरा करना है। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद, अगले चरण में इन कार्य भूमिकाओं के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों के निर्माण में निरंतर विकास शामिल है। इस पाठ्यपुस्तक विकास प्रक्रिया को उल्लिखित पाठ्यक्रम के साथ सहजता से संरेखित करने के लिए तैयार किया गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह छात्रों को नौकरी क्षेत्रों के बारे में प्रासंगिक, अद्यतन और व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। संस्थान कक्षा 9 से 12 के लिए विभिन्न नौकरी भूमिकाओं पर रोजगार कौशल, व्यावसायिक और पूर्व–व्यावसायिक शिक्षा पर डिजिटल संसाधन भी विकसित कर रहा है। जनवरी 2024 तक, 267 वीडियो को अंतिम रूप दिया गया है। इसके अतिरिक्त, संस्थान में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में डिप्लोमा चल रहा है जहां पाठ्यक्रम का 2022–23 सत्र पूरा हो गया और नए सत्र 2023–24 की पहली तिमाही अक्टूबर 2023 से शुरू हुई। संस्थान ई–कौशल प्रयोगशालाएं विकसित करने की प्रक्रिया में भी है जो न केवल सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करने के लिए बल्कि व्यावहारिक अधिगम के अनुभव भी प्रदान करने के लिए डायनामिक मंच के रूप में उभरेगी।

7. प्रौढ़ शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार, मार्च 2021 में एनसीईआरटी में राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र (सीएनसीएल) के लिए एक सेल का गठन किया गया था। यह सेल वित्त वर्ष 2022–2027 की अवधि के लिए लॉन्च किए गए जो शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम – नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसे उल्लास (समाज में सभी के लिए आजीवन अधिगम को समझना) के नाम से जाना जाता है, के अनुसार कार्य करता है। यह संसाधन सामग्री विकसित करके, देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर और सहयोग करके और न केवल शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों (वीटी) के लिए बल्कि इस जनआंदोलन में भाग लेने वाले समुदाय के लिए समर्पित शिक्षण–अधिगम केंद्र स्थापित करके 'सभी के लिए शिक्षा' (पूर्व में, वयस्क शिक्षा) को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 सभी के लिए शिक्षा के संबंध में पांच प्रमुख क्षेत्रों, जैसे, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा की बात करती है । सेल इन सभी क्षेत्रों पर एक साथ ध्यान केंद्रित करके वयस्क शिक्षार्थियों के लिए कार्य करता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान, सेल ने उल्लास के तहत शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए एक आधार तैयार करने हेतु उनकी शैक्षणिक प्रक्रिया के साथ–साथ अधिगम के परिणामों को परिभाषित करने पर कार्य किया। इसने शिक्षार्थियों और स्वयंसेवी शिक्षकों दोनों के लिए मुद्रित और गैर–मुद्रित रूप में विभिन्न संसाधन सामग्री भी तैयार की। इन सामग्रियों में शामिल हैं: चार खंडों में उजास शीर्षक वाला प्राइमर और इसकी मार्गदर्शिका, उल्लास और इसकी मार्गदर्शिका नामक संक्षिप्त प्राइमर, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में प्राइमर के विकास के लिए दिशानिर्देश, वर्कशीट, मूल्यांकन आइटम, शिक्षार्थियों के लिए स्व–मूल्यांकन को प्रोत्साहित करने वाले परीक्षण पत्र, साक्षरता की डागर पर शीर्षक वाले प्राइमर पर आधारित वीडियो कार्यक्रम, परवरिश (पेरेंटिंग) विषय पर सतत शिक्षा के तहत वीडियो कार्यक्रमों की एक श्रृंखला, हिंदी के साथ–साथ क्षेत्रीय भाषाओं में महत्वपूर्ण जीवन कौशल पर ऑडियो कार्यक्रम, प्रचार सामग्री जैसे जिंगल, वृत्तचित्र, फ्लायर्स, और सूचनात्मक पुस्तिकाएं कार्यक्रम और सेल के कामकाज के बारे में जागरूकता फैलाती हैं।

स्वयंसेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सेल ने देश भर के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम किया और शिक्षकों और मास्टर प्रशिक्षकों के लिए क्षमता

निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए, जो फिर जिला और ब्लॉक स्तर पर वीटी को प्रशिक्षित करेंगे और शिक्षार्थियों को साक्षरता की दिशा में उनकी यात्रा में मदद करेंगे। इसके अलावा, सेल ने देश के प्रत्येक जिले में मॉडल सामाजिक चेतना केंद्र स्थापित करने के उद्देश्य से साक्षरता की तलाश में शिक्षार्थियों की चुनौतियों और आकांक्षाओं को समझने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार और समर्पित सामुदायिक दौरे सुनिश्चित किए।

8. विज्ञान शिक्षा

वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता के साथ, एनसीईआरटी पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकें तैयार करता है जो वैचारिक समझ और व्यावहारिक अनुप्रयोग पर जोर देते हैं। पूछताछ–आधारित शिक्षा, व्यावहारिक प्रयोगों और समसामयिक प्रगति को एकीकृत करके, एनसीईआरटी यह सुनिश्चित करता है कि विज्ञान शिक्षा न केवल जानकारीपूर्ण हो, बल्कि आकर्षक भी हो। इसके दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों के बीच आलोचनात्मक सोच, समस्या–समाधान कौशल और अन्वेषण के लिए जुनून पैदा करना है, जो समग्र और प्रभावी शिक्षण अनुभव में योगदान देता है। अपने नवोन्मेषी तरीकों के माध्यम से, एनसीईआरटी वैज्ञानिक रूप से साक्षर व्यक्तियों की अगली पीढ़ी के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप माध्यमिक स्तर पर शिक्षक–सक्षम गणित कक्षाओं के लिए अनुभवात्मक शिक्षण सामग्री तैयार कर रही है। इस पहल के लिए विस्तृत दिशानिर्देश एनसीईआरटी वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं। इस प्रक्रिया को समर्थन और सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को उत्प्रेरक अनुदान वितरित किया जा रहा है, जो गणित शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एक ठोस प्रयास को दर्शाता है। इन लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय बाल विद्या परिषद (आरबीवीपी) 2023 के साथ, 26–27 दिसंबर, 2023 को पुणे में दो दिवसीय समन्वयक बैठक हुई। इस बैठक ने नए दिशानिर्देशों के अनुसार शैक्षिक परिदृश्य को आकार देने में शामिल हितधारकों के बीच सहयोग, विचारों के आदान–प्रदान और समन्वय के लिए एक मंच प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, प्रगति और नवीन दृष्टिकोणों को प्रदर्शित करने के लिए, कुछ राज्य राज्य–स्तरीय प्रदर्शनियों का आयोजन कर रहे हैं। ये प्रदर्शनियाँ सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, एक–दूसरे के अनुभवों से सीखने और माध्यमिक स्तर पर प्रभावी और अनुभवात्मक गणित शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करती हैं।

परिषद मिडिल स्तर पर विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम चला रही है, जिसका उद्देश्य बड़ी संख्या में उन शिक्षकों को सशक्त बनाना है जिन्हें अपनी सामग्री के साथ–साथ शैक्षणिक ज्ञान को मजबूत करने की आवश्यकता है। "ओपन एडएक्स" का उपयोग करते हुए एक एमओओसी प्लेटफॉर्म (http://www.ncertx.in) स्थापित किया गया है। स्वयं में हाइलाइट किए गए चार चतुर्थांशों को इस पाठ्यक्रम में एकीकृत तरीके से शामिल किया गया है। पाठ्यक्रम में 40 मॉड्यूल शामिल हैं। प्रत्येक मॉड्यूल बुनियादी बातों से शुरू होता है और शिक्षार्थियों की समझ को महत्वपूर्ण वैचारिक गहराई तक विकसित करने का प्रयास करता है। ये मॉड्यूल शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण प्रदर्शित करते हैं। वर्ष 2022–23 में देशभर से करीब 342 प्रतिभागियों ने इस पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था।

बच्चों और आम जनता के बीच विज्ञान के प्रति लगाव को बढ़ावा देने के साथ–साथ बच्चों की सहज जिज्ञासा और आविष्कारशीलता को बढ़ावा देने के प्रयास में, एनसीईआरटी प्रतिवर्ष बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी और राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी (एसएलएसएमईई) का आयोजन करता है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी का 50वां संस्करण, जिसे राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी (आरबीवीपी)–2022 के नाम से जाना जाता है, 26 से 31 दिसंबर, 2023 तक पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। यह आयोजन एनसीईआरटी, नई दिल्ली

और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास था। आरबीवीपी–2023 का व्यापक विषय "प्रौद्योगिकी और खिलौने" था, जिसमें छह उप–विषय, अर्थात् सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में उन्नति, पर्यावरण–अनुकूल सामग्री, स्वास्थ्य और स्वच्छता, परिवहन और नवाचार, पर्यावरण संबंधी समस्याएँ, वर्तमान नवाचार के साथ ऐतिहासिक विकास, और हमारे लिए गणित शामिल थे। प्रदर्शनी में 172 वैज्ञानिक प्रदर्शनियां प्रदर्शित की गई, जिनमें 33 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य संगठनों का योगदान शामिल है। विशेष रूप से, 77 प्रदर्शन ग्रामीण क्षेत्रों से थे, जबकि 85 शहरी क्षेत्रों से थे। प्रदर्शनों से परे, इस आयोजन में विविध प्रकार की गतिविधियों की पेशकश की गई, जिसमें पक्षी निरीक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भारतीय ज्ञान प्रणाली, अंतरिक्ष मिशन और आरएसए क्रिप्टोग्राफी जैसे विषयों पर लोकप्रिय वार्ता शामिल है। इसके अतिरिक्त, एनईएसएसी, इसरो द्वारा 'स्पेस ऑन व्हील', 'प्लेइंग विद साइंस', 'इंस्टेंट क्विज', 'साइंस शो', 'आर्ट कॉम्पिटिशन', 'ऑब्जर्वेशन ऑफ नाइट स्काई' और 'शोकेस ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज ऑफ महाराष्ट्र' जैसी इंटरैक्टिव पहलें भी थीं। 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य स्तरीय विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शनी के आयोजन के लिए एनसीईआरटी से उत्प्रेरक अनुदान का लाभ उठाया है।

विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, परिषद ''विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का केंद्र'' नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसमें दो परिचालन इकाइयां: विज्ञान पार्क और हर्बल गार्डन शामिल हैं। विज्ञान पार्क खुली हवा की सुविधा के रूप में कार्य करता है जहां कार्यात्मक मॉडल इस पार्क के माध्यम से बच्चों, शिक्षकों, शिक्षक–प्रशिक्षकों, गैर सरकारी संगठनों और विज्ञान शिक्षा में शामिल अन्य हितधारकों के लिए व्यावहारिक अनुभव, प्रतिभागी चयनित वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्यावहारिक समझ और सराहना प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, परिषद ने 27 से 28 फरवरी, 2023 तक एनआईई, नई दिल्ली में "भारत के स्वदेशी मिलेट और उनके संरक्षण" विषय पर शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और समुदायों की एक इंटरैक्टिव बैठक आयोजित की। इस कार्यक्रम ने विज्ञान को उत्सव के रूप में चिह्नित किया और भारत की कृषि विरासत के एक महत्वपूर्ण पहलू – स्वदेशी मिलेट के संरक्षण के संबंध में सार्थक चर्चा में शामिल होने के लिए शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और समुदायों के लिए एक सहयोगी मंच की सुविधा प्रदान की।

"भारत के स्वदेशी मिलेट और उनके संरक्षण" पर शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों और समुदायों की इंटरैक्टिव बैठक के हिस्से के रूप में मिलेट का प्रदर्शन

एनसीईआरटी परिसर में हर्बल गार्डनः सामुदायिक प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

एनसीईआरटी परिसर में विज्ञान पार्कः पूर्व–सेवा और सेवाकालीन शिक्षकों के साथ बातचीत

9. लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण

एनसीईआरटी लड़कियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में कार्य करता है और अनुसंधान अध्ययन, विकास और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा में जेंडर समानता लाने के लिए लगातार प्रयास करता है। यह स्कूल में ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए एक सुरक्षित, अनुकूल और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए शिक्षकों और अन्य हितधारकों को संवेदनशील बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) योजना भारत सरकार द्वारा अगस्त, 2004 में स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर अंतराल को कम करने और वंचित समूहों की लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) की स्कूल छोड़ने वाली और अधिक उम्र की लड़कियों को मुख्यधारा में लाने के लिए शुरू की गई थी। केजीबीवी एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जैसे वंचित समूहों से संबंधित 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए कक्षा VI से XII तक के आवासीय विद्यालय/छात्रावास हैं। शिक्षा मंत्रालय समय–समय पर योजना का मूल्यांकन करता है। तीसरे 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) के राष्ट्रीय मूल्यांकन' का काम इस बार जेंडर अध्ययन विभाग, एनसीईआरटी को दिया गया है। अध्ययन की एक मसौदा रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को सौंप दी गई है। इसके अतिरिक्त, लघु फिल्म कोमल के प्रसार एवं स्क्रीनिंग की समीक्षा करने के उद्देश्य से बाल यौन शोषण निवारण हेतु भारत सरकार की चुनिंदा पहलों का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन पर एक जांच शुरू की गई है।

स्कूल शिक्षा प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर से जुड़े विषयों को एकीकृत करने संबंधी एक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसमें शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, स्कूल सहायता कर्मचारियों, शिक्षक प्रशिक्षकों के साथ–साथ अन्य हितधारकों को विविध जेंडर समता वाले छात्रों को एकीकृत करने के लिए संवेदनशील और सक्षम बनाने हेतु स्कूल शिक्षा प्रणाली में ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने की समस्याओं को ध्यान में रखा गया है। यह मॉड्यूल 'ट्रांसजेंडर और कानूनी प्रावधान', 'स्कूलों में ट्रांसजेंडर के लिए समावेशी वातावरण बनाना', 'चुनौतियां और संभावनाएं' आदि विषयों पर केंद्रित है, जो स्कूल के अंदर रोजमर्रा की प्रथाओं में ट्रांसजेंडर से संबंधित विषयों को एकीकृत करने हेतु विभिन्न हितधारकों के लिए कार्यकलापों और प्रथाओं की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है।

10. राष्ट्रीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता 2023

राष्ट्रीय रोल प्ले और लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग—राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना (एनपीईपी) एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई), भुवनेश्वर में 3—4 जनवरी, 2024 को किया गया था। यह कार्यक्रम 2009 में शुरू हुआ और रचनात्मक अभिव्यक्तियों के माध्यम से बच्चों के बीच समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। इस मेगा इवेंट के आयोजन से किशोरों के बीच बढ़ते मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया गया है। किशोरावस्था में बच्चों को प्रभावित करने वाले कुछ रिपोर्ट किए गए मुद्दे मादक द्रव्यों के सेवन, अवसाद, चिंता, तनाव और अन्य शारीरिक—व्यक्तित्व संबंधी चिंताओं से संबंधित हैं।

रोल प्ले प्रतियोगिता में समग्र विकास पर केंद्रित विषय, जैसे "स्वास्थ्य के साथ बड़ा होना" "पौष्टिक भोजन और कल्याण," "व्यक्तिगत सुरक्षा (शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और यौन)," "इंटरनेट, गैजेट्स, और मीडिया साक्षरता, का सुरक्षित उपयोग" और "मादक द्रव्यों का सेवन एवं इसके कारण और रोकथाम आदि शामिल थे। सरी ओर, लोक नृत्य प्रतियोगिता में सामाजिक मूल्यों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर जोर देने वाले विषयों, जैसे "लड़कों और लड़कियों के लिए समान अवसर, " "बच्चों के विकास में संयुक्त परिवार की भूमिका," "पर्यावरण की सुरक्षा (अस्वीकार करना, घटाना, पुनः उपयोग और पुनग्रहण करें)," "मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम," और "किशोरावस्था के दौरान स्वस्थ रिश्ते'' की प्रस्तुति दी गई। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय रोल प्ले प्रतियोगिता के विजेता हरियाणा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक थे, और बहुउद्देशीय स्कूल प्रदर्शन (डीएमएस) के विजेता क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान आरआईई, मैसूर, आरआईई, भुवनेश्वर और आरआईई, भोपाल से थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से राष्ट्रीय लोक नृत्य प्रतियोगिता के विजेता कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और अंडमान और निकोबार थे, और डीएमएस से आरआईई, भुवनेश्वर, आरआईई, मैसूर और आरआईई, भोपाल थे।

11. राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023

राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन भारत की जी20 अध्यक्षता के तहत एनसीईआरटी और शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने योग की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित किया। यह 18—20 जून, 2023 तक क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई), भोपाल में आयोजित किया गया था। इसका विषय "वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग" था। इस शब्द में प्राचीन भारतीय ज्ञान के सार को खूबसूरती से दर्शाया गया है, जो इस सार्वभौमिक अवधारणा पर जोर देता है कि दुनिया एक परिवार है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय योग ओलंपियाड के आयोजन की यात्रा 2016 से शुरू हुई। इसने माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से प्रेरणा ली है जिन्होंने योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया है। महामारी के दौरान, राष्ट्रीय योग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा ऑनलाइन योग प्रदर्शन का आयोजन करके स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने में योग की उपयोगिता के बारे में जागरूकता फैलाई गई। कोविड के बाद, छात्रों को योग को अपने दैनिक जीवन का

हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बार फिर योग ओलंपियाड का आयोजन किया गया।

आरआईई, भोपाल में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2023 का आयोजन मुख्य अतिथि, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, श्री मंगूभाई पटेल की उपस्थिति में किया गया। उद्घाटन सत्र में शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान के प्रेरक संदेश को सभी ने वर्चुअली देखा। समापन सत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति सभी के लिए उत्साहवर्धक रही।

नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, भारतीय विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद, और जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (एकलव्य) जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसियों ने भाग लिया। 26 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भाग लेने वाले छात्रों और अनुरक्षण शिक्षकों की कुल संख्या 587 थी। राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात ब्लॉक, जिला और राज्य से छात्रों के चयन में बॉटम–अप दृष्टिकोण अपनाया गया था। विद्यार्थियों ने विभिन्न आसन किए। इस प्रकार, इस कार्यक्रम ने न केवल प्रतिभागियों की प्रतिभा का जश्न मनाया बल्कि कल्याण, आत्म–खोज और एकता को बढ़ावा देने में योग के व्यापक महत्व को भी रेखांकित किया।

12. कला उत्सव

कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के तहत शिक्षा मंत्रालय (एमओई) की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषित और प्रदर्शित करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए सौंदर्यशास्त्र और कलात्मक अनुभवों के महत्व को पहचानती है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी जीवंत विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं।

वर्ष 2023 – 24 में राष्ट्रीय स्तर का कला उत्सव 09 से 11 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी), कोट्टा रोड, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कला उत्सव (2023–24) का फोकस पारंपरिक लोक और शास्त्रीय कला रूपों की शैलियों पर था। इस वर्ष प्रतियोगिताओं के लिए शामिल किए गए कला रूप थेः स्वर संगीत शास्त्रीय स्वर संगीत पारंपरिक लोक, वाद्य संगीत आघात वाद्य यंत्र, वाद्य संगीत मधुर, नृत्य शास्त्रीय, नृत्य लोक, दृश्य कला (2–आयामी), दृश्य कला (3–आयामी), स्वदेशी खिलौने और खेल, और नाटक (एकल अभिनय)। इस कार्यक्रम में 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों , केवीएस और एनवीएस के छात्रों ने भाग लिया।

13. सेवा–पूर्व पाठ्यक्रम

अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और एनईआरआईई, उमियाम में स्थित एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में नियमित सेवा–पूर्व पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। केंद्रों पर (i) चार वर्षीय एकीकृत बी.एससी.बी.एड., (ii) दो वर्षीय एम.एससी. (जीवन विज्ञान) बीएड (iii) चार वर्षीय एकीकृत बी.ए.बी.एड., (iv) दो वर्षीय बी. एड., (v) दो वर्षीय एम.एड. (vi) शिक्षा में एक वर्षीय एम.फिल. और (vii) शिक्षा में प्री–पीएचडी पाठ्यक्रम और मार्गदर्शन और परामर्श में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित किया जाता है। सेवा–पूर्व पाठ्यक्रम के घटकों के रूप में छात्रों के लिए बहुसांस्कृतिक प्लेसमेंट, शिक्षण में इंटर्नशिप, समुदाय के साथ काम करना और फील्डवर्क जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गईं। आरआईई में पीएचडी कार्यक्रमों के लिए भी सुविधाएं हैं, और आरआईई, भुवनेश्वर को

शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और शिक्षा में पूर्व–पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए एक नोडल केंद्र के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।

14. अंतरराष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रभाग (आईआरडी), एनसीईआरटी विदेश में एजेंसियों और संस्थानों और एनसीईआरटी के बीच सूचनाओं के आदान–प्रदान की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने, एनसीईआरटी और विदेश में इच्छुक एजेंसियों/संस्थानों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करता है।

प्रभाग विदेश से आने वाले प्रतिनिधिमंडलों की मेजबानी करता है और राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों के निर्माण, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे के विकास, पूर्व–सेवा और सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों के संगठन, व्यावसायिक शिक्षा, शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के क्षेत्रों में सहयोग की सुविधा प्रदान करता है और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में एनसीईआरटी से संकाय की भागीदारी की सुविधा प्रदान करता है। वर्ष 2022 की प्रमुख कार्यकलापों में एनसीईआरटी और फिनलैंड की राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी (ईडीयूएफआई) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर आभासी हस्ताक्षर, एनसीईआरटी और शैक्षणिक संस्थानों के बीच मौजूदा समझौता ज्ञापनों के तहत गतिविधियों को अंजाम देना, द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देना और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधियों पर कार्य करना शामिल है।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और फ़िनिश राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी (ईडीयूएफ़आई) सहयोग की संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी) की दूसरी बैठक 30 अक्टूबर, 2023 को आयोजित की गई। फिनलैंड दूतावास के काउंसलर, श्री मिका, नई दिल्ली और फिनलैंड के विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों, वैश्विक नवाचार और शिक्षण नेटवर्क (जीआईएनटीएल) के प्रतिनिधि और प्रमुख, एनसीईआरटी और इसकी घटक इकाइयों के संकाय सदस्यों ने सहयोग और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न विषयगत क्षेत्रों पर विचार–विमर्श किया।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और फ़िनिश राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी (ईडीयूएफआई) की संयुक्त कार्य समिति (जेडब्ल्यूसी)

प्रारंभिक शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी, और फ़िनिश राष्ट्रीय शिक्षा एजेंसी (ईडीयूएफ़आई) और शिक्षण और अधिगम के लिए ग्लोबल इनोवेशन नेटवर्क (जीआईएनटीएल), फिनलैंड ने संयुक्त रूप से नवंबर, 2023 से फरवरी 2024 तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता पर वेबिनार की एक श्रृंखला आयोजित की। खिलौना–आधारित शिक्षाशास्त्र पर पहला वेबिनार नवंबर, 2023 के अंतिम सप्ताह में आयोजित किया गया था।

माननीय वरिष्ठ शिक्षा मंत्री प्रोफेसर डॉ. डी. अनु सोनी के नेतृत्व में एक लाइबेरिया प्रतिनिधिमंडल ने 13 अप्रैल, 2023 को एनसीईआरटी का दौरा किया और पाठ्यक्रम विकास, पाठ्यपुस्तक और अन्य सामग्रियों के विकास, शिक्षा के लिए आईसीटी और डिजिटल उपयोग, लाइबेरिया शैक्षिक प्रणाली को मजबूत करने और शिक्षा

के क्षेत्र में कौशल विकास ज्ञान साझा करने, शैक्षणिक योजना, पाठ्यचर्या विकास(पाठ्यपुस्तक विकास, शैक्षणिक किट)आदि सामग्री पर एनसीईआरटी के साथ सहभागिता की ।

लाइबेरिया प्रतिनिधिमंडल का दौरा

न्यूजीलैंड जी2जी की कार्यकारी निदेशक सुश्री मिशा मनिक्स–ओपी ने एनसीईआरटी का दौरा किया और 17 अप्रैल, 2023 को निदेशक, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के संकाय सदस्यों के साथ बातचीत की। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए कोरिया अनुसंधान संस्थान (केआरआईवीईटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 से 8 सितंबर 2023 तक एनसीईआरटी (एनआईई, नई दिल्ली, आरआईई भोपाल और पीएसएससीआईवीई, भोपाल) का दौरा किया। इस यात्रा का उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा और भारत में व्यावसायिक शिक्षा के विकास में कोरिया और भारत के बीच सहयोग को बढ़ाना था।

इस्लामी गणतंत्र ईरान के चार प्रतिनिधि, ईरान के माननीय राजदूत महामहिम डॉ. इराज इलाही, राष्ट्रीय फ़ारसी भाषा केंद्र के प्रमुख माननीय डॉ. घोलम अली हददे अदेल, ईरान संस्कृति हाउस के सांस्कृतिक परामर्शदाता माननीय डॉ. फ़रीद अस्र ने 12 दिसंबर, 2023 को नई दिल्ली मे एनसीईआरटी का दौरा किया और भारत में फ़ारसी भाषा को बढ़ावा देने, भाषाओं और भाषा शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भारत और ईरान के बीच संबंध, ईरान में फ़ारसी भाषा शिक्षक शिक्षा हेतु दस भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, ईरान शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में भारतीय छात्रों को आमंत्रित करने और एनसीईआरटी की मदद से फ़ारसी भाषा में शिक्षण–अधिगम शैक्षिक सामग्री तैयार करने पर निदेशक एनसीईआरटी के साथ चर्चा हुई।

जी20 गतिविधियाँ:

भारत की जी20 प्रेसीडेंसी में देश भर में हर तरह के कार्यक्रमों की भरमार देखी गई। जी20 के शिक्षा कार्य समूह ने अपने संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, स्कूल प्रणालियों, स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ देश भर में कई गतिविधियाँ कीं। एनसीईआरटी और इसके घटक – केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी), पीएसएस केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान (पीएसएससीआईवीई), अजमेर, भुवनेश्वर, भोपाल, मैसूरु, उमियम (मेघालय) में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) और क्षेत्रीय संस्थानों के डीएमएसस्कूलों ने घटक इकाइयों में कार्यक्रम, सेमिनार और सम्मेलन, सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रम आयोजित किए। एनसीईआरटी के क्षेत्रीय शिक्षा एवं प्रदर्शन संस्थान बहुउद्देशीय स्कूलों में जी–20 जनभागीदारी वेबिनार श्रृंखला का आयोजन किया गया। चौथी और अंतिम शिक्षा कार्य समूह (ईडीडबल्यूजी) की बैठक 17–21 जून, 2023 को सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय, पुणे में आयोजित की गई, जिसमें जी20 देशों के सदस्यों ने बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता और बहुभाषी शिक्षा में अपनी नीति, पाठ्यक्रम और प्रथाओं को प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भारत में शैक्षिक प्रथाओं की एक भव्य प्रदर्शनी भी देखी गई। स्कूल और विश्वविद्यालय में छात्रों को जी20 के उद्देश्य और भारत के राष्ट्रपति पद के महत्व और लाभों को समझने में सक्षम बनाने के लिए जी20 और भारत के राष्ट्रपति पद पर अंग्रेजी और हिंदी में दो पठन सामग्री और वीडियो तैयार किए गए हैं। 9209-12.pdf (ncert.nic.in) वीडियो जी20: 20 का समूह (youtube.com) पर उपलब्ध है।

15. प्रकाशन

एनसीईआरटी के प्रकाशन कार्यक्रम को चलाने के लिए फरवरी 1963 में प्रकाशन प्रभाग की स्थापना की गई थी। यह स्कूल की पाठ्यपुस्तकों, कार्यपुस्तिकाओं, पूरक पाठकों, शिक्षक गाइडों, प्रयोगशाला मैनुअल,

मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तकों, विज्ञान और गणित में अनुकरणीय समस्याओं, शोध रिपोर्टों/मोनोग्राफ और शैक्षिक पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ जारी है। एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को राज्यों द्वारा उनके राष्ट्रीयकृत पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम के तहत स्वतंत्र रूप से अपनाया जाता है। इन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, केंद्रीय विद्यालयों, जवाहर नवोदय विद्यालयों और तिब्बती स्कूलों और कई राज्य सरकारी स्कूलों से संबद्ध स्कूलों में भी व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है।

एनईपी 2020 और एनसीएफएफएस 2022 के आधार पर, बुनियादी चरण के लिए सामग्री तैयार की गई है जिसमें जादूई पिटारा के लिए कार्ड और अन्य सामग्री शामिल है और कक्षा I और II के लिए हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पाठ्यपुस्तकें तैयार की गई हैं। सभी पाठ्यपुस्तकें संबंधित क्षेत्रीय प्रकाशन–सह–वितरण केंद्रों (आरपीडीसी) के 995 थोक एजेंटों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में उपलब्ध कराई जाती हैं।

कक्षा I से XII तक की पाठ्यपुस्तकें श्री अरबिंदो मार्ग स्थित एनसीईआरटी बिक्री काउंटरों, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थित आरपीडीसी और आरआईई के बिक्री काउंटरों पर भी बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी के उर्दू प्रकाशन उर्दू अकादमी, एनसीटी दिल्ली सरकार के माध्यम से वितरित किए जाते हैं। एनसीईआरटी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आदेशों पर डाक द्वारा व्यक्तिगत और संस्थागत जरूरतों को भी पूरा करता है।

एनसीईआरटी अपने आउटलेटों के माध्यम से और देश के विभिन्न हिस्सों में फैले बड़ी संख्या में विक्रेताओं को शामिल करके पाठ्यपुस्तकों के वितरण के लिए अपने नेटवर्क को व्यापक बनाने का प्रयास कर रहा है। एक वेब पोर्टल (www.ncertbooks.ncert.gov.in) तैयार किया गया है, जहां संबंधित स्कूल और विक्रेता अपनी आवश्यकताओं को पंजीकृत कर सकते हैं और उन्हें रियायती दरों पर किताबें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। इससे एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों तक परेशानी मुक्त पहुंच संभव हो सकेगी। इसके अलावा, सभी एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें देश भर में तत्काल डाउनलोड करने और उपयोग के लिए एनसीईआरटी की वेबसाइट www.ncert.nic.in पर उपलब्ध हैं। एनसीईआरटी ने शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू माध्यम में I-XII तक विभिन्न कक्षाओं के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपनाने/अनुकूलित/अनुवाद के लिए 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कॉपीराइट की अनुमति दी है। प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में विभिन्न एनसीईआरटी प्रकाशनों की लगभग 6 करोड़ प्रतियां प्रकाशित करता है जिसमें पाठ्यपुस्तकें, पूरक पठन सामग्री, शिक्षकों की हस्तपुस्तिकाएं, मूल्यांकन पर स्रोत पुस्तकें, शोध रिपोर्ट और छह शैक्षिक पत्रिकाएं शामिल हैं।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस):

कार्यक्रम संबंधी सुधार

1. **अग्निपथ के लिए एनआईओएस शैक्षणिक उपाय**

   भारत सरकार ने "अग्निपथ" योजना का अनावरण किया है जो एक परिवर्तनकारी पहल है जो सशस्त्र बलों को एक युवा प्रोफ़ाइल प्रदान करेगी जिसमें युवाओं को अग्निवीर के रूप में सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अपने अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा के मार्गदर्शन में, एनआईओएस ने 3 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में कोठारी ऑडिटोरियम, डीआरडीओ भवन में भारतीय सेना, भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार, एनआईओएस उम्मीदवारों को खुद को नामांकित करने का अवसर प्रदान करेगा ताकि वे 4 साल की सेवा अवधि के दौरान

शैक्षणिक और कौशल दोनों पाठ्यक्रमों के लिए 10वीं/12वीं पास प्रमाणपत्र प्राप्त कर सकें।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर समारोह माननीय रक्षा मंत्री, श्री राजनाथ सिंह और माननीय शिक्षा मंत्री, श्री धर्मेंद्र प्रधान की आभासी उपस्थिति में आयोजित किया गया था। गणमान्य व्यक्तियों में रक्षा सेवाओं के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार और वायु सेना प्रमुख, एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी, श्रीमती एल स्वीटी चांगसन,अतिरिक्त सचिव (आईएनएस) शिक्षा मंत्रालय, डॉ निर्मलजीत सिंह कलसी, एनसीवीईटी के अध्यक्ष, प्रोफेसर नागेश्वर राव कुलपति, इग्नू और सुश्री त्रिशालजीत सेठी प्रशिक्षण महानिदेशक उपस्थित थे।

2. **प्रोजेक्ट तेजस्विनी: किशोर लड़कियों और युवा महिलाओं का सामाजिक–आर्थिक सशक्तिकरण**

शौक्षिणिक प्रशिक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 से 14 जनवरी, 2023 तक झारखंड के 6 जिलों– कोडरमा, पलामू, खूंटी, लोहरदगा, चतरा और सिमडेगा में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था। प्रशिक्षण एनआईओएस नोएडा के शौक्षिणिक संकाय और एनआईओएस रांची अध्ययन केंद्रों के सर्वश्रेष्ठ विषय समन्वयकों द्वारा दिया गया था।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुचारू और कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करके एनआईओएस क्षेत्रीय निदेशक रांची द्वारा शैक्षणिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण की निगरानी की गई।

कार्यक्रम के तहत झारखंड के 17 जिलों की किशोरियों और युवतियों को नामांकित किया गया है। पहला बैच अक्टूबर, 2023 में आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में उपस्थित हुआ। कुल 7153 नामांकन संख्या पूरी तरह से एपीआई एकीकरण के माध्यम से एनआईओएस एमआईएस से तेजस्विनी एमआईएस के साथ साझा की गई।

3. **विभिन्न पाठ्यक्रमों में एसएलएम का विकास**

माध्यमिक स्तर पर एसएलएम का विकास/संशोधन:

- नाट्यकला
- भण्डारण सिद्धांत और सूची प्रबंधन

वरिष्ठ माध्यमिक स्तर:

- नाट्यकला
- हिंदी
- बिजनेस स्टडीज
- परिवहन और गोदाम प्रबंधन
- सूची प्रबंधन
- परिवहन की मूल बातें
- चित्रकारी
- मनोविज्ञान
- भूगोल

तकनीक–आधारित उपलब्धियाँ

1. **माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर ई–विद्या (चैनल 10 और 12) पर लाइव पीसीपी सत्र के रूप में शैक्षणिक सहायता।**

एनआईओएस आईसीटी और मीडिया के विभिन्न तरीकों का उपयोग करके अपने शिक्षार्थियों को लगातार अधिगम में सहायता प्रदान कर रहा है। ई–विद्या (चैनल 10 और 12) पर इंटरएक्टिव लाइव सत्र अधिगम की निरंतरता प्रदान करते हैं। सांकेतिक भाषा और व्यावसायिक कार्यक्रम सहित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर विभिन्न विषयों में सोमवार से शुक्रवार तक

तीन घंटे के लाइव सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बधिर और श्रवण बाधित शिक्षार्थियों को सांकेतिक भाषा माध्यम में कुछ विषयों में अधिगम के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

2. **स्वयं पर एमओओसी**

स्वयं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक एमओओसी प्लेटफ़ॉर्म है और एनआईओएस माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तरों के लिए एमओओसी का एक राष्ट्रीय समन्वयक है। वर्तमान में, एनआईओएस माध्यमिक स्तर पर 18 एमओओसी पाठ्यक्रम और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 20 पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

एनईपी–2020 के संदर्भ में पहल

- **12वें विश्व हिंदी सम्मेलन में एनआईओएस की भागीदारी और 'आरंभिका' विषय का शुभारंभः**

12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी सरकार द्वारा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के सहयोग से 15 से 17 फरवरी, 2023 तक फिजी गणराज्य के नंदी में डेनाराऊ कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का मुख्य विषय "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पारंपरिक ज्ञान तकः हिंदी" था। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नोएडा के अधिकारियों ने भी भाग लिया।

15 फरवरी 2023 को उद्घाटन समारोह में, एनआईओएस की प्रारंभिक हिंदी–शिक्षण पुस्तक 'आरंभिका' का विमोचन फिजी के राष्ट्रपति, महामहिम रातू विलियम मेवालिली काटोनिवर और भारत के माननीय केंद्रीय विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर द्वारा किया गया। "आरंभिका" पाठ्यक्रम उन सभी लोगों के लिए फायदेमंद है जो हिंदी सीखना चाहते हैं और जिनकी पहली भाषा या मातृभाषा हिंदी नहीं है। इस पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षार्थी विभिन्न स्थितियों में हिंदी में सामान्य बातचीत कर सकेंगे और भारत की जीवन शैली और संस्कृति की झलक भी पा सकेंगे। यह पाठ्यक्रम अन्य देशों के नागरिकों के साथ–साथ प्रवासी भारतीयों को भी भारत से जुड़ने का अवसर प्रदान करेगा।

सम्मेलन के दौरान आयोजित विशेष प्रदर्शनी में एनआईओएस ने भी अपना स्टॉल लगाया। इस स्टॉल में एनआईओएस की प्रमुख पहल, शैक्षिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली, एनआईओएस ई–लाइब्रेरी 'दीप', भारतीय ज्ञान परंपरा पर पाठ्यक्रम के साथ–साथ नए लॉन्च किए गए पाठ्यक्रम 'आरंभिका' के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर एनआईओएस प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। सम्मेलन में एनआईओएस के भारतीय ज्ञान परंपरा पाठ्यक्रमों, विशेषकर 'आरंभिका' और 'दीप' को लेकर भारत और विदेश के प्रतिभागियों में काफी उत्साह देखा गया।

- **नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में भारतीय सांकेतिक भाषा में निबंध प्रतियोगिता**

एनआईओएस ने 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया । एनआईओएस ने 27 फरवरी, 2023 को प्रगति मैदान, नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले में भारतीय सांकेतिक भाषा में एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया। यह बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों को एक मंच प्रदान करने के लिए एनआईओएस की एक अनूठी पहल थी। एनआईओएस विभिन्न तरीकों से एनईपी–2020 के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहा है और यह पहल वास्तव में उस दिशा में एक पहल कदम है। एनआईओएस के विभिन्न अध्ययन केंद्रों से कुल 24 बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों ने इस प्रतियोगिता

में बड़े उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी का प्रमाण पत्र दिया गया। जूरी सदस्यों ने बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा के लिए एनआईओएस द्वारा की गई विभिन्न अनूठी पहलों की सराहना की।

एनआईओएस ने 4 मार्च, 2023 को नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और ओडीएल परिप्रेक्ष्य' पर एक पैनल चर्चा का भी आयोजन किया। एनआईओएस की अध्यक्ष प्रोफेसर सरोज शर्मा ने राष्ट्रीय शैक्षिक नीति–2020 के कार्यान्वयन में एनआईओएस द्वारा किए जा रहे निरंतर प्रयासों से सभी को अवगत कराया। प्रोफेसर शर्मा ने मुख्य अतिथि श्री संजय कुमार, सचिव, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, पैनलिस्ट, दिव्यांग शिक्षार्थियों और उनके शिक्षकों और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। श्री टीडी धारियाल, पूर्व सदस्य सचिव, आरसीआई और प्रोफेसर परशुराम शर्मा, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, दिल्ली ने पैनलिस्ट के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई और 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 और ओडीएल परिप्रेक्ष्य' पर चर्चा की। पैनल ने विकलांगों के लिए शिक्षा में ओडीएल के योगदान पर प्रकाश डाला।

श्री संजय कुमार ने पठन की आदत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि गहन अध्ययन को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। उन्होंने न केवल शिक्षा के लिए बल्कि जीवन भर के लिए अधिगम को एक आनंददायक अनुभव के अवसर के रूप में पेश करने की बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती के लिए एनआईओएस की सराहना की। उन्होंने कहा कि एनआईओएस एनईपी–2020 के कार्यान्वयन और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक शिक्षा का विस्तार करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा। उन्होंने भारतीय ज्ञान परंपरा धारा के तहत माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अंग्रेजी में संस्कृत साहित्य पर स्व–शिक्षण सामग्री जारी की और एनआईओएस को पढ़ने और समाज की सेवा करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने हेतु प्रोफेसर शर्मा को बधाई दी।

भारत सरकार के माननीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष सरकार जी ने भी 28 फरवरी, 2023 को विश्व पुस्तक मेले में एनआईओएस के स्टॉल का दौरा किया। उन्होंने एनआईओएस की पहल और कार्यों की सराहना की और भविष्य के प्रयासों के लिए बधाई भी दी।

- **बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसई), पटना के अधिकारियों के साथ बैठक के माध्यम से एनईपी कार्यान्वयन और एसओएस को मजबूत करना**

एनईपी 2020 के अनुसरण में, एनआईओएस 'सभी के लिए शिक्षा' मिशन के साथ देश में मुक्त विद्यालयी शिक्षा को बढ़ावा देने और विस्तार के लिए सभी राज्य मुक्त विद्यालयों का समर्थन कर रहे हैं।

इस संदर्भ में, बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा बोर्ड (बीबीओएसई) पटना के चार अधिकारियों की टीम के साथ 12 और 13 अक्टूबर, 2023 को एनआईओएस मुख्यालय, नोएडा, यूपी में दो दिवसीय बैठक आयोजित की गई। उन्होंने एनआईओएस की विभिन्न पहलों और ओडीएल प्रणाली के बारे में जानने के लिए एनआईओएस का दौरा किया है। एनआईओएस के सभी विभागों ने विभिन्न गतिविधियों को विस्तार से प्रस्तुत किया और अपने प्रश्नों का समाधान भी किया। इस बातचीत से उन्हें भविष्य में बीबीओएसई को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

सहयोग

1. द्वितीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), भारतीय लोकाचार में निहित 21वीं सदी के कौशल के लिए शिक्षार्थियों को तैयार करने के माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप एनईपी—2020 के कार्यान्वयन की दिशा में लगातार कार्य कर रहा है। एनआईओएस ने एनईपी—2020 की तीसरी वर्षगांठ और दूसरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम के जश्न के अवसर पर 29 जुलाई, 2023 को इस वर्षगांठ में भाग लिया और समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, डॉ. सुभाष सरकार, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजकुमार रंजन सिंह, माननीय विदेश और शिक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, और प्रोफेसर सरोज शर्मा, अध्यक्ष, एनआईओएस, डॉ. राजीव कुमार सिंह, प्रभारी सचिव एवं निदेशक (शैक्षणिक) की उपस्थिति में एमओयू का आदान—प्रदान किया गया। एनआईओएस की ओर से एनआईओएस से एमओयू पर हस्ताक्षरकर्ता था।

इस अवसर पर निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये:

(i) एनआईओएस ने भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी), दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ भारतीय सांकेतिक भाषा के मानकीकरण और भारतीय सांकेतिक भाषा में विशेष रूप से एसटीईएम विषयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के विकास के लिए विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। श्री मृत्युंजय झा, उप सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी और निदेशक, आईएसएलआरटीसी ने समारोह की शोभा बढ़ाई।

(ii) एनआईओएस ने सार्वजनिक सेवा केंद्रों (सीएससी), ई—गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक समझौता किया। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य एनआईओएस में स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) को प्रवेश की सुविधा प्रदान करना, नामांकन बढ़ाना और शिक्षार्थियों को ई—सेवा सुविधाएं प्रदान करना है।

(iii) एनआईओएस ने संस्थानों के बीच शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू), नई दिल्ली के साथ एक

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य मूल्यवर्धित पहल और कौशल–वृद्धि पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण मॉड्यूल बनाना है।

2. एनडीआरएफ के साथ समझौता ज्ञापन

एनआईओएस और एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल) के बीच 22 नवंबर, 2023 को एनडीआरएफ मुख्यालय में अध्यक्ष एनआईओएस प्रोफेसर सरोज शर्मा और महानिदेशक एनडीआरएफ श्री अतुल करवाल, आईपीएस की गरिमामयी उपस्थिति में संवादात्मक अंग्रेजी में अल्पावधि सर्टिफिकेट कोर्स के शुभारंभ के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। हस्ताक्षरकर्ताओं में डॉ. राजीव कुमार सिंह एनआईओएस, निदेशक (शैक्षणिक) और श्री मोहसिन शाहदी, डीआइजी,एनडीआरएफ मुख्यालय (टीआरएन एवं ऑप्स) शामिल थे।

अन्य पहल

1. शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए जेंडर ग्रीन टीचर कार्यक्रम को अपनाने पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए अपने ज्ञान को समृद्ध करने और शिक्षार्थियों को उनके कार्यों और व्यवहार में भारत और दुनिया भर में जेंडर और पर्यावरण के बारे में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु प्रेरित करने में सहायता करने के लिए 27 और 28 जून 2023 को कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग के सहयोग से एनआईओएस मुख्यालय नोएडा में दो दिवसीय "जेंडर ग्रीन टीचर प्रोग्राम को अपनाने संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला" का आयोजन किया है।

पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत, एनसीईआरटी की पूर्व निदेशक सुश्री प्राची पांडे, संयुक्त सचिव (संस्था), स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार, सम्मानित अतिथि और विशिष्ट अतिथि सुश्री केसांग शेरपा, सदस्य सचिव, एनसीटीई; डॉ. बशीरहमद शद्रच, निदेशक, सीईएमसीए (सीओएल); और प्रोफेसर सरोज शर्मा, अध्यक्ष, एनआईओएस; डॉ. राजीव कुमार सिंह निदेशक (शैक्षणिक) ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई और एनआईओएस के सभी विभागाध्यक्षों के साथ–साथ कर्मचारियों, शिक्षाविदों और भारत सहित नौ देशों के प्रतिष्ठित विद्वानों ने कार्यशाला में भाग लिया।

कार्यशाला का उद्देश्य शिक्षकों को अपनी कक्षाओं में जेंडर और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक उपकरण देना था। एसडीजी4 के घटक पाठ्यक्रम को उजागर करते हैं, और यह एसडीजी 5 (महिला समानता) और एसडीजी 13 (जलवायु कार्रवाई) जैसे अन्य एसडीजी को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। छात्र दूरस्थ एवं मुक्त शिक्षा (ओडीएल) डिलीवरी प्रारूप के माध्यम से पाठ्यक्रम सामग्री, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग, स्व–मूल्यांकन, असाइनमेंट और ऑनलाइन परीक्षाओं तक अपनी गति से पहुंच सकते हैं। इस माध्यम से, शिक्षक समान विचारधारा वाले पेशेवरों के साथ नेटवर्क बना सकते हैं जिनकी जेंडर समानता और पारिस्थितिक स्थिरता में रुचि है। कार्यशाला की योजना संस्थानों को जेंडर ग्रीन टीचर कार्यक्रम को संशोधित करने और प्रदान करने के लिए कार्य योजना तैयार करने में सहायता करने हेतु बनाई गई थी, जिससे ऐसा करने की उनकी क्षमता में वृद्धि होगी।

इस दो दिवसीय कार्यशाला में जेंडर ग्रीन टीचर कार्यक्रम का परिचय, पाठ्यचर्या एकीकरण, पाठ्यक्रम का अनुकूलन एवं कार्यान्वयन जैसे विभिन्न विषयों पर प्रतिभागियों के बीच विस्तृत विचार–विमर्श हुआ। प्रतिभागियों द्वारा संस्थागत कार्य योजनाएँ तैयार और प्रस्तुत की गईं। कार्य योजना और अगले चरणों पर विस्तृत चर्चा और संस्थागत कार्य योजनाओं की पूर्ण प्रस्तुति के साथ कार्यशाला सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

2. परख पर क्षेत्रीय कार्यशाला में एनआईओएस की भागीदारी

परख (समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण)–एनसीईआरटी

की एक घटक इकाई ने नागालैंड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सहयोग से 24 से 27 जुलाई 2023 तक कोहिमा नागालैंड में स्कूल मूल्यांकन और परीक्षा प्रथाओं और बोर्डों की समकक्षता के अध्ययन पर चार दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य देश में शैक्षिक बोर्डों की बदलती गुणवत्ता और मानकीकरण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करना और संभावित समाधान तलाशना था। इस कार्यशाला में एनआईओएस के शैक्षणिक, मूल्यांकन और प्रशासन विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने भाग लिया।

3. एनआईओएस की एचटी शिखर सम्मेलन में भागीदारी

एनआईओएस ने 28/08/2023 को हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा आयोजित "नीति प्रतिमानः भारत में शिक्षा सुधारों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करना" विषय पर शिक्षा शिखर सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत में प्रगतिशील शिक्षा के लिए शिक्षा सुधारों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने और विचारों का आदान–प्रदान करने के लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों और दूरदर्शी लोगों को एक साथ लाना था।

एक पैनलिस्ट के रूप में, एनआईओएस अध्यक्ष, प्रोफेसर सरोज शर्मा ने "उच्च शिक्षा में परिवर्तनः गुणवत्ता, पहुंच और रोजगार योग्यता" विषय पर बात की और संक्षेप में उल्लेख किया कि एनईपी 2020 के तहत शुरू किए गए शिक्षा सुधारों को लागू करने के लिए एनआईओएस ने अब तक क्या किया है और वंचित बच्चों तक पहुंचने' और 'स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए का उल्लेख किया। एनआईओएस द्वारा अपनाई गई योजनाओं और नीतियों '

एनआईओएस टीम ने प्रतिभागियों के साथ बातचीत की और एनईपी और एनसीएफ दिशानिर्देशों पर विचारों का आदान–प्रदान किया, इसके बाद नीति निर्माताओं और शिक्षकों के साथ संपर्क स्थापित किया।

4. 34वां स्थापना दिवस समारोह

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान ने 23 नवंबर 2023 को नोएडा में देश के प्रसिद्ध शिक्षाविदों की शुभ उपस्थिति में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। स्थापना दिवस समारोह में श्री संजय कुमार, आईएएस, सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और डॉ. सोनल मानसिंह, पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता और माननीय संसद सदस्य, राज्यसभा, प्रोफेसर शशिकला वंजारी कुलपति, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान, प्रोफेसर गिरीश नाथ झा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, सुश्री कांता, संयुक्त राष्ट्र महिला, उप देश प्रतिनिधि, भारत विशिष्ट अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर एनआईओएस जेंडर पॉलिसी जारी की गई। इस अवसर पर आरंभिका पोर्टल भी लॉन्च किया गया।

आरंभिका पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदी में सामान्य बातचीत करने की क्षमता विकसित करना और भारतीय लोकाचार और संस्कृति की झलक प्रदान करना है।

इस अवसर पर एनआईओएस के गौरवान्वित शिक्षार्थियों को भी सम्मानित किया गया।

- **एनआईओएस ने स्कूल से बाहर के बच्चों (ओओएससी) के प्रवेश के संबंध में** एसईएमएएम, समग्र शिक्षा, मेघालय सरकार के साथ दिनांक 27 मई, 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

- **एनआईओएस** ने उन सभी जैन भिक्षुओं और ननों को शिक्षा प्रदान करने के लिए **जैन श्वेतांबर थेरापंथी महासभा (जेएसटीएम) के साथ 3 अक्टूबर, 2023 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए,** जो समाज कल्याण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं।
- **एनआईओएस** ने ग्रामपंचायत (जीपी) पुस्तकालयों में दाखिला लेने वाले सभी लोगों को व्यावसायिक और शैक्षणिक पाठ्यक्रमों से संबंधित शिक्षण संसाधन प्रदान करने के लिए 5 अक्टूबर, 2023 को पंचायत राज आयुक्तालय कालिसदास स्ट्रीट, केजी रोड, बेंगलुरु – 560009 के साथ **एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।**

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई):

परियोजनाएं	उपलब्धियां
शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (एनपीएसटी)	• एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज अंतिम अनुमोदन के लिए जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है। • प्रायोगिक अध्ययन 2022 में शुरू किया गया था और 2023 में एनपीएसटी मार्गदर्शक दस्तावेज़ के कार्यान्वयन और प्रभाव मूल्यांकन को देश भर में 1175 शिक्षकों के साथ 75 केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले स्कूलों (25 केवीएस + 25 एनवीएस + 25 सीबीएसई) में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया है। • कुल 15 ओपन हाउस चर्चाओं में से 7 चर्चाएं 2022 में आयोजित की गईं और शेष 8 चर्चाएं 2023 में आयोजित की गईं। इसके बाद, सुझावों को मसौदा मार्गदर्शक दस्तावेज़ में शामिल किया गया। • यादृच्छिक नमूनाकरण के साथ चुने गए 22 शिक्षकों के साथ एक फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई थी; इनमें से 20 ने नमूना सर्वेक्षण का जवाब दिया। एफजीडी और सर्वेक्षण दोनों का उद्देश्य पूरे प्रायोगिक परियोजना पर प्रतिक्रिया प्राप्त करना और इसे आगे बढ़ाने पर सुझाव प्राप्त करना था। • 5 इन–हाउस परामर्श सत्र आयोजित किए गए।
राष्ट्रीय परामर्श मिशन (एनएमएम	• एनएमएम वेब पोर्टल को परामर्श सत्रों की सुविधा के लिए विकसित किया गया था। • 12 पहचाने गए डोमेन से 60 सलाहकारों (केवीएस) और जेएनवी से 16–16 सलाहकार और एनसीटीई से 28 सलाहकार) को शामिल किया गया। • 31 मई और 1 जून 2023 को 60 ऑनबोर्ड मेंटर्स के लिए 2–दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित की गई थी। • एनसीटीई ने 14 जुलाई 2023 को एनएमएम प्रायोगिक अध्ययन के लिए नामांकित 30 स्कूलों के संभावित मेंटीज़ के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया। • एनएमएम वेब पोर्टल पर समूह और व्यक्तिगत दोनों परामर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। अब तक, 681 मेंटीज़ को कवर करते हुए 49 सत्र आयोजित किए गए हैं। • एनएमएम पर अंतिम मसौदा ब्लूबुक जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय को प्रस्तुत की गई है और अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

परियोजनाएं	उपलब्धियां
एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम (आईटीईपी)	• एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2023–24 से आईआईटी, एनआईटी, आरआईई, केंद्रीय/राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों/संस्थानों और सरकारी कॉलेजों सहित 42 संस्थानों में आईटीईपी की शुरूआत की है। • पाठ्यचर्या की रूपरेखा और पाठ्यक्रम की डिजाइनिंग और विकास पूरा कर लिया गया है और सभी हितधारकों को भेज दिया गया है। • आईटीईपी के दूसरे चरण के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए पोर्टल 1 मई 2022 से 31 मई 2023 तक खुला था। • पहले चरण में मान्यता प्राप्त 42 संस्थानों के लिए आरआईई शिलांग, आरआईई भुवनेश्वर, आरआईई भोपाल, अशोका होटल, दिल्ली और आरआईई मैसूर में 24 अगस्त से 2 सितंबर 2023 तक 5 सूचना साझाकरण सत्र आयोजित किए गए। • 8 व्यक्तिगत हैंडहोल्डिंग सह सूचना साझाकरण सत्र पूरे हो गए हैं और शेष संस्थानों के लिए कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है।
4– वर्षीय शारीरिक शिक्षा	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
4– वर्षीय शारीरिक शिक्षा	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
4– वर्षीय कला शिक्षा	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
4– वर्षीय योग शिक्षा	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
4– वर्षीय संस्कृत	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
1– वर्षीय बी. एड.	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
2– वर्षीय बी. एड.	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)
ओडीएल कार्यक्रम	निम्नलिखित दस्तावेजों के डिजाइन और विकास के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है: 1– पाठ्यचर्या की रुपरेखा, 2– मानदंड और मानक, 3– पाठ्क्रम (सांकेतिक)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

सीबीएसई भारत में स्कूली शिक्षा का एक राष्ट्रीय बोर्ड है जो शिक्षा मंत्रालय और सचिव (स्कूल शिक्षा और साक्षरता) के तहत नियंत्रण प्राधिकरण के क रूप में कार्य करता है। बोर्ड भारत और 25 अन्य देशों में निजी (स्वतंत्र) से लेकर सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संबद्ध स्कूलों की एक विविध श्रेणी को पूरा करता है। बोर्ड को जनादेश दिया गया है;

- बोर्ड परीक्षाओं के उद्देश्य से पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम तैयार करना
- माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के लिए बोर्ड परीक्षा और ऐसी अन्य परीक्षाएं आयोजित करना, जिन्हें वह नियंत्रण प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन उचित समझे।
- संबद्ध स्कूलों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित करना
- शिक्षकों का व्यावसायिक विकास करना और छात्र संवर्धन गतिविधियों का आयोजन करना।

संगठनात्मक आरेख

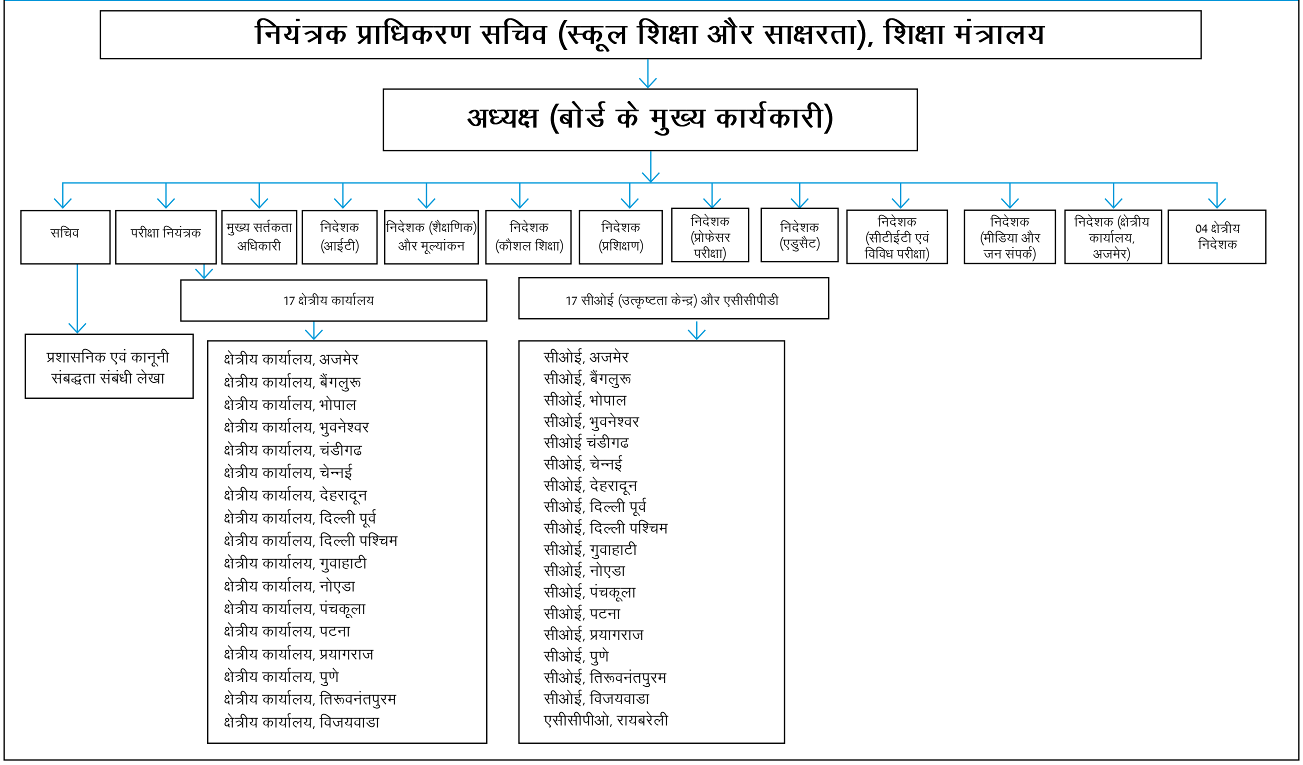

इस वर्ष बोर्ड ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिनांक 08.02.23 को विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में 17वां क्षेत्रीय कार्यालय और सीओई जोड़ा। क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा शैक्षणिक सत्र 2023–24 से बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करेगा।

I. संबद्धता इकाई

दिनांक 10.1.2024 के अनुसार संबद्ध स्कूलों की स्थिति

स्कूलों की कुल संख्या : 28973, भारत में: 28717, भारत के बाहर: 256

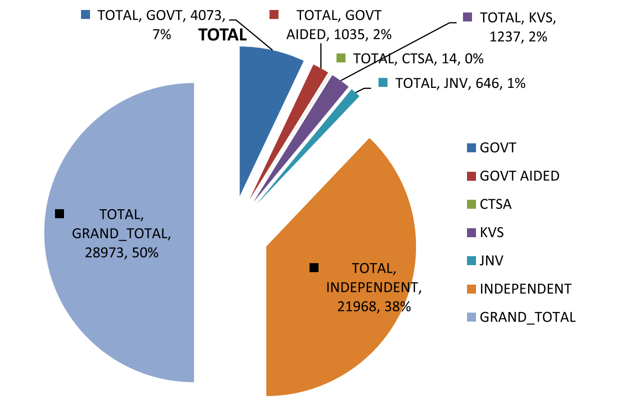

1022 स्कूलों को नई संबद्धता प्रदान की गई, जबकि 555 स्कूलों की स्थिति को माध्यमिक/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर अपग्रेड किया गया और 5530 स्कूलों को 01.01.2023 से 31.12.2023 के दौरान पांच साल की अगली अवधि के लिए संबद्धता का विस्तार दिया गया।

शैक्षणिक वर्ष 2023–24 के लिए नए स्कूलों से आवेदन की अवधि मई 2023 में सरस–4.0 में शुरू की गई थी। अनुपालन पोर्टल यह सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था कि स्कूल संबद्धता/विस्तार के समय दी गई शर्तों का पालन करें।

- शैक्षणिक सत्र 2023–24 से फाउंडेशनल स्टेज–2022 के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया।
- सभी स्कूलों को सत्र 2024–25 और उसके बाद से सरस पोर्टल पर नई संबद्धता/स्विच ओवर/अप–ग्रेडेशन/विस्तार के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और आश्वासन फ्रेमवर्क (एसक्यूएएएफ) के तहत अनिवार्य पूर्व स्व–मूल्यांकन भरने का निर्देश दिया गया था।
- शैक्षणिक सत्र 2024–25 से मध्यम वर्ग संबद्धता के अनुमोदन हेतु आवेदन करने वाले स्कूलों की अनुदान शर्तों में उन्नयन के लिए आवेदन करने हेतु 05 वर्ष की समय सीमा जोड़ी गई।
- आवासीय विद्यालयों के लिए दिशानिर्देश 01.09.2023 को जारी किए गए थे।

II. शैक्षणिक इकाई

- **एनईपी 2020 के आलोक में परीक्षा सुधारः** वर्ष 2023 में, दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 50% योग्यता आधारित प्रश्न और बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 40% क्षमता निर्माण प्रश्न शामिल किए गए थे।
- **किशोर सहकर्मी शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम** – सीबीएसई ने छात्रों के जीवन कौशल और समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए किशोर सहकर्मी शिक्षक नेतृत्व कार्यक्रम शुरू किया। वर्ष 2023 में विभिन्न विषयों पर केंद्रित चार क्षेत्रीय स्तर के शिखर सम्मेलन और दो राष्ट्रीय स्तर के शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनमें प्रत्येक में लगभग 500 से 830 प्रतिभागी एकत्र हुए। दिल्ली में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में 2000 प्रतिभागी थे।
- **सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों में बहुभाषी शिक्षा और शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग**– एनईपी की सिफारिश को लागू करने के लिए, स्कूलों को मौजूदा विकल्पों के साथ–साथ, बुनियादी चरण से माध्यमिक चरण के अंत तक शिक्षा के माध्यम के रूप में भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं का उपयोग करने पर विचार करने के लिए कहा गया था।
- **शिक्षक पुरस्कार** – सीबीएसई द्वारा नामांकित दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से नवाजा गया।

- **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की तीसरी वर्षगांठ**– सीबीएसई ने 29 जुलाई, 2023 से 28 अगस्त, 2023 तक सभी स्कूलों में 'सीबीएसई – एक बच्चा, एक पौधा अभियान' नामक एक विशाल वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया। गतिविधियों में 2396 स्कूलों और 3,06,767 छात्रों ने भाग लिया।
- **सीबीएसई द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट शून्य** – छात्रों को स्थायी जीवन शैली चलाने के लिए सशक्त बनाने, हरित स्कूल परिसरों की परिकल्पना करने, पारिस्थितिक पदचिह्नों को कम करने, संसाधन दक्षता और स्वच्छ, सुरक्षित एवं स्वस्थ वातावरण के लिए सामुदायिक भागीदारी पर केंद्रित है।
- **सीबीएसई नवोदित लेखक कार्यक्रम**– रचनात्मक कार्य करवाने एवं विभिन्न प्रकार की कहानियों को पढ़ने में संलग्न करने हेतु कक्षा 5वीं से 10वीं के छात्रों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में आयोजित किया गया था। अंतिम चयन के बाद लगभग 8000 में से हिंदी में 13 कहानियाँ और अंग्रेजी में 30 कहानियाँ प्रकाशित हुईं।
- **जीवन कौशल मापन उपकरण – मिडिल स्कूल** – यह उपकरण सीबीएसई द्वारा यूनिसेफ और यंग लाइव्स इंडिया के सहयोग से तैयार किया गया है। यह ग्रेड 6–8 (आयु 11–14) के छात्रों की जरूरतों को पूरा करता है, जिसका लक्ष्य उनके समग्र विकास और कल्याण के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जीवन कौशल का आकलन और पोषण करना है।
- **स्कूलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश** – एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों से आपदा जोखिम न्यूनीकरण विषयों को एकीकृत करता है, जिससे शिक्षक सुरक्षा उपाय सिखाने में सक्षम होते हैं। कक्षा 6 से 10 के लिए सभी विषयों की पाठ्य योजनाएं कक्षाओं में आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देती हैं।
- **आर्यभट्ट गणित चैलेंज (एजीसी) 2023** – सीबीएसई ने छात्रों के दैनिक जीवन में गणित के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए वार्षिक एजीसी ऑनलाइन प्रतियोगिता की मेजबानी की। 2023 में, लगभग 5050 स्कूलों के लगभग 5,50,000 छात्र स्कूल स्तर पर शामिल हुए। इनमें से, स्कूलों द्वारा पहचाने गए 8,591 छात्र सीबीएसई द्वारा आयोजित कंप्यूटर–आधारित परीक्षा के दूसरे चरण में शामिल हुए।
- **सीबीएसई खेल** – सीबीएसई ने संबद्ध स्कूलों के लिए 23 खेलों में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कीं। वर्ष 2023–24 में 6 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय खेल विजेता सरकार के खेलो–इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए, जो बोर्ड द्वारा खेल भावना को बढ़ावा देने को दर्शाता है।
- **प्रोजेक्ट वीर गाथा 3.0** – इस आयोजन के लिए सीबीएसई को राष्ट्रीय स्तर के समन्वयक की जिम्मेदारी दी गई। वर्ष 2023 में कुल भागीदारी 1,36,00000 रही है जिसमें से 46,41,409 छात्र सीबीएसई स्कूलों से थे।
- **स्वच्छता ही सेवा विशेष अभियान 3.0** – "गांधी जयंती" के अवसर पर समाज में स्वच्छता, साफ–सफाई और स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए "श्रमदान" करके छात्रों, शिक्षकों और समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ 'स्वच्छता ही सेवा' अभियान चलाया गया। गतिविधियों के तहत, स्कूलों से 01.10.2023 को सुबह 10:00 बजे कम से कम एक घंटे के लिए स्वच्छता अभियान – "एक तारीख एक घंटा एक साथ" चलाने का अनुरोध किया गया, जिसके परिणामस्वरूप स्कूल द्वारा चुनी गई साइट पर

साफ–सफाई दिखाई दी। अभियान में 5087 सीबीएसई स्कूलों के कुल 8,56,746 छात्रों ने भाग लिया।

- **अमृत कलश यात्राएं (मेरी माटी मेरा देश अभियान)** – मेरी माटी मेरा देश (एमएमएमडी) आजादी का अमृत महोत्सव स्मरण उत्सव का अंतिम कार्यक्रम था, जिसमें उन सभी वीरों और वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों से 656281 छात्रों और 46167 शिक्षकों के साथ–साथ अन्य समुदाय के सदस्यों ने भाग लिया।
- **चंद्रयान–3 महा क्विज** – चंद्रयान–3 मिशन की सफलता का जश्न मनाने के लिए डलळवअ प्लेटफॉर्म ने 'चंद्रयान–3 महा प्रश्नोत्तरी' का आयोजन किया। इस क्विज़ में भाग लेने के लिए, उम्मीदवारों को माईजीओवी पोर्टल पर एक व्यक्तिगत अकाउंट बनाना पड़ा। प्रश्नोत्तरी के विजेताओं को नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और सभी प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ। क्विज़ में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के कुल 4,99,474 छात्रों ने भाग लिया।
- **राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी** – लगभग 12,95,072 छात्रों ने प्रतिज्ञा लेने, दौड़, वाद–विवाद और भाषणों के आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लिया।
- **भारतीय भाषा उत्सव** – 5,50,976 छात्रों, 31,988 शिक्षकों और 98560 समुदाय सदस्यों ने भाषा विविधता का जश्न मनाने में भाग लिया। दिल्ली के अंबेडकर भवन में एक सीबीएसई स्टॉल ने स्कूलों की बहुभाषावाद रणनीतियों का भी प्रदर्शन किया।
- सीबीएसई प्रधानाचार्यों को योग्यता आधारित शिक्षा (सीबीई) को समझने और लागू करने में सक्षम बनाने हेतु विकास के लिए प्रधानचार्य योजना, प्रयोग शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम में 9605 प्रिंसिपलों ने भाग लिया और लगभग 5320 पोस्ट ट्रेनिंग टेस्ट पास करने में सफल रहे।
- **सीबीएसईः जी20–राज्य स्तरीय सम्मेलन** – जी–20 देशों के शैक्षिक कार्य समूह ने "एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य" की थीम के तहत सभी के लिए समावेशी, न्यायसंगत, प्रासंगिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आजीवन अधिगम के अवसर सुनिश्चित करने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया। जी–20 की तर्ज पर, सीबीएसई ने देश भर में 36 जी20 दो दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किए जो जीवन कौशल, मानसिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित थे।
- **एनईपी पर सम्मेलनः** देश भर में अब तक 7 स्थानों पर परिवर्तनकारी नेतृत्व पर जोर देने के साथ शैक्षणिक, कौशल शिक्षा और प्रशिक्षण में बोर्ड द्वारा की गई एनईपी 2020 पहल के बारे में चर्चा करने के लिए प्रधानाचार्यों के लिए विशेष एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इन सम्मेलनों में कुल 1935 प्राचार्यों ने भाग लिया।

अधिगम संसाधन – निम्नलिखित नव विकसित शिक्षण संसाधनों को बोर्ड की वेबसाइट पर स्कूलों के लिए अपलोड किया गया थाः

- मिडिल स्कूल के लिए जीवन कौशल मापन उपकरण
- कक्षा 6, 7, 8 के लिए–विज्ञान और गणित में अभ्यास पुस्तक,
- स्कूलों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और अंक रहित प्रतिक्रिया वाले प्रश्न बनाने पर शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश,

- रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में कक्षा 12 और विज्ञान में कक्षा 10 के लिए योग्यता–केंद्रित अभ्यास प्रश्न,
- सीबीएसई नवोदित लेखक कार्यक्रम की कहानियां पुस्तिकाएं,
- प्रोजेक्ट शून्य पुस्तिका,
- कक्षा IX और XI के लिए अरबी पाठ्यपुस्तकें,
- प्रोटोटाइप – समग्र प्रगति कार्ड बुनियादी चरण (आयु समूह 3–6 वर्ष और क्षमता निर्माण पाठ्यक्रम
- 'क्लास रूम में एआई के उपयोग' पर मैनुअल।

III. प्रशिक्षण इकाई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 खंड 5.15 में सिफारिश करती है कि प्रत्येक शिक्षक से अपने स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए, अपने स्वयं के हितों से प्रेरित होकर, प्रतिवर्ष कम से कम 50 घंटे के सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) अवसरों में भाग लेने की उम्मीद की जाती है। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए सीबीएसई ने उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की। सीओई की स्थापना के अलावा बोर्ड ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में सतत व्यावसायिक विकास के लिए उन्नत केंद्र (एसीसीपीडी) की स्थापना की है। इस केंद्र का उद्देश्य प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण, उन्नत शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल शिक्षा, शिक्षाविदों और सीबीएसई के मौजूदा और नए कर्मचारियों के प्रशिक्षण का ध्यान रखना है। उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) बोर्ड के संबद्धता उपनियमों के अनुसार बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) संचालित करते हैं, जो प्रत्येक शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के लिए अनिवार्य वार्षिक सेवाकालीन प्रशिक्षण निर्धारित करते हैं। सीबीएसई– सीबीपी को दो श्रेणियों; सामान्य और विषय विशिष्ट कार्यक्रम में व्यवस्थित किया गया है। वर्तमान में सीबीएसई–सीओई द्वारा सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए 58 सीबीपी की पेशकश की जा रही है।

ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र:

कुल मिलाकर, 17 सीओई द्वारा 01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक 4,33,279 घंटों का शिक्षकों के लिए कुल 1209 ऑनलाइन सत्र आयोजित किए गए।

ऑफ़लाइन/आमने–सामने क्षमता निर्माण कार्यक्रमः

3,28,761 शिक्षकों के लिए 01 जनवरी से 31 दिसंबर, 2023 तक 6630 ऑफ़लाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किए गए।

पीएम–ईविद्या सीबीएसई 15 टीवी चैनल

शिक्षा मंत्रालय ने 200 पीएम–ईविद्या चैनलों में से सीबीएसई के लिए एक टीवी चैनल आवंटित किया; जो शिक्षकों के प्रशिक्षण पर केंद्रित होगा। इसके परिणामस्वरूप, सीआईईटी, एनसीईआरटी द्वारा प्रशिक्षण इकाई के अधिकारियों, सीओई के प्रमुखों और विषय विशेषज्ञों के लिए 17 से 19 अप्रैल, 2023 और 24 से 26 अप्रैल, 2023 तक दो अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन दो बैचों में 40 प्रतिभागियों का अभिमुखीकरण किया गया। टीवी चैनल "पीएम–ईविद्या सीबीएसई 15" का बीटा रन शुरू हो गया है। बीटा रन में 219 वीडियो का उपयोग किया जा रहा है। ये वीडियो सीबीएसई स्कूलों, सीआईईटी एनसीईआरटी स्टूडियो में तैयार किए गए हैं।

सीपीडी प्रशिक्षण का ट्रैकिंग रिकॉर्ड – सीबीएसई प्रशिक्षण त्रिवेणी प्रशिक्षण पोर्टल

शिक्षकों के प्रशिक्षण रिकॉर्ड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए, सीबीएसई ने 31.03.2023 को एक नया पोर्टल, "प्रशिक्षण त्रिवेणी" लॉन्च किया है, जो ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पंजीकरण, उपस्थिति अंकन, फीडबैक सबमिशन और प्रमाणन के लिए एक एकीकृत मंच प्रदान कर रहा है।

नव संबद्ध विद्यालयों के लिए प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (गुरु दक्षता)

नव विकसित इंडक्शन ट्रेनिंग (गुरु दक्षता) कार्यक्रम का लक्ष्य बोर्ड के नए संबद्ध स्कूलों के साथ–साथ मौजूदा सीबीएसई संबद्ध स्कूलों के प्रिंसिपलों और शिक्षकों को उनकी भूमिकाओं में सफल होने और सीबीएसई प्रणाली में उनके सुचारू रूप से शामिल होने के लिए आवश्यक क्षमताओं और संसाधनों से सुसज्जित करना है। यह कार्यक्रम शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों को सीबीएसई के सभी घटक विभागों/इकाइयों जैसे प्रशिक्षण, परीक्षा, संबद्धता, शैक्षणिक, कौशल शिक्षा, आईटी, व्यावसायिक परीक्षा, सीटीईटी, सीओई, आरओ की संरचना, नीतियों और दिशानिर्देशों से परिचित कराता है।

मार्गदर्शन और परामर्श पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन 10–11 अक्टूबर, 2023 को गुवाहाटी (असम) में आयोजित किया गया था। सम्मेलन में 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/विदेशी स्कूलों के 879 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन और राष्ट्रीय सहोदय सम्मेलन, मुंबई में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जैसे सामान्य पाठ्यक्रमों और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा पर विशिष्ट कार्यक्रम – बुनियादी चरण, ज्ञान का सिद्धांत, सक्रिय शिक्षण, शिक्षा के बारे में माता–पिता को शिक्षित करना, शिक्षाशास्त्र के रूप में कहानी सुनाना, पर्यावरण शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और कक्षाओं में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग पर 12 नए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू किए गए।

वेबिनार की सार्थक श्रृंखला

पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियों जैसे कि भारत में महिला शिक्षा को प्रभावित करने वाली सावित्रीबाई फुले, दृष्टिबाधित छात्रों के लिए लुईस ब्रेल, भारतीय दर्शन और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओं, सड़क सुरक्षा, यूनेस्को के सहयोग से 'स्कूल स्वास्थ्य और कल्याण कार्यक्रम के अतिरिक्त पुस्तकालयों के उपयोग को बढ़ावा देना और पठन की आदतों को विकसित करना', एनईपी–2020 में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ वैयक्तिकृत अधिगम के महत्व पर बल देने हेतु 'योग्यता आधारित मूल्यांकन' संबंधी कई वेबिनार आयोजित किए गए।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों के लिए 'परीक्षा पे चर्चा' पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया।

IV. परीक्षा यूनिट

(X – XII) बोर्ड परीक्षा–2023 की महत्वपूर्ण जानकारी

स्कूलों और परीक्षा केंद्रों की कुल संख्या (पूर्ण विषय)	भारत और 26 देशों में 28471 स्कूल
पंजीकृत छात्र (X और XII)	2186485 (X) + 1696349 (XII) = कुल 3882834
छात्र और विषय (X और XII)	21786733
परीक्षा केंद्र	7241
केंद्र अधीक्षक	7241
केंद्र उप अधीक्षक	7241
परीक्षा के लिए प्रयुक्त कक्षाएँ	907781
निरीक्षक	1815561
प्रस्तावित विषय (X और XII)	76 (X) + 115 (XII) = 191 कुल

मूल्यांकन केंद्र	3578
मूल्यांकन केंद्रों पर केंद्र नोडल पर्यवेक्षक	3578
उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया	21786733
मूल्यांकन के लिए मूल्यांकनकर्ता तैनात	1089337
मूल्यांकन हेतु सहायक प्रधान परीक्षक प्रतिनियुक्त किये गये	272335
प्रधान परीक्षक	68084
समन्वयक	272335
प्रेक्षक	22913
कंप्यूटर शिक्षक	14594
सहायता के लिए नियुक्त व्यक्ति	165235

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा 10) परिणाम 2023

परीक्षा की अवधिः	15 फरवरी से 21 मार्च, 2023
परिणाम घोषणा की तिथिः	12 मई, 2023

कुल उत्तीर्ण प्रतिशत (पूर्ण विषय)

वर्ष	पंजीकृत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण %
2023	2184117	2165805	2016779	93.12

क्षेत्र–वार उत्तीर्ण : 2023

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	उत्तीर्ण %
1	तिरुवनंतपुरम	99.91
2	बेंगलुरु	99.18
3	चेन्नई	99.14
4	अजमेर	97.27
5	पुणे	96.92
6	पटना	94.57
7	चंडीगढ़	93.84
8	भुबनेश्वर	93.64
9	प्रयागराज	92.55
10	नोएडा	92.50
11	पंचकुला	92.33
12	भोपाल	91.24
13	दिल्ली–पश्चिम	90.67
14	देहरादून	90.61
15	दिल्ली–पूर्व	88.30
16	गुवाहाटी	76.90

सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (बारहवीं कक्षा) परिणाम 2023

परीक्षा की अवधि	15 फरवरी 2023 से 05 अप्रैल, 2023 तक
परिणाम घोषणा की तिथि	12 मई, 2023

कुल उत्तीर्ण प्रतिशत (पूर्ण विषय)

वर्ष	पंजीकृत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	उत्तीर्ण %
2023	1680256	1660511	1450174	87.33

क्षेत्रवार उत्तीर्ण : 2023

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	उत्तीर्ण %
1	त्रिवेन्द्रम	99.91
2	बेंगलुरु	98.64
3	चेन्नई	97.40
4	दिल्ली–पश्चिम	93.24
5	चंडीगढ़	91.84

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	उत्तीर्ण %
6	दिल्ली–पूर्व	91.50
7	अजमेर	89.27
8	पुणे	87.28
9	पंचकूला	86.93
10	पटना	85.47
11	भुबनेश्वर	83.89
12	गुवाहाटी	83.73
13	भोपाल	83.54
14	नोएडा	80.36
15	देहरादून	80.26
16	प्रयागराज	78.05

छात्रों को दस्तावेजों की उपलब्धता:

परिणाम घोषित होते ही छात्रों को उनके डिजीलॉकर में परिणाम दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए थे। डिजिलॉकर तक पहुंचने की समस्या से बचने के लिए, इस साल सीबीएसई ने स्कूलों को पहले से ही पिन उपलब्ध कराया था, जिसे परिणाम घोषित होने से पहले उम्मीदवारों को दिया जाएगा।

इसके अलावा, बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के अलावा छात्रों को मुद्रित अंक पत्र सह उत्तीर्णता प्रमाणपत्र भी प्रदान किया।

परीक्षा का सत्यापन, फोटोकॉपी और पुनर्मूल्यांकन:

सीबीएसई ने छात्रों को अपने अंकों को सत्यापित करने, फोटोकॉपी प्राप्त करने और पुनर्मूल्यांकन के लिए पहले के वर्षों की तरह सुविधाएं प्रदान कीं। इस संबंध में अलग से नोटिस जारी किया गया था।

कम्पार्टमेंट परीक्षाओं के दौरान सुधार का अवसर:

जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में परिकल्पना की गई है कि छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए अधिक अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, इसलिए, बारहवीं कक्षा के छात्रों को कम्पार्टमेंट परीक्षा में 01 (एक) विषय में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की अनुमति दी गई।

कम्पार्टमेंट एवं इंप्रूवमेंट परीक्षा 2023

सीनियर स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा (बारहवीं कक्षा)

परीक्षा की तिथि	17 जुलाई, 2023
परिणाम की घोषणा की तिथि	01 अगस्त, 2023
उत्तीर्ण प्रतिशत	47.50

माध्यमिक विद्यालय परीक्षा (कक्षा X)

परीक्षा की तिथि	17 जुलाई, 2023 से 22 जुलाई, 2023 तक
परिणाम की घोषणा की तिथि	04 अगस्त 2023
उत्तीर्ण प्रतिशत	47.40

V. आईटी यूनिट

1) विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर –''सागर से सारांश''

एनईपी 2020 कई पहलों के साथ–साथ कई आवश्यकताओं को पूरा करती है जो शिक्षा और हितधारकों के विभिन्न पहलुओं को लाभान्वित करते हैं।

एनडीईएआर अनुरूप विद्या समीक्षा केंद्र एक संस्थागत मार्ग है जो प्रमुख हितधारकों द्वारा कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए डेटा–आधारित निर्णय लेने के लिए एकीकृत और साझा 'देखने' को सक्षम बनाता है। सीबीएसई के विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश का उद्देश्य निर्णय लेने और शासन में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए ऑकड़ा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। यह सभी सीबीएसई स्कूलों, कर्मचारियों और छात्रों के ऑकड़ा को कवर करता है और सीबीएसई शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की समग्र

निगरानी को बढ़ाने के लिए उनका सार्थक विश्लेषण करता है। सीबीएसई पहले से ही अपने स्कूलों, छात्रों, शिक्षकों और बोर्ड परिणामों के बारे में ऑकड़ा एकत्र और संग्रहीत करता है। मौजूदा ऑकड़ा संसाधनों का उपयोग बोर्ड, विभागों, क्षेत्रीय कार्यालयों, स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों के लिए मार्गदर्शन और दिशा प्रदान करने के लिए अंतर्दृष्टि लाने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया गया है। सीबीएसई वीएसके सुविधा और वीएसके सॉफ्टवेयर "सागर से सारांश" को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सचिव (एसई एंड एल) द्वारा सीबीएसई अध्यक्ष, अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव, शिक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और विभिन्न स्वायत्त निकायों के प्रमुखों की उपस्थिति में शुभारंभ किया गया था।

2) व्यवधानों को रोकने और संभावित ऑकड़ा क्षति को रोकने के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी)।

3) परीक्षा– मॉड्यूल/सिस्टम निम्नलिखित मॉड्यूल/सिस्टम आईटी विभाग सीबीएसई द्वारा 2023 में विकसित और कार्यान्वित किए गए थे।

i. परीक्षा संगम – स्कूलों, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय सहित सभी प्रमुख हितधारकों से संबंधित सभी परीक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए एक व्यापक मंच।

ii. ईसीएल–परीक्षा केंद्र लोकेटर ऐपः सीबीएसई परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए एक मोबाइल ऐप जिसके माध्यम से वे केवल परीक्षा और क्रमांक दर्ज करके अपने परीक्षा केंद्र का पता लगा सकते हैं।

iii. ओईसीएमएस (ऑनलाइन परीक्षा केंद्र प्रबंधन प्रणाली): व्यापक निर्णय सहायता प्रणाली जिसमें एक पोर्टल और बैकएंड प्रणाली शामिल है जो केंद्रों और परीक्षाओं के संचालन के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्राप्त करती है जिसमें प्रश्नपत्रों के बारे में फीडबैक, उत्तर पुस्तिकाओं की पैकिंग और पर्यवेक्षकों के बारे में जानकारी भेजना आदि शामिल है।

iv. बोर्ड परीक्षाओं के लिए सीएमटीएम (गोपनीय सामग्री ट्रैकिंग और निगरानी प्रणाली) ऐपः इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के लिए तीन अलग–अलग ऐप तैयार किए गए हैं।

v. टीईटीआरए (सिद्धांत मूल्यांकन प्रवृत्ति विश्लेषण): वास्तविक समय मूल्यांकन निगरानी पर आधारित निर्णय सहायता प्रणालीः मूल्यांकन रुझानों की कल्पना, विश्लेषण और निगरानी करने के लिए वास्तविक समय मूल्यांकन निगरानी पर आधारित एक अद्वितीय पोर्टल और निर्णय सहायता प्रणाली।

vi. अक्षांश और देशांतर के आधार पर केंद्रों का सबसे कुशल और अनुकूलित चयन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र आवंटन प्रणाली (सीएएसई)।

vii. दसवीं और बारहवीं कक्षा के परीक्षा पूर्व ऑकड़ा सुधार अपलोड करने के लिए ऑनलाइन कार्यप्रवाह आधारित 'केंद्रीकृत प्रवेश मास्टर सुधार (सीएएमसी)' प्रणाली

viii. दसवीं और बारहवीं कक्षा के आंतरिक मूल्यांकन/आंतरिक ग्रेड और व्यावारिक अंक और सुधार अपलोड करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा/सैद्धांतिक अंक और आंतरिक ग्रेड सुधार (ऑप्टिक्स) प्रणाली।

ix. ऑनलाइन मैनुअल/तुलना अंक सुधार प्रणाली: दसवीं और बारहवीं कक्षा के मैनुअल/थ्योरी अंक, तुलना, गलतियाँ और सिद्धांत के छूटे अंक अपलोड करने के लिए एक पोर्टल

x. दसवीं और बारहवीं कक्षा के परिणाम के बाद के जनसांख्यिकीय ऑकड़ा में सुधार के लिए ऑनलाइन वर्कफ़्लो–आधारित 'जनसांख्यिकीय ऑकड़ा सुधार (ओपीआरडीसी)' प्रणाली।

xi. परीक्षा 2023 के लिए परीक्षा के लिए री–इंजीनियर्ड आउटलायर सिस्टम (आरओएसई) आर–5.0 आरओ स्तर पर उपचारात्मक कार्रवाई के लिए पूर्व–परिणाम घोषणा चरण में असंगत अंक मामलों का सूक्ष्मता से पता लगाने के लिए अनोखा सॉफ्टवेयर।

xii. पूरक परिणाम 2023 की घोषणा के तुरंत बाद अंक पत्र को विलय करें

4) संबद्धता, परीक्षा, प्रशिक्षण और ईएमआरएस भर्ती परीक्षा के लिए एकीकृत भुगतान प्रणाली (आईपीएस) विभिन्न हितधारकों को पारिश्रमिक के सीधे बैंक हस्तांतरण (डीबीटी) के लिए आईटी विभाग द्वारा एक ऑनलाइन मानक भुगतान प्रणाली "(आईपीएस) एकीकृत भुगतान प्रणाली" विकसित और कार्यान्वित की गई है।

5) शैक्षणिक क्षितिज– एक एकीकृत शैक्षणिक गतिविधि प्रणाली

6) खेल से प्रगति–एकीकृत सीबीएसई खेल प्रणाली

7) एक व्यापक शिक्षक प्रशिक्षण मंच ("प्रशिक्षण त्रिवेणी") जिसमें डीप ड्राइव विश्लेषण के साथ एमआईएस और बोर्ड परिणाम 2023 के साथ इसका एकीकरण शामिल है।

8) हिंदी राजभाषा पोर्टल

9) प्रवेश और भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए केविस और नविस और जेएनवीएसटी के लिए पोर्टल/प्रणाली का विकास/री–इंजीनियरिंग भी तैयार किया गया था।

पुरस्कार एवं सम्मान

'द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप' द्वारा दिए गए प्रौद्योगिकी सभा पुरस्कार 2023 (फरवरी संस्करण), (अगस्त संस्करण) और डेटा सेंटर चैंपियंस पुरस्कार 2023 और "परीक्षा संगम", "प्रशिक्षण त्रिवेणी" और 'दस्तावेज़ प्रबंधन' के कार्यान्वयन के लिए 'एंटरप्राइज़ एप्लिकेशन' की श्रेणी के तहत विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित।

VI. कौशल शिक्षा इकाई

उद्यमिता परामर्श में स्कूल शिक्षक विकास कार्यक्रम

ईडीआईआई ने सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के लिए उद्यमिता शिक्षण पर तीन ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और उनकी सीख को स्कूलों और छात्रों तक पहुंचाने के लिए 1500 स्कूल शिक्षकों का एक पूल तैयार किया।

सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्यों के लिए एक्सपोजर विजिट

वर्ष 2023 में, केविस, जनवि, ईएमआरएस, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के कुल 1,076 स्कूल लीडरों ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) के एक्सपोजर विजिट में भाग लिया।

स्कूलों में उभरती प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन को बढ़ावा देना

सीबीएसई नियमित रूप से इंटेल, आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, एआरएम स्कूल प्रोग्राम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मेटा, कोडिंग, डेटा साइंस, फिजिकल कंप्यूटिंग, हाइब्रिड लर्निंग, 21वीं सदी लर्निंग डिजाइन (सीएलडी) कौशल, डिजिटल नागरिकता, संवर्धित वास्तविकता/

आभासी वास्तविकता जैसे संगठनों के सहयोग से शिक्षकों के साथ–साथ छात्रों के लिए जागरूकता और क्षमता निर्माण सत्र आयोजित करता है।

सभी के लिए एआई	11,73,293 नागरिक
एआई तत्परता बूट शिविरों का निर्माण, फ्यूचर टेक ओलंपियाड, राष्ट्रीय कोडिंग चुनौती, स्थिरता और जलवायु कार्यक्रम पर प्रशिक्षुतावृति/परामर्श कार्यक्रम, उद्योग संलग्नता और प्रौद्योगिकी	53, 065 छात्र
क्षमता निर्माण कार्यक्रम, बूट कैंप, 21वीं सीएलडी कौशल का निर्माण, डिजिटल नागरिकता, एआरएम स्कूल कार्यक्रम, कोडिंग, डेटा विज्ञान	1,80,783 शिक्षक

❖ कौशल यात्रा अभियान

कौशल यात्रा पहल की कल्पना भारत के कार्यबल की बढ़ती जरूरतों और देश में कौशल में कमी को कम करने की अनिवार्यता के उत्तर में एक परिवर्तनकारी प्रयास के रूप में की गई थी।

यह अभियान 19 सितंबर 2023 को आईसीएआर में 'स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन' के दौरान शुरू किया गया था। इस नवोन्मेषी प्रयास के मूल में एक मोबाइल बस स्किल लैब थी, जो पूरी तरह से सुसज्जित बहु–कौशल सुविधा थी, जिसे ट्रक चेसिस पर शानदार ढंग से नवीनीकृत किया गया था और वाई–फाई, ऑडियो–विजुअल क्षमताओं और जनरेटर जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया था।

मॉडल का प्रदर्शन करने के लिए लेंड ए हैंड इंडिया, एचपी और अन्य भागीदारों जैसे विभिन्न संगठनों ने भाग लिया। कुशल प्रशिक्षकों द्वारा संचालित, कौशल यात्रा बस ने वेल्डिंग, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, बुनियादी स्वास्थ्य सेवा और मोबाइल मरम्मत जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया, जिससे छात्रों के लिए व्यावहारिक ज्ञान और संभावनाओं का अवसर प्राप्त हुआ।

कौशल यात्रा अभियान दिनांक 29.09.2023 से 17.10. 2023 तक लगभग 3000+ छात्रों को शामिल करते हुए आयोजित किया गया था।

'स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन को सुगम बनाना' विषय पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन

इस कार्यक्रम में लगातार बदलते पेशेवर पारिस्थितिकी में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को आवश्यक कौशल और ज्ञान के साथ तैयार करने में स्कूलों की आवश्यक भूमिका पर प्रकाश डाला गया। प्रख्यात वक्ताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, उद्योग जगत के नेताओं और अन्य प्रमुख हितधारकों की बातचीत के साथ–साथ, शिखर सम्मेलन ने छात्रों को एक कौशल प्रदर्शनी के माध्यम से कौशल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूलों में किए जा रहे कार्यों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया। वक्ताओं ने राष्ट्रीय मार्गदर्शन महोत्सव के हिस्से के रूप में आगामी करियर संभावनाओं, आवश्यक कौशल सेट और प्रभावी करियर निर्णय लेने हेतुजानकारी प्रदान की। शिखर सम्मेलन में 3,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

❖ यूथ आइडियाथॉन 2023

इस परियोजना के तहत कक्षा 4 से कक्षा 12 तक के छात्रों को नवीन विचारों के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। यह सीबीएसई और एमईपीएससी (प्रबंधन और उद्यमिता और व्यावसायिक कौशल परिषद) के भागीदारों के बीच सहयोग से शुरू किया गया एक वार्षिक कार्यक्रम है। कई स्कूलों ने निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अपने नवीन विचार प्रस्तुत किए और चयनित सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को आईआईटी दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया।

❖ कार्टे ब्लैंश परियोजना

सीबीएसई ने माइक्रोसॉफ्ट, यूनिसेफ और टीएजी के सहयोग से अपने संबद्ध स्कूलों के माध्यम से प्रोजेक्ट कार्टे ब्लैंश के रूप में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम की परियोजना शुरू की है। पहले चरण में, 610 स्कूलों को इस परियोजना का हिस्सा बनने के लिए शामिल किया गया है, जहां सभी स्कूलों को हाइब्रिड लर्निंग को लागू करने के लिए आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाएगा।

मिडिल स्कूल के छात्रों के लिए नए कौशल मॉड्यूल

एनईपी 2020 की सिफारिशों के अनुपालन में, सीबीएसई ने कक्षा 6 से कौशल मॉड्यूल प्रस्तुत किए थे। इन कौशल मॉड्यूल का लक्ष्य छात्रों के बीच विभिन्न कौशल/व्यवसायों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसके अलावा, वर्तमान में बोर्ड 39+ कौशल मॉड्यूल प्रदान करता है जो कक्षा 6 से आगे के छात्रों के लिए उपलब्ध हैं।

निम्नलिखित कौशल नियमावली की समीक्षा की गई और उसके स्कूलों के लिए बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया:

बेकिंग	**नीली मिट्टी के बर्तन**	**कढ़ाई**
मिट्टी के बर्तन	मास्क बनाना	खाद्य नियमावली
हर्बल विरासत	हस्तशिल्प	ब्लॉक प्रिंटिंग
खाद्य संरक्षण	कश्मीरी कढ़ाई	खादी
ग्राफिक नोवेल का निर्माण	संचार मीडिया	**फोटोग्राफी**

मल्टी मीडिया में संशोधित पाठ्यक्रम

मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र कौशल परिषद (एमईएससी) ने मल्टी मीडिया (टेक्सचर आर्टिस्ट) – कक्षा 9 और 10 और मल्टी मीडिया (एनिमेटर) – कक्षा 11 और 12 की पाठ्यक्रम सामग्री को अद्यतन/संशोधित किया।

VII. व्यावसायिक परीक्षा इकाई

1. **कक्षा VI के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा** – 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय की नवोदय विद्यालय समिति (नविस) द्वारा संचालित और प्रबंधित केंद्रीय वित्त पोषित विद्यालय हैं। जनवि में प्रवेश जेएनवीएसटी नामक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर किया जाता है। सीबीएसई इस बड़े स्तर की परीक्षा के लिए गोपनीय सहायता सेवाएं प्रदान करता है जो ओएमआर आधारित एमसीक्यू प्रकार की है। जांच परीक्षा में मानसिक क्षमता, अंकगणित और भाषा शामिल है। जेएनवीएसटी –2023 दिनांक29 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया था (9632 केंद्र, 650 जिले, 1037 संरक्षक, 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र),2467349 अभ्यर्थी उम्मीदवार पंजीकृत थे (1159180 लड़कियां + 1308169 लड़के + 146 ट्रांसजेंडर) और 47253 उम्मीदवारों का चयन किया गया।

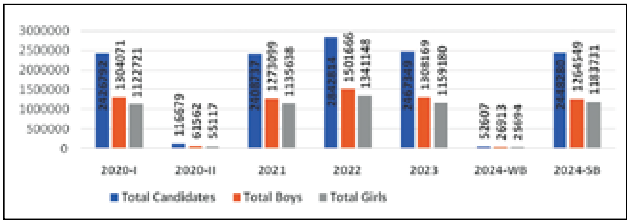

2. **जेएनवि लेटरल एंट्री टेस्ट** – कक्षा IX. जनवि में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वर्ष रिक्त सीटों के लिए कक्षा IX के लिए एक पार्श्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। जांच परीक्षा कक्षा 8 के पाठ्यक्रम सिलेबस पर आधारित बहुविकल्पी प्रकार का है। इसमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित और सामान्य विज्ञान शामिल है। लेटरल एंट्री टेस्ट–2023 दिनांक 11 फरवरी 2023 को आयोजित किया गया था (644 परीक्षा केंद्र, 482 जिले, 483 संरक्षक, 35 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र)। 181006 अभ्यर्थी

पंजीकृत थे (75840 लड़कियां + 105154 लड़के + 12 ट्रांसजेंडर) और 2572 अभ्यकर्थियों का चयन किया गया

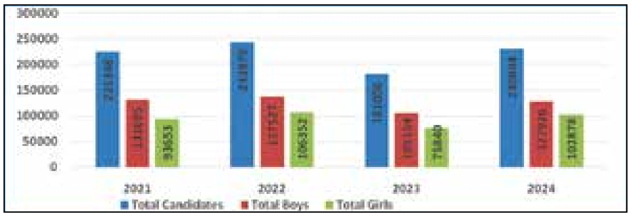

3. **ग्यारहवीं कक्षा के लिए जेएनवी लेटरल एंट्री टेस्ट – 2023 :** जेएनवी में उपलब्ध बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, प्रत्येक वर्ष रिक्त सीटों के लिए ग्यारहवीं कक्षा के लिए एक पार्श्व प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। जांच परीक्षा कक्षा 10 के पाठ्रयक्रम पर आधारित बहुविकल्पी प्रकार का है। इसमें मानसिक योग्यता, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित शामिल हैं। लेटरल एंट्री टेस्ट 22 जुलाई 2023 (640 परीक्षा केंद्र, 631 जिले, 629 संरक्षक, 34 राज्य और संघ राज्य क्षेत्र) को आयोजित किया गया था। 57716 उम्मीदवार पंजीकृत थे (28455 लड़कियां + 29261 लड़के + 02 ट्रांसजेंडर) और 5584 उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

4. **मणिपुर राज्य के लिए विशेष व्यवस्थाएँ:–** मणिपुर राज्य के अभ्यर्थियों की बड़ी सुविधा को ध्यान में रखते हुए, ग्यारहवीं कक्षा के लिए जेएनवी लेटरल टेस्ट 25 अगस्त 2023 को 11 जिलों में अलग से आयोजित किया गया था।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 16वां संस्करण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 28 दिसंबर, 2022 से 7 फरवरी, 2023 तक ऑनलाइन (सीबीटी) मोड में आयोजित किया गया था। परिणाम 3 मार्च 2023 को घोषित किया गया था। ब्यौरा इस प्रकार हैं:

	पंजीकृत अभ्यर्थी	शामिल अभ्यर्थी	सफल अभ्यर्थी
पत्र – I	17,04,282	14,22,959	5,79,844
पत्र – II	15,39,464	12,76,071	3,76,025

VIII केविस भर्ती परीक्षा2022–23

केविस में सीधी भर्ती के आधार पर शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा और सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) का कार्य शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीएसई को सौंपा गया था। सीधी भर्ती के लिए कुल 19,99,634 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था और एलडीसीई के लिए 17,617 अभ्यार्थियों ने आवेदन किया था। एलडीसीई 22 जनवरी 2023 को सीबीटी (ऑनलाइन मोड) में आयोजित की गई थी, जबकि सीधी भर्ती के आधार पर परीक्षा सीबीटी (ऑनलाइन मोड) में सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी। सभी परीक्षाओं के अंतिम परिणाम/मेघा सूचियां केविस को सौंप दी गई।

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का 17वां संस्करण 20 अगस्त 2023 को 136 शहरों में 3121 परीक्षा केंद्रों पर ऑफ़लाइन (ओएमआर शीट) 2023 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था। परिणाम 3 मार्च 2023 को घोषित किया गया था। ब्यौरा इस प्रकार हैं:

पत्र	पंजीकृत उम्मीदवार	शामिल उम्मीदवार	सफल उम्मीदवार
पत्र – I	15,01,391	12,13,704	2,98,759
पत्र – II	14,01,938	11,66,178	1,01,057

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) भर्ती परीक्षा 2023

ईएमआरएस में सीधी भर्ती पर शैक्षणिक और गैर–शिक्षण पदों के लिए भर्ती परीक्षा शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीबीएसई को सौंपी गई थी। परीक्षा दिनांक 16.12.23, 17.12.23,

23.12.23 और 24.12.23 को ऑफ़लाइन (ओएमआर आधारित) मोड में आयोजित की गई थी।

IX. मीडिया एवं जन संपर्क इकाई

मनोसामाजिक कल्याण

परामर्श कार्यक्रम वर्ष 2023 में 26 वर्ष पूरे हो जाएंगे।

बोर्ड छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण के संबंध में हमेशा संवेदनशील और सक्रिय रहा है। बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने में सहायता करने के लिए बोर्ड द्वारा पहली बार वर्ष 1998 में कक्षा 10 और 12 के परीक्षार्थियों के लिए मनोवैज्ञानिक टेली–काउंसलिंग शुरू की गई थी। बोर्ड पिछले 26 वर्षों से दुनिया भर में स्थित संबद्ध स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के लिए प्रधानाचार्यों और प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के माध्यम से यह निःशुल्क स्वैच्छिक सेवा लगातार प्रदान कर रहा है।

वर्ष 2023 में टेली–काउंसलिंग की सुविधाएं

- **टेली–परामर्शः** टेली–काउंसलिंग एक स्वैच्छिक और निःशुल्क सेवा है। इस वर्ष, भारत और नेपाल, जापान, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर, ओमान और सिंगापुर जैसे अन्य देशों से 87 प्राचार्य और काउंसलर टेली–काउंसलिंग के लिए उपलब्ध थे।
- आईवीआरएस निःशुल्क आईवीआरएस सुविधा बोर्ड के टोल फ्री नंबर पर 24×7 उपलब्ध थी। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू), परीक्षा और परिणाम से संबंधित उपयोगी जानकारी जैसे बेहतर तैयारी, समय और तनाव प्रबंधन, कोविड से बचाव, सीबीएसई कार्यालयों के महत्वपूर्ण संपर्क विवरण आईवीआरएस के माध्यम से उपलब्ध कराए गए थे।
- ऑडियो–विज़ुअल प्रस्तुतियों के माध्यम से परामर्श, आक्रामकता, इंटरनेट लत विकार, अवसाद, परीक्षा की चिंता, विशिष्ट अधिगम अक्षमता, मादक द्रव्यों के सेवन विकार और जीवन कौशल जैसे छात्रों के साथ–साथ माता–पिता से संबंधित प्रासंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करने के लिए सीबीएसई वेबसाइट और यूट्यूब पर विभिन्न विषयों पर ऑडियो–विज़ुअल प्रस्तुतियाँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

परीक्षा पे चर्चा (पीपीसी)

परीक्षापेचर्चा का छठा संस्करण 27 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया था। विभिन्न स्कूलों और छात्रों को आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल का उपयोग करके पीपीसी के बारे में जागरूक किया गया और छात्रों के साथ माननीय प्रधान मंत्री की लाइव वार्तालाप प्रसारण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। भारत और विश्व के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने 27 जनवरी 2023 को परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण देखा।

सोशल मीडिया के माध्यम से संचार

सीबीएसई ने हितधारकों के साथ व्यापक कनेक्टिविटी और संचार के लिए यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर सक्रिय रूप से महत्वपूर्ण जानकारी प्रसारित की है। बोर्ड के महत्वपूर्ण निर्णयों/गतिविधियों/नवीनतम घटनाक्रमों के संबंध में सोशल मीडिया हैंडल पर कुल 868 पोस्ट पोस्ट किए गए।

आरटीआई एवं लोक शिकायत निवारण की निगरानी

- **वर्ष के दौरान 6580 आरटीआई आवेदन और 624 अपीलें** प्राप्त हुई और उनका निपटारा किया गया।
- वर्ष 2022–23 की मूल्यांकन रिपोर्ट के लिए दिनांक 20.10.2023 को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

संस्थान(एनआईटीटीटीआर), चंडीगढ़ द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सक्रिय प्रकटीकरण के ऑनलाइन थर्ड पार्टी ऑडिट में सीबीएसई 95% अंक प्राप्त करने वाला बन गया।

- कैलेंडर वर्ष 2023 में प्राप्त 2538 शिकायतों में से 2493 शिकायतों का निपटारा किया गया। प्रभावी निगरानी और नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के साथ, सार्वजनिक शिकायतों को निपटाने का औसत कार्य समय 30 दिनों से भी कम हो गया है।

राजभाषा प्रभाग– राजभाषा प्रचार एवं कार्यान्वयन

1. **राजभाषा निरीक्षण**

   - बोर्ड मुख्यालय के अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का राजभाषाई निरीक्षण माननीय संसदीय राजभाषा समिति द्वारा 08 मई 2023 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
   - बोर्ड मुख्यालय द्वारा वार्षिक कार्यक्रम में दिये गये लक्ष्य के अनुरूप आन्तरिक शाखाओं एवं अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कार्य 25% पूर्ण किया गया।

2. **हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी बैठकों एवं कार्यशालाओं का आयोजनः**

   केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में दिनांक 14.09.2023 से 29.09.2023 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिन्दी पखवाड़ा के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें कुल 124 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सभी अधिकारियों को राजभाषा नीति से परिचित कराने के लिए नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं ताकि वे अपनी राजभाषा जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें। साथ ही वर्ष में 4 हिन्दी बैठकें आयोजित की गईं।

3. इस वर्ष राजभाषा हिन्दी के प्रचार–प्रसार हेतु बोर्ड मुख्यालय की सभी इकाइयों द्वारा प्रत्येक माह हिन्दी साहित्यकारों की कृतियों से संबंधित हिन्दी गतिविधियाँ जैसे कविता पाठ, निबंध लेखन, हिन्दी प्रश्नोत्तरी आदि का आयोजन किया गया। हिन्दी साहित्य की साहित्यिक कृतियों सहित उनकी जीवनियों के 10 इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बनवाकर बोर्ड कार्यालय में स्थापित किये गये। हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के उपाय के रूप में हिंदी नोट्स और हिंदी टेम्प्लेट आदि का द्विभाषीकरण किया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन (एनबीबी):

i. **प्रस्तवना**– राष्ट्रीय बाल भवन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है। यह संस्था 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केंद्र संचालित कर रही है। इसकी स्थापना वर्ष 1956 में बच्चों के लिए सोच, कल्पना, रचनात्मक और मनोरंजक गतिविधियों के माध्यम से सीखने के सपने को ध्यान में रखते हुए की गई थी। राष्ट्रीय बाल भवन ने देश भर में 141 संबद्ध बाल भवनों और बाल केंद्रों के साथ एक आंदोलन का रूप ले लिया है। इसके अलावा, दिल्ली के मांडी गांव में एक ग्रामीण जवाहर बाल भवन और अन्य 40 बाल केंद्र भी दिल्ली में कार्यरत हैं।

ii. **कार्य**–

1. गतिविधियों, कार्यशालाओं, सेमिनारों, शिविरों और सम्मेलनों आदि के माध्यम से सीखने के इर्द–गिर्द घूमने वाली विभिन्न गैर–औपचारिक गैर तकनीकों के माध्यम से रचनात्मकता को बढ़ावा देने और बनाए रखने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना, लागू करना।
2. राष्ट्रीय बाल भवन, जवाहर बाल भवन मंडी, दिल्ली में 50 बाल भवन केंद्रों के कामकाज की

निगरानी करना और देश भर में संबद्ध बाल भवनों और बाल भवन केंद्रों से परियोजना प्रस्तावों को संसाधित करना और तदनुसार धन हस्तांतरण करना।

3. बच्चों के हित में अन्य सरकारी/अर्धसरकारी एजेंसियों के साथ सहयोगात्मक कार्यक्रम चलाना।

4. बच्चों और वयस्कों के लिए विभिन्न विषयों पर दिल्ली और अन्य स्थानों पर राष्ट्रीय स्तर के शिविर, सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करना।

5. विभिन्न देशों से प्राप्त सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के निमंत्रणों पर कार्रवाई करना और देश भर से बाल भवन के बच्चों को शामिल करना।

iii. जनवरी, 2023 से दिसंबर, 2023 तक कार्यक्रम की मुख्य बिंदु

वर्ष 2022–23 हेतु नामांकन दिसम्बर, 2023 तक

राष्ट्रीय बाल भवन	–	3285
जवाहर बाल भवन, मण्डी	–	967
बाल भवन केंद्र, दिल्ली	–	4590

कार्यशालाएं

जनवरी से दिसंबर, 2023 तक लगभग 185 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं जैसे बेसिक सिलाई, कंप्यूटर जागरूकता, जानवरों का प्रागैतिहासिक जीवन, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स और हाउस वायरिंग, रंग बिरंगे धागो की दुनिया, जल एक अनमोल रत्न, हमारा संग्रहालय–हमारी विरासत, पॉट पेंटिंग, ऑयल पेस्टल पेंटिंग, एक्वेरियम और पर्यावरण, हिंदी कार्यशाला, मिट्टी, बुनाई, एकीकृत गतिविधियाँ, सौर मंडल, धूपघड़ी, कुचिपुड़ी नृत्य, सितार और गिटार, हस्तशिल्प, नाटक, विश्व पशु दिवस, डिजिटल ग्राफिक डिजाइनिंग, गायन संगीत, तबला और ढोलक, शारीरिक शिक्षा आदि।

राष्ट्रीय बाल भवन के मुख्य कार्यक्रम

- 23 मई से 21 जून, 2023 तक ग्रीष्मकालीन उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 3000 बच्चे प्रतिदिन भाग लेते हैं और विभिन्न नवीन गतिविधियों और कार्यशालाओं के माध्यम से अपने कौशल और रचनात्मकता को बढ़ाते हैं।

Summer Fiestaa

- राष्ट्रीय बाल सभा एवं एकता शिविर 17 से 19 नवम्बर 2023 तक आयोजित जिसमें देश भर के 14 राज्यों के 37 राज्य बाल भवनों/केंद्रों, जवाहर बाल भवन, मंडी, दिल्ली के बाल केंद्रों, सरकारी स्कूलों और राष्ट्रीय बाल भवन के सदस्य बच्चों के लगभग 2500 बच्चों ने बहुत खुशी और उत्साह के साथ भाग लिया।
- देश भर के विभिन्न वायु सेना स्कूलों के छात्र दो बैचों में 11 से 15 अप्रैल, 2023 और 25 से 29 अप्रैल, 2023 तक राष्ट्रीय बाल भवन में रहे और राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा आयोजित विभिन्न अभिनव कार्यशालाओं में भाग लिया।
- राष्ट्रीय बाल भवन ने सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें लगभग 1500 बच्चों ने हस्तशिल्प, पेंटिंग, सिलाई, एकीकृत, मिट्टी की बुनाई, नृत्य, संगीत, वाद्य संगीत, विज्ञान गतिविधियां, शारीरिक शिक्षा आदि जैसी विभिन्न नवीन गतिविधियाँ सीखीं।

- 'पारिस्थितिकी की बहाली' विषय पर 28वां राष्ट्रीय युवा पर्यावरणविद् सम्मेलन 12 से 14 मार्च, 2023 तक किलकारी बिहार बाल भवन, पटना (बिहार) में आयोजित किया गया था जिसमें 8 राज्यों के 14 बाल भवनों / केंद्रों के सैकड़ों बच्चों और अनुरक्षकों ने भाग लिया था।

Visit by Hon'ble Education Minister

- शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और मंत्रालय के अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने 16 सितंबर, 2023 को राष्ट्रीय बाल भवन का दौरा किया।
- श्री आनंदराव विष्णु पाटिल, संयुक्त सचिव, एसई एंड एल विभाग, एमओई ने दिनांक 27.10.2023 को राष्ट्रीय बाल भवन में विभिन्न गतिविधियों और प्रदर्शनी 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' का दौरा किया।
- राष्ट्रीय बाल भवन में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल, होली आदि जैसे विभिन्न त्यौहार मनाये गये।

जवाहर बाल भवन मंडी में कई गतिविधियां/कार्यक्रम जैसे आमोद दिवस, लोहड़ी उत्सव, गणतंत्र दिवस समारोह, मंडी दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, होली, लिनो प्रिंट, वुडकट प्रिंट बनाना और कला एवं शिल्प में जीवन अध्ययन, समर फिएस्टा, स्वच्छता ही सेवा के तहत गतिविधियां, एकता दिवस का उत्सव, संविधान दिवस आदि आयोजित किए गए।

दिल्ली के 40 बाल भवन केंद्रों पर कला और शिल्प, चित्रकला, नृत्य और संगीत, हस्तशिल्प, शारीरिक गतिविधियाँ आदि जैसी कई गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

iv. राष्ट्रीय बाल भवन की नियमित गतिविधियाँ /कार्यक्रम

दिनांक 03.01.2023 को नव वर्ष के स्वागत हेतु आमोद दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- 26 जनवरी 2023 को बसंत पंचमी मनाई गई।

आमोद दिवस

- 13 से 15 फरवरी 2023 तक प्रगति मैदान में संचार मंत्रालय द्वारा आयोजित अमृतपेक्स कार्यक्रम में भाग लिया।
- दिनांक 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- 10 मार्च, 2023 को राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 'गूगल मीट' के माध्यम से आयोजित की गई, जिसमें राजभाषा हिंदी के वार्षिक कार्यक्रम के साथ–साथ पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर चर्चा की गई।
- 21 अप्रैल 2023 को पृथ्वी दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया
- 9 मई, 2023 को रवीन्द्रनाथ जयंती मनाई गई
- सदस्य बच्चों ने 2 जून, 2023 को मौसम भवन का भ्रमण किया।
- 6 जून, 2023 को साइबर सेफ्टी कार्निवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

- एनबीबी के लगभग 40 सदस्य बच्चों ने 19 जून, 2023 को आम के बागों का दौरा किया।
- दिनांक 14.10.2023 को राष्ट्रीय बाल भवन के सदस्य बच्चों द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का अध्ययन दौरा।
- दिनांक 30.11.2023 को 'हिन्दी पखवाड़ा' का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित

v. शिक्षा मंत्रालय ने कार्यक्रम शुरू किये

- 27 जनवरी, 2023 को परीक्षा पे चर्चा में भागीदारी।
- राष्ट्रीय बाल भवन में फिट इंडिया मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए 21 जून, 2023 को 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया।
- राष्ट्रीय बाल भवन 17 से 22 जून, 2023 तक जी20 कार्यक्रम के लिए पुणे में विभिन्न कला तियों का प्रदर्शन किया।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।
- आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 अगस्त, 2023 को अंगदान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं।
- राष्ट्रीय बाल भवन के सदस्य बच्चों ने 3 अगस्त, 2023 को गांधीनगर, गुजरात में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 2 से 4 अगस्त, 2023 तक जी20 समापन समारोह में प्रदर्शन किया।
- "मेरी माटी मेरा देश" अभियान के अंतर्गत 9 से 30 अगस्त, 2023 तक विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।
- 16 सितम्बर, से 29 सितम्बर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा का आयोजन।
- राष्ट्रीय बाल भवन के स्टाफ सदस्य ने स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत दिनांक 01.10.2023 को 'श्रमदान' में भाग लिया और लोक नायक पार्क, फिरोजशाह कोटला, नई दिल्ली – 02 की सफाई की।
- स्वच्छता के संबंध में विशेष अभियान 3.0 के तहत 3 से 31 अक्टूबर, 2023 तक राष्ट्रीय बाल भवन के विभिन्न क्षेत्रों की सफाई और नवीनीकरण किया गया ताकि इको क्लब, कम्पोस्ट पिट, अपशिष्ट प्रबंधन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट प्रदर्शनी आदि बनाई जा सके।

G20 में भागीदारी

श्रमदान (स्वच्छता ही सेवा)

- विशेष अभियान 3.0 के एक भाग के रूप में 18 से 20 अक्टूबर, 2023 तक राष्ट्रीय बाल भवन में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसमें सदस्य बच्चों द्वारा सीखी और बनाई गई 'बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट' कृतियों का प्रदर्शन किया गया।
- विभिन्न पहलुओं में सभी को जागरूक करने के लिए, 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 तक

सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, जिसमें प्रतिज्ञा लेना, सतर्कता पर गीत सीखना, गैलरी वार्ता आदि जैसी विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

- 31 अक्टूबर, 2023 को एकता दिवस के अवसर पर शपथ ग्रहण समारोह एवं एकता दौड़ का आयोजन किया गया।
- 25 नवंबर, 2023 को संविधान दिवस मनाया गया, एनबीबी के सभी कर्मचारियों द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी गई।
- 'कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह' के तहत कर्मचारियों के लिए एक सेमिनार और जागरूकता सृजन कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

एकता दौंड

संविधान दिवस

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

अनुलग्नक

संस्थानों का समावेशन और नामांकित बच्चों की संख्या

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नामांकन			संस्थान			
		बाल वाटिका	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	आंध्र प्रदेश	0	1628153	1093097	2721250	34061	10089	44150
2	अरुणाचल प्रदेश	11619	85944	53606	151169	1523	1095	2618
3	असम	242802	2579799	1264767	4087368	34390	9950	44340
4	बिहार	0	11817896	6104359	17922255	40233	30636	70869
5	छत्तीसगढ	55834	1778533	1121246	2955613	31869	13991	45860
6	गोवा	1370	94532	66655	162557	805	426	1231
7	गुजरात	533200	2802833	1899146	5235179	10203	22316	32519
8	हरियाणा	25939	884358	640494	1550791	8671	5582	14253
9	हिमाचल प्रदेश	49771	291754	201273	542798	10404	4789	15193
10	झारखंड	38854	2718471	1458377	4215702	21469	14010	35479
11	कर्नाटक	0	2709905	1638639	4348544	20445	32839	53284
12	केरल	137872	1575615	1130920	2844407	6632	5404	12036
13	मध्य प्रदेश	0	3994755	2474949	6469704	69039	40204	109243
14	महाराष्ट्र	0	5974978	3917899	9892877	46245	39371	85616
15	मणिपुर	24419	127292	39366	191077	2304	1006	3310
16	मेघालय	130255	363286	190781	684322	7938	3276	11214
17	मिजोरम	19261	85546	43276	148083	1409	1090	2499
18	नागालैंड	44448	60950	32106	137504	1025	903	1928
19	ओडिशा	134881	2664059	1778834	4577774	33092	17526	50618
20	पंजाब	197382	1099686	672583	1969651	12891	6710	19601
21	राजस्थान	56199	3873274	2428405	6357878	32576	37468	70044
22	सिक्किम	6607	23587	18383	48577	482	387	869
23	तमिलनाडु	0	2248314	1864599	4112913	27003	16128	43131
24	तेलंगाना	0	1197507	693009	1890516	20036	8771	28807
25	त्रिपुरा	9698	231811	143054	384563	2284	2157	4441
26	उत्तर प्रदेश		11396461	6015071	17411532	87663	54359	142022
27	उत्तराखंड	769	410044	267716	678529	11481	5211	16692
28	पश्चिम बंगाल	1058921	6404557	4284744	11748222	66425	16124	82549
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3855	14679	12046	30580	183	150	333
30	चंडीगढ़	16339	47151	40786	104276	4	117	121
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	6553	42516	26585	75654	151	169	320
32	दिल्ली	118430	880193	762292	1760915	1586	1234	2820
33	जम्मू एवं कश्मीर	197460	543379	292430	1033269	8966	9265	18231
34	लद्दाख	4529	9019	4232	17780	390	403	793
35	लक्षद्वीप	1297	5074	2564	8935	14	16	30
36	पुदुचेरी	7964	29514	21353	58831	236	188	424
	कुल	**3136528**	**70695425**	**42699642**	**116531595**	**654128**	**413360**	**1067488**

रसोइया–सह–सहायकों को मानदेय

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रसोइया–सह–सहायकों को मानदेय प्रति माह (रुपये में)	रसोइया–सह–सहायकों को प्रति माह अतिरिक्त मानदेय (रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	3000	2000
2	अरुणाचल प्रदेश	2000	1000
3	असम	1500	500
4	बिहार	1650	650
5	छांत्तीसगढ	2000	1400
6	गोवा	1000	0
7	गुजरात	3000	2000
8	हरियाणा	7000	6000
9	हिमाचल प्रदेश	4000	3000
10	झारखंड	2000	1000
11	कर्नाटक	3700	2700
12	केरल	12000	11000
13	मध्य प्रदेश	4000	3000
14	महाराष्ट्र	2500	1500
15	मणिपुर	1000	0
16	मेघालय	2000	1000
17	मिजोरम	1500	500
18	नागालैंड	1000	0
19	ओडिशा	1400	400
20	पंजाब	3000	2000
21	राजस्थान	2003	1003
22	सिक्किम	1000	0
23	तमिलनाडु	7700-24200, 4100-12500 और 3000-9000	7700-24200, 4100-12500 और 3000-9000
24	तेलंगाना	3000	2000
25	त्रिपुरा	2500	1500
26	उत्तर प्रदेश	2000	1000
27	उत्तराखंड	3000	2000
28	पश्चिम बंगाल	1500	500
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1000	0
30	चंडीगढ़	3300	2300
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	5544	4544
32	दिल्ली	1000	0
33	जम्मू और कश्मीर	1000	0
34	लद्दाख	1000	0
35	लक्षद्वीप	18000-20200	18000-20200
36	पुदुचेरी	10000	90000

❖ ❖ ❖

पीएम पोषण 2023–24 के तहत अनुमोदित रसोइया–सह–सहायकों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रसोइया–सह–सहायकों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	88296
2	अरुणाचल प्रदेश	5753
3	असम	118998
4	बिहार	245316
5	छत्तीसगढ	93420
6	गोवा	2818
7	गुजरात	96329
8	हरियाणा	29813
9	हिमाचल प्रदेश	21532
10	झारखंड	79286
11	कर्नाटक	122461
12	केरल	17673
13	मध्य प्रदेश	210231
14	महाराष्ट्र	175201
15	मणिपुर	6550
16	मेघालय	20095
17	मिजोरम	4883
18	नागालैंड	4623
19	ओडिशा	112090
20	पंजाब	49449
21	राजस्थान	160064
22	सिक्किम	1891
23	तमिलनाडु	128130
24	तेलंगाना	54201
25	त्रिपुरा	12288
26	उत्तर प्रदेश	374858
27	उत्तराखंड	26970
28	पश्चिम बंगाल	248799
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	721
30	चंडीगढ़	900
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	1157
32	दिल्ली	20590
33	जम्मू और कश्मीर	32394
34	लद्दाख	924
35	लक्षद्वीप	9
36	पुदुचेरी	1031
	कुल	**2569744**

❖ ❖ ❖

रसोई–सह–भंडार के निर्माण संबंधि वास्तविक प्रगति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत रसोई–सह–भंडार	निर्माण	निर्माण
1	आंध्र प्रदेश	31525	30376	96%
2	अरुणाचल प्रदेश	4085	4085	100%
3	असम	51673	51222	99%
4	बिहार	66550	58363	88%
5	छत्तीसगढ	47266	47266	100%
6	गोवा	0	0	0%
7	गुजरात	25077	25077	100%
8	हरियाणा	11483	10950	95%
9	हिमाचल प्रदेश	14959	14959	100%
10	जम्मू एवं कश्मीर	11488	6791	59%
11	झारखंड	35570	32070	90%
12	कर्नाटक	40477	39305	97%
13	केरल	5481	5481	100%
14	मध्य प्रदेश	103401	99077	96%
15	महाराष्ट्र	66090	62276	94%
16	मणिपुर	2966	2453	83%
17	मेघालय	9758	9758	100%
18	मिजोरम	2541	2541	100%
19	नागालैंड	2223	2223	100%
20	ओडिशा	69152	69152	100%
21	पंजाब	18969	18969	100%
22	राजस्थान	77298	50312	65%
23	सिक्किम	948	948	100%
24	तमिलनाडु	28470	28469	100%
25	तेलंगाना	30408	17483	57%
26	त्रिपुरा	5304	5304	100%
27	उत्तर प्रदेश	113103	113103	100%
28	उत्तराखंड	15778	15778	100%
29	पश्चिम बंगाल	81956	81856	100%
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	251	169	67%
31	चंडीगढ़	15	15	100%
32	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	82	82	100%
33	दिल्ली	0	0	0%
34	लद्दाख	327	327	100%
35	लक्षद्वीप	0	0	0%
36	पुदुचेरी	105	105	100%
	कुल	**974779**	**906345**	**93%**

**त्रिपुरा ने संस्वीकृत की अपेक्षा 261 आर्थिक रसोइया–सह–भंडार बनवाए हैं।*

पीएम पोषण के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रस्तावित सामाजिक लेखा परीक्षा		पूर्ण सामाजिक लेखा परीक्षा	
		जिलों की संख्या	स्कूलों की संख्या	जिलों की संख्या	स्कूलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	26	520	प्रगति पर	
2	अरुणाचल प्रदेश	आयोजित नहीं किया गया		आयोजित नहीं किया गया	
3	असम	33	942	प्रगति पर	
4	बिहार	38	1415	प्रगति पर	
5	छत्तीसगढ	33	660	प्रगति पर	
6	गुजरात	15	323		प्रगति पर
7	गोवा	2	41	2	41
8	हरियाणा	22	440		प्रगति पर
9	हिमाचल प्रदेश	100	250		प्रगति पर
10	झारखंड	24	1064		प्रगति पर
11	कर्नाटक	35	700		प्रगति पर
12	केरल	14	50		प्रगति पर
13	मणिपुर	2	40	प्रगति पर	
14	मेघालय	12	213	प्रगति पर	
15	मिजोरम	4	80	प्रगति पर	
16	मध्य प्रदेश	52	2600	प्रगति पर	
17	महाराष्ट्र	35	4233	35	4233
18	नागालैंड	2	40		प्रगति पर
19	ओडिशा	30	600	30	600
20	पंजाब	23	238		प्रगति पर
21	राजस्थान	23	429	23	429
22	सिक्किम	5	100		प्रगति पर
23	तमिलनाडु	38	954	प्रगति पर	
24	तेलंगाना	33	660	प्रगति पर	
25	त्रिपुरा	8	160		प्रगति पर
26	उत्तराखंड	10	200	प्रगति पर	
27	उत्तर प्रदेश	75	1500	प्रगति पर	
28	पश्चिम बंगाल	24	5412		प्रगति पर
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	आयोजित नहीं किया गया			आयोजित नहीं किया गया
30	चंडीगढ़	1	20	प्रगति पर	
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	3	88	3	88
32	दिल्ली	16	320		प्रगति पर
33	जम्मू एवं कश्मीर	20	17009	20	17009
34	लद्दाख	2	270		प्रगति पर
35	लक्षद्वीप	1	20	प्रगति पर	
36	पुदुचेरी	आयोजित नहीं किया गया		आयोजित नहीं किया गया	

स्कूलों में स्कूल पोषण उद्यान

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल स्कूल	एसएनजी वाले स्कूलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	44150	17729
2	अरुणाचल प्रदेश	2618	959
3	असम	44340	31626
4	बिहार	70869	8820
5	छत्तीसगढ	45860	19927
6	गोवा	1231	730
7	गुजरात	32519	27254
8	हरियाणा	14253	6021
9	हिमाचल प्रदेश	15193	5054
10	झारखंड	35479	4352
11	कर्नाटक	53284	8256
12	केरल	12036	9666
13	मध्य प्रदेश	109243	70723
14	महाराष्ट्र	85616	24741
15	मणिपुर	3310	753
16	मेघालय	11214	1003
17	मिजोरम	2499	1154
18	नागालैंड	1928	1928
19	ओडिशा	50618	43000
20	पंजाब	19601	18334
21	राजस्थान	70044	5373
22	सिक्किम	869	848
23	तमिलनाडु	43131	28870
24	तेलंगाना	28807	1139
25	त्रिपुरा	4441	768
26	उत्तराखंड	16692	3822
27	उत्तर प्रदेश	142022	35000
28	पश्चिम बंगाल	82549	30875
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	333	333
30	चंडीगढ़	121	115
31	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	320	320
32	दिल्ली	2820	720
33	जम्मू एवं कश्मीर	18231	610
34	लद्दाख	793	149
35	लक्षद्वीप	30	20
36	पुदुचेरी	424	200
	कुल	**1067488**	**411192**

❖ ❖ ❖

भाग - III

उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सामान्य गतिविधियाँ

1

उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सामान्य गतिविधियाँ

उच्चतर शिक्षा विभाग और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की सामान्य गतिविधियाँ

अनुसूचित जाति – अनुसूचित जनजाति की शिक्षा

शैक्षिक विकास समाज के कमजोर वर्गों की सामाजिक–आर्थिक बेहतरी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग व्यक्ति शामिल हैं। भारत सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के हितों को बढ़ावा देने और समानता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए हैं। शिक्षण संस्थानों की संख्या बढ़ाकर बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया गया है।

अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्य योजना और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएससी और डीएपीएसटी)

योजना की पिछली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और वर्ष 2017–18 से योजना और गैर–योजना व्यय का विलय कर दिया गया है। जनसंख्या के आधार पर, नीति आयोग ने विशिष्ट योजनाओं के लिए भारत सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग द्वारा निधि निर्धारित करने के लिए नए दिशानिर्देश प्रसारित किए। डीएपीएससी और शिक्षा मंत्रालय के लिए डीएपीएसटी के लिए नीति आयोग द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रस्तावित प्रतिशत आवंटन नीचे दिया गया है:

विभाग	डीएपीएससी	डीएपीएसटी
स्कूल शिक्षा और साक्षरता	20%	10-7%
उच्चतर शिक्षा	16-60%	8-60%

"योजना घटक के तहत उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नीति आयोग द्वारा निर्धारित एससी और एसटी के लिए क्रमशः 16.60% और 8.60% प्रतिशत आवंटन का अनुपालन किया जा रहा है। इक्विटी सहायता को एससी/एसटी आवंटन से छूट दी गई है। इसी प्रकार, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अंतर्गत योजना घटक के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रतिशत आवंटन क्रमशः 20% एवं 10.7% रखा गया है। पिछले वर्ष के आवंटन के स्तर पर एससी/एसटी के समग्र आवंटन को बनाए रखने के लिए, दोनों विभागों के गैर–योजना घटकों में भी एससी/एसटी आवंटन किया गया है।

तालिकाः डीएपीएससी और डीएपीएसटी (2022–23) के तहत निर्धारित निधि रुपये करोड़ में)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	कुल			एससीएसपी			टीएसपी		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
योजना घटक	7454.97	4774.79	4162.53	1239	807.05	751.96	642.00	425.01	383.98
प्रतिशत				16.62%	16.90%		8.61%	8.90%	
योजना घटक के अलावा अन्य	33373.4	36053.6	34832.37	2650	3081.95	2906.32	1344.00	1560.99	1457.58
प्रतिशत				7.94%	8.55%		4.03%	4.33%	
कुल उच्चतर शिक्षा	**40828.4**	**40828.4**	**38994.90**	**3889**	**3889**	**3658.288**	**1986**	**1986**	**1841.562**

तालिकाः डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत निर्धारित निधि (2023–24): (रुपये करोड़ में)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	कुल			एससीएसपी			टीएसपी		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
योजना घटक	6468.03	4565.78	3107.85	1078	746.07	501.82	561	387.62	272.81
प्रतिशत				16.67%	16.65%		8.67%	8.65%	
योजना घटक के अलावा अन्य	37626.6	40178.70	28927.90	2954	3393.93	2265.10	1500	1729.24	1124.47
प्रतिशत				7.85%	8.42%		3.99%	4.29%	
कुल उच्च तर शिक्षा	**44094.62**	**44744.48**	**32035.75**	**4032.00**	**4140.00**	**2766.92**	**2061.00**	**2116.86**	**1397.28**

 # दिनांक 31.12.2023 तक की स्थिति अनुसार

तालिकाः डीएपीएससी और डीएपीएसटी के तहत निर्धारित निधि (2022–23) (रुपये करोड़ में)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	कुल			एससीएसपी			टीएसपी		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
योजना घटक	51052.37	46153.48	46051.47	10221.95	9119.72	9042.10	5631.66	5046.37	4779.54
प्रतिशत				20.02%	19.75%	19.63%	11.03%	10.93%	10.37%
योजना घटक के अलावा अन्य	12397.00	12899.30	12838.65	772.00	870.76	844.92	462.00	510.41	509.35
प्रतिशत				6.22%	6.75%	6.58%	3.72%	3.95%	3.96%
कुल स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	**63449.37**	**59052.78**	**58890.12**	**10993.95**	**9990.48**	**9887.02**	**6093.66**	**5556.78**	**5288.89**

तालिकाः डीएपीएससी और डीएपीएसटी (2023–24) के तहत निर्धारित निधि (रुपये करोड़ में)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	कुल			एससीएसपी			टीएसपी		
	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिनांक 31.12.23 तक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिनांक 31.12.23 तक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	दिनांक 31.12.23 तक व्यय
योजना घटक	54374.48	46958.00	17601.46	10889.81	8741.51	3045.53	5912.74	5071.42	2546.54
प्रतिशत				20.02%	18.61%	17.30%	10.87%	10.80%	14.46%
योजना घटक के अलावा अन्य	14430.37	14515.80	10505.34	1986.20	2099.70	1489.58	911.30	932.60	683.44
प्रतिशत				13.76%	14.46%	14.17%	6.31%	6.42%	6.50%
कुल स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	**68804.85**	**61473.80**	**28106.8**	**12876.01**	**10841.21**	**4535.11**	**6824.04**	**6004.02**	**3229.98**

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति के अनुसार

उच्च शिक्षा

जहां तक उच्चतर शिक्षा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत प्रतिनिधित्व का संबंध है, अ.जा. के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 तक लगभग 7 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है। अ.ज.जा. के सकल नामांकन अनुपात में वर्ष 2014–15 से वर्ष 2020–21 तक लगभग 7.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि देखी गई है।

उच्च शिक्षा में जीईआर (18–23 वर्ष)

वर्ष	सभी श्रेणी के छात्रों का जीईआर	अ.जा छात्रों का जीईआर	अ.ज.जा. छात्रों का जीईआर
2014-15	23.7	18.9	13.5
2015-16	23.7	19.5	13.8
2016-17	24.1	20.3	14.8
2017-18	24.6	21.0	15.3
2018-19	24.9	22.0	16.4
2019-20	25.6	22.3	17.0
2020-21	27.3	23.1	18.9
2021-22	28.4	25.9	21.2

स्रोतः अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण

केंद्रीय शिक्षा संस्थान अधिनियम, 2006, प्रवेश में क्रमशः 15% और 7.5% आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है जो अ.जा और अ.ज.जा छात्रों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और संस्थानों के लिए अपने प्रवेश में अ.जा. और अ.ज.जा. छात्रों का एक निश्चित प्रतिशत नामांकन करना अनिवार्य बनाता है। अधिनियम के निरंतर क्रियान्वयन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्ष 2014–15 और 2021–22 के बीच कुल एससी और महिला नामांकन

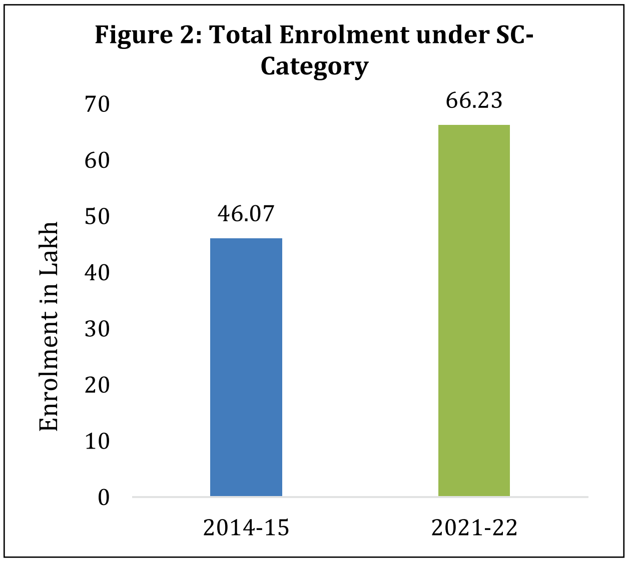

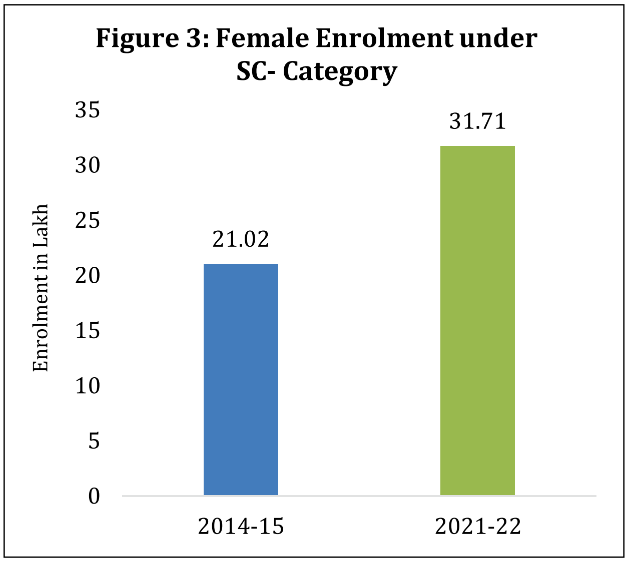

स्रोतः एआईएसएचई

अनुसूचित जाति के छात्रों का नामांकन वर्ष 2014–15 में 46.07 लाख की तुलना में वर्ष 2021–22 में 66.23 लाख है, जो 43.8% की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2014–15 से महिला अ.जा. छात्रों के नामांकन में 50.9% की उल्लेखनीय

वृद्धि हुई है; महिला अ.जा. छात्रों का नामांकन वर्ष 2014–15 में 21.02 लाख की तुलना में वर्ष 2021–22 में बढ़कर 31.71 लाख हो गया है।

वर्ष 2014–15 और 2021–22 के बीच कुल अ.ज.जा और महिला नामांकन।

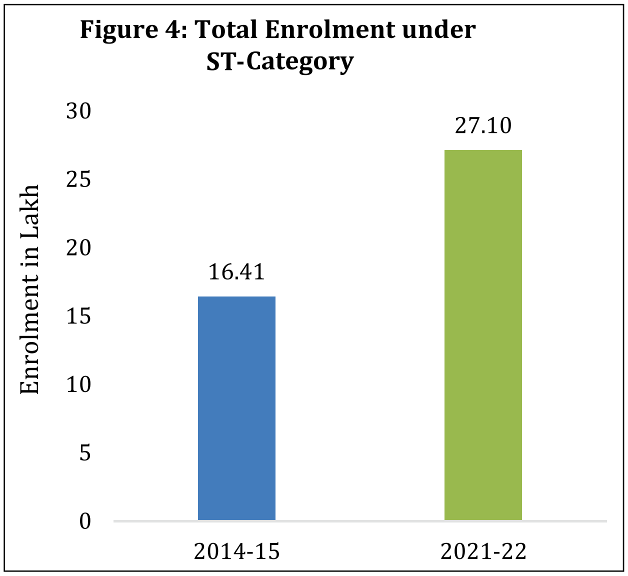

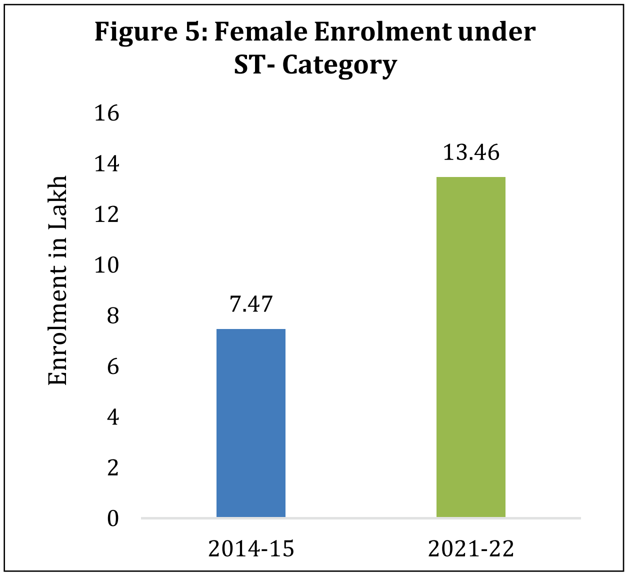

'स्रोतः एआईएसएचई

अ.ज.जा. छात्रों का नामांकन वर्ष 2014–15 में 16.41 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 27.10 लाख हो गया है। यह वर्ष 2014–15 से 65.2% की सराहनीय वृद्धि है। वर्ष 2014–15 से 2021–22 की अवधि के दौरान महिला एसटी छात्रों के नामांकन में 80.1% की भारी वृद्धि देखी गई है। महिला एसटी नामांकन वर्ष 2014–15 में 7.47 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 13.46 लाख हो गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत सरकार एवं अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग द्वारा समय–समय पर दिये गये सुझावों के आलोक में उच्चतर शिक्षा के स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु सतत एवं विशेष प्रयास कर रहा है। इन उपायों में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण, शिक्षण और गैर–शिक्षण पदों पर भर्ती में आरक्षण, छात्रावासों में सीटों का प्रावधान, छात्रवृत्ति, फेलोशिप, सुधारात्मक पाठ्यक्रम, जनजातीय क्षेत्रों में कॉलेजों को विशेष सहायता आदि शामिल हैं।

यूजीसी ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2012 को वर्ष 2012 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 31 के अनुसार अनुपालन और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिनांक 07.03.2019 के पत्र संख्या एफ.1–5/2006 (एससीटी) के माध्यम से सभी विश्वविद्यालयों को भेज दिया है। तथापि बाद में केन्द्रीय शिक्षण शिक्षा संस्थान (शिक्षण संवर्ग में आरक्षण) अधिनियम, 9 जुलाई 2019 से लागू हुआ जो अनुपालन के लिए सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू है।

सकल नामांकन अनुपात (जीईआर): वर्ष 2021–22 में, 18–23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में जीईआर 28.4 है, जबकि वर्ष 2014–15 में यह 23.7 था।

i. अ.जा. छात्र जीईआर वर्ष 2014–15 में 18.9 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 25.9 हो गया है। अ.जा. महिला जीईआर वर्ष 2014–15 में 18.1 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 26.0 हो गई है। एआईएसएचई वर्ष 2021–22 के अनुसार

महिला अ.जा. जीईआर लगातार चौथे वर्ष पुरुष जीईआर से अधिक बनी हुई है

ii. अ.जा. छात्र जीईआर वर्ष 2014–15 में 13.5 से बढ़कर 2021–22 में 21.2 हो गया है। अ.जा. महिला जीईआर वर्ष 2014–15 में 12.2 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 20.9 हो गई है।

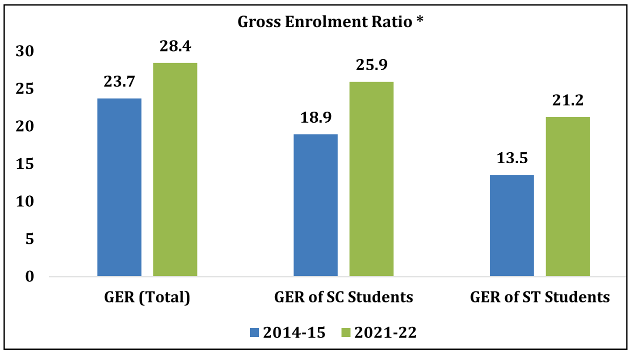

*अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई) रिपोर्ट में आयु वर्ग (18–23) के लिए वर्ष शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर),वर्ष 2021–22 की गणना वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ों के जनसंख्या अनुमान के आधार पर की गई है, जबकि एआईएसएचई, वर्ष2019–20 रिपोर्ट में जीईआर 2001 की जनगणना के आंकड़ों के जनसंख्या अनुमान पर आधारित थी।

अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कार्यक्रम/योजनाएँ

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएँ

i. कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय योजनाः–

उद्देश्यः योजना के तहत पात्र मेधावी छात्रों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पात्रताः जो छात्र बारहवीं कक्षा में सफल अभ्यर्थियों के शीर्ष 20 प्रतिशत में हैं और जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

दायराः प्रति वर्ष पुरस्कार के लिए 82,000 नई छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं (लड़कों के लिए 41000 और लड़कियों के लिए 41000)। इन्हें राज्य की 18–25 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के बीच विभाजित किया गया है।

छात्रवृत्ति दरः छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रति वर्ष और चौथे और पांचवें वर्ष के लिए 20,000/– रुपये प्रति वर्ष है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): यह योजना दिनांक 1.1.2013 से डीबीटी के अंतर्गत आती है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टलः सीएसएसएस दिनांक 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (www.scholarships.gov.in) पर शामिल हो गया है। शैक्षणिक वर्ष 2015 से उत्तीर्ण होने वाले योग्य छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इस वर्ष पोर्टल दिनांक 01.10.2023 से खोला गया था और अभी भी खुला है।

आरक्षणः योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का पालन किया जा रहा है, जिसमें अ.जा. के लिए 15% सीटें अ.ज.जा. के लिए 7.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% सीटें और सभी श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

नई पहलें

1. नोडल अधिकारियों की वास्तविकता सुनिश्चित करने के लिए सभी संस्थान नोडल अधिकारियों/संस्थानों के प्रमुखों और राज्य नोडल अधिकारियों का बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण।
2. राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर पंजीकरण हेतु लाभार्थियों की आधार मैपिंग अनिवार्य।

3. निर्धारण वर्ष 2023–24 से सभी छात्रवृत्ति भुगतान आधार के माध्यम से किया जाएगा।

वर्ष 2022 (दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.12.2023) के लिए अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लाभार्थियों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति और वितरित निधि की स्थिति इस प्रकार है:

सीएसएसएस (दिनांक 01.01.2023 – 31.12.2023)					
लाभार्थियों की संख्या (नया + नवीनीकरण)			वितरित राशि (करोड़ में)		
अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
15856	2735	15891	19.65	3.39	23.06

ii. जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना :–

उद्देश्य: जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए एसएसएस) का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें देश के बाकी हिस्सों के अपने समकक्षों के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलेगी।

पात्रता: जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के छात्र, जिनकी पारिवारिक आय 8.0 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है और इन संघ राज्य क्षेत्रों से बारहवीं कक्षा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने केंद्रीकृत परामर्श के माध्यम से इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर आवंटित सीटों पर प्रवेश प्राप्त किया है, साथ ही वे छात्र जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए पात्र हैं।

दायरा: प्रति वर्ष 5000 नई छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 100)। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों को चुनने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अध्यधीन, सामान्य डिग्री की संख्या में कमी के अध्यधीन, स्लॉट की अंतर–परिवर्तनीयता का प्रावधान है।

छात्रवृत्ति दर: ट्यूशन शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए ट्यूशन फीस के लिए छात्रवृत्ति की दर 30,000 रुपये प्रति वर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रुपये प्रति वर्ष और मेडिकल अध्ययन के लिए 3.0 लाख रुपये प्रति वर्ष है। योजना के तहत सभी छात्रों को 1.0 लाख रुपये प्रति वर्ष का निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। अंतर–मंत्रालयी समिति योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है।

आरक्षण: संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति को इस योजना के तहत अपनाया गया है, अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 8%, अनुसूचित जनजाति के लिए 10% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 22% निर्धारित है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): यह योजना डीबीटी के अंतर्गत आती है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है।

ऑनलाइन पोर्टल: छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल – www.aicte-jk-scholarship.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

नई पहल:

1. लाभार्थियों और उनके परिवारों पर योजना के सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करने

त्रवृ ा

के लिए एनआईटी, श्रीनगर द्वारा प्रभाव अध्ययन शुरू किया गया है।

2. एआईसीटीई द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यशाला के दौरान सभी इच्छुक छात्रों को सीयूईटी परीक्षा प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया और सीयूईटी जानकारी को शामिल करने के लिए पोर्टल में आवश्यक बदलाव किए गए।

3. छात्रों को एसएसएस छात्रों के लिए एनएसपी द्वारा संचालित डी–डुप्लीकेशन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई और विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में विद्यार्थियों से यह शपथ पत्र भी लिया गया कि वे किसी अन्य छात्रवृत्ति योजना के प्राप्तकर्ता नहीं हैं।

4. एआईसीटीई द्वारा आयोजित ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में विभिन्न प्रकार के सामान्य पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए, परिषद ने योजना के तहत प्रस्तावित अतिरिक्त सीटें प्रदान करने के लिए भारतीय पशु चिकित्सा परिषद और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पत्र भेजा है।

5. एआईसीटीई ने आधार के प्रमाणीकरण के लिए सीडीएसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023) के लिए अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के लाभार्थियों को प्रदान की गई छात्रवृत्ति और वितरित निधि की स्थिति इस प्रकार है: –

जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए पीएम–यूएसपी एसएसएस (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023)					
लाभार्थियों की संख्या (नया + नवीनीकरण)			वितरित राशि (करोड़ में)		
अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल
785	1108	1893	20	17	37

iii. केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी योजना (सीएसआईएस):–

उद्देश्य: योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और विकलांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से किसी को भी केवल इस कारण से पेशेवर उच्च शिक्षा तक पहुंच से वंचित न किया जाए कि वह गरीब है।

पात्रता: राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्त पोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआई) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/तकनीकी कार्यक्रमों से पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे पेशेवर संस्थान/कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक निकाय की मंजूरी की आवश्यकता होती है। ब्याज सब्सिडी केवल एक बार पूर्व या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है।

कार्यक्षेत्र: इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी छात्रों को कवर करना है, जिनके माता–पिता/परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है।

लाभ: इस योजना के अंतर्गतभारतीय बैंक संघ (आईबीए) की मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से 10.0 लाख रुपये तक के शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।

डीबीटी: ब्याज सब्सिडी दावों का वितरण छात्र के शिक्षा ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।

ऑनलाइन पोर्टल: सदस्य बैंकों को ब्याज सब्सिडी के दावे अपलोड करने में सक्षम

बनाने के लिए केनरा बैंक द्वारा प्रत्येक वर्ष एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाता है।

नई पहल:

1. बैंकों द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल अब मासिक आधार पर खोला जाता है और दावों को समेकित किया जाता है। अभिलेखों के समेकन के बाद, सब्सिडी राशि समय पर जारी की जाती है। वर्ष भर खुले रहे पोर्टल के कारण सब्सिडी का दावा न करने संबंधी शिकायतें काफी कम हो गई हैं।
2. सीएसआईएस 2022 दिशानिर्देशों के अनुसार, कुल ऋण सीमा 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपये कर दी गई। इसलिए, इस वर्ष वित्त वर्ष 2022–23 से संबंधित दावों में 10.00 लाख रुपये तक के ऋण शामिल हैं और बदले में योजना की कुल कवरेज बढ़ जाती है।

वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.12.2023) के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को निपटाए गए दावों की संख्या और वितरित निधि की स्थिति इस प्रकार है:

सीएसआईएस (दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 31.12.2023)					
दावों की संख्या			वितरित राशि (करोड़ में)		
एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी	कुल
19,336	4,534	23,870	29.38	7.00	36.37

iv. पीएम उषा:

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम–उषा) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) का तीसरा चरण। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समानता और गुणवत्ता में सुधार हेतु सहायता देने के लिए ₹ 12926.10 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ पीएम ऊषा योजना को 31 मार्च, 2026 तक अनुमोदित किया गया है।

पीएम– उषा को प्राथमिकता वाले जिलों जैसे योजना में पहचाने गए असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए संरचित किया गया है। राज्यों को कम जीईआर, एससी/एसटी की जनसंख्या, महिला नामांकन आदि के आधार पर प्राथमिकता वाले जिलों की पहचान करने की छूट दी गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण पैटर्न उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में है, और अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र 100% केंद्रीय वित्त पोषित होंगे।

v. जनजातीय विश्वविद्यालय

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना एक सतत प्रक्रिया है। केंद्र सरकार ने मुख्य रूप से देश की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान सुविधाओं के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पहले से ही दो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश की स्थापना की है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में अन्य बातों के साथ–साथ तेलंगाना में एक नए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का अधिदेश है। संसद द्वारा कानून बनाये जाने के बाद यह विश्वविद्यालय कार्यात्मक हो जायेगा। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों में कई केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं जो क्षेत्र के आदिवासी युवाओं की उच्च शिक्षा की आकांक्षाओं को भी

पूरा करते हैं। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने डॉ. अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) की स्थापना की है जो प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जाति के 100 सिविल सेवा अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित करेगा।

एक जनजातीय विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाता है और इसकी गुणवत्ता में सुधार करता है बल्कि राज्य में जनजातीय आबादी के लिए जनजातीय कला, संस्कृति, परंपरा, भाषा, औषधीय प्रणालियों, रीति–रिवाजों, वन–आधारित आर्थिक गतिविधियों, वनस्पतियों, जीवों और प्रौद्योगिकियों में उन्नति में अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाओं पर जोर देकर उच्च शिक्षा और अग्रिम ज्ञान के अवसरों को बढ़ावा देता है।

vi. बाबा साहेब भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

10 जनवरी 1996 को लखनऊ में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। संक्षेप में, विश्वविद्यालय के अधिनियम और संबिधियों सहित बीबीएयू के सभी शैक्षणिक, अनुसंधान और प्रसार कार्यक्रम, डॉ. अम्बेडकर के शिक्षा को समग्र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवर्तन का उपकरण बनाने के मूल दर्शन से प्रेरित हैं जो सबसे पहले हमारे समाज के सबसे वंचित वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करता है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम/योजनाएं

एआईसीटीई अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों में तकनीकी पाठ्यक्रम का अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को या तो एक योजना के रूप में या एक योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का सार:**

  भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों/कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले और एम.ई./एम.टेक./एम. आर्क./एम. डेस. के अनुमोदित संख्या में दिशानिर्देशों के अनुसार गेट/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को एआईसीटीई द्वारा डीबीटी के माध्यम से 24 महीने के लिए 12400/– रु. प्रति माह की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **प्रारंभ की तिथि:** 1987 से
- **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:**

  पीजी छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश के समय वैध गेट/सीईईडी अंक है।

पीजी छात्रवृत्ति योजना (नवीनतम और नवीनीकरण)

राशि (रु. में)

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1416	17557987	427	5294800	99	1227600

एआईसीटीई डॉक्टरल छात्रवृत्ति (एडीएफ)

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का सारः**

  स्टार्ट–अप की ओर ले जाने वाले संस्थान और उद्योगों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देकर इंजीनियरिंग/प्रबंधन/डिजाइन में तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभा का पोषण करके एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/विभागों/संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। पात्र अध्येताओं को छात्रवृत्ति एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ) योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएगी।

- **परिलब्धियाँ एवं भत्ते**

  चयनित उम्मीदवार पहले दो वर्षों में 37,000 रुपये की मासिक अध्येतावृत्ति और तीसरे में 42,000 रुपये प्रतिमह के अलावा सरकारी मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता के पात्र हैं। इसके अलावा, एक अध्येत्ता को वार्षिक आकस्मिक अनुदान के रूप में 15000/– रुपये दिए जाते हैं।

- **प्रारंभ की तिथि : 2018–19**

एआईसीटीई डॉक्टरल छात्रवृत्ति (एडीएफ) (नवीनतम और नवीनीकरण)

राशि (रु. में)

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
86	36691445	18	6514596	0	0

छात्राओं के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का सारः**

  एआईसीटीई मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 50,000/– रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  - o 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियां (डिप्लोमा के लिए 5000 और डिग्री के लिए 5000)।
  - o शेष 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर आदि सहित) की सभी पात्र छात्राए
  - o अ.ज.जा. के लिए 7.5%, अ.जा. के लिए 15% और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है।

- प्रारंभ की तिथिः 2014–15

- **योजना के कार्यान्वयन का तरीकाः**

  राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से देश भर के एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री) नवीनतम और नवीनीकरण **राशि (रु. में)**

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1433	69801485	586	28690775	0	0

प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा) नवीनतम और नवीनीकरण **राशि (रु. में)**

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1877	93850000	840	42000000	0	0

एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का सार:**

  यह योजना एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें अनाथ बच्चों, कोविड–19 के कारण मारे गए माता–पिता के बच्चों, कार्रवाई में शहीद हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बच्चों (शहीद) को शिक्षा में जारी रखने के लिए प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने हेतु 50,000/– रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। प्रारंभ तिथि: 2021–22

- **योजना के क्रियान्वयन का तरीका:**

  पूरे देश से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री) नवीनतम और नवीनीकरण **राशि (रु. में)**

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
32	1650000	7	350000	0	0

स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा) नवीनतम और नवीनीकरण **राशि (रु. में)**

अ.जा.		अ.ज.जा.		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
28	1400000	18	900000	0	0

आईआईटी द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों हेतु प्रदान किए गए लाभ

(क) विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारत सरकार नियमावली के अनुसार सीटों के आरक्षण का अनुपालन किया जाता है।

(ख) जेईई के माध्यम से प्रवेश के लिए अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है।

(ग) यदि अ.जा./ अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी आवेदकों के लिए आरक्षित सीटें पूरी तरह से नहीं भरी जाती हैं, तो प्रवेश मानदंडों में और छूट के आधार पर सीमित संख्या में उम्मीदवारों को एक वर्ष के प्रारंभिक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है। इस पाठ्यक्रम के लिए चयन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन छात्रों की सूची से किया जाता है जो प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाए थे। आईआईटी में प्रारंभिक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करने पर, वे बी.टेक कार्यक्रम में शामिल होने के पात्र होंगे और उन्हें दोबारा जेईई लिखने की आवश्यकता नहीं होगी।

(घ) सभी अ.जा./ अ.ज.जा. पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में ट्यूशन शुल्क के भुगतान से छात्र मुक्त हैं।

(ङ) अधिकांश आईआईटी अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों को बी.टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आवासीय स्थान से संस्थान तक यात्रा भत्ता (द्वितीय श्रेणी ट्रेन किराया/साधारण बस किराया) दे रहे हैं।

(च) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के वे छात्र जिनके माता–पिता की आय 4.5 लाख रु. प्रतिवर्ष से कम है, उन्हें छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिसमें 250/– रुपये प्रति माह की पॉकेट मनी और मूल मेनू पर निःशुल्क मेसिंग शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को एक सेमेस्टर के लिए निःशुल्क बुक बैंक की सुविधा प्रदान की जाती है।

(छ) सामान्य श्रेणी के लिए विनिर्दिष्ट कट–ऑफ अंकों में आरक्षित श्रेणी के लिए छूट।

(ज) आरक्षित श्रेणियों के लिए प्रवेश परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क कम कर दिया गया है।

(झ) छात्रों को नीट (यूजी) और जेईई (मुख्य) प्रवेश परीक्षाओं के लिए बेहतर ढ़ंग से अभ्यास करने में मदद करने के लिए, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट तक उम्मीदवारों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने हेतु ऑनलाइन निःशुल्क एक मोबाइल ऐप "नेशनल टेस्ट अभ्यास" शुरू किया है।

(ञ) सरकार की एक अन्य पहल जिसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान – प्रोफेसर असिस्टेड लर्निंग (आईआईटी–पीएएल) कहा जाता है, आईआईटी और अन्य संस्थानों में शामिल होने के इच्छुक कक्षा XIवीं और XIIवीं कक्षा के छात्रों के लिए आईआईटी प्रोफेसरों द्वारा तैयार किए गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित और भौतिकी में वीडियो सामग्री प्रदान करती है। यह सामग्री स्वयंप्रभा के समर्पित डीटीएच चैनलों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

आईआईएम द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान किए गए लाभ

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों के आरक्षण में भारत सरकार की नियमावली के अनुसार अनुपालन किया जाता है। वर्ष 2023–25 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल 8,517 छात्रों ने प्रवेश लिया, जिनमें से 1261 छात्र अ.जा. श्रेणी और 535 छात्र अ.ज.जा. श्रेणी से हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएम) में अ.जा./ अ.ज.जा. के प्रतिनिधित्व का प्रतिशतः

वर्ष श्रेणी	2018–19		2019–20		2020–21		2021–22		2022–23		2023–24	
	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी	एससी	एसटी
छात्रों की सं.	756	356	794	373	962	407	1034	342	1068	417	1261	535
प्रतिशत	14.60	6.86	14.34	6.80	14.95	6.29	15.01	4.96	14.88	5.90	14.80	6.28

आईआईएसईआर और आईआईएससी द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

i. आईआईएसईआर और आईआईएससी द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों के लिए सीटों के आरक्षण में भारत सरकार की नियमावली के अनुसार अनुपालन किया जाता है।

ii. सभी आईआईएसईआर और आईआईएससी अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों से संबंधित सभी छात्रों के लिए शिक्षण शुल्क माफी लाभ को प्रदान कर रहे हैं।

iii. अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को केंद्र/राज्य/ सरकार/अन्य वित्तीयन एजेंसियों से छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए सभी संभव सहायता प्रदान की जा रही है।

छात्रों का प्रवेश 2022–2023

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष 2022–23 में छात्रों का प्रवेश	अ.जा श्रेणी से संबंधित छात्र	अ.ज.जा श्रेणी से संबंधित छात्र
1	आईआईएसईआर कोलकाता	350	48	23
2	आईआईएसईआर पुणे	356	38	21

क्र. सं.	संस्थाओं के नाम	वर्ष 2022–23 में छात्रों का प्रवेश	अ.जा श्रेणी से संबंधित छात्र	अ.ज.जा श्रेणी से संबंधित छात्र
3	आईआईएसईआर मोहाली	374	57	20
4	आईआईएसईआर भोपाल	532	41	29
5	आईआईएसईआर टीवीएम	491	58	27
6	आईआईएसईआर तिरुपति	220	36	14
7	आईआईएसईआर बेरहामपुर	215	25	17
8	आईआईएससी बंगलोर	1309	167	46

आईआईएसईआर और आईआईएससी में अ.जा./अ.ज.जा. छात्रों के प्रतिनिधित्व का औसतन प्रतिशत

संस्थान का नाम	2021–22	2022–23
आईआईएसईआर	अ.जा. – 13.64% अ.ज.जा. – 05.26%	अ.जा. – 11.93% अ.ज.जा. – 05.94%
आईआईएससी	अ.जा. – 12.24% अ.ज.जा. – 03.78%	अ.जा. – 12.75% अ.ज.जा. – 03.51%

आईआईटी द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

i. विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सीटों के आरक्षण में भारत सरकार की नियमावली के अनुसार अनुपालन किया जाता है;

ii. केंद्रीय वित्तपोषित आईआईआईटी में शिक्षण शिल्क के भुगतान से सभी अ.जा./ अ.ज.जा. छात्र मुक्त हैं।

iii. पात्र छात्रों को सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय एवं दिव्यांग विभाग से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

केंद्रीय वित्तपोषित उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं (सीएफएचईआई) में अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों के प्रतिनिधित्व (नामांकन) का प्रतिशत (%)

क्र. सं.	संस्थान के नाम	2021–22		2022–23	
		एससी	एसटी	एससी	एसटी
1	आईआईआईटी इलाहाबाद	12.28	4.94	13.50	5.01
2	आईआईआईटी एम ग्वालियर	14.68	5.94	14.53	6.16
3	आईआईआईटीडी एंड एम जबलपुर	14.48	6.97	16.41	7.46
4	आईआईआईटीडी एंड एम कांचीपुरम	14.11	6.58	14.63	6.77
5	आईआईआईटीडी एंड एम कुरनूल	18.0	8.5	15.68	8.47

एनआईटी द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. के छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) और भारतीय इंजीनियरिंग विज्ञान संस्थान (आईआईईएसटी), शिबपुर (पश्चिम बंगाल) केंद्रीय वित्तपोषित स्वायत्त तकनीकी संस्थान हैं और दिनांक 15 अगस्त, 2007 को अधिनियमित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान अधिनियम, 2007 के तहत इन्हें 'राष्ट्रीय महत्व का संस्थान' घोषित किया गया है।

एनआईटी और आईआईईएसटी शिबपुर के स्नातक कार्यक्रमों में प्रवेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा (मुख्य) और तदनुसार संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेएसएसए) द्वारा आयोजित काउंसलिंग में छात्रों द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर होता है। इन 32 संस्थानों में छात्रों को सीटें आवंटित करते समय भारत सरकार द्वारा केंद्रीय शैक्षिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन किया जाता है। एनआईटी में अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों का प्रतिशत इस प्रकार है:

	2021–22		2022–23	
	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.जा.	अ.ज.जा.
एनआईटी/ आईआईईएसटी शिबपुर	14.16%	7.56%	14.26%	7.69%

- अ.जा./ अ.ज.जा./पीडब्ल्यूडी श्रेणी के छात्रों को शैक्षणिक वर्ष 2016–17 से स्नातक स्तर पर पूर्ण रूप से शिक्षण शुल्क छूट मिल रही है। एनआईटी और आईआईईएसटी में अ.जा. / अ.ज.जा. /पीएच एम.टेक छात्रों के लिए भी शुल्क छूट दे दी गई है।
- जेईई के माध्यम से प्रवेश के लिए अ.जा./ अ.ज.जा. उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी गई है।
- सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित कट–ऑफ अंकों में आरक्षित श्रेणी हेतु छूट।
- प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क आरक्षित श्रेणियों के लिए कम कर दिया गया है।
- अधिकांश एनआईटी में अ.जा./ अ.ज.जा. / ओबीसी प्रकोष्ठ है जिसमें अ.जा./ अ.ज.जा. से संबंधित छात्र सदस्य हैं और कुछ संस्थानों में समान अवसर प्रकोष्ठ/छात्र शिकायत प्रकोष्ठ के रूप में अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों की शिकायतों का निवारण करने के लिए अलग–अलग प्रणाली हैं। छात्र शिकायत समिति/छात्र सोशल क्लब, जिसमें संकाय और गैर–संकाय के साथ छात्र सदस्य होते हैं।

इग्नू द्वारा अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को प्रदान किए गए लाभः

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) की स्थापना 1985 में संसद के एक अधिनियम द्वारा मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से समाज के सभी वर्गों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए की गई थी। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर नवीन और आवश्यकता–आधारित कार्यक्रम प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय शिक्षा को समावेशी बनाकर और कम लागत पर देश के सभी हिस्सों में समाज के वंचित और उपेक्षित रहने वाले वर्गों तक पहुंच बनाकर इसका लोकतांत्रीकरण करता है। इग्नू एक लचीला और नवीन शिक्षण दृष्टिकोण अपनाकर निरंतर उच्च शिक्षा के अवसरों का लगातार विस्तार कर रहा है जो प्रशिक्षार्थियों को शिक्षा से काम की ओर और इसके विपरीत जाने हेतु प्रोत्साहित करता है, जो देश की विविध आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है, और पूरी क्षमता से मानवीय संसाधनों का दोहन करने और जनसांख्यिकीय लाभांश का लाभ उठाने की भी आवश्यकता है। विश्वविद्यालय ने अपने छात्र सहायता नेटवर्क के माध्यम से उत्कृष्ट बुनियादी सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण दूरस्थ और ऑनलाइन शिक्षण प्रदान करने में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाली घनी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षार्थी सहायता केंद्र (एलएससी) स्थापित करता है। विश्वविद्यालय ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में कम से कम एक क्षेत्रीय केंद्र (छात्र सहायता नेटवर्क की मध्यस्थता) स्थापित किया है। ये राज्य अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले हैं। इन क्षेत्रों में स्थित क्षेत्रीय केंद्र नियमित रूप से स्थानीय मेलों, त्योहारों में भाग लेते हैं एवं अ.जा. और अ.ज.जा. समुदायों के युवाओं को उनकी शैक्षणिक, पेशेवर और व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों के चयन में मदद करने के लिए स्कूलों और कॉलेजों का दौरा करते हैं।

विश्वविद्यालय ने कुल 3.4 मिलियन से अधिक छात्र संख्या का अनुमान लगाया है; इनमें से 13.1 हजार छात्रों की महत्वपूर्ण संख्या को रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान नए प्रवेश और पुनः पंजीकरण के माध्यम से जोड़ा गया था। नामांकन के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इनमें से 49% महिलाएं हैं, 54% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और 52% अ.जा./ अ.ज.जा. वर्ग से हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय प्रति वर्ष 2.5 लाख से अधिक नहीं है, को शिक्षा मंत्रालय से प्राप्त एससीएसपी और टीएसपी अनुदान का उपयोग करने के लिए चयनित शैक्षणिक कार्यक्रमों (बीए–जनरल, बी.एससी. जनरल और बी.कॉम. जनरल) में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। रिपोर्ट की गई अवधि में लगभग 50 हजार अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों ने वित्तीय सहायता का लाभ उठाया है।

स्कूल शिक्षा

समता हेतु विशेष परियोजनाएं: नामांकन अभियान, प्रतिधारण और प्रेरणा शिविर, लैंगिक जागरूकता मॉड्यूल आदि को बढ़ावा देकर पहुंच, प्रतिधारण और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इक्विटी के तहत विभिन्न पहलों के लिए विशेष राज्य विशिष्ट परियोजनाओं पर बल दिया जाता है। ऐसी परियोजनाओं में जीवन कौशल, जागरूकता कार्यक्रम, उत्प्रेरक, सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन आदि शामिल हैं।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी): दिनांक 30.09.2023 तक, केजीबीवी के विलय/ अभिसरण को ध्यान में रखते हुए, संस्वीकृत केजीबीवी की संख्या 5639 है। इनमें से 5074 केजीबीवी 691304 बालिकाओं के नामांकन के साथ कार्यरत हैं। बालिकाओं के नामांकन का श्रेणीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

केजीबीवी संस्वीकृत	कार्यात्मक केजीबीवी	एससी	एसटी	ओबीसी	बीपीएल	मुस्लिम
5639	5074	189696	178568	249517	46195	27194

समग्र शिक्षा के 'रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण' के तहत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों (केजीबीवी) में पढ़ने वाली बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2023–24 में केजीबीवी छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु 4013 केजीबीवी को 482.84 लाख रु. की राशि स्वीकृत की गई।

तालिका: वर्ष 2020–21 और 2021–22 के लिए अ.जा. और अ.ज.जा. का जीईआर

वर्ष	प्रारंभिक (I-VIII)			मध्यमिक (IX-X)			उच्चतर माध्यमिक (XI-XII)		
	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी	सभी	एससी	एसटी
2020-21	99.1	108.6	102.7	79.8	84.8	78.6	53.8	56.1	45.2
2021-22	100.1	109.7	103.4	79.6	84.9	78.1	57.6	61.5	52.0

(स्रोत: यूडाइस)

राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस):

केंद्रीय क्षेत्र की 'राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना' योजना मई, 2008 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मेधावी छात्रों को VIIIवीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ने से रोकने एवं XIIवीं कक्षा तक उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने हेतु प्रोत्साहित करना था। योजना के तहत प्रति छात्र 12000/– रुपये प्रतिवर्ष (1000 रुपये प्रति माह) की दर से छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। यह योजना वर्ष 2018–19 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर पूरी तरह से लागू हो गई है। मंत्रालय लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारा छात्रों को सीधे उनके बैंक खातों में छात्रवृत्ति वितरण की योजना हेतु कार्यान्वयन कर्ता बैंक एसबीआई को जारी करने के लिए वार्षिक बजट प्रावधान से निधि स्वीकृत करता है। ऐसे छात्र जिनके माता–पिता की आय सभी स्रोतों से 3,50,000 रु. प्रति वर्ष से अधिक नहीं है, वे छात्रवृत्ति का लाभ लेने के पात्र हैं। इस योजना में कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 1,00,000 छात्रवृत्तियां देने और योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण की परिकल्पना की गई है। नविस, केविसं और आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्ति का कोटा है। राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण है। योजना के तहत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए छात्रों का चयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आयोजित चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाता है और पात्र छात्रों की सूची संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। योजना के लिए 100% निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

तालिका : एसटी/एससी घटक हेतु एनएमएमएसएस के तहत आवंटित बजट:

क्र.सं.	वित्त वर्ष	बजट आवंटन (सं.अ. के अनुसार) (₹ करोड़ में)	एसटी वास्तविक (₹ करोड़ में)	लाभार्थी एसटी की सं.	बजट आवंटन (सं. अ. के अनुसार) (₹ करोड़ में)	एससी वास्तविक (₹ करोड़ में)	लाभार्थी एससी की सं.
1	2020-21	30.50	26.80	22562	65.00	70.34	58307
2	2021-22	10.50	19.75	16460	35.50	57.74	48116
3	2022-23	16.00	31.05	29695	51.00	70.11	60404
4	2023-24 रु	22.00			61.00		

#दिनांक 12-02-2024 की स्थिति के अनुसार

' अ.जा./ अ.ज.जा. मद की समाप्ति के बाद योजना के सामान्य मद से व्यय के कारण वास्तविक व्यय बजट आवंटन से अधिक हो रहा है।

'' एनएमएमएसएस को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) पर रखा गया है, जो आवेदनों के पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए प्रतिवर्ष जुलाई से दिसंबर तक संचालित होता है। अंतिम रूप से सभी प्रकार से पूर्ण सत्यापित आवेदनों पर अंतिम तिमाही में छात्रवृत्ति राशि की स्वीकृति और वितरण के लिए विचार किया जाता है।

इक्विटी में नवोदय विद्यालय समिति (नविस) की पहलः

नवोदय विद्यालय योजना, आरटीई अधिनियम या भारत सरकार के अन्य प्रावधानों के अनुसार जेनवि में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को प्रदान की जाने वाली कुछ विशेष सुविधाएं इस प्रकार हैं:

- नवोदय विद्यालय योजना, आरटीई अधिनियम या भारत सरकार के अन्य प्रावधानों के अनुसार जनवि में अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को प्रदान की जाने वाली कुछ विशेष सुविधाएं इस प्रकार हैं:

वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जाति (एससी) सं. केंद्रित जिलों में स्वीकृत अतिरिक्त द्वितीय जनवि:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवि (जिले)
1.	मध्य प्रदेश	उज्जैन
2.	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	जम्मू
3.	पंजाब	अमृतसर
4.	आंध्र प्रदेश	प्रकाशम
5.	कर्नाटक	गुलबर्ग
6.	राजस्थान	श्रीगंगानगर
7.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर
8.	बिहार	गया
9.	झारखण्ड	पलामू
10.	पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना

वर्ष 2008 के दौरान अनुसूचित जनजाति (एसटी) सं. केंद्रित जिलों में स्वीकृत अतिरिक्त द्वितीय जनवि:

क्र. सं.	राज्य/यूटी	जनवि (जिले)
1.	छत्तीसगढ़	सुकमा (पूर्व मेंदंतेवाड़ा)
2.	मध्य प्रदेश	ज़बुआ
3.	ओडिशा	मल्कानगिरी
4.	आंध्र प्रदेश	पूर्वी गोदावरी (पूर्व मेंखम्मम)
5.	राजस्थान	बांसवारा
6.	झारखण्ड	पाकुड़
7.	गुजरात	दाहोद
8.	महाराष्ट्र	नंदुरबार
9.	असम	कार्बी आंगलोंग
10.	मेघालय	पूर्वी खासी पहाड़ियाँ

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधित जिले में उनकी आबादी के अनुपात में प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि किसी भी जिले में ऐसा आरक्षण राष्ट्रीय औसत (एससी के लिए 15% और एसटी 7.5%) से कम नहीं होगा लेकिन दोनों श्रेणियों (एससी और एसटी) को मिलाकर अधिकतम 50% के अध्यधीन होगा। ये आरक्षण विनिमेय हैं और खुली मेधा के तहत चयनित उम्मीदवारों के अतिरिक्त हैं।
- जवाहर नवोदय विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा, जिसमें निःशुल्क भोजन और आवास के साथ–साथ यूनिफ़ार्म, पाठ्यपुस्तकें, प्रौडिंग आइटम स्टेशनरी, दैनिक उपयोग की वस्तुएं, परीक्षा शुल्क और आधिकारिक शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने वालों के लिए यात्रा पर व्यय (टीए/डीए) आदि शामिल हैं जो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों को प्रदान किया जाता है।
- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणियों से संबंधित छात्रों के समग्र विकास के लिए सह–पाठयक्रम गतिविधियों, बाह्य गतिविधियों, खेलकूद, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड जैसे पर्याप्त अवसर भी प्रदान किए जाते हैं।

जनवि में अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों का नामांकन:

दिनांक 31.10.2023 की स्थिति के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों का श्रेणी–वार नामांकन आंकड़ा इस प्रकार है:

इक्विटी में केंद्रीय विद्यालय संगठन (केविसं) की पहलें :

केन्द्रीय विद्यालय संगठन, भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित, शिक्षा मंत्रालय द्वारा 15 दिसंबर 1965 को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के XXI के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है। संगठन का प्राथमिक उद्देश्य भारत सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों, अस्थायी जनसंख्या और दूरस्थ में रहने वाले लोगों सहित अन्य लोगों के बच्चों के लिए स्कूलों को उपलब्ध करना, स्थापित करना, सहायता करना, रखरखाव, नियंत्रण और प्रबंधन करना है, जिसे इसके बाद 'केंद्रीय विद्यालय' कहा जाएगा और देश के अविकसित स्थानों तथा स्कूलों में अनुकूल माहौल प्रदान करने हेतु आवश्यक सभी कार्य और व्यवस्था करना है। केंद्रीय विद्यालयों में सभी नए प्रवेशों में अनुसूचित जाति के लिए 15% सीटें और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% सीटें और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी–एनसीएल) के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं। आरटीई कोटा के तहत प्रवेश पाने वाले अ.जा./ अ.ज.जा. छात्रों को शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। दिनांक 30.09.2023 की, स्थिति के अनुसार 2,82,759 अनुसूचित जाति और 91,700 अनुसूचित जनजाति के छात्र केंद्रीय विद्यालयों में नामांकित हैं।

इक्विटी पर राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई):

शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड में प्रावधान है कि अ.जा./ अ.ज.जा. /ओबीसी पीडब्ल्यूडी और अन्य श्रेणियों के लिए आरक्षण और छूट केंद्र सरकार/राज्य सरकार के नियमों के अनुसार, जो भी लागू हो, होगी।

कुल	छात्र	छात्राएँ	ग्रामीण	शहरी	सामान्य	ओबीसी	एससी	एसटी
2,84,963	1,64,797	1,20,166	2,55,076	29,887	50,685	1,07,195	69,067	58,016
%	57.83	42.17	89.51	10.49	17.79	37.62	24.24	20.36

❖ ❖ ❖

2

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का शैक्षिक विकास

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का शैक्षिक विकास

वर्तमान में, 10 राज्य और 2 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त है: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। इन राज्यों की कुछ विशिष्ट विशेषताएं हैं। उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ, पहाड़ी क्षेत्र हैं और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी मानदंड विशेष रूप से भिन्न हैं। इन राज्यों में संरचानात्मक विकास के प्रयासों में भौगोलिक त्रुटियाँ और विकास में विलंब से शुरुआत करने वाले भी हैं। सार्वजनिक व्यय राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों को योजना सहायता में अनुदान के रूप में 90% और संघ राज्य क्षेत्र होने के कारण लद्दाख में 100% अनुदान स्वीकृत करती है।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों का शैक्षिक विकास

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उच्च शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन 2021–22	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (18–23 वर्ष) 2021–22	जेंडर समानता सूचकांक उच्च शिक्षा (18–23 वर्ष) 2021–22
1	अरुणाचल प्रदेश	64890	36.5	0.90
2	असम	678012	16.9	1.09
3	हिमाचल प्रदेश	319651	43.1	1.33
4	जम्मू और कश्मीर	400423	24.8	1.20
5	लद्दाख	4440	11.5	2.19
6	मणिपुर	130388	35.4	1.01
7	मेघालय	96453	25.4	1.24
8	मिजोरम	46771	32.3	1.06
9	नागालैंड	51223	18.8	1.28
10	सिक्किम	33761	38.6	1.21
11	त्रिपुरा	100551	20.7	0.89
12	उत्तराखंड	567704	41.8	1.09

स्रोत: अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021–22

पूर्वोत्तर राज्यों में कुल छात्र नामांकन वर्ष 2014–15 में 9.36 लाख की तुलना में वर्ष 2021–22 में 12.02 लाख है। वर्ष 2021–22 में पूर्वोत्तर राज्यों में महिला नामांकन 6.07 लाख है, जो पुरुष नामांकन 5.95 लाख से अधिक है।

विशेष श्रेणी के राज्यों में केंद्र वित्तपोषित उच्च शैक्षिक संस्थान

राज्य	केंद्रीय विश्वविद्यालय	आईआईएम	आईआईटी	एनआईटी	आईआईआईटी	अन्य तकनीकी संस्थाएं
अरुणाचल प्रदेश	01			01		01—एनईआरआईएसटी
असम	02		01	01	01	01—सीआईटी कोकराझार
मणिपुर	01			01	01	
मेघालय	01	01		01		
मिजोरम	01			01		
नागालैंड	01			01		
सिक्किम	01			01		
त्रिपुरा	01			01	01	
हिमाचल प्रदेश	01	01	01	01	01	
जम्मू और कश्मीर	02	01	01	01		
उत्तराखंड	01	01	01	01		

प्रधान मंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान

पीएम उषा

प्रधानमंत्री उच्च शिक्षा अभियान (पीएम—यूएसएचए) के रूप में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए) के तीसरे चरण को पहुंच, उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में समता और गुणवत्ता में सुधार हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता देने के लिए 12926.10 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 31 मार्च 2026 तक स्वीकृति दी गई है। पीएम—उषा को फ़ोक्स जिलों की तरह ही योजना में चिन्हित किए गए असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए बनाया गया है। राज्यों को निम्न जीईआर, अ.जा./ अ.ज.जा. की जनसंख्या, महिला नामांकन आदि के आधार पर जिलों को चिन्हित करने हेतु नम्यता प्रदान फ़ोक्स की गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच निधियन पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू—कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात और अन्य राज्यों तथा विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत बिना विधानमंडल राहत संघ राज्य क्षेत्र 100% केंद्रीय वित्त पोषित होंगे।

माननीय प्रधानमंत्री 20 फरवरी, 2024 को जम्मू में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के अवसर पर संबोधित कर रहे हैं

प्रधानमंत्री 20 फरवरी, 2024 को जम्मू में 'विकसित भारत विकसित जम्मू' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।

विशेष श्रेणी के राज्यों में शैक्षिक विकास के लिए इग्नू की पहल

इग्नू ने पूर्वोत्तर राज्यों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू–कश्मीर सहित अविकसित, दुर्गम, दूरदराज और अल्पसंख्यक बहुल विशेष श्रेणी के राज्यों में रहने वाले छॉत्रों के लिए इसे सुलभ बनाने हेतु उच्च शिक्षा के विकास के लिए विशेष पहल की हैं। इन सभी राज्यों में इग्नू क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना के साथ पहल की शुरूआत की गई। उसके बाद से, विश्वविद्यालय ने इन राज्यों के दूरदराज क्षेत्रों में उच्च शिक्षा तक पहुंच की समता सुनिश्चित करने, शिक्षा के पारंपरिक रुपों को पूरक बनाने हेतु अपने छात्र सहायता नेटवर्क का विस्तार करके महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

- **पूर्वोत्तर क्षेत्र** – वर्तमान में, इग्नू का संचालन आठ राज्यों में निम्नलिखित स्थानों पर नौ आरसी के नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है: शिलांग (मेघालय), गुवाहाटी (असम), जोरहाट असम), इंफाल (मणिपुर), ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश), कोहिमा (नागालैंड), आइजोल (मिजोरम), अगरतला (त्रिपुरा) और गंगटोक (सिक्किम)। इग्नू उच्चतर शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास और अन्य पहल के अवसर प्रदान करके पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में शैक्षिक विकास के विस्तार की सुविधा प्रदान करता है। विश्वविद्यालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 राज्यों में 9 क्षेत्रीय केंद्रों और 159 प्रशिक्षार्थी सहायता केंद्रों (एलएससी) के इस नेटवर्क के माध्यम से शैक्षिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और रिपोर्ट की अवधि के दौरान क्षेत्रीय केंद्र इम्फाल (मणिपुर) में एक नया एलएससी खोला गया था।
- **उत्तराखंड** – उत्तराखंड राज्य को प्रशिक्षार्थी सहायता सेवाएं प्रदान करने हेतु 24 एलएससी के नेटवर्क के माध्यम से देहरादून में संचालितएक क्षेत्रीय केंद्र द्वारा सेवा प्रदान की जाती है।
- **हिमाचल प्रदेश** – हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक और परामर्शी सेवाएं सहायता क्षेत्रीय केंद्र शिमला के तहत संचालित 41 एलएससी की सहायता से सुचारु बनाया जाता है।
- **जम्मू, कश्मीर और लद्दाख** – इग्नू जम्मू और कश्मीर में दो आरसी अर्थात आरसी जम्मू और आरसी कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए, लेह में एक उप–क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से संचालन करता है। आरसी जम्मू के अधीन एलएससी की संख्या 39 और श्रीनगर के अधीन 45 है। लेह के उप–क्षेत्रीय केन्द्र के अधीन 4 एलएससी हैं।

पूर्वोत्तर में पुस्तक संवर्धन कार्यकलाप

एनबीटी–इंडिया ने कई पुस्तक मेलों, साहित्यिक गतिविधियों और विशेष बिक्री अभियानों के माध्यम से पूवोत्तर में अपनी पुस्तक संवर्धन गतिविधियों को आगे बढ़ाया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एनबीटी–इंडिया ने असमिया बच्चों की पत्रिका मूचक के सहयोग से 25 से 28 मार्च 2023 तक जोरहाट, असम में 4 दिवसीय अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में विभिन्न साहित्यिक और अकादमिक पृष्ठभूमि से कुल 46 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान एनबीटी–इंडिया द्वारा बच्चों के लिए प्रकाशित लगभग 150 पुस्तकों का असमिया में अनुवाद किया गया। एनबीटी–भारत के पूर्वी क्षेत्रीय व कार्यालय ने 3 अन्य पुस्तक प्रदर्शनियां – क) काजीरंगा विश्वविद्यालय पुस्तक प्रदर्शनी (19 से 22 मई 2023), ख) विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय, तेजपुर (20 से 22 जून 2023), ग) एमए आनंदमयी विद्यापीठ, अगरतला (30 और 31 अगस्त 2023) भी आयोजित कीं।

लद्दाख पुस्तक महोत्सवः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत ने लेह, लद्दाख में साहित्य प्रेमियों और पुस्तक प्रेमियों के लिए अपनी तरह का पहला पुस्तक महोत्सव आयोजित किया। लद्दाख पुस्तक महोत्सव का उद्घाटन 12 जुलाई 2023 को माननीय उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा द्वारा किया गया था। इस 5 दिवसीय महोत्सव का आयोजन 12 से 16 जुलाई 2023 तक संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख प्रशासन के सहयोग से न्यू मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम (एनडीएस मेमोरियल स्पोर्ट्स ग्राउंड), लेह में किया गया था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, माननीय उपराज्यपाल ने कहा, "पुस्तक लिखने की परंपरा हमारे देश की प्राचीन कला और साहित्य का हिस्सा है।" ''उत्सव में 50,000 से अधिक आगंतुकों की उपस्थिति के साथ पुस्तक महोत्सव का सफल समापन हुआ।

शिलोंग पुस्तक महोत्सवः एनबीटी–इंडिया द्वारा शिलांग पुस्तक मेले का आयोजन 18 से 24 सितंबर 2023 तक राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, शिलांग (मेघालय) में कला 86 संस्कृति विभाग और शिक्षा विभाग, मेघालय सरकार के सहयोग से किया गया था। पुस्तक मेले का उद्घाटन माननीय शिक्षा मंत्री श्री रक्कम ए संगमा ने यू सोसोथम ऑडिटोरियम, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, शिलांग में किया। शिलांग पुस्तक मेले में देशभर के लगभग 26 प्रकाशकों ने 50 स्टालों के माध्यम से भाग लिया। पुस्तक मेले की पूरी अवधि के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, बच्चों की गतिविधियाँ, साहित्यिक सत्र आदि आयोजित किए गए।

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम)

भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) भारत सरकार (शिक्षा मंत्रालय) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त संस्थान हैं। वर्तमान में, 21 आईआईएम हैं, जिनमें से 4 आईआईएम अर्थात् आईआईएम शिलांग, आईआईएम काशीपुर, आईआईएम सिरमौर और आईआईएम जम्मू हैं जो वर्तमान में क्रमशः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों (संघ राज्य क्षेत्र) में कार्यात्मक हैं। शिक्षा मंत्रालय शैक्षणिक कार्यकलापों, अस्थायी परिसरों की स्थापना और स्थायी परिसरों के निर्माण के लिए आईआईएम की स्थापना हेतु निधि उपलब्ध करा रहा है। संबंधित आईआईएम को जारी किए गए बजट/निधि का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया हैः

आईआईएम का नाम	31.12.2023 की स्थिति के अनुसार छात्रों की सं.		31.12.2023 की स्थिति के अनुसार संकाय की स्थिति	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक जारी निधि (करोड़ में)
	पीजीपी	एफपीएम		
आईआईएम शिलांग	390	17	36	55.31
आईआईएम काशीपुर	321	9	46	0

आईआईएम का नाम	31.12.2023 की स्थिति के अनुसार छात्रों की सं.		31.12.2023 की स्थिति के अनुसार संकाय की स्थिति	दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक जारी निधि (करोड़ में)
	पीजीपी	एफपीएम		
आईआईएम सिमौर	310	3	36	25.46
आईआईएम जम्मू	265	33	44	27.45
कुल	**1286**	**62**	**162**	**108.22**

विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशासन के लिए भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सीटों का आरक्षण

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी)

भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित एनआईटी – अगरतला (त्रिपुरा) और एनआईटी – सिलचर (असम) सहित बीस (20) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपने अधिकार में ले लिया और उन्हें एनआईटी में अद्यतन कर दिया, जो अब मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत केंद्रीय वित्तपोषित प्रौद्योगिकी संस्थान हैं। एनआईटीएसईआर अधिनियम 2007 में इन संस्थानों शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया है। जम्मू–कश्मीर राज्य में भी एनआईटी–श्रीनगर नामक एकान आई टी कार्यात्मक है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के विधित अनुमोदन के बाद उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दस (10) नए एनआईटी भी स्थापित किए, जहां एनआईटी नहीं थे। दो मौजूदा पुराने एनआईटी – सिलचर (असम) और अगरतला (त्रिपुरा) के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में इन दस नए एनआईटी में से, छह (06) एनआईटी अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, स्थित हैं। सभी नए संस्थानों ने वर्ष 2010–11 से अपना शैक्षणिक सत्र शुरू कर दिया है। इन एनआईटी का मुख्य उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इच्छुक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, उच्च गुणवत्ता वाले अंतःविषयक अनुसंधान में भागीदार बनाना है, जो औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और समग्र रूप से समाज के लिए लाभकारी है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) में स्थित उपर्युक्त आठ (08) एनआईटी और एक (01) एनआईटी का संक्षिप्त सांख्यिकीय सारांश निम्नलिखित तालिका में देखा जा सकता है:–

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संकाय की सं– (सेवारत)	गैर–संकाय की सं– (सेवारत)	छात्र क्षमता	वर्ष 2023–24 में जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	अस्थायी/स्थायी परिसर
1.	एनआईटी – अगरतला (त्रिपुरा)	137	27	4646	70.09	स्थायी परिसर
2.	एनआईटी – अरूणाचंल प्रदेश	51	55	995	41.71	स्थायी परिसर
3.	एनआईटी – मणिपुर	42	11	1099	21.95	स्थायी परिसर में आंशिक रूप से स्थानांतरित
4.	एनआईटी – मेघालय	60	79	968	56.13	अस्थायी परिसर

क्र. सं.	संस्थान का नाम	संकाय की सं– (सेवारत)	गैर–संकाय की सं– (सेवारत)	छात्र क्षमता	वर्ष 2023–24 में जारी अनुदान (₹ करोड़ में)	अस्थायी/स्थायी परिसर
5.	एनआईटी – मिजोरम	34	23	666	34.41	अस्थायी परिसर
6.	एनआईटी – नागालैंड	33	26	1001	52.10	स्थायी परिसर
7.	एनआईटी – सिल्चर (असम)	238	54	4904	136.86	स्थायी परिसर
8.	एनआईटी – सिक्किम	26	36	710	20.00	स्थायी परिसर
9.	एनआईटी – श्रीनगर	159	181	4320	120.36	स्थायी परिसर

नोटः दिनांक 18.01.2024 तक जारी राशि प्रर्दशित की गई है,

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 और उसके तहत बनाई गई संविधियों द्वारा अभिशासित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं हैं। वर्षों से, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय शैक्षिक संस्थानों का निर्माण किया है जो उत्कृष्ट बुनियादी ढांचे और सर्वोत्तम उपलब्ध प्रतिभाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित अनुसंधान के माध्यम से गतिशील रूप से निरंतर हैं। वर्तमान में, निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में निम्नलिखित चार (4) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कार्यात्मक हैं :

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईआईटी के नाम	स्थापना का वर्ष	31–12–2023 तक स्थ संकाय सदस्य	31–12–2023 तक विद्यार्थियों की संख्या	इस वित्त वर्ष में अब तक जारी कुल निधि (करोड़ रुपए में)
1	असम	आईआईटी गुवाहाटी	1994	446	8369	417-47
2	उत्तराखंड	आईआईटी रुड़की	2001*	524	9735	544.77
3	हिमाचल प्रदेश	आईआईटी मंडी	2009	163	2359	136.68
4	जम्मू और कश्मीर	आईआईटी जम्मू	2016	114	1273	330.21

**2001 में इसे आईआईटी में परिवर्तित कर दिया गया*

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी)

देश में 25 आईआईआईटी कार्यात्मक हैं, जिनमें से 5 सीएफ–आईआईआईटी आईआईआईटी अधिनियम, 2014 द्वारा अभिशासित हैं और सार्वजनिक–निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत स्थापित 20 आईआईआईटी, आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम 2017 द्वारा अभिशासित हैं। 25 आईआईआईटी में से, 3 आईआईआईटी (पीपीपी) पूर्वोत्तर राज्यों गुवाहाटी (असम), सेनापति (मणिपुर) और अगरतला (त्रिपुरा) में कार्यात्मक हैं। इस योजना को दिनांक 26.11.2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था। योजना के अनुसार, प्रत्येक आईआईआईटी की पूंजीगत लागत 128.00 करोड़ रुपये होगी, जिसे

केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उद्योग भागीदार (ओं) द्वारा क्रमशः (पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में 57.5% 35% 7.5) 50:35:15 के अनुपात में योगदान दिया जाएगा। इसके अलावा, संकाय विकास कार्यक्रम के लिए 50.00 करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा, केंद्र सरकार प्रत्येक आईआईआईटी को 10.00 करोड़ रुपये तक के आवर्ती व्यय के लिए आंशिक सहायता प्रदान करेगी। संबंधित राज्य सरकार 50–100 एकड़ जमीन निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। प्रत्येक आईआईआईटी अपने संचालन व्यय को छात्र शुल्क, अनुसंधान और अन्य आंतरिक संसाधनों से शुरू होने के 5 वर्षों के भीतर स्वयं पूरा करेगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यात्मक 3 आईआईआईटी पर संक्षिप्त सार निम्नलिखित है:

आईआईआईटी गुवाहाटी

- आईआईआईटी गुवाहाटी की स्थापना हेतु अनुमोदन दिनांक 02.07.2012 को प्रदान किया गया था। शैक्षणिक सत्र 2013–14 में शुरू हुआ था। आईआईआईटी गुवाहाटी की कुल छात्र संख्या 1107 है।
- आईआईआईटी गुवाहाटी संसदीय अधिनियम [आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017] के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- श्री एस रामादोराई संस्थान के शासी बोर्ड (बीओजी) के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर गौतम बरुआ संस्थान के निदेशक हैं।
- संस्थान को स्थायी परिसर की स्थापना के लिए गुवाहाटी के सोनटोला और बोंगोरा गांव में 67 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। संस्थान पूरी तरह से अपने स्थायी परिसर से कार्यात्मक है।
- केंद्र सरकार ने आईआईआईटी गुवाहाटी को अपना पूरा हिस्सा 83.60 करोड़ रुपये (गैर–आवर्ती: 73.60 करोड़ रुपए, आवर्ती: 10.00 करोड़ रुपए) जारी कर दिया है। आईआईआईटी गुवाहाटी के उद्योग भागीदार हैं:
    - o टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस
    - o ऑइल इंडिया लिमिटेड
    - o एसआरईआई वित्त इनफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
    - o एंटरोन (राज्य सरकार पीएसयू)

आईआईआईटी सेनापति

- आईआईआईटी सेनापति की स्थापना का अनुमोदन दिनांक 28.02.2014 को दिया गया था। शैक्षणिक सत्र 2015–16 में शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान छात्रों की संख्या 248 है। आईआईआईटी सेनापति सीएसई और ईसीई में बीटेक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- आईआईआईटी सेनापति संसद के अधिनियम [आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017] के तहत एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है।
- डॉ. सुखी उराँव संस्थान के शासी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर कृष्णन बस्कर संस्थान के निदेशक हैं।
- श्री अमित शाह, माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.12.2020 को मायांगखांग में नए परिसर का निर्माण कार्य।
- केंद्र सरकार ने आईआईआईटी सेनापति को अपना पूरा हिस्सा 83.60 करोड़ रुपये (गैर–आवर्ती: 73.60 करोड़, आवर्ती: 10.00 करोड़) जारी कर दिया है। आईआईआईटी सेनापति के लिए उद्योग भागीदार इस प्रकार हैं:–
    - o मणिपुर आईटी एसईज़ेड परियोजना विकास कंपनी (एमपीडीसीओ)
    - o मणिपुर विकास सोसाइटी (एमडीएस)

आईआईआईटी अगरतला

- आईआईआईटी अगरतला की स्थापना के लिए अनुमोदन दिनांक 02.07.2012 को दिया गया था। शैक्षणिक सत्र दिनांक 2018–19 में शुरू हुआ, जिसमें वर्तमान छात्रों की संख्या 148 है। आईआईआईटी अगरतला सीएसई में बी.टेक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
- भारत के राजपत्र में वर्ष 2017 में आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 को प्रकाशित किया गया था। आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम के माध्यम से, 15 आईआईआईटी–पीपीपी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित किया गया है। अगरतला में आईआईआईटी सहित शेष 5 आईआईआईटी (पीपीपी) को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2020 के संशोधन के माध्यम से आईआईआईटी (पीपीपी) अधिनियम, 2017 में शामिल किया गया है।
- लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) कोन्सम हिमालय सिंह संस्थान के शासी वोर्ड के अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर अभय कुमार संस्थान के निदेशक हैं।
- वर्तमान में संस्थान एनआईटी अगरतला से कार्य करता है जो आईआईआईटी अगरतला का सलाहकार संस्थान है। पश्चिम त्रिपुरा के मोहनपुर सब–डिवीजन के अंतर्गत खोवाई चौमुहानी में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इसका शिलान्यास दिनांक 12.10.2022 को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।
- आज तक, संस्थान को 1.12 करोड़ रुपये (गैर–आवर्ती: 1.00 करोड़, आवर्ती: 0.12 करोड़) जारी किए गए हैं। आईआईआईटी अगरतला के लिए उद्योग भागीदार इस प्रकार हैं:–
- ओएनजीसी
- एनईईपीसीओ

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी)

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी) की स्थापना गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत तकनीकी कार्यबल का आधार बनाने के दृष्टिकोण से पूर्वोत्तर परिषद, शिलाँग के शुरू में प्रायोगिक परियोजना के रूप में, भारत सरकार द्वारा की गई थी जिसका उद्देश्य क्षेत्र में विकास के विभिन्न चरणों में आने वाली समस्याओं का सफलता पूर्वक सामना करना है। संस्थान का परिसर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी निर्जुली, ईटानगर में स्थित है, और सड़क, वायु और रेल मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। संस्थान 1 अप्रैल 1994 को शिक्षा मंत्रालय (एमओई), भारत सरकार के सीधे नियंत्रण में आया। इसे 31 मई, 2005 से यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। संस्थान में श्रेष्ठ योग्य, प्रेरित और अपेक्षाकृत युवा संकाय और गैर–शिक्षण कर्मचारियों का एक समर्पित समूह है। एनईआरआईएसटी छात्र अनुशासित, प्रेरित और ईमानदार हैं और उन्होंने देश के कुछ सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के छात्रों के साथ सफलतापूर्वक प्रतिस्पर्धा की है। संस्थान का विज़न और कार्यालय मिशन है:

विज़न: बहुसांकृतिक वातावरण में वैश्विक आवश्यकताओं और मानकों को पूरा करते हुए, समाज को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने हेतु नैतिक मूल्यों और सामाजिक जागरूकता के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा, अनुसंधान और उद्यमिता में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए सक्षम पेशेवर कार्यालय तैयार करना।

मिशन:

1. एक नवीन मॉड्यूलर प्रणाली के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में एक जगह बनाना।
2. उच्च नैतिक मूल्यों के साथ और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र के संदर्भ में विभिन्न विषयों में विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी तकनीकी और वैज्ञानिक जनशक्ति का उत्पादन करना।

3. हितधारकों, जवाबदेही, पर्यावरण और लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्कृष्टता हासिल करने के लिए इंजीनियरों/प्रौद्योगिकीविदों और प्रशिक्षुओं को रचनात्मकता से भरी मानसिकता प्रदान करना।

4. शिक्षण, अनुसंधान और परामर्श प्रथाओं में उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु भारत और विदेशों में विश्वस्तरीय अनुसंधान एवं विकास संगठनों, उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग विकसित करना।

संस्थान इंजीनियरिंग, विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान (वानिकी), और प्रबंधन के विभिन्न विषयों में प्रमाणपत्र (Xवीं कक्षा के बाद दो वर्ष), बी.टेक., एम.टेक, और एम.एससी, और एमबीए कार्यक्रम संचालित करता है। पीएचडी कार्यक्रम इंजीनियरिंग, विज्ञान, अनुप्रयुक्त विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन में प्रस्तुत किया जाता है। पाँच प्रमाणपत्र कार्यक्रम कृषि इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं। ऊपर बताई गई सभी शाखाओं के अलावा कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। वानिकी के छात्रों को बीएससी की प्रस्तुति की जाती है।

संस्थान ने 2022–23 में निम्नलिखित स्नातकोत्तर कार्यक्रम प्रदान किए:

क. कंप्यूटर विज्ञान एवं इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी में एमटेक।

ख. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के तहत पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में एमटेक।

ग. सिविल इंजीनियरिंग विभाग के तहत जियोतकनीकी इंजीनियरिंग में एमटेक।

घ. इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के तहत पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में एमटेक।

ङ. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के तहत कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग में एमटेक

च. मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के तहत थर्मल और फ्लूइड इंजीनियरिंग में एमटेक।

छ. इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में एमटेक (वीएलएसआई/संचार इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता)।

ज. कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत फार्म मशीनरी एवं पावर में एमटेक।

झ. कृषि अभियांत्रिकी विभाग के अंतर्गत मृदा एवं जल संरक्षण अभियांत्रिकी में एम.टेक

ञ. एमएससी वानिकी विभाग के अंतर्गत वानिकी में

ट. भौतिकी विभाग के अंतर्गत भौतिकी में एमएससी

ठ. रसायन विज्ञान विभाग के अंतर्गत रसायन विज्ञान में एमएससी

ड. गणित विभाग के अंतर्गत गणित में एमएससी

ढ. सेंटर फॉर मैनेजमेंट स्टडीज के तहत बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर।

वर्ष 2023 के जुलाई–दिसंबर सत्र तक, सभी मॉड्यूल में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2,438 थी। बड़ी संख्या में एनईआरआईएसटी के छात्र भारत और विदेशों में अग्रणी कॉर्पोरेट संस्थानों में शामिल होने के अलावा अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कई शीर्ष रैंक वाले शैक्षणिक संस्थानों में शामिल हुए हैं। संस्थान ने प्रतिष्ठित बाह्य निधियन एजेंसियों से कई प्रतिष्ठित प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं को सफलतापूर्वक चलाया है। संस्थानों की अन्य मुख्य विशेषताएं हैं:

- मॉड्यूलर तकनीकी शिक्षा प्रणाली;
- मल्टी–पॉइंट एंट्री और एक्ज़िट प्रणाली;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर तकनीकी जनाधार तैयार करने के लिए अपरंपरागत और अभिनव शैक्षणिक कार्यक्रम;
- ज्ञान, कौशल और नीति–आधारित शिक्षा प्रणाली का विकास;
- श्रेष्ठ मेधावी संकाय और समर्पित स्टाफ;
- पीजी और पीएचडी कार्यक्रम;

- सुसज्जित प्रयोगशालाएँ और कार्यशालाएँ;
- पूर्णतः आवासीय परिसर;
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु समर्पित सेवाएँ

वर्ष 2023–24 का वित्तीय आंकड़ा

एनईआरआईएसटी, इटानगर		(₹ करोड़ में)
वस्तु शीर्ष	**बजट अनुमान–2023–24**	**जारी की गई कुल निधि (24.01.2024 तक)**
ओएच– 31	40.00	30.00
ओएच– 35	23.00	17.50
ओएच– 36	68.00	48.40
कुल	**131.00**	**95.90**

केन्द्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कोकराझार (सीआईटी)

केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईटी) कोकराझार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय वित्तपोषित संस्थान है, जो असम में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद (बीटीसी) के कोकराझार जिले के मुख्यालय के पास एक शांत परिदृश्य में स्थित है। संस्थान की स्थापना 6 दिसंबर 2006 को हुई थी। इस संस्थान की उत्पत्ति 10 फरवरी, 2003 को केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच हस्ताक्षरित बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल (बीटीसी) पर समझौता ज्ञापन था। संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और शासी निकाय (बीओजी) के तहत कार्य करता है। 13 दिसंबर, 2018 को, संस्थान को मंत्रालय द्वारा डी–नोवो श्रेणी के तहत "मानद–विश्वविद्यालय संस्थान" घोषित किया गया था।

सीआईटी द्वारा वर्ष 2023–24 के दौरान कोकराझार में शुरू किए कुछ प्रमुख कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

- संस्थान के छात्रों के लिए 18 नवंबर 2023 को चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य में ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2023 को सीआईटी में बस स्टैंड के पास मनाया गया।
- सीआईटी ने 05 जून, 2023 को पर्यावरण दिवस मनाया और परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण की व्यवस्था की।
- सीआईटी ने 03 जून, 2023 को बीकेबी सेमिनार हॉल, सीआईटी में माउंट कंचनजंगा के सफल अभियान पर असम माउंटरिंग एसोसिएशन के अभियान दल के सदस्यों के लिए एक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया।
- 10 दिसंबर 2023 को प्रशासनिक भवन के सामने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस समारोह मनाया गया।
- 26 नवंबर 2023 को बीकेबी सेमिनार हॉल, सीआईटी में संविधान दिवस का आयोजन किया गया।
- संस्थान ने 25 नवंबर, 2023 को बीकेबी सेमिनार हॉल, सीआईटी में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए।
- 01 अक्टूबर 2023 को परिसर के चारों ओर स्वच्छता अभियान चलाया गया।
- संस्थान द्वारा 13 अगस्त 2023 को प्रभात फेरी एवं हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया।
- सीआईटी एनएसएस स्वयंसेवकों ने 20–25 जून, 2023 के दौरान बंगालपारा, दक्षिण सौबैझार (हाल्टुगांव), कोकराझार में बाढ़ प्रभावित परिवारों को कपड़े, कंबल, आवश्यक सामग्री वितरित की।
- 27 मई 2023 को बीकेबी सेमिनार हॉल, सीआईटी में साइबर सुरक्षा दिवस का आयोजन किया गया।

- 25 दिसंबर 2023 को सीआईटी अतिथि गृह कॉन्फ्रेंस हॉल में सुशासन दिवस आयोजित किया गया।

वर्ष 2023–24 का वित्तीय आंकड़ा

सीआईटी, कोकराझार, असम		(₹ करोड़ में)
वस्तु शीर्ष	ब.अ. – 2023–24	जारी की गई कुल निधि (24.01.2024 तक)
ओएच–31	15.00	9.06
ओएच–35	16.00	0.00
ओएच–36	38.00	22.63
कुल	**69.00**	**31.69**

केंद्रीय विश्वविद्यालय

वर्तमान में देश में 56 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। 56 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 46 केंद्रीय विश्वविद्यालय यूजीसी द्वारा वित्तपोषित हैं और 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से 9 केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित हैं, जो निम्न हैं:

क्र.सं.	विश्वविद्यालय के नाम
1.	असम विश्वविद्यालय
2.	तेजपुर विश्वविद्यालय
3.	राजीव गांधी विश्वविद्यालय
4.	मणिपुर विश्वविद्यालय
5.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी (एनईएचयू)
6.	मिजोरम विश्वविद्यालय
7.	नागालैंड विश्वविद्यालय
8.	सिक्किम विश्वविद्यालय
9.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय

छात्रवृत्ति

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने दिनांक 19.01.2022 के निर्णय द्वारा छात्र वित्तीय सहायता (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन [पीएम–यूएसपी] योजना) को दिनांक 31.03.2026 तक या अगली समीक्षा तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की स्वीकृति दी। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना में तीन (3) घटक केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, अर्थात् (1) कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की केंद्रीय क्षेत्र योजना; (2) जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना; और (3) केंद्रीय क्षेत्र ब्याज सब्सिडी योजना; और शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना शामिल हैं।

(i) पीएम–यूएसपी कॉलेज और विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय क्षेत्रक छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्यः** योजना के तहत पात्र मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है
- **पात्रताः** जो छात्र XIIवीं कक्षा में सफल उम्मीदवारों के शीर्ष 20 प्रतिशत में हैं और जिनकी पारिवारिक आय 4.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है, वे आवेदन करने के पात्र हैं।
- **अवसरः** प्रति वर्ष 82,000 नई छात्रवृत्तियाँ पुरस्कार हेतु उपलब्ध होती हैं (छात्रों के लिए 41000 और छात्राओं के लिए 41000)। इन्हें राज्य की 18–25 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या के आधार पर राज्य शिक्षा बोर्डों के मध्य विभाजित किया गया है।
- **छात्रवृत्ति दरः** छात्रवृत्ति की दर पहले तीन वर्षों के लिए 12,000/– रुपये प्रति वर्ष और 20,000/– रुपये प्रति वर्ष चौथे और पांचवें वर्ष के लिए है।
- **प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी)ः** यह योजना दिनांक 1.1.2013 से प्रभावी डीबीटी के तहत शामिल की गई है, जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है।
- **ऑनलाइन पोर्टलः** सीएसएसएस ने दिनांक 1.8.2015 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल

(www.scholarships.gov.in) को प्रभावी रुप से शुरू कर लिया है। शैक्षणिक वर्ष 2015 के बाद से उत्तीर्ण होने वाले योग्य छात्रों को पोर्टल के माध्यम से नई और नवीनीकरण छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। इस वर्ष पोर्टल दिनांक 01.10.2023 से खोला गया है और अभी भी खुला है।

- **आरक्षण:** योजना के तहत केंद्रीय आरक्षण नीति का अनुपालन किया जा रहा है, जिसमें एससी के लिए 15% सीटें, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% सीटें और सभी श्रेणियों में विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण निर्धारित किया गया है।

दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों का आवंटित कोटा, प्रदान की गई छात्रवृत्तियों की संख्या और सीएसएसएस के तहत वितरित छात्रवृत्ति राशि निम्न है:

(ii) पीएम–यूएसपी जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य:** जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना (जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के लिए एसएसएस) का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को इन संघ राज्य क्षेत्रों/ के बाहर के शैक्षणिक संस्थानों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो उन्हें अपने साथ देश के बाकी हिस्सों के समकक्ष वार्तालाप करने का अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें मुख्यधारा का हिस्सा बनने में मदद मिलती है।
- **पात्रता:** जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के वे छात्र जिनकी पारिवारिक आय 8.0 लाख रु. प्रति वर्ष तक है और जिन्होंने इन संघ राज्य क्षेत्रों से XIIवीं कक्षा/समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे इस योजना के तहत आवेदन करने के पात्र हैं। जिन छात्रों ने केंद्रीयकृत परामर्श के माध्यम से

क्र. सं.	राज्य	आवंटित कोटा	पीएम–यूएसपी सीएसएसएस (01.01.2023 से 31.12.2023)	
			छात्रवृत्तियों की संख्या ताजा + नवीकरण	(राशि रुपये करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	77	उपलब्ध नहीं'	
2	असम	2002	73	0.10
3	हिमाचल प्रदेश	461	1329	1.61
4	जम्मू, कश्मीर और लद्दाख	768	587	0.73
5	मणिपुर	181	154	0.21
6	मेघालय	166	50	0.06
7	मिजोरम	75	1	0.00
8	नागालैंड	176	36	0.05
9	सिक्किम	44	उपलब्ध नहीं '	
10	त्रिपुरा	236	609	0.77
11	उत्तराखंड	616	1195	1.51
कुल		**4802**	**4034**	**5.03**

नोट: अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम राज्य को छात्रवृत्ति का वितरण केवल सीबीएसई के माध्यम से किया जाता है (इन राज्यों के पास अपना राज्य शिक्षा बोर्ड नहीं हैं)

इन संघ राज्य क्षेत्रों के बाहर आवंटित सीटों पर प्रवेश प्राप्त किया है, साथ ही ऐसे छात्र जिन्होंने सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा के आधार पर केंद्रीय विश्वविद्यालयों या मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश लिया है, वे छात्रवृत्ति के पुरस्कार हेतु पात्र हैं।

- **कार्य क्षेत्र:** 5000 नई छात्रवृत्तियाँ प्रति वर्ष (सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 2070, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 2830 और मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 100) प्रदान की जाती हैं। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों का चयन करने वाले छात्रों की संख्या में किसी भी कमी से होने वाली बचत के अध्यधीन, सामान्य डिग्री की संख्या में कमी के अध्यधीन, स्लॉट की अंतर–परिवर्तनीयता का प्रावधान रखा गया है।
- **छात्रवृत्ति दर:** शिक्षण शुल्क और रखरखाव भत्ते के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। सामान्य डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क हेतु छात्रवृत्ति की दर 30,000 रु. प्रति वर्ष, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 1.25 लाख रु. प्रति वर्ष और मेडिकल अध्ययन के लिए 3.0 लाख रु. प्रति वर्ष है। योजना के तहत सभी छात्रों को 1.0 लाख रु. प्रति वर्ष का निश्चित रखरखाव भत्ता प्रदान किया जाता है। अंतर–मंत्रालयी समिति योजना के कार्यान्वयन और निगरानी की देखरेख करती है।
- **आरक्षण:** इस योजना के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति को अपनाया गया है अर्थात अनुसूचित जाति के लिए 8%, अनुसूचित जनजाति के लिए 10% और सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (एसईबीसी) के लिए 22% निर्धारित है।
- **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** यह योजना डीबीटी के अंतर्गत आती है जिसमें छात्रवृत्ति सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में वितरित की जाती है।
- **ऑनलाइन पोर्टल:** छात्रों को एआईसीटीई वेब पोर्टल– www.aicte–jk–scholarship.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- पीएम–यूएसपी योजना के तहत जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजना में शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की अंतर–मंत्रालयी समिति (आईएमसी) के निर्देशानुसार कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। एआईसीटीई, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए शीर्ष 100 एनबीए मान्यताप्राप्त/एनआईआरएफ रैंक और 3.0 या अधिक एनएएसी मान्यता प्राप्त संस्थानों को शामिल करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। राज्य सरकार/केंद्र सरकार संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2023–24 से अपनी श्रेणी में एसएसएसजेकेएल छात्रवृत्ति के लिए भी अनुमति दी गई थी, यदि संस्थान शिक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार ऊपरोक्त मानदंडों का अनुपालन कर रहा हो। पेशेवर स्ट्रीम (इंजीनियरिंग सहित) योजना के तहत उपलब्ध छात्रवृत्तियाँ 2830 थीं; इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के छात्रों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु सामान्य स्ट्रीम पाठ्यक्रम के लिए 2070 और मेडिकल स्ट्रीम कोर्स के लिए 100 छात्रवृत्तियां थीं।
- एसएसएसजेकेएल, एआईसीटीई ने संघ राज्य क्षेत्र जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के इच्छुक छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए 22 मई से 16 जुलाई 2023 तक और लेटरल एंट्री (डिप्लोमा छात्रों) के लिए 14 अगस्त से 14 सितंबर 2022 तक पोर्टल खोला। एचएससी में 19826 छात्र (10+2) और डिप्लोमा में 248 छात्रों को एचएससी

में 5000 सीटों और डिप्लोमा में 500 सीटों (केवल द्वितीय वर्ष इंजीनियरिंग स्ट्रीम में सीधे प्रवेश) के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने हेतु जम्मू–कश्मीर और लद्दाख सरकार द्वारा पात्र घोषित किया गया था। पेशेवर, मेडिकल और सामान्य स्ट्रीम पाठ्यक्रमों में उनके द्वारा भरे गए विकल्पों के अनुसार 4260 मेधावी छात्रों को संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की आरक्षण नीति लागू करने के बाद पात्र घोषित किया गया था। जिनमें से 3794 छात्र आवंटित संस्थानों में शामिल हो गए हैं और 248 छात्रों को इंजीनियरिंग स्ट्रीम में लेटरल एंट्री (डिप्लोमा छात्र) के तहत सीटें आवंटित की गईं, जिनमें से 208 छात्र शैक्षणिक सत्र 2023–24 के दौरान आवंटित संस्थानों में शामिल हुए हैं।

- माननीय अध्यक्ष, एआईसीटीई, माननीय उपाध्यक्ष, एआईसीटीई, माननीय सदस्य–सचिव, एआईसीटीई एवं एआईसीटीई के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने कारगिल, लेह, श्रीनगर, जम्मू बारामूला, कुपवाड़ा, अनंतनाग, गांदरबल, राजौरी, रियासी, कठुआ, डोडा आदि सहित जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया है। अधिकारियों ने इच्छुक छात्रों को काउंसलिंग प्रक्रिया, प्रवेश औपचारिकताओं के बारे में सूचित किया, और उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश हेतु सीयूईटी परीक्षा प्रक्रिया और शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त निर्देश के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के साथ एआईसीटीई द्वारा आयोजित डी–डुप्लीकेशन प्रक्रिया के बारे में भी जानकारी दी गई।
- वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023) के दौरान 7,123 छात्रवृत्तियाँ (नए+नवीनीकरण) प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) को 211 करोड़ रु. जारी किए गए हैं।

(iii) पीएम–यूएसपी केंद्रीय क्षेत्रक ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी योजना (सीएसआईएस)

- **उद्देश्यः** योजना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और विकलांगों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) में से किसी को भी केवल इस कारण से पेशेवर उच्चतर शिक्षा तक पहुंच से वंचित न किया जाए कि वह गरीब है।
- **पात्रताः** राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) से मान्यता प्राप्त संस्थानों या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) या राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों या केंद्रीय वित्तपोषित तकनीकी संस्थानों (सीएफटीआइ) द्वारा मान्यता प्राप्त पेशेवर/तकनीकी कार्यक्रमों से पेशेवर/तकनीकी पाठ्यक्रमों में नामांकित छात्र पात्र हैं। वे पेशेवर संस्थान/कार्यक्रम जो एनएएसी या एनबीए के दायरे में नहीं आते हैं, उन्हें संबंधित नियामक निकाय की स्वीकृत आवश्यकता होती है। ब्याज सब्सिडी केवल एक बार पूर्व स्नातक या स्नातकोत्तर या एकीकृत पाठ्यक्रमों के लिए स्वीकार्य है।
- **कार्य क्षेत्रः** इस योजना का उद्देश्य ईडब्ल्यूएस से संबंधित उन सभी छात्रों को शामिल करना है, जिनके माता–पिता/परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रु. प्रति वर्ष तक है।
- **लाभः** योजना के तहत, भारतीय बैंक एसोसिएशन (आईबीए) मॉडल शैक्षिक ऋण योजना के तहत सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित अनुसूचित बैंकों से 10 लाख रु. तक के शैक्षिक ऋण पर अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि प्लस एक वर्ष) के दौरान पूर्ण ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना के लिए केनरा बैंक नोडल बैंक है।

- **डीबीटी:** ब्याज सब्सिडी दावों का वितरण छात्र के शिक्षा ऋण खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से किया जाता है।
- **ऑनलाइन पोर्टल:** सदस्य बैंकों को ब्याज सब्सिडी के दावे अपलोड करने में सक्षम बनाने के लिए केनरा बैंक द्वारा प्रति वर्ष एक ऑनलाइन पोर्टल खोला जाता है।

पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 की अवधि के दौरान दावों की संख्या और प्रदान की गई ब्याज सब्सिडी का ब्यौरा इस प्रकार है:

दावों की संख्या और ब्याज सहायता राशि			
क्र. सं.	राज्य के नाम	दावा	प्रदत्त ब्याज सबसिडी (₹ करोड़ में)
1	अरुणाचल प्रदेश	18	0.03
2	असम	1,246	1.95
3	मणिपुर	79	0.14
4	मेघालय	230	0.44
5	मिजोरम	44	0.09
6	नागालैंड	19	0.02
7	सिक्किम	42	0.07
8	त्रिपुरा	576	1.13
9	जम्मू और कश्मीर	4,086	6.52
10	लद्दाख	09	0.01
11	हिमाचल प्रदेश	1,654	2.70
12	उत्तराखंड	2,633	4.75
कुल		**10,636**	**17.87**

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ईशान उदय विशेष छात्रवृत्ति योजना

मंत्रालय और यूजीसी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के संबंध में विशेष रुचि ली है। सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में सुधार करने, उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने और पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, यह योजना शैक्षणिक सत्र वर्ष 2014–15 से शुरू की गई थी। योजना के तहत प्रति वर्ष 10000 छात्रों को छात्रवृत्ति के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के अधिवास वाले छात्र, जिन्होंने किसी भी मान्यताप्राप्त शिक्षा बोर्ड के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र के भीतर स्थित स्कूल से XIIवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की है और मेडिकल तथा पैरा–मेडिकल पाठ्यक्रम (एकीकृत पाठ्यक्रम शामिल) सहित सामान्य डिग्री पाठ्यक्रम, तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त किया है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान/पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के भीतर और बाहर अन्य वैधानिक परिषदों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। इस योजना के तहत छात्रवृत्ति का लाभ उठाने हेतु छात्र के माता–पिता की आय प्रतिवर्ष 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

वित्तीय सहायता का पैटर्न:

पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) से संबंधित छात्रों के लिए एक वर्ष में 10 महीनों के लिए 8,000/– रुपये प्रतिमाह की दर से दस हजार (10000) छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं।

2021-22		2022-23		2023–24 (दिस. 2023 तक)	
लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (करोड़ रुपये में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी राशि (करोड़ रुपये में)
10461	56.61	25131	142.43	13201	109.84

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना

i. **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ सहित योजना का सार:** भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों/कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले

और अनुमोदित प्रवेश के भीतर एम.ई./एम. टेक/एम.एर्क./एम.डीएस. के छात्रों को डीबीटी के माध्यम से 24 महीने के लिए 12400/– रु. प्रति माह की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है जो दिशानिर्देशों के अनुसार गेट/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं।

ii. **प्रारंभ की तिथि :** 1987 से

iii. **योजना के क्रियान्वयन का तरीका:** पीजी छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश के समय वैध गेट/सीईईडी अंक है।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकरण)								
योजना का नाम	**मुक्त**		**एससी**		**एसटी**			
एआईसीटीई पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) छात्रवृत्ति योजना	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**कुल गणना**	**कुल राशि का योग**
गैर–पूर्वोत्तर	8466	104977574	1401	17371987	340	4216000	10207	126565561
पूर्वोत्तर	77	954800	15	186000	87	1078800	179	2219600
कुल योग	8543	105932374	1416	17557987	427	5294800	10386	128785161

डॉक्टरल फेलोशिप (एडीएफ)

i. **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ सहित योजना का सार:** स्टार्ट–अप की ओर ले जाने वाले उद्योगों और संस्थान के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देकर इंजीनियरिंग/प्रबंधन/डिज़ाइन में तकनीकी अनुसंधान के लिए प्रतिभा का पोषण करके एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों/विभागों/संस्थानों में अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। पात्र शोधार्थियों को एआईसीटीई डॉक्टोरल फेलोशिप (एडीएफ) योजना दिशानिर्देशों के अनुसार छात्रवृत्ति दी जाएगी।

ii. **परिलब्धियाँ एवं भत्ते:** चयनित अनुसंधान विद्वानों को पहले दो वर्षों के लिए 37,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप और उसके बाद 42,000 रुपये प्रति माह और केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार मकान किराया भत्ता (एचआरए) मिलता है। इसके अलावा आकस्मिक अनुदान के रूप में 15,000 रुपये प्रति वर्ष की राशि दी जाती है।

iii. **प्रारंभ की तिथि:** 2018–19

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकरण)								
योजना का नाम	**मुक्त**		**एससी**		**एसटी**			
एआईसीटीई पोस्ट डॉक्टोरल फ़ेलोशिप	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**कुल गणना**	**कुल राशि का योग**
गैर–पूर्वोत्तर	365	155970549	86	36691445	18	6514596	469	199176590
पूर्वोत्तर	32	13081942	7	3234880	5	1696657	44	18013479
कुल योग	397	169052491	93	39926325	23	8211253	513	217190069

स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना

i. **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ सहित योजना का सारः** यह योजना एआईसीटीई द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अनाथ बच्चों, कोविड–19 के कारण मरने वाले माता–पिता के बच्चों, कार्रवाई में शहीद हुए सशस्त्र बलों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के बच्चों (शहीद) को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करने के लिए 50,000/– रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

ii. **प्रारंभ की तिथिः** 2021–22

iii. **योजना के क्रियान्वयन का तरीकाः** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से पूरे देश से एआईसीटीई–अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकरण)								
योजना का नाम	**मुक्त**		**एससी**		**एसटी**			
एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**कुल गणना**	**कुल राशि का योग**
गैर–पूर्वोत्तर	527	26850000	32	1650000	8	400000	571	28900000
पूर्वोत्तर	2	100000	0	0	1	50000	3	150000
कुल योग	529	26950000	32	1650000	9	450000	574	29050000

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नया और नवीनीकरण)								
योजना का नाम	**मुक्त**		**एससी**		**एसटी**			
एआईसीटीई स्वनाथ छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**गणना**	**कुल राशि**	**कुल गणना**	**कुल राशि का योग**
गैर–पूर्वोत्तर	248	12400000	28	1400000	18	900000	294	14700000
पूर्वोत्तर	2	100000	0	0	0	0	2	100000
कुल योग	250	12500000	28	1400000	18	900000	296	14800000

प्रशिक्षण और अधिगम (अटल) अकादमी

अटल अकादमी की स्थापना वर्ष 2018 में देश में गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की योजना बनाने और सहायता करने एवं विभिन्न उभरते क्षेत्रों में प्रशिक्षण के माध्यम से अनुसंधान, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने में तकनीकी संस्थानों को सहयोग करने के उद्देश्य से की गई थी। इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वास्तुकला, डिजाइन, कला और शिल्प आदि के बाद से देशभर में संकाय सदस्यों और अनुसंधान अध्येताओं के लिए संकाय विकास कार्यक्रम तीन श्रेणियों, यानी बुनियादी, उन्नत और नेतृत्व स्तर के एफडीपी में प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2023 से, भारतीय ज्ञान परंपरा पर एफडीपी और पीएम गति शक्ति को भी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शामिल किया गया है।

एटीएएल अकादमी द्वारा वित्तपोषित एफडीपी के अलावा, पिछले वर्षों में अग्रणी और मान्यता प्राप्त संगठनों और प्रशिक्षकों द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किए गए प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी जारी

किए जाते हैं। वर्ष में अधिकतम एफडीपी आयोजित करने और अधिकतम संख्या में प्रतिभागियों को प्रमाणित करने के लिए अटल अकादमी को वर्ष 2021 में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई थी। अटल अकादमी अब अपने पहले से स्थापित चार प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से एनईपी 2020 के अनुरूप विषयों पर इन–हाउस ऑफ़लाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों से देश के शैक्षणिक क्षेत्र को अनुसंधान उन्मुख, ज्ञान समृद्ध और गतिशील रूप से स्व–शिक्षित बनाने की आशा की जा सकती है।

संस्थान, संकाय और छात्र पंजीकरण और असम, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड में छात्रों द्वारा किए गए मूल्यांकन में 01 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक बड़े पैमाने पर सुधार देखा गया है जैसा कि नीचे प्रदर्शित किया गया है:

2023–2024 के दौरान एआईसीटीई–अटल पोर्टल पर एफडीपी स्थिति (01.01.2023–31.12.2023)

	जनवरी		फरवरी		मार्च		अक्तूबर		नवंबर		दिसंबर		कुल एफडीपी	कुल प्रमाणित
अटल एफडीपी	एफडीपी	प्रमाणित	एफडीपी	प्रमाणित	एफडीपी	प्रमाणित	एफडीपी	प्रमाणित	एफडीपी	प्रमाणित	एफडीपी	प्रमाणित		
अरुणाचल प्रदेश	1	21	1	11			1	42					3	74
असम			1	35					1	24	1	6	3	65
हिमाचल प्रदेश			1	28									1	28
जम्मू और कश्मीर	1	3	1	21	1	3							3	27
मणिपुर			1	47									1	47
मेघालय	1	14											1	14
मिजोरम			1	18									1	18
नागालैंड					1	30							1	30
त्रिपुरा					1	46					1	38	2	84
उत्तराखंड							1	41	1	43	1	50	3	134
कुल योग	3	38	6	115	3	79	2	83	2	67	3	96	20	621

एआईसीटीई माडरॉब जीओसी और आइडिया प्रयोगशाला योजनाएँ

राज्य	योजना के नाम	2022–23 (01.01.23 से 31.12.23)		
		जारी राशि	जारी राशि	जारी राशि
अरुणाचल प्रदेश	एमओडीआरओबी	6.96	1	8.70
असम	जीओसी	शून्य	1	4.00
	एमओडीआरओबी	14.38	1	17.96
त्रिपुरा	आइडिया लैब	शून्य	1	52.76
	एमओडीआरओबी	13.53	1	16.92

कैंपस आवास और सामाजिक अनुभव बढ़ाने वाली सुविधाओं के लिए एआईसीटीई योजनाएं

राज्य	योजना के नाम	2022–23 (01.01.23 से 31.12.23)		
		जारी की गई राशि (लाख में)	लाभार्थियों की संख्या	जारी की गई राशि (लाख में)
असम	कैफे–एनईआर	120.00	1	300.00
त्रिपुरा	कैफे–एनईआर	117.19	1	299.63
नागालैंड	कैफे–एनईआर	119.97	1	300.00
सिक्किम	कैफे–एनईआर	98.21	1	250.00
अरुणाचल प्रदेश	कैफे–एनईआर	30.00	1	300.00
असम	कैफे–एनईआर	17.29	1	200.00
	एसपीडीपी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं

जम्मू और कश्मीर प्रशिक्षुता योजना

इस योजना का उद्देश्य जम्मू–कश्मीर प्रशिक्षुता के माध्यम से जम्मू–कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक संस्कृति से परिचित कराना है। जम्मू–कश्मीर प्रशिक्षुता योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, माननीय अध्यक्ष एआईसीटीई ने अन्य आईआईटी, एनआईटी और आईआईएसईआर को भी इस राष्ट्र–निर्माण में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया है और इस वर्ष के दौरान अठारह (18) प्रमुख संस्थानों ने 26 मई, 2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2023 में 10 आईआईटी, 6 एनआईटी और 2 आईआईएसईआर शामिल हैं।

जम्मू–कश्मीर प्रशिक्षुता कार्यक्रम के समग्र आँकड़े इस प्रकार हैं:

क्र. सं.	अवधि	नामांकित छात्रों की संख्या	प्रशिक्षित छात्रों की संख्या
1	शीत 2020	1950	143
2	शीत 2021	1564	143
3	ग्रीष्म 2022	1219	167
4	ग्रीष्म 2023	1595	203

कश्मीरी प्रवासियों के क्षेत्रों के लिए छूट

कश्मीरी प्रवासियों के बच्चों के साथ–साथ कश्मीर घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर–प्रवासियों) के बच्चों को देश के अन्य हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में कुछ रियायतें दी गई। चूंकि कश्मीरी प्रवासियों को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए देश के अन्य हिस्सों में शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में कश्मीरी प्रवासी छात्रों को निम्नलिखित रियायतें भी प्रदान की गई हैं:

i. न्यूनतम पात्रता आवश्यकता के अध्यधीन 10% तक कट–ऑफ प्रतिशत में छूट।

ii. पाठ्यक्रम–वार 5% तक प्रवेश क्षमता में वृद्धि।

iii. तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में योग्यता कोटा में कम से कम एक सीट का आरक्षण।

iv. केवल कश्मीरी प्रवासियों के लिए अधिवास आवश्यकताओं से छूट देना। कश्मीरी घाटी में रहने वाले कश्मीरी पंडितों/कश्मीरी हिंदू परिवारों (गैर–प्रवासियों) को अधिवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता है

सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए अतिरिक्त सीटें– जम्मू और कश्मीर के छात्रों के लिए सभी मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अतिरिक्त कोटा के तहत 2 सीटें बनाई जाएंगी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम राज्य सहित) में 113 केन्द्रीय विद्यालय कार्यरत हैं, जिनमें दसवीं कक्षा में 6187 छात्र और बारहवीं कक्षा में 7100 छात्र नामांकित हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इन 113 केवि में से 66 सिविल में, 22 रक्षा में, 17 परियोजना क्षेत्र में और 09 उच्चतर शिक्षा संस्थानों में हैं।

वर्ष 2022–23 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सीबीएसई की दसवीं और बारहवीं कक्षा में उत्तीर्ण प्रतिशत:

क्र.सं.	राज्य	कक्षा X	नामांकित छात्र	कक्षा XII	नामांकित छात्र
1	अरुणाचल प्रदेश	94.77%	733	97.69%	652
2	असम	98.58%	3905	96.74%	4563
3	मणिपुर	100%	427	100%	495
4	मेघालय	99.09%	333	99.38	488
5	मिजोरम	100%	140	100%	122
6	नागालैंड	100%	114	98.17%	168
7	सिक्किम	100%	57	96.52%	116
8	त्रिपुरा	99.37%	478	95.94%	496

केवीएस द्वारा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित केवि के लिए जारी निधि की स्थिति (31.12.2023 तक) इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

वर्ष	योजना	गैर–योजना
2015-2016	रु. 87.50	रु.130.13
2016-2017	रु. 110.20	रु. 165.52
	राजस्व	पूंजी
2017-18	113.44	80.29
2018-19	127.89	23.45
2019-20	416.35	13.32
2020-21	235.16	04.52
2021-22	172.40	40.00
2022-23	232.25	56.00
2023-24	**287.20**	**88.50**

❖ ❖ ❖

3

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

उच्चतर शिक्षा विभागः

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई):

भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में निहित अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई), अधिनियम 2004 अधिनियमित किया गया है। आयोग एक अर्ध–न्यायिक निकाय है और एनसीएमईआई अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के उद्देश्य से इसे एक सिविल न्यायालय की शक्तियों से निहित किया गया है। आयोग के कार्यों में संस्था की अल्पसंख्यक स्थिति से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेना शामिल है। आयोग अल्पसंख्यकों की शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को परामर्श भी देता है।

वर्ष 2023–24 के दौरान (दिनांक 1.4.2023 से 24.11.2023 तक) कुल 224 नई याचिकाएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 206 याचिकाएँ अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाणपत्र देने के लिए थीं और 08 विविध मामलों से थीं और 10 अपीलीय मामले राज्य सक्षम प्राधिकारी के विरुद्ध थे। इस अवधि के दौरान 223 याचिकाओं का निपटान किया गया, जिनमें चालू मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा, दिनांक 1.4.2023 से 24.11.2023 तक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को कुल 99 अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान किए गए हैं। इनके अभिग्रहण के बाद से और दिनांक 24.11.2023 तक, आयोग द्वारा 13,927 अल्पसंख्यक स्थिति प्रमाणपत्र प्रदान/जारी किए गए हैं।

अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसीएमई):

माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय निगरानी समिति (एनएमसीएमई) का गठन दिनांक 3.8.2017 को तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था। समिति में प्रख्यात शिक्षाविद् संसद के सदस्य, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि और अल्पसंख्यक समुदायों, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल थे।

महिला छात्रावासः

यूजीसी दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों सहित 53 कॉलेजों को अनुदान प्रदान करता है, दिल्ली के कॉलेज अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रें के अंतर्गत नहीं आते हैं। तथापि, यूजीसी ने XIवीं और XIIवीं योजना अवधि के दौरान महिला छात्रावास के निर्माण हेतु 2 अल्पसंख्यक कॉलेजों अर्थात श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज (एसजीटीबी) खालसा कॉलेज और श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को अनुदान जारी किया है। अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को जारी अनुदान का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	दिल्ली कॉलेज के नाम	जारी किया गया अनुदान
1.	श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज	1,00,00,000/–
2.	श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स	1,20,00,000/–
	कुल	2,20,00,000/–

अ.जा./ अ.ज.जा. /अल्पसंख्यक/महिलाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण अकादमीः

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए आवासीय अकादमी का उद्देश्य

अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिलाओं से संबंधित छात्रों को छात्रावास सुविधाओं के साथ केंद्र/राज्य सरकार, निजी क्षेत्र की नौकरियों और आईआईटी/मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए बिना शिक्षण शुल्क के निःशुल्क/नाममात्र शुल्क कोचिंग प्रदान करके समाज के सभी वर्गों को समान विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है।

यह योजना चार केंद्रीय विश्वविद्यालयों जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ में चलाई जा रही है। समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई और मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय (एमएएनयूयू) और बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) को 31.03.2024 तक और जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को दिनांक 31.03.2025 तक विस्तार दिया गया। वित्तीय वर्ष 2023–2024 के दौरान 115.00 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।

वर्ष 2023–24 की अवधि के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अल्पसंख्यक और महिलाओं के लिए आवासीय प्रशिक्षण अकादमी योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

विश्वविद्यालय का नाम	एससी	एसटी	महिला	अल्पसंख्यक	कुल
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद	30	9	65	8	94
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ	30	9	96	136	271
जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली	44	23	82	184	333

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग:

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी):

समग्र शिक्षा के तहत, उच्च प्राथमिक स्तर पर मौजूदा केजीबीवी और माध्यमिक स्तर पर महिला छात्रावास को XIIवीं कक्षा तक की लड़कियों को आवासीय और स्कूली शिक्षा सुविधाएं प्रदान करने के लिए विस्तारित/एकीकृत किया जा रहा है। केजीबीवी के उन्नयन का कार्य वर्ष 2018–19 में शुरू किया गया था और अब तक कुल 351 केजीबीवी को Xवीं कक्षा तक और 2,264 केजीबीवी को XIIवीं कक्षा तक अपग्रेड किया गया है। दिनांक 30.09.2023 तक, केजीबीवी के विलय/अभिसरण को ध्यान में रखते हुए, स्वीकृत केजीबीवी की संख्या 5639 है। इनमें से 5074 केजीबीवी 691304 बालिकाओं के नामांकन के साथ कार्य कर रहे हैं। लड़कियों के नामांकन का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:

स्वीकृत केजीबीवी	कार्यात्मक केजीबीवी	श्रेणी–वार बालिका नामांकन									
		एससी		एसटी		ओबीसी		बीपीएल		मुस्लिम	
		लड़कियों का संख्या	लड़कियों का प्रतिशत	लड़कियों का संख्या	लड़कियों का प्रतिशत	लड़कियों का संख्या	लड़कियों का प्रतिशत	लड़कियों का संख्या	लड़कियों का प्रतिशत	लड़कियों का संख्या	लड़कियों का प्रतिशत
5639	5074	189696	27.44	178568	25.83	249517	36.09	46195	6.68	27194	3.93

मुस्लिम बहुल जिलों में केजीबीवी की स्थिति: 20% और उससे अधिक मुस्लिम आबादी वाले 88 मुस्लिम बहुल जिलों और चुनिंदा शहरी क्षेत्रों में 817 केजीबीवी स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 497 कार्यात्मक हैं। इसके अलावा,

88 मुस्लिम बहुल जिलों में 328 केजीबीवी को Xवीं/XIIवीं कक्षा तक अद्यतन किया गया है।

नवोदय विद्यालय योजना (जनवि):

नवोदय विद्यालय योजना में प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उनकी सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि का ध्यान दिए बिना अच्छी गुणवत्तापूर्ण आधुनिक शिक्षा प्रदान करने हेतु देश के प्रत्येक जिले में एक आवासीय सह–शिक्षा विद्यालय, जिसे जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) कहा जाता है, की स्थापना की परिकल्पना की गई है। वर्तमान में, तमिलनाडु राज्य को छोड़कर, जिसने अभी तक नवोदय विद्यालय योजना को स्वीकार नहीं किया है, देश के 638 जिलों में दिनांक 31.05.2014 तक कुल 661 जेनवि स्वीकृत किए गए हैं। इन 661 स्वीकृत जेनवि में से, 653 जेनवि कार्यात्मक हैं और 08 संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से समुचित भूमि और अस्थायी आवास की कमी के कारण गैर–कार्यात्मक हैं।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए), भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, जो वर्ष 2022–23 से प्रभावी हैं, केंद्र सरकार के कार्यालय का स्थान एमसीए में स्थित माना जाएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यदि जलग्रहण क्षेत्र (15 किमी के दायरे) में अल्पसंख्यक आबादी की सघनता 25% से अधिक है, 127 जेनवि के संबंध में संबंधित जिला प्रशासन द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी किया गया है। इसलिए, एमओएमए के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार **127 जनवि** अल्पसंख्यक–केंद्रित क्षेत्रें में स्थित हैं।

अल्पसंख्यक केंद्रित क्षेत्रों में स्थित जेएनवी के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) ने अब तक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत **37.86 करोड़** रुपये की राशि के लिए 99 जनवि में **1173 स्मार्ट क्लासरूम** की स्थापना के लिए वित्त पोषण किया है और **243.53 करोड़ रुपये** की राशि भी स्वीकृत की गई है। पाकुड़ – II (झारखंड), हावड़ा (पश्चिम बंगाल), उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल), पश्चिम कामेंग (अरुणाचल प्रदेश), सेनापति II (मणिपुर) और ममित (मिजोरम) जिलों में स्थित 06 जेएनवी के निर्माण के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान इसी योजना के तहत. वर्ष 2022–23 के दौरान एमओएमए ने एमसीए में स्थित **59 जनवि** में बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण के लिए **263.14 करोड़ रुपये** की राशि स्वीकृत की है। पहले चरण में **23 जनवि** में बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण एमओएमए से प्राप्त पहली किस्त से किया गया है।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा (एनआईओएस)

एनआईओएस शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान है। एनआईओएस बालिकाओं और महिलाओं, ग्रामीण युवाओं, कामकाजी लोगों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और अन्य वंचित समूहों के लिए विशेष ध्यान के साथ सभी को मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल) मोड के माध्यम से प्रशिक्षार्थी–केंद्रित गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और उपस्थिति के साथ, एनआईओएस अल्पसंख्यक समुदायों के बीच गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, एनआईओएस ने अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने के लिए वर्ष 2006 में एक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की स्थापना की है।

- **एनआईओएस द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विशेष छूट:** एसपीक्यूईएम योजना के तहत, मदरसा/मकतब/दारुल–उलूम माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर के कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए एनआईओएस से मान्यताप्राप्त अध्ययन केंद्र का विकल्प चुन सकते हैं, ऐसे मदरसे जो न्यूनतम तीन (03 वर्ष) की अवधि से अस्तित्व में हैं और केंद्र या राज्य से संबद्ध हैं, शिक्षा अधिनियम या मदरसा बोर्ड या एनसीएमईआई इस कार्यक्रम के तहत सहायता के लिए आवेदन

करने के पात्र होंगे। ऐसे प्रशिक्षार्थियों के लाभ के लिए, जिनके पास उर्दू पृष्ठभूमि है, एनआईओएस पाठ्यक्रम माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनों स्तरों पर उर्दू माध्यम में उपलब्ध कराए गए हैं। भाषा श्रेणी में मौजूदा आठ विषयों के अलावा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में अरबी और फ़ारसी विषयों को भी शामिल किया गया है।

- **ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का क्रियान्वयनः** एनआईओएस में प्रवेश प्रक्रिया 100% ऑनलाइन है। मदरसा के लिए ऑनलाइन प्रवेश एनआईओएस के आधिकारिक पोर्टल www.nios.ac.in के माध्यम से लागू किया गया है। इसने मदरसों को अपने प्रशिक्षार्थियों को ऑनलाइन मोड के माध्यम से नामांकित करने में सक्षम बनाया है। एसपीक्यूईएम के तहत, ऑनलाइन प्रवेश में मान्यता प्राप्त मदरसों के माध्यम से पंजीकृत अल्पसंख्यक शिक्षार्थियों के लिए प्रवेश और परीक्षा शुल्क में छूट दी गई है। वर्तमान में एसपीक्यूईएम के अंतर्गत आने वाले कुल 151 मदरसे पूरे भारत में एनआईओएस के अध्ययन केंद्र के रूप में कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023 में माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक दोनों स्तरों पर प्रवेश लेने वाले अल्पसंख्यक छात्रों की संख्या 2452 स्ट्रीम–1 ब्लॉक–1 थी।

❖ ❖ ❖

4

महिला का शैक्षणिक विकास

महिला का शैक्षणिक विकास

महिलाओं की बड़ी भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करना उच्चतर शिक्षा विभाग का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा है। इसलिए, उच्चतर शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना एक मुख्य प्रयास है। देश में उच्चतर शिक्षा में महिला छात्रों के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

छात्र नामांकन: अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसएचई), वर्ष 2021–22 के अनुसार, वर्ष 2020–21 में उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन 4.14 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। कुल 4.33 करोड़ छात्रों में से 52.2% पुरुष और 47.8% महिलाएँ हैं। वर्ष 2014–15 में नामांकन में 3.42 करोड़ से लगभग 91 लाख (26.5% की वृद्धि) की वृद्धि हुई है।

कुल महिला नामांकन वर्ष 2020–21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 2.07 करोड़ हो गया है। महिला नामांकन वर्ष 2014–15 में 1.57 करोड़ से बढ़कर लगभग 50 लाख (31.6% की वृद्धि) हो गई है।

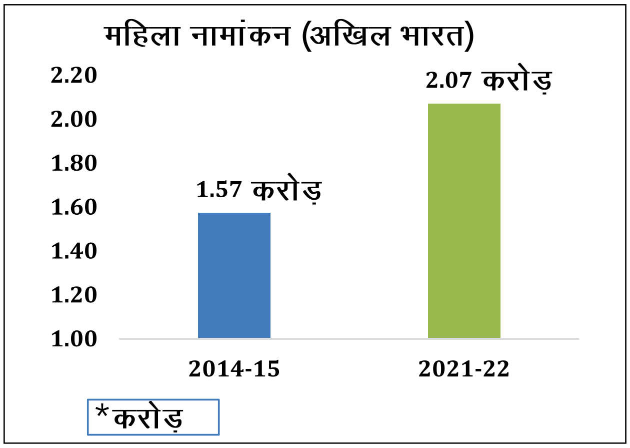

विभिन्न मापदंडों/श्रेणियों के अंतर्गत महिला नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि निम्नानुसार है:

- **एससी– महिला छात्रावास नामांकन:** अनुसूचित जाति की महिला छात्राओं का नामांकन वर्ष 2014–15 में 21.02 लाख से बढ़कर 2021–22 में 31.71 लाख (51% की वृद्धि) हो गया है।

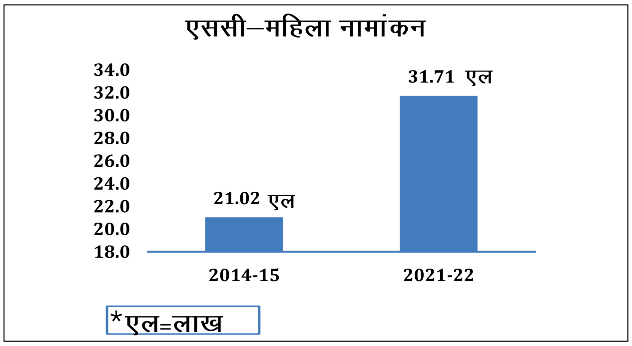

- **एसटी– महिला छात्रावास नामांकन:** अनुसूचित जनजाति की महिला छात्राओं के मामले में नामांकन वर्ष 2014–15 के 7.5 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 13.46 लाख (80% की पर्याप्त वृद्धि) हो गया है ।

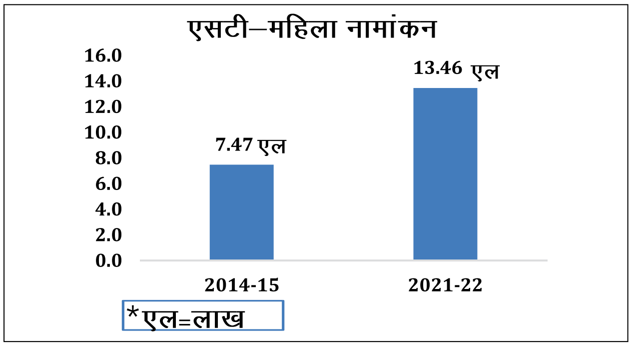

- **ओबीसी– महिला छात्रा नामांकन:** ओबीसी महिला नामांकन 52.36 लाख (2014–15) अर्थात 49.3% की वृद्धि से बढ़कर 78.19 लाख (वर्ष 2021–22) हो गया है।

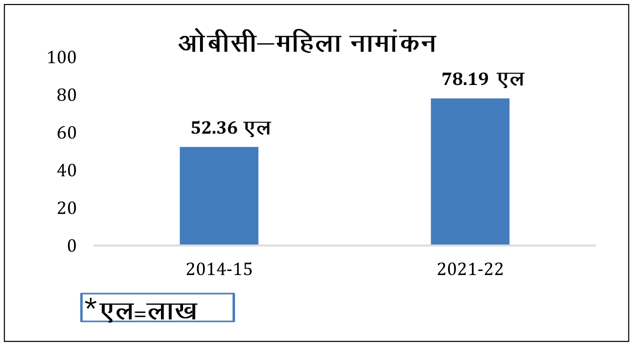

➢ **महिला पीएचडी नामांकन:** महिला पीएचडी नामांकन वर्ष 2014–15 में 0.48 लाख से दोगुना होकर वर्ष 2021–22 में 0.99 लाख हो गया है।

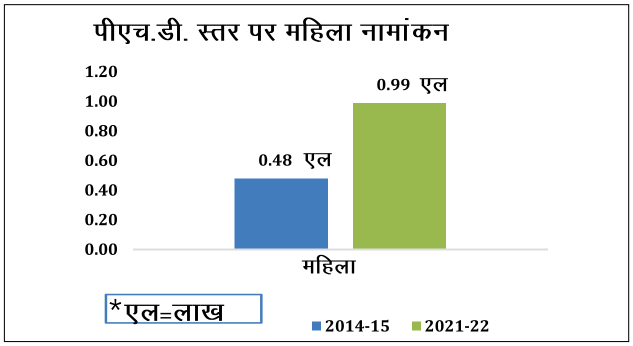

➢ **अल्पसंख्यक श्रेणी के अंतर्गत नामांकन:** वर्ष 2014–15 से महिला अल्पसंख्यक छात्रों के नामांकन में **42.3%** की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; महिला अल्पसंख्यक छात्रों का नामांकन वर्ष 2014–15 में 10.66 लाख की तुलना में वर्ष 2021–22 में बढ़कर **15.17 लाख** हो गया है।

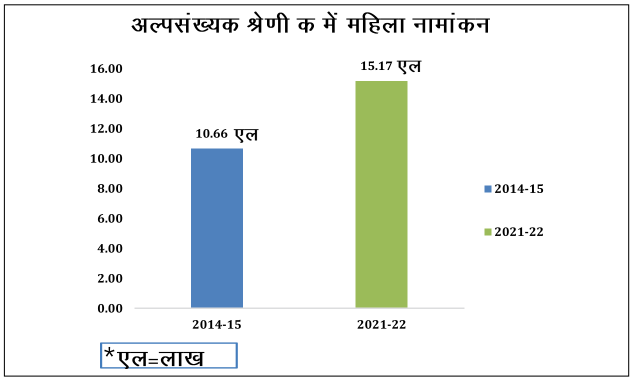

➢ **महिला शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचारी:** वर्ष 2014–15 में 5.69 लाख (2014–15 से 1.25 लाख अर्थात 22% की वृद्धि) से बढ़कर वर्ष 2021–22 में कुल महिला संकाय/शिक्षकों की संख्या 6.94 लाख हो गई है।

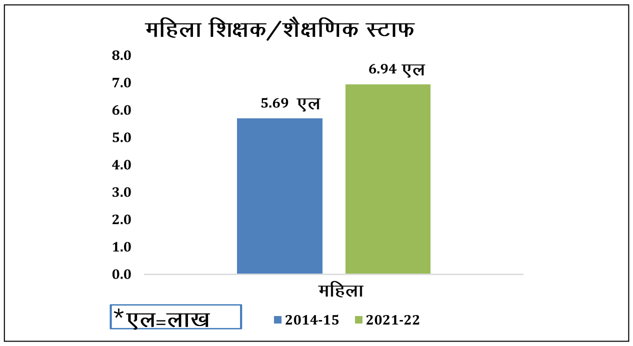

➢ **एसटीईएम में महिला नामांकन:** एसटीईएम में कुल छात्रों का नामांकन 98.49 लाख है, जिनमें से लगभग 56.56 लाख (57.4%) पुरुष और 41.93 लाख (43%) महिलाएं हैं। कुल नामांकन 7.6% बढ़ गया (वर्ष 2014–15 में 91.52 लाख से वर्ष 2021–22 में 98.49 लाख हो गया) है। एसटीईएम में महिला नामांकन 2014–15 में 35.14 लाख से बढ़कर 2021–22 में 41.93 लाख हो गया है, अर्थात 19.3% प्रतिशत की वृद्धि इुई है।

वर्ष 2014–15 से विज्ञान में महिला नामांकन 22.07 लाख से बढ़कर 29.81 लाख (अर्थात 35.1%) हो गया है।

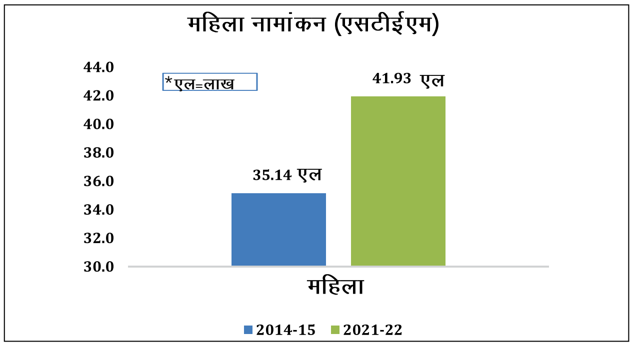

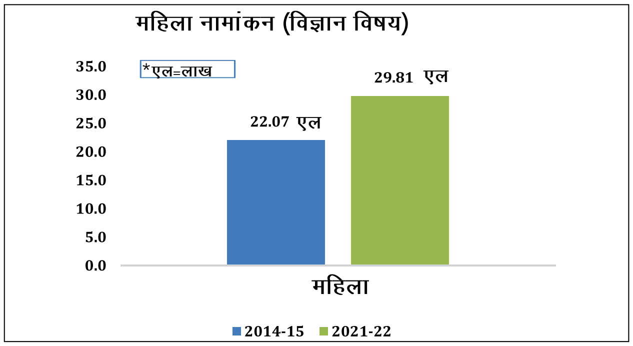

- **पूर्वोत्तर राज्यों में महिला नामांकन:** पूर्वोत्तर राज्यों में वर्ष 2021–22 में महिला नामांकन 6.07 लाख है, जो पुरुष नामांकन 5.95 लाख से अधिक है। महिला नामांकन वर्ष 2014–15 में 4.59 लाख से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 6.07 लाख हो गया है।

- **महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर):** नीचे दिया गया ग्राफ़ दोनों लिंगों के बीच जीईआर (सामान्य), जीईआर (एससी) और जीईआर (एसटी) में पिछले 8 वर्षों में समय–श्रृंखला वृद्धि को दर्शाता है। **महिला भागीदारी के मामले में, महिला जीईआर 2017–18 से लगातार पांचवें वर्ष पुरुष जीईआर से अधिक बनी हुई है।**

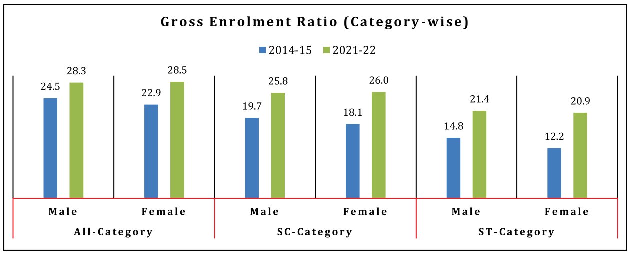

कुल मिलाकर जीईआर वर्ष 2014–15 के 23.7 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 28.4 हो गया और महिला जीईआर वर्ष 2014–15 के 22.9 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 28.5 हो गया।

एससी महिला जीईआर और एसटी महिला जीईआर में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। गौरतलब है कि, वर्ष 2021–22 में एससी महिला जीईआर भी पुरुष जीईआर से अधिक है। महिला एसटी जीईआर वर्ष 2014–15 में 12.2 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 20.9 हो गया है। महिला एससी जीईआर वर्ष 2014–15 में 18.1 से बढ़कर वर्ष 2021–22 में 26 हो गया है।

लिंग समानता सूचकांक (जीपीआई), वर्ष 2021–22 में महिला जीईआर से पुरुष जीईआर का अनुपात 1.01 है। वर्ष 2017–18 से जीपीआई 1 से ऊपर बना हुआ है।

- ✓ विशेष रूप से महिलाओं हेतु विश्वविद्यालय और कॉलेज: 17 विश्वविद्यालय (जिनमें से 14 राज्य सार्वजनिक हैं) और 4,470 कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए हैं।

- **अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021–22 के अनुसार; महिला छात्रों की उच्च प्रतिशतता वाले राज्य हैं;** केरल राज्य में छात्रों में महिला प्रतिशत सबसे अधिक है, जो 57.5% है, इसके बाद मेघालय, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में क्रमशः 54.8%, 54.5% और 54% महिला नामांकन है।

- ऐसे राज्य जहां महिला नामांकन पुरुष नामांकन के लगभग करीब है; भारत में सबसे अधिक छात्र नामांकन उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 52.6% पुरुष और 47.4% महिलाएँ हैं। महाराष्ट्र में दूसरा सबसे बड़ा छात्र नामांकन हैं, जिसमें 55.5% पुरुष और 44.5% महिलाएँ हैं। इसके बाद तमिलनाडु में 51.3% पुरुष और 48.7% महिलाएँ, मध्य प्रदेश में 53.8% पुरुष और 46.2% महिलाएँ हैं। पश्चिम बंगाल में नामांकित महिला छात्रों का प्रतिशत 49.5% है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी)

छात्रवृत्ति/फ़ेलोशिप योजनाएँ

- **एकल बालिका हेतु सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फैलोशिप:** यह योजना 'स्वामी विवेकानन्द सिंगल गर्ल चाइल्ड फ़ेलोशिप' को संशोधित करने के बाद सितंबर 2022 में शुरू की गई थी। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/कॉलेजों/संस्थानों में किसी भी स्ट्रीम/विषय में पीएचडी कर रही अपने माता–पिता की कोई भी अकेली लड़की इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र है। वर्ष 2023 (दिसंबर तक) के दौरान, 1000 लाभार्थियों को कुल ₹66.67 करोड़ संवितरित किए गए हैं।

- **एकल बालिका हेतु इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति:** योजना का उद्देश्य समाज में एकल

बालिका शिशु को बढ़ावा देने, महिलाओं के पक्ष में लिंग अनुपात बढ़ाने और समाज में छोटे परिवार के मानदंड को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एकल बालिका शिशु की स्नातकोत्तर शिक्षा में सहयोग करता है। केवल अपने माता–पिता की एकल बालिका, जिसने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या स्नातकोत्तर कॉलेज में नियमित, पूर्णकालिक प्रथम वर्ष के मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम (गैर–व्यावसायिक पाठ्यक्रम) में प्रवेश लिया है, वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र है। यह एक प्रोत्साहन योजना है और हर साल दी जाने वाली छात्रवृत्ति की संख्या पर कोई सीमा नहीं है। यह योजना 2017 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शामिल है। वर्ष 2023 के दौरान 5,428 लाभार्थियों को ₹19.65 करोड़ की राशि संवितरित की गई है।

लैंगिक बजट प्रकोष्ठ

लैंगिक बजट प्रकोष्ठ (जीबीसी) को विभिन्न लैंगिक रिस्पॉन्सिव बजटिंग (जीआरबी) पहलों को लागू करने और प्रतिबद्ध करने के इरादे से पुनर्गठित किया गया है, जिसका उद्देश्य मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों में बदलाव को इस तरह से प्रभावित और निष्पादित करना है, जिससे लैंगिक असंतुलन से निपटा जा सके, लैंगिक समानता और विकास को बढ़ावा दिया जा सके एवं मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों को सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय में लैंगिक बजट प्रकोष्ठ का पुनर्गठन 7 सितंबर, 2020 को संयुक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में किया गया।

छात्राओं के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना

- **योजना संबंधी उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ का संक्षिप्त विवरण:**

  एआईसीटीई मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 50,000/– रुपये, की छात्रवृत्ति प्रदान करती है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

  क. 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रति वर्ष 10,000 छात्रवृत्तियाँ **(5000 डिप्लोमा हेतु और 5000 डिग्री हेतु)**

  ख. शेष 13 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (पूर्वोत्तर क्षेत्र, जम्मू–कश्मीर आदि सहित) की सभी पात्र छात्राएं

  ग. एसटी के लिए 7.5%, एससी के लिए 15% और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण दिया जाता है।

- **शुरुआत की तारीख:** 2014–15
- **योजना को कार्यान्वित करने का तरीका:**

  राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से पूरे देश से एआईसीटीई–अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नए एवं नवीनीकरण)								
योजना का नाम	ओपन		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
छात्रों के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	10008	488105931	1355	65901485	379	18360775	11742	572368191
एनईआर	581	29050000	78	3900000	207	10330000	866	43280000
सकल योग	**10589**	**517155931**	**1433**	**69801485**	**586**	**28690775**	**12608**	**615648191**

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नए एवं नवीनीकरण)								
योजना का नाम	**ओपन**		**एससी**		**एसटी**		**कुल संख्या**	**कुल राशि का योग**
छात्रों के लिए एआईसीटीई प्रगति छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा)	**संख्या**	**कुल राशि**	**संख्या**	**कुल राशि**	**संख्या**	**कुल राशि**		
गैर–एनईआर	8483	424120000	1734	86700000	524	26200000	10741	537020000
एनईआर	647	32350000	143	7150000	316	15800000	1106	55300000
सकल योग	**9130**	**456470000**	**1877**	**93850000**	**840**	**42000000**	**11847**	**592320000**

आईआईटी में लैंगिक संतुलन में सुधारः

आईआईटी में बी.टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक, आईआईटी–मंडी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। आईआईटी परिषद ने दिनांक 28.04.2017 को आयोजित अपनी 51वीं बैठक में समिति की सिफारिशों पर विचार किया और अधिसंख्यक सीटें बनाकर महिला नामांकन को वर्ष 2016 में 8% से बढ़ाकर वर्ष 2018–19 में 14%, वर्ष 2019–20 में 17% और वर्ष 2020–21 में 20% करने का निर्णय लिया। जीईई (एडवांस्ड) हेतु संयुक्त प्रवेश बोर्ड उपर्युक्त निर्णय को लागू कर रहा है। वर्ष 2018, 2019 और 2020 के दौरान आईआईटी में बी. टेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन क्रमशः 15.29%, 18% और 19.8% था। तदनुसार, बी.टेक. कार्यक्रम के लिए आईआईटी में 2018 में 15.34%, 2019 में 18%, 2020 में 19.9%, 2021 में 19.72%, 2022 में 20.06% और 2023 में 19.7% महिला नामांकन हासिल किया गया।

प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा)

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तीसरे चरण के रूप में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान (पीएम उषा) है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को उनकी उच्च शिक्षा प्रणाली में पहुंच, समता और गुणवत्ता में सुधार में सहयोग प्रदान करने के लिए 12926.10 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम–उषा योजना को दिनांक 31 मार्च, 2026 तक मंजूरी दी गई है। पीएम–उषा को फोकस जिलों जैसे योजना में पहचाने गए असेवित और अल्पसेवित क्षेत्रों को प्राथमिकता देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च शिक्षा परिदृश्य को और बेहतर बनाने के लिए संरचित किया गया है। राज्यों को कम जीईआर, एससी/एसटी की जनसंख्या, महिला नामांकन आदि के आधार पर फोकस जिलों की पहचान करने की छूट दी गई है।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच वित्त पोषण पैटर्न पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10 के अनुपात में है, तथा अन्य राज्यों और विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत बिना विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र 100% केंद्रीय वित्त पोषित होंगे।

पीएम–उषा योजना, अन्य बातों के साथ–साथ, योजना के तहत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा तक पहुंच में सुधार करके विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लैंगिक समानता में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करती है जो शैक्षिक रूप से असेवित/अल्पसेवित हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पीएम–उषा योजना के तहत एक घटक के रूप में 500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ "लैंगिक समावेशन और समता पहल" नामक एक विशिष्ट घटक का प्रावधान किया गया है। इस घटक के तहत संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चुने जाने वाले 50 फोकस जिलों के लिए 10 करोड़ रुपये प्रत्येक की दर से 50

इकाइयां (शेयरिंग पैटर्न के आधार पर) स्वीकृत की जाएंगी।

दूरस्थ माध्यम से उच्च शिक्षा में महिलाओं का समावेश

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने विशेष रूप से दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रें में लड़कियों और महिला शिक्षार्थियों तक पहुँचने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। विश्वविद्यालय लैंगिक न्याय और समानता के लिए स्कूल ऑफ जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज के माध्यम से निम्नलिखित महिला–केंद्रित कार्यक्रम पेश करता है।

(i) मास्टर ऑफ आट्र्स इन वीमेन एंड जेंडर स्टडीज (एमएडब्ल्यूजीएस)

(ii) पोस्ट ग्रेज्यूएट डिप्लोमा इन वीमेन एंड जेंडर स्टडीज (पीजीडीडब्ल्यूजीएस)

(iii) डिप्लोमा इन वीमेन एमपावरमेंट एंड डेवलपमेंट (डीडब्ल्यूईडी)

(iv) पीएच.डी. इन वीमेन स्टडीज (पीएचडीडब्ल्यूएस)

विश्वविद्यालय ने मौजूदा कार्यक्रमों से प्राप्त नवाचारी ऑनलाइन (मिश्रित) कार्यक्रमों/पैकेजों/मॉड्यूल के साथ–साथ लैंगिक सुग्राहीकरण में नए कौशल–आधारित (प्रैक्सिस) मॉड्यूल/पहल के माध्यम से प्रौद्योगिकी–सक्षम शिक्षण/प्रशिक्षण पहल शुरू की है। अधिगम/प्रशिक्षण पहलों का विस्तार, अधिगम सामग्री का डिजिटलीकरण, और इंटरैक्टिव शिक्षण सामग्री का प्रावधान दूरस्थ क्षेत्रों से महिलाओं को उच्च शिक्षा में दाखिला लेने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रमुख क्षेत्र रहे हैं। वर्ष जुलाई 2023 में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित विभिन्न पाठ्यक्रमों में महिला शिक्षार्थियों का नामांकन 259921 था, जो विश्वविद्यालय द्वारा जुलाई में पेश किए गए विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल नामांकन का 50.75% है, जो महिला शिक्षार्थियों की संख्या में वृद्धि को दर्शाता है। वर्ष 2023 में लगभग 164437 शिक्षार्थी विभिन्न कार्यक्रमों में उत्तीर्ण हुए हैं। इग्नू के विशिष्ट अध्ययन केंद्र हैं जो विशेष रूप से महिला शिक्षार्थियों के लिए हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य भविष्य में महिलाओं के नामांकन में वृद्धि करना है।

❖ ❖ ❖

5

दिव्यांगजनों का शैक्षिक विकास

दिव्यांगजनों का शैक्षिक विकास

शिक्षा सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है। भारत का संविधान सभी व्यक्तियों की समानता, स्वतंत्रता, न्याय और गरिमा सुनिश्चित करता है और दिव्यांगजन सहित सभी के लिए एक समावेशी समाज को अनिवार्य रूप से अधिदेशित करता है। हाल के वर्षों में दिव्यांगजनों के प्रति समाज की धारणा में व्यापक और सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। यह महसूस किया गया है कि यदि दिव्यांगजनों के पास समान अवसर और पुनर्वास उपायों तक प्रभावी पहुंच हो तो अधिकांश दिव्यांगजन एक बेहतर और गुणवत्तापूर्ण जीवन जी सकते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020

जुलाई 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) शिक्षा की आधारशिला के रूप में पूर्ण समानता और समावेशन का समर्थन करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में सफल हो सकें। नीति में समान और गुणवत्तापूर्ण स्कूल शिक्षा की सुविधा के लिए व्यापक सुधार शुरु किए गए हैं। सभी छात्रों के लिए अधिगम सुविधा के लिए और स्कूली शिक्षा तक पहुंच के अंतर को पाटने के लिए, लैंगिक और सामाजिक–सांस्कृतिक पहचान एवं दिव्यांगताओं आदि के आधार पर सामाजिक–आर्थिक रूप से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर विशेष बल दिया गया है।

यह अपनी रुपरेखा के भीतर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा (सीडबल्यूएसएन) पर भी बल देती है। यह नीति दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के पूर्ण अनुरूप है। उपयुक्त सामग्री विकास, संसाधन केंद्रों को सुदृढ़ करने, शिक्षक प्रशिक्षण मॉड्यूल और सामान्य शिक्षकों की क्षमता निर्माण आदि जैसी सीडबल्यूएसएन सिफारिशों को नीति में शामिल किया गया है।

एनईपी–2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए विश्वविद्यालय ने एनईपी सेल का गठन किया। अखिल भारतीय स्तर पर क्षेत्रीय केंद्रों के अपने नेटवर्क के साथ, इग्नू ने 2023 में कई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी 2020) की सिफारिशों को लागू किया है और वर्ष 2024 में 19 चार–वर्षीय स्नातक कार्यक्रम (एफवाईयूपी) शुरू किए हैं। मार्च, 2023 में, इग्नू ने 12 विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में इग्नू के एमबीए पाठ्यक्रमों का अनुवाद करने और मातृभाषा में अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एआईसीटीई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

सुगम्य भारत अभियान

शिक्षा मंत्रालय ने समय–समय पर सभी केंद्रीय वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थानों को भवनों में बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न निर्देश जारी किए, जिसमें दिव्यांगजन अधिनियम में परिकल्पना के अनुसार, दिव्यांगजन को रैंप, रेलिंग, लिफ्ट, व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए शौचालयों का अनुकूलन, ब्रेल साइनेज और श्रवण संकेत, स्पर्शनीय तल आदि शामिल होंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग **(यूजीसी)** ने समय–समय पर विश्वविद्यालयों को सुगम्य भारत अभियान के संबंध में विभिन्न निर्देश जारी किए हैं, जो कि दिव्यांगजनों के लिए सर्वसुलभ पहुंच प्राप्त कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान है।

तकनीकी शिक्षा हेतु दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने

के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए एक बाधा मुक्त संरचना होना भी अनिवार्य है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को दिव्यांगजनों के सर्वोत्तम हित में 'उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए पहुंच दिशानिर्देश और मानक' (यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध) के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए पत्र जारी किया है।

यूजीसी ने सुगम्य भारत अभियान के संदर्भ में सुगम्य भारत अभियान की निगरानी के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग (फा.सं.18–15/2019–यू1(क) के दिनांक 19.10.2019 के पत्रचार के संबंध में एक पत्र संख्या एफ.6–11/2015 (एससीटी) दिनांक 13.12.2019 जारी किया है। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों/कॉलेजों से स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिव्यांगजनों के लिए पर्याप्त यूनिसेक्स सुलभ शौचालयों के निर्माण और रेट्रोफिटिंग भवन, ब्रेल शिलालेख के साथ लिफ्टों की संख्या और हैंडरेल के साथ रैंप की संख्या की प्रगति रिपोर्ट प्रदान करने का अनुरोध किया है। जानकारी निम्नानुसार है:

सुगम्य भारत अभियान की अद्यतन स्थिति (वर्ष 2022–23)

सुगम्य भारत अभियान (वर्ष 2022–23)	
विश्वविद्यालयों और कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत डेटा की संख्या	**514 (321 विश्वविद्यालय एवं 193 कॉलेज)**
यूनिसेक्स शौचालय की संख्या	7882
रेट्रोफिटिंग वाले भवनों की संख्या	1531
स्थापित लिफ्टों की संख्या?	4343
ब्रेल लेख वाली लिफ्टों की संख्या	2178
हैंड रेल के साथ रैंप की संख्या	2604

यूजीसी कॉलेजों को बिल्डिंग अनुदान प्रदान करता है। भवन निर्माण हेतु दिशानिर्देशों द्वारा कॉलेजों के संबंध में इस बात पर बल दिया गया है कि वे रैंप, रेलिंग और विशेष शौचालय जैसी विशिष्ट सुविधाओं का निर्माण सुनिश्चित करें और दिव्यांगों की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप अन्य आवश्यक बदलाव करें। ये सुविधाएं अनिवार्य हैं।

उच्चतर शिक्षा:

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को दिनांक 19.04.2017 से लागू किया गया है और 28 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया। अधिनियम का सार नीचे दिया गया है:

- उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थान अधिनियम की धारा 32 के संदर्भ में संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए पांच प्रतिशत से कम सीटें आरक्षित नहीं करेंगे।
- संदर्भित दिव्यांगजनों को अधिनियम की धारा 32 के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए ऊपरी आयु में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी।
- प्रत्येक समुचित सरकार प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में संदर्भित दिव्यांगजनों से भरे जाने वाले पदों के प्रत्येक समूह में संवर्ग की कुल रिक्तियों की कुल संख्या का 4% से कम नियुक्त नहीं करेगी।
- उच्च शिक्षा के सभी सरकारी संस्थान और सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले अन्य उच्च शिक्षा संस्थान संदर्भित दिव्यांगजनों के लिए 5% से कम सीटें आरक्षित नहीं करेंगे।

शिक्षा मंत्रालय को यह निर्देश दिया गया है कि वह शिक्षा मंत्रालय के दायरे में आने वाले संगठनों/संस्थानों/स्वायत्त निकायों में आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 विशेषकर उक्त अधिनियम की धारा 32 के लिए प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी):

यूजीसी, समय–समय पर विश्वविद्यालयों और समवत विश्वविद्यालयों को दिव्यांगजनों के संबंध में भारत

सरकार में प्रवेश और रोजगार में आरक्षण सहित नीतिगत निर्णयों से अवगत कराता रहा है। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में आयोग के स्तर पर लिए गए निर्णयों और तैयार किए गए दिशा–निर्देशों को भी कार्यान्वयन के लिए सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित किया गया है। आयोग ने विश्वविद्यालयों को दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 2016 भी परिचालित किया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे इसमें निहित प्रावधानों का सख्ती से पालन करें। यूजीसी ने उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण नीति और पहुंच दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को दिनांक 19.06.2023 को पत्र जारी किया है, जिसमें दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 और उच्च शिक्षा संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के लिए यूजीसी एक्सेसिबिलिटी दिशानिर्देश एवं मानकों का अनुपालन–2022 के प्रावधानों का अनुपालन शामिल है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)

1. दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:** एआईसीटीई दिव्यांग **(न्यूनतम 40%)** छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष **50,000/– रुपये** तक की छात्रवृत्ति प्रदान करता है।
- **शुरुआत की तिथि :** 2014–15
- **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:** राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (एनएसपी) के माध्यम से देश भर के एआईसीटीई अनुमोदित संस्थानों के सभी पात्र छात्रों से आवेदन मांगे जाते हैं।

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नए एवं नवीनीकरण)

योजना का नाम	ओपन		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिग्री)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	207	10016399	10	500000	4	200000	221	10716399
एनईआर	10	500000	0	0	0	0	10	500000
सकल योग	**217**	**10516399**	**10**	**500000**	**4**	**200000**	**231**	**11216399**

01 जनवरी –12 दिसंबर 2023 (नए एवं नवीनीकरण)

योजना का नाम	ओपन		एससी		एसटी		कुल संख्या	कुल राशि का योग
दिव्यांग छात्रों के लिए एआईसीटीई सक्षम छात्रवृत्ति योजना (डिप्लोमा)	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि	संख्या	कुल राशि		
गैर–एनईआर	997	49850000	207	10350000	41	2050000	1245	62250000
एनईआर	9	450000	0	0	0	0	9	450000
सकल योग	**1006**	**50300000**	**207**	**10350000**	**41**	**2050000**	**1254**	**62700000**

2. एआईसीटीई स्नातकोत्तर (पीजी) छात्रवृत्ति योजना

- **उद्देश्य, पात्रता मानदंड और लाभ के साथ योजना का संक्षिप्त विवरण:**

  भारत में तकनीकी शिक्षा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए, एआईसीटीई इसके द्वारा अनुमोदित संस्थानों/कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले और एमई/एम टेक./एम. आर्क./एम. डेस के स्वीकृत प्रवेश के भीतर छात्रों, जो दिशानिर्देशों के अनुसार गेट/सीईईडी परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, को डीबीटी के माध्यम से 24 महीने के लिए **12400/– रुपये** प्रतिमाह की स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करता है।

- **शुरुआत की तिथि:** वर्ष 1987 से

- **योजना के कार्यान्वयन का तरीका:** पीजी छात्रवृत्ति केवल उन छात्रों के लिए है, जिनके पास एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थान में प्रवेश के समय वैध गेट/सीईईडी स्कोर है।

पीजी छात्रवृत्ति योजना (नए और नवीनीकरण)

राशि (रुपये में)

एससी		एसटी		पीडब्ल्यूडी	
लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि	लाभार्थी	राशि
1416	17557987	427	5294800	99	1227600

इग्नू में दिव्यांगजन की शिक्षा:

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय समावेशी शिक्षा के माध्यम से ज्ञानवान समाज के निर्माण के लिए निरंतर प्रयासरत है। बहुत कम समय में, इग्नू ने मुक्त और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उच्च शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, विस्तार गतिविधियों और निरंतर व्यावसायिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वर्षों से इग्नू समाज के वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करने की देश की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण वर्ग दिव्यांगजनों का है। दिव्यांग अनुकूल शिक्षा प्रदान करना, लचीले प्रवेश मानदंड और घर–घर शिक्षा प्रदान करना दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के प्रवेश को प्रोत्साहित करती है। नेत्रहीन शिक्षार्थियों के लिए ब्रेल लिपि में मांग पर अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।

विश्वविद्यालय ने विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से दिव्यांगजनों की शैक्षिक, व्यावसायिक और पुनर्वास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिव्यांगता अध्ययन के राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की। दिव्यांग–अनुकूल स्वरूपों में मांग पर अनुदेशात्मक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 2022–23 में नए प्रवेश के बीच 4227 दिव्यांग छात्रों को नामांकित किया और देश भर में फैले शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के माध्यम से छात्रों को सहायता प्रदान की। इन एलएससी में दिव्यांगों के अनुकूल वातावरण में अधिगम की विशेष व्यवस्था है। विश्वविद्यालय नियमित रूप से जागरूकता फैलाने/दिव्यांगता के मुद्दों को हल करने के लिए अभिविन्यास/संवेदीकरण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

रिपोर्ट अवधि में, विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अनेक संवेदीकरण और अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किए। विश्वविद्यालय ने एनईपी 2020 की सिफारिशों को साकार करने के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए पाठ्यक्रम अनुकूलन और समावेशी सामग्री विकास और शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया के लिए संकाय/परामर्शदाता की क्षमता निर्माण के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। विश्वविद्यालय ने भारत सरकार की एडीआईपी योजना के तहत एलिम्को के सहयोग से विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सहायक उपकरण शिविर के मूल्यांकन और वितरण के लिए एक शिविर का आयोजन किया। विश्वविद्यालय ने इग्नू कैंपस और देश भर के क्षेत्रीय केंद्रों में जागरूकता को बढ़ावा देने और दिव्यांगजनों को शामिल करने के लिए सहायता जुटाने के लिए 'अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस' मनाया।

स्कूल शिक्षा

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन)

- **समग्र शिक्षा – सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समावेशी शिक्षाः** समग्र शिक्षा का लक्ष्य सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों की शिक्षा को मूलभूत स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में देखना है। यह योजना सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 की दिव्यांगता अनुसूची के अनुसार एक या अधिक दिव्यांगता वाले सभी बच्चों को कवर करती है। यह योजना सीडब्ल्यूएसएन सहित सभी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों द्वारा विनियमित और अभिशासित है। समग्र शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित समावेशी शिक्षा घटक है। घटक के माध्यम से, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट छात्र उन्मुख पहलों जैसे कि पहचान और मूल्यांकन शिविर, सहायता, उपकरण और सहायक उपकरणों का प्रावधान, परिवहन, स्क्राइब और एस्कॉर्ट भत्ता सहायता, ब्रेल किताबें और बड़े प्रिंट वाली किताबें, सामान्य विद्यालयों में उनकी विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं को उचित रूप से पूरा करने के लिए विशेष आवश्यकताओं वाली लड़कियों के लिए वजीफा और शिक्षण–अधिगम सामग्री आदि के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, ब्लॉक स्तर पर चिकित्सीय पहलों के माध्यम से व्यक्तिगत सहायता भी प्रदान की जाती है।

- **शिक्षा के स्तर के आधार पर सीडब्ल्यूएसएन का नामांकन**

वर्ष	प्रारम्भिक (I-VIII)		माध्यमिक (IX-X)		उच्च माध्यमिक (XI-XII)	
	सभी	सीडब्ल्यूएसएन	सभी	सीडब्ल्यूएसएन	सभी	सीडब्ल्यूएसएन
2020–21	187875490	1805383	39006375	277565	26922596	86223
2021–22	188632942	1841995	38528631	288231	28579050	110130

स्रोतः यूडाइज़ प्लस.

- **समग्र शिक्षा के अंतर्गत सीडब्ल्यूएसएन के लिए प्रावधानः वर्ष 2023–24** के लिए सीडब्ल्यूएसएन घटक के लिए समग्र शिक्षा, आईई के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए गए हैं:

  1. समग्र शिक्षा **18.60** लाख से अधिक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्री–प्राइमरी से बारहवीं कक्षा तक कवर कर रही है, जिसका अनुमानित परिव्यय **1470.4 करोड़** रुपये है।
  2. लड़कियों को स्कूल नामांकन और अपनी स्कूल शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, विशेष आवश्यकता वाली **5.57 लाख** बालिकाओं के लिए वजीफा (10 माह के लिए 200/– रुपये माह) हेतु **111.13 करोड़** रुपये के

परिव्यय की स्वीकृति दी गई है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वजीफा संवितरित किया जाता है।

3. **111.12 करोड़ रुपये** के परिव्यय के साथ अनुमोदित अभिसरण योजना जैसे एडीआईपी के माध्यम से **3.5 लाख** से अधिक पात्र सीडब्ल्यूएसएन के लिए सहायता और उपकरण।

4. योजना के तहत कक्षा XII तक के बच्चों के लिए **20.68 करोड़** रुपये के परिव्यय के साथ गंभीर और बहु–दिव्यांगता वाले **72186** बच्चों को कवर करने के लिए घर आधारित शिक्षा में नामांकित किए गए।

5. प्रारंभिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक सीडबल्यूएसएन की अधिगम जरूरतों का उचित समाधान करने के लिए विशेष शिक्षकों के माध्यम से संसाधन सहायता के लिए अलग से आवंटन किया गया है। विभाग ने वर्ष 2023–24 के लिए **32,196** विशेष शिक्षकों के लिए **743.4 करोड़** रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

6. ब्लॉक स्तर पर संसाधन कक्षों को सुसज्जित करने के लिए **1333.5 करोड़** रुपये के वित्तीय परिव्यय से 681 कमरों के लिए गैर–आवर्ती सहायता अनुमीदित की गई है।

समग्र शिक्षा का ध्यान विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करने पर है, जिसमें बच्चे अपनी क्षमताओं/अक्षमताओं की परवाह किए बिना एक ही कक्षा में एक साथ भाग लेते हैं और सीखते हैं, इस प्रकार सभी छात्रों के लिए एक समर्थकारी शैक्षिक वातावरण का निर्माण होता है। समग्र शिक्षा स्कूलों के भीतर निर्बाध पहुंच जैसे हाथ की रेलिंग के साथ रैंप और विकलांगों के अनुकूल शौचालय प्रदान करती है। यूडाइज़+ 2021–22 के अनुसार, 1069795 स्कूल में रैंप, 740395 स्कूल हैंड्रिल के साथ रैंप युक्त हैं और 401487 स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के अनुकूल शौचालय हैं।

- **वर्ष 2023–24 के दौरान सीडब्ल्यूएसएन हेतु नीतिगत पहल**

समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश और कार्यान्वयन रूपरेखा (एनजीआईएफईआईई) को अंतिम रूप दिया गया और अनुपालन के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को परिचालित किया गया। समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय दिशानिर्देश और कार्यान्वयन रूपरेखा को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। ये दिशानिर्देश अधिगम के सभी माध्यमों पर लागू होगा, जिसमें सरकारी स्कूल, निजी स्कूल, गृह आधारित शिक्षा, मुक्त स्कूल शिक्षा प्रणाली और स्कूल शिक्षा के वैकल्पिक रूप शामिल हैं। एनजीआईएफईआईई का प्रभाव मुक्त स्कूल शिक्षा प्रणाली और सेवा–पूर्व एवं सेवाकालीन शिक्षकों दोनों के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों सहित सभी शिक्षा बोर्डों पर पड़ेगा। दिशानिर्देश भारत में शिक्षा से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ सक्रिय परामर्श का एक सामूहिक परिणाम हैं। एनजीआईएफईईई, 2021–2030 किसी भी बच्चे को पीछे छोड़े बिना सभी शिक्षार्थियों के लिए एक स्कूल की संकल्पना को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक योजना है।

शैक्षणिक संस्थानों के लिए अभिगम्यता संहिता की अधिसूचना भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं 9–4/2022–आईएस.18 दिनांक 10 जनवरी 2024 (12 जनवरी 2024 को प्रकाशित) के माध्यम से प्रकाशित की गई थी। यह संहिता दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल सुविधाओं तक

पहुंच में भौतिक बाधाओं और सूचना एवं संचार बाधाओं की जांच करती है। यह मौजूदा इमारतों के लिए किफायती समाधानों के साथ—साथ सुगम्य भारत अभियान के हिस्से के रूप में नई इमारतों को राष्ट्रीय सुगम्यता मानकों के अनुरूप बनाने के लिए सभी समावेशी तत्वों के साथ क्रॉस डिसेबिलिटी और बाल—अनुकूल मानकों को भी विस्तार प्रदान करता है।

समावेशी शिक्षा संबंधी एनसीईआरटी अनुसंधान /क्षमता निर्माण कार्यक्रम

I. **स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के लिए उचित आवास की प्रभावकारिताः एक अध्ययनः** यह अनुसंधान परियोजना दिव्यांग छात्रों के लिए आवश्यक आवास के प्रकार और विस्तार का पता लगाने के उद्देश्य के साथ शुरू की गई है, जो स्कूल द्वारा मुहैया कराया जाता है तथा इसका उद्देश्य दिव्यांग छात्रों की अधिगम जरूरतों के संबंध में स्कूलों द्वारा प्रदान किए जाने वाले आवास और सहायता की प्रभावशीलता का विश्लेषण करना भी है। उत्तराखंड, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और असम राज्य में डाटा संग्रहण गतिविधि पूरी हो चुकी है। डाटा प्रविष्टि, सारणीकरण और विश्लेषण प्रगति पर है।

II. **एनईपी 2020 के आलोक में समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी गुजरात राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रमः** बच्चों संबंधी अनुसंधान विश्वविद्यालय, गुजरात के सहयोग से एनईपी 2020 के आलोक में गुजरात राज्य के मास्टर प्रशिक्षकों के लिए पांच दिवसीय समतामूलक और समावेशी शिक्षा संबंधी क्षमता निर्माण कार्यक्रम 11—15 दिसंबर, 2023 तक गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक और गैर—शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में एसईडीजी के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए समावेश और समानता के प्रमुख पहलुओं के संबंध में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करना था। कार्यक्रम में बीआरसी विशेषज्ञ शिक्षकों, विशेष शिक्षकों सहित 62 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

III. **स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा)— समतामूलक एवं समवेशी शिक्षाः** समतामूलक और समावेशी शिक्षा कार्यक्रम हेतु स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति हेतु राष्ट्रीय पहल (निष्ठा) को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और सामान्य विद्यालयों में नामांकित वंचित समूहों के बच्चों की अधिगम जरूरतों का समाधान करने के लिए सामान्य स्कूलों के शिक्षकों और अन्य पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाने और प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से मंजूरी दी गई थी। सामान्य शिक्षकों के लिए फिजिकल मोड में पांच क्षमता निर्माण कार्यक्रम अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलांग में स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों के माध्यम से आयोजित किए गए थे, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केवीएस आदि के संबंधित राज्यों के विशेषज्ञ व्यक्तियों, मास्टर प्रशिक्षकों को शामिल किया गया था। कुल 339 प्रतिभागियों को 18—22 दिसंबर, 2023 तक आरआईई भुवनेश्वर में, 18—12 जनवरी, 2024 तक आरआईई मैसूर में, 29 जनवरी से 2 फरवरी 2024 तक आरआईई भोपाल में, 5 से 9 फरवरी 2024 तक आरआईई अजमेर में और एनईआरआईई शिलांग में 19—23 फरवरी, 2024 तक समान और समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। कार्यक्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया गया; समावेशी कक्षाओं में विविधताएँः समतामूलक और समावेशी शिक्षा को समझना, पाठ्यक्रम अनुकूलन, यूडीएल और समावेशी शिक्षा के लिए विभेदित निर्देश, समावेशी कक्षाओं में संव्यवहार संबंधी मुद्दों पर चर्चा करना—सकारात्मक व्यावहारिक हस्तक्षेप

प्रणाली (पीबीआईएस), गणितीय अध्ययन में बच्चों को आने वाली कठिनाइयों को समझाना (जैसे डिस्केल्कुलिया), समावेशी कक्षाओं में गणित, विज्ञान पढ़ाने का शिक्षाशास्त्र, समावेशी शिक्षा अवलोकन में अभ्यासरत नजदीकी स्कूलों का दौरा और प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित समावेशी कक्षा पद्धतियों संबंधी अवलोकन और अभिविन्यास आदि।

IV. **डिस्लेक्सिया जागरूकता सप्ताह का आयोजन:** दिनांक 16–20 अक्टूबर, 2023 तक डिस्लेक्सिया जागरूकता सप्ताह मनाने के लिए अटेंशन डेफ़िसिट हाइपरएक्टिविटी डिसॉर्डर (एडीएचडी) और डिस्लेक्सिया सहित विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (एसएलडी) वाले छात्रों को शामिल करने संबंधी पांच दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। इन सत्रों का पीएम विद्या और जियो टीवी ऐप के तहत कक्षा 1 से 12 तक के लिए डीटीएच टीवी चैनलों पर सीधा प्रसारण किया गया। साथ ही एनसीईआरटी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर दोपहर 12.00 से 12:30 बजे तक प्रसारण किया गया। सत्र द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) थे और साथ में एक भारतीय सांकेतिक भाषा दुभाषिया (आईएसएल) भी था। प्रशिक्षण हेतु लगभग 18,330 व्यक्तियों ने पंजीकरण कराया और प्रशिक्षण उपरांत प्रश्नोत्तरी के सफल समापन के आधार पर 7,634 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए।

V. **प्रशस्त ऐप–स्कूलों हेतु दिव्यांगता स्क्रीनिंग जांच सूची:** यह विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की स्क्रीनिंग के लिए विकसित एक एंड्रॉइड ऐप है। प्रशस्त को 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रशस्त भाग–1 कक्षावार सभी छात्रों की प्रथम स्तर की प्रारंभिक स्क्रीनिंग हेतु नियमित शिक्षकों के उपयोग के लिए है। भाग–2 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 द्वारा अभिज्ञात दिव्यांगता स्थितियों की 21 श्रेणियों के अनुसार प्रशस्त भाग–1 की समुक्तियों को मान्य करने के लिए विशेष शिक्षकों द्वारा उपयोग के लिए है। स्कूल स्तर पर स्क्रीनिंग और आवश्यक जानकारी के संकलन के बाद विशेष शिक्षकों द्वारा चुने हुए छात्रों को दिव्यांगता संबंधी मूल्यांकन, पहचान और प्रमाणीकरण के लिए भेजा जाएगा। देश के सभी भागों के शिक्षकों, विशेष शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं सहित 23 भाषाओं में जांच सूची तैयार की गई है। दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक, ऐप पर 7,69,959 पंजीकृत उपयोगकर्ता थे, जिनमें 40,77,633 छात्र शामिल थे।

VI. **लाइव संवाद श्रृंखला, जिसका शीर्षक है, 'समावेशी कक्षाओं हेतु शिक्षण अधिगम पहलें'** : पीएमई–विद्या डीटीएच–टीवी चैनल कक्षा 1 से 12, जियो टीवी ऐप और एनसीईआरटी आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर लाइव इंटरैक्शन अनिवार्य आईएसएल दुभाषिया के साथ पाठ्यपुस्तकों से एक कक्षा, एक विषय और एक–अध्याय पर विचार करते हुए समावेशी शिक्षाशास्त्र पद्धतियों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करता है। प्रत्येक एपिसोड के दोपहर 12:00 बजे से 12:30 बजे (सोमवार से शुक्रवार) तक आधे घंटे की अवधि का है। प्रत्येक एपिसोड अंत में आईएसएल में तीन प्रमुख शब्दों को सीखने पर बल दिया जाता है। एनसीईआरटी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 711 सत्रों का संग्रह उपलब्ध है।

VII. **भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल):** एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को श्रव्य बाधितों हेतु सामग्री के रूप में भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में परिवर्तित किया गया है। दिनांक 22 फरवरी, 2024 तक

कक्षा I से VII के लिए पाठ्यक्रम सामग्री, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, उर्दू, अर्थशास्त्र में शब्दावली शब्दों से संबंधित 4247 आईएसएल वीडियो तैयार किए गए हैं और दीक्षा पोर्टल एवं पीएम ई–विद्या (एक कक्षा, एक चैनल) डीटीएच टीवी चैनल के माध्यम से इन ई–सामग्री की सुसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नियमित आधार पर लगातार प्रसारित किए जा रहे हैं। इनमें कक्षा I–VII के लगभग 954 से अधिक आईएसएल वीडियो शामिल हैं, जो यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ़ लर्निंग (यूडीएल) पर आधारित हैं और दीक्षा पर उपलब्ध हैं एवं नियमित रूप से पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों पर प्रसारित किए जाते हैं। "एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ आईएसएल" शीर्षक के अंतर्गत भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में दैनिक उपयोग संबंधी शब्दों का संकलन https.//ncert.nic.in/ComicFlipBookEnglish/isl.dictionary/mobile/index.html पर उपलब्ध है। आईएसएलआरटीसी के सहयोग से लगभग 10,000 शब्दों का आईएसएल शब्दकोश तैयार कर दीक्षा पर अपलोड किया गया है।

VIII. **अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस** के अवसर पर, दिनांक 23 सितंबर 2023 को माईजीओवी (My Gov) पोर्टल पर एक प्रश्नोत्तरी शुरू की गई और दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक 73,795 लोगों ने भाग लिया। दिनांक 3 दिसंबर 2023 को **अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस** पर शुरू की गई माईजीओवी क्विज़ (My Gov Quiz) में दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक 64513 लोगों ने भाग लिया।

IX. **श्रव्य पुस्तकें:** सभी 377 एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों में, कक्षा 1 से 12 तक को ईपीयूबी में परिवर्तित किया गया है, और ई पाठशाला पर उपलब्ध हैं। ये श्रव्य किताबें हैं जिन्हें किसी भी तृतीय–पक्ष टीटीएस ऐप का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। कक्षा 1 से 12 तक के लगभग 4048 अध्याय ऑडियो प्रारूप में तैयार किए गए हैं, और दीक्षा पर उपलब्ध हैं।

X. 15,964 शिक्षकों को शामिल करते हुए **सुलभ डिजिटल संसाधनों और सहायक प्रौद्योगिकियों** संबंधी ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) – दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान/सुविधाएं:

- जनवि में दिव्यांग छात्रों के प्रवेश हेतु भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाता है।
- जनवि को स्थानीय स्तर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए पेशेवर सेवाओं में लगे गैर–सरकारी संगठनों की सहायता से आवश्यकता के आधार पर विशेष शिक्षकों की सेवाएं लेने का प्रावधान है।
- जनवि के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को आवश्यकता के अनुसार सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
- जनवि के शैक्षणिक ब्लॉक, लड़कियों और लड़कों के छात्रावासों में रैंप प्रदान किए गए हैं।
- शैक्षणिक ब्लॉक, लड़कियों और लड़कों के छात्रवासों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग–अलग सुलभ शौचालयों का निर्माण किया गया है।
- जनवि के विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) को जनवि छात्रावास के भूतल पर आवास आवंटित किया जाता है और इन बच्चों की कक्षाएं शैक्षणिक ब्लॉक के भूतल पर आयोजित की जाती हैं।
- जनवि में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के छात्रों को उचित शिक्षण सहायता/उपकरण/पठन सामग्री प्रदान की जाती है।

केविसं में दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष प्रावधान/सुविधाएंः

केंद्रीय विद्यालयों में, नए प्रवेश में 3% सीटें क्षैतिज रूप से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आरक्षित हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ट्यूशन फीस और वीवीएन फीस से छूट दी गई है। दिनांक 30.09.2023 तक, विशेष आवश्यकता वाले 6899 बच्चे विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में नामांकित हैं।

समावेशी शिक्षा में एनसीटीई की पहल

उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार, कक्षा I से V और कक्षा VI से VIII को पढ़ाने के लिए शिक्षक के रूप में क्रमशः डी.एड. (विशेष शिक्षा) एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) योग्यता वाले शिक्षक नियुक्ति के बाद प्रारंभिक शिक्षा में एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त 6 महीने के विशेष कार्यक्रम में शामिल होगा।

समावेशी शिक्षा में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) :

मुक्त विद्यालयी शिक्षा के लिए समावेशी शिक्षा नीति को वर्ष 2022 में एनआईओएस द्वारा अंगीकृत किया गया था। दृष्टिहीनता और कम दृष्टि वाले शिक्षार्थियों के लिए, डेज़ी/ई–पब में माध्यमिक स्तर पर 23 विषयों और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 23 विषयों में श्रव्य किताबें तैयार की गई हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को एक भाषा विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों के लिए पेश किया गया है, एनआईओएस ने माध्यमिक स्तर पर एक भाषा विषय के रूप में आईएसएल की शुरुआत की है। बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों के लिए, अध्ययन सामग्री को माध्यमिक स्तर पर 8 विषयों और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर 5 विषयों में भारतीय सांकेतिक भाषा प्रारूप में वीडियो के रूप में तैयार किया गया है, दोनों एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं; इस प्रक्रिया में एनआईओएस द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पर माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रमों में 978+ आईएसएल वीडियो अपलोड किए गए हैं। बधिर और कम सुनने वाले शिक्षार्थियों की शिक्षा हेतु, एनआईओएस सप्ताह में तीन बार पीएम ई–विद्या टीवी चैनल (चैनल नंबर 19) पर भारतीय सांकेतिक भाषा में एक घंटे का लाइव प्रसारण (03:00 अपराह्न से 04:00 अपराह्न) पूरे देश में आईएसएल के प्रति जागरूकता प्रदान करने के लिए करता है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पहल (सीबीएसई):

बोर्ड ने स्कूलों में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया है। समावेशी शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य समतामूलक और गैर–भेदभावपूर्ण व्यवस्था से है जहां प्रत्येक बच्चे को महत्व दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है और सम्मान दिया जाता है।

1. **सीबीएसई में समावेशी प्रकोष्ठ की स्थापनाः** सीबीएसई बोर्ड में अपने संबद्ध स्कूलों में समतामूलक और मुक्त वातावरण तथा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पूर्ण भागीदारी की सुविधा हेतु एक समावेशी सेल की स्थापना की गई है। अब तक, बोर्ड ऐसी श्रेणी के छात्रों को पाठ्यक्रम संव्यवहार में बहुत लचीलापन प्रदान कर रहा है और परीक्षाओं के संचालन के दौरान कई प्रकार की छूट और सहायता भी प्रदान की जाती हैं।
2. **सीबीएसई के संबद्धता उपनियमों में किए गए प्रावधानः** संबद्धता उपविधि के खंड 14.15.2 में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि ''विद्यालय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के उपबंधों के अनुसार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप निम्नलिखित रियायतों के साथ सामान्य विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के समावेशन को बढ़ावा देगाः
    - मुख्यधारा शिक्षा में प्रवेश से इनकार न किया जाना

- विद्यालयों में नामांकन की निगरानी करना
- सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता
- भौतिक बुनियादी ढांचे और शिक्षण पद्धतियों को संशोधित करना
- विद्यालय परिसर को दिव्यांगों के अनुकूल बनाना
- दिव्यांगों के लिए अध्ययन सामग्री की उपलब्धता
- कक्षा व्यवस्था पर पुनः गौर करना
- नियमित रूप से शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण सुनिश्चित करना
- विद्यालयों में विशेष शिक्षकों की व्यवस्था
- स्कूलों में सीडब्ल्यूएसएन उम्मीदवारों के लिए अपेक्षित बुनियादी ढाँचा

3. **परीक्षा पद्धति में किए गए प्रावधानः** सीबीएसई ने आंतरिक मूल्यांकन के साथ–साथ वार्षिक/बोर्ड परीक्षाओं के दौरान मूल्यांकन से संबंधित प्रावधान इस प्रकार किए हैं:

आंतरिक मूल्यांकन के दौरान

- आंतरिक मूल्यांकन के दौरान
- विषयों के चयन में छूट,
- तीसरी भाषा पढ़ने से छूट,
- कौशल विषय चुनने की सुविधा,

परीक्षाओं के आयोजन के दौरान

- उपस्थिति में छूट
- परीक्षाओं में 20 मिनट प्रति घंटे का प्रतिपूरक समय,
- कम्प्यूटर, कैलकुलेटर एवं मैग्नीफाइंग ग्लास आदि के उपयोग की सुविधा,
- स्क्राइब/प्रॉम्पटर आदि की सुविधा
- बैठने की विशेष व्यवस्था
- परीक्षा में व्हीलचेयर ले जाने की अनुमति
- वैकल्पिक प्रश्न/व्यावहारिक घटक के स्थान पर अलग प्रश्न
- सहायक उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति
- इन विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का अलग से मूल्यांकन

इसके अतिरिक्त, स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूलों में समर्थकारी सुविधाएं प्रदान करें जैसे कि;

- प्रवेश/निकास – एक समतल सतह और सुव्यवस्थित गेट चैनल,
- प्रत्येक रास्ते, गैलरी, गलियारे, रैंप और सीढ़ियों पर उचित दिशा–निर्देश के लिए स्कूल परिसर में प्रवेश से लेकर अंदर जाते समय किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए उचित साइन बोर्ड, चेतावनी स्ट्रिप्स, प्रतीकों और संकेतों का प्रदर्शन,
- व्हीलचेयर, वॉकर और छड़ी की गतिशीलता के लिए आसान मार्ग,
- लिफ्ट, रैंप और सीढ़ियाँ – कक्षा और अन्य सुविधाओं तक आसान पहुंच के लिए दोनों तरफ रेलिंग के साथ फिसलन रोधी कवर रैंप का होना। स्कूल भवन की सभी मंजिलों तक पहुंचने के लिए एक उचित लिफ्ट/रैंप का निर्माण किया जाना चाहिए, एलिवेटर/लिफ्ट में श्रव्य संकेत।
- लो फ्लोर बसें
- निर्बाध पहुंच हेतु स्कूल भवन की सभी मंजिलों पर लिफ्ट कनेक्टिविटी की सुविधा।

6

प्रशासन

प्रशासन

शिक्षा मंत्रालय माननीय शिक्षा मंत्री के समग्र प्रभार के अधीन है और वर्तमान में 3 राज्य मंत्रियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। शिक्षा मंत्रालय में दो विभाग नामतः स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एंव उच्चतर शिक्षा विभाग हैं।

प्रत्येक विभाग का प्रमुख भारत सरकार का सचिव होता है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव को 1 अपर सचिव, 4 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, उच्चतर शिक्षा विभाग के सचिव को 1 अपर सचिव, 5 संयुक्त सचिव, 1 आर्थिक सलाहकार और 1 उप महानिदेशक (सांख्यिकी) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, 1 संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार हैं, जो दोनों विभागों के लिए हैं।

विभागों को ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्क, अनुभागों और इकाइयों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक ब्यूरो निदेशक/उप सचिव के स्तर पर मंडल प्रमुखों द्वारा सहायता प्राप्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव के एक अधिकारी के समग्र प्रभार के अधीन है।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग की संगठनात्मक संरचना क्रमशः अनुलग्नक–I और अनुलग्नक–II में संलग्न है।

दोनों विभागों के सचिवालय में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थापना एवं सेवा संबंधी मामले उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रशासन ब्यूरो में संचालित किये जाते हैं। वर्ष 2023 की गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क) दोनों विभागों के केंद्रीय कर्मचारी योजना के तहत नियुक्त अधिकारियों और केंद्रीय सचिवालय सेवा, केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और संवर्ग बाह्य पदों नामतः सलाहकार संवर्ग, सांख्यिकीय संवर्ग आदि के अधिकारियों के स्थापना मामले।

ख) संबंधित संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरणों को कैलेंडर वर्ष 2023 (दिनांक 01.01.2024 तक) के लिए अचल संपत्ति विवरण भेजना।

ग) वेतन एवं लेखा कार्यालय के परामर्श से आने वाले महीनों में सेवानिवृत्त होने वाले इस मंत्रालय के कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है।

घ) मंत्रालय ने ई–ऑफिस, कानूनी/न्यायालय मामलों की निगरानी प्रणाली और पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान की प्रक्रिया पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय में सभी अधिकारियों/एआईएस/अन्य सेवाओं के कर्मचारियों के साथ–साथ सीएसएस/सीएसएसएस/सीएससीएम के ऊपर के स्तर के अधिकारियों के लिए "स्पैरो" (स्मार्ट कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो) नामक एक ऑनलाइन प्रणाली सफलतापूर्वक संचालित की गई है। इन अधिकारियों के संबंध में एपीएआर मामले केवल इस पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं। साथ ही, पेंशन स्वीकृति और भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली के लिए "भविष्य" नामक एक ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। ईएचआरएमएस 2.0

के अधिकांश मॉड्यूल सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए गए हैं और मामलों को तदनुसार संसाधित किया गया है। सभी मामलों में, शाखा में प्राप्त वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को संबंधित संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों को प्रतिधारण के लिए भेजे जाने से पहले प्रस्तुत की गई थी।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

स्थापना शाखा के अंतर्गत ई.IV अनुभाग (पूर्ववर्ती प्रशिक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय के दोनों विभागों अर्थात स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के कोर सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के सदस्यों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को संसाधित करता है। प्रशिक्षण संबंधी मामले को सचिवीय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए), राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), नई दिल्ली, राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम), फरीदाबाद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद आदि जैसी संस्थाओं के साथ संपर्क में रखा जाता है ताकि प्रबंधन के क्षेत्रों में दोनों विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों को लोक प्रशासन, सतर्कता, रोकड़ और लेखा, कार्मिक आदि विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों के आधार पर नामित/प्रशिक्षण प्रदान किया जा सके।

प्रशिक्षण प्रकोष्ठ कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, आर्थिक कार्य विभाग आदि द्वारा विदेशी प्रशिक्षण के घरेलू वित्त पोषण आदि के तहत विदेशों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए जारी परिपत्रों के उत्तर में पात्र और उपयुक्त अधिकारियों के नामांकन भी भेजता है। वर्ष 2023–24 (दिनांक 01.04.2023 से 31.01.2024) के दौरान विभिन्न प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित/नामांकन अग्रेषित किया गया था जिसका संक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	प्रशिक्षण और प्रशिक्षु का नामकरण	प्रशिक्षण संस्थान / प्रायोजक	भेजे गए/ नामांकित अधिकारियों/ कर्मचारियों की संख्या
1.	डीओपीटी द्वारा संचालित विभिन्न स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम (ए, बी, डी, ई, चरण I, II, चरण III, चरण IV आदि)	आईएसटीएम, नई दिल्ली (ज्यादातर ऑनलाइन मोड पर)	94
2.	एएसओ (डीआर)/स्टेनो ग्रेड 'डी' के लिए फाउंडेशन प्रशिक्षण कार्यक्रम	आईएसटीएम, नई दिल्ली, आदि।	41
3.	वित्तीय प्रबंधन में डिप्लोमा	एजेएनआईएफएम, फ़रीदाबाद	1
4.	सेवाकालीन एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम	डीओपी एंड टी	6
5.	लेटरल एंट्री के तहत शामिल होने वाले अधिकारियों हेतु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	आईएसटीएम, नई दिल्ली	2
6.	विभिन्न संवर्गों के लिए मध्य कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम	संवर्ग नियंत्रण प्राधिकरण	3
7.	विविध प्रशिक्षण	आईएसटीएम, आदि	14
	कुल		**161**

उपरोक्त के अलावा, यह अनुभाग 2020 और 2022 बैच के एएसओ के लिए ऑन–द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम की नीति भी लेकर आया है। यूजीसी, एआईसीटीई, केंद्रीय हिंदी निदेशालय आदि जैसे विभिन्न प्रतिष्ठानों के फील्ड दौरे विभिन्न बैचों में 40 एएसओ के लिए समन्वित और सफलतापूर्वक आयोजित किए गए।

सूचना और सुविधा केंद्र (आईएफसी)

शिक्षा मंत्रालय में आने वाली आम जनता और गैर–सरकारी संगठनों के लिए सूचना तक त्वरित और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने हेतु जून 1997 में एक राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क (एनआईसीएनईटी) आधारित सूचना और सुविधा केंद्र (आईएफसी) की स्थापना की गई थी। सूचना और सुविधा केंद्र का मुख्य उद्देश्य एक प्रभावी, उत्तरदायी और नागरिक–अनुकूल प्रशासन को बढ़ावा देना है। केंद्र आगंतुकों, गैर–सरकारी संगठनों, भारतीय छात्रों और उच्च अध्ययन के लिए भारत आने वाले विदेशी छात्रों को मंत्रालय की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अर्थात विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के दिशानिर्देश और आवेदन पत्र मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। इंटरनेट सुविधा वाले कंप्यूटर के माध्यम से डाटा/सूचना प्राप्त की जा सकती है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग की वेबसाइट का पता www.education.gov.in है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन पर रिपोर्टः

सूचना का अधिकार अधिनियम दिनांक 12 अक्तूबर, 2005 को लागू किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर सामान्यत सूचना सुविधा केन्द्र द्वारा उसी तारीख को संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को अग्रेषित कर दिए जाते हैं। आवेदन शुल्क रु.10/– प्रति आवेदन विभाग के कैशियर के पास जमा किया जाता है।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों की बढ़ती संख्या (ऑनलाइन सहित) को ध्यान में रखते हुए और सूचना साझा करने की सुविधा के लिए, मंत्रालय में अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित करने की समीक्षा की गई है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के तहत अवर सचिव और अवर सचिव स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है और उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रभाग प्रमुखों को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। दोनों विभागों अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता एवं उच्चतर शिक्षा विभाग के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अपीलीय प्राधिकरणों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। यह जानकारी आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के प्रावधानों के अनुसार वार्षिक आधार पर अद्यतित भी की जाती है।

विभाग ब्यूरो प्रमुखों के माध्यम से अपने स्वायत्त संगठन द्वारा आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख कर रहा है। वर्ष 2010–2011 से केन्द्रीय सूचना आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन हेतु सूचना एकत्र करने की प्रणाली में उनके द्वारा संशोधन किया गया है। इसे त्रैमासिक आधार पर और ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। मंत्रालयों के स्वायत्त संगठनों के लिए ऑनलाइन सुविधा का विस्तार किया गया है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सभी संगठनों को पासवर्ड सौंपे गए हैं और उन्हें सूचित किया गया है कि वे स्वयं सीआईसी की वेबसाइट पर सूचना अपलोड करें।

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित विवरण मंत्रालय में आवेदनों/अपीलों की वर्ष–वार प्राप्ति निम्नानुसार दर्शाता हैः–

वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई
2006	359
2007	641
2008	1554
2009	2166
2010	3235

वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदनों और अपीलों की कुल संख्या और उन पर की गई कार्रवाई
2011	4833
2012	3940
2013	11028
2014	17681
2015	16643
2016	16336
2017	13645
2018	13214
2019	13321
2020	12911
2021	17379
2022	19623
2023	18358 (ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन और अपील सहित 31.12.23 तक की स्थिति)

सतर्कता गतिविधियाँ

मंत्रालय में गठित सतर्कता तंत्र सचिव (उच्चतर शिक्षा) के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन है, जिन्हें संयुक्त सचिव के स्तर के एक अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी के साथ–साथ एक उप सचिव (रिक्त), दो अवर सचिवों और अन्य सहायक कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

रिपोर्ट की अवधि के दौरान सतर्कता विंग को केन्द्रीय सतर्कता आयोग और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से विभिन्न संदर्भ प्राप्त हुए और कई शिकायतें प्रत्यक्ष रूप से व्यक्तियों से प्राप्त हुई। जनहित प्रकटीकरण संकल्प के तहत शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं जो जांच के विभिन्न चरणों में हैं। मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत विभिन्न स्वायत्त संगठनों में अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 30 अक्टूबर 2023 से 5 नवंबर 2023 तक "भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहें" विषय के साथ मनाया गया। बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए गए और उच्चतर शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों को सभी सार्वजनिक व्यवहार में ईमानदारी बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023 की प्रस्तावना के रूप में पीआईडीपीआई संकल्प को लोकप्रिय बनाने के लिए पोस्टर प्रदर्शित किए गए और मंत्रालय के अधिकारियों के लिए 'आईओ/पीओ की भूमिका और निवारक सतर्कता' पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया।

राजभाषा प्रभाग

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

मंत्रालय के दोनों विभाग अर्थात उच्च शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, गृह मंत्रलय के राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर उचित ध्यान देते हैं। वर्ष के दौरान दोनों विभागों के विभिन्न अनुभागों और संबद्ध तथा अधीनस्थ संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/परिषदों आदि में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रभावी उपाय किए गए हैं। मंत्रालय के दोनों विभागों अर्थात् उच्चतर शिक्षा विभाग एवं स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग को राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया है।

मंत्रालय में राजभाषा कार्यान्वयन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों तथा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है।

मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न गतिविधियाँ

(क) मंत्रालय में संयुक्त सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन

समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुपालन में उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) मंत्रालय में नियमित रूप से कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। दो सत्रीय कार्यशालाओं के साथ–साथ पूर्ण दिवसीय कार्यशालाएँ भी आयोजित की गई हैं। इसमें मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

(ग) 14–15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों के 12 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(घ) हिन्दी दिवस के अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा एक संदेश जारी किया गया तथा सचिव, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु अपील जारी की गयी।

(ड.) शिक्षा मंत्रालय में दिनांक 14.09.2023 से 28.09.2023 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। पखवाड़े के दौरान पाँच प्रतियोगिताएँ अर्थात् हिंदी निबंध प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण–आलेखन प्रतियोगिता, हिंदी टाइपिंग प्रतियोगिता, वाद–विवाद प्रतियोगिता और स्वरचित कविता पाठ प्रतियोगिता आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक प्रतियोगिता में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अलग–अलग प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थीं। इन प्रतियोगिताओं में दोनों विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं दो प्रोत्साहन पुरस्कार के रूप में रूपये 5000/–, रूपये 4000/–, रूपये 3000/– एवं रूपये 2000/– की राशि प्रदान की गई।

(च) इस अवधि के दौरान इस मंत्रालय के दोनों विभागों के तहत 39 संगठनों को नवंबर 2022 में राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के तहत अधिसूचित किया गया था।

(छ) वर्ष के दौरान माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने शिक्षा मंत्रालय से संबद्ध एवं अधीनस्थ 113 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/परिषदों आदि का राजभाषा निरीक्षण किया।

(ज) इस अवधि के दौरान मंत्रालय द्वारा 23 संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/परिषदों आदि का राजभाषा निरीक्षण किया गया है। इसके अलावा, इस मंत्रालय के अधीन कार्यालयों की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों में भी मंत्रालय का प्रतिनिधित्व किया गया।

(झ) मंत्रालय को अधीनस्थ संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्डों/परिषदों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति पर नजर रखने के लिए उनकी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट और बैठकों के कार्यवृत्त प्राप्त होते हैं और मंत्रालय में उनकी समीक्षा की जाती है। सुधारात्मक उपाय सुझाए गए हैं।

अनुवाद कार्य

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अनुपालन में संसदीय प्रश्नों और उत्तरों, कैबिनेट नोट्स, अनुदान मांगों, वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्टों, अधिसूचनाओं, सामान्य आदेशों, प्रेस विज्ञप्तियों आदि का हिंदी अनुवाद संसद और कैबिनेट सचिवालय को भेजने के लिए तैयार किया जाता था।

लोक शिकायत

उच्चतर शिक्षा विभाग में आर्थिक सलाहकार और उप सचिव (पीजी) के अधीन एक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है, जिन्हें क्रमशः लोक शिकायत अपीलीय प्राधिकारी और लोक शिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। लोक शिकायत प्रभाग का प्रयास शिकायत निवारण तंत्र

को अधिक सुलभ, व्यापक, मजबूत और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना है। उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के तहत विभिन्न ब्यूरो/डिवीजन/संगठनों के साथ प्रभावी समन्वय के माध्यम से नागरिकों की आवाज को और अधिकारियों को सशक्त बनाकर नागरिकों और सरकार को करीब लाने का प्रयास है।

उप सचिव (पीजी) उच्चतर शिक्षा विभाग के नोडल लोक शिकायत अधिकारी हैं। वह प्रत्येक बुधवार को सुबह 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे के बीच कर्मचारियों के साथ–साथ जनसदस्यों की समस्याओं को सुनने के लिए उपलब्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त, कोई भी व्यक्ति सभी कार्य दिवसों में कार्य समय के दौरान नोडल लोक शिकायत अधिकारी से मिल सकता है। लोक शिकायतों के निवारण के संबंध में सरकार की नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग और इसके नियंत्रणाधीन स्वायत्त/अधीनस्थ संगठनों में कई नोडल शिकायत समाधान अधिकारी (जीआरओ) नामित किए गए हैं।

सीपीजीआरएएमएस का उन्नत संस्करण 7.0 डीएआरपीजी द्वारा किए गए नवीनतम सुधारों के साथ उच्चतर शिक्षा विभाग में कार्यात्मक है, जो पोर्टल को अधिक नागरिक–केंद्रित बनाता है। यह नागरिकों को मंत्रालय/विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ अधिकारियों/संस्थानों /सार्वजनिक उपक्रमों आदि में क्षेत्र–स्तरीय शिकायत अधिकारियों को सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराने का विकल्प देता है। इस विकल्प ने शिकायत निवारण समय में सुधार किया है क्योंकि संबंधित क्षेत्र–स्तरीय शिकायत अधिकारी तक पहुंचने के लिए पहले जिन प्रणालियों से होकर गुजरना पड़ता था, उनकी संख्या कम हो गई है। उन्नत संस्करण 7.0 सीपीजीआरएएमएस अपने नवीनतम सुधारों के साथ निपटान की उच्च दरों और शिकायतों के औसत निपटान समय में उत्तरोत्तर कमी के परिणामस्वरूप एक अधिक उत्तरदायी प्रणाली है, डीएआरपीजी ने सीपीजीआरएएमएस शिकायतों के निवारण समय को सामान्य प्रक्रिया में 45 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है।

प्रतिवेदनाधीन अवधि (दिनांक 01.01.2023 से 31.12. 2023) के दौरान पीजी पोर्टल के माध्यम से अर्थात केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) और प्रधान मंत्री कार्यालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कैबिनेट सचिवालय (लोक शिकायत निदेशालय), राष्ट्रपति सचिवालय और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग सहित विभिन्न स्रोतों और उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा विकसित एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम) पोर्टल के माध्यम से भी कुल **24814** शिकायतें प्राप्त हुई। दिनांक 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त लोक शिकायतों का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:

सीपीजीआरएएम पोर्टल (डीओएचई) पर प्राप्त कुल शिकायतें	वास्तविक रूप में प्राप्त कुल शिकायतें	इंग्राम पोर्टल पर प्राप्त कुल शिकायतें	सीपीजीआरएएम पोर्टल (डीओएचई) पर प्राप्त कुल अपील	कुल रोग (प्राप्त)	सीपीजीआरएएम पोर्टल (डीओएचई) पर निस्तारित की कुल शिकायतें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) [(1) + (2) + (3) + (4)]	(6)
18913 {1621 (बीएफ) + 17292}	227	1058 (निस्तारण = 839)	4616 {859 (बीएफ) + 3757}	24814	23092/

**औसत निस्तारण अवधि 26 दिन है*

**इनग्राम के 839 निस्तारण, भौतिक रूप से प्राप्त पीजी के 227 निस्तारण और अपीलों के 4329 निस्तारण शामिल हैं।*

नागरिक/ग्राहक चार्टर

नागरिकों को प्रदान की जाने योग्य सेवाओं के संबंध में उन्हें सशक्त बनाने के साथ–साथ उनके मंत्रालय द्वारा उनके प्रति ऐसी प्रत्येक सेवा के लिए प्रतिबद्धताओं के साथ, और नागरिक–प्रशासन इंटरफेस के मौजूदा उपकरणों के रूप में चार्टर की सुपुर्दगी के माध्यम से नागरिकों और सरकारी पदाधिकारियों के बीच संबंधों को बनाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के दोनों विभागों [अर्थात् स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग एवं उच्चतर शिक्षा विभाग] ने सुशासन पर बल देने के लिए अपने नागरिक/ग्राहक चार्टर (सीसीसी) जारी किए हैं तथा नागरिकों की प्रभावी और कुशल तरीके से सेवा करने का लगातार प्रयास करते हैं ताकि न केवल उनकी अपेक्षाओं से भी अधिक कार्य को पूरा किया जा सके। नागरिक/ग्राहक चार्टर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

शिक्षा मंत्रालय में साइबर सुरक्षा

भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों की तरह शिक्षा मंत्रालय भी दिन–प्रतिदिन के कार्य के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) पर निर्भर है और दुर्भावनापूर्ण साइबर संबंधित घटनाओं के कारण आईसीटी में कोई भी व्यवधान शिक्षा मंत्रालय के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों और प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। इसलिए, यह सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है कि व्यवधान कम हों, न्यूनतम अवधि के हों और प्रबंधनीय हों तथा कम से कम क्षति हो।

शिक्षा मंत्रालय ने एक साइबर सेल का गठन किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) और डिप्टी सीआईएसओ शामिल हैं, जो निम्नलिखित संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के साथ साइबर घटनाओं के लिए तैयारी, प्रतिक्रिया और पुनर्प्राप्ति के लिए एक रणनीतिक ढांचा और कार्रवाई स्थापित करेंगे:

1. यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे में आने वाले संगठन/एचईआई सीएफआई (सीयू, आईआईएम, आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, एनआईटीटीटीआर, आईआईएससी और आईआईएसईआर) और यूजीसी/एआईसीटीई तथा स्कूल शिक्षा के स्वायत्त निकायों के तहत अन्य सभी संस्थानों में सीआईएसओ नियुक्त करते हैं।
2. साइबर संकट प्रबंधन योजना (सीसीएमपी) में निहित दिशानिर्देशों को लागू करना और उन्हें एन–सीसीएमपी के अनुरूप अपनी स्वयं की क्षेत्रीय और संगठनात्मक साइबर सुरक्षा योजनाएं तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. अब तक उठाए गए साइबर सुरक्षा उपायों की जांच करना।
4. उपयोगकर्ताओं को साइबर सुरक्षा के प्रोटोकॉल के बारे में शिक्षित करना और समय–समय पर एनआईसी–मेयटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/परामर्शों का अनुपालन सुनिश्चित करना।
5. किसी पायरेटेड सॉफ़्टवेयर या अप्रचलित सॉफ़्टवेयर के लिए उनके संगठन/संस्थान में उपयोग किए जा रहे सभी कंप्यूटरों जैसे पीसी, लैपटॉप इत्यादि का सर्वेक्षण करवाना।

गतिविधियाँ, उपलब्धियाँ और मील के पत्थर

साइबर सेल, वर्ष 2023 के दौरान शिक्षा मंत्रालय ने वेबसाइट घुसपैठ और मैलवेयर प्रसार, दुर्भावनापूर्ण कोड, फ़िशिंग, वेबसाइट विरूपण, अनधिकृत नेटवर्क स्कैनिंग/जांच गतिविधियों, डाटा उल्लंघन और कमजोर सेवाओं की 36 रिपोर्ट की गई घटनाओं को संभाला और संबंधित संगठनों के माध्यम से उनका शमन और उपचार सुनिश्चित किया। इस अवधि के दौरान आईटी संपत्तियों और उनकी कार्यक्षमता में कमियों को ठीक करने के लिए संबंधित व्यक्तियों और संगठनों के साथ 40 सुरक्षा अलर्ट और 6 परामर्शिका साझा की गईं।

साइबर जागरूकता दिवस के एक भाग के रूप में साइबर सुरक्षा खतरों और सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए तकनीकों और उपकरणों की तैनाती के बारे में शिक्षा मंत्रालय और अन्य संलग्न कार्यालयों/स्वायत्त निकायों के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। साइबर सेल, शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने साइबर सुरक्षा पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं/समीक्षा बैठकों/सम्मेलनों में भी भाग लिया। व्यक्तिगत डाटा उल्लंघन के प्रति एप्लिकेशन/प्लेटफ़ॉर्म और डाटाबेस को सुरक्षित करने के लिए इन पैनल वाले ऑडिटरों के माध्यम से साइबर सुरक्षा ऑडिट के लिए मेयटी के दिशानिर्देशों का अनुपालन निरंतर आधार पर सुनिश्चित किया जा रहा है।

साइबर हमलों के प्रति संवेदनशील आईटी संपत्तियों (550 सिस्टम झ 7 वर्ष पुराने) को लाइसेंस प्राप्त एंटीवायरस और सॉफ्टवेयर से बदल दिया गया। यूनिफाइड एंडपॉइंट मैनेजमेंट (यूईएम) और एंडपॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पांस (ईडीआर) सभी प्रणालियों में स्थापित किए गए हैं। आईटी परिसंपत्ति सूची और आईटी नेटवर्क का मानचित्र तैयार किया गया था और समय–समय पर अद्यतन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय के तहत 173 संगठनों में सीआईएसओ/डिप्टी सीआईएसओ का नामित किया गया और पूरा किया गया।

❖ ❖ ❖

7

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखा परीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखा परीक्षा

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक/पीएसी द्वारा किए गए लंबित लेखा परीक्षा समुक्तियों का सारांश

उच्चतर शिक्षा विभाग

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का सार
1.	**भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान** 1. खड़गपुर 2. गुवाहाटी 3. इंदौर 4. भिलाई	55.46 करोड़ रुपये की परिलब्धि पर 16.32 करोड़ रुपये की कर कटौती नहीं हुई। **पैरा नं. 3.2.1** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**
2.	**भारतीय प्रबंध संस्थान** 1. तिरुचिरापल्ली 2. काशीपुर 3. लखनऊ 4. इंदौर 5. कोलकाता	शिक्षण स्टाफ को संकाय विकास भत्ते का 5.49 करोड़ रुपये का अनधिकृत भुगतान **(पैरा नं. 3.2.5)** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**
3.	**पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी**	योजना की कमी के कारण बहुउद्देशीय व्यायामशाला का निर्माण नहीं हो सका और इनडोर खेल प्रशिक्षण सुविधा के निर्माण में लागत में वृद्धि हुई। **(पैरा नं. 3.2.7)** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**
4.	**अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ**	पट्टा किराया की कम वसूली – 79.31 लाख रुपये **(पैरा नं. 3.2.8)** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**
5.	1. एनआईटीटीटीआर, भोपाल 2. एबीवीआईआईआईटीएम, ग्वालियर 3. लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान, ग्वालियर	वित्त मंत्रलय के दिशानिर्देशों के अनुसार जीपीएफ/सीपीएफ अंशदान में निवेश न करना **(पैरा नं. 3.4.1)** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का सार
6.	1. आईआईटी, खड़गपुर 2. आईआईटी, गुवाहाटी 3. विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांति निकेतन 4. आईआईईएसटी, शिबपुर 5. बीबीएयू 6. एएमयू 7. बीएचयू 8. आईआईएम, लखनऊ 9. एमएनएनआईटी, इलाहाबाद 10. एनआईओएस 11. आईआईएम, काशीपुर 12. इलाहाबाद विश्वविद्यालय 13. एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता (संस्कृति मंत्रालय)	**तदर्थ बोनस का अनियमित भुगतान** 13 केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के अभाव में अपने कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2015–16 से 2017–18 अवधि के दौरान उनके कर्मचारियों को 6.08 करोड़ रुपये का अनियमित भुगतान किया गया। **[पीएसी की 62वीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा)]**

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

क्र.सं.	संस्था का नाम	पैरा का सार
1.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, दिल्ली	परिवहन शुल्क का परिहार्य भुगतान – 1.40 करोड़ रु. **(पैरा नं. 3.2.6)** **(2022 की रिपोर्ट संख्या 26)**

8

बजट

बजट

बजट भाषण 2023–24 में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

उच्चतर शिक्षा विभाग

क्र. सं.	पैरा संख्या	की गई घोषणा	स्थिति
1	31	चिकित्सा उपकरणों हेतु बहुविषयक पाठ्यक्रम भविष्य की चिकित्सा प्रौद्योगिकियों, उच्च–स्तरीय विनिर्माण और अनुसंधान हेतु कुशल कार्यबल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा संस्थानों में चिकित्सा उपकरणों के लिए निर्धारित बहु–विषयक पाठ्यक्रमों का सहयोग प्रदान किया जाएगा।	उच्चतर शिक्षा विभाग से इनपुट फार्मास्यूटिकल्स विभाग जो इस बजट घोषणा का समन्वयक है, को प्रदान किए गए हैं और वह इसे आगे ले जा रहा है। (कार्रवाई शुरू की गई)
2.	60	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेतु उत्कृष्टता केंद्र "भारत में एआई बनाएं और एआई भारत के लिए काम करे" की संकल्पना को साकार करने के लिए शीर्ष शैक्षणिक संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तीन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अग्रणी उद्योग से संबंधित लोग अंतःविषयक अनुसंधान करने, कृषि, स्वास्थ्य और संधारणीय शहरों के क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुप्रयोगों और गुणवत्ता सहित समस्या समाधान तंत्र विकसित करने में भागीदार होंगे। यह एक प्रभावी एआई पारिस्थितिकी तंत्र को प्रेरित करेगा और क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधनों का पोषण करेगा।	तीन उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना – स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और संधारणीय शहरों में प्रत्येक में 1। ईएफसी ने वित्त वर्ष 2023–24 से 2027–28 की अवधि के लिए 990 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय को अनुमोदित किया है, जिसमें 3–सीओई में से प्रत्येक के लिए 310 करोड़ रुपये शामिल हैं। सीपीएमयू के लिए 25 करोड़ रुपये (5 करोड़ रुपये/वर्ष), चरण–I प्रस्तावों के लिए 30 करोड़ रुपये और मध्य/अंतिम मूल्यांकन के लिए 5 करोड़ रुपये। यह योजना एक शीर्ष समिति द्वारा कार्यान्वित की जाएगी, जो सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है, जिसकी अध्यक्षता सचिव (एचई) और डॉ. श्रीधर वेम्बू, संस्थापक और सीईओ, ज़ोहो कॉर्पोरेशन द्वारा की जाएगी, और इसमें उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञ और संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल

क्र. सं.	पैरा संख्या	की गई घोषणा	स्थिति
			होंगे। आईआईटी जम्मू में केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की गई है, जो परियोजना के समय पर निष्पादन और निगरानी में शीर्ष समिति का सहयोग करेगी। (कार्रवाई शुरू की गई)
3.	73	5जी सेवाएँ अवसरों, व्यवसाय मॉडल और रोजगार संभावनाओं की एक नई श्रृंखला को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी सेवाओं का उपयोग करके एप्लिकेशन विकसित करने हेतु 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। प्रयोगशालाएँ अन्य अनुप्रयोगों के अलावा, स्मार्ट क्लासरूम, सटीक खेती, उन्नत परिवहन प्रणाली और स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों को कवर करेंगी।	उच्चतर शिक्षा विभाग से इनपुट दूरसंचार विभाग, जो इस बजट घोषणा का समन्वयक है, को प्रदान किए गए हैं और वह इसे आगे ले जा रहा है। (कार्रवाई शुरू की गई)

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

क्र. सं.	पैरा संख्या	की गई घोषणा	स्थिति
1	46	पीएम ईविद्या के तहत 200 डीटीएच टीवी चैनलों की शुरूआत	• कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी को छोड़कर, अन्य सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने चैनलों के संचालन के लिए एनसीईआरटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। • आज तक विभिन्न संगठनों के 10,667 ई–कंटेंट की समीक्षा की गई। • वीडियो के एक साथ प्रसारण के लिए वर्तमान में कुल 72 यूट्यूब चैनल लाइव हैं। • गुणवत्तापूर्ण और आकर्षक वीडियो सामग्री विकसित करने के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएँ शुरू हो गई हैं। पहले चरण (सीआईईटी, एनसीईआरटी में 10 से 12 अक्टूबर 2023 तक आयोजित) में हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पंजाब और हरियाणा

क्र. सं.	पैरा संख्या	की गई घोषणा	स्थिति
			(4 राज्य) एवं चंडीगढ़ तथा जम्मू और कश्मीर (02 संघ राज्य क्षेत्र) से 41 प्रतिभागी थे। दूसरा चरण, जो 18 से 20 अक्टूबर 2023 तक सीआईईटी, एनसीईआरटी में आयोजित किया गया, उसमें बिहार, उत्तराखंड और गुजरात (3 राज्यों) से 20 प्रतिभागी थे। इसका समापन दिसंबर 2023 तक हो जाना चाहिए। ● पीएम ईविद्या के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया जा रहा है। यह शिक्षार्थियों को हमें फीडबैक देने में भी समर्थकारी बनाएगा।
2	47	आभासी प्रयोगशालाओं का निर्माण	● दीक्षा प्लेटफॉर्म पर आभासी प्रयोगशाला हेतु एक वर्टिकल बनाया गया है। ● 214 सिमुलेशन और 654 अन्य संसाधन जैसे लैब मैनुअल पीडीएफ, वीडियो आदि सहित 218 आभासी प्रयोगशाला प्रयोग। ● ग्रेड 6—12 के लिए गणित और विज्ञान संबंधी 868 सामग्री संसाधन हिंदी और अंग्रेजी में 1,74,326 मिनट प्ले टाइम के साथ कुल 1,33,038 बार देखी गई। ● देश भर के शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए आभासी प्रयोगशाला संबंधी 31 घंटे के प्रशिक्षण का आयोजन किया और पीएम ईविद्या डीटीएच टीवी चैनलों और एनसीईआरटी के आधिकारिक एवं इवेंट यूट्यूब चैनलों (कक्षा VI-XII) पर सीधा प्रसारण किया गया। यूट्यूब पर आभासी प्रयोगशाला संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम वीडियो पर 4,55,206 व्यूज़ आए।
		नए ओलैब्स के विकास संबंधी प्रगति	● डेवलपर्स द्वारा छोटे टुकड़ों में प्रस्तुत किए गए नए ओलैब्स की संख्या— 189, विज्ञान— 95, गणित— 29, सामाजिक विज्ञान— 09, कंप्यूटर विज्ञान— 47, हिंदी— 04, संस्कृत— 04, अंग्रेजी— 01 ● अमृता विश्वविद्यालय/सीडीएसी मुंबई द्वारा प्रदान किए गए प्रयोगों की संख्या— 189 ● समीक्षा किए गए प्रयोगों की संख्या — 189 ● संपादन और पुनः प्रेषण हेतु डेवलपर्स को वापस भेजे गए प्रयोगों की संख्या — 189

क्र. सं.	पैरा संख्या	की गई घोषणा	स्थिति
	48	भारतीय भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाले ई–कंटेंट का विकास	• पीएम ईविद्या चैनलों, ऑल इंडिया रेडियो, सामुदायिक रेडियो स्टेशनों, आईरेडियो, दीक्षा, ईपाठशाला, स्वयम आदि के माध्यम से टेलिकास्ट/प्रसारण/प्रसार के लिए भारतीय भाषाओं में विभिन्न ऑडियो–वीडियो कार्यक्रम लगातार तैयार किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विभिन्न ग्राफिक्स उपन्यास, पोस्टर और बैनर तैयार किए जाते हैं। • वर्ष 2023–2024 के दौरान कुल 3,025 ऑडियो और 1,995 वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं।
	49	ई–सामग्री प्रतियोगिता	• प्रतियोगिता की संरचना और मानदंड तय करने के लिए निर्णायक मण्डल के सदस्यों की एक बैठक आयोजित की गई। • प्रतियोगिता के अगले संस्करण (2023–2024) की घोषणा शीघ्र ही की जाएगी। • आगामी प्रतियोगिता की तैयारियां जारी हैं।

बजटीय प्रावधान

उच्चतर शिक्षा विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
I	**केंद्र का स्थापना व्यय**			
1	सचिवालय– सामाजिक सेवाएं	164.23	170.90	162.50
2	हिंदी निदेशालय	39.77	20.00	16.54
3	वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग	13.00	13.00	15.05
4	सीआईआईएल, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र	61.37	53.50	42.07
5	विदेशी शैक्षणिक संस्थान	12.48	12.48	11.35
	योग– केंद्र का स्थापना व्यय	**290.85**	**269.88**	**247.51**

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
	योजनाएँ			
II	**केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ**			
	उच्चतर शिक्षा			
1	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसर	0.27	0.27	0.27
2	विश्व स्तरीय संस्थान	1500.00	1300.00	1800.00
3	प्रधानमंत्री बालिका छात्रवास	10.00	1.73	2.00
4	भारतीय ज्ञान परंपरा	20.00	17.00	10.00
5	उच्च शिक्षण संस्थाओं संबंधी ग्लू ग्रांट	10.00	1.00	1.00
	योग –उच्चतर शिक्षा	**1540.27**	**1320.00**	**1813.27**
	छात्र वित्तीय सहायता			
6	प्रधान मंत्री–उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन (पीएम.यूएसपी)	1554.00	1054.00	1558.00
7	पीएम रिसर्च फेलोशिप	400.00	330.00	350.00
	कुल–छात्र वित्तीय सहायता	**1954.00**	**1384.00**	**1908.00**
	डिजिटल इंडिया– ई–लर्निंग			
8	आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	400.00	400.00	480.00
9	उच्च शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (एचईएसपीआईएस)	10.00	10.00	15.00
10	क्रेडिट शैक्षणिक बैंक	10.00	5.00	10.00
	योग–डिजिटल इंडिया– ई–लर्निंग	**420.00**	**415.00**	**505.00**
	अनुसंधान और नवाचार			

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
11	राष्ट्रीय डिजाइन नवाचार पहल	10.00	10.00	10.00
12	उच्च शिक्षण संस्थाओं में स्टार्टअप इंडिया पहल	11.21	53.00	0
13	उन्नत भारत अभियान	9.40	5.00	5.00
14	इंप्रिंट (प्रभावी अनुसंधान नवाचार तकनीक) अनुसंधान पहल का कार्यान्वयन	5.00	1.00	10.00
15	शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क)	50.00	25.00	100.00
16	विज्ञान में परिवर्तनकारी और उन्नत अनुसंधान योजना (स्टार्स)	25.00	94.39	30.00
17	तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार–ईएपी (एमईआरआईटीई)	100.00	5.00	200.00
	योग–अनुसंधान और नवाचार	**210.61**	**193.39**	**355.00**
18	पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक और शिक्षण मिशन (पीएमएमएमएनएमटीटी)	45.00	45.00	100.00
19	वैश्विक शैक्षणिक नेटवर्क पहल (जीआईएएन)	10.00	5.00	10.00
20	शिक्षुता प्रशिक्षण संबंधी कार्यक्रम– छात्रवृत्ति और वजीफा/राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस)	440.00	460.00	600.00
21	भारत में अध्ययन	25.00	20.00	20.00
22	चैम्पियन सेवा सेक्टर योजना शिक्षा सेवाएँ उच्चतर शिक्षा का अंतरराष्ट्रीयकरण	200.00	100.00	104.00
23	दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) अध्येतावृत्ति	3.00	3.00	2.66
24	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में 3 उत्कृष्टता केंद्र (सीओईएस) की स्थापना		35.00	255.00
	योग–केन्द्रीय क्षेत्र योजनाएँ/परियोजनाएं	**4847.88**	**3980.39**	**5672.93**

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
III	**केंद्र प्रायोजित योजनाएँ**			
1.	राष्ट्रीय शिक्षा मिशनः राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)	1500.00	500.00	1814.94
2	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों के वेतनमान में सुधार			
	कुल– योजनाएँ	**6347.88**	**4480.39**	**7487.87**
	अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय–स्वायत्त निकाय			
	सांविधिक और नियामक निकाय			
1	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता	5360.00	6409.00	2500.00
2	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)	420.00	400.00	400.00
	कुल–सांविधिक और नियामक निकाय	**5780.00**	**6809.00**	**2900.00**
	स्वायत्त निकाय			
3 (क)	केंद्रीय विश्वविद्यालयों (सीयू) को अनुदान	10677.76	11516.58	15558.00
3 (ख)	आईएमएस (बीएचयू), सीयू को अनुदान	342.14	362.14	370.00
3 (ग)	केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय	509.00	515.50	
4	केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश	47.40	112.08	
5	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय	37.67	40.67	
	कुल– केंद्रीय विश्वविद्यालय	**11613.97**	**12546.97**	**15928.00**
6	समवत विश्वविद्यालयों को अनुदान	500.00	547.25	596.00

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान			
7	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	9361.50	9861.50	10324.50
8	आईआईटी, हैदराबाद (ईएपी)	300.00	522.71	
	कुल–भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	**9661.50**	**10384.21**	**10324.50**
9	भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) को सहायता	300.00	331.01	212.21
10	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (एनआईटी) और आईआईईएसटी को सहायता	4820.60	4820.60	5040.00
11	भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) को सहायता	1462.00	1509.00	1540.00
12 a	भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता	815.40	845.40	875.77
12 b	नैनो–विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र (सीईएनएसई)		17.97	42.50
13	भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता	290.00	326.55	315.91
14	पीपीपी मोड में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना	270.00	160.00	200.00
15	मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए परिषदों/संस्थानों को अनुदान	400.00	300.73	315.00
16	भारतीय भाषाओं के संवर्धन हेतु संस्थानों को अनुदान	300.70	300.70	314.00
17	भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान	0.10	0.10	0.10
18	राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग संस्थान (एनआईआईई), मुंबई	75.00	75.00	37.45
19	योजना और वास्तुकला के नए स्कूल	175.00	178.00	185.87

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
20	राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर)	150.00	95.00	110.00
21	प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर	34.63	34.63	38.76
22	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू)	105.00	130.80	140.00
23	राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय		4.00	100.00
24	**अन्य संस्थाओं को सहायता**			
24.01	भारतीय विश्वविद्यालय संघ	2.00	2.00	2.00
24.02	नेशनल बुक ट्रस्ट	57.82	70.00	69.30
24.03	पुस्तक प्रचार गतिविधियों और स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए अनुदान	0.02	0.02	0.03
24.04	राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान (नीपा)	61.00	66.88	73.00
24.05	ऑरोविल प्रबंधन	58.00	18.00	59.00
24.06	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग	7.00	7.00	7.00
24.07	एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता	396.00	328.00	355.00
	अन्य संस्थाओं को सहायता–कुल	**581.84**	**491.90**	**565.33**
	कुल– स्वायत्त निकाय	**37335.74**	**39908.82**	**39781.40**
	अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय–एबी के अतिरिक्त			
1	राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क	4.50	4.50	5.00

क्र.सं.	योजना	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
2	योजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता			
2.01	वैश्विक सहभागिता पहल	65.00	35.00	51.00
2.02	सेमिनारों, समितियों की बैठकों आदि पर व्यय/ गैर–सरकारी सदस्यों को टीए/डीए	0.60	0.60	0.60
2.03	शास्त्री इंडो–कैनेडियन इंस्टीट्यूट	7.16	1.00	1.00
2.04	भारत में यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन को आयकर और सीमा शुल्क का प्रतिदाय	1.64	1.64	1.64
2.05	यूनेस्को में योगदान	27.50	29.50	30.00
2.06	यूनेस्को सम्मेलनों आदि में प्रतिनियुक्ति और प्रतिनिधिमंडल।	0.80	0.20	0.80
2.07	विदेशी प्रतिनिधिमंडल का भारत दौरा	0.15	0.15	0.15
2.08	यूनेस्को के लक्ष्यों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए समितियों/सम्मेलन और प्रदर्शनी संगठनों की बैठकों का आयोजन	0.30	0.30	0.30
2.09	एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकॉक	0.50	0.50	0.50
2.10	कॉमनवेल्थ ऑफ़ लर्निंग	12.00	12.00	12.00
	आयोजना, प्रशासन और वैश्विक सहभागिता	**115.65**	**80.89**	**97.99**
	कुल ओसीई– एबी के अतिरिक्त अन्य	**120.15**	**85.39**	**102.99**
	कुल–अन्य केंद्रीय व्यय	**37455.89**	**39994.21**	**39884.39**
	सकल योग	**44094.62**	**44744.48**	**47619.77**

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ	ब.अ. 2023–24	सं.अ. 2023–24	ब.अ. 2024–25
क	**योजनाएँ**			
I	**केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ**			
1	समग्र शिक्षा	37453.47	33000.00	37500.00
2	पीएम पोषण	11600.00	10000.00	12467.39
3	एनआईएलपी	157.00	100.00	160.00
4	स्टार्स	800.00	700.00	1250.00
5	पीएम–श्री	4000.00	2800.00	6050.00
	कुल केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	**54010.47**	**46600.00**	**57427.39**
II	**केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ**			
6	राष्ट्रीय साधन–सह–योग्यता छात्रवृत्ति योजना	364.00	358.00	377.00
7	प्रधानमंत्री नवोन्मेष अधिगम कार्यक्रम (ध्रुव)	0.01	0.00	0.01
	कुल केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ	**364.01**	**358.00**	**377.01**
	कुल योजनाएं	**54374.48**	**46958.00**	**57804.40**
ख	**गैर–योजनाएं**			
III	**अन्य केंद्रीय क्षेत्र व्यय**			
8	केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)	8363.98	8500.00	9302.67
9	नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)	5486.50	5470.00	5800.00
10	एनसीईआरटी	518.50	480.00	510.00
11	राष्ट्रीय बाल भवन	22.38	20.00	26.00
	कुल स्वायत्त निकाय	**14391.36**	**14470.00**	**15638.67**
12	सचिवालय	36.01	42.82	55.02
13	प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय	3.00	2.98	0.01
	योग–स्थापना	39.01	45.80	55.03
	कुल गैर–योजनाएँ	**14430.37**	**14515.80**	**15693.70**
	सकल योग	**68804.85**	**61473.80**	**73498.10**

❖ ❖ ❖

उच्चतर शिक्षा विभाग का संगठनात्मक चार्ट

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

↓

राज्य मंत्री
(i) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (ii) डॉ. सुभाष सरकार (iii) डॉ. राजकुमार रंजन सिंह

↓

उच्चतर शिक्षा विभाग

↓

श्री के. संजय मूर्ति, आईएएस (एचपी: 1989), सचिव (एचई)

श्री सुनील कुमार बरनवाल
आईएएस (जेएच: 1997), अपर सचिव (शिक्षा)
केंद्रीय विश्वविद्यालय, एनटीए, एचईएफए, मेरिट, सम विश्वविद्यालय'', अनुसंधान परिषद'' ,एचईसीआई विधेयक' , एनईपी' यूजीसी', रूसा'' कार्मिक' प्रशासन, सामान्य प्रशासन ' ' सं. सचिव (एचई) के माध्यम से, से सचिव (स्था) के माध्यम से, सलाहकार (लागत) के माध्यम से से सचिव प्रबंधन एमसी एवं छात्रवृत्ति

सुश्री नीता प्रसाद,
(आईआईएस: 91), संयुक्त सचिव (पी और आईसीसी)
आईसीसी, नीति, ईबीएसबी, मीडिया और प्रचार, सतर्कता, भाषाएँ

श्री पी. के.बनर्जी,
(आईएसएस: 1993), संयुक्त सचिव (प्रबंधन एवं एमसी एवं छात्रवृत्ति)
प्रबंधन, अल्पसंख्यक, छात्रवृत्ति, सम विश्वविद्यालय', अनुसंधान परिषद' ''रिपोर्टिंग एएस (ई) के माध्यम से, रिर्पोटिंग

सुश्री रीना सोनोवाल कौली,
आईआईएनएफओएस (1994) संयुक्त सचिव (एचई)
इक्विप, पीएमएमएमएनएमआईटी, एचई/यू–पां लिसी, एचईफ सीडीएन, संसदीय कार्य और समन्वय, एनईपी', एचईसीआई विधेयक', यूजीसी' 'रिपोर्टिंग एएस (ई) के माध्यम से, रिर्पोटिंग

सुश्री सौम्या गुप्ता,
आईएएस (टीआर: 2004), संयुक्त सचिव (टीई)
आईआईटी, टीई, टीसी, एचई में कौशल विकास, आईकेएस, अनुसंधान समन्वय, आईआईआईटी, उन्नत भारत अभियान, आईआईएसईआर, आईआईएससी, स्टार्स, एनआईटी, एसपीए

श्री संजोग कपूर,
आईआरएस (आईटी) (99) सं. सचिव एवं वि. सलाहकार
आईएफडी, बजट, बजट घोषणाएं और निगरानी।

श्री गोविंद जायसवाल,
आईएएस (यूटी: 2007) संयुक्त सचिव (टीईएल)
टीईएल बीओएटी, एसएलआईईटी, सीआईटी, एनआईटीटीटीआर, एनबीटी, आईएसबीएन, बुक प्रमोशन, एआईसीटीई, एनबीए, एडसिल आदि।

श्री मृत्युंजय बेहेरा
(आईईएस: 2001) आ. सलाहकार (एचई)
डीएल, एआईयू, वार्षिक रिपोर्ट लोक शिकायतें, एससीएसटी सेल, एनईआर, पीडब्ल्यूडी, सभी मंत्रालयों, के शिक्षा संबंधी कार्यों में एफडीआई अन्य सभी मंत्रालयों, विभागों के नीतिगत नोट मंत्रिमंडल ईफसी।

श्री सैय्यद इकराम रिजवी,
संयुक्त सचिव (प्रशासन)
राजभाषा, पद्म पुरस्कार, सामान्य प्रशासन (एस एंड एस) ', कार्मिक प्रशासन ', सीएमआईएस, सीआईएसओ 'रिपोर्टिंग एएस (ई) के माध्यम से,

श्री आर. राजेश,
आईएसएस (1996), डीडीजी (सांख्यिकी)
सांख्यिकी

सुश्री. मनमोहन कौर,
आईसीओएस सलाहकार (लागत)
रूसा', एएस (ई) को आवंटित मंत्रालयों से संबंधित विभिन्न मामले 'रिपोर्टिंग एएस (ई) के माध्यम से,

श्री भूपाल नन्दा,
आईसीएस (1993) प्रधान सीसीए
लेखा व्यवस्थापन

अनुलग्नक –II

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का संगठनात्मक चार्ट

शिक्षा मंत्री (श्री धर्मेंद्र प्रधान)

↓

राज्य मंत्री
(i) श्रीमती अन्नपूर्णा देवी (ii) डॉ. सुभाष सरकार (iii) डॉ. राजकुमार रंजन सिंह

↓

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

↓

श्री संजय कुमार, आईएएस (बीएचः 1990)
सचिव (एसईएंडएल)

श्री विपिन कुमार
आईएएस (बीएचः 1996)
अपर सचिव (एसएस–II)

- समग्र शिक्षाः नीति, बजट, योजना और अवसरंचना, वार्षिक पीएबी कैलेंडर सहित
- पीएमएस या प्रबंध प्रणाली
- एनईपी(सार्थक) और आरटीई अधिनियम का कार्यान्वयन
- पीएम श्री और मॉडल स्कूल
- विश्व बैंक परियोजनाएं/स्टार्स, यूनिसेफ और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं,
- सर्वसुलभीकरण, स्कूल न जाने वाले बच्चों, आवासीय स्कूलों और छात्रावासों सहित पहुंच
- स्वच्छ विद्यालय घटक
- समग्र शिक्षा के टीएसजी संबंधी मामले
- पीएबी बैठकों सहित यूपी, गोवा, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, एमपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और राजस्थान राज्यों में समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन संबंधी मामले।
- एलएंडजे, पेयजल और स्वच्छता, कोयला, पावर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, पंचायती राज, दूरसंचार और ग्रामीण विकास मंत्रालयों / विभागों से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।

सुश्री अर्चना शर्मा अवस्थी
आईटीएस (आईटी) (1994)
संयुक्त सचिव (एसएस–I और एई)

- सभी के लिए शिक्षा और साक्षरता, उल्लास (एनआईएलपी), प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई)
- एई हेतु एन.सी.एफ.
- निपुण भारत मिशन, एफएलएन, ईसीसीई
- जेंडर और समानता
- केजीबीवी
- समग्र शिक्षा के घटक जिनमें शामिल हैं
- आईसीटी, स्मार्ट क्लास रूम, खेल–कूद/क्रीड़ा/खेल को बढ़ावा देना, फिट इंडिया अभियानध्स्कूलों में योग, पढ़ना/पुस्तकालयों को बढ़ावा देना, एसएमसी/एसएमडीसी सहित सामुदायिक जुटाव, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (एएलटी) योजना
- एडीबी (एस्पायर)
- कोविड–19 संबंधी मामले
- जी20 ईडीडबल्यूजी संबंधी मामले
- राष्ट्रिय डिजिटल पुस्तकालय
- पीएबी बैठकों सहित पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों में समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन संबंधी मामले
- जनजातीय कार्य, युवा कार्यक्रम और खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक कार्य और डब्ल्यूसीडी मंत्रालयों / विभागों से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।

श्री आनंदराव विष्णु पाटिल
आईएएस (टीएनः 1998) अपर सचिव
(पीएमपीवाई और डिजिटल शिक्षा)

- पीएम–ई–विद्या, एनडीईएआर , वीएसके और डीएसईएल की सभी डिजिटल शिक्षा पहल
- सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पीएम पोषण
- समग्र शिक्षा का स्वास्थ्य और पोषण घटक
- सभी स्कूल बोर्ड, लॉरेंस और सनावर स्कूल सहित निजी स्कूलों से संबंधित मामले।
- परखः
- एनएएस
- एसएएस (सभी स्कूल बोर्ड)
- मनोदर्पण, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण, रंगोत्सव, भाषा महोत्सव, कला उत्सव, खिलौना आधारित शिक्षाशास्त्र आदि जैसे एबी के सभी कार्यक्रम और पहल
- एनटीएसई
- ध्रुवांः विशिष्ट/प्रतिभाशाली बालक
- पीएबी बैठक सहित मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में समग्र शिक्षा
- एफ और पीडी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, एच और एफडब्ल्यू, आयुष, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डीपीआईआईटी, रक्षा, डीएई, एमएसएमई, रेलवे, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए है।

सुश्री अमरप्रीत दुग्गल
आईपीओएस (1999) संयुक्त सचिव
(समन्वय और मीडिया)

- ई–ऑफिस, राष्ट्रीय घटक, प्रधान मंत्री द्वारा सभी समीक्षाओं, सचिवों के क्षेत्रीय समूह, आदि सहित स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के समन्वय और संसदीय कार्य।
- ई–समीक्षा, एलआईएमबीएस, सीपीजीआरएएमएस पोर्टल
- मीडिया
- इको और युवा क्लब
- राष्ट्रीय बल भवन (एनबीबी)
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग संबंधी प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग।
- इज ऑफ डूइंग बिजनेस और अनुपालन कार्य को कम करने संबंधी मामले
- एकेएएम
- पीएबी बैठकों सहित उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन संबंधी मामले
- संसदीय कार्य मंत्रालय/विभाग, डीओपीटी, डीएआरपीजी, विदेश, सूचना एवं प्रसारण, क्षमता निर्माण आयोग, नागरिक उड्डयन, कॉर्पोरेट कार्य, संस्कृति, पर्यटन, माई जीओवी से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।

सुश्री प्राची पांडे
आईए और एएस (2001), संयुक्त सचिव
(संस्थान और प्रशिक्षण)

- एनसीईआरटी, केविसं, नविस, सीबीएसई, एनआईओएस, एनसीटीई
- एफएस, एसई, टीई, एई हेतु एनसीएफ
- केविसं उपाध्यक्ष
- व्यावसायिक शिक्षा के सभी पहलू
- शिक्षक शिक्षा, भर्ती और अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, डीआईईटी/एससीईआरटी/सीआरसी/बीआरसी के सभी पहलू
- राष्ट्रीय शिक्षक कल्याण फाउंडेशन (एनएफटीडबल्यू)
- शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार (एनएटी)
- स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार
- परीक्षा पे चर्चा
- स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग संबंधी वार्षिक रिपोर्ट – स्वायत्त निकायों द्वारा नई पहल
- एनसीटीई के माध्यम से टीई में नवाचार संबंधी भारत रिपोर्ट तैयार करना
- उच्चतर शिक्षा मंत्रालय, एमएसडीई, उपभोक्ता मामले, श्रम और रोजगार, सड़क परिवहन और राजमार्ग, इस्पात, वस्त्र, रसायन और उर्वरक, पृथ्वी विज्ञान, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, खान, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालयों / विभागों से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।

सुश्री ए. श्रीजा
आईईएस (1996) आर्थिक सलाहकार
(एसई और एल)

- बजट विश्लेषण और घोषणाएं
- आर्थिक विश्लेषण
- राष्ट्रीय साधन– सह–मेधा छात्रवृत्ति योजना
- सीडब्ल्यूएसएन के लिए पहल, समावेशन रिपोर्ट
- विभाग में एनआईसी और पोर्टल जिनमें विद्यांजलि, शगुन, विद्या अमृत आदि शामिल हैं
- डीबीटी से संबंधित कार्य
- एक भारत श्रेष्ठ भारत जिसमें ईबीएसबी संबंधी भारत रिपोर्ट तैयार करना, मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं का अध्ययन करके वार्षिक–भारत स्कूल शिक्षा अभिसरण रिपोर्ट तैयार करना और अभिसरण का सुझाव देना शामिल है।
- आकांक्षी जिले और ब्लॉक
- जम्मू–कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, दादर नगर हवेली और दमन–दीव, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ राज्य क्षेत्रों में पीएबी बैठकों, यूटी प्रशासन समन्वय सहित समग्र शिक्षा के कार्यान्वयन से संबंधित मामले
- गृह मंत्रालय, आर्थिक कार्य, नीति आयोग, यूआईडीएआई, कृषि और किसान कल्याण, वित्त आयोग, सहकारिता, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम, आवास और शहरी मामलों, एसजे और ई के मंत्रालयों / विभागों से संबंधित ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।

श्री वी. हेगड़े
आईएसएस (2000),
डीडीजी (सांख्यिकी)

- वैश्विक सूचकांक, स्कूल शिक्षा संबंधी रिपोर्टों का विश्लेषण
- यूडाइज, यूडाइज
- प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
- छात्र रजिस्ट्री
- ओओएमएफ की निगरानी
- प्रकाशन "परीक्षा परिणाम", "एक नजर में शैक्षिक सांख्यिकी" "स्कूल शिक्षा संबंधी चयनित जानकारी", सेवा सूचकांक (शिक्षा), उत्पादन, जनसंख्या प्रक्षेपण
- सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)
- शिक्षा मंत्रालय संबंधी सूचकांकों सहित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, वाणिज्य और समन्वय के मंत्रालयों / विभागों संबंधी ऐसे शेष कार्यों के लिए नोडल अधिकारी जो किसी को भी आबंटित नहीं किए गए हैं।
- यूनेस्को सांख्यिकी संस्थान (यूआईएस) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को डेटा की आपूर्ति

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
और
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग